

कांग्रेस का इतिहास

(१८८५ से १९४७ तक)

डॉ॰ बी॰ पट्टाभि सीतारामय्या

१९५८ सत्साहित्य-प्रकाशन प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय मत्री, सस्ता साहित्य मण्डल न्ई दिल्ली

> मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

प्रकाशकीय

कई वर्ष पहले 'मडल' ने डॉ॰ पट्टामि सीतारामय्या की सुप्रसिद्ध पुस्तक 'काग्रेस का इतिहास' प्रकाशित की थी। वह तीन जिल्दो में हैं और प्रत्येक जिल्द का मूल्य दस रुपया है। यद्यपि वह अपने विषय की एक ही पुस्तक हैं और काग्रेस तथा आजादी के लिए किये गए संघर्ष की वह विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती हैं, फिर भी वह आकार में इतनी बड़ी हैं और उसका मूल्य इतना अधिक हैं कि सामान्य स्थित के पाठक उसे सहज ही नहीं खरीद सकते।

इसलिए बहुत दिनो से विचार हो रहा था कि इस विशाल पुस्तक का सिक्षप्त सस्करण निकाला जाय। फलत कुछ विवरणों को कम करके, पुस्तक का आकार घटाकर, उसे एक जिल्द में प्रकाशित किया जा रहा है। अब इसका रूप ऐसा और मूल्य इतना हो गया है कि सीमित साधनोंवाले व्यक्ति भी इसे खरीदकर लाभ उठा सकते हैं। पाठक यह न समझे कि सिक्षप्त करने में कुछ विशेष घटनाएं छूट गई होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं हैं। विवरण कम हुए हैं, पर महत्व की घटनाएं न छूटे, ऐसी सावधानी बराबर रक्खी गई हैं।

पुस्तक की भाषा में भी यत्र-तत्र थोडा बहुत सुधार कर दिया गया है। इसलिए वह पहले की अपेक्षा अब अधिक प्रवाहपूर्ण बन गई है।

अपने देश को समझने के लिए काग्रेस तथा उसके काम की विस्तृत जानकारी आवश्यक है और इस दृष्टि से इस इतिहास का पहले से भी अधिक महत्व है।

पुस्तक का सिक्षप्तीकरण श्री राजेन्द्रसिह गौड ने किया है। वे बडे अनुभवी व्यक्ति हैं और उन्होंने बड़े परिश्रम से ग्रथ को अच्छी तरह पढ़कर तथा काग्रेस के किमक विकास को समझकर इस जिम्मेदारी-भरे काम को किया है। हम गौड जी तथा अन्य वधुओं के, जिन्होंने इस कार्य में सहायता दी है, आभारी है।

हमे पूर्ण विश्वास है कि यह पहला सस्करण हाथोहाथ निकल जायगा और हमें शीघ्र ही नया संस्करण करना होगा। शिक्षा-संस्थाओं में इस पुस्तक का उपयोग पाठच पुस्तक के रूप में किया जा सकता है, और कोई भी ऐसी शिक्षा-सस्था नहीं रहनी चाहिए, जिसमें इसकी प्रति न हो। कम प्रतियाँ छापी गई है, इसलिए अपनी आवश्यकता की प्रति या प्रतियाँ जल्दी ही प्राप्त कर ले।

पाठको को स्मरण होगा कि पहले तीनो जिल्दो का मूल्य ३०) था। अब केवल ५) रुपया है।

हम यह भी आशा करते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद होगा।

---मन्नो

प्रस्तावना

पहले संस्करण से

: ? :

काग्रेस का इतिहास मुख्यतः मानवीय इतिहास है। मानव दो श्रेणियों में विभाजित किये जाते हैं। कुछ तो अपने तजरबें से जानकारी हासिल करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के अनुभव से लाभ उठाते हैं। निस्सन्देह इस दूसरे प्रकार के लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें मिसाल या चेतावनी के तौर पर सम-सामयिक या चालू जमाने का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता होती हैं। भावी राष्ट्रीयता के लिए समय-समय पर उसकी सफलताओं का लिपबद्ध होना आवश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए जमाने में और परिवर्तित स्थित के अनुसार अपना रास्ता तय कर सके।

ठीक ही कहा गया है कि 'एशिया दुनिया का केन्द्र है।' भौगोलिक दृष्टि से यूरोप उसकी शाखा है, अफीका उप-महाद्वीप है और आस्ट्रेलिया उसका टापू।

एशिया एक पुराना महाद्वीप है।

१९ वी सदी की गुरूआत का जमाना ऐसा था जब उपेक्षित भूखण्डो का साबका दुनिया की बड़ी-बड़ी कौमों से पड़ा। इस सम्बन्ध से एशिया का पुनर्स्थापन हो गया और वह अपने आदर्शों की छाप बाहरी दुनिया पर डालने लगा। टैगोर और गाधी एशिया के बौद्धिक प्रसार की मिसाले हैं। सिकन्दर महान् का पूर्व और पिंचम को मिलाने का स्वप्न पुनर्जीवित हो रहा है। एशिया का समन्वयकारी आदर्श एक ऐसे विकास की ओर ले जा रहा है, जो मुक्ति की दिशा में हैं। एशिया महाखण्ड अपने भविष्य में विश्वास रखता है और उसका यह भी विश्वास है कि वह ससार को एक सन्देश देगा। उसमें आत्म-चेतनता जग रही हैं, जो चगेज खा की वह यादगार ताजी कर देती हैं जिसने सबसे पहले एशिया की एकता का आन्दोलन चलाया था। उन भावनाओं को जापान में समुचित उर्वर भूमि मिली। पर सारा एशिया इस बात को महसूस करता है कि कनप्यूशियस के शब्दों में हम अभी तक अव्यवस्थित हालत में जी रहे हैं, हम उस शांति की मजिल से दूर हैं, जिससे 'कुछ स्थिरता' मिलती हैं और वह 'अन्तिम शांति की अवस्था' तो अभी हमारी दृष्टि में नहीं आई हैं।'

१. एशिया और अमेरिका, जून १९४४, वृष्ठ २७५।

दुनिया अव जुदा-जुदा कोमो का समूह नही हो। राष्ट्रीयता को व्यापक अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धात में वदल देने पर भी उसे उस दूर तक पहुचानेवाले परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नहीं मिलता, जिसे दूसरे विश्व-व्यापी महायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है। उसी की वदौलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतत्र अलग टुकड़े के रूप में वर्ताव नहीं हुआ। इसी कारण दुनिया मि० विन्स्टन चर्चिल के इस झासे से परितुप्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो इग्लैण्ड का अपना है और अटलाटिक का समझौता ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर लागू नहीं होगा। हिन्दुस्तान अव ब्रिटिश-भवन का महत्वपूर्ण भाग नहीं रहा। यह वात अब आम तोर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान ससार के धर्मों का सन्धि-स्थल और विग्व-संस्कृति का एक संस्थल है, पर साथ ही यह देश संसार के ध्यान में ध्रुव-तारा बन गया है, और संसार की दिलचस्पी का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमण्डल के उस गोलाई में अमेरिका है, उसी तरह इस गोलाई मे यह अटलाटिक और प्रशात महासागर का सन्धि-स्थल है। कन्याकुमारी जाकर बाप पिवत्र 'केप' के छोर पर खडे होकर समुद्र की ओर मूह की जिए। आपके दाहिने हाथ अरव सागर होगा जो 'केप आव गुडहोप' (अर्थात् अफीका के दक्षिणी छोर पर स्थित आजा अतरीप) पर जाकर अटलाटिक महासागर से मिलता है, और आपके वाये हाथ की ओर वगाल की खाडी होगी, जो प्रशात महासाग्र से जा मिलती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व और पश्चिम के मिलने का स्थान है, प्रशात-स्थित राष्ट्रो की आजादी की कुजी है और अटलाटिक-स्थित राष्ट्रो की मनमानी पर एक नियत्रण है। हिन्दुस्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है, जिसकी स्वत्त्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पड़ गई थी और उसने वहाँ के ४५ करोड निवासियो की आजादी को सकट में डालने की कोशिश की थी, पर अव खुद विजेता के गर्वीले चरणो पर गिरा पडा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयकर रोग की एक दवा आजाद चीन है। पर गुलाम हिन्दुस्तान आधे-गुलाम चीन के लिए नहीं लड सकता था या यूरोप को गुलाम नहीं बना सकता था। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान की आजादी नई सामाजिक व्यवस्था का बुनियादी तथ्य कायम करेगी और इस देश के चालू सामूहिक संघर्ष का ध्येय ऐसे ही आ गाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना है। इस लडाई में अगर हिन्दुस्तान निष्क्रिय दर्शक की तरह का स्थापना करना हा इस लडाइ न जगर हिन्दुस्तान निम्म प्राप्त पराच गा पर्व बैठा यह देखता रहता कि यहाँ दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुलाम वनाने के वास्ते परि-चालित युद्ध में भाग लेने के लिए भाडे के टट्ट भर्ती किए जा रहे हैं और भारत की अपनी ही आजादी-जैसी वर्तमान समस्या की उपेक्षा की जा रही है, तो इसका मतलव भावी विच्व-सकट को निमत्रण देना होता, क्योंकि विना आजादी हासिल किये हुए हिन्दुस्तान पर लालच-भरी निगाह रखनेवाल नव-शक्ति-सयुक्त पडोसी या पडोसी के पडोसी की लार टपकती। उस समय भारत की अभिनव राजनीति, ससार की आर्थिक परिस्थिति और विविध नैतिक पहलुओ के वाहरी देवाव के. कारण काग्रेस ने एक योजना की कल्पना की और १९४२ में सामूहिक अवंजन आरम्भ करने का निञ्चय किया। इन पृष्ठों में उस सवर्ष के विभिन्न रूपी और उसके परिणामो का वर्णन है जो वम्बई में ८ अगस्त १९४२ में किये गए फैसले को अमल मे लाने के लिए किया गया था। 'भारत छोडो' का नारा इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का मूल-विन्दु था जिसके चारो ओर उसी के अनुसरण मे आन्दोलन चलता था। जल्द ही यह लडाई का नारा बन गया जिसमें स्त्री-पुरुष और वच्चे सभी समा गये, गहर, कस्वे और गाव सभी जुट गये, पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिलित हो गये, व्यापारी और कारखानेदार, परिगणित जातियाँ और आदिम निवासी सभी इस भावना के भवर में, हगामा और ऋति की लहर मे आ गये। अलग-अलग जमाने मे विभिन्न शताब्दियो मे जुदे-जुदे राष्ट्र ऐसे ही प्रभावो मे बहते रहे हैं। किसी समय अमेरिका की वारी थी, कभी फास की, किसी दगाव्द में यूनान की तो कभी जर्मनी की। इन सभी विद्रोहों के कार्य-कारण का तात्विक मूल एक ही था। सरकारो की शरीर-रचना, शासन की अवयव-क्रिया और राजनैतिक जमातो का रोगाणु निदान सभी जमाने मे और सभी मुलको मे हुआ है।

: ?:

अक्सर दुनिया में जो लडाइयाँ हुई है उनमें गस्त्रास्त्रों और साज-सरजामों की उत्कृप्टता को ही सबसे ऊचा महत्व प्राप्त हुआ है। एक इतिहासकार ने कहा है कि मैसोडोनिया के भालों की बदौलत यूनान की सस्कृति एगिया में पहुँची है और स्पेन की तलवार ने रोम को इस योग्य बनाया था कि वह आजकल की दुनिया को अपनी परम्परा प्रदान कर सका है। इसी तरह १९४४ में जर्मनी के 'उड़ानेवाले बमो' द्वारा लडाई का पलडा ही पलट जानेवाला था, पर वह व्यर्थ हो गया। तो भी तथ्य यह है कि यूरोप के युद्ध-कीशल के अतिरिक्त युद्ध में काम देने वाली और और जित्तयों भी होती है जिनका वर्णन वेकन ने इस प्रकार किया है—"शारीरिक वल और मानव-मस्तिष्क का फीलाद, चतुरता, साहस, धृष्टता, दृढ निश्चय, स्वभाव और श्रम।" इस बात के वावजूद कि वेकन एक दार्जनिक ओर वैज्ञानिक था, यह सामान्य वृद्धि के स्तर से अधिक ऊँचा नहीं उठ सका और जहाँ वह उठा वह। यह साहस में बढकर और गुणों की कल्पना नहीं कर सका। हिन्दुस्तान में हमने सामान्य स्तर में अपर उठकर सत्य और अहिमा के लिए कष्ट-सहन करते हुए लडाई जारी रखी है. ओर इस तरह हम सत्याग्रह की जिस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, उसने निस्मन्देह इतिहास का रूप वदल गया है, और जित्त और अधिकार, सच और जूट, हिंसा और अहिसा तथा पन्-वल एवं आत्म-वल के सवर्प में विजय की

सम्भावना भी परिवर्तित हो गई हैं। जिस युद्ध को ससार का दूसरा महायुद्ध कहा जाता है उसका श्रीगणेश किसी ऊँचे सिद्धात को लेकर नही हुआ था और अटलाटिक का समझौता—जो एक साल बाद हुआ था, टीका-टिप्पणी के वाद भी हिन्दुस्तान और जर्मनी के लिए एक जैसा किसी पर भी लागू न होनेवाला होगा। उससे वीसवी सदी के आरम्भिक चालीस वर्षों के युद्ध-नायको का अवली रूप प्रकट हो गया। और उस पर भी तुर्रा यह कि यह युद्ध एक सर्वग्राही युद्ध वन गया, जिसने खुले रूप मे एकाधिकार के द्वारा और मनमाने ढग मे—आयोजित रूप मे जनता की सैनिक भर्ती करके युद्ध-सचालन किया और आज दी तथा प्रजातन्त्र की सभी ऊँची वाते हवा, भाप और सुन्दर वाक्यालकार की तरह उड गई। जन कप्ट-ग्रस्तो के दावो पर अपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर आया और र्चीचल की 'अपने पर दृढ रहने' की अस्पप्ट वात को कार्यान्वित करने का मौका आया तो ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के नामधारी राजद्रोहियो को दण्ड देने, अपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वोचन स्थगित करने और समाचारपत्रो तथा पत्र-व्यव-हार तक पर कठोर निरीक्षण—सेसर रखने की नीति वरती गई। यदि युद्ध का यही उद्देश्य था और जूसे जीतने के लिए यही ढ्ग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात के लिए वदनाम नही किया जा सकता कि उसने पोलैण्ड, चेकोस्लवाकिया, यूनान और फिनलैण्ड को आजाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह और उत्तेजना क्यों नहीं प्रदिश्ति की। केवल ब्रिटेन साम्राज्यवादी और अनुदार नहीं है, विलक रूस ने भी वह वेदेशिक नीति ग्रहण करली जो जारशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त होती और सीघे निकोलस द्वितीय-द्वारा परिचालित होने पर अधिक उपयुक्त प्रतीत होती। पोलैण्ड का उद्घार करने के लिए जो युद्ध सचालित किया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसके टुकडे हो गये और उसे रूस की निर्दयता-पूर्ण इच्छा पर छोड दिया गया और उन्होने मामले को वही तक नही रखा। रूस ने वसराविया और वुकोविना, फिनलैण्ड और लटविया तथा इस्टोनिया और लिथुआनिया तक पर आक्रमण किया और डार्डेनिल्स के द्वारा मेडिटरेनियन या मृतक सागर पर भी कब्जा जमाने की माग की। डार्डेनिल्स पर रूस का हाय् होने का मतलव था फारस की मौत। इस युद्ध में हिन्दुस्तान को, विना उससे पूछे या जाचे ही ग्रस्त कर लिया गया। यह वह युद्ध था जिसने अपने साथ ब्रिटेन के लिए 'भारत-छोडों' का नारा लगाया और जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दण्ड भोगना पडा—सैकडो को वेत लगाये गये, हजार से अधिक को गोली से उडा दिया गया, कितने ही हजारों को जेल में ठूस दिया गया और करीव दो करोड़ के सामूहिक जुर्माने वसूल किये गये।

यद्यपि इतिहास का विकास सारे ससार में सामान्य सिद्धातो पर होता है, विशिष्ट राष्ट्रो, देशो और राज्यों के विकास का मार्ग उनकी अपनी विलक्षण स्थिति

में होता है। खासकर हिन्दुस्तान में इन स्थितियों का जन्म और विकास खिच्छ रूप में हुआ है। एक ऐसे विस्तृत देश का, जो लम्बाई-चौडाई में महाद्वीप के समान और जमीन और आकृति में विभिन्न है, लगभग दो सदी तक पराधीन रहेना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण आधुनिक इतिहास मे नही मिल सकता। इसके लिए हमे ससार के इतिहास में बहुत पीछे तक मुडना पडेगा जब ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से पूर्व में मिस्र तक था और जो लगभग चार सदियों तक कायम रहा था। किन्तु इस पराधीनता के उदाहरण मे एक जगह सादृश्य समाप्त हो जाता है। जव म्कित की प्रक्रिया आरम्भ होती है तो हिन्दुस्तान मे यह पराधीनता एक ऐसा नितात विरोधी रूप धारण कर लेती है जैसा संसार के इतिहास में कही भी देखने में नहीं आता। हिन्दुस्तान में गत चौथाई सदी से घटनाओं ने जो रूप धारण किया है वह संसार में अद्वितीय है और सत्य और अहिसा के सिद्धातो का प्रयोग--जिसे सक्षेप मे 'सत्याग्रह' कहते हैं--ऐसा है जिसकी बहुत-सी मजिले और दर्जे हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय क्षोभ--असहयोग से करबन्दी तक सविनय अवज्ञा-आदोलन के विभिन्न रूपो द्वारा प्रकाशित किया गया है और युद्ध-काल मे हिन्दुस्तान की यह अस्पृहणीय--अप्रत्याशितता--स्थिति बना दी गई है। काग्रेस की हमेगा यह राय थी कि युद्ध-प्रयत्न मे हिन्दुस्तान का भाग लेना इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें जुटना अपना कर्त्तंव्य समझे। इस तरह की मार्ग लगातार की गई, पर वह फिजूल साबित हुई। संघर्ष का कारण स्पप्ट था। सविनय-अवज्ञा-आदोलन के लिए वातावरण तैयार था, जो देश के लडने और साहसपूर्वक लडने के लिए एकमात्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की योग्यता की कसौटी यह है कि जनता को स्वजासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष के लिए योग्यता की कसीटी यह है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या इंग्लैण्ड १ अगस्त १९१७ या ३ सितम्बर १९३९ को लडाई के लिए तैयार था १ जनता जब युद्ध में लग जाती हैं तो उसे सीख लेती हैं। हिसा और अहिसा दोनो ही प्रकार की लडाइयों में यह बात सच हैं। सवाल सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। पहले की परीक्षा हो चुकी है और 'क्रिप्स-मिशन' के समय उसका आशिक परिणाम भी देखने में आया है। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रवल वेग से हिला दिया. जिसके फलस्वरूप मार्च १९४६ मे हिन्दुस्तान मे ब्रिटेन से मन्त्रि-मण्डल मिशन' आया।

: ३:

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुस्तक में सिक्षप्त रूप में किया गया है। काग्रेस करीव ३३ महीने जेल में रही और न केवल विना किसी प्रकार की हानि में पड़े, बल्कि इज्जत के साथ वाहर आई। फिर भी इस थोड़े से अन्तर्काल में कितनी ही घटनाएँ गुजर चुकी। हम एक ऐसे जमाने मे रहते हैं जब सदियो की तरक्की संघन होकर देशाब्दियों में और दर्शाब्दियों की वरसों में आ जाती हैं। काग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक हलचल फैल गई। पुरानी और नई दोनो ही दुनिया के लोगो ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लडाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया था, और यह कि क्या ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जैसी होने का दावा करती है वैसी सचमुच है, और अगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लडाई में भाग लेने के विरुद्ध इतना शोर क्यों मचाया? यह प्रवन भी हुआ कि अगर मुस्लिम् लीग और काग्रेस दोनो ही ने युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फौज मे भर्ती हुए है वे साम्राज्य के भक्त के रूप मे आये है या इसे खेल समझ कर इसमें साहसी पुरुषों की तरह जामिल हो गये हैं? अथवा वे लड़ाई के कठिन दिनों में गुनारे के लिए पेशेवर सैनिक सिपाही के रूप में भर्ती हुए है। एक जब्द में, आजादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार व्यापक रूप में विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। विटेन में जो लोग युद्ध-क्षेत्र में जाने से रह गये थे उनकी आवाज अभी तक क्षीण तो थी, पर उसमें समानता और न्याय की पूट थी, इसलिए उसमें काफी जोर था। वह युद्ध की घोर व्वनि और घूलि में भी सुनाई पड़ी। धीरे-धीरे यह लडाई सर्वग्राही और सर्वगोषक वन गई।

अमेरिका में लोग तीन हिस्सो में वँट गये थे—एक तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी मामला है, और एक दूसरा छोटा दल इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की आजादी जैसी विगाल समस्या पर लडाई के दिनों में विचार नहीं हो सकता, उसे लडाई खत्म होने तक ककना चाहिए। तीसरा और सबसे वडा दल जनता के उन सीये-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त आजादी मिल जानी चाहिए।

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिका और चीनी राष्ट्रो से अपील की तो वह इस वात को जानता था कि ब्रिटेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है बार अन्य राष्ट्रो का हिन्दुस्तान या ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेश या अधीनस्य देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो भी हिन्दुस्तान और कागेस इम बात से अवगत धे कि ब्रिटेन सम्य-राष्ट्रों के नक्षत्रमण्डल से अलग कोई चीज नहें, हैं और वह अन्य राष्ट्रों के साथ धनिष्ट रूप में अन्तर्सम्बन्धित है। हिन्दुस्तान अपनी शक्ति और कमशोरी दोनों को जानता हैं और वह केवल मानवता के नाम पर बाहरी देशों का हस्तक्षेप मात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ उसके ही देश में बुरा वर्ताव होता हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका वचाव किसी तरह नहीं कर सकता। तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों

या उसके किसी हिस्से के प्रति दुर्व्यवहार कभी-कभी इतना घोर होता है (जैमा कि वेलिजयन कागों के मूल निवासियों के साथ हुआ है या टर्की-साम्राज्य-द्वारा आर्मेनियन ईसाइयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हालत में दुनिया का लोकमित उससे प्रज्वलित हो उठता है। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती है कि वह ऐसे अत्याचारों का विरोध करे।

इसलिए अगर हिन्दुस्तान दमन का हाथ रोकने में सफल नहीं हुआ तो उसके गारीरिक कव्टसहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्थन-द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति कर चुके जो सघर्ष मे उसने औरो से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य और अहिसा के ऊँचे मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए उसका आजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह हिमालय की ऊँचाई से बजता हुआ प्रतिब्वनित होता है, और काबुल के सघन देश में होते हुए मक्का मुअज्जन, मदीना मुनव्वर, फिलस्तीन के सीनाई पर्वत और एणिया माइनर के पामीर तक उसकी आवाज पहुँचती है। यही नही, आल्प्स के द्वारा वह पन्छिम की ओर और एपीनाइन, पाइरेनीस और एलवियन की चाल की श्वगमाला तक जा पहुँचती है। इसी प्रकार उसकी गूज काकेशिया और यूराल तक भी पहुँचती हैं और कितने ही दुर्ल्ध्य पहाडियो को पार करती हुई नई दुनिया मे पहुच जाती है। हिन्दुस्तान अच्छी तरह जानता है और पहले से जानता आया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है और 'देशी तलवार' और देशी हायों-द्वारा' ही उसका उद्धार होगा; पर उसने वायरन का युद्ध-क्रपाण गाधीजी की शाति-पूर्ण सहारे की लाठी से बदल लिया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के लिए नये शस्त्र का प्रयोग कर इतिहास बनाने की कोशिश की है और खून के प्यासे योद्धाओ के रक्त-मास प्रदर्शन को वदलकर उसे ऊँचाई पर पहुँचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक देवी आत्मा वन जाता है। वीसवी सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर लिया और पा लिया है, एक नया झण्डा और नया नेता और इन पृष्ठो मे भारत की आजादी के पवित्र ध्येय के प्रति ससार की प्रतित्रिया का वर्णन किया गया है। उसकी आजादी के राष्ट्रध्वज के परिवर्तन और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रव्यापी सवर्ष का नेतृत्व करने वाले महात्मा गाधी के महान् उपदेश जीर उनकी योजना का भी इसमें समावेश है।

--राजेन्द्र प्रसाद



लेखक की ओर से

मुझे हर्ष है कि 'काग्रेस का इतिहास' का यह सिक्षप्त सस्करण पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। बड़ा संस्करण हिन्दी में तीन भागों में प्रकाशित हुआ था। वह बहुत वृहद था और उसका मूल्य भी इतना था कि सामान्य पाठक उसे नहीं खरीद सकते थे। इस सस्करण में विस्तार कम कर दिया गया है, लेकिन उसकी प्रमुख घटनाओं को ज्यों-का-त्यों रक्खा है। आकार घट जाने से मूल्य में भी काफी कमी हो गई है। मुझे आज्ञा है कि अब अधिक-से-अधिक पाठक इससे लाभ उठा सकेंगे।

पाठक जानते हैं कि कोई उद्देश्य निश्चित करके मैंने इस पुस्तक की तैयारी का भार नहीं उठाया था। १९३५ की ग्रीष्म-ऋतु में बेकारी के समय कलम-विसाई करते-करते यह ग्रंथ अपने-आप तैयार हो गया। बात यह हुई कि काग्रेस के मत्री महोदय ने किसी दूसरे मामले में मुझसे यो ही एक बात पूछी। उसी सिलसिले में मत्री महोदय द्वारा काग्रेस के अध्यक्ष को, जो उस समय राष्ट्रपति कहलाते थे, इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गई। उन्होंने यह मामला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक काग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया।

१९४२ से १९४५ तक जेल की जिन्दगी में मुझे काफी फुरसत मिली, जिससे में यह लम्वा इतिहास लिख सका। अवकाश मिलना लिखने की दृष्टि से सुविधा की वात होती हैं, पर चालू जमाने का इतिहास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं होती। सबसे पहली बात तो इसमें अनुपात समझने की होती हैं। जो ऐति-हासिक वर्णन किसी जमाने में काफी महत्व के होते हैं, वे भी यकायक अपनी अहमियत और विश्वस्तता खो बैठते हैं। इसीलिए जो इतिहासकार अपने लिखे हुए को छाती से लगाये रहता है, वह अपनी इतिहासकारिता का उपहास कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए जितनी सामग्री वृहद ग्रंथ में प्रकाशित हुई उससे दुगनी बड़ी कठोरता से और कुछ खेद के साथ अस्वीकार कर देनी पड़ी, यहाँ तक कि पोथी भारी न होने देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विवरण छोड देने पड़े। भिन्न-भिन्न अधिवेशनो के निश्चय कमश. उद्वृत नहीं किये गए। लेकिन फिर भी पुस्तक आशातीत रूप में बड़ी हो गई। पुस्तक में दोष भी बहुत रह गये। फिर भी मैं जो कुछ कर सकता था, उसे मेंने किया। काग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष ने पुस्तक को

दो बार पढा। इस प्रकार उन्हें पुनरावलोकन और सगोधन-कार्य में वडा परिश्रम करना पडा। काग्रेस के तत्कालीन प्रधान मत्री आचार्य कृपलानी ने भी इस पर विशेष परिश्रम किया। इन तथा अन्य मित्रों को, जिन्होंने इस जिम्मेदारी के काम में मेरी मदद की, में धन्यवाद देता हूँ। लिखना आसान है—जिस तरह भवन-निर्माण सरल है, पर उसे साफ-सुथरे रूप में पेग करने में वडे ध्यान और गक्ति की जरूरत होती है।

इस पुस्तक में सन १९४७ के बाद की घटनाओं का समावेश नहीं किया गया है। सन् ४७ में देश स्वतत्र हो गया। तब से देश के शासन की वागडोर एक पार्टी के हाथ में आ गई। स्वभावत यह पार्टी काग्रेस थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब देश का दैनिक शासन और काग्रेस की दैनिक गति-विधियाँ न केवल एका-कार हो गई है, अपितु वह एक-दूसरे से सबद्ध एवं अन्योन्याश्रित भी हो गई है। इसिलए स्वाधीनता के आगमन के बाद से इतिहास की श्रृंखला को जारी रखने का दायित्व उन लोगो पर है, जो शासन-सचालन से निकट सबध रखते हैं। इसके लिए आवन्यक है कि इस कार्य में वे काग्रेस के उन नेताओं का भी सहयोग प्राप्त करें, जिन्होंने मौजूदा इतिहास को सर्वागीण रूप से प्रभावित किया है।

१५ अगस्त १९४७ एक तरह से गगा और यमुना के सगम का प्रतीक हैं, जिसके वाद दोनो निदयाँ मिलकर बहती हैं। इस तिथि के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हुआ हैं, उसे सब जानते हैं।

मुझे आजा है कि इस सिक्षप्त सस्करण का उसी प्रकार स्वागत होगा, जिस प्रकार वडे सस्करण का हुआ था।

— बी० पट्टाभि सीतारमाय्या

हैदराबाद २२ अप्रैल, १९५८

विषय-सूची

१. काग्रेस का जन्म : १८८४

१८५७ के पहले की स्थिति, अशान्ति और मि० ह्यम की चिन्ता, काग्रेस का जन्म, पूर्व-प्रयत्न और सस्थाएँ, काग्रेस का प्रारिमक लक्ष्य, भारत और इंग्लैण्ड में प्रचार, काग्रेस का प्रथम अधिवेशन १८८५, काग्रेस का दावा।

2--- 24

२. कांग्रेस के हितैषी और कर्णधार

अग्रेज-हितैपी—जान व्राइट, फॉसेट साहव, ह्यूम साहब, सर विलियम वेडरबर्न, रैमजे मैंवडानल्ड, चार्ल्स ब्रैडला, ग्लैंडस्टन, लार्ड नॉर्थ बुक, लार्ड स्टैनले, जनरल वूथ और हेनरी काटन, भारतीय कर्णधार—दादाभाई नौरोजी, आनन्द चार्लू, दीनगा एदलजी वाचा, गोपालकृष्ण गोखले, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, बदरुद्दीन तैयवजी, उमेशचन्द वनर्जी, लोकमान्य तिलक, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, फीरोजगाह मेहता, आनन्दमोहन वसु, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य, कालीचरण वनर्जी, नवाव सयद मुहम्मद वहादुर, दाजी आवाजी खरे, सी० शकरन नायर, विपिनचन्द्र पाल, मौलाना मजहरल हक, महादेव गोविन्द रानडे, रमेशचन्द्र दत्त, एन० सुद्याराव पुन्तुल और सिच्चदानन्द सिह।

84--33

३. कांग्रेस की प्रारंभिक नीति : १८८५-१९१५

इण्डिया-कौसिल, वैधानिक परिवर्तन, सरकारी नौकरियाँ, तैनिक समस्या, कानून और न्याय, दायमी वन्दोवस्त और अकाल, णानून जगलात, व्यापार और उद्योग, विहिष्कार और स्वराज्य, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रवासी भारतवासी, नमक-कर का विरोध, गराव और वेष्यावृत्ति, स्त्रियाँ और दलित जातियाँ, अन्य विषय और कायेस का विधान।

33--48

४. दमन नीति और नई जागृति : १८८४-१९१४

सरकारी प्रलोभन और दमन-नीति का सूत्रपात।

५९---६९

५. मतभेद का अन्त: १९१५-१६

आत्म-विश्वास की झलक, समझौते का प्रयत्न, दो होमरूल लीगो की स्थापना, श्रीमती वेसेट की नीति, मत-भेद का अन्त और लखनऊ-काग्रेस १९१६।

६ उत्तरदायी शासन की माग . १९१७

होमरूल आन्दोलन, गाही युद्ध-पर्रिषद्, सत्याग्रह पर विचार, माण्टेगु की घोषणा, काग्रेस का आवेदन-पत्र, काग्रेस का सगठन और कलकत्ता-काग्रेस १९१७।

७६---८२

७ माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना १९१८

महासिमिति की बैठक, माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना का प्रभाव, काग्रेस का विशेष अधिवेशन, दमन और गिरफ्तारियाँ और दिल्ली-काग्रेस १९१८।

८२---८९

प्त सत्याग्रह और पंजाब-हत्याकाड: १९१९

रौलट बिल का मतव्य, सत्याग्रह का सूत्रपात, आन्दोलन की तीव्रता, जिल्यावाला-हत्याकाड, दुर्घटनाओं के बाद, गाधीजी का वक्तव्य, शिष्टमडल का कार्य, जाच-समिति की नियुक्ति और अमृतसर-काग्रेस १९१९।

९. असहयोग का जन्म १९२०

खिलाफत-सववी अन्याय, लोकमान्य तिलक के विचार, सत्याग्रह का निश्चय, कुली-प्रथा का अन्त, हण्टर रिपोर्ट का प्रभाव, असह-योग का प्रस्ताव, नागपुर-काग्रेस १९२०, चम्पारन-सत्याग्रह, खेडा-सत्याग्रह और अहमदावाद-सत्याग्रह। १०४

१० असहयोग का वेग . १९२१-२३

नागपुर-काग्रेस का प्रभाव, मोपला-उत्पात, युवराज का बहिष्कार, समझौते का प्रयत्न, अहमदावाद-काग्रेस १९२१, सर्वदल-

गिरफ्तारी का व्यापक प्रभाव, कार्य-सिमिति की बैठक, वडाला पर धावा, दमन का दौर-दौरा, कार्य-सिमिति-द्वारा प्रोत्साहन, ब्रेसफोर्ड का वक्तव्य, पेशावर की घटना, बम्बई में लाठी चार्ज, विभिन्न प्रान्तों में दमन, समझौते के असफल प्रयत्न, गोलमेज-परिपद् और रियाअती प्रस्ताव।

१४. गाधी-अविन-समझौता : १९३१

मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास, दमन का दौर-दोरा, वाइसराय से भेट, आशाजनक परिस्थिति, समझौता और उसकी विज्ञिष्ति, गाधीजी का वक्तव्य, पत्रकारों से भेट, काग्रेस की हिदायते, कराची-काग्रेस १९३१, गणेशशकर की हत्या, अन्य प्रस्ताव, मोलिक अधिकार का प्रस्ताव, सर्वसाधारण के अधिकार, श्रमिक वर्ग के अधिकार, कर और व्यय, आर्थिक और सामाजिक कार्य-क्रम, कार्यसमिति की बैठक, समझौते का प्रभाव और नये वाइ-सराय, कार्य-समिति की बैठक, गाधीजी की चेतावनी, जगह-जगह सिध-भग, जाच का प्रस्ताव, परिषद् से गाधीजी का इन्कार, कार्य-समिति तथा महासमिति के निश्चय, परिषद् में न जाने के कारण, लन्दन के लिए प्रस्थान, यात्रां में गाधीजी, लन्दन में गाधीजी, परिषद् में गाधीजी, वारडोली में अशात वातावरण और अन्य प्रान्तों की स्थित।

१५. काग्रेस पर महान सकट: १९३२-३५

गाधीजी वम्वई में, कार्य-समिति का प्रस्ताव, वाइसराय का उत्तर, गाधीजी का उत्तर, बन्थल का गश्ती-पत्र, दमन-चक्र और गाधीजी की गिरपतारी, आर्डीनेन्सो का राज, कार्य-समिति की तत्परता, दिल्ली-काग्रेस १९३२, गाधीजी का उपवास, पूना-पैक्ट और उपवास का अन्त, हरिजन-आन्दोलन, कलकत्ता-काग्रेस १९३३, गाधीजी का उपवास, सत्याग्रह स्थिगत, पूना-परिषद्, व्यक्तिगत-सत्याग्रह, साबरमती आश्रम का दान, गाधीजीकी गिरपतारी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की सफलता, गाधीजी की रिहाई, हरिजन-आन्दोलन, बिहार का भूकप, जवाहरलाल की रिहाई, हरिजन-आन्दोलन, बिहार का भूकप, जवाहरलाल की गिरपतारी, कौसिल-प्रवेश का प्रोग्राम, महासमिति की वैठक, कार्य-समिति के निश्चय, सरदार पटेल की रिहाई, मालवीयजी और अणे के त्याग-पत्र, अव्दुल गफ्फार खा की रिहाई,

कार्य-समिति की वैठक, गाबीजी और काग्रेस, वुम्बई-काग्रेस:- १९३४, असेम्बली का चुनाव, असेम्बली में कार्य, कार्य-समिति की पहली वैठक, कार्य-समिति की दूसरी बैठक, साम्प्रदायिक समझौते के लिए प्रयत्न, सरकार की दमन-नीति, महासमिति की वैठक, क्वेटा-भूकप, पद-ग्रहण का प्रवन, देशी राज्य-प्रजा-परिपद् और काग्रेस और कार्य-समिति की वैठक। २४९-२९०

१६. पद-ग्रहण और त्याग-पत्रः १९३५-३९

हमारी स्थिति, लखनऊ-काग्रेस १९३६, मुख्य घटनाएँ, दमन-चक, कार्य और सेवाएँ, अनुशासन का अभाव, अन्तरिष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव, फेजपुर-काग्रेस १९३७, अनुजास्त के नियम्, चुनाव में काग्रेस की विजय, गपथ की समस्या, काग्रेस की निर्दे-गॅक नीति, राप्ट्रीय सम्मेलन, नए एक्ट का विरोध, पद-ग्रहण का प्रवन, कार्यकारिणी की बैठक, पद-ग्रहण जुलाई १९३७, गाधीजी-द्वारा स्पष्टीकरण, काग्रेस की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, काग्रेसी मित्रमंडल के कार्य, काग्रेस महासमिति के निर्णय, देश की स्थिति, हरिपुरा-काग्रेस : १९३८, कार्य-समिति के निञ्चय, प्रधानमत्रियों का सम्मेलन, केन्द्रीय सरकार की स्थिति, मजदूर कमेटी की बैठक, उद्योग-मित्रयों का सम्मेलन, रियासतों की म्मस्याएँ, अन्तरिष्ट्रीय सेवाएँ, मुसलिम लीग का रुख, राज-कोट की समस्या, सभापति का चुनाव, चुनाव का प्रभाव, त्रिपुरी-काग्रेम १९३९, मुभाष वाबू का त्यांग-पत्र, मुभाष वाबू का विरोधी रख, कार्य-समिति का निञ्चय, नेहरूजी की लका-यात्रा. खादी पहनने पर जोर, वम्वई में नगावन्दी आन्दोलन, जमनालाल बजाज की रिहाई, द्वितीय महायुद्ध और भारत, गाघीजी से भेट, कार्य-समिति की बैठक, गांघीजी का वक्तव्य, भारत-सरकार का रुख, गाधीजी का उत्तर, नेहरूजी का उत्तर, पजा-परिषद् का वनतव्य, वाइसराय का वनतव्य और मत्रि-मडलो के इस्तीके। 282-280

१७. इस्तीफा देने के बाद: १९४०

वाडमराय ना वनतन्य, महात्मा गाधी का उत्तर, राष्ट्र के प्रतिनिधिया की वंठक, नार्य-समिति का रुख, स्टेफर्ड की वर्धा-यापा, नार्य-समिति की बैठन, वाडमराय का वक्तन्य, वाइसराय की गावी से भेट, कार्य-सिमिति की बैठक, रामगढ-काग्रेस १९४०, राजेन्द्रबावू का अभिभाषण, मौलाना आजाद का भापण, गायीजी की चेतावनी, प्रतिक्रिया की भावना, काग्रेस विरोधी सम्मेलन, गावी-सेवा-सघ का अधिवेशन, लार्ड जेटलैण्ड का वक्तव्य, हमारी स्थिति, सम्प्राट का सन्देश, श्री एमरी का वक्तव्य, स्टैफर्ड किप्स के विचार, फास के पतन का प्रभाव, कार्य-सिमिति के निश्चय, मौलाना आजाद और जिन्ना साहब, महासमिति की बैठक, गाधीजी का काग्रेम से सवय-विच्छेद, वाइसराय का वक्तव्य, मौलाना आजाद और वाइसराय, गाधीजी के नेतृत्व की माग, महासमिति की बैठक और कार्य-सिमिति का निश्चय।

१८. सत्याग्रह और उसकी प्रगति : १९४०-४१

गाधीजी का पत्र, व्यक्तिगत-सत्याग्रह का आरभ, नरम दल-सम्मेलन, हिंदू-मुस्लिम समस्या, श्री एमरी का भाषण, गाधीजी का वक्तव्य, शासन-परिषद् का विस्तार, विस्तार के प्रति प्रति-किया, श्री चिंचल का वक्तव्य, सत्याग्रह आन्दोलन की वर्षगाठ, विभिन्न दलों के मत, जेल से रिहाइयाँ, गाधीजी का वक्तव्य, नेहरूजी का सदेश, गाधीजी का वक्तव्य, कार्य-समिति की वैठक, वारदोली-प्रस्ताव का प्रभाव, चागकाई शेक का स्वागत, मार्शल चाग का सदेश, गाधीजी से भेट, सन्देश का प्रभाव और सेठ जमनालाल की मृत्यु।

१९ खुला विद्रोह १९४२

किप्स मिशन, प्रधानमत्री का वक्तव्य, किप्स का प्रस्ताव, किप्स की नेताओं से भेट, किप्स-योजना का अन्त, लार्ड हेलीफेक्स का भाषण, किप्स का विरोधी रुख, किप्स की वापसी, विफलता के कारण, सामूहिक आन्दोलन का निश्चय, श्री राजगोपालाचार्य का स्तीफा, कार्य-समिति का प्रस्ताव, महासमिति का प्रस्ताव, गाधीजी का भाषण, गाधीजी की हिदायते, नेताओं की गिर-प्तारी, गाधीजी का वक्तव्य, श्री एडगर स्नो का मत, सरकार का दमन-चक्र, पकल की गश्ती चिट्ठी, काग्रेस पर दोषारोपण, दमन-चक्र का प्रभाव, खुला विद्रोह, सी० पी० रामस्वामी का

स्तीका, महादेव देसाई की मृत्यु, अमरीका में प्रतिक्रिया, प्रशस्ति सम्मेलन में प्रतिक्रिया, चीन में प्रतिक्रिया, दक्षिण अफ्रीका में प्रतिक्रिया, ब्रिटेन में प्रतिक्रिया, काग्रेस-विरोधी-पुस्तिका, पार्लमेट में विचार, लार्ड-सभा में विचार, भारत-सरकार की प्रतिक्रिया, गैरसरकारी प्रतिक्रिया, मुस्लिम नेताओं की प्रति-क्रिया, हिन्दू-सभा की प्रतिक्रिया और भारतीय ईसाइयों की प्रतिक्रिया।

२०. उपवास और उसके बाद: १९४३

उपवास का आरभ, उपवास की प्रगति, इग्लैण्ड म उपवास की प्रतिक्रिया, अमरीका में उपवास की प्रतिक्रिया, भारत में उपवास की प्रतिक्रिया, निर्दलीय नेताओं का प्रयत्न विफल, राजाजी और पाकिस्तान, जिन्ना साहव का मत, गांधीजी के पत्र पर रोक, भारत में प्रतिक्रिया, इग्लैण्ड में प्रतिक्रिया, मित्रमंडलों की स्थिति, लार्ड वेवल की नियुक्ति, देश की स्थिति, गांधीजी की गिरफ्तारी की वर्षगार्ठ, प्रशान्त सम्मेलन और भारत, लार्ड वेवल का रुख, मजदूर दल का रुख, और लार्ड लिनलिथगों का कार्य-काल।

२१. अगला कदम: १९४४

वेवल का व्यक्तित्व, एमरी का वक्तव्य, वेवल की किठनाइयाँ, वेवल का कार्य, मुस्लिम लीग की स्थिति, एमरी से स्तीफा देने की माग, वेवल का भाषण, ब्रिटिंग राजनीतिज्ञों का विरोधी रुख, स्वाधीनता-दिवस १९४४, गितरोध दूर करने की लालसा, जिन्ना साहव का मत, जिन्ना साहब के मत की आलोचना, सह-योग की भावना, गांधीजी की रिहाई की माग, गांधीजी की रिहाई, रिहाई के बाद, गांधीजी का वक्तव्य और गांधी-जिन्ना-वार्ता। ५०६-५२९

२२. स्वतंत्रता की और: १९४५

नेताओं की रिहार्ड की माग, भूलाभाई-लियाकत अली-समझोता, वेवल की लदन-यात्रा, एमरी का वक्तव्य, वेवल-योजना, शिमला-सम्मेलन, वेवल का भाषण, एटली का भाषण, काग्रेस-कमेटी का मत, भारत-मत्री का मत, चुनाव की तैयारी और आजाद हिन्द फौज । ५२९-५३

२३. पराधीनता के वधन दूदे: १९४६-४७

फिलिप्स की रिपोर्ट, नवाब भूपाल की घोषणा, वेवल का भाषण, सरकारी विजिप्त, मित्र-मिगन की नियुक्ति, मित्र-मिगन का आगमन और कार्य, काग्रेस का मत, राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, काग्रेस की आपित्तियाँ, वाइसराय की हठवर्मी, मित्र-मिगन का कार्य, कार्य-सिमिति की वैठक, लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई, गाबीजी की नोआखाली-यात्रा, अतिरम सरकार की स्थापना, मेरठ-काग्रेस १९४६, लीग का मत, प्रतिनिधियों की लदन-यात्रा, वक्तव्य का उद्देश, काग्रेस का मत, पैथिक लारेस का वक्तव्य, कार्य-सिमिति का वक्तव्य, काग्रेस कमेटी का निर्णय, लीग का निर्णय, एटली का वक्तव्य, वक्तव्य की आलोचना, अगडे और रक्तपात, गाधीजी का वक्तव्य, पजाब और बगाल का विभाजन, भारत छोडने की तैयारी, काग्रेस-सिमिति की वेठक और कृपलानीजी का भाषण।

480-408

संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास



संचित्र संस्करण कांग्रेस का इतिहास

: ?:

कांग्रेस का जन्म : १८८५

काग्रेस का इतिहास हिन्दुस्तान की आजादी की लडाई का इतिहास है। कई सिदयों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ था। उन दिनों वह जिस गुलामी में फसा हुआ था उसका आरम्भ भारतवर्ष में एक व्यापारी कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ था और उस गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० वर्षों में काग्रेस ने पूर्ण प्रयत्न किया था।

१=५७ से पहले की स्थिति

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौरदौरा भारत में कोई सौ वर्षों तक रहा। इसी बीच उसने भारत के बड़े-बड़े भागो पर अपना कब्जा कर लिया और व्यापारी की जगह वह एक राज-शक्ति बन गई। १७७२ के वाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट समय-समय पर उसके कामो की जाच-पडताल करने लगी और उसको नया अधिकार-पत्र दिया जाने लगा। नया अधिकार-पत्र देने के पहले जब-जब जाच-पडताल की गई, तब-तब उसके फलस्वरूप दूरगामी परिणाम लानेवाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तो का निरूपण तो अवश्य किया जाता था, परन्तु वे सिर्फ कागज पर ही लिखे रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाको की सीमा वढाने की कोशिश न करे, परन्तु हर बार कोई-न-कोई ऐसा मौका निकाल लिया जाता था जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा वढती ही चली जाती थी। इस प्रकार उन्होने अपने छल-कपट से अटूट धन-सम्पत्ति प्राप्त कर ली थी, जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूजी का काम दिया और जिसके बल पर इग्लैण्ड स्टीम-एजिन चलाने तथा १६ वी सदी में दुनिया में अपना औद्योगिक प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो सका।

१७७४ में रेग्युलेटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स

(संचालक-सभा) के ऊपर वोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौसिल सिहत एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। तब गोया ब्रिटिंग पार्लमेण्ट ने पहले-पहल भारतीय क्षेत्रों के शासन की कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। घीरे-घीरे यह नियन्त्रण बढता गया और १७=५ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७६३, १८३३ और १८५३ में जाच करने के बाद नये चार्ट दिए गये। १८३३ में एक नया कानून बनाया गया। इस कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उठा दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासकसत्ता के रूप में सामने आ गई।

इसी समय भारत में अग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उठ खडी हुई। भारतीयों में राजा राममोहन राय और अग्रेजों में मेकाले अग्रेजी शिक्षा देने के जबर्दस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य के स्थान पर अग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धित की नीव पड़ी जो भारत में आजतक प्रचलित है।

उन दिनो अग्रेजो-द्वारा चलाये समाचार-पत्रो के अतिरिक्त देशी समाचार-पत्र न थे। इनमें भी बाज-बाज पत्रकारों को देश-निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेण्टिक की नीति समाचार-पत्रों के प्रति नरम थी। उनके उत्तराधिकारी सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भी समाचार-पत्रों पर से पावन्दिया उठा ली थी। फिर, १८५७ के पश्चात् लॉर्ड लिटन के वाइसराय होने तक समाचार-पत्र इसी खतरे में रहे। १८३३ और ५३ के बीच पजाब और सिंघ जीत लिए गये। लॉर्ड डलहीजी

की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बढा दिया। लॉर्ड डलहौजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासते भी जब्त कर ली। इसके सिवा आर्थिक शोपण भी जारी था, जिससे लोग कगाल होते जा रहे थे। यह बात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कुढ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी शासन के जुए को फेक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्न किया। इससे यह प्रतीत होता है कि यह आन्दोलन १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सौ वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाए घटती रही, उनके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं, बल्कि वह प्रत्येक देश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृतिक अभिलाषा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगो-द्वारा शासित हो, दूसरो-द्वारा हिंगज नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि आन्दोलन बेकार गया, परन्तु उसके साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी तिरोहित हो गई और भारत सरकार का शासन-सूत्र सीचा ब्रिटिश पार्लमेंट के

हायों में आगया। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा प्रकाशित

की, जिनसे याति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ और लोग यह समझने नग गये कि भारत में अग्रेजी राज्य ईस्वर की एक देन है।

श्रशान्ति श्रौर मि० ह्यूम की जिन्ता

मिटिश पार्लमेंट के हाथ में सासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार की गित-विधि पहले ही की तरह जारी रही। १८३३ के कानून के अनुसार, भारत-वामी उन तमाम जगहो पर लेने के योग्य करार दिए गये जिनके लिए वे उपयुक्त ममले जात थे। १८५२ में, जब चार्टर विचाराधीन था, पार्लमेट में यह बात गूने आम कही जाती थी कि १८३३ के कानून ने यद्यपि भारतवासियों को नौकरिया देने का रास्ता खोल दिया है, फिर भी उनको अभी तक वे जगहें नहीं दी गई है जो उन कानून के पहले उन्हें दी जा सकती थी। जब १८५३ में तिबिल सर्विस के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा जारी की गई थी तब इस बात की ओर व्यान दिलाया गया था कि इमने भारतीयों के रास्ते में बड़ी रुकाबटे पेश आएगी, क्योंकि उनके लिए उन्नें जाकर अग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में बाजी मार ले जाना अनमय होगा और वह भी उन नौकरियों के लिए जो आम तीर पर नहन टुर्लम थी। परन्तु इस बाधा के रहते हुए भी कुछ भारतीय समुद्र पार गय और उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी बीच लॉर्ड सेल्सबरी ने परीक्षा में बेटने की उन दाम कर दी। इसमें भारतीयों को लेने के देने पड़ गये। क्योंकि उपर वह अग्रेजों की नहायता ने भारत और इन्लंड के साथ-साथ परीक्षा ली जाने उपर वह अग्रेजों की नहायता ने भारत और इन्लंड के साथ-साथ परीक्षा ली जाने उपर वह अग्रेजों की नहायता ने भारत और इन्लंड के साथ-साथ परीक्षा ली जाने

में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि॰ ह्यूम को ठीक मौके पर सझी और उन्होने इस काम में हाथ डाला।"

मि० ह्यम के पास राजनैतिक अशान्ति का अकाटच प्रमाण था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टो की ७ जिल्दे लगी थी, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर वगावत के भाव फैलने का वर्णन था। ये रिपोर्टे जिला, तहसील और सब-डिवीजन के अनुसार तैयार की गई थी और शहर, कस्बे और गाव भी उनमें शामिल थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सुसगठित विद्रोह जल्दी होनेवाला था, विलक यह कि लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर गुजरना चाहते थे।

कांग्रेस का जन्म

उक्त परिस्थियो पर विचार करने के पश्चात् ह्यूम साहव ने इस अशान्ति को प्रकृट करने का एक सरल उपाय ढूढ़ निकाला। उनके दिमाग में यह स्थाल आया कि भारतीयों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय। इस विचार से उन्होंने १ मार्च १८८३ ई० को कलकता-विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटो के नाम एक ऐसा पत्र लिखा, जो अत्यन्त मार्मिक था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदिमियों की माग की जो भले, सच्चे, नि स्वार्थ, आत्म-सयमी तथा नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हित करने की तीन्न भावना रखनेवाले हो। उनका अनुमान था कि यदि सिर्फ ५० भले और सच्चे आदमी सस्थापक के रूप में मिल जाय तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है। इन लोगों के आदर्श के सबध में उनका विचार था कि सभा का विधान जनसत्तात्मक हो, सभा के लोग व्यक्तिगत महत्वाकाक्षा से परे हो और उनका यह सिद्धान्त हो, कि जो सबसे वडा हो वही सेवक हो। अपने पत्र में उन्होने गोल-मोल वाते नहीं की; विल्क साफ शब्दों में कह दिया कि यदि आप अपना सुख-चैन नहीं छोड सकते तो कम-से-कम फिलहाल हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है और यह कहना होगा कि भारत सचमुच वर्तमान सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है। इस स्मरणीय पत्र का अन्तिम भाग इस प्रकार था —

"जो मनुष्य होते हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिये, इसिलए अब से आप इस वात की शिकायत न की जिएगा कि बड़े-बड़े ओहदो पर आपकी विनस्वत अग्रेजो को क्यो तरजीह दी जाती है, क्यों कि आप में वह सार्वजिनक सेवा का भाव नहीं है, वह उच्च प्रकार की परोपकार-भावना नहीं है, जो सार्वजिनक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशोआराम को छोटा बना देती है, वह देशभिक्त का भाव नहीं है जिसने अग्रेजों को वैसा बना दिया है जैसे कि वे आज है। और मैं कहूगा कि वे ठीक ही आपकी जगह तरजीह पाते हैं और उनका लाजिमी तौर पर आपका शासक वन जाना भी ठीक है, विल्क वे आगे भी आपके अफसर बने

कांग्रेस का जन्म : १८८४

रहेगे, और आपके कन्धो पर रक्खा यह जुआ तबतक दुखदायी होगा जबतक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं कर लेते और इसके अनुसार चलने की तैयारी नहीं कर लेते कि आत्म-बलिदान और नि स्वार्थ सेवा ही सुख और स्वातन्त्र्य के अचूक पथ-प्रदर्शक है।"

पूर्व-प्रयत्न और संस्थाएँ

काग्रेस के जन्म से संबध रखनेवाली ब्योरेवार बातो का वर्णन करने के पहले यदि हम काग्रेस-काल के पहले के उन सस्थाओं का नाम-स्मरण कर ले तो अनुचित नही होगा, जिनके किया-कलाप ने एक तरह से देश में सार्वजनिक जीवन की वुनियाद डाली है। सबसे पहले बगाल के ब्रिटिश इण्डियन एसोशियेशन का नाम आता है। १८५१ में उसकी स्थापना की गई थी और यह वह सस्था थी जिसके नाम की छाया में डा० राजेन्द्रलाल मित्र और रामगोपाल घोप जैसे व्यक्ति वीसो साल तक काम करते रहे थे। यह एसोशियशन खुद भी कोई पचास साल तक देश मे एक सजीव शक्ति बना रहा। इसके पश्चात् बम्बई में सार्वजनिक कार्य की संस्था बाम्बे एसोशियशन थी। वृगाल के एसोशियशन के मुकाबिले में उसने थोड़े समय तक ही जोर-शोर से कार्य किया। उसके नेता सर मंगलदास नाथूभाई और श्री नौरोजी फरूदजी थे। दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शकर शेठ ने उसकी स्थापना की थी; परन्तु बाद में ईस्ट इण्डिया एसोशियेशन ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था। मद्रास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत हिन्दू के द्वारा हुई, जिसके सस्थापको मे एम० वीर राघवाचार्य, माननीय रगैया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और एन० सुब्बाराव पन्तुलु जैसे गण्य-मान पुरुष थे। महाराप्ट्र में पूना की सार्वजनिक सभा का जन्म प्राये उसी समय हुआ जब कि हिन्दू का हुआ था और उसके द्वारा रायबहादूर नुकलर और श्री चिपलुणकर जैसे प्रसिद्ध पुरुष सार्वजनिक कार्य करते थे।

वगाल में, १८७६ में इण्डियन एसोशियेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुरेन्द्र नाथ बनर्जी थे और जिसके पहले मत्री थे आनन्दमोहन वसु। यह घ्यान में रखना होगा कि इस काग्रेस-पूर्व-काल में भी यद्यपि सार्वजनिक जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया था तथापि उसका असर अधिकारियो पर होने लगा था। समाचार-पत्र उस जीवन का एक प्रभावशाली अग था। १८५७ में लग-भग ४७५ समाचार-पत्र थे, जिनमें से अधिकाश प्रान्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्ही दिनो देश के सुदैव से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस से मुक्त होकर उत्तरी भारत के पजाव और उत्तर प्रदेश में राजनैतिक यात्रा की। वह १८७७ के प्रसिद्ध दिल्ली-दरवार में भी सम्मिलित हुए थे और वहा देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य लोगों से मिले थे। यह माना जाता है कि उसी दरबार में देश के राजा-महाराजाओ और गण्य-मान्य लोगों को एक जगह एकत्र

देखकर ही पहले-पहल सुरेन्द्रनाथ वनर्जी के मन में यह प्रेरणा उठी थी कि एक देश-व्यापी राजनैतिक सगठन वनाया जाय। १८७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वम्बई और मद्रास प्रान्त की यात्रा की जिसका उद्देश यह था कि लॉर्ड सेल्सवरी ने सिविल सर्विस की परीक्षा की उम्र घटाकर जो १६ साल कर दी थी, उसके खिलाफ लोकमत जाग्रत किया जाय और इस विषय पर कामन-सभा में पेश करने

के लिए सारे देश की तरफ से एक मेमोरियल तैयार किया जाय। इसी समय लार्ड लिटन के प्रतिगामी ज्ञासन का बीजारोपण हुआ। उनके जमाने में (१८७८) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ, वडा खर्चीला दरवार किया गया और १८७७ में ही कपास-आयात-कर उठा दिया गया। लार्ड लिटन के बाद लार्ड रिपन का समय आया। उन्होने अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह की, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रह किया, स्थानीय स्वराज्य का आरभ किया और इलवर्ट विल उपस्थित करके एक नये युग का श्रीगणेश किया। यह आखिरी बिल भारत सरकार के तत्कालीन लॉ मम्बर मि० इलबर्ट ने १८८३ में उपस्थित किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटो पर से वह रकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपरावियो के मुकदमे फैमल नही कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने बिगडे कि कुछ लोगों ने तो गवर्नमेट हाउस के मित्रयों को मिलाकर वाइसराय को जहाज-द्वारा इग्लैंड भेजने की एक साजिश ही कर डाली। नतीजा यह हुआ कि असली विल उसी साल करीब-करीव हटा लिया गया और उसकी जगह यह सिद्धान्त भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रेट और दौरा जज को ही ऐसा अधिकार रहेगा। इस विल के सवध में गोरे लोगो को जो सफलता मिल गई उससे भारतीय जाग उठे। उन्होने शीघ्र ही इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान लिया। गोरे यह मनवाना चाहते थे कि भारत पर गोरी जातियों का प्रभुत्व है और वह सदा रहेगा। उनके इस विचार ने भारत के तत्कालीन देश-सेवको को सगठन के महत्व का पाठ पढाया और उन्होने तुरन्त ही १८८३ में कलकत्ता के अलबर्ट-हाल में एक राजनैतिक परिपद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनन्दमोहन वसु दोनो उपस्थित थे। इस सभा मे सुरेद्रनाथ बनर्जी ने अपने भाषण में खासतौर पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्ली दरबार ने उनके सामने एक राजनैतिक सस्था, जो भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमूना पेश किया था। इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् हुई जिससे अखिल भारतीय काग्रेस स्थापित करने

की प्रेरणा मिली । १८८१ में मद्रास-महाजन सभा की स्थापना हुई और मद्रास प्रातीय परिषद् का अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत मे ३१ जनवरी, १८८४ को महता, तैलंग और तैयबजी की मशहूर मण्डली ने मिलकर बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसियेशन कायम किया।

पूर्वोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि भारतवर्ण मन-ही-मन किसी अिखल-भारतीय सगठन की आवश्यकता का अनुभव कर रहा था। यह तो अभी तक एक रहस्य ही है कि अिखल-भारतीय काग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मिस्तष्क से निकंली ? १८७७ के दरवार या कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अित-रिक्त थियोसोफिकल कनवेन्शन का भी नाम इस विषय में लिया जाता है जो दिसम्बर १८८४ में मद्रास में हुआ था। वहा १७ आदिमयों की एक खानगी सभा हुई जिसमें यह वात सोची गई। मि० एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने सिविल सिवस से अवसर प्राप्त करने के बाद जो इिण्डयन यूनियन कायम का थी, वह भी काग्रेस के जन्म का एक निमित्त बतलाई जाती है। जो भी हो, मि० ए० ओ० ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदम बढाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सम्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि अगले दिसम्बर में, पूना में इिण्डयन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अब तक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण में पख फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गित दे रही थी उसने अब एक निश्चत रूप धारण कर लिया और वह एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने आ गया।

कांग्रेस का प्रारंभिक लक्ष्य

काग्रेस के जन्म के कारणों में केवल उवत राजनैतिक शिक्तयाँ और राजनैतिक गुलामी का भाव ही नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि काग्रेस का एक राजनैतिक उद्देश्य था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली सस्था भी थी। काग्रेस के जन्म से पहले, ४० या इससे भी ज्यादा वर्षों से, भारत में राष्ट्रीय नवयौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन राजा राममोहन राय के समय से विविध रूपों में परिपक्व हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता का पैगम्बर और आधुनिक भारत का पिता कह सकते हैं। उनका जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १६३३ में हुई। भारत के दो वं सुधारों के साथ उनका नाम जुडा है—एक तो सती या सहगमन-प्रथा का मिटाया जाना और दूसरा भारत में पिश्चमी-शिक्षा का प्रचार। लार्ड विलियम वेण्टिक ने, १६३५ में पिश्चमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया था उसका बहुत बडा कारण यह था कि राजा राममोहन राय खुद पश्चिमी शिक्षा के अनुरागी और पक्षपाती थे। अपने जीवन के अन्तिम

समय में वह इंग्लैंड गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रवल था कि जब वह 'केप ऑफ गुड होप' पहुँचे तब उन्होने फ्रासीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिस पर स्वाधीनता का झण्डा फहरा रहा था। वह चाहते थे कि उस झण्डे का अभिवादन करें और ज्यो ही उन्हें उस झड़े के दर्शन हुए, उनके मुह से झड़े की जय-ध्विन निकल पड़ी। यद्यपि वह इंग्लैंण्ड में मुख्यत मुगल-सम्राट् के राज-दूत वन कर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की समिति के सामने भारतवासियों के कुछ जरूरी कष्ट भी पेश किये थे। १८३२ में जव चार्टर एक्ट पार्लमेट में पेश था तव उन्होने यह प्रण किया था कि यदि यह विल पास न हुआ तो मै ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड दूगा और अमरीका जाकर वस जाऊगा। अपने समय में ही उन्होने अखबारो पर और छापेखानो पर हुआ वहुत बुरा दमन देख लिया था और सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया था। उन्होने दो वकील अपनी ओर से उसमें खड़े किए थे और जब वहा उन्हें कामयावी नहीं हुई तव उन्होंने इंग्लैण्ड के वादगाह के नाम एक सार्वजनिक दरखास्त भेजी थी। इसमे शक नही उस समय उससे भी कुछ मतलव न निकला, लेकिन जो बीज वह बो चुके थे उसका फल १८३५ में निकला, जब सर० चार्ल्स मेट्कॉफ ने हिन्दुस्तानी पत्रो को आजाद कर दिया।

प्रथम राष्ट्रीय कान्ति के वाद १८५८ म, विश्वविद्यालय कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौसिले भारत मे वनाई गई। इसके कुछ पहले ही विधवा-विवाह कानून वना था। यह समाज-सुधार की दिशा मे एक कदम् था। इसके वाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क वढता गया। पश्चिमी कानून-सस्थाएँ और पार्लमेटरी तरीके दाखिल हुए जिससे कानून और कौसिलों के क्षेत्र में एक नये युग का जन्म हुआ। राजा राममोहन राय के समय में धार्मिक सुधार के जो बीज बोये गये थे वे थोड़े ही समय मे अपनी शाखा-प्रशाखाएँ फैलाने लगे। उनके वाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिम्मेदारी आ पड़ी। उन्होने दूर-दूर तक ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया और उसके मतो पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होने मद्यपान-निषेध के आन्दोलन को हाथ में लिया। १८७२ के 'ब्रह्म मैरेज एक्ट-३' को पास कराने में उनका वहुत हाथ था। इस कानून के द्वारा वाल-विवाह मिट गया, वहु-विवाह को अपराध करार दिया गया और विधवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह की छूट मिल गई। परन्तु कुछ ही समय मे ब्रह्म समाज मे मत-भेद फैल गया। इसका मुख्य कारण था केशवचन्द्र सेन की कन्या का वाल्यावस्था में कूचिवहार के महाराज के साथ विवाह । इसपर उनके साथियो ने वहुत विरोध किया, जिसका फल यह हुआ कि आनन्दमोहन वसु के नेतृत्व मे 'साघारण ब्रह्म समाज' के नाम से ब्रह्म-समाज की एक नई शाखा बन गई।

कांग्रेस का जन्म : १८८५

यहा यह याद रखना चाहिए कि यही आनन्दमोहन वसु आगे चलकर १६६५ में काग्रेस के सभापति हुए थे।

वंगाल के ब्रह्म-समाज का प्रभाव सारे भारत पर पडा। पूना मे प्रार्थना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह आन्दोलन शुरू हुआ। यही रानडे समाज-मुधार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षी तक काग्रेस का एक अग वनकर चलता रहा। इस सुधार-आन्दोलन में भूतकाल के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा और प्राचीन परम्पराओं और विषयों के प्रति बगावत के भाव भर हुए थे और इसका कारण था पश्चिमी सस्थाओं का जादू एवं उनके साथ चिपकी हुई राजनैतिक प्रतिष्ठा । इसकी प्रतिकिया के रूप मे उत्तर-पश्चिम मे आर्य-समाज और मद्रास में थियोसोफिकल आन्दोलनो ने अपने धर्म, आदर्श और सस्कृति से दूर ले जानेवाली पश्चिमी-शिक्षा-द्वारा उत्पन्न प्रभाव को दवा दिया। यो तो ये दोनो आन्दोलन उत्कट रूप मे राष्ट्रीय थे, फिर भी आर्य-समाज मे देशभित्त के भाव बहुत प्रवल थे। आर्य-समाज वेदो की अपौरुपेयता और वैदिक-सस्कृति की श्रेष्टता का जबरदस्त हामी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस प्रकार राष्ट्र में एक तेजस्वी मनुष्यत्व का विकास हुआ, जो हमारी पूर्व परम्परा और आधुनिक वातावरण दोनों के श्रेण्ठत्व का सामजस्य था। जिस तरह प्रह्म-समाज ने बहुदेववाद, मूर्ति-पूजा और वहु-विवाह के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसी तरह आर्य-समाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ प्रचलित वुराइयो और हिन्दुओ के धार्मिक अन्धविञ्वामों से लड़ाई ठानी। यहाँ भी, जैसा कि भय था, आर्य-समाज में दो दत खड़े हुए-एक गुरुकुल-पन्थी और दूसरा कालेज-पन्थी। गुरकुल-पन्थी ब्रह्मचर्य और धार्मिक सेवा के वैदिक आदर्गों को मानते थे, और कालेज-पथी ाधुनिक ढग की शिक्षा-सस्याओ-द्वारा एक हद तक पश्चिमी सम्यताका सचार करके मगाज में नवजीवन टालना चाहते थे। एक के प्रवर्त्तक थे अमर शहीद स्वामी श्रद्धा-नन्द जी, और दूसरे के ये देश-वीर लाला लाजपतराय। थियोसोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विव्वव्यापी सहानुभूति और अध्ययन की विशंपता थी तो भी पूर्वीय सन्कृति में जो कुछ महान् आर गौरव-मय है उसके आविष्करण और पुनमञ्जीवन पर उसमे लास जोर दिया जाता था। इसी प्रवल भावना को लेकर श्रीमती वंसण्ट ने भारत के पुण्यधाम काशी में एक कालेज गुरू किया। इस तरह यियोसोफिकल प्रवित्तयों क होरा एक और जहां विश्ववन्धुत्व की भावना बढने ननी वहां दूसरी और परिचम के वृतिवाद की श्रेष्ठता का दौर-दौरा कम हुआ और उनकी जगह मन्तृति का एक नया केन्द्र स्थापित हुआ जहां फिर से इस प्राचीन सृमि मे पश्चिमी

विवेकानन्द उनके पट्ट-शिष्य थे, जिन्होने उनके उपदेशों का प्रचार पूर्व और पश्चिम दोनों जगह किया। रामकृष्ण-मिशन न तो कोरे योग-साधकों की और न केवल भौतिक-वादियों की सस्था है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक आदर्श रखनेवाली सस्था है जो लोक-सग्रह या समाज-सेवा के महान् कर्त्तव्य की उपेक्षा नहीं करती। उसने ससार के विभिन्न राष्ट्रों के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए कुजी का भी काम दिया है। ये तमाम हलचले, सच पूछिये तो भारत की राष्ट्रीयता के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूनों के समान है। भारत का यह कर्तव्य था कि इनमें एकसा सामजस्य पैदा करे जिससे पूर्व-दूषित विचार और अन्ध-विश्वास दूर होकर प्राचीन वेदान्त-मत की सशुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहा उठे और नवीन युग के राष्ट्र-धर्म से उसका मेल बैठ सके। काग्रेस का जन्म इसी महान् कार्य की पूर्ति के लिए हुआ था।

भारत श्रीर इंग्लैएड में प्रचार

उक्त परिस्थितियों में ही काग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में मि० ह्यूम का यह विचार था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन, बम्बई के प्रेसीडेन्सी एसो-सियेशन और मद्रास की महाजन-सभा जैसी प्रातीय सस्थाएँ राजनैतिक प्रश्नो को हाथ में ले और आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामाजिक प्रव्नो में ही हाथ डाले। उन्होने लार्ड डफरिन से इस विषय में सलाह ली, जो कि हाल ही में वाइसराय बनकर आये थे। वह १८५८ में लार्ड डफरिन से शिमला में मिले और उनसे सभापति होने की प्रार्थना की। लार्ड डफरिन ने उनकी बातो को घ्यान से सुना। उन्होने मि॰ ह्युम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, उपयोगी न होगों, क्योंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं है जो इग्लैण्ड की तरह यहा सरकार के विरोध का काम करे। इसलिए ऐसी दशा में यह अच्छा होगा और इसमें शासक और शासित दोनों का हित है कि यहां के राजनीतिज्ञ प्रति वर्ष अपना सम्मेलन किया करे और सरकार को बताया करें कि शासन मे क्या-क्या त्रुटिया है और उसमे क्या-क्या सुधार किये जाय। उन्होने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सभापति स्थानीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने सग्भव है, लोग अपने सही विचार प्रकट न करे। मि० ह्यूम को लार्ड डफरिन की यह दलील जची और जब उन्होंने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी जगहो के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्खा तब उन्होंने भी लार्ड डफरिन की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके अनुसार कार्रवाई भी शुरू कर दी। लार्ड डफरिन ने मि० ह्यूम से यह शर्त करा ली थी कि जबतक मैं इस देश में हूँ तवतक इस सलाह के वारे में मेरा नाम कही न लिया जाय। मि० ह्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया।

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि वडे दिनों की छुट्टियों में देश के सब भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गयी। इस बैठक के लिए एक गश्ती पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि २५ से ३१ दिसम्बर, १८८५ तक पूना में डण्डिन नेशनल यूनियन की एक परिपद् की जायगी। इसमें बगाल, बम्बई और मद्रास प्रदेशों के अंगरेजीदा प्रतिनिधि, अर्थात् राजनीतिज्ञ सम्मिलित होगे। इस परिषद के प्रत्यक्ष उद्देश होगे (१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष कोन-कौन से राजनैतिक कार्य अङ्गीकार किये जाय इसकी चर्चा करके निर्णय करना। अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिषद् एक देशी पार्लमेट का बीज-रूप बनेगी और यदि इसका कार्य सुचार-रूप से चलता रहा तो थोडे ही दिनों में इस आक्षेप का मुहतोड जवाब होगा कि हिन्दुस्तान प्रतिनिधि-शासन-सस्थाओं के बिल्कुल अयोग्य है।

इस तरह अपने को वाइसराय के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ह्यूम साहब इज्जलैण्ड पहुचे और उन्होंने वहा लार्ड रिपन, लार्ड डलहाजी, सर जेम्स कअर्ड, जॉन वाइट, मि० रीड, मि० स्वेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से विचार-विनिमय किया। उनकी सलाह से उन्होंने वहा एक सगठन किया जो आगे चलकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पार्लमेंटरी कमेटी के रूप में परिणत हो गया। इसका उद्देश्य था पार्लमेण्ट के उम्मी-दधारों से यह प्रतिज्ञा करवाना कि वे भारत के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने वहा एक डण्डियन टेलीग्राफ यूनियन भी वनाई। इसका उद्देश्य था इंग्लैण्ड के प्रधान-प्रधान प्रान्तीय पत्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए धन सग्रह करना।

कांग्रेस का प्रथम ऋधिवेशन : १८८५

काग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अत्यन्त रोचक वर्णन श्रीमती वेसेण्ट ने अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फीडम' नामक पुस्तक में किया है। वह लिखती है '— ''लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ, क्योंकि वड़े दिन के पहले ही वहा हैजा गुरू हो गया ओर यह ठीक समझा गया कि परिपद्, जिमें अब काग्रेस कहते हैं, वम्बर्ड में की जाय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज ओर छात्रालय के व्यवस्थापकों ने अपने विशाल भवन काग्रेस के हवाले कर दिय और २७ दिसम्बर की सुबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का स्वागत करने की यूरी तैयारी हो गई। २५ दिसम्बर, १८८५ को दिन के १२ वजे गोकुलदास तेजपाल गस्कृत कालेज के भवन में काग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आवाज मुनार पठी खूम साहब की, माननीय एस० सुद्धण्य ऐयर को और माननीय कामोनाथ व्यव्यक तैलग को। ह्यूम साहब ने श्री उमेश वनर्जी के सभापतित्व

का प्रस्ताव उपस्थित किया और शेष दोनो सज्जनो ने उसका समर्थन और अनुमोदन किया। वह एक अत्यन्त गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि-द्वारा सम्मानित अनेक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष का स्थान ग्रहण किया था। काग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अध्यक्ष महोदय ने काग्रेस का उद्देश्य इस तरह वतलाया —

- (क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश-हित के लिए लगन से काम करनेवालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढाना।
- (ख) समस्त देश-प्रेमियो के ह्रदय से प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार द्वारा वश, धर्म और प्रान्त सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्व-दूषित सस्कारो को मिटाना और राष्ट्रीय एक्य की समस्त भावनाओं का पोषण और परिवर्धन करना।
- (ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नो पर भारत के शिक्षित लोगो में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद परिपक्व सम्मतिया प्राप्त हो उनका प्रामाणिक सग्रह करना।
- (घ) उन तरीको और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करे।

इस प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास हुए, जिनके द्वारा भारत की मागो के वनने की शुरूआत हुई। पहले प्रस्ताव-द्वारा भारत के शासन-कार्य की जाच के लिए एक रायल-कमीशन वैठाने की माग की गई । दूसरे के द्वारा इण्डिया कौन्सिल को तोड देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव-द्वारा घारा-सभा की त्रुटिया दिखाई गई, जिनमे अवतक नामजद सदस्य थे और उनके बजाय चुने हुए रखने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देने की, उत्तर प्रदेश और पजाब मे कौसिल कायम की जाने की और कामन-सभा मे स्थायी समिति कायम करने की माग की गई—इस आशय से कि कौसिलो में वहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमे विचार किया जाय। चौथे प्रस्तावद्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैण्ड ओर भारत में एकसाथ हो और परीक्षार्थियों की उम्र वढा दी जाय। पाचवा और छठा फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता था और सातवे मे अपर वर्मा को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलित कर लेने की तजवीज का विरोध किया गया था। आठवे प्रस्ताव द्वारा यह आदेश दिया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओ को भेज दिये जाय । तदनुसार सारे दश मे तमाम राजनैतिक मण्डलो और सार्वजनिक सभाओ द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली सशोधन के बाद वे बडे उत्साह से पास किये गये। अतिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता तय हुआ और ता०. २८ दिसम्बर नियत हुई।

कांग्रेस का दावा

जिस प्रकार एक वडी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार महान् रास्थाओं का आरभ भी वहुत मामूली होता है। जीवन की गुम्आत में व बडी तेजी से दौडती है, परन्तु ज्यो-ज्यो वे व्यापक होती जाती है, त्यो-त्यो उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यो-ज्यो वे आगे वढती है, त्यो-त्यो उनमे सहायक निदया मिलती जाती है और वे उसको अधिका-विक सम्पन्न बनाती जाती है। यही उदाहरण हमारी काग्रेस के विकास पर भी लागू होता है। उसे अपना रास्ता वडी-वडी वाघाओं सं तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रक्खे, परन्तु ज्यो ही उसे समस्त भारतवासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हलचलो का भी समा-वेश कर लिया। प्रारम्भिक अवस्थाओं में उसके कार्यों में एक किस्म की हिचकिचा-हट और शकाएँ-कुशकाये दिखाई देती थी, परन्तु जैसे-जैसे वह वालिग होती गई, वैसं-वैसे उसे अपने वल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि व्यापक वनती गई। अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मा-वलम्वन की नीति ग्रहण की । इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने लगे, जिससे देशव्यापी सगठन वन गया—यहा तक कि सीधे हमले तक का कार्य-क्रम बनाना पडा । शिकायतो और अपने दु ख-दर्दों को दूर कराने के उद्देश्य से शुरुआत करके काग्रेस देश की एक ऐसी मान्य संस्था के रूप मे परिणत हो गई जो वह स्वाभिमान के साथ अपनी माग भी पेश करने लगी। शीव्र ही वह भारतवासियों की तमाम राजनैतिक महत्वाकाक्षाओं की एक जबरदस्त और सत्तापुर्ण प्रतिपादक वन गई। उसका दरवाजा सब श्रेणियो और सब जातियो के लोगो के निए खोल दिया गया। यद्यपि आरभ में वह उन प्रश्नों को हाथ में लेती हुई मकोच करती थी जो सामाजिक यहे जाते थे, तथापि उचित नमय आते ही उनने उस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकडो मे दटा हुआ है और इस प्राचीन परम्परागत विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रक्नो को मोमाधिक और राजनैतिक मीमाओं ने बाध देता है, उसने एक ऐसा मर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रन्तुत किया, जिसमे कि सारा जीवन, यहाँ से वहां तक, एक भीर अविनाज्य है। इस नरह काग्रेस एक ऐसी राजनैतिक सस्या हो गई जिसमे दी थी उसमें उन्होंने काग्रेस के वारे में ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था —

"यदि मैं गलती नहीं करता हूँ तो काग्रेस भारतवर्ष की सबसे वडी सस्या है। उसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस असे में वह विना किसी रकावट के बराबर अपने वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, वर्ग या किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्वमान्य भारतीय हितो और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मरे लिए यह बताना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्टेवियन ह्यूम को काग्रेस के पिता के रूप में हम जानते है। दो महान पारसियो-फिरोजशाह मेहता और वादाभाई नौरोजी —ने जिन्हें सारा भारत 'वृद्ध पितामह' कहने में प्रसन्नता का अनुभव करता है, उसका पोषण किया है। आरम्भ से ही काग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे, विलक मुझे यो कहना चाहिये कि उसमें सब धर्म, सम्प्रदाय और हितो का थोडी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता है। मैं जानता हू कि कभी-कभी वह अपने इस दावे को कायम रखने में असफल भी हुई है, किन्तु में यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप काग्रेस का इतिहास देखे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साय सफल हुई है। सबसे अधिक काग्रेस मूलरूप में अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ७,००,००० गावो में विखरे हुए करोडो मूक, अर्द्ध-नग्न और भूखे प्राणियो की प्रतिनिधि है, यह बात गौण हैं कि वे लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा देशी राज्यों के। इसलिए काग्रेस के मत से प्रत्येक हित जो रक्षा के योग्य है, इन लाखो मूक-प्राणियो के हित का माधन होना चाहिए। हा, आप समय-समय पर इन विभिन्न हितो मे प्रत्यक्ष विरोध देखते है। पर्न्तु यदि वस्तुत. कोई वास्तविक विरोध हो तो काग्रेस की ओर से बिना किसी सकोच के यह वता देना चाहता हू कि इन लाखो मूक-प्राणियों के हित के लिए काग्रेस प्रत्येक हित का विलदान कर देगी। इसलिए वह आवश्यक-रूप से किसानो की संस्था है और वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। आपको, और कदाचित इस समिति के भारतीय सदस्यों को भी, यह जान कर आवचर्य होगा कि काग्रेस ने आज 'अखिल भारतीय चरखा सघ' नामक अपनी सस्या द्वारा करीव दो हजार गावों की लगभग ५० हजार स्त्रियों को रोजगार में लगा रखा है, ओर इनमें सम्भवत ५० प्रतिशत मुसलमान स्त्रियाँ है। इनमे हजारो अछूत कहानेवाली जातियों की भी हैं। इस तरह हम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन गावों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० गावों में से प्रत्येक गाव में, प्रवेश करने का यत्न किया जा रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का हे, फिर

भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप काग्रेस को इन सब गांवो में फैली हुई और उन्हें चरखे का सन्देश सुनाती हुई देखेंगे।"

· २ :

कांग्रेस के हितेषी और कर्णधार

काग्रेस का क्रम-बद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के पहले हम यहाँ कुछ ऐसे देशी और विदेशो व्यक्तियो को चर्चा करना उपयुक्त समझते है जिन्होन समय-समय पर काग्रेस की सहायता की है। सबसे पहले अग्रेज हितैषियो को लीजिए ——

अंग्रेज-हितपी

जाँन प्राइट और फाँसेट साह्व स्माह्व से पहले पार्लमेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नो में दिलचस्पी लेने लगे थे। पिछली शतान्दी के पचास से सत्तर वर्ष के वीच जॉन ब्राइट साहव ने भारत का खूव पक्ष-समर्थन किया या। उन्होने १८४७ में पार्लमेण्ट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग्य में वहत उतार-चढाव आये, पर बाइट साहव का भारत-प्रेम वरावर बना रहा। उनके वाद फॉसेट साहव की वारी आई। वह १८६५ मे पार्लमेण्ट के सदस्य हुए और १८६८ में ही उन्होने प्रस्ताव किया कि भारत की बड़ी-बड़ी नीकरियों की परीक्षा केवल विलायत में न होकर भारत और इग्लैंड दोनों में साथ-साथ हो । १८७५ में इग्लैंग्ड में भारतवर्ष के लर्च से तुर्की के मुनतान के लिए लॉर्ड मेल्सवरी ने जो नाच करवाया था उसकी फॉसेट साह्व ने निन्दा की थी। उन्ही के विरोध ने अवीसीनिया की लडाई का सारा वर्च भारत के मत्ये न महा जाकर आया इंग्लैण्ड पर पडा। ड्यूक ऑफ एडिनवरा ने भारतीय नरेगो को जो उपहार दिये ये उनका मूल्य भारतीय कोप से दिये जाने का भी उन्होंने विरोध किया था। इनी प्रकार ब्रिटिश-युवराज की भारत-यात्रा के गर्न के ४,५०,०००) के भार में भी उन्होंने हमारे देश को बचाया था। लॉर्ड लिटन ने कण्डे का आयात-कर दन्य कर दिया, दिल्ली में दरवार किया और एफ-गान-गृह मोत है लिया। इन करतूनों का भी फॉनेट साहब ने विरोध किया था। ल्या भारत ने भी इन उपकारों को ददना उन्हें तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ते तो परत्या ने उन्हें भार-पर दिया और जब १५७४ में फॉनेट साहब पार्लमेण्ड के ृताय में हार गये नद आगामी चुनाय के लिए महायतार्थ उन्हें १०,०००) ने

सिंदर की धैनी भेंट की घी।

ह्यूम साहब -- ह्यूम साहब ने पार्लमेण्ट की भारत-समिति और काग्रेस के सगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। परन्तु इस स्कॉचमैन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी और गैर-सरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से जानना हमारा कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस में अनेक पदो पर रह चुके थे। जब वह जिला-मजिस्ट्रेट थे तब उन्होने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मदिरा-निषेध, देशी-भाषाओं के समाचार-पत्रों की उन्नति, वाल-अपराधियों के मुधार एव अन्य घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए परिश्रम किया था। उन्हें यदि किसी वात मे रसे था तो गाव और खेती मे। उन्हें किसी वात की चिन्ता थी तो जनता की। उन्होने घोषित किया था कि सरकार तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर ले, किन्तु स्वतन्त्र और सम्य सरकार की पाय-दारी और स्थायित्व तो इसी मे है कि प्रजा के ज्ञान की वृद्धि की जाय और उसमे सरकार की अच्छाइयो की कदर करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय। इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी, १८५६ के अपने एक गश्ती-पत्र में ह्यूम साहब को दिया। इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रसार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय और कलेक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में अपने वालको को भेजने की या पाठशालाओ की सहायता करने की प्रेरणा न करे। ह्यूम साहव ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्के की बात थी। ह्यूम साहब का दूसरा प्रिय विषय था पुलिस का सुधार। उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को विलकुल अलग-अलग कर दिया जाय। आबकारी के बारे में भी उनके उग्र विचार थे। १८५६ के अन्त में हचूम साहब की सहायता से "पीपुल्स-फ़ेण्ड" (लोक-मित्र)नामक भारतीय पत्र निकाला गया। इसकी छ सौ प्रतिया उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती थी। वाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया था। इसका अनुवाद कराकर भारत-मन्त्री द्वारा महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता था। १८६३ में ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियो के सुधार-गृह बनाये जाय । चुङ्गी की अफसरी में उन्होने मुख्य कार्य यह किया कि चुङ्गी की लम्बी-चौडी रुकावटों को घीरे-घीरे दूर करवा दिया। १८७६ में ह्यूम साहब ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की। लॉर्ड मेयों की उसके प्रति सहानु-भूति भी थी, परन्तु वह योजना यो ही गई। मुकदमेबाजी के बारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाको में किसानो को महाजनो की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी अदालतो पर है। उन्होने सिफारिश की कि ग्रामवासियो के कर्ज के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहां-के-तहा निपटाने चाहिए, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार और समझदार भारतीयो-द्वारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश वनाकर गाव-गाव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के मुकदमे गाव के बड़े-बूढों की सहायता से तय कर दिया करें। १८७६ में इसी ढंग की एक योजना दक्षिण की कप्ट-पीडित प्रजा की भलाई के लिए वनाई गई-थी; परन्तु वम्बई-सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया।

१८७० से १८७६ तक ह्यूम साहव भारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहा से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि वह बहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक स्वर से निन्दा की, परन्तु कुछ सुनवाई नहीं हुई। लॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहव को लैफ्टिनेण्ट गवनर वनाने का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहव को यह स्वीकार न हुआ। दूसरा प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (गृह-सचिव) वना दिया जाय। यह बात इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री लॉर्ड सेल्सवरी को पसन्द नहीं आई। ह्यूम साहव ने १८५२ में नौकरी से अवकाश प्राप्त किया। उन्होंने लगभग तीन लाख रुपया पक्षियों के अजायब-घर पर और लगभग ६० हजार रुपया भारत के शिकारी पक्षी नामक ग्रथ की तैयारी में खर्च किया था।

सर विलियम वेडरबर्न सर विलिर्नयम वेडरवर्न की सेवा र तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश काग्रेस-कमेटी को चलाने में वर्षों तक उन्हीं का मुख्य हाथ रहा। काग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वार्षिक खर्च करती थी। वेडरवर्न साहब वम्वई में १८७६ में, और इलाहावाद में १६१० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के सभापति हुए। जार्ज यूल साहब इलाहावाद के १८८८ वाले काग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लमेंट के सदस्य भारत-यात्रा करने और काग्रेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे।

रैमजे मैवडॉनल्ड और चार्ल्स ब्रैडला—रैमजे मैवडॉनल्ड साहव १६११ में काग्रेस अधिवेशन का सभापित-पद भी सुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहात हो जाने से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। केअर हार्डी, होलफोर्ज, नाइट, मैक्स्टन, कर्नल वैजवुड, वेनस्पूर, चार्ल्स रॉवर्टस्टन और पैथिक लारेस आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और काग्रेस अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८६ ई० में चार्ल्स ब्रैडला साहव का जो स्वागत किया गया वह शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। ब्रैडला साहव ने १८८६ में कौसिलों के सुधार के लिए एक कानून का ममविदा (विल) बनाया और उसे लोकमत-संगह के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में काग्रेस के तत्कालीन विचारों का समावेश था। काग्रेस ने भी ग्रैडला साहव की एच्छानुसार सूचनाएं पंश को जिनने भारतीय जनता का गम्भीर मत प्रदिश्तत होता था। आगे चलकर यह मसविश दापस ते लिया गया, परन्तु पार्लमेंट में ब्रैडला साहव की न्यित इतनी मजबूत थी कि लॉर्ड क्रॉस का पहला मसविदा भी ब्रैडला साहव के विरोध के कारण वापस लेना पडा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मजूर हुआ जब उसमें प्रस्तावित सुधारों की पहली किश्त के साथ, अप्रत्यक्ष ही सही, कौसिलों में निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

ग्लैंडस्टन और लार्ड नॉर्थब्रुक—विलियम राबर्ट ग्लैंडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता। भारत में ग्लैंडस्टन साहब बडें लोकप्रिय हो गये थे। इसका असली कारण था उनकी काग्रेस-आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहमति। उन्होंने १८८८ में कहा था—"इस महान राष्ट्र की उठती हुई आकाक्षाओं के प्रति तिरस्कार या उपेक्षा का व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।" लगातार कई वर्ष तक ग्लैंडस्टन साहब की वर्षगाठ पर काग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ८२वी जयती को काग्रेस ने विधिपूर्वक मनाया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रति भी काग्रेस ने १८६३ के अपने नवे अधिवेशन में कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने पार्लमेंट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम चार्जेंज' के नाम पर जो विशाल-धन-राशि खीची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय।

लार्ड स्टैनले, जनरलब्थ और हेनरी काटन--ऐसे ही हितैषियो मे एक थे एल्डले के लार्ड स्टैनले । उन्होने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत मे ही व्यतीत किया था और भारत के अभ्युत्थान के लिए परिश्रम किया था। १८६४ में उन्होने भारत-मत्री की कौसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था--- "यदि भारत-मत्री पर कौसिल का नियन्त्रण रहे तो भारत-मत्री का पद उठा दो। यदि कौसिल पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो कौसिल को मिटा दो। यह द्विविध-शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और वाधक है।" उन्होंने भारत-मन्त्री और उसकी कौसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये थे। जनरल वूथ भी हमारे हितैषी थे। उन्होने १८६१ की नागपुर काग्रेस मे एक योजना भेजी थी कि हजारों निर्धन और अपग लोगों को देश की बजर भूमि पर किस प्रकार वसाया जा सकता है। उन्हे तार द्वारा उचित उत्तर दिया गया था। यहाँ सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओ का उल्लेख किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सबध था। ज्यों ही आसाम के इन चीफ कमिश्नर साहब ने पेशन ली त्योही काग्रेस ने अपने १६०४ वाले वम्बई के अधिवेशन का सभापति-पद ग्रहण करने के लिए उन्हें आमन्त्रित किया। उन्होने पहले-पहल भारत के सयुक्त राज्य की कल्पना की थी।

भारतीय कर्णधार

वादा भाई नौरोजी--कागेस के वडे-वूढो की सूची में सबसे पहला नाम दादा

भाई नीरोजी का आता है, जो काग्रेस के आरंभ से अपने जीवन-पर्यन्त काग्रेस की सेवा करते रहे। १८८६, १८६३ और १६०६ में तीन बार वह काग्रेस के सभापति हुए और वरावर काग्रेस के साथ रहते हुए इगलैंड और हिन्दुस्तान में उन्होंने काग्रेस के झंडे को ऊँचा रखा। विटिश-राज्य की न्याय-परायणता में दादा भाई का वहुत विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा। १६०६ में दादाभाई कलकत्ते के अधिवेशन के सभापति हुए। उस समय भारत मानो एक खीलते हुए कदाव में था। १६ अक्टूबर, १६०५ को जो वग-भग किया गया था, उससे देश भर मे एक नई लहरपैदा हो गई थी। काग्रेस के सारे वायु-मण्डल मे उस समय वहिष्कार की भावना छाई हुई थी। वाबू विपिनचन्द्रपाल ने वहिष्कार शब्द को और भी व्यापक-रूप दिया और सरकार से सव तरह का संबंध विच्छेद करने के लिए कहा। प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियो ने जुदा-जुदा किया। मालवीयजी ने उसका अर्थ देशी उद्योग-धधो का मरक्षण किया; लोकमान्य तिलक ने मध्य-श्रेणी के व्यक्तियो-हारा इस्तेमाल किये जानेवाले विदेशी कपड़े के दु खद दृश्य का अन्त करने के लिए राष्ट्रों की ओर से किये जाने वाले दृढ निश्चय, विलदान और स्वावलम्बन को स्वदेशी कहा; लालाजी ने इसका अर्थ देश की पूजी को बचाना और सुरक्षित रखना वतलाया और स्वय दादाभाई के लिए यह ओंथिक और शिक्षा-सर्वेधी सुधार तथा शिक्षा-प्रचार की पुकार थी, पयोकि शिक्षा-प्रचार के ही कारण लोगों में स्वराज्य की भूख पैदा हुई थी। इस अस्मी वर्ष के यूडे ने ६,००० मील दूर इंग्लैंड से यहा आकर स्वदेशों, वहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा करदी। यह देखकर 'उगलियमैन' उन पर उवल पडा। इस प्रकार दादाभाई के सभापितत्व मे होनेवाला कलकत्ता-अधिवेशन अत्यन्त सफल रहा।

फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्तृत्व-शक्ति के साथ उनका एक विशेष व्यक्तित्व था।

दीनशा एदलजी वाचा-वाचा महोदय का खास विषय कौन-सा था, यह कहना कठिन है, क्योंकि प्राय सभी विषयों में उनका एक-समान अबाध प्रवेश था। उनके उज्ज्वल गुण तो पहले ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जविक उन्होने सेनिक परिस्थित का योग्यतापूर्वक विस्तृत सिहावलोकन किया था। दूसरे अधिवेशन में उन्होने भारतवासियों की गरीवी को लिया और भारत से हर साल ब्रिटेन को जानेवाले उस खराज की ओर सर्व-साधारण का ध्यान आकृप्ट किया जिससे विटेन तो समृद्ध हो रहा था, पर भारत कगाल बनता चला जा रहा था। बम्बई में होनेवाले कांग्रेस के पाचवे अधिवेशन में उन्होंने आवकारी नीति को लिया और बताया कि कामन-सभा ने एक प्रस्ताव-द्वारा सर्व-साधारण की इच्छानुसार आवकारी-नीति में सुधार करने का आदेश भारत-सरकार को दिया था, लेकिन उसके नौ महीने बाद भी सरकार ने कुछ भी नही किया। छठी काग्रेस में उन्होने फिर इस ओर घ्यान दिया और इसके साथ ही नमक-कर का प्रश्न भी उठाया था। इलाहाबाद में होनेवाली काग्रेस के ६ वे अधिवेशन में उन्होने चादी के सिक्के ढालना बन्द करने के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया। वह इतने चतुर थे कि अब से बहुत पहले, १८८५ में ही उन्होने लकाशायर का प्रश्न उठाया। १८६४ में उन्होंने फिर भारतीय मिलो के (सूती) माल पर उत्पत्ति-कर लगाने का और १८६७ में उन्होने अमरावती में होने वाले अधिवेशन में, सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया। काग्रेस के १५ वे अधिवेशन मे भी उन्होने मुद्रा-नीति पर अपना हमला जारी रखा और भारत में सुवर्ण-मान जारी करने की निन्दा की । १६०१में होनेवाले कलकत्ता-अधिवशन में राष्ट्र ने उनको काग्रेस का सभापति वनाने के लिए आमन्त्रित किया। १८६६ से १९१३ तक वह काग्रेस के सयुक्त प्रधान-मत्री रहे । इसके बाद उसके काम-काज मे गौण-रूप से योगदेते रहे । सर्वती-मुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान और सैनिक समस्या जैसे दुरूह विषयो एवं सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओ की भलीभाति जानकारी में उनकी जोड के उस समय थोडे ही आदमी थे।

गोपालकृष्ण गोखले—गोखले पहले-पहले १८८६ में काग्रेस में तिलक के साथ आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होंने बहुतेरे तथ्य के आकडे पेश किये। उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पाच आने हो जाती है। फिर भी उनमें कडी-से-कडी बात को बहुत ही मबुर भाषा में कहने का बडा गुणथा। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मधुर और मजुल थे तथापि वह कहते थे बात खरी, गोलमाल बाते करना उन्हें पसन्द नहीं था। १६०४ में बनारस-काग्रेस के सभापित की हैंसियत से उन्होंने राजनैतिक शस्त्र के रूप में बहिष्कार

1

का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबिक प्रबल लोक-भावनाएँ इसके अनुकूल हो। गोखले सामनेवाले के साथ वडी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पष्टता और उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था। १६०५ और १६०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इम्लैण्ड भेजे गये थे। जनता और सरकार दोनों के बीच उनकी स्थिति विषम रहती थी। इधर लोग उनकी नरमी की निन्दा करते थे, उधर सरकार उनकी उग्रता को बुरा बताती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बनकर रहते थ। वह जनता की आकाक्षाएँ वाइसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइया काग्रेस तक।

गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे राज-नैतिक कार्यकत्तांओं की एक संस्था है, जिन्होंने नाम-मात्र के वेतन पर मातृ-भूमि की सेवा करने का प्रण लिया। उनके बाद श्रीमती ऐनी वेसेण्ट ने 'भारत के पुत्र' नाम की संस्था खड़ी की। इसके बाद गांघीजी के आश्रमवासियों का नम्बर आता है। १६१६ में गांघीजी ने अहमदावाद में सत्याग्रह-आश्रम खोला और इसके बाद १६२० से उसी नमूने पर दूसरे कई आश्रम खोले गये। ये सब आश्रम जीवन की कठोरता और सांघना में 'भारत-सेवक-सिमिति' और 'भारत के पुत्र' से कही बढ़े-चढ़े थे।

सूरत के झगड़े के बाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य का प्रमुख भाग लिया। वह दक्षिण अफीका भी गये और वहा उन्होने गांधीजी के सत्याग्रह-सग्राम में उनकी अपूर्व सहायता की। १६०६ की कांग्रेस में उन्होने सत्याग्रह-धर्म की बडी प्रशसा की और उसके तत्त्व को वडी खूबी के साथ समझाया। इसके बाद उनकी प्रवृत्तियां मुख्यत बडी कीसिलों के अखाड़े के प्रति ही रही। १६१४ में जब कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब पहले तो उन्होंने इसे पमन्द किया परन्तु बाद को अपना विचार बदल दिया। इस तरह उत्कृष्ट देश-भिक्त, देश के लिए कठोर परिश्रम, महान् स्वार्यत्याग और देश-सेवामय जीवन व्यतीत करते हुए गोखले १६ फरवरी १६१५ को इस लोक से प्रयाण कर गये।

जी० सुद्रह्मण्य ऐयर — काग्रेस के सर्व प्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव पेरा करनेवाले 'हिन्दू' के सम्पादक श्री जी० सुब्रह्मण्य ऐयर थे। उनका प्रस्ताव था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही कमीशन द्वारा होनी चाहिए जिसमें भारतीयों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। इसके पश्चात् मद्रास में होनेवाली १०वी काग्रेस तक हम सुब्रह्मण्य ऐयर के बारे में कुछ नहीं सुनते। पर मद्रास-काग्रेस में भारतीय राजस्व के प्रश्न पर वह वोले और तत्सम्बन्धी जाच फरने की आवश्यकता वतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था

-देशी-राज्यो मे अखबारो की स्वतन्त्रता का अपहरण, जिसका सुब्रह्मण्य ने कसकर विरोध किया। १२ वे अधिवशन में उन्होने प्रतिस्पर्धी-परीक्षाएँ इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान मे एक साथ ली जाने की आवाज उठाई और साथ ही लगान के मियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया। अगले साल अमरावती-काग्रेस मे उन्होने सरकार की सरहदी-नीति का विरोध किया। १८६८ मे जब तीसरी बार मद्रास में काग्रेस का अधिवेशन हुआ तब श्री सुब्रह्मण्य ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की तथा युद्ध-नीति का भी घोर विरोध किया। श्री सुब्रह्मण्य का प्रिय विषय था भारत की आर्थिक स्थिति। लाहौर में होनेवाले १६वें अधिवेशन में उन्होने बार-बार पडनेवाले अकालो को रोकने के उपाय मालूम करके उन पर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयों की आर्थिक अवस्था की पूरी और स्वतन्त्र जाच कराने क लिए कहा। साथ ही सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों को उनसे महरूम रखने की शिकायत की। १७वे अधिवेशन में जनता की दुर्दशा और गरीवी पर ध्यान दिया। उनका ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विशाल उनका दृष्टि-कोण था। अहमदाबाद में होनेवाले १ दवे अधिवेशन में एक बार उन्होने सर्व-साधारण की गरीबी पर प्रकाश डाला। अपने लेखो की बदौलत उन्हें जेलखाने की हवा खानी पड़ी, जहा से बीमार हो जाने पर ही उन्हें रिहाई मिली।

वदरहीन तैयबजी—बदरहीन तैयवजी एक पक्के काग्रेसी थे, जो बढते-बढते काग्रेस के तीसरे अधिवेशन के सभापित हुए थे। सभापित-पद से दिए हुए अपने भाषण में उन्होंने काग्रेस के प्रतिनिधि-रूप पर जोर दिया। बाद में वह बम्बई-हाईकोर्ट के जज हो गये। १६०४ में सरकारी जगहो पर हिन्दुस्तानियो की नियुक्ति-सम्बन्धी प्रस्ताव की बहस में उन्होंने भाग लिया था। १६०६ के प्रारम्भ में उनका स्वर्गवास हो गया। काग्रेस के पहले अधिवेशन का सभापितत्व उमेशचन्द्र बनर्जी ने किया था, दूसरे के सभापित पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थे। इसके बाद तीसरे अधिवेशन का सभापित तैयबजी को बनाना अत्यन्त उचित था, क्योंकि

वह मुसलमान थे।

उमेशचन्द्र बनर्जी—यदि प्रामाणिक रूप से जानना हो कि काग्रेस का प्रारम्भिक उद्देश्य क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापित उमेशचन्द्र बनर्जी के भाषण की ही ओर निगाह दौडानी पडेगी। उसमें उन्होने स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद के आठवे अधिवेशन में वह दुबारा काग्रेस के सभापित हुए थे। यह याद रहे कि १८६१ में सहवास-बिल के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन उठ खडा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्र बनर्जी ने अपने इलाहाबाद वाले भाषण में वे कारण बताये थे जिनसे काग्रेस ने अपने को सामाजिक प्रश्न से अलहदा रक्खा था।

लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक भारत के बिना ताज के बादशाह थे। शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का श्रेय उन्ही को है। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८६७ को कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीने की कड़ी कैंद की सजा दी गई थी, पर वह ६ सितम्बर १६६८ को ही छोड़ दिए गये। १८६६ से ही वह काग्रेस के समर्थक थे। १८६६ में जब वह लॉर्ड सेण्डस्ट की निन्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तब एक विरोध का तूफान खड़ा हो गया था। उनकी नीति उग्न थी। सूरत में काग्रेस के दो टुकड़ों का हो जाना उस समय बड़ी चर्चा का विषय हो गया था। लोकमान्य तिलक उसमें सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे और कहा जाता था कि उन्होंने २५ वर्ष की जमी-जमाई काग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। दोनो तरफ के लोग अपने-अपने पक्ष की बाते कहते थे। वास्तव में इस प्रकार के मतभेद की नीव कलकत्ते में ही पड़ चुकी थी। लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण किसी तरह वह हट-सा गया था। वही १६०७ में जाकर प्रबल हो गया। गरम दल के लोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक सभापित हो, परन्तु नरम दल के लोग इसके विरोधी थे। उन्होंने अपने विधान के अनुसार डॉ० रासबिहारी घोष को चुन लिया। इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया, परन्तु लाला लाजपतराय ने इन्कार कर दिया।

काग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ बजे आरभ हुई। १६०० से ऊपर प्रतिनिधि मीजूद थे। जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खतम कर चुके तब स्वागत-समिति के नियमानुसार मनोनीत सभापित डॉ० रासिबहारी घोप का नाम उपस्थित किया गया। इस पर गुलगपाडा मचा और कार्रवाई दूसरे दिन के लिए मुल्तवी करनी पड़ी। नये सिर से फिर निपटारे की कोशिश की गई; मगर कोई फल नही निकला। २८ को फिर काग्रस शुरू हुई। जब सभापित का जुलूस निकल रहा था, तब लोक-मान्य तिलक ने एक चिट श्री मालवीयजी के पास भंजी, जिसमें लिखा था— "जब सभापित के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तब मैं प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता हूँ।" लेकिन अधिवेशन आरभ होने पर लोकमान्य तिलक बोलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर बढ़े। स्वागताध्यक्ष और डॉ० घोष दोनों ने तिलक को बोलने की इजाजत नहीं दी। बस क्या था, गुलगपाडा और गोलमाल शुरू हुआ। इतने ही में प्रतिनिधियों में से किसी ने एक जूता उठाकर फेका, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा। तब मानो एक लडाई शुरू हो गई—कुर्सिया फेकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे काग्रेस उस दिन के लिए खतम हो गई। अब नरम दल के नेता जमा हुए और

उन्होने 'कनवेन्शन' बनाया और ऐसा विधान तैयार किया जिससे गरम दल के लोग आही न सके।

लोकमान्य तिलक राष्ट्र-धर्म के जबरदस्त उपासक थे। अपने समय की मर्यादा को वह जानते थे। उस पुराने युग मे एक वही थे जिन्हें लगातार जेलों में तथा अन्यत्र कष्ट-ही-कष्ट भोगना पड़ा था। १६०६ में जब जज ने उनकों सजा दी और उनके बारे में खरी-खोटी बाते कहकर पूछा कि आपकों कुछ कहना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर में स्वर्णाक्षरों में लिखकर रखने योग्य है। "जूरी के इस फैसले के बावजद में कहता हूँ कि मैं निरपराध हूँ। ससार में ऐसी बड़ी शक्तिया भी हैं जो सारे जगत का व्यवहार चलाती है और सम्भव है ईश्वरीय इच्छा यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट-सहन से अधिक फूले-फले।" ऐसी ही तेजस्विता उन्होंने १६७ में दिखाई थी जब कि उन पर राजद्रोहात्मक लेखों के लिए मुकदमा चल रहा था और उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे अदालत में कह दे कि ये लेख मेरे लिखे नहीं हैं, परन्तु उन्होंने कतई इन्कार कर दिया। उन्होंने वड़ी शान्ति और अनासित्त के साथ इन सजाओं को भुगता और जेल में बैठे-बैठे बड़े भव्य-प्रन्थों की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो 'आर्क-टिक होम ऑफ दी वेदाज' और 'गीता-रहस्य' की रचना न हो पाती।

जब १८६६ में गांधीजी पूना गये तब वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी। गाधीजी पर दोनो की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान् उच्च, परन्तु अगम्य दिखाई पड़े, लेकिन गोखले गगा की पिवत्र धारा की तरह जिसमें वह आसानी से गोता लगा सकते थे। तिलक और गोखले दोनो महाराष्ट्रीय थे, दोनो बाह्मण थे, दोनो चितपावन थे, दोनो प्रथम श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनो ने अपने-अपने जीवन में भारी त्याग किया था, परन्तु दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न थी। यदि हम स्यूल भाषा का प्रयोग करे तो कह सकते हैं कि गोखले 'नरम' थे और तिलक 'गरम'। गोंखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे बनाना चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पडता था, तो तिलक को नौकरशाही से भिडत करनी पडती थी। गोखले कहते थे-जहा सम्भव हो सहयोग करो, जहा आवश्यक हो विरोध करो। तिलक का झुकाव अडगा-नीति की ओर था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर मुख्य घ्यान देते थे, तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सब से मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहना। गोखले विदेशियो को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले उच्च वर्ग और बुद्धि-वादियों की तरफ देखते थे और तिलक सर्वसाधारण और करोडों की ओर। गोखले का अखाडा था कौसिल-भवन, तिलक की अदालत थी गाँव की चौपाल। गोखले अग्रेजी में लिखते थे, तिलक मराठी में। गोखले का उद्देश्य था स्वशासन, जिसके योग्य लोग अपने को अंग्रेजों की कसौटियों पर कसकर बनाए, तिलक का उद्देश्य था 'स्वराज्य', जो कि प्रत्येक भारतवासी का जन्म-सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाधा की परवाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे। ऐसा था उनका व्यक्तित्व जो १ अगस्त १६२० को उठ गंया।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी—भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञो के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्थान है। काग्रेस के साथ ४० साल से अधिक उनका सम्बन्ध रहा। भारत में काग्रेस के मच से उठी उनकी बुलन्द आवाज सम्य ससार के दूर-दूर के कोने तक पहुचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना-प्रवणता, उच्च-भावुकता, वीरोचित-हुकार, इन गुणो में उनकी वक्तृत्व-कला को पराजित करना कठिन था। उनके भाषणों का मसाला होता था अपनी राजभित्त की दुहाई। उन्होंने इसे एक कला की सीमा तक पहुंचा दिया था। उन्होंने दो बार काग्रेस के सभापति-पद को सुशोभित किया था—पहली बार १८६५ में पूना में और दूसरी बार १६०२ में अहमदाबाद में। काग्रेस में प्रति वर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयो पर विविध प्रस्ताव लाए जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकी पहुच के बाहर रहता हो। उनका आदर्श था ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना। एक-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था— "अग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच्च है, इन्लैण्ड और भारत की अखण्डता एकता का चिह्न है। यह सम्यता भारत-वासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और अग्रेजों के सुनाम को अपूर्व ख्याति दिलानेवाली है।" उनके इन तमाम विश्वासो और मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टों के वाइसराय-काल में वरीसाल में उन पर लाठी चलाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बगाल का मत्री बनना था, इसलिए बच गये।

मदनमोहन मालवीय—प० मदनमोहन मालवीय का काग्रेस-मच पर सबसे पहली वार काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन में व्याख्यान हुआ था। तब से वह वराबर अथक उत्साह और लगन के साथ इस राष्ट्रीय सस्था की सेवा करते रहे; कभी तो एक विनम्न-सेवक के रूप में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्ता-धर्ता बनकर, कभी कुछ थोड़ा-सा विरोध प्रदिश्ति करनेवाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह-आन्दोलन के विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर। उन्होंने काग्रेस की विविध रूपों में सेवा की थी।

सन् १६१८ के अप्रैल मास मे, २७, २८ और २६ तारीख को वाइसराय ने गत महायुद्ध के सहायतार्थ जन, धन तथा अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए भारतीय नेताओं की जो सभा बुलाई थी उसमें मालवीयजी भी आमत्रित किए गए थे। देश में जब असहयोग आन्दोलन चला तब मालवीयजी उससे तो दूर रहे, परन्तु काग्रेस से नही। नरम दल वालो ने अपने जमाने में काग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तब वह उससे अलग हो गये। श्रीमती वसेण्ट ने काग्रेस पर एक बार अधिकार प्राप्त कर लिया था, पर बाद में उन्होने भी, अपने से प्रवल दलवालो के हाथो में उसे सौप दिया। लेकिन मालवीयजी तमाम उतार-चढावो में प्रशसा और बदनामी सहते एव किसी की परवा न करते हुए सदैव काग्रेस का पल्ला पकडे रहे । मालवीयजी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनमें इतना साहस था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उसमे चाहे कोई भी उनका साथ न दे, पर वे अकले ही मैदान में खम ठोककर डटे रहते थे । १६३० में जब सारे काग्रेसी सदस्यो ने असम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तव मालवीयजी वही डटे रहे। उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था, क्योंकि वह काग्रेस के टिकट पर असेम्बली में नही गये थे। लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया। मालवीयजी ने उस समय की आवश्यकता को देखकर असम्बेली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया । सन् १६२१ मे उन्होने असहयोग-आन्दोलन का विरोध किया था, लेकिन १६३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही दिखाई दिये। वह स्वय एक सस्या थे। पहले-पहल सन् १६०६ में वह लाहौर-काग्रेस के सभापति हुए थे। काग्रेस के २४ वे अधिवेशन के सभापित चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्ही अज्ञात कारणो मे उन्होने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अत उनके स्थान की पूर्ति मालवीयजी ने ही की थी। १० वर्ष वाद सन् १९१८ में काग्रेस के दिल्ली वाले ३३ वे अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने उनको फिर मनोनीत किया था। काशी-विश्व-विद्यालय तो उनकी कीर्ति का अमर स्तभ ही है।

लाला लाजपतराय—काग्रेस के पुराने पूज्य पुरुषों में लाला लाजपतराय का सार्वजिनक व्यक्तित्व भी महान था। वह जितने वडे काग्रेस-भक्त थे उतने ही बडें परोपकारी और समाज-सुधारक भी थे। सन् १८८८ में होनेवाले इलाहाबाद काग्रेस के चौथे अधिवेशन में वह सबसे पहली बार सिम्मिलत हुए थे। राजनैतिक क्षेत्र में उनकी लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने सारे देश में उनका सबसे ऊचा स्थान बना दिया था। बनारस-काग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्र-वादी के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। सन् १६०७ में उन्हें सरदार अजीतिसह के साथ निर्वासन का दण्ड दिया गया था। सन् १६०७ की काग्रेस के सभापित-पद के लिए राष्ट्रीय-विचार के लोगों ने उनका नाम पेश किया, परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सन् १६०६ में गोंखले के साथ वह भी शिष्ट-मण्डल में इंग्लैण्ड भें गये थे। वाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना तग किया कि उन्होंने विदेशों में ही

ठहरना ठीक समझा। प्रथम महायुद्ध के दिनो में तो वह अमरीका ही में रहे। काग्रेस के सभापित बनने का लालजी का नम्बर जरा देर से आया। सन् १६२० के सितम्बर मास में कलकत्ते में काग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से बाहर मछली की होती है। असहयोग-आन्दोलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा। वह वीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए सत्याग्रह या सविनय भग का अर्थ कानून-भग के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनका समय बड़ी किटनाइयों और सघर्षों में बीता। उनके अपने ही प्रान्त में नौजवानों का एक दल ऐसा था जो उनके खिलाफ था। कौसिल में जाने पर उनका जौहर फिर से खिल उठा। लेकिन अफसोस कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरतापूर्ण वार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय में ही चले गये!

फरोजशाह मेहता—सर फिरोजशाह मेहता उन व्यक्तियों में थे जिनका सम्पर्क काग्रेस के साथ उसके आरम्भ से ही था। काग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण में उनका बहुत प्रमुख भाग था। कलकत्ता में होनेवाले छठे अधिवेशन के वह सभापित थे। कई वर्ष तक वह काग्रेस के पीछे एक वास्तिवक शक्ति के रूप में थे। उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन सिमितियों, शिष्ट मण्डलों और प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा ही किया जिनके वह सदस्य चुने गये थे। १६०७ में उन्होंने नरम-दल की ओर से सूरत-काग्रेस के अवसर पर काग्रेस-कार्य में कुछ कियात्मक भाग लिया था। इसके वाद वह दृष्टि से बिलकुल ही ओझल हो गये। लाहौर-काग्रेस के २४वें अधिवेशन के जब वह सभापित चुने गये तब यकायक उन्हों ने काग्रेस के सभापित का आसन ग्रहण करने से ५ दिन पहले इस्तीफा दे दिया। अतः उनके स्थान पर पं० मदनमोहन मालवीय काग्रेस के सभापित चुने गये।

आनन्दमोहन वसु—आनन्दमोहन वसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। ब्रह्म-समाज की प्रगित में उनका हाथ था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन-एसोशियेशन के वह सर्व-प्रथम मन्त्री और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी थे। काग्रेस-आदोलन के साथ १८६६ से पहले तक उनका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध रहा या नही, यह नो ज्ञात नही होता, पर १८६६ के १२वे अधिवेशन में उन्होने शिक्षा-विभाग की नौकरियों के पुनस्संघटन की योजना से होनेवाले नये अन्याय का विरोध किया था और कहा था कि यह योजना तो भारतीयों को शिक्षा विभाग के उन्हें पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद शीघ्र ही १८६८ के मद्रास-अधिवेशन में वह काग्रेस के सभापित हुए। सभापित-पद से दिया हुआ उनका भाषण अकाट्य युक्तियों तथा प्रेम एवं राष्ट्र-सेवा के उपदेशों से परिपूर्ण था। उन्होंने पार्लमेण्ट में भारत के चुने हुए प्रतिनिधि रखे जाने की बात सुझाई

थी। यह देश का दुर्भाग्य था कि जब उसे उनकी सेवाओं की सब से अधिक आवश्य-कता थी तब, १६०६ में, ईश्वर ने उनको हमसे छीन लिया।

चक्रवर्ती विजयराधवाचार्य—सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराधवाचार्य सब से पुराने काग्रसियों में से थे। काग्रेस के तीसरे अधिवेशन में काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें उनका नाम था। इसके बाद लखनऊ में होनेवाले १५वें अधिवेशन में और उसके अगले साल लाहीर में होनेवाले १६वें अधिवेशन में और उसके अगले साल लाहीर में होनेवाले १६वें अधिवेशन में उन्होंने दायमी बन्दोबस्त का प्रस्ताव पेश किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि-कर बतौर किराया है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कभी भी नहीं रहा। ऋपि-मुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हीं की है जो उसमें पैदा हुए हैं, जमीन को जो जोतता-बोता है उसीकी वह सम्पत्ति होती है। राजा, जो उसकी रक्षा के लिए है, अपनी सेवाओं के बदल में किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यह विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय नहीं बल्कि पश्चिमी है।

सूरत-काण्ड के बाद से, वस्तुत वह काग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल की काग्रेस से उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये सशोधन से गरम दलवालों के लिए काग्रेस का दरवाजा खुल गया, तब वह फिर उसमें आ गये और १९१८ में होनेवाले विशेषाधिवेशन बम्बई तथा १९१९ में होनेवाले अमृतसर-अधिवेशन में उन्होंने कियात्मक-रूप से भाग लिया। अमृतसर अधिवेशन में उन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश हाला। इसके बाद ही उन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापित चुना गया, जहां बडी योग्यता और कुशलता के साथ उन्होंने कार्य सम्पादित किया।

कालीचरण वनर्जी—काग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आमतौर पर यह प्रथा थी कि जो आवश्यक प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते थे वे सब एक बड़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे और साल-दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा उस सयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विपयों का भली-भाति स्पष्टीकरण कर मकती थी। १८८६ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय ईसाई थे। कई वर्षो तक उन्होंने काग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलचस्पी ली थी। १८६० में ब्रिटिश जनता के सामने काग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इन्लैण्ड गया था उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। ६वी काग्रेस में उन्होंने न्याय और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक् करने का प्रस्ताव पेश किया था। समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे सर्वसाधारण में राजनैतिक जागृति बढ़ती गई, वैसे-वैसे उसकी स्वतत्रता पर अधिकाधिक प्रतिवन्घ लगने लगे। सरकारी सहायता-प्राप्त

कांग्रेस के हितैषी और कर्णधार

संस्थाओं के व्यवस्थापको और अध्यापको पर यह पाबन्दी लगा दी गई कि जूब तक शिक्षा-विभाग के प्रधान अधिकारी की स्वीकृति न ले ली जाय तु तक वे न तो राजनैतिक हलचलों में कोई हिस्सा लें और न राजनैतिक सभाओं में ही उपस्थित हो। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किये गये इस प्रहार का, १५वीं काग्रेस में श्री कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया। दु ख की बात है कि वह अधिक दिनों तक जीवित न रह सके।

नवाब सय्यद युहम्मद बहादुर—काग्रेस के मन्त्रियों में हिन्दू के माथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १६१४ की मद्रास-काग्रेस से शुरू हुई थी, जिसमें नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्बाराव मत्री चुन गय थे। लेकिन नवाब साहब तो इससे पहले, १६१३ की कराची-काग्रेस में, सभापित-पद को भी सुशोभित कर चुके थे। वह पहले काग्रेसी थे, इसके बाद मुसलमान। १६०३ में होनेवाली मद्रास-काग्रेस के १६वे अधिवेशन के वह स्वागताध्यक्ष थे और १६०४ की काग्रेस (२० वा अधिवेशन बम्बई) में काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी थी उसमें उन्हें भी रखा गया था। वह ऐसे देश-भक्त थे जिनमें मजहबी संकीर्णता बिलकुल नहीं थी। कराची-कांग्रेस के सभापित-पद से उन्होंने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई थी और इस बात पर जोर दिया था कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को अलग-अलग दुकडों में बटने के बजाय सयुक्त-रूप से आगे बढना चाहिए।

दाजी आवाजी खरें—काग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी बन्दोबस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय काग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा। लाहौर में होनेवाले ६ वे अधिवेशन में श्री दाजी आबाजी खरे ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया था। काग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १६०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ भाग १६०८ में बननेवाले विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निमार्ण में उन्होंने बहुत भाग लिया था। १६०६ से १६१३ तक, श्री दीनशा वाचा के साथ वह काग्रेस के मत्री रहें और १६११ में उन्होंने भारतीय सूती माल पर लगाया गया वह उत्पृत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-च्यवसाय के प्रसार में रुकावट पड़ती थी। १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तब श्री खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा था कि स्व-शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही प्राप्त होगा।

सी० शंकरन नायर—सर सी० शकरन् नायर अपने वक्त के एक समर्थ पुरुष थे। काग्रेस की सेवाओ के पुरस्कार-स्वरूप काग्रेस ने उन्हें बहुत जल्टी, १८९७ में, अमरावती-अघिवेशन का सभापित चुना था। बम्बई के चन्दावरकर और तैयबजी की तरह शकरन् नायर को भी पीछे मद्रास के हाईकोर्ट-बेच का सदस्य बना लिया गया और वहा से १६१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १६१६ में मार्शल लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोक-प्रिय हो गये। लेकिन 'गांधी एण्ड अनार्की' नामक पुस्तक में गांधीजी पर उन्होंने निराधार आक्षेप किया। इसी पुस्तक के कारण पजाव के लेफ्टिनैण्ट गवर्नर सर माइकेल ओड्वायर ने उन पर मुकदमा चलाया जिसके फलस्वरूप सर शकरन् को मानहानि तथा खर्चे के लिए तीन लाख रपये देने पडे।

विपिनचन्द्र पाल—विपिन बाबू का काग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह प्रसिद्ध वक्ता थे। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय-शिक्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होने सारे देश मे अपनी वक्तृत्व-शिक्त का सिक्का जमा दिया था। उन्होने १६०७ मे मद्रास मे जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-जनरल (सर) वी० भाष्यम आयगर ने उन्हें भड़काने वाले—राजद्रोहपूर्ण नही—समझा था और वह मद्रास अहाते से निकाल दिये गये। लार्ड मिण्टो के समय में उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला था। एक दूसरे अवसर पर, जब 'वन्देमातरम्' के सपादक की हैसियत से श्री अरिवन्द घोष पर मुकदमा चल रहा था, तव उन्होने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गवाही अरिवन्द बाबू के बहुत खिलाफ पड़ेगी। इस कारण ६ मास की सख्त कैंद की सजा उन्होने बड़ी खुशी से भुगत ली। उन्होने इंग्लैंड में 'हिन्दू रिव्यू' नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें 'वम के कारणों' पर विचार किया गया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होने माफी माग ली। उनका आखिरी इतिहास राप्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़ से लोगो में थे, जिन्होने अपने भाषणो और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखो-द्वारा उस समय के युवको पर बहुत जादू कर दिया था।

मौ० मजहरूल हक—मौ० मजहरूल हक काग्रेस के, शारीरिक और बौद्धिक दोनो दृष्टियो से, एक महारथी थे। वह पक्के राष्ट्रवादी थे और बिहार में काग्रेस के भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें चिढ थी। काग्रेस के २५ वे अधिवेशन में जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिन्ना ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था, इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था। इस अवसर पर उन्होंने एक योग्यतापूर्ण भाषण दिया जिसमें हिन्दुओ और मुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा थी। यह याद रखने की बात है कि मिण्टो-मार्ल-शासन सुघार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कौसिलों के लिए साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया गया था। मुसलमान अपनी इस सफलता पर फूलकर कुप्पा हो रहे थे। मौ० मजहरूल हक ने उस समय

उनसे कहा था कि उन्हें जो सफलता मिली हैं दरअसल वह दोनो महान जातियों की सिम्मिलत भलाई के लिए बड़ी घातक है। देश को जरूरत इस बात की है कि दोनो एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे के साथ मिल-कर काम करें। १६१४ में जब काग्रेस का शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया तब मौ० मजहरूल हक भी उसके सदस्य बनाये गय। इसके बाद उन्होंने काग्रेसी मामलों में कोई क्रियात्मक रस नहीं लिया, लेकिन रहें अन्त समय तक वह पक्के राष्ट्रवादी। जीवन के आखिरी दिनों में उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ और शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दिया। वस्तुत उनका आखिरी जीवन एक फकीर का जीवन था।

महादेव गोविन्द रानडे—-महादेव गोविन्द रानडे, काग्रेस में एक उच्च शिखर के समान थे। यदि बहुत बारीकी में उतरे तो उन्हें काग्रेसी नही कहा जा सकता, क्योकि वह बम्बई सरकार के न्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसो तक वह पीछे से काग्रेस का सूत्र-सचालन करनेवाली शक्ति बने रहे। काग्रेस आन्दोलन को उन्होने स्फूर्ति प्रदान की थी। उनका ऊचा कद, चेहरे का मूर्तिवत् बनाव और उनका अपना रग-ढग भिन्न-भिन्न अधिवेशनो में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक थे। अंर्थशास्त्री और इतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय थे। 'महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान' एव 'भारतीय अर्थशास्त्र पर निबन्ध' के रूप मे वह राष्ट्र को अपने पाण्डित्य एव विद्वत्ता की विरासत छोड़ गये है। समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और वर्षो तक समाजसुधार-सम्मेलन, जो काग्रेस की एक सहायक-सस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहे। १८६५ मे, पूना अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि काग्रेस समाज-सुधार के मामलो और समाज-सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नही, तब जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा दिया था। प्लेग की महामारी के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नही किया जा सकता। इस प्रकार पुन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और काग्रेस का काम करते हुए, १६०१ में, अपनी ऐसी स्मृतिया छोडकर रानडे हम से बिदा हो गये जो सदैव हमारी सहा-यता करती रहती है और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी।

रमेशचन्द्र दत्त—गत शताब्दी के अन्त में काग्रेस की राजनीति में श्री रमेश-चन्द्र दत्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह अपने जीवन-क्रम में किमश्नर के ऊचे पद तक चढ चुके थे, फिर भी उन्होंने काग्रेस का साथ दिया था। आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने सार्वजिनक प्रश्नों पर जो अमित अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था उसका लाभ उन्होंने काग्रेस को पहुंचाया था। उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण घघो का विनाश ही दुर्भिक्ष के कारण है। उन्होने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा था कि जिस देश ने ३,००० साल पहले ग्राम-शासन (पचा-यतो) का सगठन किया था आज उसी पर पुलिस, जिला अफसरो तथा जनता के बीच की घृणित-श्रृंखला द्वारा शासन हो रहा है। मालगुजारी, दुर्भिक्ष तथा अन्य आर्थिक प्रश्नो पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे। १८६० में लखनऊ-काग्रेस के अधिवेशन के वह सभापित बने थे।

एन० सुब्बाराव पन्तुलु — श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी काग्रेस के भक्त थे। काग्रेस से उनका सम्बन्ध उसके जन्म के साथ ही हो गया था। वह काग्रेस के चौथे अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे और वोले भी थे। तब से वह काग्रेसम्ब पर नमक-कर, न्याय और शासन कार्य, भारतीयों का कार्यकारिणी में लिया जाना, जूरी द्वारा मकदमों का फैसला और वकीलों की स्थिति आदि विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे। जब उनके समकालीन काग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, तब उन्होंने उसे लेने की कभी परवाह नहीं की। दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८६५ में उन्हें काग्रेस का स्वागताध्यक्ष चुना और १६१४, १५, १६ तथा १७ में काग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही। उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने खर्च पर हिन्दुस्तान का दौरा करने और काग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रखा था।

सिचानन्द सिंह— सिच्चिदानन्द सिंह को सबसे पहले १८६६ की लखनक काग्रेस में लागों ने देखा। उसीमें उन्होंने न्याय और शासन-विभाग के पृथक्करण के प्रस्ताव पर भाषण भी दिया। लाहौर-अधिवंशन में भी इस प्रश्न पर वह बोले थे। १७ वें अधिवंशन में भी 'पुलिस-सुधार' पर वह बोले थे। २० वें अधिवंशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १६०५ में आम चुनाव होने से पहले इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय। उसी अधिवंशन में उन्होंने दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी कॉटन और मि० जोन जार्डिन को पार्लमेण्ट का सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १६०८ की पहली 'नरम' काग्रेस में श्री सिंह कियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-काग्रेस में श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माग पेश की। वह फिर मद्रास में १६१४ में शामिल हुए। इस काग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिन्ट-मण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वश्री भूपेन्द्र वसु, जिन्ना, समर्थ, मजहण्ल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय थे।

काग्रेस के उक्त कर्णधारों के अतिरिक्त काशीनाथ त्र्यम्बक तैलग, प० अयोध्या-नाथ, मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष, राजा रामपाल सिंह, मशी गुगा प्रसाद वर्मा, रघुनाथ नृसिह मुघोलकर, पी० केसव पिल्ले, अंबिकाचरण मजुमदार, भूपेन्द्रनाथ वसु, प० विश्वन नारायण दर, लाला मुरलीघर आदि ने भी अपनी अमर सेवाओ-द्वारा उसे गौरवान्वित किया था। आगे आनेवाली पीढी इन सेवकों के प्रति सदा ऋणी रहेगी।

: 3:

कांग्रेस की प्रारंभिक नीति : १८८५-१६१५

काग्रेसं के प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इरादा नहीं है। एक-के-बाद-एक होनेवाले अधिवेशनों में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि १८८५ तक काग्रेस की नीति और उसके कार्यक्रम का रुख क्या रहा। इसके लिए प्रस्ताव के महत्वपूर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न भागों में बाट कर क्रमशः विचार करना उत्तम होगा।

इग्डिया कौंसिल

कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-मंत्री की कौसिल (इण्डिया कौसिल) तोड़ दी जाय। बाद के दो अधिवेशनो में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसने अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मत्री को परामर्श देने के लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और १६१३ में कराची-काग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन सशोधनों का भी उल्लेख कर दिया जिन्हें वह चाहती थी। इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में सशोधित प्रस्ताव पेश हुए। इसका कारण यह नहीं था कि कौसिल को तोडने की इच्छा उतनी प्रबल नहीं थी, बिल्क यह भावना कि जबिक इसके जल्दी तोड़ें जाने की कोई सभावना नहीं है तब इसका कुछ सशोधन ही हो जाय। वह कौसिल निरुपयोगी है, यह विश्वास तो बना ही रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १६१७ में शासन-सुधारों की जो योजना बज्ञाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा गया था।

वैधानिक परिवर्तन

आरंभ से ही काग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि उस पर शायद ही ३ कोई 'गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप लगा सके। काग्रेस के पहले अधिवेशन मे जो कुछ मागा गया'वह यही कि ''वडी और मौजूदा प्रातीय कौसिलो का सुधार और उनके आकार में वृद्धि होनी चाहिये। दूसरे अधिवेशन में काग्रेस ने कौसिलों के सुघार की एक व्यापक योजना पेश की। इसमे कौसिलो के आघे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धात मान लिया गया। कहा गया कि प्रातीय कौसिलो के सदस्यो का चुनाव तो म्युनिस्पल और लोकल बोर्डो, व्यापार-सघो तथा विश्वविद्यालयो द्वारा हो और बडी कौसिल का चुनाव प्रातीय कौसिलो-द्वारा हो । इतना ही नही , बल्कि सरकार को कौसिलो के निर्णय अस्वीकृत करने का अधिकार देने की बात भी इसमें मान ली गई, बशर्ते कि प्रातीय कौसिलो की अपील भारत-सरकार से और बड़ी कौसिल की अपील कामन सभा की स्थायी समिति से करने का अधिकार रहे। १८८७, १८८८ और १८८६ में भी यह प्रस्ताव दोहराया गया। १८६० में काग्रेस ने 'इडिया कौसिल एक्ट' में सशोधन करने वाले श्री चार्ल्म ब्रैडला के उस विल का समर्थन किया जो उन्होने पार्लमेट मे पेश किया था और काग्रेस की राय मे जिसमे काफी मात्रा में भारत के चाहे हुए सुघार मिलते थे । लेकिन यह बिल बाद मे छोड दिया गया । १८६१ मे काग्रेस ने अपने इस निश्चय का समर्थन किया कि जब तक हमारे देश की कौसिलो में हमारी जोग्दार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होगे तबतक भारत का शासन सुचार-रूप से और न्यायपूर्वक कदापि नही चल सकता। १८६२ में सुधार सवधों लार्ड क्रॉम का 'इडियन कौसिल एक्ट' पास हो गया । तब और बातो को छोडकर भारत-सरकार के नियमो और प्रातीय सरकारो द्वारा अपनाई हुई प्रथाओ पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत थी, काग्रेस ने अपना हमला शुरू किया । यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि १८६२ के सुधारों में कौसिलों

यहा इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि १८६२ के सुधारों में कौसिलों के प्रतिनिधि चुनने का कोई विधान नहीं था। म्युनिस्पल और लोकल वोर्ड आदि स्थानीय सस्थाओं और अन्य निर्वाचन-मण्डलों को कौसिल के लिए चुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त था वह सिर्फ नामजद करने के ही रूप में था। यहीं नहीं, बल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करना-न-करना सरकार परहीं निर्भर था, परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करतीं थी।

१८६२ में काग्रेस ने 'इण्डियन कौसिल एक्ट' को राजभिक्त के भाव से तो स्वीकार किया, परन्तु साथ ही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि स्वत उस एक्ट के द्वारा उन लोगों को कौसिलों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। १८६३ में एक्ट को कार्य-हप में परिणत करने की उदार-भावना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया कि यदि वास्तविक रूप में उस पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्त्तन करने

आवश्यक है। साथ ही पंजाब में कौसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गई। १८६४ और १८६७ में भी इन प्रार्थनाओं को दोहराया गया। १८६२ के सशोधन से १८६३ में कौसिलों के गैरसरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधि-कार मिल गया था, इसलिए १८६७ में काग्रेस ने प्रश्नकत्तीओं को प्रश्नों के आरंभ में प्रश्न पूछने का कारण बताने का अधिकार भी देने के लिए कहा गया; लेकिन उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ।

इसके बाद १६०४ तक काग्रेस ने इस विषय में कुछ नहीं किया। १६०४ में प्रत्येक प्रात से दो सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव-द्वारा कामन-सभा में भेजने और भारतवर्ष में कौसिलों का और विस्तार करने एवं आर्थिक मामलों में उन्हें भिन्न मत देने के अधिकार की भी माग की गई। साथ ही भारत-मन्त्री की कौसिल तथा भारत के प्रातों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया। १६०५ में काग्रेस ने जासन-सुधारों पर पुन जोर दिया और १६०६ में राय जाहिर की कि ब्रिटिश उपनिवंशों में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी जारी की जाय। १६०० में समय में पहले ही काग्रेस ने भविष्य में होनेवाले शासन-सुधारों पर प्रसन्न होना शुरू कर दिया, लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बदी थी। प्रतिनिधित्व की बात तो एक ओर, वस्तु-स्थिति यह हुई कि १६०६ के शासन-कानून के अन्तर्गत जो नियम स्वीकृत हुए उनमें तो उतनी भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन मार्ले ने इससे पहले अपने खरीते में प्रदिश्तित की थी।

यहा यह भी जान लेना आवश्यक है कि मॉर्ले-मिण्टो के नाम पर दस साल तक जिन शासन-सुधारों का दौर-दौरा रहा, वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार बनने वाली वडी (सुप्रीम) कौसिल में ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेप ३३ सदस्यों में से ज्यादा से ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, वाकी में ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित जातियों की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और दो अन्य सदस्य भी उसी के द्वारा नामजद होते थे जो प्रदेश विशेष के वजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित सदस्यों में भी बहुत-कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे, जैसे सात प्रातों में जमीदार, पाच प्रातों में मुसलमान, एक प्रान्त में (सिर्फ वारी-वारी से) मुसलमान जमीदार और दो व्यापार-संघ के प्रतिनिधि, इनके वाद जो स्थान वचते थे उनका चुनाव नी प्रान्तीय कौसिलों के गैर-सरकारी सदस्यो-हारा होता था।

मॉर्ले-मिण्टो शासन-सुधारो के अनुसार दो भारतवासी (आगे वढाकर तीन कर दिये गये) १६०७ में इण्डिया-कौसिल के सदस्य नियुक्त किये गये; एक को १६०६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला और एक-एक भारतवासी १६१० में मद्रास तथा वम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियो में नियुक्त किया गया। इसी साल बगाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी

सदस्य उसमें भी रखा गया। बाद को वह प्रात प्रेसीडन्सी (अहाते) की श्रेणी में रखा गया और स-कौसिल गवर्नर के मातहत हो गया। बिहार-उडीसा को मिला-कर १६१२ में स-कौसिल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के मातहत एक पृथक् प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वहा की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।

१६०६ में काग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। पहले प्रस्ताव में मजहव के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दी जाहिर की गई, दूसरे प्रस्ताव-द्वारा उत्तर प्रदेश, पजाब, पूर्वी बगाल, आसाम और ब्रह्मदेश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थ कार्यकारिणिया बनाने की प्रार्थना की गई, तीसरे प्रस्ताव में पजाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारों को असन्तोष-प्रद बताया गया और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार में कौसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रात के जमीदारों और जिला तथा म्युनिसिपल बोर्डों की ओर से बड़ी कौसिल के लिए चुने जानेवाले दो सदस्यों के निर्वाचन से वरार को महरूम रखने पर असन्तोप प्रकट किया गया। १६१० और १६११ में अमली तौर पर काग्रेस ने शासन-सुधार-सम्बन्धी अपनी १६०६ की आपत्तियों एव सूचनाओं का ही समर्थन किया और पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्तों को म्युनिस्पल तथा जिला-बोर्डों पर भी लागू कर देने का विरोध किया।

१६१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित किमया दूर न की जाने पर निराशा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा समस्त प्रान्तीय कौसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहें, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अपराधों (राजनैतिक) के लिए सत्ता पानेवालों को जिनमें नैतिक दोष न हों, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय और अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार कौसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय। पजाब में कार्यकारिणीं की स्थापना और स्थानीय सस्थाओं के लिए भी पृथक् निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की ताईद की गई। आश्चर्य की बात है कि काग्रेस के शासन-मुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी था कि 'जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।'

१६१५ में बम्बई में काग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारत-सरकार के सर्वप्रथम भारतीय लॉ-भेम्बर सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिह इसके सभापित थे। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा महासमिति को आदेश दिया गया कि शासन-सुधारों के सम्बन्ध में वह आल इण्डिया मुसलिम लीग की कमेटी से सलाह-मशिवरा करे। इसके फलस्वरूप सयुक्त भारत की आकाक्षाओं की द्योतक एक सम्मिलित योजना बनाई गई और १६१६ की लखनऊ-काग्रेस ने उसपर स्वीकृति की मृहर लगा दी। इसके अनुसार काग्रेस ने स्वराज्य की ओर एक निश्चित कदम बढाने की माग की और कहा कि भारतवर्ष

का दर्जा वढाकर उसे पराघीन देश के वजाय साम्राज्य के स्व-शासित उपनिवेशों के समान भागीदार वना दिया जाय।

इस योजना को प्रस्ताव-द्वारा स्वीकार करके ही काग्रेस सन्तुष्ट नही हो गई, विल्क सर्व-साधारण को इसे समझाने एव इसका प्रचार करने के लिए उसने अपनी एक कार्य-समिति भी वनाई। प्रधान मित्रयों ने श्री० एस० वरदाचार्य जैसे प्रसिद्ध वकील के पास, इसे भेजा और इसपर से भारतीय शासन-विधान का एक ऐसा सशोधक-विल तैयार करने के लिए कहा जिससे 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' में काग्रेस-लीग-योजना के अनुसार सशोधन हो जाय।

१६१७ की कलकत्ता-कांग्रेस में इस घोषणा पर कृतज्ञतापूर्वक सन्तोष प्रकट किया गया कि भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश्य है, पर साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि स्वय विधान में इसके लिए समय की कोई अविध नियत कर दी जाय, जिसके अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त हो जाय और शासन-सुधारों की पहली किश्त के रूप में सुधारों-सम्बन्धी कांग्रेस लीग-योजना को असली रूप दे दिया जाय।

मि० माण्टेगु नवम्बर १६१७ में भारत आये और माण्ट-फोर्ड-शासन-सुधार की रिपोर्ट जून १६१८ में प्रकाशित हो गई। सितम्बर १६१८ के बम्बई के विशेष अधिवरान में उसपर विचार हुआ। इसके सभापति श्री हसन इमाम थे। माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट मे प्रस्तावित शासन-सुधारो की योजना के आगे, जिसका मुख्य भाग द्वैध-शासन था, काग्रेस-लीग-योजना दव गई। नई (माण्ट-फोर्ड) योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल मे राज्यपरिषद् (कौसिल आफ स्टेट) के नाम से एक परिषद् का आयोजन किया गया, गवर्नर जनरल के सहायतार्थ प्रातो में बड़ी-बड़ी समितिया बनाई गईं और कौसिलो-द्वारा समर्थन न पानेवाली वातो के लिए गवर्नरो को अधिक अधिकार दिये गये। वम्बई के विशेष अधिवेशन ने निश्चय किया कि राज्य-परिषद् न रखी जाय, किन्तु यदि राज्य परिषद् वनाई ही जाय तो भारतीय-सरकार के लिए भी प्रान्तों की तरह रक्षित और हस्तान्तरित दिभागों की तजवीज की जाय, उसके कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हो और सर्टिफिकेट देने का नियम केवल रक्षित विषयों के लिए हो। साथ ही द्वैय-शासन स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय परिषद् की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्वैध-शासन जारी कर दिया जाय, यद्यपि माण्ट-फोर्ड योजना में यह दात नहीं थी।

इन प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात् राज्य-परिषद् को, वेकार कर दिया, विषोक्ति नेन्द्र में हैंघ-शासन की जो माग की गई थी उसे उसने मजूर नहीं जिया। वस्दई के विशेषाधिवेशन ने माण्ट-फोर्ड (शासन-मुधारो के) प्रस्तावों को कुत मिनाकर निराशाजनक और असन्तोषप्रद वतलाया और पहले के दो

अधिवेशनो की मागो की ताईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समानता, स्वतन्त्रता, जानमाल की सुरक्षा और लिखने-बोलने तथा सभाओ में सिम्मिलित होने की आजादी, शस्त्र रखने का अधिकार एव शारीरिक सजा सब प्रजाजनो पर एक-समान लागू करने के मौलिक अधिकारो-सम्बन्धी एक धारा जोडी, फिर भी सच पूछिये तो उसमें मि० माण्टेगु की ही पूरी जीत हुई। १६१८ का दिल्ली-अधिवेशन प० मदनमोहन मालवीय के सभापितत्व में हुआ और उसने भी इन्ही बातों की ताईद की, परन्तु उसने सब प्रातों के लिए द्वैध-शासन की नहीं, बिल्क पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की। दिल्ली-अधिवेशन में केन्द्रीय शासन में द्वैध-शासन-प्रणाली जारी करने के लिए कहा गया, पर परराष्ट्र-विभाग और जल-थल-सेना के विषय रक्षित मानकर उससे पृथक् रखे गये। द्वितीय परिषद् के बारे में बम्बई के विशेष अधिवेशन का प्रस्ताव ही दोहराया गया और उसके आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया।

११ नवम्बर १६१८ को सुलह की घोषणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का खात्मा हुआ। इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपति विलसन, प्रवान मन्त्री लायड जार्ज तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की घोषणाओं को उद्धृत कर, आत्म-निर्णय के सिद्धात को समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, काग्रेस ने निश्चय किया कि भारत पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रह कर दिये जाय, परन्तु इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

सरकारी नौकरियाँ

सरकारी नौकरियों में खासकर उच्च पदो पर, भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न को काग्रेस ने विशेष महत्व दिया था। १८३३ में कानून-द्वारा भारतीयों को सब पदों पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई थी और १८५३ में जब प्रति-स्पर्द्धी परीक्षाओं का आरभ हुआ तब कहा गया था कि उसमें भारतीयों के लिए बड़ी रुकावट है। लार्ड सेल्सबरी के शासन-काल में सिविल-सिवस की प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के उम्म में कमी की गई। इसे काग्रेस ने उन कठिनाइयों में और भी वृद्धि करना समझा, जो कि इसके लिए पहले से भारतीयों के सामने उपस्थित थी। भारतवासियों ने हमेशा यह माग की कि ये परीक्षाएँ इगलैंड और भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिये जिससे भारतीयों की कठिनाई दूर हो जाय। जून १८६३ में कामन-सभा ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षाएँ होने के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, जिसका काग्रेस तथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे ही साल सरकार ने घोषणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा। इससे सारा उत्साह नष्ट होकर गहरी निराशा छा गई। भारत की सरकारी नौकरियों के सवध में नियुक्त शाहीं कमीशन के सामने भारतीयों की जो गवाहिया हुई उनसे

यह वात स्पप्ट हो गई कि जबतक यह सुधार न हो जाय तब तक भारतीय मागो के साथ कदापि न्याय नही हो सकता।

दूसरे अधिवेशन में काग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस सवध मे विस्तृत व्यौरा तैयार किया और माग की कि प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ भारतवर्प और इगलैंड में साथ-साथ हो जिससे सम्प्राट के सव प्रजाजन बिना किसी भेद-भाव के उसमे भाग ले सके तथा योग्यता के अनुसार नियुक्तियो की क्रमागत सूची तैयार की जाय। चौथे अधिवेशन तक जाकर कही इस आन्दोलन में थोडी सफलता मिली। सरकारी नौकरियो (पवलिक सर्विसेज) के कमीशन ने अपनी रिपोंट में इस संवध में जिन सुविधाओं की सिफारिश की उनकी काग्रेस ने तारीफ की, परन्तु उन्हे अपर्याप्त बताया । इसमे सन्देह नही कि काग्रेस के इच्छा-नुसार इण्डियन-सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए वय-मर्यादा १६ से २३ कर दी गुँड थी, लेकिन दूसरी तरह से कमीशन की सिफारिशो पर जारी की गई सरकारी आज्ञा से स्थिति और भी खराब हो गई थी। क्योंकि उससे भारतीय उच्चाधिकारियो के लिए दो ही उपाय रह गये थे —या तो जिस स्थिति में स्टेच्युटरी सर्विस के मातहत वे उस समय थे उसी में बने रहे, या प्रान्तीय सर्विस में सम्मिलित हो जाय, जिनके सदस्यों के लिए शासन के सब उच्च पदो पर ताला डाल दिया गया था। स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्व-भारतीय नौकरियो के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ होती थी, दूसरे स्टेच्युटरी सनदी नौकरिया थी जिनकी है नौकरिया १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के लिए रक्षित थी, तीसरे सनदी नौकरिया थी जिनमें भारतीय ही भारतीय थे। १८६२ में काग्रेस ने पिंवलक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत सरकार के प्रस्ताव पर असतोप प्रकट किया और उसके वारे में कामन-सभा को एक प्रार्थना-पत्र भेजा। वात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६४१ नौकरियो में है पद १५८ भारतीयों के लिए रखें गये थे, परन्तु पब्लिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिए। भारत-मत्री ने उस 'चाहिए' शब्द को भी वदल कर 'दिये जा सकते हैं' कर दिया। इससे १५० में से, जो १०८ पद सरकार के हाथ में थे उममें से सिर्फ ६३ पद ही १८२ में भारतीयों को दिये गये। इसके वाद तो स्थिति और भी खराव हो गई। भारत-सरकार के तत्सवधी प्रस्ताव की भारत-मत्री ने अपने खरीते-द्वारा पुष्टि कर दी । फलत. १८६४ में जाति-भेद के आघार पर भारतीयो के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर लग गई, क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ननदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम से कम इतने अग्रेज अफसर तो रहने ही चाहिए। २ जून १८६३ को कामन-सभा ने इस आशय का जो प्रस्ताव पान किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनो देशों में साथ-नाप परीक्षाएँ होने का कम की घ्र अमल में ले आना चाहिए, उसका इससे वात्मा हो गया। इस प्रकार जबिक भारतवर्ष 'इण्डियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इजिन्यिरिंग, टेलीग्राफ, फारेस्ट और एकाउण्ट्स सिवसेल' (नौकरियो) में प्रवेश करने के लिए दोनो देश में साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ होने की सुविधा माग रहा था, सरकार ने १८६५ में उनसे उलटा रुख अख्तियार किया। शिक्षा विभाग की ऊची नौकरियो को दो भागो में बाट दिया गया—बडी अर्थात् आई० ई० अस० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात् पी०ई० एस० (प्रान्तीय), बडी नौकरियो की नियुक्ति इंग्लैण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रखा गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय बंगाल में उच्चपदस्य भारतीयों और अग्रेजों को एक समान वेतन मिलता था। दोनों का प्रार्थिक वेतन ५०० रुपये होता था, पर १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और १८८६ में २५० रु० ही रह गया, यद्यपि भारतवासी इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट होते थे। भारतवासियों के लिये अधिक-से-अधिक वेतन १८६६ में ७०० रु० था, चाह कितने ही समय की उनकी नौकरी क्यों न हो जाय, परन्तु अग्रेजों को अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,००० रु० मिलने लगते थे। नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कालेजों के प्रिन्सिपल होने से भी महरूम कर दिया जो अग्रेजों की पढाई के लिए रिक्त थे।

सैनिक समस्या

सैनिक समस्या पर भी काग्रेस ने घ्यान दिया। अपने पहले अधिवेशन में ही काग्रेस ने सैनिक खर्च की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। अगले वर्ष इस विना पर भारतीयों को सैनिक स्वयसेवक बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है उसमें यदि कोई खतरनाक वक्त आ जाय तो वे (ब्रिटेन की) सरकार के लिये बड़े सहायक सिद्ध होगे। तीसरे साल भारत की राजभिक्त और १८५८ की घोषणा में महारानी विक्टोरिया-द्वारा दिये गये वचन के आधार पर सेना-विभाग की ऊँची नौकरियों का दरवाजा भारतवासियों के लिए भी खोलने का मतालवा किया गया। इसके लिए काग्रेस ने देश में सैनिक कालेज की स्थापना करने के लिए कहा। चौथे और पाचवे अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई। छठ में कोई विचार नहीं हुआ, पर सातवे में इस पर चर्चा हुई और सरकार से आग्रह करते हुए यह मतालबा किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा सशोधन करें कि वे धर्म, जाति या वर्ण के भेद-भाव वगैर सव पर एक-समान लागू हो, साम्राज्य के जिस-जिस भाग में अधिक सैनिक प्रवृत्ति के लोग हो वहा-वहा अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धित प्रचित्त करके उनका सगठन किया जाय और भारत में सैनिक-विद्यालयों की स्थापना एव सैनिक-स्वयसेवकों की मर्त्तीं की प्रथा बारम्भ की जाय। इन प्रार्थनाओं

भीर विरोधों के होने हुए भी सैनिक व्यय में उनटे असाधारण वृद्धि हुई। तब आठमें अधिवशन में काग्रेस को यह माग पेश करनी पड़ी कि इस व्यय का एक हिम्मा इंग्लेण्ड को भी बरदाश्त करना चाहिए। नवे अधिवेशन न इस विषय के सामाजिए पहलू अर्थात् भारत की फीजी छावनियों में होनेवाली वंश्यावृत्ति एव छून की घीमारियों पर विचार किया और दसवे अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टि की। १६६४ में बेल्बी-कमीशन नियुक्त हुआ जो कि सैनिक व्यय को इंग्लैण्ड और भारतवर्ण के बीच विभक्त करने वाला था। ग्यारहवें और बारहवें अधिवेशनों में इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु मीमाप्रान्त में सरकार ने शो मीनि प्रत्य की थीं उनके फनस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इस पर विचार हुआ और सरकार ने शो की सम्बन्ध में इस व्यय में उन्लेण्ड को भी हिस्सा बटाना चाहिए। चौदर वे अधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय किया, परन्तु पन्द्रहवें अधिवेशन ने इसके एक नये परन्तु को स्पर्श किया। सीमाप्रान्त की लडाई खत्म हो जाने पर मोलहवें अधिवेशन में काग्रेन फिर सैनिक विद्यालय के प्रश्न पर जा पहुची। इस अधिवेशन के साथ उत्तीववीं नशे समाप्त हो गई। १६०१ में महारानी विवटोरिया भी

मे राष्ट्रीय नव-चेतना के समय भी साल-दर-साल सामने आनेवाले इस दुस्साघ्य विषय को भुलाया नही गया।

१६० में काग्रेस ने जोरो के साथ ३,००,००० पौण्ड के उस नये भार का विरोध किया जो रोमर-कमेटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोष पर लाद दिया था। १६०६ और १६१० में साल-दर-साल बढते जानेवाले सैनिक व्यय की आलोचना की गई। १६१२ और १६१३ के अधिवेशनों में सेना विभाग के उच्च पद भारतीयों को न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आकृष्ट किया गया। १६१४ में काग्रेस ने अपनी इस माग को फिर दोहराया कि सेना-विभाग की ऊची नौकरिया भारतवासियों को भी दी जाय, सैनिक स्कूल खोले जाय और भारतीयों को सैनिक-स्वयसेवक बनाया जाय। डचूक आफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किया। १६१७ में भारतवासियों पर से सेना की 'कमीशन्ड' जगहें मिलने की बाधा हटा ली गई और नौ भारतवासियों को ऐसी जगहें भी दी गईं। इससे उस अन्याय की आशिक पूर्ति हुई। फलत कलकत्ता में होनेवाली १६१७ की काग्रेस ने इस विषय में अपना सन्तोष प्रकट किया और १६ से १८ वर्ष तक की उम्र के युवकों की 'केंडेट कोर' प्रत्येक प्रान्त में सगिठत करने पर जोर दिया।

कानून श्रीर न्याय

ब्रिटिश-भारत में कानूनी सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के समय से आरभ हुआ। उन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विषय में जिन सुधारों का प्रतिपादन किया उनमे से एक यह भी था कि ज्ञासन और न्याय कार्यो को एक दूसरे से सर्वथा पृथक् किया जाय, लेकिन नतीजा कुछ भी नही हुआ। राजा राममोहन राय के बाद उत्साही कार्यकत्ताओं के एक दल ने जिसमें श्री दादाभाई नौरोजी सवसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथ में लिया। इसके लिए बगाल, बम्बई तथा मद्रास में सघ बनाये गये, जिनमें बगीय राष्ट्रीय-सघ खास तौर पर उल्लेखनीय था। शिक्षा-प्रचार के साथ-साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर के साथ बढा और १८८५ में काग्रेस ने इस प्रश्न को अपने हुन्थ में ले लिया । दूसरे अधिवेशन में काग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की कि शासन और न्याय-कार्यो का शीघ्र एक-दूसरे से पृथक् होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा गया कि ऐसा करने में खर्च बढाना पडता हो तो भी इसमे दरी न की जाय। अगले साल यह विषय और जूरी-प्रथा का प्रक्न, दोनो एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि मूल प्रस्ताव में ही अब उसका भी प्रवेश हो जायगा, लेकिन ऐसा हुआ नही। प्रति वर्ष काग्रेस इस प्रस्ताव को दोहराती रही और १८६३ मे तो यहा तक कह दिया गया कि न्याय और शासन-कार्यो का सम्मिश्रण भारत

कांग्रेस की प्रारंभिक नीति : १८८५-

के ब्रिटिश-शासन के लिए एक बडा कलक है, जिससे/
और समाज वाले लोगों को बेहद तकलीफ उठानी पडती
दो भूतपूर्व भारत-मिन्त्रयों (लार्ड किम्बरली तथा लु
धृत किय वे भी उसके समर्थक ही थे। और यह वस्तुः
िक वे मत जिम्मेदार अधिकारियों के थे, किसी एरे-गैरे व्योक्त
हुआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन बराबर जारी रहा। मदनमोहन जा हुआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन बराबर जारी रहा। मदनमोहन जा हसमें खास तौर पर दिलचस्पी ली और इसे अपने अध्ययन का मुख्य विषय वनाया। १८६६ में उनकी मृत्यु होजाने पर, बारहवें अधिवेशन में, काग्रेस ने उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हुए इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि 'न्यायालयों को शासन-कार्य से अलग रखने के विचार का इंग्लैण्ड और भारतवर्ष की जनता ने समर्थन किया है। १८६६ में इस अत्यन्त आवश्यक सुधार को कार्यान्वित करने के लिए कई प्रसिद्ध अग्रेज न्यायाधीश और सार्वजनिक सेवकों ने सपरिषद् भारत-मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेजा। इससे काग्रेस को और बल मिला। १६०१ में, काग्रेस ने देखा कि मामला आगे बट गया है और भारत सरकार इस पर गौर कर रही है। परन्तु १६०८ तक कोई अमली तरक्की नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसी साल काग्रेस ने इस बात पर सन्तोप प्रकट किया कि बगाल प्रान्त के लिए सरकार

जूरी के अधिकार कम करने और न्याय तथा शासन-कार्य सिम्मिलित रखने के पुराने घाव अभी हरे ही थे और उनमें सुवार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, कि १८६७ में एक नया घाव और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन (वगाल), १८१६ का दूसरा रेग्युलेशन (मद्रास) और १८२७ का पच्चोसवा रेग्युलेशन (बम्बई) ये तीन पुराने कानून प्रकाश में आये, जिनके मात-हत हर किसो को मुकदमा चलाये वगैर ही जलावतन किया जा सकता था। सर-दार नातू-बन्धुओ पर इस शस्त्र का प्रयोग किया गया, जो १८६७ के काग्रेस अधिवेशन होने के बक्त ५ महीने से अधिक समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखकर दग रह गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नही दिया गया था जिसे इन रेग्युलेशनों के अन्तर्गत देना जरूरी था।

ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि काग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया। इसके बाद

लगातार दो अधिवेशनो मे इसो निराशा का राग अलापा गया।

१८७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दी गई जो खुद उनके लिखे हुए नहीं थे। पूना में ताजीरी पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह (दफा १२४ए) तथा खतर की झूठी अफवाहे फैलाने-सम्बन्धी (दफा ५०५) धाराओं में ऐसा संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गई। काग्रेस ने

मे राााधारण के अधिकारो पर किये जाने वाले इस आक्रमण का विधिवत् विरोध विषया ।

दायमी वन्दोवस्त श्रीर श्रकाल

काग्रेस ने सबसे पहले नहीं तो भी आरभ में ही थोडे-थोडें समय के लिए होनेवालें जमीन के बन्दोबस्त पर भी घ्यान दिया। इलाहाबाद में होनेवालें काग्रेस के चौथे अधिवंशन ने अपनी स्थायी समिति को यह काम सौपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८६ के अधिवंशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। १८८६ में बाबू वैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुभिक्ष के कारणों की जाच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने दायमी बन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-मन्त्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होने यह भी बताया कि कभी-कभी तो लगान में बढाई हुई रकम गाव में पैदा होनेवाली फसल सभी बढ जाती है।

१८६२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, और कृषि-सम्बन्धी बैंको की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल भारत-मत्री द्वारा दिये गये उन वचनो की पूर्ति करने के लिये कहा गया, जो उन्होंने अपने १६६२ और १८६५ के खरीतो में दायमी बन्दोबस्त के लिए दिये थे। १८६६ में कांग्रेस ने अपने इख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के बाद दूसरा बन्दो-बस्त करने में कम-से-कम ६० साल की अविधि रखी जाय। १८०३ में कांग्रेस इससे भी आगे बढी और 'लगान अधिक न लगाया जाय' इसके लिए कानूनी तथा अदालती रकावटे लगाने के लिए कहा। १८०६ में कांग्रेस ने लॉर्ड कैंनिंग और लार्ड रिपन की नीति से, जो उन्होंने कमश १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के सबध में प्रतिपादित की थी, १६०२ में एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित लॉर्ड कर्जन की नीति की तुलना करके दोनों को परस्पर विरोधी बताया और इस विचार का विरोध किया कि भारतवर्ष में जमीन का लगान 'कर' नहीं बल्क 'किराया' है। १९०५ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश होकर अपने आप कांग्रेस ने इस विषय को छोडी दिया।

सिचाई-कर के प्रश्न पर काग्रेस ने केवल एक बार विचार किया और वहें १८६४ में हुए मद्रास के अधिवेशन में, जिस साल कि एक हुक्म निकालकर आब-पाशी का कर ४) से बढ़ाकर ५) प्रति एकड़ कर दिया गया था। इन दिनो लगातार जो दुभिक्ष हुए उनका आधिक कारण इन करो और महसूलो की लगातार वृद्धि होते जाना ही था। १८६६ के दुभिक्ष की परिस्थिति के कारण काग्रेस को सरकार की आधिक नीति का सिहावलोकन करना पड़ा। सरकार से कहा गया कि वह अकाल-रक्षक-कोष बनाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करे। दायमी बन्दोबस्त

कांग्रेस की प्रारंभिक नीति : १८८५-१९१५

और कृषि-सम्बन्धी वैकों तथा कला-कौशल सम्बन्धी स्कूलो की स्थापना को गरीबी, दूर करने का असली उपाय वतलाया गया। इसके बाद ही एक अकाल-कमीशन वैठाया गया। इसी बीच अकाल-पीडितो की सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुई उदारतापूर्ण रकमो के लिए घन्यवाद प्रकट करते हुए काग्रेस ने १,००० पीण्ड की रकम लन्दन के लार्ड मेयर के पास भेजने का निश्चय किया ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक बना दे। यह १८६८ की बात है। लेकिन ऐसा करते हुए काग्रेस ने उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रहीं थीं। १८६६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धों की उन्नति की जाय और जमीन का लगान तथा दूसरे करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की माग पेश की गई कि भारत-वासियों की आर्थिक अवस्था की जाच कराई जाय। इसके बाद क अधिवेशनों में हम इस विषय पर और कुछ नहीं पाते, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में काग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी वदल गया था।

कानून जंगलात

जगलात के कानूनो से हुए नुकसान को काग्रेस ने अच्छी तरह नही समझा। उनका मुकावला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता था, जिन्होंने लोगो पर असह्य वोझ डाल दिया था। १८६२-६३ में वडी नम्रता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जगलात के कानूनों से जो कठिनाइया उत्पन्न हुई है, खास-कर दक्षिण-भारत और पजाव के पहाड़ी इलाको में, उनकी जाच कराई जाय। पजाव-सरकार ने इस सम्बन्ध मे जो नियम बनाये वे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नवे अधिवेशन मे प० मेघनराम ने उन्हे अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-सरकार के लिए कलक-रूप वताया था। इनके अनुसार अगर कही आग लग जाती, फिर चाहे वह आकस्मिक हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उसपर काविज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो उसने जान-यूजकर कानून की परवाह न की हो। जिन पहाडी लोगो के लिए पहाड़ो पर पैदा होनेवाली घास या लकडी ही सब कुछ थी और जिसपर उनकी और उनके पराओं की जिन्दगी का दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गरी। यहा तक कि जगल में तापने के लिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके विरद्व हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर १८६४ को भारत-सरकार ने २० २२ एफ० का एक गन्ती प्रस्ताव प्रकाशित किया. जिसमें जङ्गलो के प्रवन्य में रैयतो की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रश्नो को कम महत्व देने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था।

इस पर काग्रेस ने अपने दसवे अधिवेशन में, आग्रह किया कि तीसरे और चौथे वर्ग के जगलों में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने को चीजें, मकान और खेती के औजार वनान के लिए सागौन और खाने की जङ्गली चीजें आदि, उचित प्रतिबन्धों के साथ, हर हालत में मुफ्त दी जाय और जगलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जाय जिससे किसानों को इस महकमें के कर्मचारियों से तग हुए विना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों का उपभोग करने की छूट रहें। ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस वात पर जोर दिया गया कि जगलात के कानूनों का उद्देश्य जङ्गलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं, बिल्क किसानों और उनके पशुओं के लिए उन्हें रक्षित रखना है। साथ ही इस वात की शिकायत भी की गई कि भिन्न-भिन्न प्रातीय सरकारों ने जो नियम बनायें हैं उनके अनुसार महकमें जङ्गलात के कामों से देहाती लोगों पर बुरा असर पड़ता है और वे उस महकमें के छोटें कर्मचारियों के दबाव और तकलीफ में पड़ जातें हैं। लेकिन १८६६ के बाद के अधिवेशनों में, जगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। सिर्फ एक बड़ा प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था।

व्यापार श्रीर उद्योग

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्याएँ थी, उनके खास-खास पहलुओं को काग्रेस के प्रारम्भिक राजनीतिज्ञों ने भली-भाति समझ तो लिया था, परन्तु ये समस्याएँ ऐसी थी कि उनको हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पडता था। यह बात वे जान गये थे कि लकाशायर के मुकाबले में भारतीय हित छोटे और गौण है, साथ ही यह बात भी उन्होंने बखूवी जान ली थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो, मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है।

१८६४ में काग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होनेवाले सूती माल पर कर लगाये जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि इस कर का निश्चय करते वक्त लंकाशायर के हितो के सामने भारतीय-हितो का विल्वान किया गया है। ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० नवम्बर से नीचें के भारतीय सूती माल को कर से मुक्त रखने पर लकाशायर वालो ने जो आपित की है वह वे-बुनियादी है। १६०६ में, दादाभाई नौरोजी के सभापितत्व में, कलकत्ता-काग्रेस का जो प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें प० मदनमोहन मालवीय ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे उद्योग-धन्घों के वारे में हमें सफलता क्यों नहीं

मिलती। उन्होने कहा कि हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो एसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का सरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों की शैशवावस्था में करते हैं।

लो० तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे ज्यादा खपत मध्य-श्रेणी वालो में ही है। उन्होने कहा कि हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृढ-निञ्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए। स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर और १६०६ तथा इसके बाद के वर्षों में बहिएकार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप भारतवर्ष का घ्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुन-र्जीवन की ओर खिच गया। गाव और उनके उद्योग-धन्धो एवं खेती की बरवादी की ओर भी भारतीय राजनीतिज्ञो का घ्यान गया। १८६८ में ही पं० मदनमोहन माल-वीय ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार को देशी उद्योग-धन्धो एवं कला-कौशल की उन्नती करनी चाहिए। १८९१ की नागपुर-काग्रेस में, उर्दू में भाषण करते हुए, ला० मुरलीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बडी जोरदार अपील की थी। काग्रेस के नवें अधिवेशन में पण्डित मदनमोहन मालवीय ने पुन अपना प्रभावशाली मत प्रकट किया। आगे चर्सकर सर एसं० सुब्रह्मण्य ऐयर ने हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के बाद १६१४ में गांवो के पुनर्जीवन और कर्जा-संस्थाओं की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया । १८६६ में ला० लाजपतराय की प्रेरणा पर काग्रेस ने आधा दिन शिक्षा एवं उद्योग-धधो के विचार में लगाया और इसके लिए एक उपसमिति कायम की । इन सब कार्रवाडयो के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता काग्रेस के साथ १६०१ में हुई। इसके बाद कमश. इसमे उन्नति होती गई। उद्योग-धन्धो की ओर काग्रेस का घ्यान १८६४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही आकृष्ट हुआ। इसका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन स्वयं गवर्नर-जनरल-द्वारा उसका विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नहीं गया। उसे उठाना तो दूर, उलटे लार्ड सेल्सवरी ने यह निर्देश किया कि भारतीय माल की प्रतिस्पर्छी से व्रिटिश माल को बचाने के लिए उपाय किये जायं। लगान का यह हाल था कि एक छोटे से जिले में १८६१ में ६६ फीसदी वढा, दूसरे में ६६ फी सदी और तीसरे में १६६ फी सदी हो गया और कुछ गावो मे तो ३०० से १५०० फी सदी तक वढा, जविक इसके साय-साथ फीजी खर्च भी बेशुमार बटता रहा।

उस तमय जर्मनी में भी सैनिक १४५ रु०, फ्रांस में १८५ रु० और इंग्लैण्ड में २८५ रु० वार्षिक व्यय होता था, परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७५ रु० सालाना खर्च किया जाता था, और यह उस हालत में जबकि भी आदमी की औसत आमदनी इंग्लैंण्ड में ४२ पौण्ड, फ़ास में २३ पौण्ड और जर्मनी में १८ पौण्ड थी और हिन्दुस्तान में सिर्फ १ ही पौड थी। ये अक १८६१ के हैं। अकालों के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए और मज्दूरी के सिलसिलें में सजा देने के कानून को उठा देने के लिए १८८७ में ही प्रस्ताव किया गया।

बहिष्कार श्रोर स्वराज्य

१९०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फैल गया, उसका मूल-कारण वग-भग था। पुण्य-नगरी काशी में जब काग्रेस का २१वा अधिवेशन १६०५ में हुआ तब उसमें वग-भग पर विधिवत् विरोध प्रदिशत किया गया और कहा गया कि वह रद्द कर दिया जाय। कम-से-कम उसमें ऐसा सशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा वगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वग-भग आन्दोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस काग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल-मोल था । १६०५ में जिस साहस का अभाव था वह १६०६ में आ गया। वग-भग पर एक प्रस्ताव करने के बाद काग्रेस ने बहिष्कार-आन्दोलन का भी सम-र्थन किया। इसके बाद काग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया। बस, गाडी यही रुक गई। दूसरे साल सूरत में काग्रेस के दो टुकडे हो गये और नरम-दल-वाली काग्रेस ने तो आगे के सालों में बहिष्कार को कतई छोड दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रखा और स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ मिण्टो-मॉर्ले सुधार-योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १६१० में नये वाइसराय लॉर्ड हार्डिङ्ग आये। उसी वर्षे काग्रेस ने उनसे राजनैतिक कैदियो को छोडने की अपील की। दूसरे साल फिर ऐसी अपील की गई। परन्तु १६१४ में जब मद्रास में काग्रेस का अधिवेशन हुआ तव उसने साहस करके सरकार से यह मतालवा किया, कि तारीख २५ अगस्त सन् १६११ के खरीते में प्रान्तीय पूर्णिधिकार के सम्बन्ध मे जो वचन दिया गया है उसे वह पूरा करें और भारतवर्ष को सघ-साम्राज्य का एक अग बनाने और उस हैंसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हो वे सब किये जाय।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

सभवत लोगो का अनुमान होगा कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रश्न आजकल ही खडा हो गया है, परन्तु ऐसा नही है। सर ऑकलैण्ड कॉलविन (१८८८) जब उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर थे तब इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमान काग्रेस के विरोधी है। यहां तक कि ह्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इसके विषय में एक लम्बा जवाब उन्होंने सर ऑकलैंण्ड को भेजा। मुसलमानो पर भी इस विचार का तुरन्त प्रभाव पडा। काग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी हुआ। उसमें शेख रजाहुसेन खा ने घडल्ले के साथ कहा कि मुसलमान नहीं, बल्कि उनके मालिक, सरकारी हुक्काम है, जो काग्रेस के मुखालिफ है।

लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विचार ने मूर्त-रूप धारण किया। मिण्टो की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वा-चन-संघ की तजवीज की गई थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ज्यो-का-त्यो कायम रखा गया था। इस सबध में जो बड़ी अजीब बात थी वह यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार रखा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी वाला जहा मतदाता हो सकता था वहा एक गैर-मुसलिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो सकता था। मुसलमान ग्रेजुएट को मतदाता बनने के लिए इतना काफी था कि उसे ग्रेजु-एट हुए तीन साल हो जाय; परन्तु गैर-मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तींन हजार रुपये और दूसरी तरफ तीन लाख रुपये । एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल ! १६१० में हालत वहुत नाजुक हो गई। सर डब्ल्यू० एमं० वेडरवर्न काग्रेस के सभापति हुए। उन्होने यह चाहा था कि हिन्दू और मुसलमानो की एक परिपद् की जाय, जिससे इस जातिगत प्रश्न पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियो और लोकल-बोर्डी में पृथक् निर्वाचन तरीके के जारी होने की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश मे, जहां कि पृथक् निर्वाचन नही था, यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानो की संख्या कुल आबादी की 🖁 होते हुए भी जिला-बोर्डी मे मुसलमान १८६ और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिस्पिलिटियो मे मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२ । यहाँ तक कि सर जॉन हचूवेंट जैसा प्रतिगामी उत्तर प्रदेश का लेफिटनेण्ट गवर्नर भी उस प्रान्त में दोनो जातियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के पक्ष में नहीं था। एक 'बर्न'सरक्यूलर अवश्य निकला था जोकि स्थानीय सस्थाओ मे जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमे यह प्रतिपादित किया गया था कि मुसलमानो को पृथक् निर्वा-चन के अलावा सयुक्त निवचिन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए; क्यों कि इससे दोनो जातियो में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद मिलेगी। इस पर १६११ में कलकत्ता-काग्रेस के सभापति प० विशन नारायण दर ने कहा था कि मै इतना ही कहूंगा कि हमारी एकता बढाने की यह उत्कण्ठा हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुण्डी लिखवा लेना है।

परन्तु इसके थोडे ही दिनो वाद दुनिया की हालतो मे एक भारी परिवर्तन हो गया।बालकन-राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुर्गो के लडने का अखाड़ा बना हुआ था, फिर एक बार नई लडाइयो का मैदान बन गया। तब १६१३ में नवाब सय्यद मुहम्मद बहादुर ने, जो कराची-काग्रेस के सभापित थे, यूरोप मेतुर्क-साम्राज्य की नीव उखाडने और ईरान के दम घोटने के प्रयत्नो की ओर घ्यान दिलाया। तुर्की साम्राज्य को लगे उस धक्के को जिस दु ख के साथ मुसलमानो ने महसूस किया उसी को उन्होने वहा प्रदिश्तित किया। अन्त मे उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानो को अपनी मातृभूमि के लिए कन्ध-से-कन्धा मिलाकर काम करने परवहुत जोर दिया। ऐसी परिस्थितिया थी जिनमे १६१३ की कराची-काग्रेस में हिन्दू और मुसलमानो ने अपने भेद-भाव मिटा दिये और मुस्लम-लीग के इस विचार को, कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों को स्वशासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू मुसलमानों के बीच मेल एव सहयोग का भाव बढाने वाले मुस्लिम लीग के कथन को पसन्द किया। काग्रेस ने मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदिशत इस आशा का भी स्वागत किया कि भिन्न-भिन्न जातियों के नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलो पर मिलकर एक साथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह कोशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति तथा तबके के लोगों से प्रार्थना की कि वे इस उद्देश्य की पूर्ति में हर तरह की सहायता करें।

उस समय काग्रेसवालों के मनोभाव कैसे ऊचे उठ रहे थे, इसका पता उन वक्ताओं के भाषणों की बढी-चढी भाषा से लगता है जो कराची में इस विषय के प्रस्ताव पर बोले थे। परन्तु इतना सब होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व ज्यों-का-त्यों वना रहा। जातिगत प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मिण्टो-मार्ले-योजना हिंदुस्तान के मत्थे जबरदस्ती मढ दी गई। लोगों से इस बारे में कोई सलाह-मशिवरा नहीं लिया गया। इसिलए १६१६ में जब सुधारों के नये टुकडे देने की तजवीज चली तब देश ने सोचा कि हिन्दू मुसलमानों का हृदयपरस्पर मिल जाना चाहिए। इसके लिए काग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिनिधि (नवम्बर १६१६) कलकत्ते में इण्डियन एसों-शियेशन के स्थान पर इस उद्देश्य से मिले कि १६१५ में काग्रेस ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय। वातावरण भी इसके अनुकूल था। परन्तु काग्रेस के हल्के में जो बडे-बूढे लोग थे वे अपनी तरफ से कुछ करने में आगापीछा करते थे। फलत यह काम युवको पर आ पडा। शायद उम्र में सवसे छोटे लोगों ने, जो उस समय मौजूद थे, आगे कदम बढ़ाया। लेकिन पृथक् जातिगत निर्वाचन अटल ही रहा।

प्रवासी भारतवासी

जहा भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराव थी, वहां दक्षिण-अफीका स्थित भारतीयों की हालत बद से बदतर हो रही थी। अखिल भारतीय काग्रेस के सामने पहले श्री मदनजीत ने दिक्षण का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें

सन्दह नही कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहा के पूरे ममाचार यहा की जनता तक पहुँचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रति वर्ष इसी उद्देश्य से जाते थे। अपने नारगी कपड़ो, ठिगने कद तथा नम्बी लाठी के कारण वह काग्रेस में कभी छिपे न रह सकते थे। दक्षिण अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुत पहला विरोध १८६४ में हुआ, जब कि अध्यक्ष नं इस आशय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह विल रह कर दिया जाय जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था । इसके बाद हर काग्रेस में दक्षिण अफीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया। १८६ में भारतीयों ने अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये । उसी समय गाधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया। इसमें भी सबसे अधिक अफसोस की बात यह थी कि तत्कालीन वाइसराय लार्ड एलगिन ने इस कानून के पास होने पर सहमति टी थी और उस समय के भारत-मन्त्री लार्ड जार्ज हैमिल्टन हमें 'जगितयो की जाति' कहकर सतुष्ट हुए थे। १६०० में भूतपूर्व वोअर-जनतन्त्र ब्रिटिंग-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६वें अधिवेशन (१६००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र वोअरो पर नियत्रण करने मे सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई है, इसलिए अब नेटाल मे प्रवेश-सम्बन्धी पावन्दिया और डीलर्स लोडमैन्स-कानून उठा देने चाहिए। १६०१ की १७वी काग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी ने दक्षिण-अफीका-प्रवासी लाखो भार-तीयों की ओर से प्रार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश विया था । १६०२ मे भारत-मन्त्री ने इस प्रदन पर एक शिष्ट-मण्डन भी मिला, ेकिन कोई नतीजा न निकला। कायेन ने १६०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावो को दोहराया। बिटिन-सरकार के जिम्मेदार हतको मे बोअर-युद्ध के जितने कारण पापित किये गये थे. उनमें से एक यह भी था कि विदिश-मस्राट की भारतीय प्रजा

होनेवाले कठोर, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया और यह चेतावनी दी गई कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के हितो को भारी हानि पहुचेगी।

१६०६ से काग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि का कोई परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की काग्रेस में श्री गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए अधिकारियों के विश्वासघात और गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-सग्राम का वर्णन किया। अब प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) का महान् सग्राम शुरू हुआ। इसके लिए १८,०००) का चन्दा भी जमा हो गया। इसके अलावा सर जमशेंद जी ताता के दूसरे पुत्र श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २४,०००) दिया। काग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १६१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का सग्राम अपनी चरम सीमा पर पहुच गया था। काग्रेस ने ट्रान्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम, साहस और त्याग की प्रशसा की, जो अपने देश के लिए वीरतापूर्वक कैंद भोगते हुए, और अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी, अपने प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्वक और स्वार्थहीन लडाई लड रहे थे।

काग्रेस का २७ वा अधिवेशन (१६११) अधिक आशामय वातावरण में सम्पन्न हुआ, इसमें रिजस्ट्रेशन और गिरिमिट-सम्बन्धी एशिया-विरोधी कानूनो को रद कराने पर ट्रासवाल के भारतीय समाज तथा गांधीजी को हार्दिक धन्यवाद दिया गया। अगले साल (१६१३) भी गिरिमट-कानून की अनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने अपने वचनों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश-सम्राट से काग्रेस ने इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिङ्ग वाइसराय थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई का रुख लिया और उन्हें अधिक बलशाली बनाने के लिए कराची-काग्रेस ने १६१३ में शर्तबन्दी कुली-प्रथा को नष्ट करने का अपना प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद शीध्र ही यह प्रथा तोड़ दी गई। काग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आशिक समझौते के लिए लॉर्ड हार्डिङ्ग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १६१६ और १६१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार करना पड़ा। कराची-अधिवेशन में गांधीजी तथा उनके अनुयायियों के वीरतापूर्ण प्रयत्नों तथा भारत के आत्म-सम्मान की रक्षा और भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रश्ना में एक प्रस्ताव पास किया गया।

कनाडा की प्रिवी कौसिल ने 'लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आज्ञा देकर भारतीयों के प्रवेश की मनाही कर दी थी। इस सबध में भी कराची-काग्रेस ने १९१३ के २८ वे अधिवेशन में इस आधार पर इसका विरोध किया। कनाडा की इस घारा को तोड़ने के लिए बाबा गुरुदत्तिंसह नामक एक सिख सज्जन ने 'कोमागाटामारू' जहाज किराये पर लिया और हागकाग या टोकियो बिना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिखो को कनाडा ले गये। कोमागाटामारू जहाज के यात्रियो को कनाडा में उतरने नही दिया गया। इससे जहाज को भारत लौटना पड़ा। वापसी पर यात्रियो को बजवज से, जहा वे उतरे थे, सीधा पजाब जाने की आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियो ने सीधे पजाब जाना पसन्द नही किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी बात तो सुन ले, हमारे साथ इस हुक्म से अन्याय होता है और इसमें आधिक हानि भी बहुत होगी। सीधे पजाब जाने के बजाय, उन्होंने गिरफ्तार हो जाना अधिक अच्छा समझा। फलस्वरूप दगा हुआ, कुछ आदमी मारे गये, कुछ गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तिसह ७-६ साल तक गुम रहे और उडीसा, दक्षिण भारत, ग्वालियर, राजपूताना, काठियावाड और सिन्ध में १६१८ तक घूमते रहे। इसके बाद बम्बई जाकर महाल बन्दर में बल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैंनेजर हो गये। अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १६२१) में वह गाधीजो से मिले। गाधीजीने उन्हे गिरफ्तार हो जाने की सलाह दी। बावाजी ने इस परामर्श को कार्यान्वित किया और २६ फरवरी १६२२ को वह लाहौर-जेल से उस आडिनेन्स की अविध समाप्त होने पर छोडे गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार किये गये थे।

नमक-कर का विरोध

१६३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो उठा था। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-कमीशन की सिफारिशे जानते हें उन्हें यह जान कर वहुत आश्चर्य होगा कि १८८८ में काग्रेस ने इस कर का विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश्य ब्रिटेन के जहाजी व्यवसाय और निर्यात व्यापार को बढाना था; बिल्क इस आधार पर किया कि "नमक-कर में हाल ही में की गई वृद्धि से गरीब लोगो पर भार और भी वढ गया है, और इसके द्वारा सरकार ने ज्ञान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोप में से खर्च करना शुरू कर दिया है जो खास मौको के लिए साम्राज्य की एक मात्र निधि है।" १८६० में काग्रेस ने नमक-कर में की गई वृद्धि को वापस लेने की—न कि नमक-कर को हटाने की—माग की। दूसरे अवसरो पर काग्रेस ने केवल इसी प्रार्थना को दुहराया और एक वार १८६२ में इस प्रश्न पर अन्तिम वार विचार करते हुए काग्रेस ने यह भी कहा कि इस समय जो बहुत-सी बीमारिया फैल रही है उनका एक खास कारण (नमक-

कर के कारण) नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है। इसके बाद 'नमक' काग्रेस से उठकर कौसिलों में पहुच गया और वहा श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहे।

शराव श्रौर वेश्यावृत्ति

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि काग्रेस उस पर घ्यान दिये विना न रह सकी। शराव की बढ़ती हुई खपत को देखकर सयम और मद्य-निवारण की माग की गई। मि० केन और स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और १८८६ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास हुआ। काग्रेस ने भी कामन-सभा वाले प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने का अनुरोध किया। १८६० में काग्रेस ने शराव पर आयात-कर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराव पर कर लगाने, बङ्गाल-सरकार के ठेके पर शराव बनाने की पद्धित को दूर करने के निश्चय तथा मद्राम-सरकार द्वारा ७,००० शराव की दूकानें बन्द करने पर हर्ष प्रकट किया। इसके वाद दस साल तक काग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया। १६०० में काग्रेस ने सस्ती विकनें के परिणाम-स्वरूप शराब की बढ़ती हुई खपत को देखकर सरकार से प्रार्थना की कि वह अमेरिका के भेन लिकर लाँ के समान कोई कानून बनाए और सर विलफीड लॉसन के 'परिमिसव बिल', या 'लोकल आप्शन एक्ट' के समान कोई बिल पेश करें और दवा के सिवा दूसरे कामो के लिए आनेवाली नशीली वस्तुओ पर अधिक कर लगाए।

राज्य-नियतित वेश्या-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बन्धित एक विषय था।
यह सब जानते हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों तथा युद्ध-यात्राओं में
स्त्रियों को एकते करती थी। जब ऐसी बाते पहले-पहल अमल में लाई गईं तब
बहुत भीषण मालूम हुईं, लेकिन ज्यो-ज्यो उनका सहवास बढ़ने लगा त्यो-त्यों क्षोम
कम होता गया। काग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की अध्यक्षता
में उन भारत-हितैषियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य
की ओर से बननेवाले कानूनों और नियमों को पूर्णत्या रद कराने के लिए इंग्लैण्ड
में कोशिश कर रहे थे। कैप्टेन बैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि
२,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेश्यावृत्ति के कृत्सित उद्देश्य से
इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असयत जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए थे।
इलाहाबाद में होनेवाले आठवें अधिवेशन (१८६२) में एक बार फिर सरकार
हारा नियमित अनैतिक कार्यों का विरोध किया गया था। अगले साल इण्डियाआफिय-किमटी के पार्लमेण्ट के सदस्यों ने छावनियों की वेश्यावृत्ति तथा छूत-रोगोसम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और प्रथाओं के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की। कार्येस

ने इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को बन्द करने के लिए स्पष्ट कानून बनाने की मांग की।

स्त्रियां श्रोर द्लित जातियां

मि॰ माण्टेगु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का दावा भी देश के सामने आया। वस्तुतः यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत में शीघ्र ही पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिये गये। कलकत्ता-काग्रेम ने १६१७ में यह सम्मित प्रकट की थी कि शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली निर्वाचित सस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार खडे होने की, स्त्रियों के लिए भी, वहीं शर्ते रखीं जायं जो पुरुषों के लिए हैं। इसीसे मिलते-जुलते दलित जातियों के प्रश्न पर भी, इसी काग्रेस ने एक उदार प्रस्ता व स्वीकार किया।

श्रन्य विषय

इस अविध में काग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की ओर घ्यान दिया। शिक्षा के विविध पहलुओ—प्राथमिक, विद्यापीठ, पुरातत्व और कला-कौशल-सम्बन्धी शिक्षा में काग्रेस ने वहुत दिलचस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चादी-कर, आय-कर और विनिमय-दर के मुआवजे आदि आर्थिक विषयों पर भी काग्रेस प्राय. घ्यान देती रही। स्थानीय स्वराज्य-सस्थाओं और विशेषतः मद्रास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के सम्बन्ध में प्रतिगामी कानूनों से काग्रेसी वहुत रुष्ट हुए। स्वास्थ्य और विशेषत प्लेग और क्वारण्टीन तथा वेगार वगरा पर भी कभी-कभी विचार हो जाता था। राज-भिक्त की शपथ भी कई बार ली गई। १६०१ में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु और १६१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर काग्रेस को अपनी राजभिक्त फिर प्रकट करने का अवसर मिला। एडवर्ड और जार्ज पचम के स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये।

कांग्रेस का विधान

काग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-सम्बन्धी इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते हैं कि काग्रेस की स्थापना किसी जॉइण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह 'ऑटिकल्स' या 'मेमोरेण्डम आफ एसोशियंगन' बनाकर या १८६० के २१ वे कानून के अनुसार 'रिजस्टउं सोसाइटी' की तरह पहले में ही नियमादि बनाकर नहीं हुई थीं। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई थीं। शुरू में १८८६ में काग्रेस के नचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर गम्भीरता से विचार हुआ।

एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए किमटी तो बना दी गई, लेकिन विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड दिया गया। फिर भी पूरे साल भर काग्रेस के काम को चलाने की आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने लगी। १८८६ में काग्रेस के प्रतिनिधि इतनी बड़ी सख्या में आये कि काग्रेस को प्रति दस लाख जन-सख्या के पीछे पाच प्रतिनिधियों की सख्या सीमित कर देनी पड़ी। भारत में काग्रेस का एक सहायक-मत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैंण्ड की समिति को भी एक वैतनिक मन्त्री दिया गया। इस पद पर पहले-पहल सुप्रसिद्ध मि० डब्ल्यू० डिग्बी सी० आई० ई० नियुक्त हुए।

काग्रस के चौथे अधिवेशन (१८८६) में जब यह निश्चय किया गया कि जिस प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्वसम्मित से या लगभग सर्वसम्मित से आपित्त करेंगे, वह विषय-समिति में विचार के लिए पेश नहीं किया जा सकेंगा। यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीकृत हुआ, जो सूरत के झगड़े के बाद १६०८ में बनाया गया था, फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्वसम्मित के बजाय है कर दिया गया। प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव १८८६ में पास हुआ, लेकिन अमल में वह दूसरे वर्ष ही लाया गया।

इंग्लैण्ड में किये जानेवाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह इसीसे मालूम होता है कि १८६२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश-समिति और काग्रेस के पत्र 'इण्डिया' के खर्च के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८६६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। १८६८ में काग्रेस के विधान को बनान का नया प्रयत्न किया गया। मद्रास-काग्रेस ने विधान का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उस पर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक समिति भी बनाई । अगले साल (१८६६) लखनऊ में एक सम्पूर्ण विधान स्वीकृत हुआ। उस समय तथा १६०८, १६२० और १६२६ में काग्रेंस ने अपने जो-जो ध्येय निश्चित किये, उनकी तुलना बडी मनोरजक होगी। लखनऊ में काग्रेस का ध्येय इस प्रकार निश्चित हुआ "वैध उपाय से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हितों को बढाना अखिल-भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का घ्येय होगा।" लखनऊ-विधान के अनुसार कार्य-सचालन के लिए काग्रेस द्वारा निश्चित ४५ सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इन ४५ में से ४० सदस्य ऐसे चुने गए थे जिनकी विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो ने सिफारिश की थी। सिमिति के एक अवैतिनिक मन्त्री और एक वैतिनिक सहायक मन्त्री रखे गये। साल के खर्च के लिए ५०००) स्वीकृत किए गये। इसमें से २५००) तो गत अधिवेशन की स्वाग्त-समिति पर और २५००) आगामी अधिवेशन की स्वागत समिति पर डाले गये।

रथायी काग्रेस किमिटियों की स्थापना तथा प्रान्तीय सम्मेलनों के आयोजन-हारा कांग्रेस का काम पूरे साल-भर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष का चुनाव तथा प्रस्तावों के मसविदे बनाने का काम इण्डियन काग्रेस-सिमिति करती थी। सात ट्रिट्यों के नाम पर कांग्रेस के लिए एक स्थायी कोप भी स्थापित किया गया। प्रत्येक प्रान्त से एक-एक ट्रस्टी काग्रेस नियुक्त करती थी। १६०० में ४५ सदस्यों वाली इण्डियन काग्रेस सिमिति और वडी कर दी गई। पद की हेसियत से इतने व्यक्ति और सदस्य मान लिये गये—सभापित, मनोनीत सभापित, जिस दिन से नामजद किया जाय, पिछली काग्रेसों के सभापित; काग्रेस के मन्त्री और सहायक मन्त्री तथा स्वागत-सिमिति-हारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मन्त्री।

लन्दन में कार्य का संगठन १६०१ में गुरू किया गया। 'इण्डिया' पत्र को और गुनाए-रूप से चलाने के लिए उसकी ४००० कापिया विकने का इस तरह प्रवन्ध किया गया कि प्रत्येक प्रान्त एक नियत सख्या में 'इडिया' खरीदे। 'इण्डिया' और ब्रिटिश-समिति का खर्च पूरा करने के लिए १६०२ से प्रत्येक प्रतिनिधि से फीस के अलावा १०) और लेने का भी निश्चय किया गया। यह स्पष्ट है कि उन दिनों काग्रेस भारत और इगलैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही नहीं करती थी। वम्बई के २० वे अधिवेशन (१६०४) में यह निश्चय किया गया कि पार्नमेण्ट के चुनाव से पहले इग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए २०,०००) इकट्ठे किये जाय। काशी में (१६०५) काग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी समिति बनाई गई। १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने काग्रेस का उद्देश्य एक शब्द में रूप दिया—"हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्वराज्य में आ जाता है। इगलैण्ड या उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है, वहीं भारत में भी जारी की जाय" और इसके लिए अनेक मुधारों की मंग की गई।

कलकत्ता-कार्यम का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लवालव था। उनिलए राष्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम वढाया गया और निर्चय किया गया कि प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी में उस तरह प्रान्तीय याप्रेस निर्मित का नगठन करे, जिस तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निर्चय किया जाय। कार्यस के तमाम विषयों में प्रान्तीय कार्यन कमिटी प्रान्त की ओर ने कार्य विषय-निर्वाचिनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। यह माना गया कि समिति के ५५ सदस्य प्रतिनिधि रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिये जायगे जिसमें काग्रेस होगी। उस वर्ष के सभापित, स्वागत समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के सभापित और स्वागत-समिति के अध्यक्ष, काग्रेस के प्रधान मन्त्रीगण और काग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मत्री भी अपने पद के अधिकार से विषय-निर्वाचिनी समिति के सदस्य माने जायगे।

काग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुत युग प्रवर्तक था। सूरत के झगड़ के कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद में 'कन्वेशन' खड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विधान बनाया। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित सभापित बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि सूरत में डा॰ रासिबहारी घोष के चुनाव पर ही बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद लोगों के विचार का वास्तिवक विषय था, काग्रेस का 'कीड' यानी घ्येय। सूरत-काग्रेस के भङ्ग के एक दिन बाद २८ दिसम्बर (१६०७) को वैसे ही विचार रखनेवाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया—"काग्रेस का उद्देश्य है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत के लोगों के लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और जिम्मेदारियों में सम्मिलत होना"।

१६०८ के विधान के अनुसार महासमिति के विभिन्न प्रान्तों से सदस्य चुने गये, यह भी तय हुआ कि यथासम्भव कुल सख्या का ५ वा भाग मुनलमान सदस्य चुने जाय। इसके अलावा भारत में उपस्थित या भारत में रहनेवाले काग्रेस के सभापित और प्रधान मत्री भी महासमिति के सदस्य माने जाय। काग्रेस का प्रधान मत्री इसका भी प्रधान मत्री समझा जाय। इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी बहुत बढ गई। महासमिति के सभी सदस्य और कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये हुए प्रतिनिधि ही इनका चुनाव करते थे।

सयुक्त बङ्गाल-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी ने काग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो इलाहाबाद (१६१०) में एक उप-सिमित को सीपे गये। १६११ के कल-कत्ता-अधिवेशन में इस सिमिति की सिफारिशे स्वीकार कर ली गई और अगले सशो-धनो के लिए विधान महासिमित के सुपूर्व किया गया। इसके बाद ५ सालो तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १६१४ में जब यूरोप का महासमर छिड गया, तब श्रीमती एनी बेमेन्ट ने अपना महान राजनैतिक आन्टोलन अ० भा० होमरूल-लीग की छत्रछाया में आरम्भ किया। इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में २३ अप्रैल १६१६ को एक पृथक् होमरूल-लीग स्थापित की। इसके बाद १६२० में काग्रेस के विधान में परिवर्तन हुआ। कलकत्ता-काग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को

स्वीकार कर चुकी थी। नागपुर के अधिवेशन ने काग्रेस के विधान मे अनेक संशोधन किये। काग्रेस का १६०८ वाला ध्येय 'समस्त शान्तिमय और उचित उपायो से भारतीयो द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' में बदल दिया गया। सम्पूर्ण काग्रेस-कार्य नये सिरे से सगठित किया गया। भापा-कम के आधार पर प्रान्तो का पुर्निवभाजन किया गया। आन्ध्र को पृथक् बनाने का प्रश्न १६१५ और १६१६ में उठाया गया था और १६१७ में सभापित डॉ॰ एनी बेमेण्ट तथा मद्रास के अनेक प्रतिनिधियों के तीव्र विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया गया। १६१७ में तो गाधीजी की भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न सुधारो तक स्थिगत कर दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य तिलक की दूरदिशता थी जिससे आन्ध्र को पृथक् प्रान्त का रूप दे दिया गया। इसीके परिणाम-स्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार और संशोधन करके अपनी रिपोर्ट महासमिति में पेश करने के लिए एक और उपसमिति बनाई गई। इसके बाद ही सिध ने भी अपने पृथक् प्रान्त बनाये जाने की माग की। यह मागभी स्वीकृतहो गई, लेकिन कर्नाटक और केरल की मागो का तब फैसला हुआ, जब १६२० के नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुर्निवभाजन हुआ।

:8:

दमन-नीति और नई जागृति : १८८५-१६१५

पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लडाई-झगडो में जो काग्रेस नेता थे वे ज्यादातर वकील-बैरिस्टर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि भारत सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पालमेण्ट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नपी-तुली भाषा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की उज्च पदं देकैं र इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय काग्रेस की स्थापना की थी। उसके द्वाराण का क्षेत्र ही और उच्च अकाक्षाओं को प्रदिश्ति करते थे। उस युग की परिस्प्रियर तो काग्रेस कि अपने दुख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दली ऐयर १६०८ करने तथा नई रिआयतों और विशेपाधिकारों के लिए मामूली माग्त्र कर्त्ता-धर्ता कुछ नहीं हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीघ्र हीए तत्कालीन रूप में परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रत्रीण-वृद्धि और दूसरी आदियों और शील और भावना-प्रधान वक्तृत्व-कला, दोनों ने उस काम को अपने ऊर ही थे कि जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने थे। काग्रेस के प्रस्तावों के स सर गंकरन

व्याख्यान होते थे और काग्रेस के अघ्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमे दो बाते हुआ करती थी—एक तो प्रभावकारी तथ्य और आकडे, दूसरे अकाटच दलीलें। उस समय जब भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-प्रदर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख अख्तयार किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नीव में छ फीट नीचे जो ईट, चूना और पत्थर गडे हुए हैं क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है वियोक्त वहीं तो हैं जिनके उपर भारी इमारत खडी हो सकी है। पहले उपनिवंशों के ढड़्ज का स्वशासन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, इसके बाद स्वराज्य और सबसे उपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मजिले एक-के-बाद-एक बन सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के समर्थन में अग्रेजों के प्रमाण देने पडते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानिया की थी। आज अगर हमारा रास्ता साफ है तो यह सब हमारे उन्ही पुरुखाओं की बदौलत है जिन्होंने जगल-झाडियों को साफ करने का कठिन काम किया है।

काग्रसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोब के भाव आ गये हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि १८८५ से १६०५ तक काग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी वैध-आन्टोलन के प्रति उनका दृढ और अग्रेजो की न्याय-प्रियता पर अटल विश्वास । इसी भाव को लेकर १८६३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दयाल-सिह मजीठिया ने काग्रेस के विषय में कहा था कि भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है। आगे चलकर उन्होने यह भी कहा कि हम उस विधान के मातहत सुख से रह रहे हैं जिसका विरुद है आजादी, और जिसका दावा है सहिष्णुता। काग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद १८८८) के प्रतिनिधि ने लार्ड रिपन का यह विचार उद्धृत किया था "महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलहनामा नही है, न वह कोई राजनैतिक लेख ही है, बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है।" लार्ड सेल्सवरी के इस वचन पर कि "प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रथा पूर्वी लोगो की परम्परा के मुआफिक नही है," जोर के साथ नाराजगी प्रकट के संयुक्त बेड्न १८०० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो यहा तक कह दिया था सुझाये, जो इलाहन का कोई अन्देशा नही है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अन्त मे जाकर कत्ता-अधिवेशनर अवश्य घ्यान देगे ।" बारहवे अिववेशन (१८६६) के अध्यक्ष-पद धनो के लिए वितुल्ला सयानी ने तो और भी असदिग्ध रूप में कहा था कि "अग्रेजो परिवर्तन नहीं रा ईमानदार और मजबूत कौम इस सूरज के तले कही नहीं है।" एनी बेमेन्ट नेउस कीम ने हिन्दुस्तानियों के अनुनय-विनय और विरोध का जवाब छत्रछाया में से दिया, तब भी मद्रास काग्रेस (१८६८) के अध्यक्ष आनन्दमोहन १६१६ को देकर कहा था कि "शिक्षित-वर्ग इगलैण्ड के दोस्त है, दुश्मन नहीं। विधान में पी। मने जो महान कार्य है उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक

मित्र और सहायक है।" हमारे इन पूर्व-पुरुषो ने अंग्रेजो और इंग्लैण्ड के प्रति जो विश्वास रखा वह कभी-कभी दयाजनक और हेय मालूम होता है; परन्तु हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझे।

काग्रेस के इतिहास में जो पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाच वर्षी (१६०६ से १६११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा जो जगली समझे गये। हालां उसमें इघर-उघर मारकाट भी हो गई, मगर अन्त में उसमें पूरी सफलता मिली। आखिर १६११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वग-भग रद कर दिया गया। किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रश्नसा का विषय बन गया। इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया और धुआधार वन्तृताओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकाश होने लगा। परन्तु इसी के साथ काग्रेसियों ने उन दु खदायी कानूनों की तरफ से अपना ध्यान नहीं हटाया, जो १६११ और उससे भी आगे तक जारी रहे। काग्रेस के बड़े-वृद्धों ने, अपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों और दमनकारी कानूनों को हटवाने में लगाई, परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय-प्रश्न के अशो का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। १८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने स्व-शासन का समर्थन किया था। २० वे अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी काटन ने 'भारत के संयुक्त राज्य' अथवा 'भारत के स्वतन्त्र और पृथक् राज्यों के सघ' की कल्पना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किगडम या उपनिवेशो-जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्न किया था।

सरकारी प्रलोभन

काग्रेस के पहले पच्चीस सालों में जिनके ऊपर काग्रेस की राजनीति का दारो-मदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे। यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही सिद्ध होती है जो समय-समय पर उनके द्वारा की जाती थी, बल्कि स्वय सरकार भी उनके साथ रिआयते करके और हिन्दुस्तानियों को ऊचे पद देकर यही सिद्ध करती थी। ऐसे उच्च पदों के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावत सबसे उपयुक्त था। मद्रास के सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर तो काग्रेस के पहले ही अधिवेशन में सामने आये और श्री बी० कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ में होनेवाली मद्रास की पहली कनवेशन-काग्रेस के एक मात्र कर्ता-धर्ता थे। वह बहुत कड़े विधान के मातहत हुई थी और इसके लिए तत्कालीन मद्रास गवनर ने अपना तम्बू देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियों और काग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहनेवाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर ही थे कि जो अग सड-गलकर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए। सर शंकरन् नायर अमरावती में हुए अधिवेशन (१८६७) के सभापित हुए थे। और तो और श्री रमेशन् (सर वेपा सिनो) १८६८ से काग्रेसवादी ही थे। इसके बाद जिनका नम्बर आता है वे हैं (१) श्री टी॰ बी॰ शेषिगिर ऐयर, जो १६१० की काग्रेस में सामने साये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम् ऐयर जो १६० में श्री कृष्णम्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहो मद्रास हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्यकारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये-एक मद्रास में और दूसरा दिल्ली मे। इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १६०६ में काग्रेस के सभापति होनेवाले थे, परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। श्रीमती वेसेण्ट द्वारा चलाये होमरूल-आन्दोलन के सनय, १९१४ में, वह फिर काग्रेस के क्षेत्र मे आ गये । इतना हो नही, उन्होने अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया। उससे मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनो ही उनसे नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हैसियत से जो पेन्शन उन्हें मिलती थी उसे वन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्तु वाद में कुछ सोच कर फिर ऐसा नही किया गया। और आगे चले तो सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी काग्रेसी थे, जो बाद मे कार्यकारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही हाल सर मुहम्मद हबीवुल्ला का हुआ ! वह पहले मद्रास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाय गये। मद्रास-सरकार के लॉ-मेम्बर होनेवाले सर एन० कृष्ण नैयर १६०४ की काग्रेस में बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० बी० रेड्डी तो १६१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एव सुप्रसिद्ध काग्रेसी थे। सर एम॰ रामचन्द्रराव बहुत समय तक काग्रेस में रह चुके थे।

कलकत्ता में श्री ए० चौधरी जिन्होने वग-भग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहा की हाईकोर्ट के जज वना दिये गये। १६० में जव लार्ड मिण्टों ने भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तब दो नाम उनके सामने थे, एक तो श्री आगुतोष मुकर्जी का और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह का। सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह १८६६ की कलकत्ता-काग्रेस में, देशी-नरेश को विना मुकदमा चलाये निर्वासित कर देने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) तरजीह काग्रेसमैन को ही दी गई। इसी प्रकार १६२० में गवनर-जनरल की कार्य-कारिणों में जब जगह हुई तब भी लॉर्ड चम्सफोर्ड (१६२०) ने तो महाराजा वर्दवान को रखना चाहा, पर मि० माण्टेगु ने बड़ी कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० माण्टेगु ने श्री श्रीनिवास शास्त्री का नाम इमके लिए सुझाया, लेकिन चूकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री बीं० एन० शर्मा को रखा,

जो अमृतसर-काण्ड के समय भी सरकार के पृष्ठ-पोषक थे। बंगाल में काग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊंचे सरकारी ओहदे मिले उनमें श्री एस० के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य हैं। इनमें श्री दास १६०५ की काग्रस-कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न पर बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय बगाल की कार्यकारिणी के सदस्य।

उत्तर प्रदश में सर तेजबहादुर सपू-जैसे जबरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया गया। बिहार के मय्यद हसनइमाम १६१२ की काग्रेस को पटना में आमंत्रित करने के बाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सिन्चिदा-निन्दिसह को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहा यह भी बतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी ओहदो का देना ही नहीं रहा। फिरोजशाह मेहता को १६०५ में 'सर' की उपाधि दी गई और वह भी लॉर्ड कर्जन-द्वारा जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। तात्पर्य यह कि सरकार को भी अगर योग्य भारतीयों की जरूरत हुई तो इसके लिए उसे भी काग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी और उनके राजनीतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के ओहदों के लिए नाकाबिल मान लेती।

दमन-नीति का सूत्रपात

काग्रेस का इतना महत्व स्वीकार करते हुए भी सरकार उसके प्रति सदैव सतर्क रहती थी और उसकी जड खोदने के लिए दमन नीति से काम लेती थी। जब-जब जनता में कोई आन्दोलन आरभ होता था तब-तब जोरो का दमन किया जाता था और उसमे यह नीति रखी जाती थी कि जबतक लोग अन्दोलन करते-करते बिलकुल थक न जाय तबतक उनकी मागो पर कोई ध्यान न दिय। जाय। लॉर्ड लिटन का १८७० का प्रेस-ऐक्ट जो जल्द ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व सूचना थी। राष्ट्र के बढते हुए आत्मचैतन्य का दूसरा उत्तर शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दू ख-रूपी फोडे को और भी पका दिया। १८८६ में इन्कम टैक्स ऐक्ट बना। उसका भी तीव्र विरोध उसी समय किया गया। जैसे-जैसे काग्रेस हर साल बढती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखते गये। लॉर्ड डफरिन ने ह्यम माहब को यह सलाह दी थी कि वह काग्रेस का क्षेत्र केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनाये। किन्तु वही लॉर्ड डफरिन फिर काग्रेस के शत्रु हो गये और उसे राजद्रोही कहने लगे। १८८६ में वाइ-सराय ने कलकत्ता में और १८८७ में मद्रास के गवनर ने काग्रेस का स्वागत किया, परन्तु बाद में उत्तर प्रदेश के सर ऑकलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक उसके विरीधी हो गये । इन महाशय ने काग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी। शायद उन्हें यह पता न था कि ह्यूम साहब ने भी आरम में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड डफरिन के कहने से ही उन्होंने इसे राजनैतिक सगठन का रूप दिया था। सर ऑकलैण्ड की सम्मित में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मद्रास के अधिवेशन से उग्र रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि काग्रेस का सरकार की निन्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार क प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में राज-भक्त और देश-भक्त ऐसे दो भेद खड़े हो जायगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि काग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जो दावा करती है, वह ठीक नहीं है। ह्यूम साहब ने इसका मुहतोंड जवाब दिया। इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में काग्रेस को अकथनीय कठिनाइया का सामना

इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइया का सामना करना पडा। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली। श्रीमती एनी वेमेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सज्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के विरुद्ध मद्राम (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुए थे और उनसे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,०००) की जमानत मागी गई थी। हालत तेजी से खराब होती गई और १८६० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ गया। बगाल-सरकार ने सब मित्रयों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गश्ती-पत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि भारत-सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओं में दर्शक-रूप में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग लने की भी मनाही की जाती है। इसी प्रकार २५ जून १८६१ को भारत-सरकार ने देशी रियासतों के प्रेसी पर अनेक पाबन्दिया लगाने के लिए एक गश्ती-पत्र जारी कया था।

१८६३ में कौसिलें और बड़ी कर दी गई और जनता के थोड़े से प्रतिनिधि उनमें लें लिये गये। इस तरह लोक-प्रतिनिधियों की सख्या बढ़ जाने पर सरकार ने आवश्यक समझा कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषा-धिकार मिले हैं वे कम कर दिये जाय। पहले शिक्षा-विभाग में यह नियम बनाया गया था कि उसमें भारतीयों और यूरोपियनों के लेने में कोई भेद-भाव न रखा जाय, परन्तु उनकी योग्यता में जहां समानता कायम रखी गई वहां दरजे में विषमता ला दी गई। इसके बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहों पर लिये ही नहीं गये, उनका दरजा और वेतन भी कम कर दिया गया। होमचार्जेज का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पौण्ड से बढ़कर १३० लाख पौण्ड हो गया। २०वीं सदी के पहले पाच माल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी, सरकारी गुप्त-समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लाना जिससे शिक्षा महंगी हो गई, भारतीयों के चरित्र को 'असत्यमय' वताना, वारह सुधारों का वजट, तिब्बत-आक्रमण (जिसे पीछें से तिब्बत-मिशन का नाम दिया गया) और अन्त में वग-विच्छेद—ये सब लॉर्ड

कर्जन के ऐसे कार्य थे, जिनसे राज-भक्त भारत की कमर टूट गई और सारे देश में एक नई जागृति पैदा हो गई।

बग-भग ने बगालो भाषाभाषी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रातों में बाट दिया था। इसके पारेणाम-स्वरूप जहा जनता में एक व्यापक और जबरदस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहा सरकार ने भी उग्रता से दमन शुरू कर दिया। जलूस, सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे, और उधर सरकार उन्हें रोक देती थी। हडताले होती थी और विद्यार्थी तथा नागरिक एक-सी सजा पाते थे। शिक्षणालयों के नियम और भी सख्त कर दिये गये तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक दिया गया। पूर्वी बगाल के लैफ्टिनेण्ट गवर्नर सर बैम्फील्ड फुलर ने बड़े- बड़े प्रतिष्ठित नागरिकों को बुलाकर रक्तपात की धमकी दी। इसके साथ ही पूर्वी बगाल में गुरखा पलटन के आने की घोषणा भी की गई। यह सब तब हुआ, जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार जनता में हिसा की भावना का चिह्न तक नहीं पाया जाता था। ऐसी दशा में सरकार की दमन-नीति का उलटा प्रभाव पडता था। प्रत्येक प्रान्त ने बगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को जोडकर आन्दोलन को और भी अधिक गहरा रग दे दिया था। 'कैनल कालोनाइजेशन बिल' ने पजाब के सैनिक प्रदेश में एक नया उत्साह भर दिया था। इस सबध में लाला लाजपतराय और सरदार अजितसिह को देश-निकाले की सजा दी गई थी।

राजनैतिक सभाओ तथा प्रदर्शनो में विद्यार्थियों को सिम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन सुरू हुआ। केवल पूर्वी बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाई स्कूल खुल गये और भूतपूर्व जिस्टस सर गुरुदास वनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए वग जातीय विद्या-परिषद् की स्थापना की गई। बाबू विपिनचन्द्र पाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १६०७ में आन्ध्र-देश में उनका दौरा बहुत ही ज्ञानदार और सफल रहा। राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाई स्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रैनिग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें मानपत्र दिया। इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-सग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की बेरोक दमन-नीति ने देशभक्तों और वीर सिपाहियों को पैदा किया।

१६०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस कियात्मक प्रस्तावो पर जोरो से अमल किया। जहा वगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव तथा आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलो और विश्व विद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, वहा स्वदेशी का अ। सम्पूर्व देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक वार गु

Ų

गया। इस बार करघे में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विटेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया।

वगाल से नौ नेता निर्वासित किए गये—कृष्णकुमार मित्र, पुलिनविहारी दास, क्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अक्वनीकुमार दत्त, मनोरजन गुह, सुवोधचन्द्र मिललक, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। य नेता वगाल को और विशेषकर युवक बगाल को सगठित कर रहे थे। पराक्रम और गौर्य उस समय आदर्श थे। दूसरी तरफ सर बैम्फील्ड फुलर के आदर्ग 'गुरला सेना' नथा 'यदि आवश्यक हो तो खून-खरावी' थे। १६०० में स्थिति चरम-सीमा को पहुच गई थी। अखबारो पर मुकदमें चलाना एक आम वात हो गई। 'युगान्तर', 'सध्या', 'वन्देमातरम' नई जाग्रति के प्रचारक पत्र थे, वे सब बन्द कर दिये गये। 'सध्या' के सम्पादक देशभक्त ब्रह्मवाधव उपाध्याय अस्पताल में मर गये। अनेक किंत्नाइयो और तीन मुकदमों से गुजरने के बाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड-कर पाडेचरी चले गये और वहा आश्रम बनाकर रहने लगे।

३० अप्रैल १६०८ को मुजफ्फरपुर मे दो स्त्रियो, श्रीमती और कुमारी कैनाडी, पर दो बम गिरे। ये बम स्थानीय जिला जज किन्सफोर्ड को मारन के । लेये बनाये गये थे। इस अपराध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम बोस को फासी की सजा मिली। उसकी तसवीरे गारे देश में घर-घर फैल गई। स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दल के सम्पादकत्व में निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमो मे हिसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस युवक को लम्बी सजा भिली, तब उसकी बूढी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्ष प्रकट किया और बगाल की ५०० स्त्रिया उसे बधाई देने उसके घर गई। 'वन्देमातरम्' मे राजविद्रोहात्मक लेखो के लिए श्री अरविन्द पर जो मुक-दमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम में अपवाद न था। महाराष्ट्र में १३ जुलाई १६०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये जौर उसी दिन आन्ध्र में श्री हरि सर्वोत्तमराव तथा दो अन्य स्ज्जन पकडे गये। पाच दिनो की सुनवाई के बाद लोक-मान्य तिलक को छ साल देश-निकाले की सजा मिली। १८६७ में छुटी हुई छू मास की कैंद भी इसके साथ जोड दी गई। आन्ध्र के श्री हरिसर्वोत्तमराव को नी महीने की सजा मिली। सरकार ने इतनी थोडी मजा के खिलाफ अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी मजा वढाकर तीन साल कर दी। राजद्रोह के लिए पाच साल् सजा देना तो उन दिनो मामूली वात थी। इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह देश स गायव हो गया । वास्तव मे वह अन्दर-ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह वम तथा पिस्तील ने ले ली। १६०८ में राजद्रोही सभावन्दी-कानून तथा 'प्रेस-एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल बाद किमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट भी बन गया। सभावन्दी

विल पर वहस करते हुए श्री गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि "युवक हाथ से निकले जा रहे हैं और यदि हम उन्हें वश में न रख सके तो हमें दोप मत देना।" कभी-कभी इक्के-दुक्के राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमें सब से साहस-

कभी-कभी इक्के-दुक्के राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमे सब से साहस-पूर्ण खून १६०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन वाइली का हुआ। यह खून मदनलाल धिगड़ा ने किया था, जिसे बाद में फासी दी गई। अभियुक्त को बचान की कोशिश करने वाले डॉ० लालकाका नामक एक पारसी सज्जन को भी फासी की मजा दी गई। लाहौर (१६०६) में होनेवाले काग्रेस के २४वे अधिवंशन में सभापित पं० मदनमोहन मालवीय ने इन घटनाओ तथा नासिक के कलक्टर मि० जैक्सन की हत्या पर दु ख प्रकट किया। लन्दन में रहनेवाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समर्थक थे। मिण्टो-मॉर्ले सुधारो, अथवा भारत-सरकार और मद्रास एव वम्बई की सरकारों की कौसिल में भारतीयों के लेने से भी यह बढा-चढा वैमनस्य शान्त न हुआ। जब तक वग-विच्छंद उठा न लिया जाय, तब तक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रोव जाता था। तब वंग-भग के कारण जो साप-छछूदर की-सी हालत हो गई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूँढा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हार्डिङ्ग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड कू भारत-मत्री वने, तब भारत में ब्रिटिश-नरेश जार्ज पचम के राज्याभिषेक-महोत्सव का लाभ उठाकर वंग-भग रद कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आये।

जब यह कहा जाता है कि वग-भग रद कर दिया गया, तब यह समझना चाहिए कि स्थित यथापूर्व कर दी गई। पहले पश्चिमी वगाल और आसाम-सहित पूर्वी वगाल के रूप में वग-भग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। पहले बिहार को पिंचमी वगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर और उठीसा के साथ मिलाकर एक प्रान्त बना दिया, अर्थात् आसाम के साथ पूर्वी और पिंचमी वगाल के दो प्रान्तों के वजाय अब तीन प्रान्त हो गये—वगाल एक प्रान्त, बिहार छोटा नागपुर और उडीसा दूसरा प्रान्त और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्याभिषेक के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, यह अब उडीना को पृथक् प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया।

दन सब नफलताओं के बाद काग्रेस का वाधिक अधिवेशन (कलकता, १६११) बहुत खुशी के साथ मनाया गया। श्री मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने, बगाल को गर भारत में भियनेवाली मदद के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए यह उच्च आगा प्रकट की थी कि भारत भी स्वशाशन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतन्त्र सथ-माम्राज्य का एक अभिन्न अग बनेगा। लेकिन इन सब आशाओं और खुशियों में लोग राज-द्रोह, मनाबन्दी-जानून (१६०८), प्रेस-एवट (१६०८) और श्रिमिनल लॉ एमेण्ड-मेण्ड भाट (१६१०) को मृत नहीं थे। इन्हीं के द्वारा तो जनता की आजादी की जड पर कुल्हाडा चलाया गया था। इन सबसे बढकर १८१८ का रेग्युलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तो के रेगुलेशन अब तक मौजूद थे, जिनके अनुसार १९०६-८ के देश निकाले की सजा जगह-जगह दी गई थी। भारत में बननवाले कपडे पर 'उत्पत्ति-कर' भी अब तक मौजूद था। इनकी बढौलत जान-माल की स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता तथा उद्योग-धन्धों के हित खतरे में थे।

१६१२ मे राजनैतिक खिचाव कुछ-कुछ कम हो गया था। लेकिन इसी वर्ष एक भारी दुर्घटना हो गई। लॉर्ड हाडिङ्ग जब जलूस के साथ हाथी पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवश कर रहे थे, किसी ने उन पर वम फेका और वह मरते-मरते वने। इस घटना के वाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिमसे प्रेस-एक्ट को रद करने की लगातार आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड़ लिया। काग्रेस कई सालो तक इसका विरोध करती रही। १६०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अविक खराब था, जिसे १६१० में स्थायी कानून वना दिया गया।

माण्टफोर्ड-सुघारों के बाद किर्मिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोडकर वाकी सब दमनकारी कानून रद कर दिये गये। वग-भग के रद किये जाने अार अहिंसा-वाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त तकलीफें झेलनी पडती थी। इथर राजनैतिक वानावरण में जो एक स्तब्धता और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १६१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-कान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोष-जनक घटना हो गई। बग-भग के दिनों से ही मुसलमानों ने राष्ट्रीय आदर्शों से अलग रहकर नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रखा था। १६१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" काग्रस ने १६१३ में मुस्लम लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

जुलाई १६१४ में महासमर छिड गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का दरवाजा खटखटा रहा था, लाई हार्डिङ्ग ने भारतवर्ष से फौज वाहर भेज दी। इग्लैण्ड वडी आफत में था। भारत में फौज इमलिए रखी गई थी कि वह इग्लैण्ड के लिए भारत की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तव भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या? मार्सेल्स में एक दिन भी आराम किये बगैर भारतीय फौज फ्लार्ड्स-रणक्षेत्र में, जहा अग्नि वर्षा हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने मित्रराष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुचने पर १६१५ के फरवरी-मार्च में उनपर आ जाती। १६१४ की काग्रस में स्वशासन की माग फिर की गई। श्रीमती बेसेण्ट ने लॉर्ड पेण्टलैण्ड के समय में होमरूल का महान् आन्दोलन उठाया। वही पुराना कार्यक्रम—स्वदेशी, विहण्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल—पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने मदनल्ली-स्थित अपनी थियोसोफिकल शिक्षण-सस्थाओं का सरकारी विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध तोड दिया और अडचार में एक राष्ट्रीय हाई स्कूल खोल दिया। सिन्ध तथा अन्य प्रान्तों में भी उन्होंन एक स्कूल खोला और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नित के लिए डॉ० अरण्डेल के सभापितत्व में एक शिक्षा-सिमित मंगीठत की। श्री बी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से सगठन किया। दोनो पहले ही से काग्रेस में काम करने लग गये थे। 'न्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमोन्द्वारा होमरूल-लीग का खूब प्रचार तथा कार्य होता था। विद्यार्थी भी आन्दोलन में बडी शक्ति वन गये थे, पर लॉर्ड पेण्टलैण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया था। फलस्वरूप आन्दोलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और श्रीमती वेसेण्ट तथा मि० अरण्डल तथा वाटिया १६ जून १६१७ को उटकमण्ड में नजरवन्द कर दिये गये।

: ሂ :

मत-भेद का अन्त: १६१५-१६

श्रात्म-विश्वास की भलक

सन् १६१५ से भारतीय राजनीति में एक नये युग का श्रीगणेश हुआ। इनका मुख्य कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ थी। जापान ने हस पर जो विजय प्राप्त की थी उनसे, एशिया की जातियों में अपनी वीरता और क्षमता के कारण आत्मिविस्वाम की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के अयर पर, १६१४ की कड़ाके की सर्दी में, फ्लैण्डर्स और फ्रांस के मैदानों में, जर्मन-नेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फींजों ने जिस अद्भुत वीरता, धैर्य और सहन्यीलता के साथ सफनतापूर्वक मुकावना किया था उसमें एशिया और यूरोपीय देशों पर भारतवासियों की खान्मी धाक वैठ गई थी। पित्वमी देशों की द्रित में नो वे ततने ऊने उठ गये थे जितने अभी तक कभी नहीं थे। भारतीय फींजों बारा गत्म में की गई सेनाओं के फलस्त्रहण कुछ भारतवानियों के हृदय में तो पुरक्तार की और पुछ के हृदय में अपने अधिकारों की मावना जाग्रत हो गई थी। नर मुरेज्यनाथ बनर्सी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती बेमेण्ड दूसरे दल के लोगा ने थी।

नेतृत्व का श्रभाव

वैसे तो मि० बैडला के समय से ही श्रीमती बेसेण्ट का सारा जीवन गरीबो और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ था, लेकिन काग्रेस में वह १६१४ में ही सिम्मलित हुई। उन्होने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टिकोण और सगठन का एक बिलकुल ही नूतन ढग लेकर काग्रेस-क्षेत्र मे पदार्पण किया। इस समय काग्रेस में दो दल थे-एक नरम दल और दूसरा राष्ट्रीय दल । दोनो दलो में पर्याप्त मतभेद था । इसके साथ ही काग्रेस काकोई मार्ग-प्रदर्शक भी नही था। इस कारण १६१५ के आरभ मे देश की वास्तविक अवस्था अच्छी नही थी। १६ फरवरी १६१५ को गोखले का स्वर्गवास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वृद्धा-वस्था-जन्य निर्वलताएँ अपना अधिकार जमाती चली जा रही थी। लोकमान्य तिलक जून १६१४ में मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य ले लिया था, लेकिन वह सदैव फिसड्डी ही रहे । पडित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नही थी कि वह नरम मार्ग पर काग्रेस का नेतृत्व करते। उनमे न वह शक्ति एव मानसिक दृढता ही थी जिससे वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते । गाधीजी तो उस समय देश मे आये ही थे। उन्होने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढग पर श्रीगणेश भी नही किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत के अनुसार चल रहे थे। वे इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि एक मुद्दत से वह वाहर विदेशों में रहे थे। लाला लाजपतराय अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्येन्द्रप्रसन्न सिह (वाद में लार्ड) जिन्होने १६१५ की बम्बई की काग्रेस का सभापतित्व किया था, इस समय नई धारा के साथ विलकुल मेल नही खा रहे थे। इसलिए बम्बई-कागेस के वाद उन्होने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्राय राष्ट्र के हाथ से निकल कर नौकरशाही के हाथो मे जा रहा था। नरम दल-वालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीय दल अभी तक अपने को सम्हाल न पाया था। श्रीमती वेसेण्ट का १६१४ तथा १५ का दोनो दलो (नरम दल और राष्ट्रीय दल) को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था। असफलता की इस कहानी का यहा सक्षेप में अवलोकन करना अनुचित न होगा।

समभौते का प्रयत्न

लोकमान्य निलक जून १६१४ में जेल से छूट कर आये थे। वह राष्ट्रीय दल के नेता थे। आते ही उन्होने अपने कार्य-क्रम में तीन वातो को स्थान दिया

(१) काग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुन संगठन करना और (३) एक दृढ तथा सुसगठित विराट् होमरूल-आन्दोलन चलाना। इन तीनो वार्ता में से पहुली के लिए लोकमान्य तथा राष्ट्रीय-दल के लोग यह चाहते थे कि काग्रेस के प्रतिनिधियो के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाय। अबतक काग्रेस के विधान के अनुतार काग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार केवल कुछ सस्थाओं को ही था। इस कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेण्ट और काग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सुब्बाराव पन्तुलु दिसम्बर १६१४ के प्रथम सप्ताह मे पूना गये। उन्होने लोकमान्य तिलक, गोंखले तथा अन्य नेताओ से परामर्श किया। एक संशोधन पर सव राजी हो गये। फिर श्री सुन्बाराव, सर फिरोजशाह से परामर्श करने के लिए बम्बई गये, परन्तु वह विलकुल निराश होकर लौटे। फिर वह तिलक तथा गोखले से मिले। गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का काग्रेस में पुन प्रवेश काग्रेस के पुराने झगडे के लिए एक सिगनल का कार्य करेगा। इस-लिए उस मशोधन के प्रति अपने समर्थन को उन्होने वापस ले लिया और इसके सम्बन्ध मे उन्होने श्रीमती बेसेण्ट की जवानी कहला दिया। उन्नीसवी काग्रेस के मनोनीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होने अपने विचार बदलने के कारणो का उल्लेख भी किया। कुछ ही समय मे वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया। उसमे यह लिखा था कि तिलक ने खुल्लम्खुल्ला अपने यह विचार प्रकट किये हैं कि वह 'सरकार का बहिष्कार करेगे' और यदि वह काग्रेस में घुस गये तो आयरलैंड वालो की भाति अडंगा-नीति का अवलम्बन करेगे। इस सम्बन्ध मे श्रीमती वेसेण्ट ने जब जांच-पड़ताल की तब तिलक ने इस बात का खडन किया। इसपर उनसे क्षमा-याचना भी की गई। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की बात स्थगित ही रही। इसी बीच गोखले की मृत्यु हो गई।

१६१५ और १६ में तिलक ने अपने दल को सगिठत करने के लिए घनघोर प्रयत्न किया। उनका विचार था कि एक सुदृढ दल के लिए (१) आकर्षक नेता, (२) एक विशेष लक्ष्य और (३) एक युद्ध-घोप जरूरी है। जोसेफ विष्टस्टा के रूप में लोकमान्य को एक वहत ही योग्य सहयोगी मिल गये। उन्ही के सभा-पित्त्व में पूना में राष्ट्रीय दल के लोगों की एक परिषद् हुई, जिसमें एक हजार व्यक्ति सिम्मिलत हुए। इस परिषद् में और वाद को जो नरम दलवालों का एक सम्मेलन हुआ उसमें जमीन-आसमान का अन्तर था। नरम-दल की परिषद में वहुत थोडी उपस्थिति थी और लॉर्ड विलिगडन ने पधार कर उसकी जोभा वढाई थी। पूना-परिषद् से लोगों को होमरूल' के रूप में एक 'युद्धघोप' मिल गया। अब लोकमान्य के पास एकमात्र कार्य यह रह गथा था कि किस प्रकार भार लक्ष्य तक ले जाय। उनकी इच्छा थी कि मजदूर-दल के नेताओ-द्वार

में पार्लमेण्ट में एक बिल पेश कराया जाय और स्वय अपनी सारी शक्तियों को एक विराट् आन्दोलन में केन्द्रीभूत कर दिया जाय।

१६१५ की काग्रेस का अधिवशन बम्बई में होने जा रहा था। चूिक मेलमिलाप के सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे, इसिलए यह काग्रेस नरम दल
वालों की ही थी। काग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात् नवम्बर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिह, जिनकी योग्यता और
रतवे की सर्वत्र धाक थी, इस काग्रेस के सभापित चुने गये थे। वैसे काग्रेस के साथ
उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा था, लेकिन उनके सभापितत्व से बबई काग्रेस के।
वह सारी प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त हुई जो सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेम्बर के नाम
के साथ जुड़ी रहती थी। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका भाषण अत्यन्त प्रतिगामी था।
उनके विचार से भारत के भविष्य के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी
जिससे एक ओर तो उठती हुई पीढ़ी की महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति हो और दूसरी ओर
वे लोग भी उसे मजूर कर ले जिनके हाथ में भारत का भाग्य सौपा हुआ है। इसी
विचार से वह ऐसी नीति की घोषण। चाहते थे।

लेकिन बम्बई की सन् १९१५ वाली काग्रेस के प्रति जनता के उस अनुराग के चिह्न फिर से दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-काण्ड के बाद विलीन हो गयेँ थे। लखनऊ-काग्रेस और उसके वाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। बम्बई की काग्रेस मे २२५६ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विषयो पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। वे प्रस्ताव उन प्रस्तावो के सार मात्र थे जो काग्रेस के जन्म से लेकर समय-समय पर काग्रेस में पास होते रहे थे। १६१५ की एक वडी दिलचस्प घटना यह हुई कि गाधीजी विषय-समिति के सदस्य नही चुने जा सके। इसलिए सभापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति में नामजद किया। वम्बई-काग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने काग्रेस के विधान में ऐसा महत्वपूर्ण सशोधन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी काग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे, क्योंकि यह तय हो गया था कि उन सस्थाओ द्वारा बुलाई गई सार्वेजनिक सभाएँ काग्रेस के लिए प्रति-निधि चुन सकेगी जिनकी स्थापना १६१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश्य वैध-उपायो से ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना हो। लोक-मान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। उन्होने तुरन्त ही इस बात की सार्वजिनक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आशिक रूप में खुले द्वार से काग्रेस में प्रवेश करने को सहर्प तैयार है।

दो होमरूल लीगों की स्थापना

सन १९१६ का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, काग्रेस-कार्य के लिए और

भी गुभ हुआ। इधर देण वहे-वहे घक्को के कारण और भी असहाय हो गया था, क्योंकि १६१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए तो अभी तक कोई स्थान ही नही था, क्योंकि वम्वई में जो सम्मीता हुआ था उमके अनुसार उन्हें पूरे साल भर तक इन्तजार करना था। इसी के वाद वह काग्रस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर अपने ढग से चला सकते थे। अत उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का निश्चय किया। इस नाजुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओ और त्याग के कारण नेतृत्व करने के लिए पूर्णत योग्य थे। उन्होंने काग्रस को एक शिष्ट-मण्डल इन्लैण्ड भेजने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन एसा हुआ नही। तव उन्होंने २३ अप्रैल १६१६ को अपनी होमरूल लीग की स्थापना की। इसके ६ मास वाद श्रीमती वेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लीग खडी की। नौकर-शाही तिलक के विरुद्ध थी। तिलक भी ६० वर्ष के हो चुके थे और वह प्राय. अस्वस्थ रहते थे। होमरूल-लीग की स्थापना तो उन्होंने कर ली थी, पर उसके सवंध में प्रचार करना उनके वस और वूते की वात नही थी।

श्रीमती वेसेंट की नीति

यह थी दशा १६१६ में भारत की, जिसकी पुकार पर कोई घ्यान नहीं देता था और जिसे अपने लिए एक नेता ढूढ निकालने की आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही नाजुक ममय में श्रीमती वेसेण्ट धार्मिक क्षेत्र से एकदम राजनैतिक क्षेत्र में कूद पटी। थियोमोफी को छोटकर उन्होंने होमरूल को अग्नाया। उन्होंने 'न्यू इण्डिया' नामक एक दैनिक और इसके वाद "कामन-त्रील" नाम का एक साप्ताहिक पर निकाला। होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय बनाने में उनका प्रथम स्थान था। इसके लिए उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान मचा दिया। वैसे १६१५ में ही "होमरूल फार इण्डिया लीग" की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था, लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी, वयोकि सोचा यह गया पा कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट हप में उस वर्ण की काग्रेस अपने हाथ में तो ले तो ठीक होगा।

वस्वई-काग्रेन ने काग्रेस और मुस्तिम-त्रीग के प्रतिनिधियों का एक मम्मेलन करने का जो आदेग दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान् जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना। एक सिम्मिलित सिमिति भी दनाई गई जिसके मुपुर्द यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करें और साम्मजा के अन्तगत स्वराज्य पाने के उद्देश्य को शीघ्र ही फर्नाभूत करने के तिए अन्य गारे आवश्यक प्रवन्य करें। यह तय हुआ दि इस सिम्मिलित सिमिति जारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१६१६) कांग्रेस और

मुस्लिम-लीग दोनो मिलकर पास करे। इसी सम्बन्ध में २२, २३ और २४ अप्रैल १६१६ को, इलाहाबाद में, प० मोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-सिमित की बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ। महा-सिमित की इस बैठक में जो प्रस्ताव कच्चे तौर पर पास हुए थे उन पर मुस्लिम-लीग की कौसिल और महासिमित की सिम्मिलित बैठक ने, जो अक्तूबर १६१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल वगाल और पजाब के प्रतिनिधियो की सख्या की समस्या हल नही हुई। इसका अन्तिम निर्णय लखनऊ-अधिवेशन पर छोड दिया गया। सिम्मिलित सिमिति ने कलकत्ते में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ काग्रेस ने स्वीकार कर लिया।

श्रीमती बेसेण्ट, काग्रेस का कार्य जिस मन्द गित से चल रहा था, उसमे सन्तुष्ट नहीं थी। काग्रेस की ब्रिटिश-समिति निस्सन्देह इंग्लैण्ड में अपना काम कर रहीं थी। लेकिन वह वस्तुत एक प्रकार से, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती वेसेण्ट एक तंजतर्रार और जीती-जागती सस्था चाहती थी। इसलिए उन्होंने १९१४ की मद्रास-काग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून १९१६ को लन्दन में एक सहायक-होमरूल-लीग की स्थापना की। भारतवर्ष में तो निश्चत रूप से, पहली सितम्बर १९१६ ई० को, मद्रास के गोखले-हाल में उनकी होमरूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। इस सस्था ने १९१७ भर घडाके से श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस सस्था की तीन वर्ष के लिए अध्यक्षा चुनी गई थी। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, २३ अप्रैल १९१६ को लोकमान्य तिलक ने की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में था। दोनो के नाम में गडबंड न हो इसलिए श्रीमती वेसेण्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १९१७ में 'ऑल इंडिया होमरूल-लीग' रख दिया था।

मतभेद का श्रन्त, लखनऊ कांत्रेस : १६१६

लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १६१६ की लखनऊ-काग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी सख्या को लखनऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली। काग्रेस के तत्कालीन विधान के अनुसार ऐसा नियम था कि विषय समिति में प्रत्येक प्रांत के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं की सख्या के बराबर के सदस्य प्रत्येक प्रांत से, अधिवेशन में सिम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जाय। लोकमान्य ने नरम-दल वालों के सामने विषय-समिति के चुने जानेवाले सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने बम्बई के प्रतिनिधियों से, जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को ही चुनवाने का निश्चय किया। अधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एक साथ पेश किये गये। अर्थात् एक नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय दल का ही आदमी चुना गया। जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गया तब गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी चुन लिये गये।

लखनऊ की इस काग्रेस के सभापित श्री अम्बिकाचरण मजुमदार चुने गये थे। यह काग्रेस अपने ढग की अद्वितीय थी। एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ, दूसरे स्वराज्य की योजना पेश हुई और काग्रेस के दोनो दलो में, जोिक १६०७ से पृथक-पृथक् थे, एका हो गया। वास्तव में यह दृश्य देखते बनता था। लोक-मान्य तिलक और खापड़ें, रासिबहारी घोष और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एक साथ एक ही स्थान पर बराबर बैठते थे। श्रीमती बेसेंट भी अपने दो सहयोगी अरण्डेल और वाडिया साहब के साथ, जिनके हाथो में होमरूल के झण्डे थे, वही बैठी थी। मुसलमानो में में राजा महमूदाबाद, मजहरूल हक और जिन्ना साहब भी उपस्थित थे। गाधीजी और मिस्टर पोलक भी वही विराजमान थे। काग्रेस-लीग योजना पर, जिसे कांग्रेस ने पास किया था, तुरन्त ही मुस्लिम-लीग ने भी अपनी मुहर लगा दी।

वम्बई-काग्रेस की भाति लखनऊ-काग्रेस में भी उपस्थिति अच्छी थी। २,३०१ प्रितिधियों के अतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीड़ थी, जिनके मारे सारा पण्डाल खचाखच भर गया था। इसमें प्राय वह सब प्रस्ताव पास हुए जिन्हें काग्रेस अब तक हर साल पास करती चली आ रही थी। काग्रेस ने दो प्रस्ताव और पास किये थे। एक तो उत्तरी विहार के गोरे जमीदारों और वहा की रैयत के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में था, जिसमें इन बात की आवच्यकता पर जोर दिया गया था कि सरकार शीच्र ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित समिति नियुक्त करे जो बिहार के किसानों के कप्टों का पता लगाये। दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी विल था जो कि वडी कौसिल में पेश किया जा चुका था। उत्तरी बिहार के गोरे जमीदार और वहा की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों का पता लगाने बिहार गये थे, जिस पर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा।

काग्रेस और लीग दोनो के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की प्रथा का जो श्रीगणेश वम्बई में हुआ था वहीं लखनऊ में भी जारी रखा गया। लखनऊ के अधिवेशन में स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके बाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास हुआ था कि सारे देश की काग्रेस-किमटिया

तथा अन्य सगठित सस्थाएँ और किमटिया शीघ्र ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य गुरू कर दे। इस आदेश का देश ने आक्चर्यजनक उत्तर दिया। एक प्रात ने दूसरे प्रात से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्द्धा की। मद्रास ने तो श्रीमती बेसेट के नेतृत्व में इस कार्य में सबसे अधिक बाजी मारी।

काग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन सुगमता से समाप्त नहीं हो गया। १८६६ मे जब काग्रेस का इसी स्थान पर १५ वा अधिवेशन होने जा रहा था तब अकथनीय कठिनाइयो का सामना करना पडा था। लेकिन उस समय, तत्कालीन लेफ्टिनेट-गवर्नर सर एन्थोनी मैक्डोनल्ड ने उन सबका अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १६१६ में हुई थी। उत्तर-प्रदेशीय सरकार के मन्त्रि-मण्डल ने कांग्रेस की स्वागत-समिति को एक चेतावनी भंजी थी कि भाषणो मे किसी प्रकार के राज-द्रोहात्मक भावो को न आने दिया जाय। काग्रेस के मनोनीत सभापति के पास भी बगाल-सरकार द्वारा उसी की एक नकल भेज दी गई थी। स्वागत-समिति ने इस अकारण तौहीन का मुह-तोड उत्तर दिया और सभापित ने उस पत्र को कोई महत्व नही दिया। श्रीमती बसेन्ट ठीक इन्ही दिनो बरार और वम्बई की सरकारो से देश-निकाले की आज्ञा पा ही चुकी थी। इसलिए स्वभावत लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही आशकाएँ थी। लेकिन सर जम्स मेस्टन की बुद्धिमानी से इस तरह की कोई घटना नहीं घटी और इसलिए कोई पेचीदगी पैदा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अधिकारीवर्ग-सहित सर जैम्स मेस्टन अपनो धर्मपत्नी सहित काग्रेस मे भी पधारे थे। सभापति महोदय ने उनका जो स्वागत किया था, उसका सर जैम्स ने उपयुक्त उत्तर भी दिया था।

: ६:

उत्तरदायी शासन की माँग: १६१७

होमकल आन्दोलन

काग्रेस के दो दलों के बीच पारस्परिक मत-भेद का अन्त तथा भारत की दो महान जातियों के बीच समझौता हो जाने से सन् १६१७ का वर्ष ठोस कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ। १६१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चलाया गया था उसकी कल्पना स्पष्ट और भावना शुद्ध थी। १६१७ में सारे देश में वडी तेजी के साथ एक राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो विराद् आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी बहुत ही लोकप्रिय था। होमरूल की

आवाज देश के सुदूर कानो तक फैल गई थी और सर्वत्र होमरूल-लीगो की स्थापना हो गई थी। श्रीमती बेसेण्ट-द्वारा प्रेम की शक्ति में विशेष उन्नति हुई। परन्तु इसके साथ-साथ दमन-चक्र भी चला। श्रीमती बेसेण्ट से, जिनका 'न्यू इिया' नामक दैनिक और 'कामन-वील' नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत नागी गई और वह जब्त भी कर ली गई। एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का विचार, दावानल की तरह, सर्वत्र फैल रहा था। होमरूल-आन्दोलन की शक्ति, श्रीमती बेसेण्ट के १६१७ में कलकत्ता काग्रस के सभापति-पद से दिये गये भाषण के कारण, दसगुनी अधिक बढ गई थी। इस आन्दोलन की सफलता का एक वडा कारण यह था कि प्रारम्भ से ही भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तो को मान लिया गया था और उसी के अनुसार देश का प्रान्तीय-सगठन किया गया था। इस प्रकार इस रूप में वह काग्रेस से भी आगे निकल गई थी और सच पूछिए तो काग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था।

१५ जून १६१७ को श्रीमती बेसेण्ट, अरण्डेल और वाडिया साहब को नजर-बन्दी का हुक्म मिला। उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना था। उन्होंने कोयम्बट्र और उटकमण्ड को पसन्द किया। अपने तीन नेताओं की नजरबन्दी के कारण होमरूल-लीग और भी लोक-प्रिय हो गई और श्री जिन्ना भी उसमें सम्मिलित हो गये। सरकारी हुक्म और खुफिया-पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतन्त्रता पूर्वक बरा-बर अपने पत्र 'न्यू-इडिया' के लिए लेख लिखती रही। श्री पढरीनाथ काशीनाथ तैलग 'न्यू इण्डिया' के सम्पादक बनकर मद्रास पहुच गये। देश में स्थिति बडी विकट हो गई। लेकिन इंग्लैण्ड में अधिकारी-वर्ग जरा भी झुकने को तैयार न था।

शाही युद्ध-परिषद्

भारतवर्ष में जब यह राजनैतिक तूफान उमड रहा था, लन्दन में एक शाही युद्ध-परिषद् हो रही थी, जिसमें सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराज बीकानेर और सर सत्येन्द्रप्रसन्नसिंह इन्लैण्ड भेजें गयें थे। इन लोगों ने वहाँ अपनी जान-बान और रङ्ग-ढङ्ग तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रोब जमाया कि उनका वहाँ खूब ही स्वागत हुआ। भारत-वर्ष इस समय होमरूल के सम्बन्ध में नजरबन्द हुए लोगों को छुडाने के लिए सत्या-ग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था। जुलाई १६१७ में महासिमिति और मुस्लिम लीग की कौसिल की एक सिम्मिलित बैठक बुलाई गई। इसमें सर विलियम वेडरवर्न की सलाह के अनुसार एक छोटा-सा शिष्टमंडल इन्लैण्ड भेजने का निश्चय

हुआ। उसके सदस्य थे—सर्वश्री जिन्ना, शास्त्री (यदि वे न जाय तो सी० पी० रामस्वामी ऐयर), सप्नू और वजीर हसन। सत्याग्रह करने के प्रश्न पर यह तय हुआ कि प्रान्तीय-काग्रेस-किमटियो और मुस्लिम-लीग की कौसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्तत राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करे, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं? इस विपय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर काग्रेस के प्रधान मन्त्री के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी।

सत्याग्रह पर विचार

३० जुलाई को भारत-मत्री, प्रधानमत्री तथा सर विलियम वेडरबर्न के पास इस वक्तव्य का मुख्य भाग तार-द्वारा विलायत भेज दिया गया। इसी वीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस कमिटियो ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनो में विचार किया। बरार की राय में तो सत्याग्रह करना उचित था, पर बम्बई, बर्मा और बजाब का कहना था कि अभी सत्याग्रह स्थगित् रखा जाय, क्योकि मि० माण्टेगु के भारत आने की सभावना है। उत्तर प्रदेश ने वर्तमान अवस्था मे सत्याग्रह करना अनुपयुक्त बताया । बिहार ने कहा कि होम रूल के नजरबन्दो—मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयो को मुक्त कराने के लिए एक तारीख नियत कर देना चाहिए। इस दी गई मियाद के बीच बिहार स्वय स्थान-स्थान पर सभाये करके इस माग का बल बढाने को तैयार था। मद्राम-प्रान्तीय काग्रेस-कमेटी ने १४ अगस्त १९१७ को सत्याग्रह का समर्थन किया। मद्रास-नगर मे तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इस पर सबसे पहले सर एस० सुब्रह्मण्य ऐयर ने हस्ताक्षर किया। वह मद्रास हाईकोर्ट के पेशनयापता जज, पुरान काग्रेसी तथा आल इडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होने अपनी 'सर' की उपाधि को श्रीमती बेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। प्रनिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्पादक श्री कस्तुरी रगा आयगर थे।

मार्एटेगु की घोषणा

जिस समय भारतवर्ष में होम रूल-आन्दोलन वढ रहा था उस समय मि॰ चेम्बरलेन की जगह मि॰ माण्टेगु भारत-मत्री हुए । उनके भारत-मत्री होने से, भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी। लोगो की आशा के अनुसार मत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय वाद २० अगस्त को मित्र-मडल की ओर से, उन्होंने एक घोषणा की, जिसमें ब्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना बताया गया। लोगो के प्रति अपने विश्वास-

भाव को प्रकट करने के लिए उन्होने उस जातिगत प्रतिबन्ध को भारतीयो पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर उन्होने यह भी घोषित किया कि वह भारत आयेंगे और वाइसराय से परामर्श करेंगे, एव भारत को स्वराज्य की ओर बढ़ाने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी वाते करेंगे। इस नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सितम्बर को मुक्त कर दिये गये।

कांग्रेस का आवेदन-पत्र

६ अक्तूबर को इलाहाबाद में महासमिति और मुस्लिम-लीग की कौसिल की एक सम्मिलित बैठक हुई। इस सम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर वाइँसराय तथा भारत-मत्री के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने की बात तय की। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के साथ काग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक युक्ति-सगत आवेदन-पत्र भी भेजने की बात तय हुई। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की गई। श्री सी० वाई चिन्तामणि उसके मत्री थे। इसका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० भाण्टेगु से नवम्बर १६१७ में मिला। आवेदन-पत्र में कहा गया कि "भारत-सरकार की रजामन्दी से सम्राट्-सरकार-द्वारा जो अधिकार-पूर्ण घोषणा की गई है उसके लिए भारतवासी बड़े ही कृतज्ञ है, पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के अनुसार कार्रवाई की जाय तो उन्हें और भी अधिक सन्तोष होगा। गत दो वर्षों से एक ऐसी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहा के निवासी इस बात पर बलपूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। इस वर्ष के आरम्भ में जो शाही-युद्ध परिषद् हुई उसमे महाराज बीकानेर, सर जैम्स मेस्टन और सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये है। युद्ध के मित्र-मण्डल में भी इन लोगो को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है। इससे हमें बहुत प्रसन्नता है और इसको हम आगे बढाया हुआ कदम मानते है। हम लोग शाही-परिषद-द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव के मूल्य को भी नही भूल सकते हैं जिसके द्वारा शाही-युद्ध-परिषद् में भारत को आगे प्रतिनिधित्व देना तय हुआ है। हमारी प्रार्थना तो केवल यही है कि जबतक भारत-सरकार एक मातहत-सरकार है, तब-तक वह न प्रतिनिधि ही है और न जनता के प्रति उत्तरदायी ही। उपनिवेशों के साथ उसकी समानता भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह प्रतिनिधित्व भारत-सरकार को दिया गया है, न कि भारवासियो को । इसमे शक नही कि शाही-परिपद् के लिए उनकी ओर से सरकार जिनको चुनेगी वे अपनी शक्तिभर अपने देश के प्रति अपने

कर्ज्ब्यं का पालन अवश्य करेंगे, लेकिन उनके साथ वह प्रारम्भिक असुविधा अवश्यं लगों रहेगी जो जनता के प्रति उत्तरदायी न होनेवाले के साथ होती है। यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठिनाई रहेगी। हमारी यह माग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करें। यह भी नहीं कि बहुत अधिक मतदाताओं द्वारा हुआ करें। इतना काफी होगा, यदि बड़ी और प्रान्तीय कौसिलों के चुने हुए सदस्यों को प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार दे दिया जाय। आशा है सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।"

कांग्रेस का संगठन

इस बीच काग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे। वे काग्रेस-लीग-योजना के लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहें थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजर-बन्दी से छुटकारा पाने के बाद श्रीमती वंसेण्ट ने वाइसराय से कितनी ही बार मिलने के लिए समय मागा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लॉर्ड चेम्सफार्ड श्रीमती वंसेण्ट को दूर ही रखना चाहते थे। मि॰ माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर-भाव प्रदिश्तत नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सत्याग्रह से अपनी अलहदगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगम्य ही है।

१६१७ के अन्त के महीनो में भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्टफोर्ड हीं माण्टफोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दौरा हो रहा था। उनसे विभिन्न स्थानो पर शिष्ट-मण्डल मिलते थे। मि० माण्टेगु श्रीमती बेमेन्ट, लोकमान्य तिलक और गाधीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी बाते सुनी। उनकी भारत-यात्रा का उद्देश्य यह जान लेना था कि भावी-शासन में मत्री, कार्य-कारिणी के सदस्य और एडवोकेट जनरल कौन-कौन वनाने लायक है। वह उन आदिमयों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना को कार्य-रूप में परिणत कर सके। इस समय गांधीजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियो के साय-जैसे राजेन्द्र वाबू, वृजिकशोर बाबू, गोरख वाबू, अनुग्रह वाबू और अध्यापक कृपलानी तथा भारत-सेवक-समिति के डा० देव को लेकर बिहार में निलहे गोरो के प्रति वहा के किसानो की जो शिकायते थी, उनकी जाच कर रहे थे। वह पूरे ६ मास तक आन्दोलन से कर्तर्ड अलग रहे और अपने सब साथियो को भी अलग रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव अवश्य रखा कि काग्रेस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित कर दी जाय, लोगो को उसे समझाया जाय और उसमे शासन-सुधारों की जो योजना है, उसके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर कराये जाय। इस प्रस्ताव को ज्योही कार्य रूप में लाया गया त्योही देश ने काग्रेस की शासन-सुधार-योजना का स्वागत किया । यहा तक कि १६१७ के अत तक दस लाख से ऊपर लोगो ने हस्ताक्षर कर दिये । यह देश-व्यापी मगठन, काग्रेस की ओर से सम्भवत पहला ही प्रयत्न था।

उत्तरदायी शासन की मांग: १९१७

कलकत्ता-कांग्रेस : १८१७

इस वर्ष काग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। कलकत्ता नरम-दल वाली का एक गढ था। उनमें और नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय दल वालों में तीव्र मत-भेद था। राष्ट्रीय दल वालों तथा नये होमरूल वालों ने भी कलकत्ते को ही अपना सुदृढ गढ बना लिया था। पुराने दल के नेता थे राय बैकुण्ठ नाय सेन, अम्बिका-चरण मजुमदार, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा भूपेन्द्रनाथ वसु। चित्तरजनदास भी काग्रेस-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने नये दल के साथ अपना भाग्य जोड लिया था जिसमें बी०के० लाहिडी, आई० वी० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे।

यद्यपि अधिकाश प्रन्तीय-काग्रेस किमिटियो ने श्रीमती बेसेण्ट को आगामी काग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी, नो भी स्वागत-सिमिति में इस बात पर तीन्न मत-भेद था। तत्कालीन विधान के अनुसार उन दिनो प्रान्तीय काग्रेस किमिटियो के अधिकाश मत को ही मानना पड़ता था। स्वागत-सिमिति की ३० अगस्त १६१७ की बैठक तो इस विषय पर विकट मत-भेद और विरोध का एक दृश्य बन गई थी। अन्त में श्रीमती बेसेन्ट सभानेत्री चुन ली गई।

श्रीमती बेसेण्ट का काग्रेस के सभानेत्री-पद से दिया गया भाषण, भारत के स्वशासन पर, परिश्रमपूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निबन्ध था। सेना और भारत की व्यापारिक समस्या पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णत प्रकाश डाला गया था। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक-विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री थी। उन्होंने वस्तुत. १६१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे बिल की माग पेश की थी जिसके अनुसार भारत को ब्रिटिश उपनिवंशों के समान स्वराज्य दे दिया जाय, वह भी १६२३ तक, या अधिक-से-अधिक १६२८ तक। बीच के पाच या दस वर्ष अंग्रंजों के हाथों से भारतीय सरकार के हाथों में आने में लगे और अग्रेजों से भारत का वही सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवंशों के साथ है।

इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोडकर पहले-के-से साचे में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलकत्ते के ए० रसून की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और सम्राट् के प्रति भारत की राजभितत के प्रस्ताव उन्हें होने के बाद मि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ। मौलाना महम्मद्र-अली और शौकतअली को, जो कि अक्तूबर १६१४ से नजरबन्द थे, निह्न कर हेने का भी प्रस्ताव पास हुआ। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा, भारतीयों के उन्हें सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भाति जोर देते हुए इन दिन्ह ने उनके साथ न्याय किये जाने की माग की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा १८१० के देने एकट हारा शासकों को बहुत विस्तृत और निरंकुश-सत्ता कि

एकट, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार और उनकी असुविधाओं के प्रति अपने विरोध को दोहराया। उसने कुली प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए भी माग पेश की। एक पार्लमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्त्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कानूनो तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून के प्रयोग के सम्बन्ध में जाच करे। कार्यस ने एक प्रस्ताव-द्वारा रौलट कमीशन की निन्दा की और बताया कि इस कमीशन का उद्देश्य दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था करना था, लोगों का कष्ट दूर करना नहीं। मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है —

"सम्राट् के भारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देय भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इस पर यह काग्रेस कृतज्ञतापूर्वक सन्तोष प्रकट करती है।

"यह काग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना का विधान करने वाला एक पार्लमेण्टरी कानून बने और उसमें बताय हुए समय नक पूरा स्वराज्य मिल जाय।

"इस काग्रेस की यह दृढ राय है कि शासन-सुधार की काग्रेस-लीग-योजना कानून-द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप मे प्रारम्भ की जानी चाहिए।"

श्रीमती बसेण्ट के समापितत्व में, होमहल-लीग और काग्रेस एक-दूसरें के बहुत ही निकट आ गई। यह काग्रेस इसलिए भी स्मरणीय है कि इसमें पहली बार राष्ट्रीय झण्डे का सवाल वाजाव्ता उठाया गया। इस कार्य के लिए एक किमटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित करे। लेकिन इस किमटी की बैठक कभी नहीं हुई। अन्त में होमहल का झण्डा ही काग्रेस का झण्डा वन गया।

9

मार्ग्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना : १६१८

महासमिति को वैठक

१६१७ की काग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर को महा-समिति की पहली बैठक में, काग्रेस के लिए स्थायी-कोष जमा करने के प्रश्न पर विचार किया गया, और प्रान्तीय काग्रेस कमिटियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत में शिक्षा और इंग्लैंग्ड में प्रचार-कार्य आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना दे। इसके बाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने में ही व्यतीत हुए।

महासिमिति की दूसरी बैठक दिल्ली मे १३ फरवरी १६१८ को हुई। उसमें वाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रस्ताव पास हुआ जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पाल के दिल्ली और पंजाब में प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गर्य है, उसे मसूख कर दे। शिष्ट-मडल वाइस-राय से मिला, लेकिन निरर्थक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टंगु शासन-सुधारो सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे। इसलिए महासिमिति ने यह निश्चय किया कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहाबाद में काग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। उसने इंग्लैण्ड को एक शिष्ट-मडल भेजना भी तय किया।

३ मई १६१८ को महासमिति की तीसरी बैठक हुई। उसमें सीलोन (लका) और जिब्राल्टर से दोनो होमरूल-लीग के शिष्ट-मण्डलो को, जो इंग्लैण्ड जा रहे थे, वापस लौटा देने पर सरकार का खूब विरोध किया गया। किमटी ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकारपूर्ण घोषणा कर टी जाय कि लडाई खतम होने पर भारत को उत्तरदायी-शासन दिया जायगा। इससे कम के लिए भारतीय नौजवान कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे नहीं बढेंगे।

माएटेगु-चेम्सफोर्ड-योजना का प्रभाव

जून १६१ में माण्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक-दृष्टि में यह ऊचे दरजे की चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञो द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को स्वशासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। उसमें सुधारों के मार्गों की रुकावटों का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवश्य मिलना चाहिए। रिपोर्ट के पक्ष में एक और भी बात थी। देश की दो महान् सस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को तैयार किया था उसमें अपरिवर्तनीय कार्यकारिणीं की तजवीज थी। परन्तु उसमें उत्तरदायी शासन की एक बड़ी ही आकर्षक योजना थी, जिसमें मिन्त्र-यडल बदला जा सकता था। मित्रमण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी और वह कौसिल के मतो पर निर्भर करती थी। यह ठीक ब्रिटिश नमूने के स्वराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और चाहिए ही क्या था? इसके अनुसार, भारतीयों की राय में, कौसिलें भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीमगाह न रह कर सार्वजिनक न्यायालय हो जाती थी, जहा कि मत्रीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थित साफ करनी पड़ती और अपने साथी सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवलेंम्बत रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके भुलावे में

आ गये और इसकी तारीको के पुल बाघने लगे। पलडा काग्रेस-योजना की ओर से माण्ट-फोर्ड-योजना की ओर झुक गया।

कांग्रेस का विशेष अधिवेशन

ऐसी स्थिति में इस बात पर भिन्न-भिन्न नेताओं में तेजी से चर्चा होने लगी कि इसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। महासमिति ने काग्रेस के विशेष अधिनेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना लाजिमी था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेग। अतः वम्बई में काग्रेस का विशेष अधिनेशन करना तय हुआ और थोडे ही समय में सारी तैयारी की गई। काग्रेसवालों में रिपोर्ट के सबध में तीन्न मतभद था। वैस कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नहीं था, लेकिन उनके आलोचना करने के ढग में अन्तर अवश्य था। ऐसा जान पडता था कि एक दल तो, उसे विलंकुल अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा। काग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी जगह एक बार मिले और दोनो दलों में समझौता हो जाय। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

काग्रेस का अधिवेगन २६ अगस्त १६१ द को हुआ। श्री हसन इमाम सभापित थे। काग्रेस मे उपस्थिति खूब थी। उसमे ३,८४५ प्रतिनिधियो ने भाग लिय। था। श्री विट्ठलभाई पटेल स्वागत-समिति के सभापित थे। चार दिन के वादिवाद के पश्चात् काग्रेम ने अपनी पुरानी योजना के आधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस वात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकाक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। माटेगु-योजना की उसने विस्तार-पूर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। माटेगु-रिपोर्ट में इसके विरुद्ध जो बात कहीं गई थी उसका प्रतिवाद किया गया। काग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय, दोनो शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहा उत्तरदायी शासन के किमक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए और जब तक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तब तक आवश्यक बानों में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे।

आगे चलकर प्रस्ताव मे ऐसी बाते भी सुझाई गई जिनका होना उत्तरदायी शासन की ओर बढने के लिए पूर्णतया आवश्यक था—जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित बातों के लिए काग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित विषय रखें जायं उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए

रूँ रहे। कौसिले प्रातीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर—कानून, न्याय और पुलिस पर भी—कानून बना सकेगो, किन्तु जहा सरकार को कानून, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी बातों में कौसिल के निर्णय से सन्तोष न हो वहा उन्हें भारत-सरकार के सामने पेश कर सकेगी। भारत-सरकार उसे वड़ी कौसिल के सामने पेश कर देगी और साधारण तरीका बर्ता जायगा। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति बढ़ाया जाय और पार्लमेट और भारत-मत्रों के अधिकार कम किये जाय। इण्डिया कौसिल तोड़ दी जाय। भारत मत्री को सहायता देने के लिए दो स्थायी सहायक-मन्त्री रहें, जिनमें से एक भारतीय हो।

जातिगत प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में काग्रेस ने निश्चय किया कि छोटो और बड़ी कौसिलों में मुमलमानों का प्रतिनिधित्व वही रहना चाहिए जो काग्रेस-लीग योजना में रखा गया है। स्त्रिया मताधिकार के अयोग्य न ठहराई जाय। आधिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतोयों को कमीशन दिये जाने के सबध में जो माग पेश की गई थो उसे सरकार ने बिलकुल अपूर्ण रूप से स्वोकार किया था। इस पर काग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह रायदी कि भारतीयों को सेना में कम-से-कम २५ प्रतिशत कमीशण्ड जगहें देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह औसत धीरे-धीरे बढकर १५ साल में ५० फीसदी तक जाना चाहिए। काग्रेस ने इगलैंड में शिष्ट-मण्डल भेजना तय किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक किमटी नियुक्त कर दी। इस तरह यह विशेष अधिवेशन ऐसे निर्णयों पर पहुंचा जिससे विभिन्न मतो में मेल हो गया तथा सारे देश के अधिकाश काग्रेसियों ने पूर्णस्प से उनका समर्थन किया। उन्हों दिनों मुस्लिम-लीग की भी बैठक हुई जिसके सभापित थे महमूदाबाद के राजा साहब। उसमें भी काग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ।

दमन श्रौर गिरफ़्तारियां

लेकिन भारत के दु खो का अन्त नही हुआ। भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरो के साथ अपना काम कर रहा था। मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-भाइयो की नजरबन्दी हो चुकी थी। अमृतसर काग्रेस के पहले अली-बन्धु काग्रेसी नही थे। १६१६ मे रिहा होते ही वे अमृतसर-काग्रेस में पहुचे थे। मुहम्मदअली "कामरेड" नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। उनके बडे भाई शौकत अली "हमदर्द" के सम्पादक थे। यह उर्दू का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के छिडते ही ब्रिटिश-सरकार की तरफ से लोगो को दिखाने के लिए बडी शान से एक घोपणा की गई, जिसमे यह कहा गया था कि युद्ध निर्वल राष्ट्रो की रक्षा के लिए लडा जा रहा है। मौलाना मुहम्मदअली

ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा, जिसका नाम था "मिश्र को खाली कर दो।" मीलाना और अली-बन्धु उसी समय नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इसी अवस्था में २५ दिसम्बर १८१६ तक रहे।

महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भरती करने का ढंग अत्यन्त अनुचित था। इनके कारण पजाव और अन्य जगह आगे चलकर भयकर स्थितिया पैदा हो गई थी। देहात में तो "इडेण्ट" की प्रया प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके हलके से युद्ध के लिए कितना धन मिल सकता था और फिर उसी के अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी बात को कायग रखने के लिए, "दवाव तथा समझाने" की नीति को काम में लाकर युट्ट के लिए जितना हो सकता था रूपया वसूल करने थे। इन उपायों में अन्त में एगी स्थित पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोंथ में आकर एक तहसीलदार का बगला पेर लिया और उसके वाल-बच्चों को छोड़कर उसे मय बगले के जलाकर भरम कर दिया।

लार्ड चेम्मफोर्ट के शासन-काल मे, जहा तक राजनैतिक क्षेत्र मे सम्बन्ध है, दमन-चन्न मुख्यत प्रेम-ऐन्नट के रूप में बड़ी तेजी से चला था। भारत-रक्षा-कानून के अनुसार लार्ड विलिगडन ने श्रीमती बेसेण्ट को बम्बई-अहाते में प्रवेश न करने की आजा दे दी थी। बगाल में नजरबन्द नवयुवकों की संस्या तीन हजार तक पहुच गई थी। उसके बाद श्रीमती बेगेन्ट नजरबन्द हुई। दूसरे वर्ष रीलट बिल तथा डगांग नाथ ही उसके विकृत आन्दोलन दोनों ने पदार्पण किया।

दिल्लो-कांग्रेस : १६१८

काग्रेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन आगामी दिसम्बर मास में दिल्ली में होनेवाला था। दिल्ली-अधिवंशन का सभापित प्रातीय काग्रेस-कमेटियो और स्वागत-सिमिति ने लोकमान्य तिलक को चुना था। लेकिन उन्हें वंलेन्टाइन चिरोल पर चलाये गये मुकद्दमें के सम्बन्ध में इग्लैंड जाना था। अत सभापित बनने में उन्होंने असमर्थता प्रकट की। इसपर प० मदनमोहन मालवीय को सभापित बनाया गया। हकीम अजमल खा स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १६१ को अस्थायी-सिन्ध के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, लायड जार्ज तथा मित्र राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्म-निर्णय के सिद्धातों की घोषणा कर दी थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाणों को तथा आलोचनाओं को, जो माण्टफोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवंशन के बाद हुई थी, सामने रखकर काग्रेस शासन-सुधार-योजना पर पुन विचार करे।

काग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट् के प्रति राज-भिकत प्रकट की और युद्ध के, जो कि ससार के सब लोगो की स्वाधीनता के लिए लडा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिको की वीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशसा की। तीसरे-प्रस्ताव द्वारा इस बात की प्रार्थना की गई कि शान्ति-सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशों में समझे जिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा। इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए वह यह बताई गई कि उन सारे कानूनो, आर्डिनेंसो और रेग्यूलेशनो को, जिनके कारण स्वतत्रतापूर्वक राजनैतिक समस्याओ पर खुलकर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, रोकने देश-निकाला देने, साधारण अदालतो मे बिना मुकदमा चलाये ही सजा करने का अधिकार दे दिया गया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। काग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी माग पेश की कि साम्राज्य-नीति के पुनर्निर्माण में पार्निमेन्ट शीघ्र ही भारत को एसा पूर्ण उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशी में है। काग्रेस ने यह भी इच्छा प्रकट की कि शान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियो द्वारा हो। इसके लिए लोकमान्य तिलक, गाधीजी और श्री हसनइमाम को प्रतिनिधि भी चना गया।

शासन-सुघारो के लिए काग्रेस ने उसी विशेष अधिवेशन वाले काग्रेस-लीग योजना के प्रस्ताव को ही दोहराया। साथ ही यह बात भी कही गई कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एव देशरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार कुछ अपवादी

सत्याग्रह भौर पंजाब-हत्याकांड : १९१९

को छोड़कर, भारत-सरकार को है। इसके सम्बन्ध में भी वर्म्बई के प्रस्ताव की समर्थन करते हुए यह बात कही गई कि इसमें शासन-सुधारों की स्फल्ट्राम्बिक व्याहवारिक रूप देने में बाधा पड़ेगी। काग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा कानून, प्रेस एक्ट, राज-द्रोह, सभावन्दी-कानून, क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेट ऐक्ट, रेग्यूलेशन्म तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नजरबन्दों तथा राजनै तक कैदियों को मक्त कर दिया जाय।

औद्यागिक कमोशन की रिपोर्ट पर भी विचार हुआ। उसकी सिफारिशो का और इस नाित का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को इस देश की औद्यो-गिक उन्नित के लिए अधिक काम करना चाहिए, काग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धात को कार्यान्वित करने में यह उद्देश्य सामने रखा जायगा कि भारतीय पूजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशों की लूट में भारत को वचाया जाय। एक और प्रस्ताव द्वारा काग्रेस ने सरकार में अली-वन्धुओं को मुक्त कर देन की प्रार्थना की गई। युद्ध के बन्द हो जाने और अभूतपूर्व आधिक संकट के कारण काग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि युद्ध के कार्यों के लिए ४ करोड ५ लाख रुपया देने के भार से भारत का मुक्त कर दिया जाय। आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों के सम्वन्ध में भी एक वडा हा मनोरजक प्रस्ताव काग्रस ने पास किया। उसमें सरकार से सिफ।रिश की गई कि विदेशों चिकित्सा-प्रणाली के लिए जो सुविधाये प्राप्त है उन्होंकी व्यवस्था आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय। इस प्रकार एक ओर जहा इस काग्रेस ने बम्बई-काग्रेस के प्रस्तावों को प्राय दोहराया वहा कुछ आगे भी कदम बढाया।

٠٤:

सत्याग्रह ऋौर पंजाब-हत्याकांड : १६१६ रौलट विल का मन्तव्य

दिल्ली-काग्रेस से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १६१६ के फरवरी में रीलट-बिल ने देश को अपना दर्शन दिया। वे दो बिल थे। एक अस्थायो था जिसका उद्देश्य था भारत-रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना और वह भी युद्ध के समाप्त हं ने पर शान्ति स्थापित होने के ६ मास बाद। उसमें यह विधान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमें हाईकोर्ट के तीन जाों को अदालत में पेश हो बार वे शाम्र उनका फैसला कर दे एवं जिन स्थानों में पान्तिकारी अपराध बहुत हो वहा अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह

अधिकार भी दे दिया गया था कि राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर सदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे तथा उसे किसी स्थान-विशेष मे रहने और किसी खास काम को करने से रोका जा सके। किसी व्यक्ति को ऐसा हुक्म देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होगे उनकी जाच एक जज और गैर-सरकारी आदमी किया करेगा। तोसरे प्रान्तोय सरकारो को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर उचित रूप से यह सदेह हो कि वह कुछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति भग होने की आशका हो, गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानो मे बन्द कर दे और यह बता दे कि इन अवस्थाओ या स्थिति मे रहना पडेगा। दूसरा विल साधारण फौजदारी-कानून मे एक स्थायी परिवर्तन चाहता था। किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन या वितरण करने के उद्देश्य से पास रखना ऐसा अपराध करार दे दिया गया था जिसमे जेल की सजा हो सकती थो। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने की राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधिकारियो पर रखा गया था। उन अपराघो के लिए, जिनके लिए, सरकार की आजा पहले से प्राप्त किये विना मुकदमा नहीं चल सकताथा, जिला-मजिस्ट्रेटो को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस-द्वारा उस मामले की प्रारम्भिक जाच करवा ले। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने में सजा मिल चुको हो उसकी सजा के बाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की जमानत ली जा सकती थी।

सत्याग्रह का सूत्रपात

रौलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरो १९१६ को, विलियम विन्सेण्ट ने वडी कौसिल मे, रौलट-विलो को पेश किया। पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास हो गया और दूसरा वापस ले लिया गया। गाधोजी ने यह घोषणा की कि यदि रौजट-कमीशन की सिफारिशो को बिल का रूप दिया गया तो वह सत्याग्रह-युद्ध छेड देगे। इसके लिए गाधोजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका सब जगह धूमधाम से स्वागत हुआ। गाधोजी तो देश के लिए, अन्य नेताओ की अपेक्षा, अपरिचित व्यक्ति के समान थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यो किया? सरकार इसका उत्तर अपनी १९१६ की रिपोर्ट में इस प्रकार देता है —

"मि॰ गाधो अपनी नि स्वार्थ भावना और ऊँचे आदर्शों के कारण आम तौर पर टाल्स्टाय के अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रांका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके कारण उन्हें यह सब मान-गोरव प्राप्त है जो पूर्वी देशों में एक तपस्वी और त्यागी-नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह अहमदाबाद में रहने लगे हैं, तब से वह बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दिलतों और पीडितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को अंद भो प्रिय हो गये हैं। बम्बई अहाते के क्या देहात और क्या नगर, सब जगह उनका अत्यिक प्रभाव है और उनको सब पर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए 'पूजा' शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। भौतिक-बल से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसलिए गांधाजी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रौल उपेक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफोका में सफलता पूर्वक आजमाया था।"

सरकार के इस रख के वावजूद भी गाधीजी ने अपने निश्चय के अनुसार २४ फरवरी को सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी। सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनातिज्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिता की दृष्टि से देखा। बड़ी कौसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सार्वजिनक रूप से ऐसे कार्य के अनिष्ट परिणामों को ओर सकेत किया। श्रीमती बेसेन्ट ने तो, गाबीजी को अत्यन्त गभीरतापूर्वक यह चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शिक्तया उभड़ उठेगो जिनसे न जाने क्या-क्या भयकर बुराइया हो सकती है। यहा यह बात स्पष्ट रूप से बता देन। चाहिए कि गाधीजी के रख या घोषणा में काई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आक्रमणकारी नहीं, रक्षात्मक पद्धित है। गाघोजी तो शुरू से हा पशुबल को निन्दा करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि वे सिवनय-भग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगे कि वह रौ नट-ऐक्ट का परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रौलट बिल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है:——

"सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इडियन किमिनल ला अमेण्डमेट विल न० १ और किमिनल इमरजेसी पावर विल न० २ अन्यायपूर्ण हैं और अन्याय और स्वाधीनता के सिद्धातों के घातक हैं। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिन पर भारत को और स्वय राज्य की रक्षा निर्भर है। अत. हम शपयपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन विलो को कानून का रूप दिया गया तो जवतक इन्हें वापस न ले लिया जायगा तव तक हम उन अन्य कानूनों को भी जिन्हें कि इसके बाद नियुक्त की जाने वाली किमिटी उचित समझेगी, मानने से नम्प्रता-पूर्वक इन्कार कर देगे। हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमान-दारों के साथ सत्य का अनुसरण करेगे और किसी के जान-माल को किसी तरह नुकक्षान न पहुँचायेगे।"

देश ने चारो तरफ से इस आन्दोलन का खूब साथ दिया। प्रारभ मे वगाल जामोश रहा। दक्षिण ने उसमें आशातीत साथ दिया। गाघीजी ने उपवास के

साथ आन्दोलन का श्रीगणेश किया। ३० मार्च १६१६ का दिन हडताल के लिए नियत किया गया था। इस दिन लोगो से उपवास रखने, ईश्वर-प्रार्थना करने, प्रायश्चित्त करने तथा देश-भर में सार्वजनिक सभाएँ करने के लिए कहा गया था। बाद को यह तारीख बदल कर ६ अप्रैल नियत को गई, परन्तु इस परिवर्त्तन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची। इसलिए वहा ३० मार्च को ही जलूस निकला और हडताल हुई। गोली भी चली। इस दिन के जलूस का नंतृत्व स्वामी श्रद्धानन्दजी कर रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसपर उन्होने अपनी छाताँ खोल दी और कहा--'लो, मारो गोली।' बस, गोरो को धमको हवा मे उड गई। लेकिन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कुछ झगडा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए। ६ अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। सब लोग वडे ही उत्तेजित थे। उस समय एक बात मार्के की दिखाई पडती थी ऑर वह था हिन्दू-मुस्लिम-भ्रातृ-भाव। इस जोश-खरोश के जमाने में छोटो जातियों ने भी अपने मतभेद भुला दिये। वह भ्रातृ-भाव का एक अद्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-खुल्ला पानी लेत-देते थे, जलूसो के झण्डो और नारो, दोनो से हिन्दू-मुसल-मानो का मेल ही प्रकट होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खडे होकर हिन्दू नेताओं को बोलने भी दिया गया था। इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात् टर्की की अस्तव्यस्त अवस्था हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वभावत बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो खतरा था उससे तो उनमे और भी उत्तेजना फैली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानो की इन भावनाओं के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की। १६१६ के अप्रैल मास से भारतीय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ हआ।

श्रान्दोलन की तीव्रता

भारतवर्ष के कष्ट-सहन और सघर्ष का दृश्य अव पजाव मे दिखाई देने लगा जो कि विदेशो उद्योग-धन्वे और व्यापारिक आक्रमण के लिए भारत का द्वार बना हुआ था। पजाव सिक्खो तथा भारत की अन्य सैनिक जातियो का निवास-स्थान भी था। इसलिए पजाव का निरकुश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन की छूत की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में काग्रेस और उसमें इस बात पर रस्साकशी थी कि आया १६१६ में अमृतसर में होनेवाली काग्रेस पजाव में हो या नहीं। १० अप्रैल १६१६ के दिन प्रात काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल को, जो काग्रेस का सगठन कर रहे थे, अपने बगले पर वुला भेजा और वहा से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इस घटना से एक

सनसनी फैल गई। खबर फौरन ही दूर-दूर तक पहुच गई। लोगों का एक झुण्ड जिला-मजिस्ट्रेट के यहा उनका पता पूछने के लिए चला, परन्तु उस चौराहे पर, जो शहर से सिविल-लाइन की ओर जात हुए सिविल-लाइन और शहर के बीच में है, फौजो सिपाहियों ने भीड़ को रोक लिया। और, अब वह ईटों के फेकने की कहानी आतो है, जो सरकार को मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। भीड़ पर गोली चलाई गई, जिसके फल-स्वरूप एक या दों की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों की भीड़ अब शहर को वापस लाटा और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर जलूस निकला। रास्ते में नेशनल-बैंक की इमारत में आग लगा दों गई और उसके यूरोपियन मैंनेजर को मार डाला गया। स्वभावत अधिकारी इन घटनाओं से आगववूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आप १० अप्रैल को शहर फीज के अधिकार में दे दिया।

गुजरानवाला और कसूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई। कसूर में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को वहुत नुकसान पहुँचाया। गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घर लिया और उस पर पत्थर वरसाये। लाहाँर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते-जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पजाव का दुर्घटनाओं की वात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डा॰ सत्यपाल के वुलाने पर गांधीजी प अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करा। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठा कर १० अप्रैल को वम्बई भेज दिया गया।

गावीजों को गिरपतारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को वीरमगाव और निडयाद में भी कुछ उत्पात हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ। वहा गोली चली जिससे १ या ६ आदमी जान से मारे गये और १२ बुरी तरह पायल हुए। वम्बई पहुचकर गावीजी ने स्थिति को शान्त करने में मदद की और फिर वहा से वह अहमदाबाद गये। उनकी उपस्थिति ने वान्ति स्थापित करने में यहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने नत्याग्रह को स्थिगत कर दिया और उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला।

एक ओर यह स्थिति थी, दूसरी ओर अमृतसर में दुर्घटनाएँ विकट रूप घारण करती पा रही थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फौजी-कानून जारी करने को कोई घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह वात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल ने ही ज्यावहारिक रूप में फौजी-कानून जारी था। सच पृद्धिए तो लाहीर और अमृतसर में १५ अप्रैल को हो फौजी कानून जारी करने की

घोषणा की गई थी। इसके बाद ही पजाब के दो-तीन जिलो में वह और जारी कर दिया गया था।

जिलयांवाला-हत्याकांड

१३ अप्रैल को, अमृतसर मे एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जलियावालाबाग में एक वडी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मघ्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी वनाये हुए है। इसका दरवाजा बहुत ही सकरा है, इतना कि एक गाडी उसमें हो कर नहीं निकल सकती। बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, स्त्रिया और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घुसे उस समय हसराज नाम का एक व्यक्ति व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया । गोली तब तक चलती रही जब तक कि सारे कारतूस खतम नहीं हो गये। कुल सोलह सौ फैर किये गये थे। सरकार के स्वय अपने बयान के मुताबिक चार सै। मरे और घायलो की सख्या एक और दो हजार के बीच थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजो से चलवाई गई थी, जिनक पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब बाग में एक ऊचे स्थान पर खडे हुए थे। सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतको और उन लोगो को जो संख्त घायल हो गये थे, सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहा उन्हें रात भर न तो पानी ही पीने को मिला और न डाक्टरी या कोई अन्य सहायता ही मिलो।

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी भी सजाये देखने को मिली जिनका स्वप्त में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबकें सामने बेत लगाना आम तोर पर चालू था। लेकिन 'पेट के बल रेगने के हुक्म' ने इन सब को मात कर दिया था। रेलवे-स्टेशनो पर तीसरे दर्जें का टिकट बचनें की मनाही कर दी गई थी। इससे लोगो का सफर करना आमतौर पर बन्द ही गया था। दो आदिमयों से अधिक एक-साथ पटिरयों पर नहीं चल सकते थे। सार्जिक्ले सब-की-सब फीज ने अपने कब्जे में ले ली थी। जिन लोगों ने अपनी द्काने बन्द कर दी थी उन्हें खोलने के लिए बाध्य किया गया था। न खोलनेवालें के लिए कठोर दण्ड की आज्ञा थी। किले के नीचे नगा करके, सबके सामने बेत लगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के अनेक भागों में वेत

अमृतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमो का फैसला किया गया था,

उनके अनुसार सगीन जुर्मों के अभियोग में २६ म आदिमयो पर मार्शल-ला-कमीशन के सामने मुकदमें चले। मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जाव्ते के साधारण नियमों के पालन करने का भी कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। इनमें से २१ म आदिमयों को सजायें दी गई। ५१ को फासों की सजा, ४६ को आजन्म कालापानी, २ को १०-१० वरस की सजा, ७६ को ७-७ वरस की सजा, १० को ५-५ की, १३ को ३-३ की और ११ को बहुत थोड़ी मियाद की सजायें दी गई। इसमें वे मुकदमें शामिल नहों है जिनका फैसला सरसरी में फौजी अफसरों ने किया था। इनकी सख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और १० आदिमयों को मार्शल-ला के अनुसार मुक्की मिजस्ट्रेटों ने सजा दी थी।

हन्टर-किमटी के सदस्य जिस्टस रैकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल डायर ने जो उत्तर दिया था उसे भी हम यहा देते हैं —

जिस्टिस रैकिन—जनरल, मुझे इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा कीजिए कि, आपने जो कुछ किया वह क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ?

जनरल डायर—नहीं, यह भय-प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तव्य था, जिसका मुझे पालन करना पडा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैंने सोचा कि मैं खूब अच्छो तरह गोली चलाऊं और इतने जोर के साथ चलाऊ कि मुझे या अन्य किसी को फिर कभी गोली न चलानी पडे। मेरा खयाल है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीड को तितर-वितर कर सकता था। लेकिन लोग फिर वापस आ जाते, मेरी हसी उडाते और मैं बेवकूफ बना होता।

उपर्युक्त वाते वे हैं जिन्हें हन्टर कमीशन के सामने १६२० के आरम्भ में जनरल डायर ने स्वय स्वीकार किया था। अमृतसर की दुर्घटना के वाद, पजाब से आने और जाने वाले लोगों पर इतनी कड़ी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तार-पूर्वक समाचार काग्रेस-किमटी को भी जुलाई १६१६ से पहले नहीं जात हो सका और मालूम भी हुआ तो खुल्लमखुल्ला नहीं। कलकत्ते के लॉ-एसोसियेंगन के भवन में जब काग्रेस-किमटी की बैठक हो रही थी, तब यह समाचार कानो-कान डरते-डरते कहा गया, फिर भी यह साववानी रखी गई कि यह समाचार ओरों से न कहा जाय। पजाब की दुर्घटना अमृतसर तक हो सीमित न रही, विक्कि नाहाँर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को भी अत्याचार और वर्वरतापूर्ण कृत्या का शिकार होना पड़ा।

मरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अन्य स्थानो की अपेक्षा, लाहाँर मे फीजी-कानून का बहुन जोर था। करप्यू-आर्डर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था। यदि फोई व्यक्ति शाम के द बजे के बाद बाहर निकलता तो वह गोली से मार दिया जा सनता था, बेत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो मकता था, कैद हो सकती थी, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दुकाने वन्द थी उन्हें लोलने की

आज्ञा दे दी गई थी। जो न खोले उसे या तो गोली से उडाया जा सकता था या उसकी दुकान खोलकर सारा सामान लोगो में मुफ्त बाट दिया जा सकता था। वकील तथा दला नो को यह आज्ञा दे दो गई थी कि वे शहर से बाहर कही न जाय। जिनके मकानो की दावारो पर फौजो कानून के नोटिस चिपकाय गये थे उन्हें यह हुक्म दे दिया गया या कि वे उनकी हिफाजत करे ओर यदि किसी ने उन्हें विगाड दिया या फाड दिया तो वे सजा के मुस्तहक होगे, हालाकि रात्रि के समय उन्हें बाहर रहने की इजाजत नही थो। भारतायो को मोटर-साइकिलो तथा मोटरो को फौज मे जमा कर देने का हुक्म जारो कर दिया गया था। इतना ही नही, अधिकारियो को वे इस्तेमाल के लिए दे दो गई थी। तागेवालो ने भी हडताल में भाग लिया था। इन लोगो को सबक सिखाने के लिए ३०० तागे जमा कर लिये गये थे, और यह हुक्म दे दिया गया था कि वे नगर का घनो आबादी से वाहर, नियत समय और जगहो पर, अपनी हाजिरी दिया करे। १६ से २० वर्ष की उम्र के लडको तथा विद्यार्थियो पर विशेष रूप से कडी नजर थी। लाहौर जैसे शहर मे, जहाँ कई कॉलेज है, विद्यायियो को दिन मे चार बार हाजिरी देने का हुक्म था। जहाँ जहाँ हाजिरी ली जाती थी उनमें से एक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील की दूरी पर था। अप्रैल मास की कडी धूप में, जोकि पजाब में वर्ष का सबसे अधिक गर्म महीना होता है अर्र जबिक गर्मी १०८ डिग्रो से ऊपर होती है, इन नौजवानो को रोजाना १६ मील पैदल चलना पडता था। इनमें से कुछ तो रास्ते में बेहोश होकर गिर भी जाते थे। इतना होने पर भी कर्नल जॉनसन, बहुत हो प्रसन्न थे। लाहौर के यूरोपियनों ने तो उन्हें बिदाई देते समय एक दावत दी थी और "गरीबों का रक्षक" की उपाधि से अलकृत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की थी। गुजरान-वाला में कर्नल ओब्रायन ने, कसूर में कैप्टिन डोवटेन ने और शेखूपुरा में मिस्टर बॉसवर्थ स्मिय ने खास तौर पर अत्याचार करने में खूब ही नाम कमाया था। कर्नल ओन्नायन ने कमिटी के सामने अपनी गवाही में कहा था कि भीड जहा कही पाई गई वहीं उस पर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक बार एक हवाई जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेण्ट डॉडिकन्स के चार्ज मे था, एक खेत मे २० किसानो को एकत्र देखा । उन्होने उन पर मशोनगन् से तब तक गोली चलाई जब तक कि वे भाग नहीं गये। उन्होंने एक मकान के सामने आदिमियों के एक झुण्ड को देखा। वहा एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसलिए वहा उन्होने उन पर एक बम गिरा दिया, क्यों कि उनके दिल में इस तरह का कोई शक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुर्दनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्वी वह सज्जन है जिन्होने लोगो के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि वे वलवाई है, जो शहर से आ-जा रहे है। उन्ही के शब्दो में सुनिए --"लोगो की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मैने उनको तितर-वितर करने के लिए

गोली चला दी। ज्योही भीड तितर-ियतर हो गई, मैंने गाव पर भी मजीनगन लगा दी। में निया है कि कुछ मकानों में गालिया लगी थी। में निया और अपराधी में जोई पहचान नहीं कर सकता था। में दो सी फीट की ऊँचाई पर या और यह मेंने प्रकार देख सकता था कि मैं नया कर रहा हू। मेरे उद्देश्य की पूर्ति गियल वम बन्माने में नहीं हुई। गोली केवल नुकसान पहुचाने के लिए ही नहीं चलाई गई थी, वह स्वयं गाववालों के हिन के लिए चलाई गई थी। कुछ का मार कर में समझता था, में गाववालों को फिर एक इहोने में रोक दूगा। मरे इस कार्य का अनर भी पड़ा था। इसके बाद शहर की तरफ मुड़ा। वहां बम बरसाये और उन लागे। पर गालिया चलाई जो भाग जाने की काशिन कर रहे थे।"

कनंत अधायन ने एक यह हुक्म जारी किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किनी अपन अफार से मिल तो वह उनको सताम करे, अगर नवारी में जा रहा हो वा पाउं पर नवार हा तो उत्तर जाय, अगर छाता लगाये हुए हो तो उसे नीचे सुका दे। कर्नेल आहायन ने कमिटी के नामने कहा था कि "यह हुक्म इमिलए अन्छा था कि नौगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नये मातिक आये हैं।" गोगों क कोंडे लगवाये गये, जुमीना किया गया और पूर्वोक्त राक्षणी हुक्म न मानने

मौको पर लडको से यह कहलाया जाता था, "मैने कोई अपराघ नही किया है, मैं कोई अपराघ नही करूगा, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है!"

दुर्घटनात्रों के बाद

घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप धारण कर लेने से गाधीजी के हृदय को बहुत बडा धक्का लगा। उन्होने इस बात को स्वीकार किया कि मैने महान् भूल की है। अत उन्होने एक ओर तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दूसरी और यह घोषणा की कि मै शान्ति स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हू। लॉर्ड चेम्सकोर्ड ने १४ अप्रैल १९१६ को एक हुक्म निकाला, जिसमे स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई कि वह उत्पातों का शीघ्र ही अन्त कर देने के लिए जितनी शक्ति उसके पास है सबको लगा देगी । इसी बीच तीसरे अफगान-युद्ध ने पञ्जाब को स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। ४ मई को सारी फौज युद्ध के लिए तैयार कर ली गई। इधर फौजी-कानून अपने खूनी कारनामो को ११ जून तक बराबर चलाता रहा। फौजी-कानून को आव-रयक रूप से एक मुद्दत तक जारी रखने के विरोध में सर शकरन् नायर ने १६ जुलाई को वाइसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय मे पञ्जाव पर एक कठोर सेसर बिठा दिया गया । एण्डरूज साहब को पञ्जाब की भूमि पर कदम रखने की मनाही करदी गई । बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया गया। यह मई मास केप्रारम्भ की बात है। मिस्टर ई० नार्टन बैरिस्टर को जो कि पञ्जाब इसलिए जाना चाहते थे कि वहा कैदियो की पैरवी करे, पञ्जाब मे घुसने को मनाही कर दी गई। चारो ओर से पञ्जाब में हुए अत्याचारो की जाच के लिए एक कमीशन बैठाने की पुकार मच रही थी। खास फौजी-अदालतो-द्वारा लोगो को जो घातक और जङ्गली सजाये दी गई थी उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी माग थी। लाला हरिकशनलाल को, जो एक प्रतिष्ठित काग्रेसी और बहुत बडे धनिक व्यक्ति थे, आजन्म कालेपानी की सजा दी गई थी। लगभग ४० लाख रुपये की उनकी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्म दिया गया था।

सितम्बर १६१६ में वाइसराय ने इस उद्देश्य से ह्न्टर-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की, कि वह पञ्जाब के उपद्रवों की जान करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर को, इनडेम्निटी-बिल आया, जो आम तौर पर फौजी-कानून के साथ आया करता है। पण्डित मदनमोहन मालवीय ने इसे मुल्तवी कराने के लिए बहुत जोर लगाया, परन्तु इसका फल कुछ भी नहीं हुआ।

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई। उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्ली और पञ्जाब से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोध

किया गया और पञ्जाब में किये गये अत्याचारो की जाच करने पर जोर दिया गया । देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा हो गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए श्री विट्ठलभाई पटेल और श्री नृसिंह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ। ये लोग २६ अप्रैल १६१६ को इंग्लैण्ड के लिए रवाना हो गये। प जून को महासिमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। इधर गवर्नर-जनरल ने २१ अप्रैल को ही एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमे पञ्जाब की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जर्म हए हो उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत-द्वारा करा सके। गिरफ्तार शुदा लोगो को अपनो इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नही थी। देश के सारेँ प्रमुख-पत्रो के सम्पादको, श्रीमती बेसेण्ट और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने एण्डरूज साहब से अनुरोध किया कि वह पञ्जाव जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जाच करे। पर वहा वह गिरफ्तार कर लिये गये। प जून की बैठक में यह बात सुझाई गई कि तहकीकात के लिए जो कमिटी नियत हो वह पञ्जाब जाकर इस बात की भी जाच करे कि सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रगरूट भरती करने में किन हथकण्डो और ढगो को काम में लाया गया था, किस प्रकार 'लेबर कोर' में आदिमियो को भरती किया गया था, किस प्रकार लडाई के लिए कर्ज लिया गया था और फौजी-कानूनो द्वारा किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हार्निमैन को इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, कि उन्होने 'बाम्बे कानिकल' मे सरकार की पजाव-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हानिमैन साहब को दिये गये देश-निकाले के हुक्म की मसूख कर दे।

महासमिति ने एक किमटी इसलिए नियुवत की कि वह पजाव की दुर्घटनाओं की जाच करे, इस सम्बन्ध में इग्लैण्ड तथा दोनो स्थानो में आवश्यक कानूनी कारं-वाई करें और इस कार्य के लिए धन एकत्र करें। इस किमटी में बाद को, यानी १६ अक्तूधर को गांधीजी, एण्डल्ज, स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया। नवम्बर के प्रारम्भ में मि० एण्डल्ज दक्षिण-अफीका चलें गयें। उन्होंने गवाहियों के रूप में जितनी सामग्री एकत्र की थी वह सब कांग्रेस-किमटी को देते गयें। १६ और २० जुलाई को कलकत्ते में महासमिति की फिर बैठक हुई, जिसमें जिचारणीय मुख्य बात यह थी कि कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कहा किया जाय। अन्त में उसे अमृतसर में ही करने का निश्चय हुआ। एक प्रस्ताव द्वारा उस मांग को फिर दोहराया गया जिसमें सम्राट की सरकार-द्वारा जाच करने के लिए एक सिमिति नियुक्त करने की प्रार्थना की गई। १० हजार रुपयें की एक रकम पञ्जाब सिमिति के लिए जमा की गई। २१ जुलाई को गांघीजी का वक्तव्य

प्रकाशित हुआ, जिसमें सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थगित करने का जिक था। वह इस प्रकार हैं —

गांधीजी का वक्तव्य

''बम्बई के गवर्नर-द्वारा भारत-सरकार ने मुझे एक बहुत ही गम्भीर चेता-वनी दो है, कि सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत हो बुरा परिणाम निकल सकता है। बम्बई के गवर्नर ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तब यह चेतावनी उन्होने और भी जोर के साथ दोहराई थो। इन चेता-विनयों को ध्यान में रखकर, मैने बहुत सोच-विचार करने के बाद यह निश्चय किया है कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्भ न करूँ। मै यहा इतना और बता देना चाहता हू कि उन कुछ मित्रों ने भी, जो गरम-दल के माने जाते हैं, मुझे यही सलाह दी है। उनका कहना सिर्फ इतना हो था कि इससे सम्भव है वे लाग, जिन्होने सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझा है, फिर मार-काट कर बैठे। जव दूसरे सत्याग्रहियो के साथ मैं इस नतोंजे पर पहुचा कि सविनय-भग के रूप मे सत्याग्रह शुरू कर दिया जाय, तब मैंने वाइसराय को एक पत्र भेजकर उन पर अपना यह इरादा प्रकट कर दिया था और उनसे यह अनुरोध किया था कि वे रौलट बिल को वापस ले ले और एक जोरदार तथा निष्पक्ष कमिटी शोध नियुक्त करने की घोषणा करे जिसे यह भी अधिकार रहे कि पञ्जाब की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में दी गई सजाओ को फिर से निगरानो कर सके। मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि जिस जाच-कमिटी के लिए मैने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रमाणों के मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ों हो नासमझी होगी, यदि मैं सरकार की चेतावनी पर घ्यान न दू। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाना है। एक सत्याग्रही कभी सरकार को विषम स्थिति में डालना नहीं चाहता। मैं अनुभव करता हूं कि मैं देश की, सरकार की और उन पञ्जाबी नेताओ की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय-पूर्वक सजा दो गई है, और वह भी बड़ो हो निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक सेवा करूँगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को स्थगित कर दू। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मैंने हो लगाई थी। मेरा कभी-कभी सत्याग्रह करना यदि आग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की किताब में ज्यो-का-त्यों बनाये रखने का हठ देश के हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याप्रह फिर से न होने देने का एक-मात्र उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया जाय।"

शिष्ट मंडल का कार्य

गाघीजी ने जिस समय यह वक्तव्य दिया उस समय इग्लैण्ड मे लॉर्ड सेलवार्न की अध्यक्षता में सयुक्त पार्लमेण्टरी कमिटी की बैठक हो रही थी। ऐसे अवसर पर काग्रेसी शिष्ट-मडल वहाँ पहुंचा। उसके सामने श्री विट्ठलभाई पटेल और वी० पो० माववराव ने वडी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपस्थित किया। उनके साथ लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्र पाल, गणेंग श्रोकृष्ण खापर्डे, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रङ्गस्वामो आयगर, नृसिह चिन्तामणि केलकर, सय्यद हसनइमाम, डा० साठचे, भि० हानिमैन आदि भी थे। श्री वी० पी० माघवराव मैसूर-राज्य के भूतपूर्व दोवान थे। उनकी शिष्टता आर सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतन्त्रता-प्रिय स्वभाव ने काग्रेस को इंग्लैण्ड को जनता की नजरों में बहुत ही ऊचा उठा दिया और मि० बेन स्पूर (एम० पी०) जैसो ने उनकी भूरि-भूरि प्रश्नना का।

श्रा विठ्ठलभाई पटेल और काग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुहरा मुकाबला था। एक और ता उसे काग्रेस की ब्रिटिश-किमटो से उलझना था, दूसरी ओर श्रीमती बेसेण्ट से जो अपनी अथक शक्ति के साथ काग्रेस का विरोध कर रही थी। काग्रेशो शिष्ट-मण्डल आत्म-निर्णय आर पूर्ण उत्तरदायी शासन को माग के साथ दिल्लोवाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। २५ अक्तूबर १६१६ को अलवर्ट-हाल में जो सभा हुई, उसमें दोनो दलों के मृतभेद इतने खुले तीर पर सामने आये कि सभापति मि॰ लान्सवरी वडो दुविधा में पड गये। यह सभा भारतीय हामरूल-लीग को लन्दन-शाखा की ओर से को गई थो, जिसकी स्थापना श्रीमता बसेण्ट ने की थो। अन्त में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो। सकतो थी। प्रस्ताव में कहा गया कि 'बिटिश राष्ट्र समूह की यह विशाल सभा जो इस वात पर जोर देती है कि राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत सब राष्ट्रों को स्व-शासन का अविकार मिलना चाहिए, इस बात को ऐलान करती है कि भारतीय जनता भी शोघ्र-स-शोघ्र आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण स्वत्व पाने की हकदार है।' मि० लान्सवरो इस सभा के चुने हुए सभापति थे। उनके बीच मे पड़ने से हा प्रस्ताव को यह रूप प्राप्त हुआ, नहीं तो पहले जो मसविदा वनाया गया था उसमें तो मि॰ माटेगु के विल का समर्थन किया गया था। लेकिन इतने पर भी श्रीमती वेसेण्ट ने स्पप्ट रूप से मि॰ माटेगु के विल का समर्थन किया, जिस पर श्री विट्रलभाई पटेल को उनका प्रतिवाद करना पडा।

जांच-सिर्मात की नियुक्ति

महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मोतालाल नेहरू और मदनमोहन मालवीय पजाव में हुई दुर्घटनाओं को जाच के लिए पजाव गये। कुछ ही समय वाद दीनवन्धु एण्डरूज भी वहा पहुँच गये। इसके वाद पं० मोतोलाल और मालवीयजी लीट आये, लेकिन मोतोलालजी दुवारा फिर वहा गये। पं० जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तमदास टण्डन एण्डरूज

साहब के साथ हुए। गाधीजी भी, जैसे ही उन पर से प्रवेश-निपेध का हुक्म उठाया गया, १७ अक्तूबर को सबके साथ जा मिले। पजाब के लोग भयभीत हो रहें थे, लेकिन ज्यो हां गाधोजो उनके पास पहुचे त्यो हो उनमे फिर से आत्य-विश्वास आ गया। लाहौर और अमृतसर में, दोनो जगह, उनके आगमन को विजय से कम नहीं समझा गया। इसा बीच सरकारी जाचे की घोषणा हुई। जिन वाती की जाच सरकारी जाच-किमटी करनेवाली थी उनकी मर्यादा काग्रेस की जाच से वहुत कम थो। फिर भी सरकारी किमटो से सहयोग करना ठीक समझा गया। चित्तरजन दास तुरन्त कलकत्ता से पजाब आये और काग्रेस का और से हण्टर-कमोशन के सामने हाजिर हुए। लेकिन काग्रेस-उप-समिति को ऐमी कठिनाइयो का सामना करना पड़ा जिनको पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुर्घटनाओ की जाच करने वा नी कमिटी (हटर-कमिटी) से उसको अपना सहयाग हटा लेना पड़ा। काग्रेस उप-समिति चाहती थी कि मार्शन लॉ के कुछ कैदिया को पहरे के अन्दर जाच के समय हाजिर रहने तथा जाच में मदद करने के लिए बुलाया जाय, लेकिन इस वात को इंजाजत नहीं दो गई। उप-सिमिति ने इस पर पजाब-सरकार के खिलाफ भारत-सरकार और भारत-मन्त्री से अपील को, लेकिन उन्होने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया। ऐपो हालत में उन लोगो ने भो, जो कि फाजो-कानून के मातहत जे नो में थे, सहयोग न करने के निश्चय की हो ताईद को—-ओर बाद के अनुभव ने भी इस निश्चय को उचित हो सिद्ध किया । अतएव काग्रेस ने एक समिति द्वारा अपनो जाच अलग शुरू की। गा गोजो, मोतोलाल नेहरू, चित्तरजन दास, फजलुल हक ओर अव्वास तैयाजी इस किनटी के सदस्य थे और के० सन्तानम् मन्त्रा । लेकिन इसके बाद शोध्र हो प० मोती नाल नेहरू अमृतसर-काग्रेस के सभा-पित निर्वाचित हुए, इसलिए उन्होने पद त्याग दिया और श्रा मुकुन्दराव जयकर उनको जगह सदस्य बनाये गये। लन्दन के सालिसिटर मि० नेवलो भी, जिनके सुपूर्व प्रित्री-कौसिल में को जानेवाली अपीलो का काम था, कमिटा के साथ थे। साथ हो यह भी निश्चय हुआ कि जलियावाला-बाग को प्राप्त करके वहा शहीदी का एक स्मारक बनाया जाय, और इसके लिए मालवीयजी की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी गई।

अ्रमृतसर-कांग्रे**स**ः १६१६

अमृतसर-काग्रेस में श्री चित्तरजन दास प्रमुख रूप से सामने आये। उस अधि-वेशन में उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास बाबू बना कर लाये थे और सशोधन के बाद विषय-समिति ने उसे मजूर किया था। वह इस प्रकार है—

"(क) यह काग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि

भारतवर्ष उत्तरादायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो वात समझी या कही जाती है उनको यह काग्रेस अस्वीकार करती है।

(ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की काग्रेस-द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर हो काग्रेस दृढ है और इसकी राय है कि सुवार-कानून अपूर्ण, असन्तोष-जनक और निराशापूर्ण है।

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्लमेंट को शोध्र कार्रवाई करनी चाहिए।"

अमृतसर-काग्रेस मे ५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वापस वुलाने से लेकर कानून मालगुजारी, मजदूरों को हीनावस्था और तीसरे दर्जे के मुसा फिरो के दु खो की जाच की माग तक के प्रस्ताव थे। इस काग्रेस में ३६ हजार लोग आये थे, जिनमे ६ हजार मामूली प्रतिनिधि और काई १२०० किसान-प्रतिनिधि थे। काग्रेस के सारे वातावरण में मानो विजली फैली हुई थी। पंजाब और उसपर हुए अत्याचारो पर स्वभावत ही सबसे अधिक घ्यान दिया गया था। गाधीजी उत्सुक थे कि पजाव और गुजरात में जो मारकाट लोगो को तरफ से हो गई थी उसकी निन्दा की जाय. लेकिन विषय-समिति में उनका प्रस्ताव गिर गया। गाधीजी को इससे निराशा हुई। रात बहुत हो चुको थी। उन्होने, यदि काग्रेस उनके दृष्टि-विन्दु को न अपना सके तो दृढता परन्तु साथ ही शिष्टता और अदव के साथ काग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की । दूसरे ही दिन सुवह प्रस्ताव मजूर हुआ। इस विषय पर गाधीजी ने जो व्याख्यान दिया वह अत्यन्त उच्चकोटि का आर प्रभावशाली था। उन्होने वहुत सक्षेप में अपने सग्राम को योजना और भावी नाति का दिग्दर्शन कराया था। उन्होने कहा कि "हमारी भावी सफलता को सारी कुंजी इसी वात में है कि हम उसके मूलभूत सत्य को समझ लें, उसे हृदय से स्वीकार कर ले और उसके अनुसार आचरणे भी रखे। जिस अश तक हम उसके मूल शाञ्वत सत्य को मानने में असमर्थ होगे उसी हद तक हमारी असफलता भी निश्चत है। मैं कहता हू कि यदि हम लोगों ने मारकाट न को होतो—तो यह वसेड़ा न खड़ा होता, लेकिन उस समय सरकार भी पागल हो गई थी और हम भी पागल हो गये थे। मैं कहता हू, पागलपन का जवाब पागलपन से मत दो, बल्कि पागलपन के मुकावले में समझदारी से काम लो और देखों कि सारी वाजी आपके हाय में है।" आत्मा को जगानेवाले कैसे शब्द है ये, जो अवतक कानों में गूजते हैं! परन्तु प्रश्न यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समझा होगा ? ज्य समय तक गाधीजी सरकार से सहयोग तोडने के लिए न तो राजी थे और न तैयार ही थे। इसोलिए युवराज के स्वागत करने का प्रस्ताव यहा पान किया गया; गोया दिल्ली में जो बात छूट गई थो उसकी पूर्ति यहा की गई। यही कारण है कि अमृतसर में सहयोग के आश्वासन वाले प्रस्ताव में जोडा गया टुकडा पास हो गया, हालाकि समझौते के कारण वह बहुत-कुछ कमजोर हो गया था।

पजाब में किये गये अत्याचारों के प्रश्न पर विचार करते हुए काग्रेस ने उस हर्जाना लेने को व्यवस्था को, जो कुछ लोगों पर कही-कही लागू को गई थी, रह करने को प्रार्थना को। मौलिक अधिकारो-सम्बन्धों भी एक प्रस्ताव पास हुआ, जिससे शासन-सुधार-सम्बन्धों प्रस्ताव का वल और बढ गया। इसके बाद काग्रेस ने प्रेस-ऐक्ट और रौलट-ऐक्ट को उठा देने और सम्राट् की ओर से मुक्ति की घोषणा होने पर जो कैंदी तब तक जेल में पड़े हुए थे, उनकी रिहाई के लिए जोर दिया।

: 9:

असहयोग का जन्म : १६२०

खिलाफत-सम्बन्धी श्रन्याय

१६२० का आरम्भ भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में दलवन्दियों से हुआ। उदार अर्थात् नरम दल वाले काग्रेस से अलगहों गये थे और १६१६ के दिसम्बर में कलकते में एकत्र हुए थे। बाको वचे काग्रेसियों में भी फूट के लक्षण दिखाई पड रहें थे। अमृतसर में मुख्य प्रश्न था, असहयोग या अडगा। नये साल का आरम्भ होने के कुछ महोने बाद अमृतसर में बने दलों को स्थिति उलट गई। गांधीजी ने असहयोग का बोडा उठा लिया था और जो लोग अमृतसर में उनके सहयोग के विरुद्ध थे वे अब एक बार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। बात यह थी कि पजाब के अत्याचार और खिलाफत के प्रश्न पर जनता में खलबली बढ रही थी। १६२० की घटना खिलाफत के महान् आन्दोलन को लेकर आरभ हुई थी। महायुद्ध के समय प्रधान मत्रों मि० लायड जार्ज ने भारत के मुसलमानों को कुछ बचन दिये थे, जिनके कारण भारतीय मुसलमान देश के बाहर गये और अपने तुर्की सहर्यों यो से लडे। परन्तु जब युद्ध समाप्त हो गया तब दिये गये वचनों को बुरो तरह भग किया गया। ब्रिटिश प्रधान-मत्रों के विश्वासघात से भारत के मुसलमानों में कोच का लहर फैल गई। अमृतसर में प्रमुख काग्रेसी और खिलाफतों नेता एकत्र हुए और उन्होंने लायड जार्ज की करतूत से उत्पन्न हुई देश की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और अन्त में गांधोजी के ने तृत्व में खिलाफत आन्दोलन करने का निश्चय किया।

१६ जनवरी १६२० को डा० अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला। उसने उन्हें बताया कि तुर्की-साम्राज्य क और सुलतान को खलीका बनाये रखना आवश्यक है। वाइसराय का उत्तर बहुत कुछ निराशा-जनक था। इस पर मुसलमान नेताओ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमे

उन्होने यह दृढ सकल्प प्रकट किया कि यदि संधि की शर्ते मुसलमानों के धर्म और भावों के विरुद्ध गई तो इससे मुसलमानों को वफादारी को धक्का लगेगा।

फरवरा और मार्च के महोनो में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र में बराबर प्रमुख स्थान पाता रहा। १६२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट-मण्डल मोलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया। इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव का ओर से मि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्डल प्रधानमन्त्री से भी मिला। उसने अपने विचार शान्ति-परिषद् की बड़ी कौसिल के आगे रखन की अनुमति चाही, पर वह न मिली।

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ हा इस बात पर जोर दिया कि वैसे तुर्की तुर्की-भूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जा प्रदेश तुर्की नहीं है उसपर कोई अधिकार न रख सकेगा। इसने भारत के खिलाफत-सम्बन्धों सारे प्रश्न की ही जड काट दी। इसलिए १६ मार्च राष्ट्रोय गोक-दिवस नियत हुआ। उस दिन उपवास, प्रार्थनाए और हडताले को गई।

गाधीजो फिर मैदान मे आये। उन्होने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि को शर्ते भारत के मुसलमानो के भावो के अनुकूल न हुई तो मैं असहयोग-आन्दोलन शुरू करूणा। उन्होने अपने विचार अपने १० मार्च के घाषणा-पत्र मे प्रकट कर दिये जिसमे उन्हें ने कहा कि "यदि हमारी मागे स्वीकार न हुई तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जगली मार्ग पुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोडिए, क्योंकि वह अव्यव-हाँ ये है। यदि में सबको समझा सकू कि यह उपाय हमेगा बुरा है, तो हमारे नव उद्देश्य शोघ्र सिद्ध हो जाय। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग-द्वारा जो रानित उत्पन्न कर सकता है उसका मुकावना कोई नहीं कर सकता। अतएव हमारे निए असहयोग हो एक-मात्र अं।पधि है। यदि यह सब तरह को हिंसा से मुक्त रजी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामवाण औपिध है। यदि सहयोग-हारा हमारा पतन होता हो और हमारे धार्मिक भाव को आघात पहुंचता हैं, तो असहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है। इन्लैण्ड हमने यह खाशा नहीं रख नकता कि हम उन अधिकारों का हनन चुपचाप सह लेगे जो मुगलमानों के जीवन-मृत्यु के प्रम्न हैं। इसलिए हमें जड़ और चोटो दोनो ओर से काम आरम्भ करना चाहिए। जिन लोगों को नरकारी उपाधिया और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें त्याग देना चाहिए। लो नीचे दर्जे की मरागरी नौकरियों पर हैं उन्हें भी नौकरिया छोड़ देनी चाहिए। राटरपोध का गानगी नौकरियों में कोई वास्ता नहीं है। पर मैं उन लोगों के, जो

असहयोग की औषधि को नहीं अपनात, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने वात को पसन्द नहीं कर सकता। सत्याग्र हो हो कर नौकरी छोड़ देना हो जनता भावों और असतोष की कसौटी है। सैनिकों से सेना में काम करने से इन्कार क को कहने का समय अभी नहीं आया है। यह उपाय अन्तिम है, पहला नहीं जब वाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान मंत्री हमें दाद न दें तब हमें इस उपाय अवलम्बन करना चाहिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदम ब समझ-बूझकर रखना होगा। हमें धोरे-धोरे बढ़ना होगा, जिससे बड़े-से-बड़े उत्ते पर भी हम अपना आत्म-सयम बनाये रख सके।"

लोकमान्य तिलक के विचार

अशान्ति के इस वातावरण मे २५ मार्च १६२० को पजाब के अत्याचारो गैर सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अ कटाक्षो का लक्ष्य बनाया। १९१९ की घटनाये ६ अप्रैल से आरम्भ हुई थी व उनका अन्त १३ तारीख को जिलयावाला-बाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ थ अत वह सप्ताह १६२० में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। १४ मई १६२० तुर्किस्तान के साथ सिंघ की शत प्रकाशित हुई, जिससे खिलाफत आन्दोलन और भी जोर पकडा। इसके वाद ही गाधोजी ने अपने एक सकल्प का घोष की। लाकमान्य तिलक ने इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं किया, पर स ही इसका विरोध भी नहीं किया। इन दोनो महान् नेताओं ने अप्रैल के ती। हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये। इसी अवसर पर गावोजी ने होमरू लीग का सभापतित्व ग्रहण किया। अपने वक्तव्य मे उन्होने कहा कि "मुझे आ है कि सारे दल काग्रेस को एक ऐसी राष्ट्रीय सस्था बनाना चाहेगे जिसके द्वारा काग्रेस की नीति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से अपील कर सके। मैं ली की नोति को ऐसी बनाना चाहता हूँ जिससे काग्रेस दल-बन्दियो से ऊपर कर अपना राष्ट्रीय पद कायम रख सके। मेरा विश्वास है कि देश के राजनित् जीवन में कठोर सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है में लीग से यह आशा नहीं रखता कि वह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, ' मै शक्ति भर चेष्टा करूगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामो में सत्य और अहिंसा काम लिया जाय। तब हम सरकार और उसके उपायो से न भयभीत होगे, उनके प्रति अविश्वास रखेगे। फिलहाल मेरा उद्देश्य अपने काम के औवित्य उसमें समाविष्ट नोति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सदस पर विश्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओ को आमि करना है।"

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुघारों के प्रति अपनी नीति प्रव

करते हुए कहा कि काग्रेस-प्रजातंत्र दल मे काग्रेस के प्रति अगाध भिक्त और प्रजा-तत्र के प्रति आस्था काम कर रहो है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक अथवा सामाजिक बंधन लगा दिये गये है उन्हे उठा दिया जाय। इस दल का धार्मिक सहिष्णुता ओर अपने लिए अपने धर्म को पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता को खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्तव्य हैं। यह दल मुसलमानो के उस दावे का समर्थन करता है जो खिलाफत-सबधो प्रश्नो का हल इस्लाम धर्म के सिद्धान्तो के अनुसार चाहता है। यह दल जोर के साथ प्रतिपादन करता है कि भारत प्रतिनिधि उत्तरदायो शासन के सर्वथा योग्य है और अन्तिम-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार का ढाचा स्वय तैयार करने का और यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली भारत के लिए सबसे अच्छो रहेगो, पूर्ण अधिकार चाहता है। यह दल माण्टेगु-सुधार-विधान को अपर्याप्त, असन्ताब-पूर्ण और निराशाजनक समझता है और इस दोष को दूर करने की चेष्टा करने के निमित्त मजदूरदल के सदस्यो और ब्रिटिश-पार्लमें प्ट के अन्य भारत-हितैपियो को सहायता से शोघ्न-से-शीघ्र एक नवीन सुधार-बिल पास कराना चाहता है। जिसका उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्था-पित करना हो और जो सेना पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी स्वतत्रता प्रदान करे और वैधानिक-गारिण्टयो-सहित अधिकारो की विस्तृत घोषणा करे।"

सत्याग्रह का निश्चय

अभी मुसलमानो का शिष्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुर्किस्तान के साथ सिंघ को प्रस्तावित शर्ते प्रकाशित हो गई आर भारत में उनके साथ-ही साथ वाइस-राय का सदेश भी प्रकाशित हुआ, जिसमें भारतीय मुसलमानो को वे शर्ते समझाई गई थी। हण्टर-किमटी की रिपोर्ट भी इसो समय प्रकाशित हुई। वस, सारे देश में आग लग गई। खिलाफत-किमटी की बैठक बम्बई में हुई जिसमें गांधीजी के असह-योग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १६२० की २८ मई को असहयोग भारतीय मुसलमानो का एकमात्र शस्त्र समझ कर अपना लिया गया। ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें हण्टर-किमटी की रिपोर्ट और तुर्किस्तान के साथ संधि की शर्तों पर विचार किया गया। लम्बे-चीडे वाद-विवाद के बाद असहयोग पर विचार करने के लिए काग्रेस का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया।

इस समय तक गाधीजी चम्पारन, खेडा और अहमदाबाद में सत्याग्रह करके देश को स्थायो लाभ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त कर चुके थे। उन्होने चम्पारन में १६१७-१८ में सत्याग्रह किया और नोल की खेती का अन्त करने में सफल हुए।

गाधीजी ने १९१८ में खेडा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह दो कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय। अन्त में खेडा के किसानों को आशिक छूट मिल गई। तोसरी घटना अहमदाबाद मिल-हडताल थी, जो १६१८ के माचें में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच एक समझौता ठहराया गया, पर इसी बीच कुछ मजदूरों ने दुर्बलता और विह्वलता का परिचय दिया और मजदूरों का सगठन टूटता-सा दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर गाधीजी ने उपवास करने की प्रतिज्ञा को। इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा करने का गाधीजी का यह पहला अवसर था, पर इसके सिवा और कोई चारा न था। इससे सपूर्ण देश पर चिन्ता छा गई। अन्त में समझौता हो गया। इन सत्याग्रह-आन्दोलनों में सफल होने से उनके प्रति जनता का विश्वास जम गया।

कुली प्रथा का अन्त

भारत के राजनैतिक क्षेत्र मे १६२० को घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमे १६२० की १ जनवरों के उत्सव को चर्चा करनो है। इस दिन तक उपिनवेशों में शर्त-बन्दी कुलो-प्रथा एक शताब्दी से जारो था। जब भारत सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने को अनुमित देने से इन्कार कर दिया तब नेटाल मे इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुला-प्रथा का अन्त स्वत ही हो गया, क्यांकि वहा मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथ्वी के अन्य भागों के उपनिवेशों में शर्तवन्दी कुला-प्रथा उसी प्रकार जारी था। गावोजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। श्रोमता बेंसण्ट ने मद्रास मे श्रागणेश किया। १६१७ के मार्च-अप्रैल मे आन्दोलन पूरे जोर पर था। गाधोजी ने ३१ मई १९१७ का दिन नियत कर दिया कि उस दिन तक यह प्रया बन्द होनी चाहिए, नहीं तो भरती रोकने के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा। लॉर्ड चेंम्सफोर्ड ने १२ अप्रैल १६१७ को घोषणा की कि भारत-रक्षा-विधान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कार्रवाई के रूप में मजदूरों की भरती बन्द की जाती है, पर यह स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते हो वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेंगे जिनका उसमें बहुत बडा आर्थिक-हित था। इसलिए एडक्ज साहब गाबीजी की सलाह अर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को हार्दिक सहानुभूति प्राप्त कर ताजा मसाला इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर फिजी गये। वह एक साल तक फिजो में रहें और पहली बार से भी अधिक भयकर ह होकते जमा कर लाये। १६१८ के मार्च में उन्होने मि० माण्टेगु से दिली में भेट की और उनके सामने सारा मामला पेश कर दिया कि शर्तवन्दी कुली-प्रथा घोर अनैतिक है। फलत यह प्रया उठा दी गई। पहली जनवरी १९२० को फिजो, ब्रिटिश गायना, ट्रिनडाड, सुरीनाम

और जमैका के प्रवासी-भारतोयों में हर्ष का वारापार न रहा; क्योंकि वहा अभी तक यह प्रया जारी थो। यह प्रया १८३५ में आरभ की गई थी जिससे उपनिवेशों में शक्कर की खेंगे के लिए हुनों मिन सके।

हएटर रिपोर्ट का प्रभाव

३० मई को महासमिति को बैठक बनारस में हुई, जिसमें हण्टर किमटी की रिपोर्ट पर भारत की ओर से कोव प्रकट किया गया और उस मामले पर विचार करने के लिए विशेष काग्रेस अतिवे गन का निश्चय किया गया। लोकमान्य तिलक इस अवसर पर वनारस से होकर गुजरे, पर उन्होने महासमिति मे भाग न लिया, क्यों कि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रचा न था। फिर भी उन्होंने देशभित और सोजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य कह दिया कि वह महासमिति के धादेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गायीजो ने नेताओं का एक सम्मेलन मुलाकर असहयोग-आन्दोलन का, उसके सामने रखने का निश्चय किया। अवतक भसहयाग-आन्दोलन खिलाफत के प्रश्न से हो सम्बन्ध रखता था। सारे दलो के नेता २ जून १६२० को इलाहाबाद में एकत्र हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की मीति अपनाने का निश्चय किया गया आर कार्यक्रम तैयार करने के लिए गाधोजी शीर कुछ मुसलमान नेताओं को एक समिति बनाई गई। इस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूलो, कालेजो और अदालतो के वहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव मे नवम्बर १६१६ मे दिल्ली अ० भा० खिलाफत-परिषद् ने गांवीजी की सलाह के अनु नार सरकार से असहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय की पुष्टि कलकता और अन्य स्थानों के मुनलमानों ने, ओर १७ अप्रैल १६२० की मद्रास को खिलाफत-परिपद् ने, कर दी थी। मद्रास को खिलाफत-परिपद् ने असहयोग को योजना को जो परिभागा का थी उसके अनुसार उपाधियो और सरकारी नोकरियो का परित्याग, आनरेरी पदो आर कौतिलो की मेम्बरी तथा पुलिस और फीज की नोकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। इस प्रकार खिलाफत पंजाब के अत्याचारो और अपर्याप्त सुवारों ने उवनती हुई त्रिवेणों का रूप धारण कर लिया था। इसी बीच मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, प्यों वि अब तुर्किस्तान के साथ ब्रिटेन की सिंध के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह जान्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमान्त प्रदेश में जा फैरा। व्चगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठ-भेड हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और अगस्त के भीतर-भारार अनुमानत १८,००० मुसलमान अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर क्यान-सरकार ने शोध्र ही इन मुहाजिरीन का दाखिला वन्द कर दिया। जनसे मुननामानो के विचार बदल नवे।

श्रसहयोग का प्रस्ताव

उक्त परिस्थितियो में असहयाग की योजना का नियमानुसार आरम्भ १ अगस्त को हुआ। गाधीजी और अली-भाइयो ने देश का दौरा किया। गाधीजी ने जनता को अनुशासन का पाठ पढाया ओर उसक उछलते हुए उत्साह को सयम में रखा। इस नवीन आन्दोलन के लिए काग्रेस के विशेष अधिवेशन की आवश्यकता थी। इस अधि-वेशन का निश्चय मई में ही हो चुका था। अत यह १६२० के ४ से ६ सितम्बर तक कलकत्ते में हुआ। यह अधिवेशन वडा हो महत्वपूर्ण था। बगाल गांधीजी से पूरी तरह सहमत नहीं था। देशबन्धुदास गावीजी के असह्योग-कार्य-कम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकाश प्रतिनिधियों के ह्एयों में कौसिलो और अदालतो के वहिष्कार की योजना के प्रति बिलकुल सहानुभूति नही थी। पर तो भी ७ मत के सकीण निश्चयात्मक बहुमत से कार्य-सिमिति ने गांधीजो का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होने शनैं:-शनै बहिष्कार करने की सलाह दी थी। काग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बडे उत्साह के वीच हुआ। श्री व्योमकेश चक्रवर्ती स्वागत-समिति के प्रधान थे और लाला लाजपतराय, जो हाल ही में अमराका से लौटे थे, सभापति थे। पहले प्रस्ताव में लोकमान्य बाल गगाधर तिलक की मृत्यु (३१ जुलाई १६२०) पर दु ख प्रकट किया गया। अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखने वाला था, जिसे गाधीजी ने पेश किया। प्रस्ताव का सार इस प्रकार है —

"चूिक खिलाफत के प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन दोनो देशो की सरकार भारत के मुसलमानो के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने जान-बूझ कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा है और चूिक प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई धार्मिक-विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करें,

"और चूकि अप्रैल १६१६ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पजाब को बेकसूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सजा देने में, जो पजाब की जनता के प्रति असम्य तथा सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है, इसलिए जबतक उक्त भूलों का सुधार न हो जाय और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं हैं कि वे गाधोजी-द्वारा सचालित क्रमिक अहिंसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और अपनाये।

"और चूकि आन्दोलन को चलाने में यह वाञ्छनीय है कि कम-से-कम खतरा रहे और वाञ्छित उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक कम-से-कम त्याग का आह्वान किया जाय, यह काग्रेस सब के साथ सलाह देती है कि.—

(क) सरकारी उपाधियो तथा अवैतिनिक पदो को छोड दिया जाय और

म्युनिसिपल वोर्ड तथा अन्य संस्थाओं मे जो लोग नामजद हुए हों, वे इस्तीफा दे दे;

(ख) सरकारी दरवारो आदि द्वारा किये जाने वाले सरकारी और अर्द्ध-सरकारी उत्सवी में भाग लेने से इनकार किया जाय;

(ग) राजकीय तथा अर्द्ध राजकीय स्कूलो तथा कालेजो से छात्रो को धीरे-

धीरे निकाल लिया जाय,

- (घ) वकोलो तथा मुविकलो द्वारा ब्रिटिश अदालतों का घीरे-घीरे बहि-प्कार किया जाय और खानगी झगड़ो को तय करने के लिए पचायती अदालतों की स्थापना की जाय;
- (ड) फौजी, क्लर्की तथा मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भरती होने से इनकार करे,
- (च) नई कौसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उम्मीदवारी से वापस ले ले, और

(छ) विदेशो माल का बहिष्कार किया जाय।

"आर चूिक असहयोग को अनुशासन तथा आत्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया गया है जिसके बिना कोई भी सच्ची जन्नति नहीं कर सकता, और चूिक असहयोग के सबसे पहले युग में हो हर स्त्रो-पुरुष व बालक को इस प्रकार के अनुशासन एव आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए, यह काग्रेस सलाह देता हैं कि एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया जाय; और हरेक घर में हाय की कताई तथा हाथ की बुनाई को पुनरुज्जीवित करके बड़े पैमाने पर वस्त्रों की उत्पत्ति तुरन्त ही बढाई जाय।"

इस प्रस्ताव पर गरमागरम वहस हुई। वावू विपिनचन्द्र पाल ने एक संशोधन पेश किया, जिसका देशवन्धु चित्तरञ्जनदास ने समर्थन किया। इस सशोधन के अनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मत्री को भारत के एक शिष्ट-मडल से मिलने के लिए कहा गया। वहुत देर के विवाद के वाद अन्त मे गांधीजी का प्रस्ताव पास हो गया।

२ अक्टूबर १६२० को महासमिति ने अपनी बैठक में 'अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोष' तथा 'स्वराज्य-कोष' नाम के दो कोष इकट्ठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिसम्बर १६२० तक रही की टोकरी में ही पड़ा रहा।

नागपुर काँग्रेस : १६२०

नागपुर-काग्रेस में असहयोग के कार्य-क्रम पर अन्तिम रूप से विचार होकर निरचय होना था। काग्रेस के सभापित दक्षिण के अनुभवी नेता चत्रवर्ती विजय राषवाचार्य थे। कर्नल वेजवुड, मि० हालफोर्ड नाइट तथा मि० वेन स्पूर ने गांग्रेस में इंग्लैण्ड के मजदूर-दल के मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया था। श्री चित्तरंजनदास पूर्वी बगाल तथा आसाम से लगभग २५० प्रतिनिधियों का एक दल लाये थे। उन्होंने उनका दोनों ओर का व्यय दिया था और अपनी जेव से लगभग ३६०००) इसलिए खर्च किया था कि कलकत्ते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके। श्री दास के आदिमयों और उनके विरोधों श्री जितेन्द्रलाल वन्जीं के आदिमयों के बोच एक मामूली-सी तकरार भी हो गई थी। महाराष्ट्र का विरोध भी कुछ कम तगड़ा न था। कर्नल वेजवुड, मि० वेन स्पूर तथा मि० हालफोर्ड नाइट ने विषय-समिति को बैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेजवुड ने तो असहयोंग के विरोध में दलीले पेश करने में अपनी सारी शिक्त लगा दी थी, परन्तु नतोजा कुछ भी न हुआ। खादो-सम्बन्धी धारा और भी कड़ी कर दी गई। अस हयोंग का प्रस्ताव फिर दोहराया गया। अधिवेशन में गांथोंजी के व्यक्तित्व की विजय हुई।

नागुर-काग्रेस में असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव का पास हो जाना स्वय एक वडी भारी बात थी, लेकिन उसके बारे में सबसे बडी बात यह थी कि उसे श्री चित्तरजनदास ने पेश किया ओर उसका लाला लाजपतराय ने समर्थन किया। नागुर में गांधीजी को निस्सदेह कलकत्ते से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। कलकत्ते में केवल एक हो परले सिरे के राजनीतिज्ञ प० मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का साथ दिया था, और सो भी अधिवेशन को समाप्ति के करीब जबिक गांधाजी ने नेहरूजी का यह सशोधन स्वीकार कर लिया कि अदालतो तथा कालेजो का बहिष्कार धीरे-धारे हो।

नागपुर के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव ने करीब-करीव कलकत्तावाले प्रस्ताव को ही दोहराया। एक ओर उपाधियाँ छोड देने की बात तो दूसरी ओर करो के न देने तक की बात उसमें शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धोरे-धोरे विदेशी व्यापारिक सम्बन्धों को छोडे और हाथ की कराई बुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करें। राष्ट्रीय सेवक दल को सगठित करने और 'अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोष' को बढाने के लिए काग्रेस पर जोर दिया गया। कौसिलों के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी भी प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने को प्रार्थना की गई। पुलिस तथा पलटन और जनता में मित्रता के जो भाव बढ रहे थे उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता से बर्ताव करते समय अधिक नरमी तथा ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करें और सब सार्वजिनक सभाओं में बिना डर के खुले तौर पर भाग ले। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्न अग है। वचन और कर्म दोनों में अहिंसा का होना आवश्यक माना गया और उस पर जोर

दिया गया, विनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप स्वर्ण-विनिमय मान-काप तथा कागजी-मुद्रा कोप में 'लूट' मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस वात की मान पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे की पूरा करें। पाचवे प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि ब्रिटिश माल की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनिमय को वर्तमान दरों पर अपना वादा पूरा करने से इन्कार करने के हकदार हैं। उच्चूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव तथा समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुराय किया गया। मजदूरों की प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जिरये जारी किये गये उनके सम्माम के प्रति सहानुभूति प्रदिशत की गई। पंजाब, दिल्लो तथा अन्य स्थानों में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को घ्यान में रखा गया और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धैर्य से सहै। काग्रेस ने सब देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शोध-से-शोध प्रयत्न करें।

काग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। काग्रेस का ध्येय "शान्तिमय तथा उचित उपायों में स्वराज्य प्राप्त करना" घोषित किया गया। काग्रेस का प्रातोय संगठन प्रान्तों को भाषा के अनुसार किया गया। विषय-समिति की बैठकों का काग्रेस के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना तथा उसकी सदस्यता केवल महा-समिति के सदस्यों तक सीमित रखना—ये मार्के के परिवर्तन थे; लेकिन विषय-समिति के सदस्यों की संख्या बढाकर ३५० तक कर दी गई। सभापित, मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विवान का एक ऐसा अंग था जिसने काग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक कार्ति ही कर दी।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले उन तीन प्रमुख सत्याग्रहियों का उल्पेख कर देना आवश्यक हे जिन्होंने तत्कालीन राजनीति को विशेषरूप में प्रभावित किया था।

१. चम्पारन-सत्याग्रह

डिमीसबी घताब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहरों ने चम्पारन में नील की खेती करना प्रारम्भ किया था। आगे चलकर इन नोगों ने वहा के जमीदारों से, प्रस्थायों और स्थायी जैसे भी सांदा पटा, भूमि के बड़े-बड़े भागों को अपने हाथ में करिनया तथा भी हा वहा के गानों के किसानों से अपने निए नील की खेती कराना प्रारम कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो नया कि किनान अपनी भू, या भू, भूमि पर नील अवध्य बोवे। कुठ ही दिनों में इन लोगों ने बगाल टेनेन्सी एवं में इन बात को बानून का रूप दिनवा दिया। नील पैदा करने की यह प्रया आगे जदकर 'तीन किठ्या' के नाम से मशहूर हुई, जिस में मानी थे एक दीवे का

३।२० भाग । किसानो की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे उनको अन्य खेती को नुकसान पहुचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी भिलती थी वह नाममात्र थो। कई बार उनको शिकायतो ने जोर मारा, परन्तु कडाई के साथ उन्हें वहीं-का-वही दबा दिया गया।

१६१७ में गावीजी मोतोहारो पहुचे। यह जिले का मुख्य स्थान था। गावो को देखने के लिए वह रवाना होने वाले हो थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त हो जिले से बाहर चले जाओ। गावीजी भला इस हुक्म को कब मानने-वाले थे। उन्होने अपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण-पदक, जो कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के लिए पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्ट्रेट को अदालत में उन पर दफा १४४ भग करने का मुकदमा चला। उन्होने अपने को अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया। अन्त मे सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाच करने दी। इस जाच में उन्होने अपने मित्रो की सहायता से कोई २० हजार किसानो के बयान कलमबन्द किये। इन्ही बयानो के आधार पर गाधीजी ने किसानो की मागे पेश की। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा जिसमे जमोदार, सरकार और निलहे गोरो के प्रतिनिधि थे। गाधीजी को किसानो की ओर से प्रतिनिधिरला गया था। इस कमीशन ने जाच के बाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया । इस रिपोर्ट मे एक समझौता भी लिखा गया, जिसमे किसानो पर बढाये गये लगान को कम कर दिया गया और जो रुपया गोरो ने नकद वसूल किया था, उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ । इनकी सिफारिश को बाद मे कानून का रूप दे दिया गया, जिसके अनुसार नील पैदा करना या 'तीन कठिया' लेना मना कर दिया गया।

२. खेडा-सत्याग्रह

चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्त्वपूर्ण खेडा का (१६१८) भी सत्याग्रह था। गांधीजी के भारत के सार्वजिनक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के दिनों में भी वे सरकार के लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ एतराज कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एव प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्थानीय कौसिल में प्रस्ताव करते थे। बस यहां तक उनका विरोध समाप्त हो जाता था। १६१८ में गांधीजी ने एक नये युग का श्रीगणेश किया। गुजरात के खेडा जिले में इस वर्ष ऐसा बुरा समय आया कि जिले भर की सारी फसल खराब हो गई। अवस्था अकाल के समान हो गई।

किसान यह महसूस करने लगे कि अवस्था को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौको पर जो उपाय काम मे लाये जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। अतः गाधीजी के पास किसानो को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होने लोगो से स्वय-सेवक और कार्यकर्त्ता बनने की अपील की और कहा कि वे किसानो में जाकर उन्हें अपने अधिकारो आदि का ज्ञान कराये। गाधीजी की अपील का असर तुरन्त हो हुआ। सबसे पहले स्वय-सेवक बनने को आगे बढने वाले सरदार वल्लभ-भाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और बढती हुई वकालत पर लात मार दी, और सब कुछ छोडकर गाधीजी के साथ फकोरी ले ली। खेडा का सत्याग्रह हो इन दो महान् पुरुषो को मिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के सार्व-जिनक जीवन में प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होने अन्तिम निश्चय करके अपने आपको गाधीजी के अर्पण कर दिया। सत्याग्रह की खूब धूम रही। गिर-पतारियाँ हुई, मुकदमे चले और सजाये हुई। आखिरकार इस झगडे का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरोब किसानों के लगान को मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होने किसानो को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है।

३. श्रहमदाबाद्-सत्यात्रह

गाधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के सगठन की कहानी उपन्यास की भाति ऐसी रोमाचकारी हैं कि उससे किसी भी जाति की स्वतन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ सकती हैं। उस समय तक महात्माजी ने काग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। औद्योगिक झगडों को सुलझाने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिसका आधार सत्य और अहिंसा था। १९१६ से श्रीमती अनसूया बेन साराभाई मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थी। १९१८ में बुनकरों और मिल-मालिकों में जो झगड़ा उठ खडा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामशं लेने के लिये उन्हें गाधीजी के पास जाना पडा। उन्होंने मिल-मालिकों को जवरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा जनसे पचायत के सिद्धात को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। गाधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की और से पच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पच-फैसले की बात बीच में ही टूट गई, क्योंकि थोडी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हडताल कर दी। गाधीजी ने स्वय इसके लिए खेद प्रकाशित करके मजदूरों को वापस काम पर भेज दिया। यद्यपि समझौता-भग दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल मालिक कुछ सहमें ही

न थे। गाधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले खुद इस समस्या का गहराई के साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलो को होने वाले लाभ, जीवन की आवश्यक वस्तुओ की महगाई और दूसरी ओर मिलों में उत्पत्ति-खर्च-वृद्धि-ये उनकी जाच के मुख्य विषय थे। इस जाच के पश्चात् जिस परिणाम पर गायोजी पहुचे वह यह थाँ कि मजदूरो की मजदूरी में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। इस प्रकार जो माग तैयार को गई थी उसे मिल-मालिको के सामने रखा गया। उन्होने २० फी सदी से अधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी १९१८ से मिलो में ताले डाल दिये जायगे। इस पर गाघीजी ने सारे मजदूरी की एक सभा बुलाई ओर एक पेड के नीचे, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तवतक काम पर नही लौटेगे, जबतक कि उनकी पूरी माग स्वीकार नहीं हो जाती। प्रतिज्ञा में यह बात भी थी कि वे लोग जवतक मिलो में ताले पड़े रहेगे तबतक किसी हालत में शाति-भग न करेगे। लेकिन अजदूर लोग इस बात के आदी नही थे। इसलिए उनमे कम-जोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। यह देखकर गाबीजी ने शाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जवतक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं पा जाते तबतक वह न तो किसी सवारी में हो चलेगे ओर न भोजन ही करेगे। यह समा-चार विद्युन्-गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह आमरण-अनशन था। मजदूरो ने उन्हे बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अटल था। इस पर गाधीजी ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ नष्ट न करे, ओर उन्हें जो कोई भी काम भिल जाय उस पर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करे। गाधीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वे इन मजदूरो की आर्थिक सहायता के लिए धन की अपील करते, जिससे काफी धन अवश्य आ जाता, लेकिन इस तरह भिक्षान देना उन्हे पसन्द न था। सत्याग्रहाश्रम साबरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरी को काम भिल भी गया। वहा इमारते वन रही थी। वे आश्रम के सदस्यो के साथ वडे आनन्द से काम करने लगे। इनमें सबसे आगे श्रीमती अनसूया वेन थी, जो मिट्टी, इँट ओर चूना ढो रही थी। इसका बडा ही नैतिक प्रभाव पडा। इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ हो गए, और मिल-मालिको के भी दिल दहल गए। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपीले की। उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी प्रतिज्ञा-भग नहीं होती थी और इधर मिल-मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनो ने पच-फैसला मानना स्वीकार कर लिया। पचो ने मजदूरों की माग के अनुसार ही ३५ फी सदी वढोतरी कर देने का निर्णय किया। मजदूरो की समस्या के शान्ति-पूर्ण ढग से सुलझ जाने के कारण काग्रेसी नेताओं और मजदूरों में एक सुदृढ़ सम्बन्ब स्थापित

असहयोग का वेग: १९२१-२३

हो गया। इसीके फलस्वरूप मजदूरो का 'मजूर महाजन' नामक एक स्थायी सगठन हो गया।

: 20:

असहयोग का वेग: १६२१-२३

नागपुर-कांग्रेस का प्रभाव

नागपुर-कांग्रेस से भारत के इतिहास मे एक नये युग का सूत्रपात हुआ। निर्वल, कोधपूर्ण और आग्रहपूर्वक प्रार्थनाओं के स्थान पर दायित्व और स्वाव-लम्बन की नयी भावना जाग्रत हो उठी।

नागपुर-काग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौसिलों के बहि-कार में सराहनीय सफलता मिला। देश भर में कितन ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी और उन्होंने दिलों-जान से अपने को आन्दोलन में झोक दिया। राप्ट्रीय-शिक्षा के क्षेत्र में भी आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। जनवरी के मध्य तक देश-बन्धुदास को अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार दी। गाधीजी कलकत्ता गयें और उन्होंने ४ फरवरी को वहा एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह पटना भी गयें और वहा एक राष्ट्रीय कॉलेज खोलकर बिहार-विद्यापीठ को स्थापना की। इस तरह चार महीन के भोतर-हो-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ अलोगढ, गुजरात-विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक वड़ो तादाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १६२१ के प्राय हर महोने में विभिन्न स्थानों में हुई। महासमिति की पहली बैठक (नागपुर) ने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की सख्या का बटवारा किया। जनवरी १६२१ में नागपुर काग्रेस के स्वागताध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी रायबहादुरी की पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक स्वराज्य-कोष में एक लाख रुपया दिया। इस कोष से किसी वकील को १००) और किसी राष्ट्र-सेवक को ५०) मासिक से अधिक नहीं मिल सकते थे।

रचनात्मक कार्य श्रौर द्मन-नीति का श्रारंभ

यद्यपि लोग सुधार और सङ्गठन के निर्दोष कार्यो का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से दफा १४४ और १०८ का दौर आरभ कर दिया था। देशवन्धुदास मैमनिसह जाने से रोक दिये गये थे और बावू राजेन्द्रप्रसाद तथा मौ० मजहरुल हक को आरा जाने की मनाही कर दी गई थी। श्री याकूबहुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये थे। लाहार में सभावन्दी कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकावले में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले सप्ताह में गुरुद्वारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए। वह शान्ति-मय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलियाँ चलाई गई, जिसमें लोगो के कथनानुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मौते हुई। ननकाना जैसा भीषण-काण्ड पहले कही नहीं हुआ था।

२८, २६ और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई में महासमिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बेजवाडा-कार्यक्रम को देश में जो सफलता मिली थी उससे चारो और प्रसन्नता छाई हुई थो। तिलक-स्वराज्य-कोष में निश्चित धन से १५ लाख रुपये अधिक आ गये थे। काग्रेस-सदस्यों की सख्या आधे के ऊपर पहुच गई थी, चर्ले करीब-करीब २० लाख चलने लगे थे। इसके बाद बुनने तथा खादी सम्बन्धी विविध कियाओं की ओर देश का घ्यान गया। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि तमाम काग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशों कपड़ों का उपयोग छोड दे। बम्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोब किया कि वे अपने कपड़ों की कोमत मजदूरों की मजदूरों के अनुपात से रख और वह ऐसी हो जिससे गरोब भी उस कपड़ को खरीद सके और मौजूदा दरों से तो दाम हिगज न बढाये जाय। विदेशों कपड़े मगानेवालों से कहा गया कि वे विदेशों कपड़ों के आईर न भेजे और अपने पास के माल को हिन्दुस्तान के बाहर खपाने का उद्योग करे।

यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक काग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था और इस समय भी उसे सार्वजिनक-सस्थाओं तक ही सीमित रखा गया था। व्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशाली चीजों का व्यापार बन्द कर दे। पूर्ण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रित काग्रेस सतर्क थी, फिर भी दमन-चक्र वड भयावह और विस्तृत-रूप में जारी था। उत्तर प्रदेश में उसका वहुत जोरशोर था। कई जगह तो गोली-काण्ड भी हुए थे। बहुत से लोग, विना मुकदमा लड़े, जेलों में पड़े हुए थे। परिस्थित यह थी कि देश के विभन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के उत्तर में सिवनय अवज्ञा शुरू करने की माग की थी। इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि सिवनय अवज्ञा को उस समय तक स्थिगत कर देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम पूरा न हो जाय। युवराज के आगमन के सवध में महासिमित ने निश्चय किया, कि उनके आगमन के सिलिसिले में सरकारी तौर पर

अथवा अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, उनमे कोई शरीक न हो और न किसी प्रकार को कोई सहायता दे।

१६ अगस्त को जब पटना मे कार्य-समिति की बैठक हुई तब उसमे हरदोई जिले (उत्तर प्रदेश) का वह पत्र पेश हुआ, जिसमे वहा लगाई गई दफा १४४ के विरुद्ध सविनय अवजा शुरू करने को इजाजत मागी गई थी, लेकिन उसका विचार अगलो बैठक के लिए स्थेगित कर दिया गया। कार्य-सिमिति की अगली बैठक भी जल्दी ही ६,७,८,६ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी। धारवाड-गोली-काण्ड और मोपला-उत्पात को जाच की रिपोर्ट उसमे पेश हुई और प्रस्ताव पास हुए। इसके पश्चात हो मौलाना मुहम्मदअली को, जो कि आसाम से मद्रास जा रहे थे, १४ सितम्बर को वाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुछ दिनो तक एक छोटी-सी जेल में रखा गया, फिर उन्हें रिहाई की आज्ञा सुनाई गई और दुबारा गिरफ्तार करके कराची ले जाया गया। मुहम्मदेअली की गिरफ्तारी के बाद ही फौरन बम्बई में शौकतअली पकड़े गये। जब यह पता चला कि ८ जुलाई को कराची में होनेवाली अखिल भारतीय परिषद के अवसर पर दिए गए भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तब गाधोजी ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापल्ली में थे, भाषण को स्वयं दोहराया । उन्होने इस गिरफ्तारी को इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को दोहराने को आज्ञा दो। दिल्लो की ५ नवम्बर १६२१ की महासमिति की बैठक ने प्रातोय काग्रेस-कमिटियो को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया। सत्याग्रह में कर-बन्दी भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का भार प्रातीय काग्रेस-कमिटियो पर छोड़ दिया गया। शर्त यह थी कि प्रत्येक सत्याग्रही ने असहयोग के कार्य-क्रम के उस अश को जो उस पर लागू होता हो, पूर्ति कर लो हो, वह चर्खा चलाना जानता हो, विदेशों कपड़ा त्याग चुका हो, खद्दर पहनता हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफत और पजाब के अन्यायों को दूर करने और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्पृश्यता को राष्ट्री-यता के लिए कलक समझता हो।

मोपला-उत्पात

यहा उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिनसे मलाबार में मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ था। मोपले वे मुसलमान है जिनके पूर्वज अरब थे। वे मलाबार के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे और वही शादी-ब्याह करके रहने लगे थे। साधारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या खेती-बारी करते हैं। पर धार्मिक उन्माद को धुन में वे इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि प्राणों की या शारीरिक सुख तक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते। मोपलों के आये दिन के दगों ने 'मोपला दगा-विधान' नामक एक विशेष कानून को भी जन्म दिया था। सरकार आरम्भ से इस वात के लिए चिन्तित थी कि 'भडक जाने वाले' मोपलो मे असहयोग की चिनगारी न लगने पाये। पर आन्दोलन और सब जगहो की भाति केरल मे भी पहुचा। फरवरी मे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मा० याकूबहसन जैसे प्रमुख नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याकूबहेंसन ने खासतौर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निषेवात्मक आज्ञा जारी की गई और १६ फरवरी १६२१ को चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये। मोपले मुख्यत बाल्वनद और एरण्ड ताल्लुको मे रहते है। सर-कार ने इन ताल्लुको में दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आतं रग-इग ही बदल् गया और मोपलो ने मार-काट आरम्भ कर दी। शोघ्र ही उनकी हिसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया। उन्होने वन्द्रको और तलवारो से लुक-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये । अक्तूबर के मध्य मे पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फीजो-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अफसरो को लूटने और व्रवाद करने के अलावा हिन्दुओ को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और हत्या करने के भागी वने। महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उनके अत्याचारो का विरोध किया।

युवराज का वहिष्कार

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये । नई वडी कौसिल की वही खोलने वाले थे, पर १६२० के अगस्त के वातावरण को देखकर भारत-सरकार ने डचूक ऑफ कनाट को बुलाया । १६२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश सरकार की आन वनाये रखने के लिए भेजा गया । काग्रेस ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि युवराज को अगवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उत्सव का बहिष्कार किया जाय । यही किया गया । जगह-जगह विदेशी कपड़ो की होली जलाई गई। युवराज के बम्बई-पदार्पण के दिन शहर में केवल मुठभेड ही नहीं हुई, बिल्क चार दिनो तक दगे और खून-खच्चर होते रहें, जिनके फलस्वरूप ५३ आदमी मरे और लगभग ४०० आदमी घायल हुए। ये दगे सरोजिनी देवी और गांधीजी के रोके भी न रुके। गांधीजी ने जब तक शांति स्थापित न हो जाय, जनता को ज्यादितयों का प्रायश्चित्त करने के निमित्त ५ दिन का बत किया। युवराज के आगमन के फलस्वरूप देशभर में स्वयसेवका के दल सगठित हुए। युवराज २५ दिसम्बर को कलकत्ता जाने वाले थ। बगाल-सरकार ने पहले से ही किमिनल लॉ-अमेण्ड-मेण्ट-एक्ट के अनुसार स्वयसेवक भरती करना गैर-कानूनीकरार देदिया था। बहुत से आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें देशवन्धुदास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे।

इसके वाद ही उत्तर प्रदेश ओर पजाब की वारी आई। अहमदावाद-काग्रेस होते-होते लालाजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशवन्धु दास जेलमे वन्द कर दिए गये।

समसोते का प्रयत्न

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की वातचीत चल पड़ी। भारत की राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ले जाते समय यह प्रवन्ध किया गया था कि वाइसराय हर साल बड़े दिनो में तोन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेगे। युवराज के बड़े दिन भी कलकत्ते में ही विताने का निरुचय किया गया। पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्य सज्जनों ने कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग की उप-स्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझाता कराने की चेप्टा की। लॉर्ड रीडिंग भी राजी हो गये। २१ दिसम्वर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व मे एक जिण्ट-मण्डल वाइसराय से मिला। देगवन्युदास कलकत्ते की अलापुर-जेल में थे। उनसे मध्यस्थो को टेलीफोन-द्वारा वात हुई। गोघ्र ही गाधीजी से तार-द्वारा बातचीत करना आवश्यक समझा गया। वह अहमदाबाद में थे। सरकार इस बात पर राजी हो गई कि सत्याग्रह के कैदियो को छोड दिया जाय आर मार्च १६२२ में गोलमेज-परिपद् बुलाई जाय, जिसमें काग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हो। इस परिपद् में सुधार-योजना पर विचार किया जाय। देगवन्युदास की माग यह थी कि नये कानून के अनुसार सजा पाये हुए मारे कैदियों को छोड दिया जाय। समझाते के निरचय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैरा आर फतवे के कैटी जिनमें मालाना मुहम्मदअली, मीलाना शांकतअली, डॉ॰ किचनू और अन्य नेता गामिल थे, जेल में ही रह जाते। परन्तु गायोजी कराची के फेर्दियों का छुटकारा चाहते ये। सरकार ने आशिक रूप में इसे भी स्वीकार मुर् तिया। उन्होने माग पेश की कि फतत्रे के कैदियों को भी छोडा जाय और मिनेटिंग जारी रायने का अधिकार माना जाय। ये माने नामजर कर दी नई।

श्रहमदावाद-कांग्रेस: १६२१

१६२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद-काग्रेस हुई। अहमदावाद का अधिवेशन कई सुघारों के लिए प्रसिद्ध है। इस बार प्रतिनिधियों के बैठने के लिए कुरिसयों और बेचों का प्रबन्ध नहीं था। स्वागताध्यक्ष बल्लभभाई पटेल का भाषण छोटे-से-छोटा था। कम-से-कम कुल ६ प्रस्ताव पास हुए। काग्रेस की मुख्य भाषा हिन्दी थी। काग्रेस-कार्य के लिए जो तम्बू और डेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी।

गायोजो ने एण्डरूज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने और एक धार्मिक संदेश देने का निमत्रण दिया था। उन्होंने आना निश्चित किया,लेकिन यह भी स्पष्ट कह दिया कि मैं विदेशी कपड़े की होलों के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे डर है कि वह हिंसा के भाव जाग्रत करेगो। अपनी मामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिबास में आये, जिससे कि वह विदेशों कपड़े की होलो-नोति पर अपना विरोध स्मष्ट कर सके। अपने व्याख्यान में उन्होंने इसे स्पष्ट भी किया। लोगों ने उनको बातों को बहुत आदर आर प्रेम से सुना, यद्यपि वे उनके विचार से सहमत नहीं थे।

अधिवेशन के सभापति हकीम अजमल खाँ थे। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रित्मूित्त थे। उनके सभापित्व में असहयोग और उसके प्रति देश के कर्तव्य के सम्बन्ध में मुख्य प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि चूकि काग्रेस के पिछले अधिवेशन के समय से अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप भारतीय जनता ने निर्भयता, आत्म-बिलदान और आत्म-सम्मान के मार्ग पर पर्याप्त प्रगति करने के साथ-साथ सरकार के सम्मान को बहुत बडा धक्का पहुचाया है और चूँकि देश की प्रगति स्वराज्य की ओर तीव्र गित से हो रही है, इसिलए यह काग्रेस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन-द्वारा स्वोक्तत और नागपुर में दोहराये गए प्रस्ताव को स्वोकार करती है और दृढ निश्चय प्रकट करती है कि जबतक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जायगी तबतक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की अपेक्षा अधिक उत्साह से उस प्रकार चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक प्रात निश्चय करेगा। इस प्रस्ताव के अगले अशो में लोगो को स्वयसेवक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। स्वय-सेवक के लिए कुछ प्रतिज्ञाएँ भी निश्चित की गई। प्रतिज्ञाएँ इस प्रकार थी —

ईश्वर को साक्षी करके मै प्रतिज्ञा करता हूँ कि —

(१) मै राष्ट्रोय स्वयसेवक-सघ का सदस्य होना चाहता हू।

(२) जबतक मैं सघ का सदस्य रहूगा तबतक वचन और कमें में ऑहंसात्मक रहूगा ।

(३) मुझे साम्प्रदायिक एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए मैं सदैव प्रयत्न करता रहगा।

- (४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशों का प्रयोग आवश्यक है और मैं दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के कते और वुने खद्दर का ही इस्तेमाल करूगा।
- (५) हिन्दू होने को हैसियत से मैं अस्पृश्यता को दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हू।

(६) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने,

आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हू।

(७) अगर मैं जेल जाऊगा तो अपने कुटुम्बियो या जो लोग मुझ पर निर्भर है, उनकी सहायता के लिए काग्रेस से कुछ नहीं मागूगा।

सर्वदल-सम्मेलन : १६२२

अहमदाबाद काग्रेस के समाप्त होते हो काग्रेस के मित्रों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, काग्रेस ओर सरकार में समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट को। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावो को स्याही सुखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ फरवरी को बम्बई में एक सर्व-दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमे भिन्न-भिन्न दलो के लगभग ३०० सज्जनो ने भाग लिया। सम्मेलन के आयोजको ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आधार पर अस्यायो-सिध की बात चलाई जा सके। गाधीजी ने असहयोगियो की स्थिति साफ करते हुए कहा कि मै वैवानिक रूप से सम्मेलन मे भाग न ले सकूगा, पर मै सम्मेलन की सहायता अवश्य करुगा। इसका कारण उन्होने बताया कि सरकार की तरफ से दमन बरावर जारी है और जबतक सरकार के मन मे उसके प्रति पश्चात्ताप नही है तवतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से कोई लाभ नहो । सम्मेलन के बीस सज्जनो की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया था वह सम्मेलन के इजलास मे रखा गया। गाधाजी ने फिर असहयानियो की स्थिति स्पष्ट की। सर गकरन् नायर इस सम्मेलन के सभापित थे। उन्होने इस प्रस्ताव को ना-पसद किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये। उनका स्थान सर एम० विश्वेश्वरय्या ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जिसमे सरकार की दमन-नाति को धिक्कारा गया था और साथ हो यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक समझौते को वात-चीत चनती रहे, अहमदावाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिषद् नीघ्र हो बुलाने को पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पजाव और स्वराज्य-सम्बन्धी नामलो पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अतर्गत सस्थाओं को गैर-कानूनी करार देनेवाले सारे आदेशो तथा राजद्रोहात्मक सभावन्दी-कानून आदि को रद करने के लिए सरकार से अनुरोध करे। कमेटो के जिम्मे उन मुकदमो की जाच का भी काम सुपुर्द किया गया जिनके मातहत आन्दोलन मे भाग लेनेवालो को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। काग्रेस की कार्य-समिति ने अपनी ७ जनवरी को बैठक मे इन प्रस्तावो को पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए मुल्तवी कर दिया, परन्तु वाइसराय ने सम्मेलन की शर्तों को मजूर करने से इकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था वह कितना खोखला था।

श्रन्तिम चेतावनी

३१ जनवरी १६२२ को कार्य-सिमिति की बैठक मे बारडोली ताल्लुका-परिषद का प्रस्ताव पेश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ताल्लुका के लोगो को सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा आत्म-बलिदान करने के निश्चय पर बधाई दी गई। कार्य-समिति ने भारतवर्ष के अन्य सारे भागो को सलाह दी कि वे वारडोलो के साथ सहयोग करें और उस समय तक किसी प्रकार का सामृहिक सत्याग्रह न करे जबतक उन्हें महात्मा गाधी की अनुमति पहले से प्राप्त न हो जाय। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप १ फरवरी को गाधीजों ने वाइसराय के नाम एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि 'पेश्तर इसके कि बारडोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आरम्भ करें, आपके सरकार के प्रधान अफसर होने की हैसियत से, मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हू कि आप अपनी नीति में परिवर्तन करें और उन सारे असहयोगी कैंदियो को मुक्त कर दे जो अहिसात्मक-कार्यों के लिए जेल गये है या जिनका मामला अभी विचाराधीन है। मै आपसे यह भी अनुरोध करता हू कि आप साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अहिसात्मक हलचल में— चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हों, चाहे पजाब या स्वराज्य के सम्बन्ध मे, अथवा चाहे और किसो विषय में हो, यहा तक कि वह ताजीरात हिंद या जाव्ता फीजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमन-कारी कानूनो के भीतर क्यों न आतो हो—सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दे। हा, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे। मै आपसे यह भी अनुरोध करूगा कि आप प्रेस पर से कडाई उठा ले और होल में जो जुर्माने किये गये हैं उन्हें वापस करा दे। मैं आपसे जो यह करने का अनुरोध कर रहा हू, सो ससार के उन सभी देशों में किया जा रहा है, जहां को सरकार सभ्य है। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं उस समय तक के लिए उम्र सत्याम्रह मुल्तवी क्रने की सलाह दूगा जब तक सारे कैदी छूटकर नये सिरेसे अवस्था पर विचार न कर ले। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर देतो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूगा और फिर

नि संकोच भाव से सलाह दूगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दवाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मागो की पूर्ति के लिए अर भो ठोस लोकमत तैयार करें। ऐसी अवस्था में उग्र सत्याग्रह तभो किया जायगा जब सरकार विलकुल तटस्थ रहने की नोति का परित्याग करेगो, अथवा जब वह भारत के अधिकाश जन-समुदाय की स्पष्ट मागों को मानने से इकार कर देगो। भारत-सरकार ने तुरन्त हो गाधोजी के इस वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति वम्बई के दगो, अनेक स्थानो पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयसेवक-वलो द्वारा हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है।

हिसात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव

पर काग्रेस के सिर पर एक अशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को उत्तर प्रदेश में गोरखपूर के निकट चौरो-चौरा में एक काग्रेस-जलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ सिपाहियो और एक थानेदार की भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगादो। वे सब आग में जल मरे। उधर ऐसे हो हत्याकाड १३ जनवरी को मद्रास में तथा १७ नवम्वर को वम्वई में हो चुके थे। यह देखकर १२ फरवरी को वारडोलो में कार्य-समिति को एक वैठक हुई, जिसमे इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। काग्रेसियो से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और स्वयंसेवको का सगठन और सभाये केवल सरकार की आज्ञा को तोडने के लिए न की जाय। एक रचनात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमे काग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चर्ले का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयो को खोलना और मादक द्रव्य-निषेध का प्रचार और पचायत सगठित करना आदि शामिल था। २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की वैठक हुई। उसमे कार्यसमिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावो का समर्थन हुआ। हां, व्यक्तिगत रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवस्य दे दो गई। महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह को यह परिभापा को कि व्यक्तिगत सत्याग्रह दह है जिसके अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसो सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लंघन किया जाय। इस प्रस्ताव से मध्यस्थ लोगों में हलचल मच गई। पण्डित मोतोलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जेल के भोतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गांघीजी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दण्ड देने के लिए आडे हायो लिया। वंगाल और महाराष्ट्र तो गांघीजी पर टूट पडे । वावू हरदयाल नाग जैसे गांघी-भक्त ने बगावत ना सण्डा मड़ा किया। दारडोली के प्रस्तावों की एक-एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैठक में डॉ॰ मुजे ने गांधीजी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिय जो गांधीजी के विरुद्ध बोले थे। गांधीजों ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमित न दी। तूफान आया और निकल गया और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाति अचल रहे।

गांधीजी की गिरफ्तारी

पासा पड़ चुका था। अब गाधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढी हुई हो। वह सब के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछ हटने लगती है तब दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ टूटता है। १३ मार्च को गाधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गाधीजी को राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपुर्द कर दिया गया। यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदा-बाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवों ने एक छोटो-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, "जिस समय गाधीजी के छुश, शान्त और अजय-देह ने अपने भनत, शिष्य और सहबन्दी-शकरलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया उस समय कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खडे हुए।" कानूनी अहलकारों ने तीन लेख छाटे जिनके लिए गाधीजी पर मुकदमा चलाया गया था (१) 'राजभिक्त में दखल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-तर्जन'। ज्यो ही अभियोग पढकर सुनाये गये, गाधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया। इसके बाद गाधीजी ने अपना लिखित बयान पढा, जो निम्न प्रकार है :—

गांधीजी का वक्तव्य

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इग्लैण्ड और भारत की जनता को यह बता दू कि मैं कट्टर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया। मैं अदालत को भी बताऊगा कि मैं इस सरकार के प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिये अपने आपको दोषी क्यो मानता हू।

"मेरे सार्वजिनक जीवन का आरम्भ १८६३ मे दक्षिण-अफ्रोका की विषम परिस्थित में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरा कोई अविकार नहीं है। मैने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी हूँ।

"पर मैंने हिम्मत न हारो। मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वह दोष एक अच्छो-खासी शासन-व्यवस्था में यो ही आकर घुस गया है। मैंने खुद हो दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तब मैंने उसकी खूब आलोचना को, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

"जव १८०० में वोअरों की चुनाती ने सारे ब्रिटिश-साम्राज्य को महान विपद में डाल दिया, उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवाये भेट की—घायलों के लिए एक स्वयसेवक-दल बनाया और लेड़ी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाइयां लड़ी गईं, उनमें काम किया। इसी प्रकार जव १६०६ में जूलू लोगों ने विद्रोह किया तव मैंने स्ट्रेचर पर घायलों को ले जानेवाला दल संगठित किया और जवतक 'विद्रोह' दव न गया, बरावर काम करता रहा। इन दोनों अवसरों पर मुझे पदक मिले और खरीतों तक में मेरा जिक किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो काम किया उसके लिए लार्ड हार्डिंग ने मुझे कैंसर-ए-हिन्द पदक दिया। जव १६१४ में इंग्लैंड और जर्मनों में युद्ध छिड़ गया तव मैंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयं-सेवक दल बनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम की साहना की। जब १६१७ में लार्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिषद् में खास तौर से अपील की तव मैंने खेड़ा में रंगरूट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को जाखिन में डाल दिया। मुझे इसमें सफलता मिल ही रहा था कि युद्ध वन्द हो गया और आज्ञा हुई कि अब और रंगरूट नहीं चाहिए। इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए बरावरों का दर्जा हासिल कर सक्गा।

"पहला घक्का मुझे रालट-ऐक्ट ने दिया। यह कानून जानता की वास्तविक स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके बाद पंजाब के भीपण काण्ड का नम्बर आया। इसका आरम्भ जलियावाला बाग के कत्ले-आम से बोर अन्त में पेट के बत रेगाने, खुले आम वेत लगाने और दूसरे वयान से वाहर अपमानजनक फारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधान-मन्त्रों ने भारत के मुसलमानों को जो आक्वासन दिया कि तुर्की बार इस्लाम के तीर्य-स्थानों का पिवत्रता बदस्तूर रखी जायगी, वह कोरा आक्वासन ही रहेगा।

"वैने १६१६ को अमृतसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे साववान किया और मेरी नीति की सार्यकता में सदेह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा वि भारतीय मुनलमानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो दादा किया है उसका पालन किया जायगा, पजाब के जख्मों को भरा जायगा और नाकाफी और असन्तोष जनक होने पर भी सुधार भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देगे। फलत मैं सहयोग और माटेगु-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की बात पर अडा रहा।

रहा । "पर मेरी सारी आशाये धूल में मिल गईं। खिलाफत-सम्बन्धी वचन पूरा किया जानेवाला नही था। पजाब-सम्बन्धी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर अधपेट भूखे रहनेवाले भारतवासी घोरे-घारे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो थोडा-सा सुख-ऐश्वर्य मिल जाता है वह विदेशों शोपक की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली जनता के खून से निकाली जाती है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन कायम है वह इसो जनता के धन-शोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झूठे-सच्चे तर्क से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसो चालाकी की जाय असख्य गावो में जो नर-ककाल दिखाई पड रहे है उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सकता। यदि हमारा कोई ईश्वर है, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने ढग का निराला अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेही इंग्लैंड की जनता और हिन्दुस्तान के नागरवासियों को करनी होगो। इस देश में कानून का उपयोग विदेशी धन-शोपको के सुभीते के लिए किया गया है। पजाब के फौजी कानून के सम्बन्ध में मैने जी निष्पक्ष जान की है, उससे मैं इस नतीजे पर पहुचता हू कि १०० पीछे ६५ मामलो में सजा के फैसले बिलकुल खराव रहे। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मुकदमो का तजर्बा मुझे बताता है कि दस पोछे नौ दण्डित आदमी सोलह आने निर्दोप थे। इन आद्मियो का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मामलो में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतो में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में न्याय नहीं मिलता। मैं अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूं। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह के मामलों से काम पड़ा है उसका यहीं अनुभव है।

"सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अग्रेजो और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के जिम्मे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जानते कि मैंने जिस अपराध का वर्णन किया है उसमें उनका हाथ है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत-से अग्रेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी हृदय से इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को अमल में ला रहे हैं वह ससार की बढ़िया-से-बढ़िया शासन-व्यवस्थाओं में से है और हिन्दुस्तान धोरे-धोरे परन्तु निश्चित रूप से उन्नति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्ष्म परन्तु कारामद ढग से आतक का सिक्का वैठाया गया है और किस तरह एक ओर शक्ति का

असेसरों के सामने सिर्फ दो ही मार्ग है। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है, वह बुरा है और में निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें और बुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर ले, अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की जनता के मगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।"

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गाधीजी को छ वर्ष की सजा दी और श्री शकरलाल बैंकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छ मास और। गाधीजी ने गिने-चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम-सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने जज को सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गाधीजी को बिदा किया। बहुतों की आखों में आसू भी भरे हुए थे।

गिरफ्तारी के वाद

गाधीजी की सजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही। खद्दर-विभाग सेठ जमनालाल वजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया। मालावार के कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ५४,०००) की मजूरी दी। सेठ जमनालाल बजाज ने वकीलों के भरण-पोपण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। खद्दर के अनिवार्य 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी वकीलो को एक बार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ मे न ले, और असह-योगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैरवी ने करे। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे मोपला-विद्रोह की जाच करने तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराने का काम दिया गया। अस्पृश्यता-निवारण-सबधी योजना वनाने के लिए एक क्मिटी नियुक्त की गयी। ७, ५ और ६ जून १६२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी ओर अन्य सिफारिशो पर विचार किया गया। वास्तव में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय-भग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विज्ञान और कला का सिहाबलोकन करना । देशबन्धुदास और विट्ठलभाई पटेल-जैसे चोटी के नेता, ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ मे हो सके। महासमिति ने इस बात पर विचार किया। वाद-विवाद के पश्चात् इस बात को अगस्त के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सभापति से अनुरोघ किया गया

कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी किमटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। तदनुसार सभापित ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डा० अन्सारों, श्रीयुत विट्ठलभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को नियुक्त किया। हकीम अजमलखा को किमटी का अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की। इसलिए उनके स्थान पर श्री एस० कस्तूरी रगा आयगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके।

बोरसद्-सत्याग्रह

इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। यह सत्याग्रह १६२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक छटा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। उघर एक मुसल-मान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के मुकाबले में छापे मारने लगा। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में हो है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस तथा रेवेन्यू अफसरों ने मिलकर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीब सोच निकाली। उन्होंने देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्त पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहे और ४-५ सशस्त्र सिपाहा दिये जाय। अधिकारी राजी हो गये। चोर को पकड़ने के लिए चोर नियुक्त किया गया। पर पुलिस के इस नये साथी ने अपने आदिमयों और हथियारों का उपयोग तहसील में और भी धूम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अपराधों की सख्या बढ़ी। अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गानवालों की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त-पुलिस वैठाई गई और एक भारी ताजीरी-कर भी लोगों पर लगा दिया। यह कर बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इसी बीच गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाक के समझौते का पता चल गया। श्री वल्लभभाई पटेल ने इस मामले में सरकार को चुनौती दी। वह बोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा। जिन लोगों को डाकुओं ने घायल किया या उनके शरीर से गोलिया निकाली गई इससे सावित हुआ कि गोलिया सरकारी है। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलिया बार सरकारी रायफलों का उपयोग किया है। श्री वल्लभभाई पटेल ने २०० स्वयसेवक रात दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैनात किये। लोग कई हफ्तों से शाम से ही घरों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। श्री पटेल ने उन्हें

दरवाजे खुले रखने को राजी किया। गाववालो ने फोटो की तसवीरो द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ताल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमो भीतर से स्वय दरवाज बन्द कर देते हैं और बाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भ्रम हो जाय कि घर खालों हैं। वाहर जहाँ जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनो चारपाइयों के नोचे घुस जाते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी वाते विलकुल सच्ची साबित हुई। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालो पर मुकदमा चलाती, या चुप्पी साधकर अपने-आपको कसूरवार सावित करती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तब बडौदा-पुलिस गावों से झटपट रियासत में हटा ली गई। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनो रहो और ताजीरी-कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय वम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी तब वहा तत्काल होम-मेम्बर को भेजा जिसने सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। देवर बावा वल्लभभाई और स्वयसेवको के पहुचते ही वहा से गायब हो गया।

सत्याप्रह-समिति की रिपोर्ट

इसके बाद सत्याग्रह-किमटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भग न हुआ था। किमटी के सदस्य जहां कही गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। किमटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी, पर ऐसा न हो सका। सत्याग्रह-किमटी की रिपोर्ट तैयार करने में जो-जो शक्तियाँ काम कर रही थी उनके सम्बन्ध में विशेष सिफारिशे सक्षेप में यहाँ दी जाती हैं—

१. सत्याग्रह—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूकि-सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भग अथवा किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रान्तीय काग्रेस-किमटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी शर्त पूरी होती हो तो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-सत्याग्रह की मजूरी दे सकते हैं।

२. कौंसिल-प्रवेश—कौसिल प्रवेश के सबध में डा॰ एम॰ ए॰ अनसारी, राजगोपालाचार्य तथा एस॰ कस्तूरी रगाअयगर की सिफारिश थी कि काग्रेस की नीति में तत्सवधी किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय। इसके विरुद्ध हकीम अजमल खा,प॰ मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का मत था कि:—

(१) असहयोगियो को उम्मीदवारी के लिए पजाव और खिलाफत् की

ैदादरसी और तत्काल स्वराज्य-प्राप्तिके उद्देश्य से खडा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक संख्या में पहुँचने की काशिश करनी चाहिए।

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुंच जाय कि उनके वर्गेर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कीसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहा में चले आना चाहिए और फिर किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कीसिल में केवल इसलिए जायें कि उनके रिक्त स्थान पूरे न हो सके।

(३) यदि वसहयोगी इतनी सख्या में पहुचे कि अधिक होने पर भी उनके विना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का जिसमें वजट भी शामिल है, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाव, खिलाफत और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिए।

(४) यदि असहयोगी अल्पसंख्या में पहुंचे तो उन्हें वही करना चाहिए जो न०२ में वताया गया है, और इस प्रकार कौसिल के बल को घटाना चाहिए।

(४) कांसिलो के बहिष्कार कंसम्बन्ध में काग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए।

३. स्यानीय संस्थाएँ—हमारी सिफारिश है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यश्रम को अमली जवल में देने के लिए म्युनिसिपैलिटियो, जिला और लोकल बोडों की उम्मीदवारी के लिए खडे ह, परन्तु असहयोगी सदस्यों के वहा आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी खास ढग के नियम-उपनियम न बनाये जायें।

४. स्कूल-कालेजो का बहिष्कार—स्कूल-कालेजो के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि मांजूदा पोरदार प्रचार दन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलो और कालेजों का बहिष्कार करने की गलाह न देनी चाहिए।

५. अदालतो का वहिष्कार—पचायते स्थापित करने की कोशिय करनी चाहिए और इस ओर लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए। हमारी यह भी सिफा-रिया है कि इस समय वकीलो पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन्हें उठा लेना चाहिए। च कवर्ती राजगोपालाचार्य का मत था कि विशेषज्ञो की सारी वातो के सग्रह करने और उनकी जाच-पडताल करने में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति द्वारा सिद्धात-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगो और आदोलन को हानि पहुंचेगो।

उनत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दल समान-रूप से बटे हुए थे। पर दोनो थे असहयोग के हो दल और सरकार से सहयोग करने की दोनो में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना हो था कि नवीन दल असहयोग की कमान में एक दूसरो डारी चढाकर उससे नौकरशाहो के गढ कोसिल के भीतर से ही तोर छोड़ने का समर्थक था। स्थानोय बोड़ों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशे को गई थो उनको करना तो पहले ही से को जा सकतो थी। काग्रेसियो और असहयोगियो ने म्युनिसिपैलिटियो ओर स्थानोय बोड़ों के लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। सफल होने पर वे अस्पतालो में खहूर और नोकरो के लिए खादी की बिदयो के व्यवहार पर जोर देते थे, आफिसो पर राष्ट्रोय-झण्डा फहराने का आग्रह करते थे, म्युनिसिपल स्कूलो में चर्चा और हिन्दी के प्रचार को सिफारिश करते थे और यदा-कदा गवर्नरो और मिनिस्टरो के आगमन का बहिष्कार करने पर बल देते थे। इस प्रकार उन्होने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर इन सारी कार्रवाइयो से केवल उनके रुख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर नहीं आता था।

महासिमिति की जो बैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के लिए रक गई। उस महोने की २०, २१, २२, २३ और २४ तारीख को किमटी की ऐतिहासक बैठके हुई। काग्रेस-किमटी की चर्चा क्या थी, एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था, जिसमें अपने-अपने पक्ष के योद्धाओं का ध्यानपूर्वक छाटा गया था। पहले दिन की बैठक इण्डियन एसोसियेशन के कमरों में हुई, पर वहा खुलो हवा न मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८, रसा रोड पर देशवन्धु चित्तरजन दास के भव्य-भवन में शामियाने के नोचे हुई। पाच दिन की उधेडबुन, नुकताचीनी, तानाजनों और वाक्-प्रहारों के बाद किमटों ने निर्णय किया कि देश सामूहिक सत्याग्रह को लिए तैयार नहीं है। पर किमटी ने प्रान्तीय काग्रेस-किमटियों को अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका आ पड़े तो वे अपनी जिम्मेदारी पर सामित रूप से सत्याग्रह की मजूरी दे सकती हैं, बशर्ते कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी शर्ते पूरी हो। कौसिल-प्रवेश का अधिक जिल्ला प्रश्न गया-काग्रेस के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी प्रकार अग्रेजी माल के बहिष्कार का प्रश्न, स्थानीय वोर्डो आदि में प्रवेश करने का प्रश्न, स्कूलो-कालेजों और अदालतों के वहिष्कार का प्रश्न, आत्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्न—ये सव भी मुलतवी कर दिये

गये। बोर्डो मे प्रवेश के प्रश्न को इसलिए स्थगित किया गया कि रचनात्मक कार्य मे वाधा न पड़े। इस कार्य में काग्रेस के १६,०००) खर्च हुए।

गया-कांग्रेसः १६२२

१६२२ की गया-काग्रेस हर प्रकार से अपने ढग की निराली थी। प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो-हल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कौसिल-प्रवेश का इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भग हो जायगो, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि कौसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रति-वन्ध न उठाया जाय। कुछ ऐसे बुद्धिशाला व्यक्ति थे, जो कहते थे कि हम कौसिलों में जाकर न शपथ लेगे, न स्थान ग्रहण करेगे आर इस ढग से शत्रु को पराजित कर देगे। इसके बाद उन जोशाले राजन तिज्ञों को बारी थी, जो कहते थे कि हम शोर को उसकी माद में जाकर पराजित करेगे, रुपये को मजूरी न देगे, धिक्कार का प्रस्ताव पास करेगे और सरकारी यत्र का चलना असम्भव कर देगे। इस प्रकार यद्यपि असहयोग को नाव को दूसरी और ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तिया जुट गई था, तो भी एस० श्रोनिवास आयगर अर पण्डित मोतीलाल नेहरू की प्रतिभा के रहते हुए वह नाव अपने रास्ते चलता रहा। एस० श्रोनिवास आयगर ने सशोधन पेश किया कि काग्रेसी उम्मोदवारी के लिए खडे हो, परन्तु कौसिलों में स्थान ग्रहण न करे। पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शताँ के साथ इस पर रजामन्द हो गये।

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-काग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उनको जेव मे वास्तव में दो महत्त्वपूर्ण कागज थे. एक था सभापति का भापण और दूसरा था सभापति-पद से त्याग-पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। किसी को आशा न थी कि दास-जैसे व्यक्तित्व का पुरुन, पण्डित मोतोलाल नेहरू और श्रो विट्ठलभाई पटेल-जैसे चोटी के आदिमयों का सहारा पाकर भी जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कीसिल बहि-प्कार के लिए राजी हो जायगा। फलत. एक पार्टी वनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। श्री दास के जिम्मे वनाल की प्रान्तीय कौसिल पर कव्जा करने का काम रहा और प० मोतीलाल नेहरू को दिल्ली और शिमला पर धावा वोलने का काम दिया गया।

वम्बई में समभौता

गया में अपिरवर्त्तनवादियों की जो विजय हुई थी वह स्थायी सावित नहीं हुई। १ जनवरी १९२३ को महासिमिति ने निञ्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयसेवक भरती किये

जाय। कार्य-सिमिति के जिम्मे यह सारा काम सौपा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात सभापित देशबन्धुदास का त्याग-पत्र था। उन्होने पहले ही विषय-सिमिति को अपनी स्वराज्य-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासिमिति की २७ फरवरी १६२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थिगत कर दिया गया। इस बठक में आपस में समझाता करके दोनो दलो ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी ओर से कौसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच अपने-अपने कार्यक्रम का शेष भाग दोनो दल पूरा करने को स्वतन्त्र रहे। कोई किसी के काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनो दल अपना रवैया रखे। इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पिष्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट चुके थे। महासिमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनो को धन्यवाद दिया।

रचनात्मक कार्यक्रम

इघर काग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट-मङल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगापालाचार्य, सेठ जमनालाल वजाज और श्री देवदास गांधी थे। इस शिष्ट-मङल ने देशभर का दौरा किया और तिलक स्वराज्य-कोष के लिए काफी चन्दा जमा किया। मई १६२३ को बम्बई में हुई कार्य-समिति की बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की। १६२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-समिति की बैठक के साथ महासमिति की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-काग्रेस के अवसर पर मतदाताओं में कौसिल-प्रवेश-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उस पर अमल न किया जाय। इस बैठक में मध्यप्रात के स्वयसेवकों को नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए बधाई दी गई और साथ हो देश के स्वयसेवकों को आवश्यकता पडने पर नागपुर-सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया।

बम्बई के उक्त समझौत से कई प्रातीय काग्रेस-किमिटिया स्वभावत ही क्षुब्ध हुई। बाद को नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौते वाले प्रस्ताव को जायज और उपयुक्त समझा गया और इस बात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गई। पर इसी किमिटी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार सितम्बर में बम्बई में काग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया, जिसमें कौसिल-बहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना अबुलकलाम आजाद को इसका सभापित चुना गया और कार्य-सिमिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार सौपा गया।

असहयोग का वेग: १९२१-२३

नागपुर का भंडा-सत्याप्रह

इसी बीच नागपुर-सत्याग्रह ने भीषण रूप धारण कर लिया। नागपुर की पुलिस ने १ मई १६२३ को १४४ धारा के अनुसार सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय झण्डे समेत जलूस ले जाने का निषेध कर दिया। स्वयसेवको ने कहा—'हमें अधिकार है, जहा चाहे झण्डा ले जायेगे।' बस, गिरफ्तारियाँ और सजाएँ आरम्भ हो गई। वात-की-वात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। महासमिति ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय किया और साथ हो देश को आह्वान किया कि आगामी १८ तारीख को गाधी-दिवस मनाए जाने के बदले उसे 'झण्डा-विवस' कहकर भनाया जाय। प्रान्तीय काग्रेस-किमटियो को आज्ञा हुई कि उस दिन जलूस निकालकर जनता-द्वारा झडा फहराएँ। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में उसके लिए कोई बोली लगानेवाला न निकला ओर अन्त मे उसे काठियावाड ले जाया गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आह्वान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे। इस प्रकार नागपुर-झडा-सत्याग्रह शाघ हो एक अखिल-भारतीय आन्दोलन हो गया। ऐसी स्थिति में श्री वल्लभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया गया। वल्लभभाई पटेल ने १८ तारीख के लिए जलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी वदस्तूर लगी हुई थी। पर इतने पर भी १८ तारीख को जलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर खुब हो-हल्ला मचा।

प्रवासी भारतीयों की खमस्या

जुलाई, अगस्त ओर सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण हल-चल हुई जिसकी ओर काग्रेस का घ्यान गया। केनिया में अवस्था दिनपर-दिन बुरी होती जा रही थी। वहा के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से असन्तोषजनक थी। इस उपनिवेश को उपजाऊ बनाने का श्रेय भारतीय मजदूरों और भारतीय पूजी को था। कई मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले कदम आगे वढाया था। परन्तु भारतवासियों को इस उपनिवेश के हाइलेड्स (ऊंची भूमि) की खेती योग्य जमीने देने की मुमानियत कर दी गई थी। इससे भारतायों में अधिक असन्तोप फैला। तत्कालीन औपनिवेशिक मन्त्री ने १६२३ के आरम्भ में केनिया के गवर्नर को बुला भेजा। गवर्नर के साथ अन्तिम समझति की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन और भारतीय प्रतिनिधि भी गये।

भारतीय (वडी) कौसिल ने भी एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा, जिसके सदस्य मान-नीय श्रोनिवास शास्त्री थे। केनिया के प्रतिनिधि-मण्डल ने एण्डरूज साहब से अपने साथ चलने का आग्रह किया। अगस्त १६२३ में काग्रेस ने इस मामले में निश्चयात्मक कार्रवाई आरम्भ की। इस विषय पर महासमिति ने एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि २६ अगस्त को देश भर में हड़ताल की जाय और जगह-जगह सभाएँ की जाय।

दिल्ली मे विशेष श्रधिवेशन

उक्त दोनो घटनाओं के बाद हो काग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर के वीसरे सप्ताह में वम्बई में न होकर दिल्ली में हुआ। इसके सभापित मौलाना अबुलकलाम आजाद थे। कौसिल-प्रत्रेश का समर्थन करनेवाले दल ने विना कठिंनाई के काग्रेस से यह अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि जिन काग्रेस-वायों को कौसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें अगले निविचनों में खडे होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने का आजादी है, इसलिए कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्द किया जाता है। साथ हा यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने मे दूनी शक्ति से काम लेना चाहिए। रामभजदत्त चौधरों के स्वर्गवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नाभा के जबर्दस्ती गद्दों छोड़ने और विहार, कनाड़ और वर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और समवेदना-सूचक प्रस्ताव पास किये गये। एक किमटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन सगिठत करने ओर विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धों हलचल को व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और किमटो नियुक्त हुई जिसके जिम्मे काग्रेस के विधान में परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी किमटी राष्ट्रोय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलो में वडे सयम से काम लिया जाय। अकाली लोग दमन का जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक वार फिर वधाई दी गई। खद्दर प्रचार के द्वारा विदेशी कपडे का वहिष्कार करने पर जोर दिया गया और एक कमिटी देशी माल बनाने वालो को प्रोत्साहन और अग्रेजी माल का बहिष्कार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय निश्चित करने के उद्देश्य से नियुक्त की गई। झण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए वधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, खास कर लालाजी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया।

केनिया के सम्बन्ध में कोच और तुर्की के सम्बन्ध में हुर्ष प्रकट किया गया। दो किमटिया और भी नियुक्त की गईं जिनमें से एक के सुपुर्व हिन्दू-मुस्लिम-कलह को रोकने का काम, और दूसरी के सुपुर्व गुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलन में वल का प्रयोग करने को सत्यता की जाच करने का काम हुआ। शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक दल बनाने और शारीरिक वल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया।

कोकनडा-कांग्रेस : १६५३

काग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनाडा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरि-वर्त्तनवादियों को अब भी थोड़ो-बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला है, कोकनडा उसे चाहे विलकुल मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव समाप्त हो जायग, फिर भी वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर उसी पुराने असहयोग का शाण्डा जड़ा रख़ा जायगा। मंग्लाना मुहम्मदअली को सभापित चुना गया। कोक-नड़ा-काग्रेस में जूब कश-म-कश रही। अपरिवर्त्तनवादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता धरीक नहा हुए। राजेन्द्र वावू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-काग्रेस में न जा मके और चक्रवर्गी राजगोपालाचायं ने दिल्लो के प्रस्ताव पर अपना प्रभाव डाला। श्री वल्लभनाई उपस्थित थे, परन्तु दिल्ली के प्रस्ताव के समझोते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वाकृति वंगाल के वृद्ध जजर वावू श्याम-सुन्दर चक्रवर्शी ने हानिल कर ली थी। उन्हें देश-निर्वासन और कारावास, निर्ध-नता और दिव्हता में अनेक वर्ष वितान पड़े थे। उन्होंने कोकनडा-काग्रेस के प्रवल समुदाय को अपने कांसिल-प्रवेश-विरोधों भाषण से थरी दिया। परन्तु पासा पड़ चुना था। कांनिल-बहिष्कार के भाग्य का निपटारा हो चुका था। गये, जो पास हुए। सरकार ने शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबधक-कि अकाली-दल पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश्य से एकत्र होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे काग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान सघर्ष में उनका साथ देने और उन्हें आदमी तथा रुपये और हर प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया।

गुरुद्धारा-श्रान्दोलन

इसी वर्ष एक और महत्त्वपूर्ण घटना हो गयी। यह गुरुद्वारा-आन्दोलन था। अग्रेजो ने पजाब को, १८४६ मे ब्रिटिश-भारत में मिला लिया था। इस रहोबदल के अवसर पर सिक्ख-धर्म के केन्द्र और गढ-स्वरूप अमृतसर के दरबार साहब के बदोवस्त मे गडबडा मची हुई थी। अमृत छके हुए सिवखो की एक कमिटी को ट्रस्टी बनाया गया था और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति सरबराह या अभिभावक बना था। एक मैनेजर नियुक्त किया गया था जिसके हाथो से हर साल लाखो रुपये निकलते थे। परन्तु १८८१ में यह किमटी भग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सारे अधिकार आ गये। नियत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेदारी और आचार हीनता का जन्म हुआ। एक ओर मैंनेजर और ग्रन्थियो और दूसरी ओर सिक्ख-जनता में आये दिन मुठभेड होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करे। १६२० के अन्त मे एक कमिटो बनाई गई जो बाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक कमिटी हुई। इस किमटी के पहले सभापित सरदार सुन्दर्सिह मजीठिया हुए जो कुछ दिनो के बाद ही पजाब सरकार की कार्य-सिमित के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक सिक्ख 'अकाली' कहलाते थे। उन्होने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारो को अपने हाथ मे कर लिया। तरन-तारन मे फसाद हो गया, कई सिक्ख घायल हुए और दो मरे। १९२१ के आरम्भ मे ननकानासाहब मे निर्दोष यात्रियो की हत्या हो ही चुको थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामर्थ्य को अपने कब्जे मे करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तो को बढावा मिला। इन महन्तो मे वे लोग भी थे जिन्होने अकालियो से समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार सुधारक सिक्खों के अन्धा-धुन्ध दमन पर उतारू थी। १६२१ के मई मास में सैकडो सिक्ख जेलो मे ठूस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तो को फिर अधिकार दिया गया। फलत जहा तक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी ने १६२१ की मई में सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पास कर दिया।

सरकार जो गुरुद्वारा-बिल पास कराना चाहती थी, वह सिक्खो में नरम-दल-वालो और सहयोगियो तक को मजूर न हुआ। फलत उसका विचार छोड दिया गया। सिक्खो पर एक निश्चित लम्बाई से अधिक बडी कृपाणे पहनने के लिए असहयोग का वेग: १९२१-२३

मुकदमे चलाये गये। पजाव-प्रान्तीय-काग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महोने के अन्त में सिक्खों को जेल से छोड दिया गया। झव्वा के भाई करतारसिंह और भूचड के भाई राजासिंह को १८ और ७ वर्ष का वर्वरतापूर्ण कारावास-दण्ड दिया गया। २८ अगस्त १६२१ को कौसिलो के सिक्ख सदस्यो से इस्तोफा देने के लिए कहा गया। सरवारबहादुर सरदार महताबसिंह वैरिस्टर ने गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी वकालत आर पजाव-कौसिल के उपाध्यक्ष के पद् से इस्ति फा दे दिया। १६२१ के सितम्बर के आरम्भ में उपर्युवत लम्बी सजा पाये हुए दोनो सिक्खो तथा अन्य कई को छोड दिया गया। परन्तु गजाव प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी के प्रधान-मत्री सरदार दाार् लिसिह कवीश्वर को, जिन्हे १६२१ के जून में १२४ ए धारा के अनुसार पाच वर्ष का संपरिश्रम कारावास हुआ था, और गुरुद्वारे के अन्य क र्यकत्ताओं को न छोड़ा गया। अचानक १६२१ की ७ नवम्बर को सरकार ने अमृतसर के दरबार-साहब की चाविया छीन ली, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर सजावट न हो सकी। सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवधक-किमटी ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पड़ा। बस, इसके बाद से चाविया ही सारे झगड़ेकी जड़ बन गई और जन-सभाओ-द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा। सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानून जारी किया और सरदार खड्गिसह और सरदार महताबिसह को कड़ी कैंद की सजा दी गई। गुरु गोविन्दर्सिह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२२को था। सरकार ने चाविया उस समय तक के लिए सौपने की तैयारी दिखाई जवतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में दायर किये गये मुकदमें का फैसला न हो। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-किमटी ने चाविया लेने से इन्कार कर दिया। जब २०० सिक्ख-कार्यकर्ता गिरपतार हो चुके तब सरकार ने हाथ रोक लिया और सारे कैदियों को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। १६२२ की ११ जनवरी को चाविया भी सौप दी गई; पर पण्डित दीनानाथ को न छोड़ा गया। फलतः राजद्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १६२२ की - फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवन्धक-किमटी की प्रवय-सिमिति के सारे सदस्य एक सभा में वोले। अन्त में पण्डित दीनानाथ को भी रिहा कर दिया गया और कोमागाटामारू (१९१४) वाले वाबा गुरुदत्तसिह को भी छोड दिया गया।

अकाली काली पगड़ी पहनते थे। १९२२ के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहले से ही निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूरथला की रियासतों में अकाली सिक्कों को एक-साथ पकड़ना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ी वाले सिक्क गिरपतार कर लिये गये। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी और

पजाब-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी के सभापित सरदार खडगिंसह को ५ वर्ष का किन कारावास-दण्ड दिया गया। मार्च १६२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा—'कृपाण तलवारे हैं जिनके बनाने के लिए लाइसेन्स की जरूरत है।' लोगो को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा वताये गये नये ढग से कृपाण पहनी जाय। फौजी सिक्खों का कृपाण धारण करना भी जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४ वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कडी सजा दी गई। कोमागाटामारूवाले बाबा गुरुदत्त-सिंह को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १६२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतासिंह को ६ साल की सजा मिली।

चारो ओर किमिनल लॉ-अमेण्डमेण्ट-ऐक्ट का दौर-दौरा था और जमानत सम्बन्धी धाराएँ उसकी सहायिका थी। पण्डित मदनमोहन मालवीय पजाब गये और राजा नरेन्द्रनाथ की अध्यक्षता में किमटी नियुक्त कराई, जिसके जिम्में सरकारी ज्यादितयों, गैर-कानूनी कार्रवाइयों और निर्देयता के सम्बन्ध में जाच करना था। १६२२ की चौदह मई को पजाब-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर धार्मिक सुधारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के, जिनका सुधार से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, बदअमनी फैलानेवाले और गैर-कानूनी कामों से अलग रहें। १५ जून १६२१ तक १६०० से २००० तक सिक्ख गिरफ्तार किये जा चुके थे।

इसी अवसर पर गुरु-का-वाग-काण्ड (१६२२) हुआ। इस काण्ड के सिल-सिले में जो ज्यादितया की गई उनकी जाच पजाव-सरकार के एक यूरोपियन सदस्य ने की। एण्डरूज साहब जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादितयों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "अव तक मैंने जितने हृदय-विदारक और करुणाजनक दृश्य देखें हैं, यह उनमें सबसे बढ़कर है। अहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहें हैं।" पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा — "एक घरा डाल दिया गया था और कई दिन तक काटेदार लोहें के तारों को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुरुद्वारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कही उस घरें के एक छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली।"

इस सिलिसिले मे २१० गिरफ्तारिया हुई। एक ही आनरेरी मिजिस्ट्रेट ने ५ इजलासो मे १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी श्रद्धानन्द को १८ महीने की सजा मिली। २२ अक्टूबर को एक जत्था अमृतसर से गुरु-का-बाग को रवाना हुआ। इस जत्थे मे १०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता लोग थे, जिनमें से ५५ नान-किमशण्ड अफसर थे और बाकी सिपाही थे। ये लोग मारू बाजा बजाते रवाना हुए। इनके साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप में थे। पजा साहब के स्टेशन से होकर एक रेलगाडी गुजरनेवाली थी, जिसमें फौजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ लोग उनके

असहयोग का वेग: १९२१-२३

लिए भोजन की सामग्री लिये बैठे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तब वे पटरियो पर लेट गये। रेलगाड़ी तब भी न रोकी गई। फलतः २ आदमी मरे और ११ घायल हुए। कुछ दिनो बाद पीटना बन्द कर दिया गया और गिरफ्तारियाँ आरम्भ हुई। जत्थो के मुखियो को कड़ी सजाये मिली। पर अभी इससे भी बुरी घटनाये आने को थीं। जनता के दबाव और 5 मार्च १६२३ के कीसिल के प्रस्ताव के उत्तर में अकालियों को धीरे-धीरे छोडा जाने लगा। १७० अकालियो को रावलपिण्डी में छोडा गया, पर उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा गया । कसूर यह बताया गया कि वे रेलवे-स्टेशन से बताये रास्ते से होकर नही गये थे । फीजी सिपाही और घुडसवार—सवने एक साथ मिलकर उन्हे तितर-वितर किया। १२८ व्यक्तियो को सगीन चोटे आई। ३ मई से रावलपिण्डी ने पूर्ण हडताल मनानी आरम्भ की। जब पजाब-कौसिल में इस मामले की जाच करेने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने का सवाल उठाया गया तव सरकार के चीफ सेकेटरी ने वडी शान्ति से सलाह दी कि हटर-किमटी की भाति पुराने जरूमो को दुबारा खोलने का नतीजा ठीक न होगा। गुरु-का-बाग-काण्ड की दुखदायी घटनाओं की स्मृति को जितनी जल्दी भुला दिया जाय, अच्छा है। परन्तु अकालियों के दुर्दिन अभी पूरे न हुए थे। १६२३ के मध्य में महाराजा नाभा ने गद्दों त्याग दी, पर शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रवधक-किमटी ने इसे महाराजा को गद्दी से उतारा जाना समझा और उन्हें दुवारा गृही पर विठान के लिए नाभा रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जगहो पर सभाये आदि करके एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। जो भाषण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक समझा गया और वक्ताओ को अखण्ड पाठ पढते-पढते गिरफ्तार कर लिया गया।

इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड पाठ के ऊपर झगड़ा शुरू हो गया और कुछ समय तक २५-२५ सिक्खों के जत्थे रोज जैतो भेजे जाने लगे। बाद को फरवरी मे ५०० आदिमयों का शहोदी जत्था भेजा गया। डा० किचलू और आचार्य गिडवानी इस जत्थे के साथ दर्शक की हैसियत से गये। जैतों के निकट इस जत्थे पर गोली चलाई गई और कुछ आदिमी मरे। किचलू और गिडवानी दोनों को नाभा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों की सुश्रूपा कर रहें थे! कुछ दिनों बाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के अन्त तक नाभा जेल मेही रहे। शहीदी जत्थे बरावर जाते रहें और गिरफ्तारिया भी होती रही। इस प्रकार अकाली हजारों की संस्या में जेल में पहुंच गये। उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसकी खराव रिपोर्ट आई। अकाली-सहायक व्यूरों में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिक्कर ने लिया। काग्रेस की कार्य-समित ने जेल में अकालियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की जांच के लिए जाच-कियों मेजी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी आर्थिक सहायता भी दी।

वाद को जब गुरुद्वारों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तब यह प्रश्न भी तय हो गया।

: 22:

कांग्रेस ज्ञौर कौंसिल-प्रवेशः १६२४-२६ गांधीजी की रिहाई

१२ जनवरी १९२४ को महात्मा गाधी के 'अपेडिसाइटिस' रोग से भयकर रूप में वीमार पड़ने और आधी रात में कर्नल मैडॉक-द्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गई। पर गाधीजी के स्वस्थ होने और अन्त में ५ फरवरी को उन्हें समय से पहले ही विना किसी शर्त के छोड़ दिये

जाने से वह चिन्ता दूर हो गई।

जेल से छूटकर भी गान्धीजी को न तो शान्ति मिली, और न विश्वान्ति। कोकनडाकाग्रेस में जा फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढती जा रही थी। एक ओर अपरिवर्त्तनवादी आशा कर रहेथे कि काग्रेस का इजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर
लौट पडेगा, दूसरी ओर परिवर्त्तन-वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा
में प्राप्त हुई विजयों को पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ धब्बा बाकी रह गया है
उसे घो लिया जायगा। परिवर्त्तनवादियों की 'स्वराज्य पार्टी' बन चुकी थीं और
उसने देश की विभिन्न कौसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया था। बड़ी कौसिल में
४५ स्वराजी पहुचे जिनमें खूब अनुशासन था और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने
का वत लिए हुए थे। वे राष्ट्रीय-दल का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके
कौसिल में आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके थे। उनकी पहली विजय तब हुई जब
श्री टी० रगाचारी ने शासन-व्यवस्था में तत्काल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में
एक प्रस्ताव पेश किया और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने यह सशोधन पेश किया कि
भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेजपरिषद् बुलाई जाय।

सरकार को यो तो कई बार हार खानी पड़ी, पर कुछ राजनैतिक कैंदियों को छोड़ने, दक्षिण-अफ़ीका से भारत में आनेवाले कोयले पर कर लगाने तथा सिक्ख-आन्दोलन की व्यवस्था के सम्बन्ध में जाच करने के बारे में पूरी हार हुई। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभी नरम-दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी वढ गया था। स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी मागों की चार मदों को नामजूर कर

दिया। ऐसा पहले कभी नही हुआ था।

गांधीजी का वक्तव्य

१६२४ की गींमयों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए हम अब गांधीजी, दास वाबू और नेहरूजी के वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वार्तालाप के बाद प्रकाशित किये गये। गांधीजी ने अपने वक्तव्य में कहा . "अपने स्वराजी मित्रों के साथ काग्रेसवादियों के द्वारा कौसिल-प्रत्रेश के जटिल प्रश्न पर वातचीत करने के बाद मुझे दु ख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत न हो सका। ××× मेरी अब भी यही सम्मित है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार कौसिल-प्रवेश असगत है। हमारा मतभेद 'असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभापा तक ही सीमित हो सो बात भो नहीं है; यह मतभेद तो चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याओं के सुलझान में मतभेद अनिवार्य हो जाता है। उस मनोवृत्ति के पैमान से ही बहि- क्कार-त्रयी की सफलता या विफलता को जाचना होगा, फल-सिद्धि के पैमान से नहीं। मैं इसी दृष्टि-कोण से कह रहा हूँ कि देश के लिए कौसिल से वाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कही अविक लाभदायक होगा।

"दिल्ली और कोकनडा-काग्रेस ने उन काग्रेसवादियों को कौसिलों और असेम्बली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो। इसिलए मेरी राय में स्वराजी कौसिलों में जाने का और अपरिवर्त्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आगा रखने का अधिकार रखते हैं। उनको वहां जाकर अड़गा-नीति धारण करने का भी हक है; क्यों कि उनकी नोति ही यह थी और काग्रेस ने उनके कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि स्वराजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे सशयशील व्यक्तियों को अपनी भूल अवश्य मालूम हो जायगी और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो में जानता हूं कि वे देश-भक्त है और अवश्य अपना कदम पीछे हटा लेगे। इसिलए में उनके मार्ग में वाधा डालने के काम में शरीक न होऊंगा और न स्वराजियों के कौसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में ही भाग लूगा। हा, में ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं है . . . ।

"कौतिलों में क्या ढंग अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौतिलों में तभी घुसूगा जब मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकूंगा। अतएव यदि मैं कौतिलों में जाऊगा तो मैं सोलह आने अडगा नीति का अलबम्बन न करके काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेण्टा करूगा। मैं उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों से चाहुंगा कि

(१) वे सारे कपडे हाय के कते और हाथ के बुने खद्दर के खरीदें।

(२) विदेशी कपडो पर बहुत भारी चुगी लगा दे।

(३) शराब आदि की आय को ही रद कर दे, और सेना-विभाग के व्यय मे,

अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दे।

"यदि सरकार कौसिलों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इन्कार कर दे, तो मैं सरकार से कौसिलों को भग करने के लिए कहूंगा और उन्हीं खास-खास बातों पर फिर निर्वाचकों के वोट हासिल करूंगा। यदि सरकार कौसिल भग करने से इकार कर दे तो मैं अपनी जगह से इस्तीफा दे दूगा और देश को सत्या-ग्रह के लिए तैयार करूंगा। जब यह अवस्था आ पहुंचे तब स्वराजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी कसौटी वहीं पुरानी है।"

स्वराजी-वक्तव्य

देशबन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा .—

"हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सके। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौसिल-प्रवेश नागपुर-काग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं। है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, तो हम देश के वास्तविक हित.के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

"हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में 'अडगा' शब्द का जो व्यवहार किया है वह ब्रिटेन की पार्लमेण्ट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नही है। मातहत और सीमित अधिकारो वाली कौसिलो में उस अर्थ में अडगा डालना असम्भव है, क्यों कि सुधार-कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौसिल के अधिकार गिने-चुने हैं, पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अडगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई क्कावटो का मुकाबला करने का अधिक है। 'अडगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकाबले से है। हमने स्वराज्य-पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है।

"पर यहा भी हम इस बात के व्यर्थ वाद-विवाद का अन्त करना चाहते हैं कि इस नीति को "सतत और लगातार अडगे की नीति" कहा जा सकता है या नहीं। हम तो अपनी नीति को विस्तार के साथ बताकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। हमारे मित्र यदि चाहे तो इसे अधिक उपयुक्त नाम प्रदान कर सकते हैं।" इसी सिद्धान्त

और नीति के अनुसार वक्तव्य में एक भावी कार्यक्रम भी सम्मिलित था।

महासमिति की बैठक

अहमदावाद में २७, २८ आर २६ जून को महासमिति की बैठक हुई। निर्वाचित काग्रेस-सस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,०० गज अच्छी तरह ऐठा और कता हुआ सूत भेजना अनिवार्य कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर चर्ची हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्मानेवाली वात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बैठक से उठकर चले गये। यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्मानेवाली बात हटा ली और महासमिति ने नागा करनेवालों के खिलाफ जान्ता कार्रवाई करने की सिफारिश की।

विदेशी कपड़े, अदालतो, स्कूलो-कालेजो, उपाधियों और कौसिलो के पाची प्रकार के (कोकनड़ा के प्रस्ताव को घ्यान में रखते हुए) बहिष्कार पर जोर दिया गया और काग्रेस के मतदाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को काग्रेस की मातहत-संस्थाओं में न चुना जाय जो पाचो प्रकार के बहिष्कार के सिद्धान्त में विश्वास न रखते हो और स्वयं भी उस पर अमल न करते हो। सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्दा की गई और एण्डरूज साहब से अनुरोध किया गया कि वह आस मवालों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जाच करे। सिक्खों ने जीतों के अनावश्यक और निर्दयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अवसर पर जो शातिपूर्ण साहस दिखाया था उसके लिए उन्हें बधाई दी गई।

इस वैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आनेंस्ट हे की हत्या के धिक्कार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की वात को, जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथ-भ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की कि इस प्रकार के कृत्य काग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध है, स्वराज्य के मार्ग में रुकावट डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में वाधक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर खूव वाग्युद्ध हुआ।

स्वराजों इस बैठक में अपनी इच्छानुसार सव-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की हुई सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक रुकना पडा। जहांतक अपरिवर्त्तनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाती शर्त को उन्होंने आश्चर्यजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७६० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्तूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये।

साम्प्रदायिक दंगे

परन्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों का होना, खासकर दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहापुर, इलाहाबाद, और जबलपुर में। सबसे अधिक भयकर दगा कोहाट में हुआ। कोहाट के दगे ने तो भारत-वर्ष की कमर तोड़ दी। दगों के कारणों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गांधीजी और मौ० शौंकतअली की एक किमटी नियुक्त की गई। दोनों ने रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद था कि दगों की जिम्मेदारी किस पर है। १६२४ की ६ और १० सितम्बर की घटनाओं को बीते आज बत्तीस वर्ष से भी अधिक हुए, पर दगे के फौरन बाद ही कोहाट के भ्रातृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दगा-पीडित-सहायक समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमाच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ६ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कत्लेआम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुस्ओं को सवार कराकर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने बाद तक रावलिएडी की जनता की और १४०० अन्य स्थानो की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे।

गांधीजी का उपवास

ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जो गाधीजी ने २१ दिन के उपवास का वृत लिया। इस कोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होने अपने-आपको ठहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अभी अपेण्डिसाइटिस के भयकर ओर लगभग साघातिक प्रकोप से उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अत यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गाधीजी ने व्रत मौलाना मुहम्मदअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान में ले जाया गया। इस अवसर से लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं ं को एकत्र किया गया । कलकत्ते के बडे पादरी भी शरीक हुए । यह एकता-परिषद् २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन् १६२४ तक होती रही। परिषद् के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और मत की स्वतन्त्रता के सिद्धात का पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेगे और उत्तेजन मिलने पर भी इनके विरुद्ध किये गये आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रक्खेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पचायत बनाई गई, जिसके स्योजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए और ह्कीम अजमलखा, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, डा० एस० के० दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्दरसिंह सदस्य हुए। परिषद् ने धार्मिक सिद्धातो को मानने, धार्मिक विचारो को प्रकट करने और घार्मिक रीति-रिवाजो का पालन करने, घर्म-स्थानो की पवि-त्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध

में सवका एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखवारों को चेतावनी दी कि वे साप्रदायिक मामलों में समझवूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गाधीजी के उपवास के अतिम सप्ताह में देगभर में प्रार्थना को जाय। द अक्तूबर जन-सभाओं द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया।

सर्वदल-सम्मेलन

अभी गाघीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें वस्वई में २१ और २२ नवस्वर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके वाद ही और उसी के सिलिसिलें में २३, २४ को महा-सिमिति की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वदल-सम्मेलन फरने का उद्देश्य यह था कि बगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और तारकेश्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिषद् ने बगाल-सरकार द्वारा जारी किये गये किमिनल-ला-अमेण्डमेण्ट-आर्डिनेन्स के विरुद्ध, निन्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगूलेशन ३ को रद करने पर जोर दिया। सर्वदल-सम्मेलन ने बंगाल की अञान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और एक किमटो नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्वराज्य की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस किमटो में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रक्खा गया। ३१ मार्च १६२५ तक रिपोर्ट मागी गई। परिषद् के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे सम्भवत देशवन्ध चित्तरजन दास की गिरफ्तारी टल गई।

वेलगांव-कांग्रेस : १६२४

असहयोग के इतिहास में बेलगाव-काग्रेस खास महत्व रखती है। गाधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीव-करीव अन्तिम सीमा तक पहुच चुका था। काग्रेस अब ऐसे स्थान पर खडी थी जहां से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। काग्रेस-वादियों को अब दो परस्पर विरुद्ध दलों में वट जाना चाहिए या समझौता करके सपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो तो इस जटिल काम को गाधीजी के सिवा और कान हाथ में ले? केवल गाधीजी ही ऐसे ये जो सत्याग्रह का कार्य-कम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को सांत पर समते ये और कौसिल-प्रवेदा का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुष्ट रख मको ये। यदि जिसी महती योजना के आरम्भ करने के लिए महान् व्यक्ति की आपर्यम्यता है, तो उने बन्द करने में भी महान् व्यक्ति ही समयं हो सकता है। दमिल पर समय के अनुकून ही हुआ कि १६२४ की काग्रेस के नभापित गाधीजी रूप। उन्होंने अपना अद्भुत भाषण पेश किया; पर कांग्रेस में उसका मंक्षेप ही

सुनाया गया। इस भाषण में उन्होने १९२० से उस समय तक की घटनाओ पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार काग्रेस मुख्यत एक ऐसी सस्था रही है जिसके द्वारा भोतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सब तरह के बहिष्कारो को भिन्न-भिन्न दलो ने अपनाया। वैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन सस्याओं का बहिष्कार किया गया उनका रौव बहुत-कुछ कम हो गया। सबसे वडा बहिष्कार हिंसा का वहिष्कार था। पर अहिंसा ने असहाया-वस्था की निष्त्रियता को छोडकर अभो साधन-सम्पन्न और परिष्कृत रूप धारण नहीं किया था। जिन्होने असहयोग में साथ नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिनो हुई हिंसा से काम लिया गया। पर अहिंसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दबाये रखा। फलत सब प्रकार के वहिष्कार उठा लिये गये, केवल एक बहि-ष्कार--विदेशो कपडो का रह गया। इस प्रकार वहिष्कार करने का जनता का न केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्त्तव्य भी था। अहिंसा के सम्बन्ध में भी उनका यही रुख था। परन्तु अकेले घरेलू-धन्धे ने ही जिन हजारी आदिमियो के दरवाजे से सुख-चैन को दूर कर रक्खा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुखी था। उनके और स्वराजियों के मतभेदों में समझौता हो गया था। स्वराजी सूत कात कर देने को राजी हो गये और गाघीजी ने उनके कौसिलो में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दगे पर सन्ताप प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानु-भूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। इस प्रकार भूमिका बाधने के बाद गाधीजी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ बाते बताई।

मताधिकार के लिए शारीरिक परिश्रम की शर्त, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता न्याय, मादक-द्रव्य और उससे आने वाली चुड़ी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रातों का भाषा को दृष्टि से पुनर्निर्माण, इस देश में विदेशियों के इजारों (मोनोपली) की नये सिरे से जाच-पड़ताल, भारतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्रारा खलल न पहुँचने का आश्वासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न-भिन्न सस्थाओं को धार्मिक-स्वतन्त्रता, देशी-भाषाओं द्वारा सरकारी काम-काज, और

हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मानना उपयक्त समझा गया।

पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकृष्ट हुआ। अहमदा-वाद के वाद से उनके विचार सौम्य हो गये थे, क्योंकि उस समय वे आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहा तक सरकार के रग-ढग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड गया था। उन्होंने कहा—"मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूगा, पर यदि स्वय ब्रिटेन के दोष से ही उससे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नहीं करूगा।" इसके वाद उन्होंने

कांग्रेस ग्रौर कींसिल-प्रवेश: १९२४

स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र किया और बैंगाल की जिल्हा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करने भाषण समाप्त किया।

इस अधिवेशन में काग्रेस-मताधिकार में परिवर्तन किया गया। हिन्दुओं के कोहाट-त्याग पर खेद प्रकट किया गया। कोहाट के मुसलमानो को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनके जान-माल के सम्बन्ध में आश्वासन दे, साथ ही हिन्दू मुहाजरीन को सलाह दी गई कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावें तवतक वे वापस न जाय। इसी तरह गुलबर्गा के पीडितो के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। वैतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद वताया गया। अकाली-दल, मिदरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और काग्रेस के विधान में कुछ जरुरी तब्दीलिया की गईं।

अङ्गा-नोति

१६२५ की राजनीति मुख्यत कौसिलो में किये गये काम तक सीमित रही। स्वराजियों को अपरिवर्त्तनवादियों की ओर से परेशानी नहीं थी, क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर रखनें को मौजूद थे। मध्यप्रदेश और बगाल में द्वैधशासन का अन्त हो गया था। लॉर्ड लिटन के निमत्रण पर देशवन्धु दास ने बगाल में मित्रमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया था। जब लॉर्ड रीडिंग का १६२४ का न० १ ऑडिनेन्स समाप्त हुआ तब बगाल-कौसिल में एक बिल पेश किया गया, जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के प्रभाव ने १६२५ की जनवरी में रद कर दिया। लॉर्ड लिटन ने उसे सहों कर दिया और लन्दन सम्राट्-सरकार की मजूरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को बगाल-कौसिल ने प्रस्ताव पास करके वजट में मित्रयों के बेतन की गुजाइश रखने की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पड़ा, पर उन्होंने शोघ्र ही इस क्षित को पूरा कर लिया। इधर बगाल असहयोंग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मित्रत्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे वह भीतर से विव्वंस कर सके वड़ी कौसिल में स्वराज्य-पार्टी १६२४ और १६२५ में विरोधों दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट किमटियों में भाग लिया और लाभदायक कानून पास करने में सहयोंग दिया। कभी किसी पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का और यदाकदा सरकार का भी।

देशवन्धु को मृत्यु

इस समय तक देशवन्बुदास ने काग्रेस में अपने लिए गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर निया था। इसो वःच वेलगाव-काग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशवन्धु दास ने अपनी सारी सम्पत्ति देश को अर्पण कर दी है,

जिसका उपयोग परोपकार मे किया जायगा। इस बात से देशवन्धुदास जनता की दृष्टि में और भी ऊचे उठ गये थे। १६२५ के मार्च और अप्रैल में गाघीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया। दक्षिण से गांधीजी बगाल जानेवाले थे। उस समय तक दास वाबू अस्वस्थ हो चुके थे। उन्हें शाम को ज्वर रहने लगा था जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इसके लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया गया था । फरीदपुर की बगाल-प्रान्तीय-परिपद के अवसर पर यही स्थिति थी । देशवन्धु ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमे उन्होने कहा "हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक घडी आ रही है। इस वर्ष के अन्त मे ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तिया काम में लग जायगो। इधर हम दोनो बीमार पड़े हैं। ईश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।" इसके कुछ ही दिनो वाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशवन्धु को स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १९२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास वाबू का जीवन स्वय ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। उनके देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गाधीजी ने दुखी होकर कहा था-"उनकी स्मृति को अमर वनाने के लिए हमे क्या करना चाहिए। आसू बहाना बडा आसान है। परन्तु आसुओ से हमे या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियो को कोई लाभ न होगा। यदि हम लाग हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, ये सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, सकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशवन्धु जिये और जिस काम में वह निमग्न रहे उसे पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सबमें उनकी जैसी बुद्धि नहीं है, पर वे जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।"

गाधीजी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह बगाल ही में एक गये। उन्होने उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक बनाया। उन्होने दस लाख रुपया एकत्र किया। देशवन्धु दास का भवन १४ दसा-रोड, देश के अपण हुआ। इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट-योजना के अनुसार, जो उन्होने बेलगाव-काग्रेस से पहले प्रकट की थो, स्त्रियो और बच्चो का अस्पताल बना दिया गया। गाधीजी ने स्वराजियो के हाथ में सारी शक्ति देने और बगाल में स्वराज्य-पार्टी की जड़ मजबूत जमाने में कोई कसर न उठा रखी। इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुष्त को कौसिल में स्वराज्य-पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर और बगाल प्रान्तीय काग्रेस-किमटी का सभापित बनाने का काम उन्ही का था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए थे सेनगुप्त के सिर पर रख दिया गया।

स्वराज्य पार्टी से मत-भेद

इधर गाधीजी स्वराजियो को निश्चित करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे,

उघर गाघीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। स्वराज्य-पार्टी की जनरल कौसिल का विरोध सूत देने की उस शर्त के खिलाफ हुआ था, जो बेलगाव में तय हो चुकी थी। यह विरोध बढता ही गया, और अन्त में इस शर्त को उडा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौप दिया गया। महा-समिति में स्वराज्य-पार्टी का वहुमत था। १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की वैठक के बाद सम्भवत गांधीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूकि काग्रेस में स्वराजियों की वहुलता है, और चूकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति है, इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए। गाधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि में इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वराजियों में हलचल मच गई। पर अन्त मे यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अन्त तक गाधीजी ही महासमिति के सभापति वने रहेगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की गर्त उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा दे देगे और एक अलग चर्का-संघे स्थापित करेगे। कार्य-समिति ने सूत कातने की शर्त में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रश्न पर दुवारा विचार करने के लिए १ अक्तूबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस वीच गाघीजी ने स्वराज्य पार्टी को समर्थन करने में कुछ उठा न रखा। अगस्त में गाधीजी ने लिखा था-"मुझे काग्रेस के मार्ग में और अधिक खडा न होना चाहिए। काग्रेस का पय-प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के द्वारा, जिसने अपने आपको अपढ जनता में मिला दिया है और जिसका भारत के शिक्षित-समाज की मनोवृत्ति से मौलिक अन्तर है, होने की अपेक्षा शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के मार्ग में मैं वाधक वनना नही चाहता। मैं अव भी उन पर अपना असर डालना चाहता हूं, परन्तु काग्रेस को छोड़ कर नही। यह काम तभी अच्छी तरह हो सकता है, जब मैं रास्ते में से हट जाऊ और काग्रेस की सहायता से, उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक कार्य में लगा दू। में कार्येस की सहायता और उसके नाम का उपयोग उसी हद तक करूगा जिस हद तक निक्षित भारतीय मुझे अनुमित देंगे।" असली वात यह थी कि एक ओर तो स्वराजी लोग गांधीजी के सिद्धातों का खण्डन करते थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी पाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तो पर चाहते थे।

पटना-महासमिति

२१सितम्बर १६२४ को पटना में महासमिति की बैठक हुई। इस बैठक में माग्रेन की स्पिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। खद्र का राजनै-तिक महत्व छिन गया। हाप-यता सूत देने की शर्त केवल चार आना न देने की हारत में ही लाग् रही। राजनैतिक काम ना भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब स्वराज्य-पार्टी काग्रेस का एक अङ्ग-मात्र न रही। वह स्वयं काग्रेस हो गई। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं, स्वय काग्रेस करेगी। कौसिल-प्रवेश में विश्वास रखने वाली बड़ी कौसिल के सदस्य अब "स्वराजिस्ट" नहीं कहलायेगे, बल्कि कौसिलों में काग्रेस-सदस्य कहलायेगे। सूत कातने की शतं अब एकमात्र शतं नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शतं को मानने वाले कम थे —१०,००० सदस्य मौजूद थे —परन्तु यह था कि स्वराजियों को यह शतं पसन्द न थी। इस प्रकार खद्दर के समर्थकों और कौसिल के समर्थकों में काग्रेस का बटवारा हो गया। एकता ऊपर-ही-ऊपर थी। वास्तव में खद्दर के समर्थकों में असतोष फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती थी। फलत पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उसपर सही करनी पड़ी।

कानपुर-कांग्रेख : १६२५

१६२५ की कानपुर-काग्रेस के दिन आ लगे थे। जनता ज्यो-की-त्यो थी——उसमे पहले की भाति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी। पर वह तभी जब 'शिक्षित' समुदाय उसके पास कोई जीता-जागता आदर्श, कोई फकडता हुआ कार्यक्रम ले जाय। परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। फलत मसाला मौजूद था, पर उसकी शक्ति गायब हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपायो से न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो चार कदम बाद मोटर के इजन में गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुवारा रोके जाने तक काम करता रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियाँ उस समय के लिए हकी हुई थी और उसमें गति उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। ऐसे ही वातावरण में २६ दिसम्बर को कानपुर की काग्रेस हुई।

कानपुर-काग्रेस को पटना के निर्णय पर सही करनी थी। पटना में भी यह बात सिदग्ध समझी जा रही थी कि बेलगाव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के मिल्कियत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है, वह महासमिति भी स्वीकार करेगी अथवा नहीं। कानपुर-काग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेत्री भारत की कवियत्री श्रीमती सरोजिनी नायड़ थीं, इसी प्रकार के जिंटल प्रश्न मौजूद थे। गांधीजी केवल ५ मिनट बोले। उन्होंने कहा कि "अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद में अपनी ऐसी एक भी बात नहीं पाता जिसे रद करू, न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ जिसे वापस लू। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगो में जोश और उत्साह है तो मैं आज सत्याग्रह आरम्भ कर दू। पर अफसोस! हालत ऐसी नहीं है।" सरोजिनी देवी ने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह काग्रेस-भच से दिया

गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया।

कानपुर-काग्रेस का अधिवेशन स्वभावत. ही देशबन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, डा॰ सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर और अन्य नेताओ की मृत्यु पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफीका से एक शिष्ट-मण्डल आया हुआ था। काग्रेस ने उसका स्वागत किया। बगाल आर्डि-नेन्स और गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैंदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। वर्मा के गैर-वर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करने वालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये गये बिलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। काग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात् सविनय-भग में अपनी आस्था प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मिर्मरता ही एक पथ-प्रदर्शक समझी जाय। इसके बाद काग्रेस ने जो निश्चय किए उनमें मुख्यत. इन बातो पर बल दिया गया:—

- (१) देश के भौतर काग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों के सप्बन्ध में शिक्षा दी जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्खें और खद्दर के प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की वृद्धि, अस्पृश्यता-निवारण, दिलत जितयों का उद्धार और नशें की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जाय, साथ ही स्थानीय सस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-सगठन करना, राष्ट्रीय ढग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजदूरों और खेतों का काम करने वाले मजदूरों का सगठन करना, मजदूरों और मालिकों, तथा जमीदारों और किसानों में सौहाई स्थापित करना और देश के राष्ट्रीय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना भी शामिल रहेंगा।
- (२) देश से वाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थिति का प्रचार करना होगा।
- (३) काग्रेस ने देश की ओर से समझौते की उन शतों को मजूर किया जिन्हें वड़ी कौसिल की इण्डिपेण्डेण्ट और स्वराज्य-पार्टियों ने अपने १८ फरवरी १६२४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रखा था, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय किया कि स्वराज-पार्टी जल्दी-से-जल्दी वड़ी कौसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना आख़िरी निर्णय सुनाने का अन्रोध करें। यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे काग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष सिमिति अथवा महासमिति-द्वारा नियुक्त सदस्य, सतोपजनक न समझे, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-द्वारा वड़ी कौसिल में सरकार को सूचित कर दे

कि अब वह पहले की तरह वर्तमान कौ सिलो में काम न करेगी। इसके वाद स्वराज्य पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्य परिषद् में हो, चाहे बड़ी कौ सिलो में, चाहे छोटी कौ सिलो में—उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमेटी में शरीक न हो। अपनी जगह को खाली घोषित करने से रोकने, प्रान्तीय वजटो को नामजूर करने अथवा कोई नया कर लगानेवाले बिल को रद करने के लिए कौ सिलो में जाया जा सकता है।

(४) यह काग्रेस विभिन्न प्रान्तीय काग्रेस-कमिटियो की कार्य-सिमितियों को अधिकार देती है कि वे अगले वर्ष के कौसिलो और बड़ी कौसिलो के निर्वाचन के लिए अपने प्रान्तों में उम्मेदवार शोध्र-से-शीध्र चुनना आरम्भ कर दे।

अन्त में काग्रेस और महासमिति की कार्रवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा अपनाई गई। महासमिति को प्रवासी भारतवासियों के हितों की देख-भाष रखने के लिए अपने अन्तर्गत एक वैदेशिक विभाग खोलने का अधिकार दिया गया। अगला अधिवेशन आसाम में करना तय हुआ। डॉ॰ मुख्तारअहमद अन्सारी, श्री ए॰ रगस्वामी आयगर और श्री के॰ सन्तानम प्रधान मन्त्री नियत हुए।

साम्प्रदायिक दंगे

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमे उन हिन्दू-मुस्लिम दंगो का जिक करता है जो १६२५ में कई स्थानों में होते रहें। हिन्दू-मुस्लिम-दंगो का जिक करते हुए १६२५ की पहली मई को गांधीजों ने कलकत्त के मिर्जापुर-पार्क में कहा— "मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औषि बतानेवाले वैद्य की विशेषता मुझमें नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू अथवा मुसलमान मेरी औषि को स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए आजकल मैंने इस समस्या की यो ही उडती-सी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर लिया है। मैं यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक-न-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा और यदि हमारे भाग्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डाले हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोडने पर उताक है तो हमें ऐसा मर्दानगों के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-मूठ के आसून बहाने चाहिए, और यदि हम एक दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं करनी चाहिए।"

१६२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद थे। वकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्तबाद नामक स्थान पर भी दगा हो गया। १६२५ का साल समाप्त करने से

पहले सिक्खों की समस्या का भी जिन्न करना आवश्यक हैं। १६२४ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पजाब-कौसिल में गुरुद्वारा-बिल पेश किया गया और पास हो गया। साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदी शर्तनामें पर दस्तखत करके नये कानून को मजूर कर लेगे और पहले को भाति आन्दोलन न करने का जिम्मा लेगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बहुतों ने इसपर कोंध प्रकट किया, पर धोरे-धीरे कोंध शान्त हो गया। बहुत-से कैदियों ने कानून न मानने का जिम्मा लिया। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक कियी में इस बात को लेकर फूट पड़ गई। अधिकाश कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगतने के लिए जलों में ही रहे।

सहयोग की श्रोर

१६२६ का आरम्भ कौसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा। १६२३ की नवीनता का आकर्षण इस समय तक फीका पड चुका था। केवल 'युद्ध' की खातिर लगातार 'युद्ध' किये जाना कुछ थकाने वाली बात सिद्ध हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देने लगे।

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक रायसीना (दिल्ली) में हुई जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एक बार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि स्वराज्य के मार्ग में रोडे अटकानेवाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे संकल्प के साथ मुकाबला किया जायगा और विशेष रूप से उस समय तक कौसिलों में गये हुए काग्रेसी सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले पदों को स्वीकार न करेंगे जब तक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक उत्तर न मिलेगा।

बड़ी कौसिल में जब बजट की चर्चा आरम्भ हुई तब पण्डित मोतीलाल नेहरू ने जाहिर किया कि मैं और मेरे समर्थक मत देने में कोई भाग न लेंगे। कौसिल-भवन की गैलिरिया खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि स्वराजियों के बड़ी कौसिल से 'वाक्-आउट' करने की बात पहले से ही लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्पूर्ण समझौते की बात का किस प्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी से काम न लिया तो देश भर में गुप्त-समितियां कायम हो जायगी। इतना कहकर नेहरू जी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कौसिल-भवन से बाहर चले गये।

इस 'वाक्-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई । अघ्यक्ष श्री विट्ठलभाई पटेल ने इस 'वाक्-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूकि कौसिल की सबसे जबर्दस्त पार्टी कौसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिनिधित्व रूप इस कौसिल का नहीं रह जाता। अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करें कि बड़ी कौसिल को वैठक जारी रहें या नहीं ? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून पेश न करें, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके जो भारत-सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को अनिश्चित समय तक के लिए स्थिगत करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा—"मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के बाद मैं इस नतीज पर पहुचा हू कि अध्यक्ष को अपने अधिकारों का जिक न करना चाहिए था, और न ऐसो भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए था, जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप में किया जा सके, बल्कि कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है।" इससे सरकार की चिन्ता मिट गई।

राष्ट्रीय दल का जनम

असहयोग का जो पत्थर गया में ऊचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरम्भ में साबरमती में करीब-करीब नीचे आ गिरा। हम यह देख चुके हैं कि प्रतिसहयोगी, स्वतन्त्र और राष्ट्रीय-दलवालो के कितना निकट पहुच गर्ये थे। तदनुसार उन्होने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलो के नेताओ के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप "इंडियन नेशनल पार्टी" (राप्ट्रीय दल) का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था शान्तिपूर्ण और वैध उपायो से (सामूहिक सत्याप्रह और करबन्दी को छोडकर) शी घ्रे औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने की तैयारी करना। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के सगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चीत के बाद स्वराज्य-पार्टी के दोनो दलों की एक बैठक २१ अप्रैल को साबरमती में बुलाई गई। इस बैठक में अन्य नेताओ के अलावा सरोजिनीदेवी, लाला लाजपतराय, श्री केलकर, श्री जयकर, श्री अणे और डा॰ मुजे भी थे। यहां महासमिति द्वारा पुष्टि मिलने की शर्त रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के बीच यह तय हुआ कि १६२४ की फरवरी में स्वराजियो ने जो माग पेश की थी उसके सरकार-द्वारा दियं गयं उत्तर को सतोष-जनक समझा जाय, यदि मन्त्रियो को प्रातो में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छा-पूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। भिन्न-भिन्न प्रान्तो की कौंसिलो के काग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोडा गया कि इस प्रकार दिये ग्रे अधिकार पर्याप्त है या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी की, जिसमे पण्डित मोतीलाल नेहरू और श्री मुकुन्दराव जयकर हो, पुष्टि मिल जाना

आवश्यक रखा गया। पर अभी इस समझौते की स्याही सूखने भी न पाई थी कि आन्ध्र प्रान्तीय काग्रेस-अभिटी के सभापित श्री प्रकाशम् ने अपनी असहमित प्रकट की। अन्य अनेक प्रमुख काग्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का असतीय प्रकट किया। साधारणतया यह समझा जाने लगा कि चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, स्वराजी शोध्र ही फिर कौसिलों में चले जायँगे और मित्र-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु प० मोतीलाल नेहरू ने यह प्रकट करके कि पद-ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों क पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्तें थी.—

(१) मन्त्री कौसिलो के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जायँ और उनपर सरकार का कोई शासन न रहे, (२) आय का उचित भाग "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिये नियत किया जाय और (३) मित्रयो को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियो पर पूरा अधिकार हो।

परन्तु सारी बाते फिर खटाई मे पड गईं। श्री जयकर ने उस मसविदे को, जो किमटी के सामने रखा गया, समझौते के बिलकुल विरुद्ध बताया। साबरमती के समझौते का निपटारा करने के लिए १ मई को महासमिति की बैठक हुई। इस बैठक मे पिण्डत मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "चूिक शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर करनेवालों में इतना मतभेद हैं कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से समझौते की जो बातचीत चला रहा था उसे रद समझा जाय।" वह इंग्लैण्ड जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली और श्रीनिवास आयगर ने उनका स्थान ग्रहण किया।

साम्प्रदायिक दंगे

१६२६ को मध्य में देश की राजनैतिक स्थिति भयंकर हो गयी। ६ अप्रैल १६२६ को लॉर्ड इर्विन भारत में आये। लगभग उसी समय कलकते में बड़ा ही भयानक साम्प्रदायिक दगा हो गया। छ सप्ताह तक कलकते की सड़के हत्या-काण्ड और अव्यवस्था का अखाडा बनी रही। जगह-जगह सड़को पर दगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरो और मस्जिदो पर हमला किया गया। सरकारी बयान के अनुसार पहली मुठभेड में ४४ आदमी मरे और ५६४ घायल हुए और दूसरी मुठभेड में ६६ आदमी मरे और ३६१ घायल हुए। ६ सप्ताह के विघ्वस और हत्या-काण्ड के वाद दगा शान्त हुआ। लॉर्ड इर्विन इन दगो से बड़े बेचैन हुए। उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमे उन्होंने अपनी सारी आस्था और विह्वलता, सारी धर्म-भावना और सहुदयता रख दी। उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और धर्मके नाम पर भारत की उस सुकृति को बचाओ जिसे वर्तमान वैमनस्य मिटा रहा है।

निर्वाचन में कांग्रेस की विजय

सितम्बर में लाला लाजपतराय और पण्डित मोतीलाल नेहरू के वीच वडी कौसिल के काम के सबध में फिर मतभेद उठ खडा हुआ। लालाजी का ख्याल या कि स्वराजियों की 'वाक्-आउट' की नीति हिन्दू-हितों के लिए स्पष्टतया हानिकर है। वह पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में साबरमती के समझौते की पुष्टि के पक्ष में भी थं। इसलिए उन्होंने वडी कौसिल में काग्रेस-पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वडी कौसिल की अविध भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी। नये निर्वाचन सर पर मौजूद थे।

१६२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मद्रास के काग्रेसी उम्मीदवार—अब वह स्वराजी न कहलाते थे—पूर्ण रूप से विजयी हुए। लॉर्ड वर्कनहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखे, गोहाटी में काग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवास आयगर गोहाटी-काग्रेस के सभापित चुने गये।

गोहाटी कांग्रेस : १६२६

गोहाटी-काग्रेस स्वभावत ही तनातनी के वातावरण मे हुई। तनातनी का कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की बात है कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी रुकावट डालना था, उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था मे, जब कौसिलो में स्वराजियो का मताधिक्य हो, करने की बात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग अस-हयोग के निकट आ लगा, क्या कौसिलो की कमिटियो के निर्वाचन-द्वारा प्राप्त होने वाली जगहो के सम्बन्ध मे और क्या भारत-सरकार की कमिटियो की नामजद जगहो के सम्बन्ध मे । अन्त मे यह असहयोग सावरमती मे सहयोग के आस-पास् घूमने लगा, पर झिझक के साथ। कौसिल-पार्टी इस सम्बन्ध में बात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने मे सकोच करती थी । इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी असहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर वह राष्ट्रीय-दल, स्वतन्त्र-दल या उदार-दलवालो की स्थिति अपनाने को तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड में उडाती थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और आवश्यक होने पर अडगा डालने की, और सुधारों के मामले में सहयोग करने की वात करते जरूर ये। इन्ही सूक्ष्म पर पूर्ण रूप से व्यावहारिक प्रश्नों ने प्राग्ज्योतिषपुर (गोहाटी) में आपस में खिचाव पैदां कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम-खुल्ला प्रशसा करके, और अप्रत्यक्ष रूप से उसे आमित्रत करके, प्रलोभन दे रही थी और उन सारे हथकण्डो

से काम ले रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मस्तिष्क और भीरू-हृदय काबू मे आते है।

यह खिचाव काफी सताने और तपानेवाला था, पर दु खान्त न था। किन्तु जब अकस्मात गोहाटी में यह समाचार पहुचा कि एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द को रोग-शय्या पर उनसे मुलाकात करने के बहाने, गोली मार दी तब यह और भी बढ गया। जिस दिन यह समाचार मिला उस दिन गोहाटी में काग्रेस के सभापित का हाथी पर जलूस निकाला जानेवाला था। आसाम हाथियो का देश ठहरा, इसलिए वह काग्रेस के सभापित का सम्मान अद्भृत और अपूर्व ढग से करना चाहता था। पर जलूस का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमान दोनो में इस दुखद सवाद से शोक छा गया।

जब श्रीनिवास ने अपना भाषण समाप्त किया तब उसमें कोई बात दिखाई न पड़ी। उनके सारे विचार पहले से ही जाने-बूझे थे। उन्होंने निर्वाचनों का जिक्र किया और कहा कि स्वराज्य-पार्टी ने कौसिलों में जिस नीति का अवलम्बन किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है। फिर देशबन्ध की समझौतें की कोशिश, भारत का दर्जा, सेना और जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौसिल के कार्यक्रम की चर्चा की। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समस्याओ, मुद्रा और साम्प्रदायिक झगड़ों और साथ ही खद्दर, अस्पृश्यता और मादक-द्रव्यनिषेध की चर्चा की और सहिष्णुता और एकता पर जोर दिया।

गोहाटी के प्रस्ताव हस्ब मामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने। गांधीजी ने समझाया कि मजहब की असलियत क्या है, और हत्या के कारणों को बताया— "शायद अब आप लोग समझ जायगे कि मैने अब्दुल रशीद को भाई क्यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं ठहराता। दोषी तो असल में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया ह।" केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा था। केनिया में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा था। आरम्भ में कर २० शिलिंग था। फिर वह मुद्राव्यवस्था की उलट-फेर के द्वारा बढाकर ३० शिलिंग कर दिया गया और उसके बाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहा यूरोपियन हितों की रक्षा भारतीय हितों के, उनकी स्वतन्त्रता के और उनकी आकाक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कौसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि—

(१) जवतक सरकार राष्ट्रीय माग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो काग्रेस की या महासमिति की राय में सन्तोषजनक हो, तबतक काग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-द्वारा प्रदान किये जानेवाले और किसी पद को स्वय ग्रहण न करेगे, और अन्य पार्टियो-द्वारा मन्त्रि-मण्डल की रचना का विरोध करेगे।

(२) काग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव पेश करेगे और ऐसे प्रस्तावो और विलो का समर्थन करेगे जो राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी हितो की उन्नति के लिए, और व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा सगठन करने और समाचार पत्रो की आजादी और फलत नौकरशाही को स्थान-च्युत करने के लिए आवश्यक हो।

इस जमाने में काग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में लम्बे-चौंडे प्रस्ताव पास करना और कौसिलों में मुठभेड करते रहना मात्र रह गया था। पर एक वात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में विशेषता धारण कर ली थी। जबसे अखिल-भारतीय चर्छा-सघ बना, खहर, ग्रामोन्नित और मितव्ययिता के पितत्र वातावरण में पन-पने लगा। जिन स्त्री-पुरुषों ने खहर का व्रत ले लिया था वे पृथक् रूप से इसके प्रचार में लगे हुए थे। वार्षिक प्रदिश्तियों के द्वारा सिद्ध हुआ कि कराई ने कितनी उन्नित कर दिखाई है। विहार ने गोहाटी के अवसर पर खहर तैयार करने में अपनी छ सात साल की जो उन्नित दिखाई वह सारे देश के लिए दृष्टात-स्वरूप थी।

: १२ :

साइमन कमीशन का बहिष्कार: १६२७-२८ महासमिति की वैठक

वम्बई की महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-विरोधी परिषद् के प्रक्रपर विचार हुआ। प० जवाहरलाल इस समय यूरोप में थे। उन्होंने परिषद् में भारत का प्रतिनिधित्व किया और ब्रूसेल्स से, जहा परिषद् की बैठक हुई थी, काग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी। महासमिति ने जवाहरलाल की सेवाओं की मुक्तकठ से प्रशसा की और साम्राज्यवाद-विरोधी सघ के प्रयत्ने को भी सराहा। महासमिति ने काग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह सघ को अपनी एक सहायक-सस्था मानकर उसके उद्देश्य तथा कार्यों का समर्थन करे।

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा चीन की आजादी की लडाई के साथ भारतीयों की सहानु-भूति प्रकट की गई और चीन को फौजे भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई, साथ ही फौजों की वापसी की भी माग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को एम्बुलेन्स कोर भेजने का जो इरादा किया था उसकी

महासमिति ने प्रशंसा की । ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बगाल-काग्रेस का झगडा, मजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहि-ष्कार—ये अन्य विषय थे जिन पर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इस समय मई के चौथे सप्ताह में बड़ा आनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाष बाबू छोड दिये गये। लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घबराते रहते थे।

द्ंगों की वाद

सन् १६२७ की गर्मियों में अन्य सालो को भाति कोई मार्के का कानून पास नहीं हुओ, लेकिन देश में हिन्दू-मुस्लिम दगों की बाढ-सी आ गई। सबसे भीषण दगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये तथा २७२ घायल हुए। बिहार, मुलतान, बरेली तथा नागपुर मे भी इसी प्रकार के दगे हुए। लाहार के बाद नागपुर का दगा इन सबमें भीषण था, जिसमे १६ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन दुगो के पहले क्या-क्या घटनाएँ घटी, जो इन दगो में कुछ का कारण बनी, इसके बारे में कुछ कहना आव-श्यक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रंगीला रसूल'। किताब के नाम से पता चलता है कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी। सरकार ने उसके लेखक पर मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो अपील में भी बहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रद कर दी और लेखक को बरी कर दिया। 'रिसाला वर्त्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जि्समे अभियुक्त को सजा हो गई। इन दो मुक-दमो का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १६२७ को एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था ——
"जो कोई व्यक्ति सम्राट् की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर

जान-बूझकर और बुरे इरादे से चोट पहुचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य सकेतो से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओ का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दो साल की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या उस पर सजा व जुर्माना दोनो होगे।"

एकता सम्मेलन

दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभीतक २६ दंगे हो चुके थे जिनमें से १० उत्तर प्रदेश में, ६ बम्बई में और २-२ पंजाब, मध्य-देश, बगाल, विहार तथा दिल्ली में हुए थे। २६ अगस्त सन् १६२७ को भारतीय धारा-सभा में भाषण देते हुए वाइसराय लार्ड इविन ने बताया कि १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गयें और २५०० से अधिक

घायल हुए। वायसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके बाद एक एकता-सम्मेलन भी किया गया, लेकिन उसे कुछ अधिक कामयावी न मिली। महासमिति ने भी २७ अक्तूबर १६२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयगर ने किया। बहुत लम्बी बहस के बाद सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया। सम्मेलन ने उन्ही दिनो के कुछ कातिलाना हमलो की भी निन्दा की और हिन्दू तथा मुसलमान नेताओ से अपील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करे। सम्मेलन ने काग्रेस की महाममिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिन्दूमुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रात में एक-एक किमटी नियुक्त करे।

महासमिति की बैठक

एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २८, २६ व ३० अक्तूबर १६२७ को कलकत्ता में महासमिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर एकता-सम्मेलन के प्रस्ताव ज्यो-के-त्यो पास कर दिये गये। इसके पश्चात् बगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने आया। इन नजरबन्दों में कुछ तो चार-चार साल से जेलों में पड़े हुए थे। इसलिए उनकी शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई कराने का प्रयत्न करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई।

साइमन कमीशन का उद्देश्य

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बाते हुईं। वाइसराय अपने दौरे का कार्यक्रम रद करके दिल्ली वापस आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ४ नवम्बर तथा उसके बाद की तारीखों में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर बगलौर में थे। उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली आ पहुचे। जब वह वाइसराय से मिले तब कोई ऐसी विशेष बात न निकली। लार्ड इविन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री की घोषणा रख दी। जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या बस यही काम है, तो लार्ड इविन ने कहा, "बस, यही।" गांधीजी ने सोचा कि यह सन्देश तो एक आने के लिफाफ के जिरये भी उनके पास पहुच सकता था। पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा भारत में द नवम्बर सन् १६२७ को की गई। वाइसराय उसके प्रति सद्भावनापूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। काग्रेस के सिवा भी भारत की सब पार्टिया साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुईं कि उसमे एक भी भारतीय नहीं रखा गया था। श्री दिनशा वाचा जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कमीशन के विरुद्ध एक

साइमन कमीशन का बहिष्कार : १९२७-५८%

घोषणा-पत्र निकाला। काग्रेस के सिवा भारत के सब राजनीतिक दलो के प्रतिके निधियों ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये।

और आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह धिक्कारा जो रहा श्रम, किस काम के लिए नियुक्त किया गया था ? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम सौपा गया था कि वह ब्रिटिश-भारत के शासन-कार्य की शिक्षा-वृद्धि की, प्राति-निधिक सस्थाओं के विकास की एवं तत्सम्बन्धी विषयों की जाच करें और इस बात की रिपोर्ट पेश करें कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू करना ठीक है या नहीं ? यदि है तो किस दरजे तक ? और अभीतक उत्तरदायी शासन जिस मात्रा में स्थापित किया गया है उसे बढाया जाय, या कम किया जाय या उसमें और किसी प्रकार कोई हेर-फेर किया जाय ? इन प्रश्नों के साथ इस बात की रिपोर्ट भी पेश की जाय कि प्रान्तों में दो-दो कौसिलों का स्थापित करना वाछनीय है या नहीं ?

जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दे और उसपर भारत-सरकार तथा सम्राट् की सरकार विचार कर ले तब सम्राट्-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पार्लमेण्ट के सामने अपने निर्णय पेश करे। लेकिन समाट्-सरकार का पार्लमेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उक्त निर्णयों पर भारत के भिन्न-भिन्न विचारवालों की राये जाहिर न हो जाय उससे पहले ही वह उन निर्णयों को स्वीकृत कर ले। इस-लिए सम्राट्-सरकार ने निश्चय किया है कि वह पार्लमेण्ट से यह कहे कि ये निर्णय विचारार्थ दोनो हाउसों की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) किमटी के सुपुर्द किये जायं और इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय धारा सभाये उक्त किमटी के सामने अपने विचार पेश करने के लिए प्रतिनिधि-मण्डल भेजे जो ज्वाइण्ट किमटी की बैठकों में भाग ले और उनके साथ विचार-विमर्श करे। ज्वाइन्ट-किमटी जिन-जिन सस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने का भी उसे अधिकार हो।

मद्रास-कांग्रेस : १६२७

ऐसे वातवरणों में १६२७ की काग्रेस मद्रास नगर में हुई। कमीशन के सम्बन्ध में काग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पता नहीं था। प्रश्न यह था कि इस अधिवेशन का सभापित कौन हो ? १६२७ में हिन्दू-मुस्लिम दङ्गे हो रहे थे। दो एकता-सम्मेलन हो चुके थे और महासिमिति ने एक सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिये थे। ऐसे वर्ष में काग्रेस का सभापितत्व एक मुसलमान से बढकर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों में भी डॉ॰ असारी से बढकर ? वही मद्रास-काग्रस के सभापित चुने गये। उन्होंने अपने भाषण में साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रश्न को खूब जगह दी। काग्रेस की नीति का सक्षेप में वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि काग्रेस की नीति ३५ साल तक तो

सहयोग की रही, फिर डेंढ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौसिलों में अडगेबाजी करने और कौसिलों का काम ही रोक देने की। "असहयोग असफल सिद्ध नहीं हुआ" डॉ॰ अन्सारी ने कहा, "हम ही असहयोग के लिए विफल सिद्ध हुए। शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सघ, चीन, पासपोटों का न मिलना आदि ऐसे विषय थे जिन पर हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। चूकि स्वराज्य का मसविदा तैयार करने की माग की गई थी और काग्रेस के सामने कई मसविदे पेश थे, अत काग्रेस ने कार्य-सिमिति को अधिकार दिया कि वह अन्य सस्थाओं से मश-विरा करके स्वराज्य का मसविदा तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे। इस कार्य के लिए कार्य-सिमिति को और सदस्य बढाने का भी अधिकार दिया गया। काग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसका प्रारम्भिक अश इस प्रकार था—"चूकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह काग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से बहि- क्कार करे।"

काकोरी-केस के अभियुक्तों को बर्बरतापूर्ण सजाये दी जाने पर और उससे जनता में रोष की प्रबल भावना फैलने पर भी सरकार ने उनकी सजाये न घटाई। उस पर भी एक विशेष प्रस्ताव-द्वारा दु ख प्रकट किया गया और काग्रेस ने उनके

परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की।
अन्त में काग्रेस के घ्यय की भी एक पृथक प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई।
इसके अनुसार यह कहा गया—"यह काग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है।" यह प्रस्ताव कुछ साल तक काग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था। यूरोप से जवाहरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ। स्वय श्रीमती बेसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न की। आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि भारत के लक्ष्य का यह बडा ही शानदार व स्पष्ट वक्तव्य है। गांधीजी उस समय समिति की बैठक में मौजूद नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला जव कि वह पास हो गया।

कमीशन का वहिष्कार

जब १६२८ का साल प्रारम्भ हुआ तब देश कमीशन के वहिष्कार मे जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉर्ड इविन ने कहा था कि भारतीयसम्मानतथा भारतीय गौरव को जान-बूझ कर अपमानित करने का सम्राट्- सरकार का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी थी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतोयों को सहायता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लमेण्ट में पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पार्लमेण्ट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगो, करेगी।

३ फरवरी को कमीशन बम्बई में आकर उतरा। उस दिन भारत-भर में हड़ताल मनाई गई और कमीशन के बहिष्कार का श्रीगणेश कर दिया गया। मद्रास में हाईकोर्ट के पास पुलिस ने भोड़ पर गोली चला दी। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहा-का-तही मर गया और दो बाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की मुठभेड हुई।

कमीशन बम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्लो आया। दिल्लो में कमीशन को "गो बैक, साइमन!" "साइमन वापस लौट जाओ" के झण्डे तथा तस्ते दिखाये गये। दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन (जो आम तौर पर जिस्टस-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था)तथा कुछ मुस्लिम सस्याओं को छोडकर यह कहा जा सकता है कि भारत ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया।

कमीशन के बहिष्कार की इतनो भारो सफलता देखकर सरकार के मन में यह वात आई कि अब आतक तथा दबाव से काम लेना चाहिए। लाहौर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जन-समूह एकत्र हुआ। पुलिस वालों ने भोड़ पर हमला किया और कई प्रतिष्ठित नेताओं को डण्डों और लाठियों से ठोका-पीटा। लालाजी के कई जगह गहरी चोटे आई। यह एक आम ख्याल है कि उनको मृत्यु इस बुजिदलाना हमले के कारण ही हुई थो। यद्यपि लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर यह अभियोग लगाया गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जाच करने से साफ इन्कार कर दिया।

लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशस्त्र तथा शान्त भीड पर
पुलिस ने कई बार जानबूझ कर व अकारण डण्डे बरसाये। उत्तरप्रदेश की
पुलिस ने तो जवाहरलालजी तक को न छोडा। लखनऊ तो पैदल तथा घुडसवार पुलिस के कारण एक विशाल फौजी पडाव-सा ही बन गया। चार दिन
तक पुलिस के बर्वरतापूर्ण हमले होते रहे। पुलिस वाले लोगों के घरों तक में
घुस गये और "साइमन, वापस चले जाओ।" के नारे लगाने पर हो उन्होने
कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह
पीटा। लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिक इन बर्वरता-पूर्ण हमलों से तिनक
भी न घवराए। अधिकारी-वर्ग को तो उन्होने एक बार इतना छकाया कि वह
देखता का-देखता रह गया और सारा शहर हँसी के मारे लोट-पोट हो गया।
मामला इस प्रकार था: कुछ ताल्लुकेदारों ने कैसरवाग में साइमन कमीशन

को एक पार्टी दी। पुलिस ने कैंसरवाग को चारो ओर से घेर लिया। इतनी एहितयात रखने पर भी जब आसमान से सैंकडो काली-काली पतंगे तथा गुव्बारे, जिन पर 'साइमन चले जाओ', 'भारत भारतवासियो के लिए है' आदि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर बाग में गिरने लगे तब सारी पार्टी का मजा किरिकरा हो गया।

जब कमीशन पटना पहुचा तव उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ५० हजार आदिमयों की एक भारी भीड जमा हुई। कमीशन का स्वागत करने के लिए भी कुछ सरकारी चपरासी और मुट्ठीभर सरकारी कमेंचारी मौजूद थे। सरकार ने आस-पास के गावों से लारियों में भर-भर कर किसान बुलवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पों में घुसने के बजाय वे बहिष्कार कैम्पों में जा डटे और स्टेशन पर विराट् जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिंसा-पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा बहिष्कार-पार्टियों के बल को देखकर तो सरकार की आखे ही खुल गई।

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमनने वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने कहा कि कमीशन एक सयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमे एक ओर कमीशन के सातो अग्रेज सदस्य होगे और दूसरी ओर वडी कौं।सल-द्वारा चुने गये सातो भारतीय। सम्मेलन के सब सदस्यों को सब कागजात देखने का अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमे वरावरी के दर्जे पर माने जायगे। प्रान्तीय कौसिलो से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटिया चुनने की सिफारिश करने को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयो पर कमीशन के सामने विचार होगा तब उसके साथ बड़ी कौं।सल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त-सिलेक्ट-किमटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयो पर विचार होगा तव उस प्रान्तीय कौसिल की सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी, जिसका उन विषयो से सम्बन्ध है। कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग ब्रिटिश-सरकार को देगा और सयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्ट अलग वडी कौंसिल को। इस घोषणा का भी भारत पर कुछ असर न हुआ। घोषणा के निकलने के दो-तीन घन्टे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली में एकत्र हुए और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तिया थी वे ज्यो-की-त्यो बनी हुई है और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नही रखना चाहते। असेम्बली ने तो केन्द्रीय सयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूकि कमीशन की सदस्यता तथा उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली को अस्त्रीकार्य है, अतः वह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "कमीशन के साथ भारतीय

उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जब कि उसमें भारतीय भी इतनी ही संख्या में नियुक्त किये जायं।" प्रस्ताव ६२ के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गया। सरकार को लाचार होकर स्वय केन्द्रीय किमटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े। यहा यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब कमीशन बम्बई में घूम रहा था तब 'सर' की पदवी घारण करनेवाले २२ नाइटो में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की। देश में बहिष्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है?

सर्वद्ल सम्मेलन

साइमन कमीशन के भ्रमण के बाद काग्रस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में फरवरी-मार्च १६२८ में सर्वदल-सम्मेलन की बैठक की गई। सम्मेलन में उपस्थित संस्थाएँ और काग्रेस इस बात पर एक मत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या पर 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार मानकर विचार होना चाहिए। दो महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ बैठके हुई और लगभग है समस्याएँ शातिपूर्वक तय हो गई। १६ मई को डा० अन्सारी के सभापितत्व में फिर सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धातों का मसविदा तैयार करने के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक किमटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १६२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश की भिन्न-भिन्न सस्थाओं के पास भेजा जाय। २६ राजनैतिक संस्थाओं ने किमटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी।

वारडोली सत्यापह की बैठक

१६२८ की घटनाओं में बारडोली का सत्याग्रह भी प्रमुख था। बारडोली वह तहसील है जहां गांधीजी 'सामूहिक-सविनय-अवज्ञा' का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो तीन बार इरादा करके उन्होंने फरवरी १६२२ में उसे छोड दिया था। वारडोली में बन्दोबस्त होनेवाला था। बन्दोबस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक परिणाम अवश्य होता है कि मालगुजारी लगभग २५ प्रतिशत बढ जाती है। बारडोली के आदिमयों का कहना था कि उनपर माल गुजारी बढने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन से जो कुछ भी उनकी फसल बढी है या अच्छी है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय खर्च करना पड़ा है। फिर भी बारडोली में सरकार ने २५ प्रतिशत मालगुजारी बढा दी। जाच कराने के सभी उपाय व्यर्थ हो गये। अन्त में चुनौती दे दी गई और करवन्दी आन्दोलन शुरू हो गया। काग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिषद् में कर लिया था और सरदार वल्लभभाई पटेल को आमन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व

करे। ऐसी हालत में सरदार पटेल ने आन्दोलन को सगठित किया। सरकार ने जानवरों की कुर्की कराना शुरू किया। लोगों ने कुर्किया होने के मार्ग में कोई रकावट नहीं डाली। इसके बाद जल्द ही, बम्बई-कौसिल के कुछ निर्वाचित सदस्यों ने विरोध में कौसिल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लगे। असेम्बली के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने इस बात को घमकी दी कि यदि सरकार न झुकेगो तो वह इस्तोफा देकर इस काम में जुट जायगे। आखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढाई गई मालगुजारी जमा कर दो, कैंदियो की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद का लौटाया जाना तय हो गया और आन्दोलन वापस लेने का निश्चय हुआ। सरकार ने एक अदालत विठा दो, जिसमे न्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि थे। अदालत ने मामले की जाच की और यह निश्चय किया कि मालगुजारी केवल ६ प्रैत-शत बढाई जाय। वास्तव मे देखा जाय तो न तो कानून में ही और न मालगुजारी के नियमों में ही ऐसा कोई विधान था कि कोई अदालते जाच के लिए बिठाई जाय। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि अदालत ने यह सिफारिश की थी कि केवल ६ र्रे मालगुजारी बढाई जाय, तो भी वास्तव मे बारडोली तहसील में मालगुजारी बिलकुल बढ़ी ही नही और फैसले के बाद भी अपनी पहली हद तक ही रही। समझौते की वास्तिविक सफलता तो इस बात मे थी कि मालिको को बेवी हुई जमीने और पटेल तथा तलाटियो को अपनी जगहे फिर मिल गई।

सर्वद्त सम्मेलन की बैठक

नेहरू-किमटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठके लखनऊ में २८, २६ तया ३० अगस्त १६२८ को हुई। नेहरू-किमटी को उसके परिश्रम के लिए वधाई दी गई। सम्मेलन ने उसे औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलो को अपने विचारो के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई, जिनका घ्येय 'पूर्ण स्वतन्त्रता' था। उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढकर सुनाया, जिसमें बात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्त्रता दी गई थी, खूब फायदा उठाएँ। इसलिए जहा उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया, वहा उन्होंने सम्मेलन के कार्य में कोई वाधा न डाली। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए वे न तो उस पर होनेवाली वहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई सशोधन पेश करेंगे। सम्मेलन में जिन अन्य विषयों पर विचार

हुआ वे सिन्ध, प्रान्तो का बटवारा तथा सयुक्त-निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे। सम्मेलन को रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्लो मे ४ तथा ५ नवम्बर को विचार किया। महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के घ्येय को दोहराया, नेहरू-कमिटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वोकार किया और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने मे सहायक है उन्हें आमतौर पर स्वीकार किया।

कलकत्ता-कांग्रे सः १६२८

कलकत्ता-काग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनो में एक बड़े महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे काग्रेस का भावो मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्त्व के कारण पिडत मोतीलाल नेहरू उसके सभापित चुने गये। इसके साथ सर्वदल-सम्मेलन भी लागू हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था और जिस समय काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पिडतजी ने अपने अभिभाषण में बताया कि कमीशन का देश में, कितने जोर के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एग्लो-इण्डियनो के दिमाग पर क्या असर किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य स्वाधोनता है, जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस पिरिस्थित में हमें प्राप्त होती है। आगे पंडितजी ने इस बात पर जोर दिया कि "सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुच गया है वहीं से सरकार को उसका कार्य शुरू कर देना चाहिए और जहा तक हम जा सके वहाँ तक उसे हमारा साथ देना चाहिए।"

कलकत्ता-काग्रेस की एक भारी विशेषता यह थी कि विदेशो से व्यक्तियों तथा संस्थाओं को सहानुभूति के सैकडो सन्देश प्राप्त हुए जिनमें न्यूयार्क से श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सनयात सेन, मोशिये रोम्या रोला और फारस के समाजनवादी दल तथा न्यूजीलैंड के कम्यूनिस्ट दल प्रमुख थे। विदेशों से आये सन्देशों तथा बयाइयों के उत्तर में विदेशों मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश तथा बथाइया दी गई और महासमिति को आदेश दिया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करें। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वावीनता प्राप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन तथा ईराक के स्वातन्त्रय-युद्ध के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साम्राज्य-विरोधी-सघ के दितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया गया। ब्रिटिश माल के विह्या के आदोलन पर भी जोर दिया गया। बारडोलों की शानदार विजय पर सरदार वल्लभभाई पटेल को बधाई दी गई। सरकारी उत्सवो, दरबारों तथा

सरकारी अधिकारियो-द्वारा आयोजित अथवा उनके सम्मान में किये जाने वाले अन्य सब सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवी में भाग लेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव द्वारा माग की गई। सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हआ था वह इस प्रकार था --

"सर्व-दल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट मे शासन-विधान की जो तजबीज पेश की गई है उसपर विचार करके काग्रेस उसका स्वागत करती है और उसे भारत की राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक समस्याओ को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती है। साथ ही सब सिफारिशो को प्राय सर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बघाई देती है। यद्यपि यह काग्रेस मद्रास-काग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक वडा पग मानकर उसे मजुर करती है।

"अगर ब्रिटिश-पार्लमेण्ट इस विधान को ज्यो-का-त्यो ३१ सितम्बर १६२६ तक या उसके पहले स्वीकार करले तो यह काग्रेस इस विधान को अपना लेगी, बशर्ते कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक पार्लमेण्ट उसे मजूर न करे या इसके पहले ही उसे नामजूर कर दे ती काग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करो का देना वन्द कर देगी और उन अन्य तरीको-द्वारा, जिनका बाद में निश्चय हो, अहिसात्मक असहयोग का आन्दोलन सगठित करेगी।"

कलकता-काग्रस ने अपना अगला कार्य-क्रम भी निर्धारित किया जिसकी मस्य बाते इस प्रकार थी --

- (१) सब नशीली चीजो का व्यवहार बन्द कराने के लिए कौसिलो के भीतर और बाहर देश में हर तरह से कोशिश की जायगी।
- (२) हाथ की कती और बुनी खादी की उत्पत्ति बढाकर तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायगे।
- (३) जहा कही लोगो को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हो तो उस शिकायत को दूर कराने के लिए अहिंसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जायगा ।
- (४) काग्रेस की ओर से कौसिलो के लिए जो सदस्य जायगे उन्हें अपना अधिक समय काग्रेस-कमिटी-द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्य कम में लगाना होगा।

(५) प्रत्येक हिन्दू-काग्रेसवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक

कुरीतियो तथा अस्पृश्यता को दूर करने के लिए पूरी चेष्टा करेगा और अछूत कहें जाने वालों को उनकी अयोग्यताएँ दूर करने में यथासंभव सहायता देगा।

कलकत्ता-काग्रेस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरी-द्वारा किया गया प्रदर्शन सदा स्मरण रहेगा। आस-पास के मिल-क्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुव्यव-स्थित रूप से एक जलूस बना कर काग्रेस-नगर में घुस आये और राष्ट्रीय-झण्डे की सलामी करके पंडाल में आकर दो घण्टे तक अपनी सभा करते रहे। इसके पश्चात भारत के लिए स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास करके वे पंडाल छोड़कर चले गये।

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी। देश में जगह-जगह युवक-सघ तथा छात्र-सघ बन गये। बम्बई और बगाल में तो उनका बड़ा जोर था। युवको ने साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहि-ष्कार-प्रदर्शनो में भी खूब भाग लिया था। लखनऊ में पुलिस की लाठियो और डडो की मार तो खास तौर पर उन्होंने ही खाई थी।

गांधीजी की श्रोर

अब हमें पाठकों को संक्षेप में यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता काग्रेस में कैसे आ फंसे। याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद काग्रेस के बाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए वह १९२२ की गया-काग्रेस, सितम्बर १९२३ के दिल्ली के विशेष अधिवेशन और १९२३ के कोकनडा के वार्षिक अधिवेशन मे उपस्थित न हो सके थे। ५ फरवरी १६२४ को वह छूटे और बेलगाव-काग्रेस के सभापति बने। कानपुर-काग्रेस में स्वराज्य-पार्टी से साझे-दारी के मामले में पटना के निर्णयो पर काग्रेस की छाप लगवाने के लिए ही वह आये थे। इसके बाद उन्होने राजनीति मे चुप्पी साधने की एक साल की शपथ ले ली और गोहाटी में उसे पूरा कर दिया। गोहाटी में उन्होने काग्रेस के बहस-मुबाहसो में सिकय-भाग लिया, लेकिन मद्रास में तो वह बिलकुल उदासीन रहे। यह बात सन्देहजनक ही थी कि वह कलकत्ता-काग्रेस के अधिविशेनो में भाग लेंगे या नहीं। कुछ वर्षों से वह काग्रेस के सालाना अधिवेशनों के पहले एक मास वर्धा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब काग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते मे दिसम्बर १६२८ में होने वाला था, वह वर्घा मे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जिन्हे स्वागतार्थ ३६ घोडो की गाड़ी में बिठाकर शहर में जलूस में निकाला गया था, अपने आपको बडी विकट परिस्थिति मेपाने लगे। लखनऊ-सर्वदल-सम्मेलन मे जिन विरोधियो ने सभापति के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर करके औपनिवेशिक स्वराज्य के विरोध में और स्वतन्त्रता के पक्ष में घोषणा की थी, वे भी वहा मौजूद थे और उन्होने अपना स्वाधीनता-संघ भी बना लिया था। इनमे जवाहरलाल भी शामिल

थे। बगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और श्री सुभाषचन्द्र वसु उसके मुखिया थे।

सर्वदल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना उचित होगा। सम्मेलन बुरी तरह असफल हुआ। मुसलमानो के अतिरिक्त अन्य अल्प-संख्यक जातियो ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को धिक्कारा। उधर श्री जिन्ना भी, जो अभी इंग्लैंण्ड से वापस आये थे और जिन्होने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे। कुछ मुसलमान पहले ही उसकी मुखालफत जाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री जिन्ना ने लीग की बैठक स्थगित कर दी। ऐसी दशा में कलकत्ते में सर्वदल-सम्मेलन मृत्यु-शय्या पर पहुच चुका था। अत उसे स्वर्ग मे पहुँचाने की आवश्यकता थी। गाँघी-जी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुचा सकता था? अत उन्होने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पास हो गया। अब काग्रेस निश्चित रूप से गाधीजी की ओर झुक रही थी, लेकिन वह अपने खुद के कई बोझो से लदी हुई थी। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हामियो पर मुकदमे चलने की अफवाहें, वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण भाषण, "फारवर्ड" के सम्पादक को सजा होना, मद्रास में मुकदमो का दौर-दौरा-एसी घटनाये थी जिन्होने गाधीजी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला। वह कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक बेचैन थे। इन बातो के अलावा गाधीजी के पास यूरोप आने का भी निमत्रण था। लेकिन अच्छी तरह विचार करके और मित्रो से परामर्श करने के बाद गाधी जी इस नतीजे पर पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हे अपना दौरा स्थिगित रखना चाहिए। यह फरवरी १६२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें अब देखना है कि फरवरी १६३० के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या बदा था।

: १३:

कांग्रेस का उग्र रूप: १६२६-३० मज़दूर-दल की विजय

१६२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति वस्तुत बडी विकट थी। इस समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेण्ट्रल किमटी भी देश में दौरा कर रही थी। इस किमटी में चार सदस्य तो राज्य-परिषद् से चुने गये थे और पाच सरकार ने असेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन कमीशन ने भी १४ अप्रैल १६२६ को अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया था। कमीशनवाले विलायत में पहुंचे ही थे कि मई १६२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर-दल का मन्त्रिमण्डल बना। मैंकडानाल्ड प्रधानमंत्री बने और वेजवुड बने भारत-मत्री। लार्ड अविन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुचे। इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि साइमन-कमीशन के परणाम-स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-योजना पार्लमेण्ट के समक्ष रखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थित स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलो का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

उपसमितियों का कार्य

काग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-सिमिति ने अनेक उप-सिमितिया बनाईं। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्रध्यों के निषेध, अस्पृश्यता-निवारण, महासभा के संगठन तथा स्वयसेवको और स्त्रियों की बाधाओं को दूर करने के लिए किमिटिया नियुक्त की गई। इघर यह हो रहा था, उघर काग्रेस अपने निश्चयों के अनुसार रचनात्मक कार्यों में लगी थी। विदेशो-वस्त्र-बहिष्कार सिमिति के अध्यक्ष थे गाधीजी और मंत्री थे श्री जय-

विदेशो-वस्त्र-बहिष्कार समिति के अध्यक्ष थे गाधीजी और मंत्री थे श्री जयरामदास दौलतराम। यह समिति वर्ष-भर काम करती रही। बहिष्कार के काम
में अपना सारा समय लगाने के लिए श्री जयरामदास ने बम्बई-कौसिल का सदस्यपद छोड दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादकद्रव्य-निषेय-समिति का काम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ में था। उन्होंने
इस कार्य को अपना खास विषय बना लिया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण भारत
और गुजरात में हुआ। सफलता भी अच्छी मिली। इस आन्दोलन की ओर विदेशों
तक का घ्यान आकृष्ट हुआ। नशे के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के
लिए मद्रास-सरकार चार लाख रुपया खर्च करने के लिए राजी हो गई। उत्तर प्रदेश
की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई की आशा हुई। श्री राजगोपालाचार्य
भारतीय-मद्यपान-निषध-सघ के मंत्री हुए और उसके अंग्रेजी त्रैमासिक मुख-पत्र
'प्रॉहीबिशन' का सम्पादन करते रहे। अस्पृश्यता-निवारण-आदोलन का काम
श्री जमनालाल बजाज के सुपुर्द किया गया। उन्होने भी काफी परिश्रम किया।
जो लोग दीर्घकाल से दिलत रखे गये थे उनकी बाधाये दूर करने के लिए सर्वत्र
लोकमत जाग्रत किया गया। जहा दिलत जातियो को मनाही थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध
मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। सिमिति को बहुत से कुएँ और पाठशालाये भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्युनिसिपैलिटियों ने इस काम में
सहयोग दिया। श्री जमनालाल बजाज ने मद्रास, मध्यप्रांत, राजस्थान.

पजाब और सीमाप्रान्त में लम्बे प्रवास किये। काग्रेस के पुनस्सगठन के लिए जो सिमिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपीर्ट पेश कर दी।

गाधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। वहा विदेशो कपडे की होली जलाई गई। इस सम्वन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होने आज्ञा-भग की है या आज्ञा-भग में सहायता दी है। आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानो पर घास-फूस आदि न जलाया जाय। गाधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। इसके बाद उन्होने आन्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ मास में खद्दर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये जमा किये।

इन कार्यों के अतिरिक्त कार्य-समिति ने १० पौण्ड मासिक की रकम इस-लिए मजूर की कि बिलन में भारतीय छात्रों को सलाह और सहायता देने वाली एक समिति स्थापित की जाय। थोड़े समय पश्चात् यह सिमिति श्री० ए० सी० ए 10 निम्बयर की देख-रेख में कायम हुई। इससे बहुसख्यक भारतीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णत सिद्ध हो गई। श्री शिवप्रसाद गुप्त ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस सिमिति का निरीक्षण किया और इसके कार्य की भूरि भूरि प्रशासा की। उनकी सिफारिश पर कार्य-सिमिति ने एक वाचनालय के निमित्त सहायता में दो पौण्ड मासिक की वृद्धि कर दी। यह सस्या अच्छे ढग से चली। इसकी रिपोर्ट प्रति मास आती रही।

कलकत्ता-काग्रेस ने महासमिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य-समिति ने इस मामले मे आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान-मन्त्री को दे दिया। वह स्वयं इस विभाग की देख-भाल रखने लगे। उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया।

महासमिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप मे ही मजदूरो-सम्बन्धो प्रश्न के लिए एक अनुसधान-विभाग भी खोला गया। हिन्दुस्तानी सेवादल ने स्वयसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागो में किया। अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ। वहीं दल का दफ्तर और व्यायाम-मिन्दर भी था। काग्रेस के सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बहिष्कार के काम में दल ने वड़ी मदद दी। मासिक झण्डाभिवादन के कार्यक्रम का सगठन करने में हिन्दु-स्तानी-सेवा-दल को आशातीत सफलता मिली। बहुत-सी म्युनिसिपैलिटियो ने भी अपनी इमारतो पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झण्डे लगाये। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल की पुनर्रचना की गई। थोडे दिनो बाद मई १६२६ में महासमिति की बम्बई में बैठक हुई।

वम्बई में महासमिति की वैठक

वम्बई की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। सरकार घोष्रणा कर चुकी थी कि असेम्बली का कार्य-काल बढ़ाया जायगा। इस वात पर भी काग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत थी। इवर देश-भर में गिरफ्तारियों का ताता वय गया था। कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्बमूर्ति पकड़ लिये गये थे और पजाव में घोर दमन- चक्र चल रहा था। इससे यह सन्देह होता था कि शायद और वातों के साथ-साथ इसका उद्देश्य लाहीर के काग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में वाधा डालना भी हो। इन सब कारणो से प्रत्येक प्रात में काग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। अतः वरवई मे यह तय हुआ कि प्रातीय-काग्रेस-कमेटियो मे प्रात की समस्त जनसंख्या के 🐉 फोसदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिए और प्रातीय-कमिटी में कम-से-कम आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिला और तहसील कमिटी में आवादी से कम-से-कम है फीसदी चार आनेवाले सदस्य होने चाहिए और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फीसदी। कार्य-समिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशो का पालन न करे उसका सम्बन्ध-विच्छेद किया जाय। कार्य-सिमति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के हित के लिए वह जो उपाय उचित समझे उसका पालन असेम्बली और प्रातीय-कांसिलो के काग्रेस-सदस्यो से भी करा ले। धारा-सभाओं में काग्रेसी दल के वारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि वंगाल और आसाम के सिवा वडी अयवा जन्य प्रातीय कौसिलो के सारे काग्रेसी सदस्य इन कौसिलो की भी वैठक मे अयवा उनके द्वारा अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक मे नवत्क शामिल न हो जवतक कि महासमिति अथवा कार्य-समिति दूसरा निर्णय न करे। यह भी निश्चय हुआ कि काग्रेमी सदस्य अब से अपना सारा समय काग्स के कार्यकम को पूरा करने में ही लगाये। मेरठ के अभियुक्तों के सहायतार्थ भी १५००) मजुर हए।

सभापति का चुनाव

भविष्य के गर्भ में बड़ी-वड़ी घटनाये छिपी थी। अन्य अधिवेरानों की भाति तहींर-काग्रेम के लिए भी सभापित की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गांधीजी के लिए पाच ने भी बल्लभ भाई पटेल के लिए और तीन ने पण्टित जवाहरनाल रेट्ट के लिए राप दी। गांधीजी वा चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया, परन्तु पर्दोंने त्याग-पत्र दे दिया। अत. २६ सितम्बर १६२६ को लयनऊ में महानमिति की बेटा हुई। मदकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। अत उन पर फिर जोर

डाला गया। परन्तु उनकी दूर्दिशता ने काग्रेस की गही पर ऐसे किसी युवक को ही विठाने की सलाह दी जिस पर देश के युवक-हृदयों की श्रद्धा हो। गांधी जी ने इसके लिए युवक जवाहरलाल को सभापित वनाना उचित समझा। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से प० जवाहरलाल को चुन लिया।

लार्ड ऋविंन की घोषणा

अक्तूवर का महीना घटनापूर्ण था। लॉर्ड अर्विन विलायत जाकर २५ अक्तूवर को लौट आये थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने पहलो नवम्बर को दिल्लो में कार्य-समिति की जरूरी बैठक बुलाई। समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजधानी में अन्य दलों के नेता भी उक्त घाषणा को सुनने और उस पर सम्मिलित कार्रवाई करने के लिए मौजूद थे। जून १६२६ के अन्त में इग्लैण्ड को रवाना होते समय लॉर्ड अर्विन ने कहा था, "विलायत पहुचकर मैं ब्रिटिश-सरकार से इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने के लिए अवसर ढूढूगा। जैसा में अन्यत्र कह चुका हूँ, जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि है उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियों को ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख रखना मेरा कर्तव्य होगा।" इसके वाद उन्होंने अगस्त १६१७ की घोषणा और सम्राट्-द्वारा दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र का हवाला दिया। इस आदेश-पत्र में सम्राट् ने कहा था— "हमारी सर्वोदिश-भारत को कमश उत्तरदायों शासन-प्राप्त के लिए पार्लमेण्ट ने जो योजना वनाई है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशों में ब्रिटिश-भारत को भी अपने योग्य स्थान मिले।"

लॉर्ड अविन ने अपनी ३१ अक्तूबर की घोषणा के अन्त में कहा कि ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।

घोषणा का प्रभाव

यह घोषणा हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घण्टे के भीतर पण्डित मालवीय, सर तेजबहादुर सप्रू और डॉ॰ बेसेण्ट आदि बड़े बड़े लोग दिल्ली आ पहुँचे। काग्रेस की कार्य-सिमिति तो वहा थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात इस सिम्मिलित सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया। इस वक्तव्य में कहा गया कि "हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल औपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक सस्थाओं में विश्वास उत्पन्न करने

और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यों का किया जाना और कुछ का साफ होना जरूरी है।

प्रस्तावित परिषद् की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि-

- (क) वातावरण को अधिक शान्त करने के लिए समझौते की नीति अख्ति-यार की जाय।
 - (ख) राजनैतिक कैदी छोड दिये जायं।

(ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओ को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबसे बडी सस्था होने के कारण काग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जायं।

(घ) औपनिवेशिक दर्जे के सम्बन्ध में वाइसराय की घोषणा में सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या है, इस विषय में लोगो ने सन्देह प्रकट किया है। हमारी सम्मित में जनता को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि आज ही से नवीन युग आरम्भ हो गया है झौर नया विधान इस भावना पर केवल मुहर लगायेगा।

निस्संदेह इस नये रवैये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टि-कोण था। इस वीच में अग्रेज मित्र तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर डाल रहे थे कि वह भारत की सहायता करने के प्रयत्न में मजदूर-सरकार का साथ दे।

गांधीजी का उत्तर

उत्तर में गांधीजी ने कहा, "मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ। इसी हेतु से पहला माँका आते ही मैंने हाथ आगे वढ़ा दिया है। परन्तु जैसे मैं कलकत्ता-काग्रेस के प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द पर कायम हू, वैसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के प्रत्येक शब्द पर भी अटल हूं। इन दानों में कोई विरोध नहीं है। किसी भी दस्तावेज के शब्दों में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी भावना की रक्षा हो जाय। यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए में ठहरा भी रह सकता हूँ। अर्थात् आवश्यकता इस वात की हे कि हृदय-परिवर्तन सच्चा हो, अंग्रेज भारतवर्ष को एक स्वतत्र और स्वाभिमानों राष्ट्र के रूप में वस्तुत. देखें और भारत में अधिकारी मण्डल की भावना सेयापूर्ण हो जाय। इसका अर्थ हैं सगोनों के वजाय जनता के सद्भाव की स्थापना। वया अग्रेज स्त्री-पुरुष अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलों और तोप-पत्त्रकों के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं यदि उनकी यह तैयारी अभी नहीं है, तो मुझे कोई औरनिवेशिक स्वराज्य सतुष्ट नहीं कर स्वता। अगिनवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह हैं कि यदि में चाहूँ तो आज ही दिदिश-सम्बन्ध विच्छेद कर सकू। ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय पर ने में जवरदस्ती-जैसी कोई वात नहीं चल सकती।"

सर्वदल सम्मेलन

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही कार्य-समिति की बैठक हुई। ऐक्य-भाव बनाए रखने के सब प्रयत्न किए गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पिडत जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड दिया। पिडत मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी वढकर थे। उन्हें कामन-सभा की छल-कपट-पूर्ण कार्रवाई और कैंप्टिन बेन के दुमुहेपन पर बडा कोंध आ रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मिन्त्र-मण्डल जो चित्र खीच रहा था वह ऐसा था कि भारतवासियों को उसमें स्वराज्य दीखे और वियालतवालों को ब्रिटिश-राज्य।

नेतात्रा से भेंट

इयर 'पायोनियर' के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार पत्रो मे चिट्ठी-पर-चिट्ठिया छपवा रहे थे और लॉर्ड अविन पर जोर डाल रहे थे कि लाहाँ र काग्रेंस से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिये जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहौर न पहुँचना पडें। लॉर्ड अविन, डॉ॰ सप्रू के मार्फत, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी लखनऊ मे अपने वकालत के काम से मुक्त न हो सके। विलसन साहव ने अखबारो में लिखा कि वाइसराय गाधीजी, पडित मोतीलालजी और मालवीयजी से शीघ्र ही मुलाकात करनेवाले है। इधर वाइसराय साहब १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होने डॉ॰ सप्रू को लिखा कि अगर पहले हैदराबाद (दक्षिण) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिल्ली में गाधीजी और नेहरूजी से मुलाकात होगी। लॉर्ड अविन समय पर, अर्थात् २३ दिसम्बर को, दिल्ली लौट आये। उसी दिन नई दिल्ली से १ मील दूर पुराने किले के स्थान पर उनकी गाडी के नीचे वम फटा। लार्ड अविन तो बाल-वाल वच गये, परन्तु उनकी खाने की गाडी को नुकसान पहुचा और उनका एक नौकर घायल हुआ। उसी दिन गांधीजी और मोतीलाल जी काग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिले। दूसरे विचार वालो की बात कहनेवालो में श्री जिन्ना, सप्नू और विट्ठलभाई पटेल थे। लार्ड अविन ने हसते-हसते बात-चीत की। उनके दिल पर प्रात कालीन दुर्घटना का कोई असर न था। पौन घण्टे तक तो बम की घटना और उसके परिणामो पर ही चर्चा होती रही। फिर लॉर्ड अविन ने प्रस्तुत विषय को हाथ में लिया। उन्हें राज-नैतिक कैदियों से अच्छी शुरुआत करनी थीं, परन्तु गाधीजी तो वाइसराय से औप-

निवेशिक स्वराज्य के मामले पर निपट लेना चाहते थे। वह यह आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिषद् की कार्रवाई पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को आघार मानकर होगी। वाइसराय साहव ने उत्तर दिया, "सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये हैं। इससे आगे मैं कोई वचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नहीं हैं कि औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वादा करके गोलमेज परिषद् में आप लोगों को बुला सकू।"

लाहौर-कांग्रेस : १६२६

उत्तर-भारत के निर्दय हेमन्त में लाहाँर का काग्रेस अधिवेशन अन्तिम था। तम्बुओं में रहना प्रतिनिधियों के लिए वड़ा कष्टप्रद सिद्ध हुआ। परन्तु भीतर भावना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से समझाता न होने पर रोप था और युद्ध के बाजे सुन-सुनकर लोगों की वाहे फड़क रही थी। पंडित जवाहर-लाल नेहरू जितने कम उम्र के थे उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय नेता थे। उनका अभिभाषण क्या था, मानो उन्होंने अपने हृदय को उड़ेलकर देशवासियों के सामने रख दिया था। उसमे भारत के अपमान पर कोब भरा था। उसमें उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने की अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदर्शों और सफल होने के अपने दृढ निश्चय को व्यक्त किया था।

पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिभाषण में वताया कि वाइसराय की घोषणा दोखने में समझीते का प्रस्ताव है। वाइसराय का इरादा नेक और उनकी भापा मेल-मिलाप की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन मीठी-मीठी वातो से कोई अतर नहीं पडता। हम अपनी ओर से कोई पीर राप्ट्रीय सग्राम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समझौते का द्वार अभी खुला है। परन्तु कैंप्टिन वेजवुड वेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम है। हमारे सामने एण ही घ्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। इसके पश्चात् उन्होंने अल्प-सर्यक जातियों, देशी राज्यों और किसानी तथा मजदूरी के तीन बड़े प्रश्नों को लिया। फिर उन्होने अहिंसा के प्रत्न का विवेचन किया और कहा कि— हिंसा के परिणाम बहुधा विपरीत और अष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देत में तो इससे सत्यानाश हो सकता है। मैं नमझता हू, हममें ने अधिक लोग नैतिज दृष्टि से नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं। यदि हमने हिसा में मार्ग का परित्यान किया है तो इसलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निक-लता नहीं दिलाई देता। स्वतंत्रना के किसी भी आंदोलन में जनता का गामिल हैना जरूरी है और पनता के आदोलन तो शात ही हो नवते हैं। हा, मगठिन विदेश की बात अनग है। अत में उन्होंने कहा कि यह कोई नहीं कह रायता कि

सफलता कब और कितनी मिलेगी। सफलता हमारे कावू की चीज नही है, परन्तु विजय का सेहरा प्राय उन्हीं के सिर बँधता है जो साहस करके कार्य-क्षेत्र में बढते हैं। जो सदा परिणाम से भयभीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग में सफलता क्विचत् ही होती हैं। इन विचारों से भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवा-हरलाल नेहरू दोनों सहमत थे। इस कारण लाहौर-काग्रेस का कार्य-संचालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री यतीन्द्रदास और श्री फुङ्गी विजय के महान् आत्मोत्सर्ग की प्रशसा की गई और पिडत गोंकर्णनाथ मिश्र, प्रोफेसर पराञ्जपे, श्री भक्तवत्सल नायड् आदि के देहावसान पर शोंक प्रदिशत करने के बाद वम-दुर्घटना पर एक प्रस्ताव पास हुआ।

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-स्वाधीनता के सम्वन्ध में था, जो इस प्रकार

"औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूवर को वाइसराय ने जो घोषणा की थी और जिसपर काग्रेस एव अन्य दलो के नेताओ ने सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का यह काग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आदोलन को निपटाने के लिए वाइस-राय की कोशिशों की कद्र करती है, किन्तु उसके बाद जो घटनाये हुई है और वाइसराय के साथ महात्मा गाधी, पडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेताओ की मुलाकात का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने पर काग्रेस की यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परिषद् में काग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गत वर्ष कलकत्ते के अधिवेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनु-सार यह काग्रेस घोषणा करती है कि काग्रेम-विधान की पहली कलम में 'स्वराज्य' शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। काग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट में वर्णित सारी योजना को समाप्त समझा जाय। काग्रेस आशा करती है कि अब समस्त काग्रेसवादो अपना सारा घ्यान भारतवर्ष की पूर्ण स्वा-धीनता को प्राप्त करने में ही लगायेगे। चूिक स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना और काग्रेस की नीति को उसके नये ध्येय के अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाना आवश्यक है, इसलिए यह काग्रेस निश्चय करती है कि कार्गसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाले दूसरे लोग भावी निर्वाचनो में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग न ले और कौसिलो और कमिटियो के वर्तमान काग्रेसी सदस्यो को त्याग-पत्र देने की आज्ञा देती हैं। यह काग्रेस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है और महासमिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहा चाहे, आवश्यक प्रतिवन्धो के साथ सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्य-क्रम आरम्भ कर दे।"

दूसरी वात इस काग्रेस ने यह की कि वार्षिक अधिवेशन का समय दिसम्बर से वदलकर फरवरी अथवा मार्च कर दिया।

काग्रेस ने इन प्रस्तावों के परिणाम-स्वरूप विघान में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार कार्य-समिति को दे दिया। सदा की भाति पूर्व-अफीका पर भी प्रस्ताव हुआ। देशो-राज्यों का विषय महत्वपूर्ण था ही। काग्रेस ने सोचा, अब समय आ गया है कि भारतीय नरेंग अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्ति की रक्षा के नागरिक हकों के बारे में घोषणायें करें और कानून बनाएँ।

नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा। इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना आवश्यक समझा गया। काग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि स्वाधीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रवनों का निपटारा सर्वथा राप्ट्रोय ढग से ही होगा। परन्तु चूकि सिक्खों ने विशेषत. और मुसलमानो और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणत नेहरू-रिपोर्ट के प्रस्तावा पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए काग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी भावी-विधान में काग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पक्षों को पूर्ण सन्तोप न हो। कलकत्ता-काग्रेस के बाद जो भिन्न-भिन्न समितिया फरवरी १६२६ में बनी थी जनका काम विशेषज्ञों को सीपा गया। स्वयंसेवकों का सगठन जवाहरलालजी और सुभाष बाबू के हवाले किया गया। काग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में वाटा ऑर कार्य-समिति के अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्द किया गया। कलकत्ते में राप्ट्रीय माग को स्वीकार करने के लिये सरकार को वारह मास का समय दिया गया था। तद-नुनार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय पूर्ण स्वतत्रता के प्रस्ताव के रायों की गिनती खतम हुई। उस समय सारी काग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झड़ा फहराया।

कार्य-समिति की वैठक

प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ। नई कार्य-समिनि की देठन २ जनवरी १६३० को हुई। पहला काम उसने की सिल-छहिष्कार के निश्चय पर जनन करवाने का किया। इसके लिए उसने मत-दाताओं में अनुरोध किया कि जो नदन्य जाग्रेस की अपील पर द्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इन्नी का दें जिन्न को अपील पर द्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इन्नी का दें जीर नये चनाव में शामित न हो। उसके परिणाम-स्वरूप अमेन्द्रनी के २७ परचों ने र्नीका दें दिया। दूसरा निष्चय कार्य-समिति ने देश-भर में पूर्य-स्वराज्य- जिन्छ ननाने या जिया और इसके लिए २६ जनवरी १६३० का दिन निजन हुआ। देर-भर के जनर-नगर और गाव-गांव में एक भोगणा-पत्र नैयार करने जनता के

सम्मुख पढकर सुनाना और उस पर हाथ उठवाकर श्रोताओ की सम्मति लेना तय हुआ। उस दिन सुनाया जानेवाला घोषणा-पत्र सक्षेप मे यह था —

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

"हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रो की भाति अपना जन्म-सिद्ध अधि-कार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहे, अपने परिश्रम का फल हम स्वय भोगे और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाये प्राप्त हो जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। अग्रेजी सरकार ने भारतवासियो की स्वतत्रता का ही अप-हरण नहीं किया है बल्कि उसका आधार भी गरीवों के रक्तशोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है। अत हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अग्रेजो से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

"भारत को आर्थिक बरबादी हो चुकी है। हाथ-कताई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये है। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान वेकार रहते है। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढग से निश्चित की गई है जिससे देश का करोड़ो रुपया बाहर चला जाता है। राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अग्रेजो के जमाने में घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ मे वास्तविक राजनैतिक सत्ता नही आई है। संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड ही काट दी है और हमें जो तालीम दी जाती हैं उससे हम अपनी गुलामी की जजीरों को ही प्यार करने लगे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नामर्द बना दिया गया हैं। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती हैं। उसने हमारी मुकाबले की भावना को बड़ी बुरी तरह कुचल दिया है। उसने हमारे दिल में यह बात बिठा दी हैं कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथा सम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तयारी करेगे और सविनय-अवज्ञा एव करबन्दी तक के साज सजायेगे। हमारा दृढ विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी-राज्य का नाश निश्चित है। अत हम शपथ-पूर्वक सकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु काग्रेस समय-समय पर जो आज्ञाये देगी उनका हम पालन करते रहेगे।"

गांधीजी की ग्यारह शर्तें

स्वाधीनता-दिवस जिस ढग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि स्वदेश-भिक्त और आत्म-विलदान के अगारे राज-भिक्त या कानून और व्यवस्था की

गुलामी की राख से केवल ढके हुए थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के लाल अगारो पर जमी हुई राख को फूक मार कर हटा दिया जाय। स्वाधीनता- दिवस का समारोह खत्म ही हुआ था कि २५ जनवरी को असेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण भी प्रकाशित हो गया। इसने भारत के आशावादी और विश्वासशील राजनीतिज्ञों की रही-सही आशाओं पर पानी फेर दिया। आगे चलकर गाधीजी ने 'यग इंडिया' में लॉर्ड अविन के सामने नीचे लिखी शतें रक्खी—

- (१) सम्पूर्ण मिदरा-निषेध।
- (२) विनिमय की दर घटा कर एक शिलिग चार पेस रख दी जाय।
- (३) जमीन का लगान आधा कर दिया जाय और उस पर कौसिलो का नियन्त्रण रहे।
 - (४) नमक-कर उठा दिया जाय।
- (५) सैनिक-व्यय मे आरम्भ मे ही कम-से-कम ५० फीसदी कमी कर दी जाय।
- (६) लगान की कमी को देखते हुए बड़ी-बड़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कम आधे कर दिये जायं।
 - (७) विदेशी कपड़े के आयात पर निषेध-कर लगा दिया जाय।
- (८) भारतीय समुद-तट केवल भारतीय जहाजो के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय।
- (६) हत्या या हत्या के प्रयत्नों में साधारण ट्रिब्यूनलो-द्वारा सजा पाये हुओं के सिवा, समस्त राजनैतिक कैंदी छोड़ दिये जाय, सारे राजनैतिक मुकदमें वापस लें लिये जाय, १२४ अ धारा और १८१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आ जाने दिया जाय।
- (१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय।
- (११) आत्म-रक्षार्थं हथियार रखने के परवाने दिये जायं और उन पर जनता का नियन्त्रण रहे।

गाधीजी ने यह भी कहा—"अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हो, परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करें, आप लोग स्वराज्य के इस मत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लडाई निकट आ रही हैं उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करें।"

श्रसेम्वली तथा कौसिलों से त्याग पत्र

जब असेम्बली में वाइसराय साहब ने अपना भाषण दिया, तब वसन्त ऋत् थी। उस समय वातावरण सरकार के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण कानून उसी समय वना था। इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आर्थिक-परिषद् की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्य के साथ रिआयत करने की नीति लाद दी है। इस कारण पण्डित मदन-मोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। काग्रेस के आदेश पर कौसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १६३० तक इस्तीफ दे दिये इनमें से २१ असेम्बली के और ६ राज्य-परिषद् के सदस्य थे। प्रान्तीय कौंसिलों में वगाल से ३४, विहार-उडीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, मद्रास से २०, उत्तर-प्रदेश से १६, आसाम से १२, वम्बई से ६, पंजाब से २ और बर्मा से १ ने इस्तीफा दिया।

सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश

१४,१५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावरमती में बैठक हुई कौसिलो के जिन मेम्बरो ने इस्तीफा नहीं दिया था या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गए थे उनसे कहा गया कि या तो वे काग्रेस की निर्वाचित समितियों की सदस्यता छोड़ दे, अन्यथा उनपर जाब्ते की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैंदियों के साथ सद्व्यवहार करने का आश्वाशन दिया था, परन्तु सरकार ने इस वचन का पालन नहीं किया। इस पर सावरमती में कार्य-समिति ने खेद प्रकट किया, किन्तु इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सिवनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। इस प्रस्ताव ने गाधीजी और उनके विश्वस्त साथियों को सिवनय-अवज्ञा करने का अधिकार दिया। कुछ समय वाद अहमदाबाद में महा-समिति की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का और भी विस्तार करके सिवनय-अवज्ञा आदोलन चलाने की सत्ता भी उन्हें दे दी।

नमक-कानून का विरोध

परन्तु सिवनय-अवज्ञा शुरू करे तो कैसे ? गाधीजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गए थे। वम्बई में ये समाचार पहुच चुके थे और कार्य-सिमिति को सावरमती की बैठक से पहले ही पहुच चुके थे कि नमक के ढेरो पर घावा वोला जायगा। १४ फरवरी से पहले ही वम्बई में प्रचार-कार्य भी शुरू हो गया था। नमक-कर का इतिहास खोज निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३६ में एक नमक-कमीशन वैठा था और उसने भारत में अग्रेजी नमक की विकी के खातिर भारतीय नमक

पर कर लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल बन्दर में माल के बिना जहाज खाली पड़े थे और अशात समुद्र पर वे तबतक चल नहीं सकते थे जबतक कि आवश्यक भार को पूरा करने के लिए भी कोई माल उनपर लदा न हो। इसलिए कुछ माल, कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हें लाना ही पडता था। इसके लिए चेशायर के नमक से अच्छी चोज और क्या हो सकती थी। ऐसी नीति का विरोध आवश्यक था। साबरमती को बैठक के बाद थोड़े दिनों में वातावरण नमक-ही-नमक से व्याप्त हो गया। लोग पूछने लगे, क्या बनाया हुआ नमक पडता खायगा? सरकारी कर्मचारी और भी आगे बढ़े। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने में ईंधन और मजदूरी का हिसाब लगाकर बताया कि नमक-कर से तिगुना खर्च नमक बनाने में लगता है। ये बेचारे यह न समझ सके कि यह संग्राम भौतिक नहीं, नैतिक था।

गाबीजी नमक-सत्याग्रह का आरभ करने वाले थे। उनकी योजना थी कि वह किसी नमक के क्षेत्र में जाकर नमक उठाएँगे, दूसरे नहीं उठाएँगे। उस समय अगर कोई उनसे पूछता था 'क्या हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहें ?' तो यहीं उत्तर मिलता था—'अवश्य। परन्तु मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो।' उन्हें तो आशा थी कि परिणाम तत्काल होगा। वह वल्लभभाई तक को कूच में साथ न ले गये। केवल साबरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने अपने साथ लिया। वर्धा-आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एक साथ भारत-भर में लडाई शुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतत्र थे। उन्हें दीख गया था कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह अन्दोलन फैल जायगा और खूब जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे।

सरकार को श्रंतिम चेतावती

गाधीजी की योजना सदा उनकी अन्त प्रेरणा से बनी हैं। मस्तिष्क के भावना हीन, हानि लाभ-दर्शक तर्क से नहीं बनो है। उनका गुरु और मित्र उनका अन्त - करण ही रहा है। इसीको लायड जार्ज साहब ने 'सदियों की प्रगति का निचोड़ एक युग में निकालना' बताया है। इसी को भारतीय शब्दों में कहा जाय तो, उन्होंने हजारों वर्ष का काम बारह महीने में कर दिखाया। गाधीजी की दिव्य-दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा सभी ने माना। नरम-दलवालों तक ने नमक-सत्याग्रह को भले ही बेहूदा और खतरनाक बताया हो, गाधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी इन्कार नहीं कर सके। गाधीजी ने वाइसराय को बहुत देर तक अधेरे में नहीं रक्खा। सदा की माति इस बार भी (२ मार्च १६३० को) उन्होंने लार्ड

अविन को चिट्ठी भेजी जिसमे उन्होने 'सविनय अवज्ञा' का उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होने लिखा —

"सविनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सालों से सदा हिचिकचाता रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आप तक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न करने में प्रसन्नता है। अनेक देश-बन्धुओं की भाति मुझे भी यह सुख-स्वप्न दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश मित्र-मडल पूर्ण-औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का आश्वा-सन नहीं दे सकते, तब गोलमेज-परिषद् वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्ञानपूर्वक और अशिक्षित जनता दिल-ही-दिल में छटपटा रही है। राष्ट्र के नाम पर काम करनेवालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तडप के पीछे हेतु क्या है। इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में आ सकती है कि जिन करोड़ों मूक किसानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो। इसी कारण मैं कुछ अरसे से जनता को वाछित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझा रहा हैं।

"सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है। इसका बोझ इतना भारी है कि स्वाधीन भारत को इसमें काफी कभी करनी पड़ेगी। स्थायी बन्दों- बस्त अच्छी चीज है, परन्तु इसमें भी मुट्ठो-भर अमीर जमीदारों को लाभ हैं, रितंब किसानों को कोई लाभ नहीं। वे तो सदा से बेबसी में रहे हैं। उन्हें जब चाह बेदखल किया जा सकता है। भूमि-कर को घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-व्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पड़ेगी कि रैयत की भलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे। परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत को जान निकाल लेने के लिए ही किया है। नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यो दीखने में तो वह सब पर बराबर पडता है, परन्तु इस हृदय-हीन निष्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबो पर ही पड़ता है। याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ हैं जो अलग-अलग भी और मिलकर भी अमीरो की अपेक्षा गरीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक-कर का बोझ गरीबो पर और भी ज्यादा पड़ता है। अत कर का भार बहुत अधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जब शासन-व्यय भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया-पलट कर देना। मेरी राय में २६ जनवरी के स्वाभा-विक प्रदर्शन में लाखो ग्रामीणो ने स्वेच्छा से जो भाग लिया उसका भी यही

अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायेगी।

"यह सभी को मालूम है कि भले ही हिसक-दल कितना ही असगठित या सम्प्रति महत्वहीन हो, फिर भी उसका जोर बढता जा रहा है। उसका और मेरा घ्येय एक ही है। परन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि वह मूक-जनता का कष्ट-निवारण नहीं कर संकता। मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन दृढतर होता जा रहा है कि ब्रिटिश-सरकार की सगठित हिसा को शुद्ध अहिसा ही रोक सकती है। यह अहिंसा सविनय-अवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। आरम्भ में आश्रम-निवासी ही इसमें भाग लेगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल हो जायगे। मैं जानता हूँ कि अहिसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा बडी-से-बडी जोखिमो के उठाये बिना नही हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-सख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोखिम बडी नही है। मैने 'ठीक रास्ते पर लाने' के शब्द जान-बूझकर प्रयोग किये है। कारण, मेरी यह महत्वाकाक्षा है कि मै अहिंसा द्वारा ब्रिटिश जाति का हृदय पलट दू और उसे भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दू। में आपकी जाति को हानि पहुंचाना नही चाहता। मैं उसकी भी वैसी ही सेवा करना चाहता हू, जैसी अपनी जाति की। अगर यह बात सच है तो यह ज्यादा देर तक छिपी न रहेगी। बरसो तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के बाद मेरे कुनबे वालो ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है, वैसे ही अग्रेज भी किसी दिन करेंगे। यदि मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाति अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-ऐसे कष्ट-सहन करेगी जिन्हे देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नही रह सकता।

"इस पत्र का हेतु धमकी देना नही है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पित्र कर्तव्य-मात्र है। इसलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अग्रेज मित्र के हाथ रहा हू जो भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है।"

इस चिट्ठी को रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। रेजिन नाल्ड रेनाल्ड कुछ समय तक आश्रम में रह चुके थे। गाधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों ने अन्तिम चेतावनी का नाम दिया। लॉर्ड ऑवन का उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाइसराय ने खेद प्रकट किया कि गाधीजी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और सार्वजिनक शान्ति-भग होगी। गाधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह सच्चे सत्याग्रही के एकमात्र कवच, विनय और साहस की भावना से कूट-कूट कर भरा था। उन्होने लिखा—"मैंने दस्तबस्ता रोटो का सवाल किया था और मिला पत्थर। अग्रेज जाति सिर्फ शिक्त का ही लोहा मानती है। इसलिए मुझे वाइसराय के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेलखाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है।"

द्राडी-यात्रा की तैयारी

इस प्रकार गांधीजी का कूच अनिवार्य हो गया था। सब तैयारी पहले से ही हो चुको थो। लम्बी-चौडी तैयारी को तो जरूरत भी न थी। दण्डी समुद्रतट पर एक गांव है। गांधीजों को वहीं पहुँचना था। उन्होंने मार्ग के ग्रामवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को विद्या भोजन न दे। इधर गांधीजी शुद्ध नैतिक ढग की ये तैयारिया कर रहे थे, उधर वल्लभभाई अपने 'गुरु' के पहले ही आनेवाली तपस्या और सकटों के लिए तैयार होने की प्रेरणा करने के लिए गांवों में पहुँच चुके थे। सरकार ने प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया। जब बल्लभभाई इस प्रकार गांधीजी के आगे-आगं चल रहे थे, सरकार ने समझा, "यह तो १६०० वर्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन बैपटिस्ट है।" उसने तुरत मार्च के प्रथम सप्ताह में वल्लभभाई को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार मास की सादी सजा दे दो। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का बच्चा-बच्चा सरकार के खिलाफ खडा हो गया। इस समाचार से प्रभावित होकर सावरमती के रेतीले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निश्चय किया—

"हम अहमदाबाद के नागरिक सकल्प करते हैं कि जिस रास्ते वल्लभभाई गये हैं उसी रास्ते हम जायगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके छोडेगे। देश को आजाद किये बिना न हम चैन लेगे, न सरकार को लेने देगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और अहिंसा से

ही होगा।"

गावीजी ने कहा, 'जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहे, अपने हाथ ऊचे कर दे।' सारे जन-समूह ने हाथ उठा दिये। उघर वल्लभभाई ने गुजरात मे अपने भाषणो से जीवन फूँक दिया था। इस प्रकार यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी।

द्राडी-यात्रा का आरंभ

गाघीजी अपने ७६ साथियों को लेकर १२ मार्च १६३० को दण्डी-यात्रा पर निकल पड़े। यह एक ऐतिहासिक भव्य-दृश्य था और प्राचीनकाल की राम एव पाण्डवों के वन-गमन की घटनाओं की स्मृति ताजा करता था। यह विद्री- हियो की यात्रा थी। इधर कूच जारी थी, उधर ग्राम-कर्मचारियों के धडाधड़ त्याग-पत्र आ रहे थे। ३०० ने नौकरी छोड दी। अहमदाबाद की खानगी बात-चीत में गांधीजी ने कहा था, "मैं आरभ करू तबतक ठहरना। जब मैं कूच पर निकलूगा तब विचार अपने-आप फैल जायगे। फिर आप लोगो को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए।" यह बात एक तरह से दिमागी-अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विरोध की ऐसी योजना थी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-से-योग्य अनुगामी भी नहीं कर सकते थे। शायद गांधीजी को भी भावी योजना की पूरी कल्पना नहीं थीं। ऐसा लगता है, मानो उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पडती थी और उसी के प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित करते थे। कूच आरम्भ होते ही जनता उनके झण्डे के नीचे आ खडी हुई। विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगा। ज्योही विचारों और भावनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की किया-शक्ति के बन्द भी खुल गये। कूच का आरम्भ में तो उपहास किया गया, बाद में उसे घ्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसी की प्रशंसा की गई। नगर तो डरते रहे, पर गाव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगो का गाधीजी के अचूक निर्णय पर विश्वास था। उनका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त महासागर की लूट का घावा नही था। यह अग्रेजो की सत्ता के खिलाफ

रेरे करोड भारतीयों के विद्रोह का परिचायक-मात्र था।

कूच के बीच में ही २१ मार्च १६३० को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन और नमक-कानून पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि गाधीजी के दण्डी पहुचकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कही सिवनय-अवज्ञा शुरू न की जाय। सरदार वल्लभभाई और श्रीसेनगुप्त की गिर-प्तारियों पर और सरकारी नौकरिया छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बधाई दी गई। सत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की प्रतिज्ञा निश्चित करना वाञ्छनीय समझा गया और गाधीजी की अनुमित से प्रतिज्ञा-पत्र बनाया गया जिसमें सत्याग्रह करनेवालों के लिए कर्त्तांच्यों का विधान था।

गाधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रखे, इस विषय में भी गाधीजी ने अपनी सूचनाएँ दे दी। इसी समय के आस-पास पडित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द-भवन का शाही दान दिया। उस वर्ष काग्रेस के अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस भेट को स्वीकार किया।

गाघीजी-द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को संख्या, घन और प्रभाव का बल मिलता ही गया। गाघीजी ने सूत्र रूप से विचार दिया था। उनके शिष्यो ने भाष्यकार बनकर उसे जनता को समझाया। अनेक कार्यकर्ता राष्ट्र-दूत बनकर उसका प्रचार करने दूर-दूर निकल पड़े। इस प्रकार यह नवीन धर्म देश के कोने-कोने और घर-घर में फैल गया। गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई देती थी, एक ही सप्ताह में उसके होश-हवास गुम हो गए। गाधीजी के महाप्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में वह वल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी कार्रवाईया कर चुकी थी। कूच के बाद उसने यह आज्ञा दी कि लगोटी और दण्डधारी गाघी की पैदल-यात्रा को सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय। बम्बई, उत्तर प्रदेश, पजाव और मद्रास आदि सभी प्रातो ने ऐसी ही आज्ञाये निकाल दीं।

गाधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकडी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सेना विलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम फुर्ती से उठता था और सभी को प्रेरणा देता था। असलाली गाव १० मील दूर या, लोग घण्टो पहले से भारत के महान् सेनापित के दर्शनो की उत्सुकता में खडे थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बडा जलूस निकला, उतना पहले कभी निकला हुआ याद नही पडता। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। कूच को देखने और अपने अलोकिक उद्धारक के प्रति श्रद्धा प्रदिशत करने के लिए भीड सर्वत्र मिलती थी। कूच मे ही गाधीजी ने घोषित कर दिया था कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊगा या आश्रम के बाहर रहुँगा। नमक-कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नही है। अग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सास्कृतिक ओर आध्यात्मिक सभी तरह नाश कर दिया है। मै इस राज्य को अभिशाप समझता हु और इसे नष्ट करने का प्रण कर चुका ह।

'मैने स्वय 'गाड सेव दि किग' के गीत गाये है और दूसरो से गवाये है। मुझे 'भिक्षादेहि' की राजनीति मे विश्वास था। पर वह सब व्यर्थ हुआ। मै जान गया कि इस सरकार को सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लडाई अहिसा की लडाई है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाशी शासन को खत्म कर देना हमारा परम-कर्तव्य है।"

गाधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। श्री अब्बास तय्यवजी उनके उत्तरा-धिकारी मुकरेर हुए।

गाधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहें कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूरत में गाधीजी ने जो भाषण दिया उसका उपस्थित जनता पर जबरदस्त

असर हुआ। नवसारी में पारिसयों को सम्बोधन करके गांधीजी ने उनसे शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया—"यदि हम नमक-कर और शराब की बिकी को उठा देने में भी सफल हो गये, तो ऑहसा की जीत है। फिर पृथ्वी पर कौन शिक्त भारतवासियों को स्वराज्य लेने से रोक सकती हैं यदि ऐसी शक्ति होगी, तो मैं उसे देख लूगा। या तो जो चाहिए वह लेकर लौटूगा, या मेरी लाश समुद्र पर तैरती थिलेगी।"

नमक-कानून टूटा

५ अप्रैल को प्रात काल गाधीजी दण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनी देवी भी उनसे मिलने आई थी। प्रात काल को प्रार्थना के थोडी देर बाद गाधीजी और उनके साथी समुद्र-तट से नमक बीनकर न कि-कानून तोड़ने निकले। नमक-कानून तोड़ते ही गाधीजी ने यह वक्तव्य प्रकाशित किया.—

"नमक-कानून विधिवत् भग हो गया है। अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो वह जहा चाहे और जब सुविधा देखे, नमक बना सकता है। मेरी सलाह यह है कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक बनाएँ; जहा उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना आता हो वहा उसे काम मे भी लाएँ और ग्राम-वासियो को भी सिखा दे, परन्तु उन्हें यह अवश्य जता दे कि कानून छिपाकर नही, खुल्लम-खुल्ला भंग करना है।" दूसरे वक्तव्य में स्त्रियो के विषय में गाधीजी ने नवसारी में कहा कि मै

दूसरे वक्तव्य में सित्रयों के विषय में गांधीजा ने नवसारी में कहा कि मैं इतना विश्वास अब भी रख सकता हूं कि सरकार हमारी बहनों से लड़ाई मोल नहीं लेगी। इसको उत्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जबतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए; जब सरकार सीमोल्लघन करे तब भले ही स्त्रिया जी खोलकर लड़े। मैंने स्त्रियों के सामने जो कार्यत्रम रक्खा है उसमे उनके बहुत काम है। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिखाएँ और जोखिम उठाएँ।

सरकार का दमन-चक्र

६ अप्रैल से नमक-सत्याग्रह से छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आग-सी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में विराट सभाएँ हुईं। कराची, पूना, पेशावर, कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि इस सम्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मद्रास में भी गोली चली। २३ अप्रैल को बगाल-आर्डिनेन्स फिर जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल को वाइसराय साहब ने भी कुछ सशोधन कर के, १९१० के प्रेस-ऐक्ट को आर्डिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर दिया। गाधीजी का 'यंग इण्डिया' अब

साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। थोडे दिन बाद गांघीजी ने अपने 'क जीवन प्रेस' के व्यवस्थापक को आदेश दे दिया कि सरकार जमानत मागे तो न जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय। 'नवजीवन' गया और उसके साथ-सा नवजीवन-प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देश के अधिकाश पत्रका ने जमानते दाखिल कर दी।

अब गाधीजी ने जनता को गावो में ताड़ी के सारे पेड़ काट डलाने का आदे दिया। शुरुआत तो उन्होने अपने ही हाथो से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियो व सभा में वह बोले—"भविष्य में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चाहिए तकली पर तुम बारीक-से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपडा पहले-पह सूरत के बन्दर पर उतरा था। सूरत की बहनो को ही इसका प्रायश्चित्त करन है।" यही पर उन्होने जातीय पचायतो से अपनी मिदरा-त्याग की प्रतिज्ञा पाल करने का अनुरोध किया। किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजि बहिष्कार के विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पड़ी। खेडा जिला गुजरा का रणागण बन गया था।

धारासना पर धावा

इसी समय गाधीजी ने वाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैया किया और सूरत जिले के धारासना और छरसाडा के नमक के कारखानो पर घाव

करने का इरोदा जाहिर किया। उन्होने वाइसराय को लिखा —

"ईश्वर ने चाहा तो धारासना हुच कर नमक के कारखाने पर अधिका करने का मेरा इरादा है। मेरे साथ मेरे साथी भी रवाना होगे। जनता को य बताया गया है कि घारासना व्यक्तिगत सम्पत्ति है। यह महज घोखाधडी है घारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियत्रण है जितना वाइसरार साहब की कोठी पर है। अधिकारियो की स्वीकृति के बिना चुटकी-भर नमन् भी कोई वहा से नहीं ले जा सकता। इस धावें को रोकने के तीन उपाय हैं —

(१) नमक-कर उठा देना।

(२) मुझे और मेरे साथियो को गिरफ्तार कर लेना, परन्तु जैसी मुझे आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर न होगा।

(३) खालिस गुण्डापन। परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुड वाने को तैयार रहेगा तो यह वार भी खाली जायगा।

यह निश्चय बिना हिचक के नहीं कर लिया गया है। मुझे आशा थी कि सत्या ग्रहियों के साथ सरकार सम्य तरीके से लडेगी। यदि उनपर साधारण कानून का प्रयोग करके सरकार सन्तोष कर लेती तो मैं कह ही क्या सकता था? इसके वजाय

जहां प्रसिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोडा-बहुत जाब्ता बरता भी है, वहा साधारण सैनिको पर पाशविक ही नही, निर्लज्ज प्रहार भी किये गये है। ये घटनाये इक्की-दुक्की होती तो उपेक्षा भी कर ली जाती। परन्तु मेरे पास बंगाल, बिहार, उत्कल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बम्बई से जो सवाद पहुचे हैं उनसे गुजरात के अनुभव का समर्थन होता है। गुजरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढरो है। कराची, पेशावर और मद्रास के गौली-काण्ड भी अकारण एवं अनावश्यक प्रतीत होते है। हिंडुया चूर-चूर करके और अण्डकोष दवा-दबा कर स्वयसेवको से वह नमक छोनने का प्रयत्न किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था। हा, स्वयसेवको के लिए अलवत्ता यह बेशकीमती था। बगाल में नमक के सम्बन्ध में मुकदमे और प्रहार तो कम ही हुए दीखते है, परन्तु स्व मसेवको से झण्डा छीनने के काम निर्देयता का परिचय दिया गया बताते है। समाचार है कि चावल दिये गये और खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये गये। कर्मचारियं भाजी न बेचने के अपराध पर गुजरात में एक सब्जी-मण्डी ही न ये कृत्य जन-समूहो की आखो के सामने हुए है। काग्रेस की आज्ञा ये लोग बदला लिये बिना छोडते ? क्रुपया इन वृत्तान्तो पर वि ये मुझे उन लोगो से मिले हैं जिन्होने सत्य का वत ले रखा है भाति वडे-वडे कर्मचारियो-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा है खेद है, इन दिनो भी कर्मचारी झूठी बाते प्रकाशित करने ने अन्त मे उन्होने लिखा—"अत ऑप नमक-कर उठा न सर्टें इ मनाही दूर न करा सके तो मुझे अनिच्छा होते हुए भी इस

कार्रवाई करनी पड़ेगी।"

इन विचारों को हम रोक न सके और इस ईश्वर-दूत को हिरासत में लेने के लिए उषा के प्रकाश में रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा।"

गिरफ्तार होने से पहले गाधीजी ने दण्डी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा

दिया था। वह यह था —

"यदि इस शुभारम्भ को अन्त तक निभा लिया तो पूर्ण-स्वराज्य मिले बिना नहीं रह सकता। फिर भारतवर्ष समस्त ससार के सम्मुख जो उदाहरण उपस्थित करेगा वह उसके योग्य ही होगा। त्याग के बिना मिला हुआ स्वराज्य टिक नहीं सकता। अत सम्भव है जनता को असीम बिलदान करना पड़े। सच्चे बिलदान में एक ही पक्ष को कष्ट झेलने पडते हैं, अर्थात् बिना मारे मरना पडता है। पर-मात्मा करे, भारत इस आदर्श को पूरा कर दिखाए। सम्प्रति भारत का स्वाभाविक स्वाभिमान और सर्वस्व एक मुट्ठी नमक में निहित है। मुट्ठी भले ही टूट जाय,

पर खुलनी हरगिज न चाहिए।

"मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घबराना न चाहिए। इस आन्दोलन का सचालक में नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी तो वह अवश्य रास्ता दिखाएगा। हमारा मार्ग निश्चित है। गाव-गाव को नमक बीनने या बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। स्त्रियों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दूकानो पर घरना देना चाहिए। घर-घर में आबाल-वृद्ध सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहियें और रोज स्त्र के ढेर लग जाने चाहिए। विदेशी वस्त्रों की होलिया जलाई जाय। हिन्दू किसी को अछूत न माने। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब हृदय से गले मिले। बड़ी जातिया छोटी जातियों को देन के बाद बचे हुए भाग से सन्तोष करे। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दे और सरकारी नौकर उन पटेलों और तलटियों की भाति नौकरिया छोड़कर जनता की सेवा में जुट जाय। इस प्रकार आसानी से हमें पूर्ण स्वराज्य मिल जायगा।"

गिरफ़्तारी का व्यापक प्रभाव

गाधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपने-आप फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुंचना था कि बम्बई, कलकत्ता और अनेक स्थानो पर सम्पूर्ण और स्वेच्छापूर्वक हडताल हो गई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हडताल और भी व्यापक थी। वम्बई में विराट् जलूस निकला। शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मचो पर से भाषण देने पड़े। ८० में से ४० के लगभग मिले बन्द रही। ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल आये। जी०आई०पी० और बी० बी० सी० आई० के कारखानो के मजदूर भी काम छोड़-कर हडताल में शरीक हो गये। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के

लिए कपडे के व्यापारियों ने ६ दिन की हडताल का निश्चय किया। गांधीजी पूना में नजरबन्द किये गये थे। वहां भी पूरी हडताल हुई। समय-समय पर सरकारी पदों और पदिवयों के छोड़ने की घोषणा होने लगी। इस देश ने प्रायः सर्वत्र महा-तमाजी के उपदेशों का आश्चर्यजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर झगड़ा भी हो गया। शोलापुर में ६ पुलिस-चौकिया जला दी गई, जिनके फल-स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें २५ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। कलकत्ते में शहर की हडताले तो शान्तिपूर्ण रही, परन्तु हबड़ा और पचतल्ला में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वी घारा के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गई।

परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विश्व-व्यापी हुआ। पनामा के भारतीय व्यापारियों ने २४ घण्टे की हडताल मनाई। सुमात्रा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी हिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा ही किया और वाइसराय साहब एवं कांग्रेस को तार भेज कर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट किया। फांस के पत्र गांधी-जी और उनकी बातों से भरे थे। बहिष्कार-आन्दोलन का परिणाम जर्मनी पर भी हुआ। वहा के कपड़े के व्यापारियों को उनके भारतीय आढितयों ने माल भेजने की मनाही करदी। रूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छीट के कारखानों को खास तौर पर हानि हो रही है। नैरोबी के भारतीयों ने भी हड़-ताल रखी।

इसी बीच अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादियों ने तार-द्वारा रैम्जे मैंकडानल्ड साहब की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनसे अनु-रोष किया कि गाधीजी और भारतवासियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाय। इसपर हस्ताक्षर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीज होम्स ने करवाये थे। सन्देश में प्रधान मन्त्री से अपील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का हित इसी में है कि इस सघर्ष को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयकर विपत्ति से रक्षा की जाय।

भारत-सरकार को स्थिति की गभीरता का अवश्य पूरा खयाल था। वाइस-राय ने सर तेज बहादुर सप्रू और सर चिम्मनलाल सीतलवाड जैसे नरम नेताओ से लम्बी-लम्बी मुलाकाते की। नरम-दल-सघ की कौसिल की बम्बई में बैठक हुई। उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया और नरम-नेताओ ने इस बात की आवश्यकता बताई कि वाइसराय शीध्र ही दूसरी घोषणा करें और गोलमेज-परिषद् की तारीखें मुकर्रर करें। किन्तु सर्वदल-सम्मेलन और नरम-दल की कौसिल की बैठक के एक दिन पहले ही वाइसराय ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और प्रधान-मन्त्री के साथ का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया। नरम-दल की कौसिल ने भी मौजूदा परिस्थिति पर एक वक्तव्य निकाला। इसमें कानून-भग के

आन्दोलन की भरपेट निन्दा की गई और औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए गोलमेज-परिषद् की जल्दी तैयारी करने का वाइसराय से अनुरोध किया गया। इस बात पर भो जोर दिया गया कि सरकार परिषद् की शर्ते और मर्यादाये प्रकट कर दे, ताकि उस समय भी जो लोग परिषद् से अलग् थे वे नरम-दल वालो के साथ उसमे शामिल हो सके। इस बात पर भी आग्रह किया गया कि कानून-भंग का आन्दोलन और सरकार का दमन-चक्र साथ-साथ वन्द हो, राजनैतिक कैदी छोड दिये जाय और सब राजनैतिक दलो पर सरकार पूर्ण विश्वास करे।

कार्य-समिति की वैठक

महात्माजी के स्थान पर श्री अब्बास तैयबजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे। वह भी १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियो, लाठी-प्रहारो और दमन का दौर-दौरा जारी रहा। एक के बाद दूसरा स्वयसेवक-दल नमक के गोदामो पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हे लाठियो से मारती रही। बहुतो को सख्त चोटे आईं।

गाधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून-भग का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नमक के धावों के लिए धारसाना अखिल-भारतीय केन्द्र माना गर्या, सविनयकानून-भग मे शाइवत विश्वास प्रकट किया गया और महात्माजी के कारावास-काल में लडाई को दुगुने उत्साह से चलाने का निरुचय किया गया। साथ ही विद्यार्थियो, वकीलो, व्यवसायियो, मजदूरो, किसानो, सरकारी नौकरो और समस्त भारतीयो को सफलता के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह भी निश्चय किया गया कि हाथ-कते हुए तथा बुने हुए कपडे की पैदावार बढाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खद्दर देने वाली सस्थाये खडी की जाय और सामान्यत हाथ-कताई को प्रोत्साहन दिया जाय। श्रीमती सरोजनीदेवी कार्य-समिति की बैठक में प्रयाग गई थी। श्री तैयवजी

की गिरफ्तारी का समाचार सुनकर वह शीघ्र ही धारसाना लौट आईं और उन्होने धावे का संचालन करने का गांधीजी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वह और उनका स्वयसेवक-दल जाब्ते से गिरफ्तार तो १६ तारीख को ही कर लिया गया, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकाल कर उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके वाद स्वयसेवकों के दल नयक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर हटा दिया गया। उसी दिन शाम को पुलिस ने २२० स्वयसेवकों को गैर-कानूनी संस्था के सदस्य करार देकर गिरफ्तार कर लिया और धारसाना की अस्यायी जेल मे नजरबन्द कर दिया।

वड़ाला पर घावा

१६ ता० को प्रात काल ही वडाला के नमक के कारखाने पर स्वयसेवक बडी सख्या में एकत्र हो गये। पुलिस की तत्परता के कारण धावा न हो सका। उस दिन पुलिस तमचे लेकर आई थी। उसने ४०० सत्याग्रहियो को पकड़ लिया।

वड़ाला के नमक के कारखाने पर कई धावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयं-सेवक पकड़े गये और वर्ली भेज दिये गरे। २५ ता० को १०० स्वयसेवको के साथ २००० दर्शको की भीड़ भी गई। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार। धावा दो घण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर धावा हुआ। इसमे १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उड़ाके श्री कबाड़ी भी इनमें शामिल थे। २६ ता० को ६५ स्वयसेवक मैदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। बाकी भीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अबतक जो गडबिडियाँ हुई हैं वे अधिकतर दर्शको ने की है और इनमें सैनिको का-सा अनु-शासन नहीं है, अत जनता को धावों के समय वड़ाला से दूर रहना चिहये। किन्तु सबसे चमत्कारी धावा तो १ जून को हुआ। युद्ध-समिति उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारिया कर रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिको और असैनिको ने वड़ाला के विशाल सामूहिक धावें में भाग लिया।

पोर्ट-ट्रस्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचा। थोडी देर में धावा करने वाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का घरा तोड कर कीचड पार करके कढाइयो पर पहुँचे। लगभग १५० काग्रेसी सैनिको के मामूली चोटें आईं। पुलिस ने धावा करने वालो को खदेड दिया। यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ।

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बडा उपद्रव हो गया। स्थिति को सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन वडाला के ४ हजार अभियुक्तों से पुलिस की भिड़न्त हो गई। लगभग ६० घायल हुए। २५ को सख्त चोटे आई। किन्तु जिस प्रकार धावा करनेवालों के साथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बडा रोष फैला। दर्शक उस निर्देय दृश्य को देखकर चिकत रह गये।

दमन का दौर-दौरा

परन्तु एक-एक बात को कहा तक गिनाये । घटनाओं का अन्त नही था। लार्ड अरिवन ने अपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होंने गाधीजी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। परन्तु गाधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को लग गया था। सर्वत्र कूच के नक्कारेवजने लगे थे। उनकी पुकार पर हजारो

महिलाये मैदान मे निकल आई थी। इस कारण सरकार बडे चक्कर में पड गई। उन्होंने आते ही शराब और विदेशी कपडे की दुकानी पर धरना देने का काम अपने हाथ में ले लिया और जवतक शौर्य पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तबतक पुलिस भी उनके आगे कुछ न कर सकी। १४ अप्रैल को जवाहरलालजी को पकड कर सजा दे दी गई। जवाहर क्या बन्दी हुआ, काग्रेस बन्दी हो गई। सारा देश एक विशाल जेलखाना बन गया। धरना, करबन्दी और सामाजिक बहिप्कार सवकी रोक के लिये आर्डिनेन्स निकल गये। राष्ट्रीय झडे पर अनेक मुठभेडे हुई। सजाये दिन-दिन कठोर होने लगी। कैंद के साथ-साथ जुर्माने किये जाने लगे। सभा-भग की आज्ञा तो होती थी देश के साधारण कानून के अनुसार और उस पर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रहारों से। नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरात-हिन्द की धाराये मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजाये दी जाने लगी। फरवरी १६३० के मध्य मे एक सरकारी आज्ञा निकली। उसमे राजनैतिक कैदियो का वर्गीकरण किया गया, पर उसमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नही आने दिया गया। 'ए' वर्ग तो नाममात्र को ही था। 'बी' क्लास भी वडी कजूसी से दिया जाता था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊचे रहन-सहन के अभ्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च-वर्ग के हकदार थे। पर उन्हें भी 'सी' क्लास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलो में पत्थर तोडने, घानी पेरने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियो के साथ किये गये व्यवहार ने इस सरकारी आज्ञा की शीघ्र कलई खोल दी। एक बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपस्थित लोग तो ताले में बन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटको पर आड लगाकर पहरे विठा दिये गये। पाशर्विक व्यवहार की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बगाल से हुई, पर थोडे ही दिनो में दक्षिण-भारत में यहीं हाल होने लगा। आदोलन के उत्तराई-काल में वहा दमन की अमानुषिकता का पार नहीं रहा। बबई लडाई का मुख्य केन्द्र वन गया। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार पर सारा जोर आ पडा। इसमे मिल मालिको का स्वार्थ साय था। सौभाग्य से पडित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह बम्बई गये और उन्होने अहमदाबाद के मिलवालो से समझौते की बात-चीत की। अहमदाबादवालो से निपटना आसान था, पर वम्बई के मिलो में यूरोपियनो का हिस्सा था। उनसे काग्रेस की मुहर लगवाने की शर्त कबूल कराना बडा मुश्किल काम था। परन्तु मोतीलालजी ने असम्भव को सम्भव कर दिखाया। बात यह थी कि वायुमण्डल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण था। जनता के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी थी । विदेशी कपडे की सैकडो गाठे बन्दर पर पडी थी। व्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वे माल नहीं लेगे। इस कारण देश में कपडे की तगी होने लगी थी।

कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून आ पहुंची। उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई। उसने बहुत-से शहरों और गावों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की प्रगति पर सतीष प्रकट किया और समस्त काग्रेस-सस्थाओं तथा देशभर से अनुरोध किया कि ब्रिटिश माल के सम्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और उसके लिए हिन्दुस्तान में न बनने वाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदें। जनता से यह भी अनुरोध किया गया कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय आदोलन का गला घोटने के लिए जनता पर अमानुपिक अत्याचार करने में भाग लिया है उन सबका सगठित और कठोर-रूप में सामाजिक बहिष्कार किया जाय। भारत के कालेजों के विद्यार्थियों से भी राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता के संग्राम में पूर्ण भाग लेने की अपील की गयी।

ऐसी समितियो और संस्थाओ से, जो सरकार-द्वारा गैर-कानूनी घोषित कर दी गई थी यह कहा गया कि वे सरकार की घोषणा की पर्वाह न करके पहले की भाति काम करती रहें और काग्रेस-कार्यक्रम को जारी रखें।

उन दिनो विलायती कपड़े का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। खहर से किसी भाति कपड़े की मांग पूरी होती दीखती न थी। इसके बाद मिल के सूत का हाथ से बुना हुआ कपड़ा ही देश-भक्त नागरिकों के लिए ग्राह्म हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और बाघक होनेवाले कारखानों में भेद करना पड़ा। तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा द्वारा कांग्रेस के नियन्त्रण में लाया गया। मिलों से जो शर्ते करवाई गई उनमें से मुख्य ये थी कि वे अपनी मशीनरी ब्रिटिश कम्पनियों से न खरीदेगी, अपने आदिमयों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से न रोकेगी, कांग्रेस की दी हुई रिआयत का बेजा फायदा उठाकर अपने माल की कीमत न बढायेगी और ग्राहकों को हानि न पहुचायेगी। मिलों ने घडाघड़ इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके पश्चात् महासमिति गैर-कानूनी ठहरा दी गई। पण्डित मोतीलाल नेहरू को ३० जून १६३० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी वृद्धि और हुई कि बहिष्कार-आदोलन की तीन्नता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरता भी बढती गई। बम्बई के स्वयंसेवक-सगठन में कोई कसर बाकी न थी। स्त्रिया आती गई और जब ये कोमलागिया केसरिया साडी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्नता के साथ घरना देती थी, तब लोगों के हृदय बात-की-बात में पिघल जाते थे। यदि कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो उसकी पत्नी घरना देने आ वैठती थी। अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभाये वींजत करार दे दी गई। पर इन आजाओं को मानता कीन था?

बेल्सफोर्ड का वक्तव्य

ब्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी और जनता के साथ जो पाशनिक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आखो देखा था। १२ जनवरी १६३१ के 'मैंचेस्टर गार्जियन' में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया-- "पुलिस के खिलाफ जिम्मेदार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी शिकायते हैं कि उनको जाच करना वडी टेढो खीर है। इस तरह को बहुत-सी बाते मुझे प्रत्यक्षदर्शी अग्रेजो और घायलो को मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरो ने सुनाई । मैंने भी दो सभाये देखो । उन्हें नहीं रोका गया था । भाषण राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शान्तिपूर्वक । हिंसा की वरावर निन्दा को गई। लोग जमीन पर बैठे तकलिया चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियो की सख्या भी खूव थी। अगर इन सभाओं को रोका न जाता तो कोई उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोडे दिन में ऊवकर अपने-आप घर बैठ जाती। पर हुआ यह कि खासकर वम्बई में मारपीट कर तितर-वितर करने की नीति से सारे शहर का जोश उमड आया, लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्न वन गया और शहादत के जोश में सैकडो स्वयसेवक मार खाने के लिए निकल आये। उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। इस वात मे तो मुझे कोई शका रही नहीं कि अग्रेज अफसरों की अयोनता में भी पुलिस राजद्रोह की सजा अक-सर शारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्र झरोलो पर खडे थे। शान्त जलूस पर होने वाले लाठी-प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे—"बुजदिलो!" दो घण्ट वाद एक अग्रेज अफसर पुलिस लेकर पहुंच गया, और पढ़ाई के कमरों में घुस-घुसकर पढ़ते-लिखते हुए विद्याधियों की आख मीचकर पिटाई हुई। यहां तक कि दीवारे खून से रंग गई। विश्व-विद्यालय की ओर से जाब्ते में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था। इस घटना का हाल मुझे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकों यूरोप के विज्ञान-जगत में खूब ख्याति है। हाईकोर्ट के एक भारतीय न्यायाधीश का लड़का भी इस पिटाई का शिकार हुआ था। लाहीर में भो ऐसी घटनाएँ हुई। वगाल के कण्टाई गाव में निर्दोष भोड को तितर-वितर करते हुए पाच आदमी तालाव में ढकेल दिये गये। पाचो डूबकर मर गये। मेरठ में एक बडे वकील से मिला। वहा भी एक सभा भंग की गई थी। वकील महाशय मुख्य वक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया और उसी हालत में पास खंडे पुलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। वेचारो को अपनी बाह कटवानी पड़ी।"

पेशावर की घटना

२३ अप्रैल १९३० को पेशावर में जो घटनाएँ हुई उनका भी सार यहा दे

देना ठीक होगा। भारत के अन्य भागो की भाति सीमा प्रान्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर-शहर में काग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से शराब को दुकानो पर पहरा लगेगा। परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए। २२ अप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुचनेवाला था। इसका उद्देश्य सीमा-प्रान्त के विशेष कानूनों के अमल की जान करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेशावर मे जलूस निकला और शाही बाग मे विराट सभा हुई। दूसरे दिन तड़के ६ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ६ बजे दो नेता और पकड लिये गये। परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह विगड गई। नेताओं ने थाने पर आ जाने का आश्वासन दिया और वे छोड दिये गये। तदनुसार जनता उक्त नेताओं का जलूस बनाकर बिंकी दरवाजे के थाने पर ले गई। पर थाना बन्द था। इतने में एक पुलिस अफसर घोडे पर आ पहुचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया और अकस्मात् दो-तीन स्शस्त्र मोटरे आ पहुची और भीड के भीतर घूस गई। इसी समय एक अग्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था। उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर में से किसी ने गोली चलाई और सयोग से मोटर में आंग भी लग गई। डिप्टी कमिश्नर अपनी सशस्त्र मोटर में से उतरा और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पडा। वह वेहोश हो गया, किन्तु जल्दी ही होश में आ गया। इसके बाद सशस्त्र मोटरो से गोलिया चलने लगी। लोगो ने मृत शरीरो को वहा से हटाने का प्रयत्न किया। फौजी दस्ते और मोटरे भी हटा ली गई। दूसरी बार फिर गोलिया चलाई गई और वे करीव ३ घण्टे तक चलती रही। दुर्घटनाओ के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में मृतको की सख्या ३० और घायलो की सख्या ३३ दी गई है; किन्तु लोग इन सख्याओं को करीब-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते थे। साय-काल फौज काग्रेस के बिल्लो और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले गई। २४ तारीख को फौज और सामान्यत वहा रहनेवाली पुलिस दोनो हटा ली गई। २८ तारीख को पुलिस ने फिर आकर काग्रेस और खिलाफत के स्वयसेवको से, जो शहर के दरवाजो पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फीज ने कब्जा कर लिया।

वम्बई में लाठी-चार्ज

१ अगस्त १६३० को बम्बई में लोकमान्य तिलक की बरसी मनाई गई और श्रीमती हसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय नगर-काग्रेस की डिक्टेटर थीं, एक जलूस निकाला गया । काग्रेस-कार्य-समिति की बैठक नगर में लगातार तीन दिन से हो रही थी। वह उस समय वहा गैर-कानूनी घोषित नही हुई थी, क्योंकि सरकार उस हुक्म को एक प्रान्त से दूसरे में धीरे-धीरे जारी कर रही थी। कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायकाल के जलूस में शामिल हो गये थे। जिस समय वे आगे बढे चले जा रहे थे उस समय उन्हें जलूस निकालने की निषेधाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस मिला। उस समय तक जलूस में हजारो आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुक्म मिला उस समय सडक पर एक विशाल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद भी एक इच हटना नहीं चाहता था। लोग सचमुच पानी के पोखरों में ही बैठे थे। यह आशा की जा रही थी कि जलूस को आधी रात के बाद आगे बढने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पहले हुआ था। किन्तु यह न हुआ। चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति की सूचना पूना-स्थित होम-मेम्बर को दी। मि० हॉटसन ने उत्तर दिया कि जब तक मैं न आऊगा तब तक कुछ भी नही करना चाहिए। वह सुवह होते-होते वहा पहुचे और भीड़ को विक्टोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने लगे। कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलाये भी, और तव भोंड को तितर-बितर करने के लिए लाठी-प्रहार का हुक्म हुआ। कार्य-समिति के जो सदस्य उस समय गिरफ्तार हुए उनमें प० मदनमोहन मालवीय, श्री वल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिबहन (वल्लभभाई की सुपुत्री) जलूस मे थी, इसलिए वह भी गिरफ्तार कर ली गईं। कोई सौ अन्य महिलाये भी गिरफ्तार की गई थी। उनमें डिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थी।

विभिन्न प्रान्तों में दमन

जब वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काट कर बाहर आये तब पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें काग्रेस का स्थानापन्न अघ्यक्ष नियुक्त किया। उन्होने बम्बई और गुजरात में कार्य सगठित करना आरंभ किया और आन्दोलन को और भी तीव्र कर दिया। इस राष्ट्रीय-आन्दोलन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट-सहन किया। भिन्न-भिन्न स्था गे पे भिन्न-भिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था। इसका कारण था—भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, सम्बन्धित अफसरों का स्वभाव, पट्टें की शत आदि। दक्षिण-भारत पर तो बहुत ही बुरी बीती। वहा लाठी-प्रहार, भारी-भारी जुर्मानों और लम्बी-लम्बी सजाओं की शुरुआत आन्दोलन के बढनेपर नहीं, बाल्क पहले ही से हो गई थी। बगाल-प्रान्त ने देश भर में सब प्रान्तों से अधिक कैदी दिये। अग्रेजी कपडें का बहिष्कार बगाल और विहार-उडीसा में सबसे अधिक हुआ। वहा नवम्बर १६२६ के मुकाबले में नवम्बर १६३० में अग्रेजी कपडें का आयात ६५% गिर

गया था। स्वतन्त्रता के युद्ध में गुजरात की कारगुजारिया अनुपम थीं। कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था। वहा अक्तूबर १६३० में जमीदारो और काश्तकारो दोनो को ही लगान और मालगुजारी रोक लेने के लिए कहा गया था। पजाब भी किसी से पीछे न रहा। अहिंसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्त की जितनी राजनैतिक जीत हुई उतनी ही नैतिक विजय भी हुई। बिहार में चौकीदारी-टैक्स देना अधिकाश वन्द कर दिया गया। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-पूरे कष्ट सहे। वहा के लोगो को सजा देने के लिए वहा अतिरिक्त-पुलिस रख दी गई और छोटी-छोटी रकमो के लिए उनकी बडी-बडी जायदादे जब्त कर ली गईं। मध्य-प्रान्त में जगल-सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमें सफलता मिली। लोगो ने भारी-भारी जुर्मानो और पुलिस की ज्यादित्यों के होने पर भी उसे जारी रखा। तीन लाख ताड और खजूर के पेड काट डाले गये। सिसीं ताल्लुके के १३० पटेलो में से ४६ ने त्याग-पत्र दे दिये थे। अकोला में करबन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिसीं और सिद्दापुर में वह आर्थिक कारणो से शुरू हुआ था। किसानो की तबाही भी एक कारण थो। केरल, जो कि प्रान्तों में सबसे छोटा है, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा। दूसरे सिरे पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल है, राष्ट्रीय महासभा की आवाज का शानदार जवाब दिया। इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी दमनकारी घटनाएँ हुईं।

गुजरात में किसानों की हिजरत वर्णन करते हुए मि॰ विल्सफोर्ड ने लिखा है कि यहां के देहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी गाडियों में जमाया और फिर वे उन्हें बड़ौदा की सीमा में हाक ले गये। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती फसलों को ले जाना असम्भव देख जला दिया। उन्होंने चटाइयों की दीवारें और टाट पर ताड़ के पत्ते विछाकर छते बना ली और काम चलाऊ घर बना लिये। मैंने उनमें से एक वड़े दल से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये हैं हैं हित्रयों ने बहुत जल्दी सीधे साद उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में है।' पुरुषों को अपने आर्थिक कष्ट का ज्ञान था। उन्होंने कहा, 'खेती में इतना पैदा नहीं होता और लगान बेजा है।' एक-दों ने कहा, 'स्वराज्य लेने के लिए।' मैंने सूरत की काग्रेस के सभापित के साथ उन परित्यक्त गावों में भ्रमण करते हुए दो दिन व्यतीत किये, जो मुझे सदा याद रहेगे। घरों की कतार-की-कतार खाली पड़ी थी। उनपर कपड़ा सिले हुए ताले लगे थे। इन परित्यक्त गावों में से एक से जब हमारी मोटर रवाना होने लगी तब सगीन चढ़ी हुई रायफल वाले पुलिसमैन ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। उसने कहा कि 'आप पुलिस की लिखित आज्ञा लेकर ही गाव से जा

सकते हैं', किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखी तब वह तुरन्त डर गया। टूटी-फूटी अग्रेजो में सिटिपटाते हुए बोला—'हुजूर।' किन्तु मजे को बात तो यह थी कि उसकी वर्दी पर नम्बर का कही पता भो न था। जब मैंने उससे उसका नम्बर पूछा तब उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम सब लोग गुप्त नम्बर रखते हैं। वह सिपाही उस दल का आदमी था जो उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयर्लेंड के 'ब्लेक एन्ड टान्स' दल से मिलता-जुलता था। इस दल के सगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होगे कि उनकी वर्दियो पर उनके नम्बर नहीं रहते।

इस दु खभरी कहानी को समाप्त करते हुए हमें पेशावर और वहाँ के पठानी के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। पठान, जिनका नाम निर्दयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनो के समान सीधे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन गये थे। खान अब्दुलगपफार खाँ ने अपने 'खुदाई खिदमतगारो' का ऐसे सुनि-यन्त्रित और सच्चे ढग से सगठन किया था कि भारतवर्ष का जो भाग इस दिशा मे अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केन्द्र बन गया था। सीमातप्रान्त में की गई निर्दयताओं को विलकुल अन्वकार में रखा गया था और श्री विट्ठलभाई पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जब्त कर ली थी। एक महत्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त मे हुई थी, वह यहा उल्लेखनीय है। उस प्रान्त मे जो दमन हुआ उस सिलसिले मे गढवाली सिपाहियो को, एक सभा में बैठे हुए लोगो पर, गोलों चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और नि शस्त्र भीड पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। इस कारण उन सिपा-हियो पर फौजी अदालत मे मुकदमा चलाया गया और उन्हे १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्बी सजाये दी गई। बोरसद में भी इसी प्रकार की एक रोमा-ञ्चकारी घटना हुई। वहाँ की महिलाओ ने बडी वीरता दिखाई। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। स्त्रियो ने जलूसवालो को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानो पर पानी के बडे-बडे बर्तन रखे छोडे थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनो को ही तोडा। फिर स्त्रियो को बलपूर्वक तितर-वितर कर दिया। यह भी कहा जाता है कि जब स्त्रियाँ गिर गई तब पुलिसवाले उनके सीनो को बूटो से कुचलते हुए चले गये। पुलिस के गुण्डेपन का कदाचित् यह अन्तिम कार्य था। क्योंकि २६ जनवरी को समझौते की वातचीत चलाने योग्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए गाधीजी और उनके २६ साथियो को बिना शर्त छोड देने की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी।

समभौते के श्रसफल प्रयत्न

समझौते की वातचीत पहले से ही चल रही थी। २० जून १६३० को बम्बई मे प० मोतीलालजी से, जब वह वाहर थे, 'डेली हेरल्ड' के संवाददाता मि० स्लोकोम्ब ने मुलाकात की थी और उनसे 'काग्रेस किन शर्तों पर गोलमेज-परिषद् में शामिल हो सकती है?'—इस विषय पर बातचीत की थी। इसके थोड़े दिन बाद मि० स्लोकोम्ब की सोची हुई शर्तों पर एक सभा में, जिसमे पण्डितजी, श्री जयकर और मि० स्लोकोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वोकार हुई। सर सप्रू और जयकर मध्यस्थ हुए। पिडत मोतीलालजी समझौते की तजबीजे लेकर काग्रेस के सभापित प० जवाहरलाल नेहरू और गाधीजों के पास जाने को राजी हो गये। शर्त यह थी कि बिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जायँ कि, चाहे गोलमेज-परिषद् की कुछ भी सिफारिशे हो और चाहे पार्लमेन्ट हमारे प्रति कुछ भी रुख रखे वह स्वय भारत-वर्ष की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की माग का समर्थन करेंगे। शासन-परिवर्तन की खास-खास तर्मोमों और शर्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिषद् रखे, उनमें गुजाइश रहे। इस आधार पर मध्यस्थों ने वाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गाधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल में मिलने की इजाजत मागी। यह १३ जुलाई की बात है। तब तक मोतीलाल जी को जेल हो चुकी थी। वाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानवाले स्वराज्य के प्रकार को और भी नरम कर दिया। उन्होने वादा किया कि 'हम भारतवासियों को उनके गृह-प्रवन्ध का उतना अश दिलाने में सहायता देगे जितना कि उन विषयों के प्रवन्ध से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा, जिनमें जिम्मेदारी लेने की स्थिति में वे नहीं है।'

उक्त दो कागजों को लेकर सप्नू और जयकर ने यरवदा जेल में २३ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिसमें गाँधीजी ने उन्हें नैनी-जेल (इलाहावाद) में पं॰ मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र दिया। गांधीजी चाहते थे कि गोंलमेज परिषद् के वाद-विवाद को संरक्षणो-सम्वन्धी विचार तक ही सीमित रखा जाय। सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न दिया जाय। गोलमेज-परिषद् की रचना सतोषजनक हो, सिवनय-अवज्ञा-आदोलन के रोक लेने की दशा में भी तवतक विदेशी वस्त्र और शराब का धरना जारी रहे, जबतक कि सरकार स्वय शराब और विदेशी वस्त्र का निषेध कानून न कर दे और नमक का बनाया जाना विना किसी भी तरह की सजा के जारी रखा जाय। इसके वाद उन्होंने राजनैतिक विन्यों के छुटकारे का, जायदादो, जुर्मानों और जमानतों के वापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुर्नानयुक्ति का और आदिनेत्सों को वापस लेने का जिक्र किया। उन्होंने सन्देशवाहकों को सावधान किया और कहा कि मैं एक कैंदी हूँ, इसलिए मुझे राजनैतिक गित-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। ये मशविरे मेरे अपने हैं। मैं स्वराज्य की हरेक योजना

को अपनी ११ शर्तो से कसने का हक अपने लिए सुरक्षित रखता हूँ। गाधीजी से वाते करने के पश्चात् सन्देश-वाहको ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। खूब बहस भी हुई। मोतीलालजी और जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १६३० के पूत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जर्वतक मुख्य-मुख्य विषयो पर एक समझौता ने हो जाय तवतक किसो भी परिषद् में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को श्री जयकर गांधीजी से पुन मिले, तब गांधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमे चाहे जब साम्राज्य से पृथक् होने की इजाजत न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह वातो के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिले।

थोडे दिन बाद ही दोनो नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये। वहा १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमे एक तरफ मध्यस्य थे जयकर तथा सप्रू और दूसरी तरफ गाधीजी, दोनो नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास दौलतराम और श्रीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में प्रकाशित हुआ जिसमें हस्ताक्षर-कर्ताओं ने, समझौतो की शर्तों को, दोहराया था। उसमे उन्होने भारतवर्ष के पृथक् होने के हक को और अग्रेजो के दावो और उनकी रियायतो की जाच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की माग को भी शामिल कर दिया था। वाइसराय ने अपने २८ अगस्त के एक पत्र में लिखा कि मै तो प्रान्तीय सरकारो से राजनैतिक बन्दियो को बड़ी सख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलो पर उनके प्रकारो और योग्यता के अनुसार विचार करना उन्ही को अधिकार होगा। दोनो नेहरूओ ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांधीजी को लिखा कि वाइसराय मुख्य प्रारम्भिक बातो पर विचार करना भी गैर-मुमिकन खयाल करते है। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि शान्ति की बात-चीत असफल हो गई। सप्रू-जयकर की समझौते की बात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के हितैषियों को निराशा नहीं हुई। इसके बाद मि० हौरेस जी० अलक्जैण्डर के, जो सैली ओक कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसराय से और जेल मे गाघीजी से मिले। गाघीजी की साफ मागो से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दा-डम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की सीधी-सादी समस्याओं का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड अविन ने एक दर्जन के करीब आर्डिनेन्स निकाल दिये थे। वह आर्डिनेन्सो की बहुत आव-श्यकता भी वताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता की थोडी कर भी कर रहे थे।

गोलमेज-परिषद्

१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिषद् शुरू हुई। अपर-हाउस की शाही गैलरी में बडी शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ६६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासतो से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैंड के भिन्न-भिन्न दलो के मुखिया थे। गोलमेज-परिषद् बीच-बीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्राय सभी ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पिट्याला, बोकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संव-राज्य के पक्ष में थे। प्रधान-मन्त्रों ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्ते रखी। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछजी बात की खूबिया दिखलाई। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशोल होगी उसे अगली पीढी पित्र विरासत समझेगी। इसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितिया बनाई गई जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अल्प-सख्यको, ब्रह्मा, सरकारी नौकरिया और प्रान्तीय तथा सघ-शासन के ढाचो की बावत वाकायदा रिपोर्ट दी। परिषद् अधिवेशन को जल्दो समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जनवरो को खुला अधिवेशन हुआ। इसके वाद प्रधानमन्त्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादो की घोषणा की और फिर परिषद् समाप्त हुई।

रिश्रायतो प्रस्ताव

परिषद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष की स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से विना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आदिमयों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। काग्रेस-कार्य-सिमिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष प्रस्ताव को यहा देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर 'रिआयती' (Privileged) लिखा हुआ था। यह 'रिआयती प्रस्ताव' काग्रेस कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ वजे स्वराज्य भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया।

"अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्यसमिति उस 'गोलमेज परिषद्' की कार्रवाईयो को स्वीकार करने को तैयार नही है जो ब्रिटिश-पार्लमेट के खास-जास सदस्यो, भारतीय नरेशो और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थको में से चुने हुए उन व्यक्तियो ने मिलकर की थी, जो भारतवासियो के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश-सरकार ने मारतीय-प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेनाल किया है, उनसे उसने स्वय अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव बात तो यह है कि वह, भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरु जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बद करके, आर्डिनेसों और सजाओं द्वारा और सिवनय-अवज्ञा-द्वारा अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभिक्तपूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शात, शस्त्रहीन, और मुकावला न करनेवाले लोगों पर लाठी-प्रहार करके और गोलिया चलाकर, इस देश की सच्ची आवाज को रोकतो रही है।

"इस कार्य-सिमिति ने १६ जनवरी १६३१ को मिन्त्र-मडल की ओर से इगलैंड के प्रधान मत्री मि० रेम्जे मैंकडानल्ड-द्वारा घोषित सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस सिमिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे काग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

"यह समिति लाहौर-काग्रेस में स्वोक्तते पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ है और यरवड़ा जेल से १५ अगस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म० गाधी, प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लागो ने जो विचार प्रकट कि में हैं उनका समर्थन करती है।

"सिमिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित किये हुए कार्यक्रम के अनुसार मनाये और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशा-पूर्ण होकर स्वाधीनता की लडाई जारी रखने का दृढ निश्चय

कर चुका है।"

जब काग्रेस-कार्य-सिमिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेंन्द्र बाबू काग्रेस के काम-चलाऊ अध्यक्ष थे। वल्लभभाई तो ११ मास में तीसरी बार जेल गये हुए थे, इसिलए वही उनके स्थानापन्न थे। प० मोतीलाल नेहरू जेल में सख्त बीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद खत्म होने से पहले ही छोड दिये गये थे। इसके थोडे दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। कार्य-सिमिति की बैठक का और उसके उद्देय का प्रेस द्वारा खुला एलान कर दिया गया था। इस अवसर पर कार्य-सिमिति के सदस्य इलाहाबाद में जमा हुए। कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। प० मदनमोहन मालवीय यद्यपि रोगी थे, किन्तु फिर भी सिमिति की इस बैठक में उपस्थित हुए थे। सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं इस पर मतभेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। किन्तु दूसरे दिन अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिससे इसे प्रकाशित न करने का निश्चय ही ठीक सिद्ध हुआ। लन्दन से डा० सप्रू और शास्त्रीजी का एक तार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-सिमिति से उनके आने से पहले उनकी वाते विना सुने प्रधान-मन्त्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। उस तार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु जैसा कि ऐसे मामलो में प्राय हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर बाद ही सीधी सरकार के पास पहुँच गई थी। २५ जनवरी १६३१ को गवर्नर-जनरल ने एक वक्तव्य निकाला जिसके अनुसार काग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, वातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी गई और वे जेल से मुक्त कर दिये गये।

: १४ :

गांधी-अविन-समभौता : १९३१

मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

कांग्रेस-कार्य-सिमिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात से पहले होने वाली थी। इस बात की भी हिदायत थी कि उनकी पित्नया यदि जेल में हो तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। बीच-बीच में जो लोग किसी के बजाय कार्य-सिमिति के सदस्य बने थे उनकी रिहाई की भी आज्ञा थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल सख्या २६ तक पहुँच गई। गांधीजी, छूटते ही, पं० मोती-लाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहा वह वीमार पडे हुए थे। कार्य-सिमिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। वहीं स्वराज्य-भवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को, कार्य-सिमिति की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में कहा गया कि जवतक स्पष्ट रूप से सिवनय अवज्ञा आन्दोलन को बन्द करने की आज्ञा न निकाली जाय तवतक आन्दोलन बरावर जारी रहेगा। साथ ही विदेशी कपड़े और शराव तथा अन्य नशीली चीजों की दूकानो पर धरना देना जवतक विलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जवतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई एकावट न पडती हो तवतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत हैं।

कार्य-सिमिति के असेनी और स्थानापन्न सदस्य ३ फरनरी तक इलाहाबाद हो रहे। पण्डित मोतीलाल की हालत दिन-द-दिन खराव होती जाती थी। इसिलिए यह आवश्यक सनझा गया कि उन्हें 'एक्सरे-परीक्षा' के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तवतक करीव-करीव सभी लोग थोड़े दिनों के लिए वहां से चले गये, परगांघीजी सहित कुछ लोग वही रहे। गांघीजी तो मोतीलालजी के साथ लखनऊ

भी गये, जहा मौत से वड़ी कश-मकश के वाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोती-लाल जी सदा के लिए हमसे विदा हो गये--"हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिये। मेरी मोजूदगो में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य-निर्णय के आखिरी सम्मानपूर्ण समझौते मे मुझे भी साझीदार होने दों। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतत्र भारत की गोद में हो मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नीद गुलाम देश मे नही, विल्क आजाद देश में हो लेने दो।" इस प्रकार पंडितजी की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। जव उनको दूरन्देशी और तत्काल वृद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओ को स्पष्ट रूप से सुलझाने में पर्याप्त सहायता मिलने की आवश्यकता थी तब उनका हमारे वीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षिति थी कि वस्तुत उसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी। उनकी मृत्यु पर, ७ फरवरी को, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह संदेश दिया—"मोतीलालजी को मृत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईर्ष्यास्पद होनी चाहिए। क्यों कि अपना सब-कुछ न्योछावर करके वह मरे हैं और अन्त समय तक देश का ही घ्यान करते रहे हैं। इस वीर को मृत्यु से हमारे अन्दर भी विलदान की भावना आनो चाहिए। हम में से हरेक को चाहिए कि जिस स्वतन्त्रता के लिए वह उत्सुक थे और जो अब हमारे बहुत नजदीक आ पहुची है, उसको प्राप्त करने के लिए अाना सर्वस्व नहीं, तो कम-से-कम इतना वलिदान तो करे ही कि जिससे वह हमें प्राप्त हो जाय।"

दमन का दौर-दौरा

राजनैतिक परिस्थित में इस समय जो वात वस्तुत शोकजनक थी, और जिसके लिए गांधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह यह थी कि इंग्लैंण्ड में तो खूब चिल्ला-चिल्ला कर हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता देने की बात कही जा रही थी, पर उसके कारण हिन्दुस्तानों के अधिकारियों के रुख में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर दमन-चक्र अपने भयंकर रूप में जारी था। ठीक इसी समय गोलमेज परिषद् में गये हुए प्रतिनिधि लौटकर हिन्दुस्तान आये और आते ही, ६ फरवरी १६३१ को, उन्होंने काग्रेस से निम्न प्रकार अपील की — "गोलमेज-परिषद् की योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की

"गोलमेज-परिषद् की योजना अभी तो खाली एक खाका है, तफसील की वाते तो जिनमें से कुछ बहुत सार की और महत्वपूर्ण है, अभी तय होनी हैं। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि अब कांग्रेस तथा अन्य दलो के नेता आगे बढ़कर इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है कि वातावरण को ऐसा शात कर दिया जाय जिसमें आवश्यक विषयो पर भलीभाति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैंदियों की रिहाई हो

सके।"

लेकिन इसके बाद भी सजाये दी जाती रही। फरवरी १६३१ में कानपुर शहर में पिकेटिंग के अपराध में १३६ गिरफ्तारियाँ हुईं। साथ ही जेलों में भी क्या खाना-कपड़ा और क्या दवादारू—कैंदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था। उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता बैठक हुई। इस समय तक डा० सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गाधीजी और कार्य-समिति से मिलने के लिए वे दौडे हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कडी जिरह की। यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मृदुता तक न रख पाते थे; क्योंकि शास्त्री जी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी बाते कह गये थे जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्क उनके प्रति रोष भी बढ़ रहा था।

वाइसराय से भेंट

गाधीजी ने लार्ड अविन को एक पत्र लिखा, जिसमे देश में पुलिस-द्वारा की जा रही ज्यादितयों, खास कर २१ जनवरी को बोरसद में स्त्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जाच कराने के लिए कहा। लेकिन इस माग को ठुकरा दिया गया। तब गाधीजी ने लार्ड अविन के पास मुलाकात के लिए एक सिक्षप्त पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उनसे बहैसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के बड़े सबेरे तार-द्वारा इसका उत्तर आ गया। १६ तारीख को ही गाधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये। पुरानी कार्य-सिमित के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुच गये। कार्य-सिमित ने एक प्रस्ताव द्वारा गाधीजी को काग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे। गाधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली बार मुलाकात की और कोई चार घण्टे तक वाइसराय से उनकी बाते होती रही। तीन दिन तक लगातार यह वात-चीत चलती रही।

इस बात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादितयों की जांच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जांच की बाते ऐसी विवादास्पद थी जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं थी। १६ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञाप्ति प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी बाते उठी हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे वातचीत होने में कई दिन लग जायं।

पहले दिन की बात-चीत से एक प्रकार की निश्चित आशा बधती थी। दूसरे

दिन यह स्पष्ट हो गया कि गाघीजी की स्थिति को वाइसराय समझते तो है, लेकिन उनके अनुसार करने को तैयार नहीं है। चूकि इग्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए बात-चीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावना पैदा हो गई, स्वय वाड्सराय ने गांधीजी को दुवारा शनिवार २१ तारीख को बुलवाने के लिए कहा। लेकिन गुरुवार १६ तारीख को एकाएक बुलावा आ पहुचा। इवर सरकार और काग्रेस के वाच चलने वाली वातचीत के दौरान में उठने वाले विविव-विषयो के विचारार्थ १२ व्यक्तियो का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिसको सख्या वाद में वढकर तीस हो गई। वाइसराय लन्दन से इस विषय मे तार आने को प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए इस सम्मेलन को २४ ता० तक ठहरना पडा। वहुत प्रतीक्षा के वाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का वुलावा आ ही पहुचा। २६ ता० को गाघीजी वाइसराय के पास गये और साढे-तोन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ और मित्रता-पूर्वक वातचीत हुई। २८ ता० को, वाइसराय की इँच्छानुसार, गाधीजी ने पिकेटिंग के वारे मे उन्हें अपना मन्तव्य भेजा और वाइस-राय ने प्रस्तावित समझौते के वारे मे अपने कुछ विचार गाघोजी को लिख भेजे। समझौते के सिलसिले में उठी प्रत्येक वात पर वाइसराय ने गाघोजी के निश्चित विचार जानने चाहे और इसके लिए १ मार्च के दिन दोपहर के २।। वजे उन्हें वाइसराय-भवन में मिलने के लिए बुलाया। १ मार्च को हालत एकदम निराशा-जनक मालूम पडने लगी। निश्चित समय पर गाघीजी वाइसराय से मिले और सायकाल ६ वजे वाइसराय-भवन से वापस आ गये। इतने थोडे समय मे उनके लौट आने से एकदम निराशा छा गई, लेकिन शीघ्र ही समझौते की फिर से आशा वंघने लगी। १ मार्च के तीसरे पहर जब गाधीजी वाइसराय से मिले तब वाइस-राय का रुख बिलकुल दोस्ताना था। होम-सेकेटरी मि० इम्सेन भी बडी अच्छी तरह पेश आये। वाइसराय ने गायीजी से कहा कि मि० इमर्सन के सलाह-मशिवरे से वह पिकेटिंग के बारे में कोई हल सोचे।

श्राशाजनक परिस्थिति

इतने समय के वाद अब सम्भवत हम यह कह सकते हैं कि यिश अधिकारों की भावना के ऊपर कर्तव्य-भाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझोता विलकुल ही न हुआ होता। पिकेटिंग के बारे में वहस-तलब एक बात यह थो कि सारे "विदेशी माल के खिलाफ को जाय या ब्रिटिश माल के ?" दूसरी बात उसके लिए ग्रहण किये जानेवाले साधनों के बारे में थी। सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड अविन ने गांधीजी और मि॰ इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया।

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सन्तोषजनक

रही। गांधीजी ने नजरबंदो का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं, पर वैयिक्तिक रूप में वह उनके मामलों को तहकीकात अवश्य करेंगे। जब्त सम्पत्ति के वारे में तय हुआ कि उसमें से जो विक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती। गांधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिले, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीवो वातचीत चलाने के लिए तैयार नहों है। मगर जब्त जमीनों के वारे में वम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशो-चिट्ठी गांबीजी को देने का वाइसराय ने बादा किया। नमक के बारे में तो स्थिति अच्छो हो रही। जिन जगहो पर नमक अपने-आप तैयार होता हे वहा से आजादों में नमक लने-देने का वाइसराय ने आग्वासन दिया। यह एक ऐसी सुविवा थो जो गांबोजी के लिए वडी सतीप-जनक हुई। पुलिस को ज्यादितयों के प्रश्न पर दोनों हो अड गये। गांघीजी ने इस सम्बन्ध में अपने को कार्य-सिमिति पर ही छोड दिया। वाइसराय से बातचीत करके वह १ वजे वापस आये और रात के २। वजे तक कार्य-सिमिति के सदस्यो तथा अन्य मित्रों के सामने भाषण देते रहें। वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिकेटिंग के बारे में उसो रात एक हल निकल आया, लेकिन उस पर और विचार करने के लिए ३ मार्च का दिन तय रहा, क्योंकि २ मार्च को सोम-वार पडता था, जो गांधोजी का मौन-दिवस था।

समझौते को जो आशा थी, ३ मार्च को उसमें एक और वडी किठनाई उत्पन्न हो गई। वारडोजो के किसानो की जमोन लीटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अव फिर उस मामले को उठाया गया। वाइसराय की भी अपनी किठनाइया थी। जव वारडोली में करवन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तव उन्होंने वम्बई-सरकार को एक पत्र में लिखा था, कि चाहे कुछ हो, मैं किसानों की जन्त जमीने लीटाने के लिए कभी नहीं कहूगा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि अव उनसे विलकुन उलटो वात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने चाहा कि गामीजों सर पुरुषोत्तमदास और सर इहाहीम रहीमतुल्ला ने इसके लिए वीच में पड़ने को कहे, और आजा प्रकट की कि सब ठीक हो जायगा। गायोजी ने जाहा कि वाइसराय स्वयं ऐना करें। आखिरकार वाइसराय वम्बई सरकार के गाम ऐना पत्र तिनने के तिए तैयार हुए कि जमीने प्राप्त कराने के मामले में पूर्वोक्त रोनो महानुभावों की मदद की जाय। इन वातचीत के दौरान में वम्बई सरकार के रेदेन्य-मन्वर भी दिल्ली पहुंचे। वह तत्सम्बंधी वातचीत के लिये बुछाये गये।

समभौता श्रोग उसको विद्यप्ति

गाघीजी बडे उत्साह मे थे। अपने स्वभाव के अनुसार गाघीजी ने उस रात की सव घटनाये कार्य-समिति के सदस्यो को सुनाई। कार्य-समिति के सदस्यो में शाम तक पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूव गरमागरम वाद-विवाद हुआ, क्योंकि उसका पहले-पहल जो मसविदा बनाया गया उसमे मुसलमान दुकानदारो के यहा पिकेटिंग न करने की धारा रखी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोडो-बहुत खामी थी। वल्लभभाई समझौते की जमीन सम्बन्धी अश से सहमत नही थे। जवाहर-लाल को विधान-सम्बन्धी अश नापसन्द था। कैदियो वाली बात पर तो किसी को भी सन्तोष न था। लेकिन यदि प्रत्येक अश ऐसा होता कि उसपर प्रत्येक को सन्तोष हो जाता तो फिर वह समझौता ही कहा रहता, वह तो काग्रेस की जीत ही न होती। जब काग्रेस समझौता या राजीनामा कर रही थी तब ऐसा नही हो सकता कि उसी-उसकी बात रहे। गाधीजी ने कार्य-समिति के प्रत्येक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनो के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या प्रत्येक वात पर, या आप कहे तो समूचे समझौते पर मैं सुलह की वातचीत तोड दू ? समझौते की आखिरी घारा पर, जिसमें सरकारने अपने लिए यह अधिकार रेखा था कि "यदि काग्रेस इस समझौते की बातो पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो उसे (सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा, जो, उसके परिणाम स्वरूप, सर्वसावारण तथा व्यक्तियो की रक्षा औरकानून-व्यवस्था के उपयुक्त अमल के लिए आवश्यक हो," यह ऐतराज उठा कि यह हक दोनो पक्षो के बजाय एक ही के लिए क्यों रखा जाय? दूसरे शब्दों में, ऐतराज करनेवाली का कहना था कि एक घारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समझौते की बातो पर पूरी तरह अमल न कर सके तो काग्रेस सविनय-अवज्ञा को घोषणा कर सकेगी। लेकिन यह समझना कोई बहुत मुश्किल बात नही थी कि काग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की शुरुआत नहीं की थी, इसी तरह उसकी फिर से शुरुआत करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नही थी।

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और काग्रेस के बीच खूब गहरा वाद-विवाद हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप ५ मार्च १६३१ को यह समझौता हुआ। इसकी मुख्य-मुख्य बाते यहा दी जाती हैं —

"सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौसिल-सहित गवर्नर-जनरल का निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है —

(१) विधान-सम्बन्धी प्रश्न पर सम्राट्-सरकार की अनुमित से यह तय हुआ कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा,

जिसपर गोलमेज-परिषद् में पहले विचार हो चुका है। वहा जो योजना वनी थी, सघ-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है।

- (२) १६ जनवरी १६३१ के प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार, ऐसी कार्र-वाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर आगे जो विचार हो उसमें काग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सके।
- (३) सविनय-अवज्ञा अमली रूप मे बन्द कर दी जायगी और (उसके वदले में) सरकार अपनी ओर से कुछ कार्रवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आदो-लन को अमली तौर पर बन्द करने का मतलव है उन सब हलचलो को बन्द कर देना, जो कि किसी भी तरह उसको बल पहुचानेवाली हो।
- (४) विदेशी कपड़ो के वहिष्कार के सर्वध में यह बात तय पाई है कि सविनय-अवज्ञा-आदोलन वन्द करने मे ब्रिटिश माल के विहिष्कार को राजनैतिक शस्त्र के तीर पर काम में लाना निश्चित रूप से वन्द कर देना भी शामिल है, और इसलिए आदोलन के समय में जिन्होंने ब्रिटिश माल की खरीद-फरोस्त वन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय वदलना चाहे तो अवाध-रूप से उन्हे ऐसा करने दिया जायगा।
- (५) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराव आदि नशीली चीजो के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले जपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ऐसे उपाय काम में नहीं लाये जायँगे जिनसे कानून की मर्यादा भंग होती हो।

(६) सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में जो कानून (आर्डिनेन्स)

जारी किये गये हैं वे वापस ले लिये जायंगे।

- (७) १६०८ के किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट के मातहत सस्याओ को गैर-कानूनी करार देने के हुक्म वापस ले लिये जायगे, वशर्ते कि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिल में जारी किये गये हो।
- (५) जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होगे और ऐसे अपराधो से सम्वन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्फ नाम के लिए होगो या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने की वात् हो। यही सिद्धान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती घाराओं के मातहत चलने वाले मुकदमो पर लागू होगी। सैनिको या पुलिस वालों पर चलाने वाले हुवम-उदूली के मुकदमे, अगर कोई हो, इस घारा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयेगे।
- (है) वे कैंदी छोड़े जायंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलिमिले में ऐंगे अपराधों के लिए कैंद भोग रहे होगे जिनमें नाम-मात्र की हिंसा को छोड़ कर भीर किसी प्रकार की हिंसा या हिमा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो।
 - (१०) जुर्माने जो वनुल नहीं हुए है, माफ कर दिये जायंगे। इसी प्रकार

जाब्ता-फौजदारी की जमानती घाराओ के मातहत निकले हुए जमानत-जब्ती के हुक्म के बावजूद जो जमानते वसूल नहीं हुई होगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा। जुर्माने या जमानतो की जो रकमें वसूल हो चुकी है, चाहे वे किसी भी कानून के मुताबिक हो, उन्हें वापस नहीं किया जायगा।

(११) सिवनय अवज्ञा आन्दोलन के सिलिसले में किसी खास स्थान के बाशिन्दों के खर्चे पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनात की गई होगी उसे प्रानीय सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा। इसके लिए वसूल की गई रकम, यि असली खर्चे से ज्यादा हो तो भी लौटायी नहीं जायगी, लेकिन जो रकम

वसूल नही हुई है वह माफ कर दो जायगो।

(१२) वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में आर्डिनेन्सो या फोजदारी-कानून की धाराओं के मात-हत अधिकृत की गई है, यदि अभी तक सरकार के कब्जे में होगो तो लौटा दी जायगी। जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगो या सरकार-द्वारा अतिम रूप से जिसका भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी बिकी से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी।

(१३) जिस अचल-सम्पत्ति पर १६३० के नवे आर्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया गया है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार लौटा दिया जायगा। जहा अचल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी, जहातक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा अन्तिम समझा जायगा।

(१४) जिन लोगो ने सरकारी नौकरियो से इस्तीफा दिया है उनके रिक्त-स्थानो की जहा स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहा सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति को पुन नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगो के मामलो पर उनके गुण-दोष की दृष्टि से प्रातीय सरकारे विचार करेगी।

(१५) नमक-व्यवस्था सम्बन्धी मौजूदा कानून के भग को गवारा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए

नमक-कानून में ही कोई खास तब्दोली की जा सकती है।

(१६) यदि काग्रेस इस' समझौते की बातो पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगो जो, उसके परिणाम-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियो के सरक्षण एव कानून और व्यवस्था के उप-युक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी।"

गांधीजी का वक्तव्य

समझौते से निबटते ही गांधीजो ने, ५ मार्च की शाम को अमरीकन, अग्रेज व भारतीय पत्रकारो और प्रेसमैंनो के एक समूह के सामने एक युगान्तकारी वक्तव्य दिया। पूरा वक्तव्य लिखाने मेगांधीजी को कुल डेढ घण्टा लगा। वक्तव्य गांधीजी ने मुह-जवानी ही लिखाया था और उसमे कही भी एक-बार भी रद्दो-बदल नही किया। इस वक्तव्य में उन्होने लॉर्ड अविन की उचित प्रशंसा की और पुलिस, सिविल-सर्विस तथा क्रातिकारियों से उपयुक्त अपील को। उन्होंने कहा कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायो होना स्वाभा-विक ही है। यह जो सिन्ध हुई है वह कई बातो कः पूर्ति होने पर निर्भर है। काग्रेस गोलमेज-परिषद् में भाग ले सके, इसके पहले कई बातो का पूरा हो जाना आवश्यक है। काग्रेस का ध्येय तो पूर्ण स्वराज्य है, जिसको अंग्रेजी मे अनुवाद करके 'पूर्ण स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रो की भाति भारत का यह जन्म-सिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। सब-शासन (फेडरेशन) मृगतृष्णा भी हो सकता है, अथवा एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जिसके दोनो हाथ इस प्रकार कार्य करते हो कि उनसे उसका शरीर मजबूत बन जाय। इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है वह या तो बिल्कुल छाया के समान नि सार है या बडा ऊंचा, विशाल अथवा न झुकने वाले वरगद के पेड के सदृश हो सकता है। एक दल इन तीन पायो का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। इस धारा के अनुसार दोनो दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। काग्रेस ने परिषद् की कार्रवाई में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि वह संघ-शासन, उत्तरदायित्व, संरक्षण, प्रतिबन्ध अथवा उन्हें जिन नामों से पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उनसे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हो। यदि परिषद् ने काग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर मान लिया, तो मेरा दावा है, कि इसका परिणाम 'पूर्ण-स्वाधीनता' होगा। लेकिन में जानता हू कि यह मार्ग बहुत कठिन और थका देनेवाला है। मार्ग में बहुत-सी चट्टाने हैं और बहुत से गड्ढे हैं। लेकिन यदि काग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास एव उत्साह के साथ करेगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता। अत् यह उन्हीं के हाथ मे है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-से-अच्छा उपयोग करे।

अपने वन्तव्य में गांघीजी ने अंग्रेजो से भी अपील की। उन्होंने कहा कि यदि भारत को परिषदो तथा विचार-विमर्ज द्वारा ही अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अंग्रेजो की सद्भावना एवं सिक्तय-सहायता की वड़ी आव-व्यकता होगो। मुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि लदन में पहली परिपद् में जिन-जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वे तो उस घ्येय की आधी भी नहीं है जिस घ्येय तक भारत पहचना चाहता है। यदि अग्रेज वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। उन्हें इस बात के लिए

तैयार होना पडेगा कि वे भारत को गलतिया करने के लिए छोड दे। यदि गलती करने की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी, स्वतन्त्रता किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नही आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होगे जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यो न हो, दूसरी जाति के मनुष्यो के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं?

अमरीकन-राजतन्त्र तथा ससार के अन्य राष्ट्रों की जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा—"मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने जिसका आधार सत्य और अहिंसा है—उनके मन पर वडा असर डाला है और उनमें उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं, वे इससे भी आगे वढे हैं। उन्होंने और खासकर अमरीका ने सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद की है। काग्रेस को ओर से और अपनी ओर स मैं कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके वहुत आभारी हैं। मुझे आशा है कि काग्रेस अब जिस मुश्किल काम में पडनेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी बिल्क वह दिन-प्रति-दिन बढती भी जायगी। मैं वडी नम्रता से यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यदि सत्य एव अहिंसा के द्वारा भारत अपने घ्येय तक पहुच गया तो जिस विश्व-शांति के लिए ससार के सब राष्ट्र तड़प रहे हैं, उसके हित में वडा भारी काम कर दिखायेगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी खोलकर जो सहायता दी है, उसका कुछ थोडा-सा बदला भी चुक जायगा।"

गांधोजी ने आखिरी अपील पुलिस तथा सिविल-सर्विस. अर्थात् सरकारी अधिकारियो से की। उन्होंने कहा—"समझौते में एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ ज्यादितयों की जाच की मांग की थी। इस जाच की मांग को छोड देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा पुलिस द्वारा शासन की जो मशीन चलती रहती है उसका सिविल सर्विस एक अभिन्न अग है। यदि वे वास्तव में यह महसूस करते हैं कि भारत शीध्र ही अपने घर का मालिक बननेवाला है और उन्हें बफादारी तथा ईमानदारी से भारत सेवकों की तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोभा देता है कि वे अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि सिविल-सर्विस तथा पुलिसवाल उनके सेवक हैं।"

जेल में पड़े बन्दियों के बारे में गांधीजी ने कहा—व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के जो हिंसा करने के दोषी है, जेल भेजे जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेगे कि मैं न्यायपूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे अथवा कार्य-समिति के सदस्यों को उनका खयाल ही नहीं है।

अन्त में गाधीजी ने कहा कि काग्रेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर

ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहण किया है। यदि काग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन शर्तों को जो उनपर लागू होती है, पूरी-पूरी तरह से पालन करें तो काग्रेस का गौरव बहुत बढ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्का बैठ जायगा कि जहा काग्रेस ने, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहा उसमें शान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है। मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मैने लार्ड अविन को अपना वचन दे दिया है कि मैं समझौते की शर्तों को, जहातक उनका काग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुट जाऊगा। मैने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालू, बिक्क इसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे विलकुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोडू और उसे उस ध्येय तक पहुचाने वाला पेशवा समझू जिसे प्राप्त करने के लिए काग्रेस कायम हैं।

पत्रकारों से भेंट

उक्त वक्तव्य के पश्चात् दूसरे दिन, गांशीजी ने कई पत्रकारों से भेट की। ६ मार्च १६३१, दिल्ली में ११।। वजे भारत तथा विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित थे। गांशीजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर अमरीका के 'असोशिएटेड-प्रेस' के श्री जेम्स मिल्स, 'लन्दन-टाइम्स' के श्री पीटरसन, 'शिकागों ट्रिब्यून' के श्री शिरार, 'वोस्टन ईविनग ट्रासिकप्ट' के श्री हाल्टन जेम्स, 'किश्चियन साइन्स मॉनीटर' (अमरीका) के श्री० इंगल्स, 'हिन्दुस्तान-टाइम्स' के श्री जे० एन० सहानी, और 'पायोनियर' व 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के श्री नीडहम आदि पत्रकार उपस्थित थे। कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहा दिए जाते हैं —

प्रश्न-आपने अपने कल वाले वक्तव्य में 'पूर्ण स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूली तौर से 'पूर्ण-स्वाधी-नता' होता है। सो 'पूर्ण-स्वराज्य' की आपकी सही व्याख्या क्या है? उत्तर-में आपको इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा

जत्तर—में आपको इसका ठीक उत्तर नही दे सकता, क्यों कि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं जो, 'पूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके। स्वराज्य का मूल अर्थ तो स्व-राज्य अर्थात् स्व-शासन है। 'स्वाधीनता' से इस प्रकार का कोई मतलव नहीं निकलता। स्वराज्य का मतलव है आत्म-नियत्रित-शासन और पूर्ण का मतलव है पूरा। कोई वरावरी का शब्द न मिलने के कारण हमने अंग्रेजी में complete independence (पूर्ण-स्वाधीनता) शब्दों को चुन लिया है जिन्हें हर कोई समझता है। 'पूर्ण-स्वराज्य' का यह मतलव नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैण्ड से ही कहिए, सम्बन्च नहीं रखा जा सकता। विकित यह सम्बन्य स्वेच्छा से और दोनों के फायदे के लिए ही हो सकता है।

प्रश्न-समझौते की दूसरी धारा को देखते हुए क्या काग्रेस के लिए युक्ति-सगत होगा कि वह पूर्ण-स्वाधीनता के प्रस्ताव को, जो उसने मद्रास, कलकत्ता, तया लाहीर के अधिवेशनों में पास किया था, फिर से दोहराये ?

उत्तर-अवश्य ही, क्योंकि कराची-काग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रस्ताव पास करने से रोकने की और आगामी गोलमेज-परिषद तक में उसपर जोर देने

से रोकने की कोई शर्त नहीं है।

प्रश्न--द्वितीय गोलमेज-परिषद् का भारत में होना आप पसन्द करते हैं या इग्लैड मे?

उत्तर-परिस्थिति पर इसका दारोमदार है। मेरा अभी कोई खास विचार नहीं है। मोटे तौर पर मैं यह चाहूगा कि गोलमेज-परिषद् का पूर्वाई भारत में हो और फिर उसकी समाप्ति लेन्दन में हो।

प्रश्न-क्या आप नियमित रूप से परिषद् में भाग लेगे ?

उत्तर-में आशा तो करता हू और शायद हो भी यही।

प्रक्त--क्या आप परिषद् में 'पूर्ण-स्वराज्य' के लिए जोर देगे ?

उत्तर-यदि हम उसके लिए जोर न दें तब तो हमें अपने अस्तित्व से ही इन्कार कर देना चाहिए।

प्रश्न-क्या आप इस समझौते को अपने अबतक के जीवन की सबसे वडी

सफलता समझते हैं ?

उत्तर (हसकर) — मुझे यही मालूम नहीं कि मैंने जीवन में अबतक कौन-कौनसी सफलताये पाई और यह उनमें से एक है या नहीं?

प्रश्न-यदि आप 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त कर ले तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता मान सकेगे?

उत्तर—मैं समझता हू कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे अवश्य ऐसा मानूगा। प्रश्न—क्या आप अपने जीवन-काल में 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते है ?

उत्तर-यकीनन । जरूर । (मुस्कुराते हुए) पाश्चात्य विचारो के अनुसार

तो मै अपने को ६२ साल का युवक मानता हू।

प्रश्न-क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशी-कपडे का बहि-

ष्कार ढीला कर देना चाहिए?

उत्तर-नही, कदापि नहीं। विदेशी कपडे का बहिष्कार राजनैतिक अस्त्र नहीं है। यह तो भारत के एकमात्र सहायक धन्धे चर्खे की उन्नति के लिए है। उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत-आगमन से सम्बन्ध रखता है।

प्रश्न--परिषद् में जाने से पूर्व क्या आप हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलझा

लेने की आशा करते हैं?

उत्तर—यह मेरी आकाक्षा तो है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहा तक पूरी हो सकेगो। परिषद् में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल है।

प्रश्न-क्या हिंदू-मुस्लिम-एकता स्थापित करने में बरसो लगेगे?

उत्तर—नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हिन्दू तथा मुसलमान जनता में कोई नाइत्तिफाकी नहीं है। नाइत्तिफाकी केवल सतह पर है और इसका अधिक महत्त्व इसलिए है कि सतह पर जो आदमी हैं, वे वहीं है जो भारत के राजनैतिक दिमाग के प्रतिनिधि है।

प्रश्न-क्या आप इस वात की सम्भावना देखते हैं कि जव 'पूर्ण-स्वराज्य' मिल जायगा तो राष्ट्रीय-सेना हटा दी जायगी?

उत्तर--गगन-विहारी आदमी का उत्तर है तो अवश्य, लेकिन मेरा विचार है कि मैं अपने जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकूगा। विलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुचने के लिए भारतीय-राष्ट्र को कई युगो तक ठहरना होगा। सम्भव है कि श्रद्धा की कमी के कारण ही मेरी यह शकाशीलता हो। लेकिन ऐसी सम्भावना असम्भव नही। वर्तमान सामूहिक जागृति की तथा अहिंसा पर लोगो के डटकर कायम रहने की-अपवादों को छोड दीजिये-किसे आशा थी ? इसी बात से मुझे कुछ आशा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि अब हमें किसी सेना की जरूरत नहीं। मुल्की कामो के लिए पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिए।

प्रश्न-क्या आप भावी सरकार के प्रधान मंत्री वनना स्वीकार करेंगे? उत्तर—नही। यह पद तो नीजवानो और मजबूत आदिमयो के लिए है। प्रश्न—लेकिन यदि जनता आपको चाहे और अड जाय, तो ? उत्तर—तो मैं आप जैसे पत्रकारो की शरण ढूँढूगा। (हसी) प्रश्न—"यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो क्या आप सब मशीनरी

उडा देगे?" एक अमेरिकन पत्रकार ने पूछा।

उत्तर-नहीं, विलकुल नहीं। उड़ा देने के वजाय मैं तो अमरीका को शायद भार भी अधिक मशीनरी का आंडर दूगा (हसी) और कौन कह सकता है कि में ब्रिटिश मशीनरी को ही तरजीह दू? (और अधिक हंसी)
प्रश्न—स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लांडेगे?

उत्तर-मेरा विचार केवल आश्रम देखने का है। जवतक पूर्ण-स्वराज्य

पा मेरा वत पूरा न हो जायगा तवतक मैं आश्रम में नही रहूंगा। परन सेना-सम्बन्धी प्रश्न के आपके उत्तर से क्या यह निष्कर्ष निकाला ना सकता है कि आप इस बात की सम्भावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेचीद-िंगो को सुनज्ञाने में अहिंसा उपयोगी वस्त्र हो सकता है?

उत्तर—अगर ससार के अन्य राष्ट्रों की भाति भारत में भी सेना हो तो, मेरा खयाल है, कि अहिंसा ऐसा अस्त्र वन जायगा। सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होगा। कार्य तो सदा घीरे-घीरे होता है। ज्यो-ज्यों समय जायगा, राष्ट्र विचार-विमर्श तथा पचायती फैसलों पर अधिकाधिक विश्वास करेंगे और शनै शनै सेनाओं पर कम। सम्भव है कि सेनाये केवल दर्शन-मात्र की ही चीज रह जाय, जिस प्रकार खिलौने पुरानी किसी चीज के अवशेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रक्षा के साधन।

कांग्रेस की हिदायतें

समझौता होते ही काग्रेस-किमटियो तथा सस्थाओ पर से रोक उठा ली गई और वे फिर से जीवित हो गई। महासमिति के प्रवानमत्री ने काग्रेस के आगामी अधिवेशन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के चुनाव के वारे में अपनी सूचनायें काग्रेस-वादियों के पास भेजी। कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक जिले से दो प्रकार के प्रतिनिधि चुने जाय। आधे प्रतिनिधियो का चुनाव तो वे व्यक्ति करे जिन्हे आन्दोलन में सजा मिल चुकी हो, और शेष का चुनाव साधारण नियमों के अनुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिदायते जारी की गई। जेल हो आने वालो का चुनाव एक सभा बुलाकर करना था। वगाल के प्रतिनि-धियो के चुनाव के निर्णायक श्री अणे नियत किये गये थे। उसी दिन काग्रेस-वादियों को यह भी हिदायत दी गई कि वे सविनय-अवज्ञा, करबन्दी-आदोलन और ब्रिटिश-माल के बहिष्कार को बन्द कर दें। लेकिन नशीली चीजो, सब विदेशी कपड़ो व शराब की दुकानो के बहिष्कार की इजाजत दे दी गई और उन्हें जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि पिके-टिग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमे दबाव न रहना चाहिए, विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के मार्ग में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए और देश के साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के प्रकाशन बन्द करने का आदेश भी हुआ। इस प्रकार समझौते की हरएक मद के सम्बन्ध में हिदायते जारी की गई और स्वय गाधीजी ने उन आदेशों के साथ वे शर्तें जोड़ दी जो शराब तथा विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयसेवको को माननी चाहिए।

करांची-कांग्रेस : १६३१

कार्य-सिमिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को कराची-काग्रेस के सभापित-पद के लिए चुन लिया, क्योंकि करीब एक साल तक काग्रेस की जो साधारण परिस्थिति थी उसके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापित का चुनाव होना सम्भव न था। कराची-काग्रेस के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कोई आसान काम न था।
यद्यपि १ मार्च के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा दिखाई देने लगा था, तो भी अस्थायी-सिन्ध के
भाग्य ने कराची-काग्रेस के प्रबन्धकों की स्थिति बड़ी असमजस में डाल दी था। एक
सुभीता अवश्य था—और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाडे रह गये थे। अधिवेशन के मार्च में करने से पडाल की भी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि काग्रेस
अब खुले मैंदान में हो सकती थी। केवल एक सभा-मञ्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के चारो ओर एक घेरा डालने की।

कराची-अधिवेशन के प्रवन्ध की सफलता का बहुत अधिक श्रेय कराची की म्युनिसिपैलिटी को था जिसने जमशेद मेहता की अध्यक्षता एवं संचालकत्व में कार्य किया। काग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई, जिसमें चार आने की प्रवेश-फीस देने वाले गाधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे। इस प्रकार १०,०००) इकट्ठा हुआ।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सभापितत्व किया। उन्होंने अपने छोटे से अभिभाषण में सभापित चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं, किन्तु गुजरात को, जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक वडा भाग लिया था, प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि काग्रेस ने गाधी-अविन-समझौता न किया होता तो उसने अपने-आपको गलती में रख दिया होता। उन्होंने समझौते का वास्तविक महत्व समझाते हुए यह वताया कि समझौते के रहते हुए काग्रेस-वादियों का क्या कर्त्तव्य हैं।

कर ची-काग्रेस जो एक सर्व-व्यापी आनन्दमयी छटा के साथ होने जा रही थी, वा स्तव में विवाद और सन्ताप की घनघोर घटा से घिरकर हुई। काग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन नौजवान भगतिंसह, राज-गुरु तथा सुखदेव फासी के तख्ते पर चढाये जा चुके थे। इन तीन युवको की आत्मायें उस समय काग्रेस-नगर पर मंडराती हुई लोगो को शोक-सन्ताप में डुवो रही थी। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि भगतिंसह का नाम भारत-भर में उतना ही लोकपिय था जितना कि गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधीजी इन तीन युवकों की फासी की सजा रद नहीं करा सके थे। लेकिन जो लोग दन तीनो युवकों की जान बचाने के गांधीजी के प्रयत्नों की अभीतक प्रयत्ना कर गई थे, अब इस बात पर बेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनो शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जाने वाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो। पडित मोतीलाल नेहरू, मांलाना मुहम्मद जुनैर तथा गुरनन्वा मुदालियर की मृत्यु पर शोक प्रकाशित करने के पश्चात् सबसे पहने तथा गुरनन्वा मुदालियर की मृत्यु पर शोक प्रकाशित करने के पश्चात् सबसे पहने

जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतिंसह के सम्बन्ध में था। इस प्रस्ताव में बहस एव मतभेद की केवल यही बात थी कि भगतिंसह तथा उनके साथियों की वीरता और आत्मत्याग की प्रशसा करते हुए ये शब्द कि 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव में जोडे जाय या नहीं?

दूसरा प्रस्ताव जिस पर काग्रेस ने विचार किया, वह विन्दियों की रिहाई के बारे में था। उस समय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि विन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कजूसो-जैसी नीति ही नहीं बरत रही हैं, विल्क उन वादों से भी मुकर रही हैं और उन शर्तों को भी तोड रही है जो उसन समझौतें के सिल-सिले में की थी। इसिलए काग्रेस ने अपना यह दृढ मत प्रकट किया कि यदि सरकार और काग्रेस के समझौतें का उद्देश ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भाव बढाना है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन को शासनाधिकार छोड़ने की इच्छा को वास्तिविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बन्दियों, नजरबन्दों तथा विचाराधीन बन्दियों को, जो समझौता की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दें और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हो या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण, लगा रखी हैं। काग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि यदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो जनता का वह रोष जो हाल की फासियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।

गणेश शंकर की हत्या

भगतिंसह आदि की फासियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने कराचीकाग्रेस में उदासी के बादल छा दिये थे। जब इधर काग्रेस का अधिवेशन हो रहा
था, कानपुर में जोरों का हिन्दू-मुस्लिम-दगा शुरू हो गया और श्री गणेश शकर
विद्यार्थी शान्ति एव सद्भाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओं के रोष
से बचाने के प्रयत्न में मारे गये। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं थीं जो साम्प्रदायिक
कलहों के लिए बदनाम रही हो। १६०७ में एक इक्की-दुक्की मार-पीट हुई थीं
और फिर १६२८ तथा २६ में। भगतिंसह तथा उनके साथियों को लाहौर में
२३ मार्च को जो फासी दी गई थीं उसके सबध में देश-भर में हडताले की गई।
कानपुर में हडताल पूरी नहीं हुई। हिन्दुओं ने तो अपनी दुकाने वन्द कर दी, लेकिन
मुसलमानों ने नहीं की। कुछ समय पहले जब मौं० मुहम्मदअली मरे थे उस समय
हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हडताल में भाग नहीं लिया था। बस, अधिक कहने
की जरूरत नहीं—चिंगारी भी मौजूद थीं और बारूद का ढेर भी मौजूद था।
२४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च की रात

को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्निकाण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानो और मन्दिरो में आग लगा दी गई और वे जल-जल कर खाक हो गये। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, मार-काट, अग्निकाण्ड, हुल्लडवाजी का वाजार गरम हो गया। लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़-छोड कर आस-पास के गावो में जा बसे। काग्रेस ने वावू पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा अन्य कुछ मित्रो को शीघ्र ही कानपुर घटना-स्थल पर भंजा, लेकिन शान्ति के वातावरण को वापस लाना सहज न था। श्री गणेशशकर विद्यार्थी २५ ता० से लापता थे। उनकी लाश का पता २६ ता० को लगा। उन्होंने उस दिन कई मुसलमान परिवारो को वचाया था। पता चलता है कि उन्हें फसा कर किसी स्थान पर ले जाया गया था जहा वे विना किसी सकोच के चले गये और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की भाति कुद्ध भीड के सामने उन्होंने अपना सिर झुका दिया। काग्रेस ने इस शोक-भरी घटना पर भी एक प्रस्ताव पास कियाऔर डा० भगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक किमटी नियुक्त की। किमटी ने एक मोटी रिपोर्ट तैयार करके कार्य-सिमिति के सामने पेश को, जो बहुत दिनो वाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका विवरण रोक दिया।

श्रन्य प्रस्ताव

इसके पश्चात अस्थायी सिन्धवाला प्रस्ताव आता है जो एक मुकिम्मल नीज है। इसमें काग्रेस का दृष्टि-कोण दर्शाने के साथ-साथ काग्रेस की ओर से वह वात भी स्पष्ट कर दी गई जो गाधी-अविन-समझौते में अस्पष्ट अथवा सन्देहास्पद समझी गई थी। इसके वाद काग्रेस ने उन सव व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, बधाई दी जिन्होंने गत सिवनय-अवज्ञा-आन्दोलन में महान् कष्ट उठाये थे। महात्मा गाधी को काग्रेस ने गोलमेज-परिपद् के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और यह निश्चय किया कि उनके अतिरिक्त जिन्हें काग्रेस-फार्यसमिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में काग्रेस का प्रतिनिधित्व करेगे। अन्य प्रस्ताव साम्प्रदायिक उपद्रव, पूर्ण मद्य-निषेच, खादी-प्रचार, शान्तिमय घरना आदि के सवध में थे।

मोलिक अधिकार का प्रस्ताव

यहा यह कह देना शेप हैं कि 'मांलिक अधिकारो तथा आर्थिक व्यवस्था' पाना प्रस्ताव कार्य-समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेश हुआ था। मांलिक अधिकारों का प्रश्न सबसे पहले श्री चन्नवर्ती विजय राघवाचार्य ने अमृतसर-काग्रेस में ज्ञाया था। एव दूसरे साल नागपुर में काग्रेस-अधिवेदान के वह न्दय समापति दने तब इस प्रदन को और महत्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रौढ़- वर्ग में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद-सा था। यह सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए और कार्य-सिमिति तथा महासमिति के सदस्यो द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए। यह सलाह मान ली गई। इसलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के सिद्धान्तो तथा उसको नीति को आघात पहुँचाये विना उसमे रहो-वदल करे। वम्वई मे, अगस्त १६३१ मे, महासमिति ने मूल प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये। इसके वाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ वह इस प्रकार था

सर्वसाधारण के ऋधिकार

(१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय मे, जो कि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र सस्याये तया सघ बनाने और विना हथियार के एव शातिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वजनिक शान्ति और सदाचार में बाघक न होनेवाले धार्मिक विश्वास और

आचरण की स्वतन्त्रता है।

(३) अल्पसंख्यक जातियो और भिन्न भाषा-भाषी वर्ग की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी।

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि मे बिना किसी धर्म, जाति,

विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान है।

(५) सरकारी नौकरियो, अधिकार और सम्मान के पदो और किसी भी व्यापार या घन्धे के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास

अथवा लिंग के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जायगा।

(६) सरकारी अथवा सार्वजिनक खर्च से बने अथवा नागरिको-द्वारा सार्व-जनिक उपयोग के लिए समर्पित कुओ, सडको, पाठशालाओ और सार्वजनिक आवागमन के स्थानो के सम्बन्ध में सब नागरिको के समान अधिकार और कर्त्तव्य है।

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनु 🔆

सार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और घारण करने का अधिकार है।

(५) कानुनी आघार के बिना किसी तरह किसी भी मनुष्य की स्वतन्त्रता न छीनी जायगी और न किसी के घर और जायदाद मे प्रवेश और कुर्की या जब्ती की जायगी।

(६) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ होगी।

(१०) वालिग उमर के तमाम मनुष्यों को मताधिकार होगा।

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

- ' (१२) सरकार किसी को खिताव न देगी।
 - (१३) मीत की सजा उठा दी जायगी।
- (१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर मे अमण करने, उसके किसी भाग मे ठहरने या वसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या घंघा करने में स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के विषय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा।

श्रमिक वर्ग के श्रधिकार

- (१) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एवं अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परिस्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के बीच झगडों के निपटारें के लिए उपयुक्त साधन और बुढापा, बीमारी तथा बेकारी के आर्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी।
 - (२) दासत्व या लगभग दासत्व-जैसी दशा से मजदूर मुक्त होगे।
- (३) मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त छुट्टी का विशेष प्रवध होगा।
- (४) स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानो और कारखानो में नौकर न रक्खे जायंगे।
- (५) किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अधिकार होगे।

कर श्रोर व्यय

- (१) जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका वदला जायगा और छोटे किसानो को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी से तुरन्त और यदि अराजी से लाभ न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृपको के बोझ का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा।
- (२) एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमागत विरासत-कर लिया जायगा।
- (२) फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्तमान व्यय से वह कम-से-कम आधा रह जायगा।
- (४) मुल्की-विभाग के व्यय और वेतन में वहुत कमी की जायगी। खास तोर पर नियुक्त किये गए विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी

भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) मातिक से अधिक न होनी चाहिये, अधिक वेतन न दिया जायगा।

(५) हिन्दुस्तान में वने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

श्राधिंक श्रौर सामाजिक कार्यक्रम

- (१) राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायो का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी घन्यों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रति-योगिता से रक्षा करेगा।
- (२) औषधियों के काम के सिवा, नशीलें पेय और पदार्थ सर्वथा वन्द कर दियें जायगे।

(३) हुण्डावन और विनिमय का नियंत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा।

(४) मुस्य उद्योगो और विभागो, खनिज साघनो, रेलवे, जल-मार्ग, जहाज-रानी और सार्वजनिक आवागमन के अन्य साघनो पर राज्य अपना अधिकार और नियन्त्रण रखेगा।

(५) कृषको के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष रूप से लिये जाने वाले ऊचे दर के व्याज पर सरकार का नियत्रण होगा।

(६) नियमित सेना के सिवा, राष्ट्र-रक्षा का साधन संगठित करने के लिए राज्य नागरिको की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

कार्य-सिमिति की वैठक

गाघी-अविन समझौते की सफलता तथा इससे भी अधिक कराची के प्रस्तावों को सफलता गाघीजी तथा काग्रेसके भारी वोझो को और भी अधिक वोझीला वनाती-गई। कराची-काग्रेस में एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे रह गए थे जिन्हें उसने कार्य सिमित एवं महासमिति के लिए छोड दिया था। सिक्खों ने राष्ट्रीय झण्डे तथा उसमें उनके लिए समाविष्ट किये जानेवाले रग के प्रश्न को उठाया। यह प्रश्न पहले लाहौर में भी उठाया जा चुका था, कराची में इसे और भी अधिक महत्व मिला। चूकि काग्रेस का अधिवेशन ऐसी तफसील पर विस्तार-सहित विचार नहीं कर सकता था, अत उसे काग्रेस की कार्य-समिति के सुपुर्द किया गया। नई कार्य-समिति ने, जिसकी वैठके १ और २ अप्रैल को हरचन्द्रराय-नगर में हुई, इस आपित की जाच कराने के लिए कि राष्ट्रीय-झण्डे के रग साम्प्रदायिक आघार पर निर्घारित किये गये हैं अथवा नहीं, और यह सिकारिश करने के लिए कि काग्रेस कोन-सा झण्डा स्वीकृत करे, एक किमटी नियुक्त करने का निश्चय किया। किमटी को गवाहिया लेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १६३१ से पहले उसकी रिपोर्ट मागी गई।

को शराब न पीने और विदेशी कपड़े से तन न ढकने की शिक्षा देने लगे थे और ये सब बाते उसी सिपाही की आखो के सामने होने लगी थी जो कल इन लोगो पर मिडिय की तरह दूटता था। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले निराशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदो रोज छोड़े जा रहे थे। उन्हें मालाये पहनाई जाती थी, उनके जलूस निकाले जाते थे। वे भाषण देते थे। अब उनके व्याख्यानों में विजय की व्विन और ललकार को भावना होतो थी। १८ अप्रैल को लार्ड अविन ने भारत से प्रस्थान किया और गाधीजी ने बम्बई में उन्हें विदाई दी। वाइसराय-भवन के व्यक्ति बदल गये।

१७ अप्रैल को नए वाइसराय लार्ड विलिगडन ने चार्ज लिया। वह देश की स्थिति से अन्नभिन्न थे। देश के हाकिम समझौते को अपनी हतक-इज्जत समझते थे। इसलिए प्रतिदिन काग्रेस के दफ्तरों में यह शिकायते आती थी कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता। गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न आई थो। पूर्वी गोदावरी के वादपल्ली में बहुत दुखद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये थे और कई घायल हो गये थे। यह गोली-काड महज इसलिए हुआ था कि लोगो ने एक मोटर पर गाधीजी का चित्र रक्खा था और पुलिस इस पर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघ्र ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-काड में बदल गई। लाठिया और गोलिया चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वह इसके बिना रह नहीं सकती थी।

कार्य-समिति की बैठक

जब काग्रेस ने अस्थायी सिंघ की थी, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दशा में हमारी मददगार होगी। लेकिन ये सब उम्मीदे नाकामयाब हुईं। गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहा हिन्दू-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने की बिनस्बत भारत में ही रहना अधिक उपयुक्त है। फिर भी, कार्य-सिमिति ६, १० और ११ जून १६३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी मुसलमान मित्रों के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया—

"सिमिति की यह सम्मिति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिलें तो भी काग्रेस के रुख के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से वचने के लिए महात्मा गांधी गोलमेज-परिषद् में काग्रेस की ओर से प्रतिनिधि-

त्व करे, यदि वहाँ काग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो।"

कार्य-सिमिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत मे नहीं, तो इग्लैण्ड मे अवश्य समझौता हो जायगा। उसने मौलिक-अधिकार, उप-सिमिति और सार्वजिनिक ऋण-सिमिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी और मिल के सूत से बने कपड़े के व्यापारियो तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनो बहुत बढ़ गई थी, बन्द कर दिया। कुछ काग्रेस-सस्थाये विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे रही थी। उनको बुरा बताया गया। श्री नरीमैन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार करें जो कि अस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते और उसे गांधीजी के सामने पेश करें।

गांधीजी की चेतावनी

अस्थायी-सिन्य और उसकी शर्तों के पालन के सबध में गाधीजी ने सारे देश के काग्रेसियों को झगड़ा न शुरू करने की, पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी दी। गाधीजी पस्त-हिम्मती के भारी शैतान को दूर रखना चाहते थे। वह भय और असहायता पर हावी होने का सदा आग्रह करते थे। काग्रेसियों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि—

"यदि वे समझौता का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हैं, तो यह इस वात की स्पष्टतम चेतावनी हैं कि हम भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं। हम कोई नई स्थिति अपने आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि झण्डाभिवादन रोक दिया जाता है तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और हमें इस पर जरूर अड़े रहना चाहिए। यदि एक जलूस रोक दिया जाता हैं तो हमें उसके लिए लाइसेन्स की प्रार्थना करनी चाहिए और यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें जलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। लेकिन जहां मासिक झण्डाभिवादन और सार्व-जिनक सभा का मामला हो, हमें इजाजत की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। हमें असहायता और उससे उत्पन्न होने-वाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए। करबन्दी-आन्दोलन के बारे में तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेगे और अपने मित्रो को भी इस आन्दोलन में लेआएँगे। जब ऐसा होगा, तब आर्थिक प्रश्न बन जायगा और जब यह आर्थिक प्रश्न बन जायगा, तब जनता इस आन्दोलन की ओर खिंच जायगी।"

जगह-जगह संधि भंग

उक्त चेतावनी के फलस्वरूप सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड विलिंगडन ने मीठे शब्दो की भी कमी न रखी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनो की सच्चाई पर सन्देह किया जाता। लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि वाइसराय की हवाई बातो से जो ऊंची आशाये की गई थीं, वे सब झूठी हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में गाधीजी के दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो गया था। किसी-न-किसी रूप में दमन सब जगह जारी था। उत्तर

प्रदेश के अन्तर्गत सुलतानपुर में ६० आदिमयो पर दफा १०७ ताजीरात हिन्द के अनुसार मुकदमा चलाया गया था। भवन शाहपुर में ताल्लुकेदारों ने किसानों को राष्ट्रीय झण्डा हटा लेने का हुक्म दिया था और उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में विठा दिया था। मथुरा में एक थानेदार ने सार्वजिनक सभा को जवर-दस्ती भग कर दिया था। वारावको में जिला-मिजस्ट्रेट ने पुलिस-इस्पेक्टरों को १४४ धारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये थे। डिप्टी किमश्नर ने गाधी-टोपियों को उत्तरवा दिया था और लोगों को गाधी-टोपी न पहनने तथा काग्रेस में न जाने की चेतावनी दी था।

अहमदाबाद, अकलेश्वर और रत्नागिरी जिलो में गैर-लाइसेन्स-शुदा शराव की दुकानो पर और गैर-लाइसेन्स शुदा घण्टो मे शान्तिमय पिकेटिंग की आज्ञा नहीं दी गई। कैदी भी नहीं छोड़े गये। वलसाड में पाच आदिमयो से इसलिए जुरमाना मागा गया कि सत्याग्रह सग्राम के दिनों में उन्होंने स्वयसेवक-कैम्प के लिए अपनी जमीने दे दी थी। उनसे जवतक जुरमाना वसूल नही हुआ तवतक उन्हें जमीने नहीं दी गईं। कर्नाटक में पश्चिमी जमीने तवतक वापस नहीं की गईं, जवतक यह वचन नहीं ले लिया कि आगे वे आदोलन में भाग न लेगे। कई पटेल और तलाटी फिर बहाल नही किये गये । दो डिप्टी-कमिश्नरो को, जिन्होने इस्तीफा दे दिया था, पेन्शन नहीं दो गई, यद्यपि लॉर्ड अविन वचन दे चुके थे। बगाल में वकीलो तथा बैरिस्टरो से 'आयन्दा ऐसा न करने का वचन लेने से एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। नवे आर्डिनेन्स के मातहत एक जब्त आश्रम वापस नही लौटाया गया। गोहाटी में विद्यार्थियो से ५०)-५०) की जमानते मागी गई। जोर-हट में सुपरिन्टेण्डेन्ट बार्टली की आज्ञा से १६ जून को प्रभातफेरी करनेवाले लडको को पीटा गया। दिल्ली मे विद्यार्थियो से आगे के लिए वादे लिये गये। मद्रास में १३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि अस्थायी सन्धि के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी साल' पर पिकेटिंग शामिल नही है। तजोर के वकीली पर शराब की दुकानो की पिकेटिंग न करने के लिए १४४ दफा की रू से नोटिस तामील किये गये । पिकेटिंग करते हुए स्वयसेवको पर बनावटी अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानो पर उन्हें पीटा गया और झण्डा तथा छाता रखने से भी रोका गया। लोगो को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें पानी न दिया जाय। शोलापुर के मार्शल-लॉ कैंदियो की रिहाई की निश्चित प्रतिज्ञा लार्ड अविन कर गये थे, लेकिन फिर भी वे न छोड़े गये। परन्तु वारडोली में सरकार ने अस्थायी-सिध को जिस ढग से भग किया उसके सामने ये सब बाते फीकी पड जाती है। पाठकों को याद होगा कि इस ताल्लुके में लगान-बन्दी का आदोलन था। नई मालगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमे से २१ लाख रुपये दिये जा चूके थे। इस प्रकार प्रश्न केवल एक लाख के सबध में था।

जब गाधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये तब उन्होंने ये सब शिकायते भारत-सरकार तक पहुंचाई। अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गाधीजी ने बारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधं सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति बम्बई-सरकार को भी भेजी। वम्बई के गवर्नर का जवाब भी असन्तोष-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया।

जांच का प्रस्ताव

तब गाधीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस संबंध में भारत-सरकार के होम-सेकेटरी इमर्सन साहब और उनके बीच पत्र-व्यवहार हुआ। यह पत्र-व्यवहार जुलाई के अितम सप्ताह तक चलता रहा। गाधीजी ने २१ जुलाई, १६३१ का शिमला से इमर्सन साहब के पास जो चौथा पत्र मेजा उसमें उन्होंने लिखा कि वाइसराय-भवन में आज शाम को किये गये वादे के अनुसार मैं अपनी यह प्रार्थना लेखबद्ध कर रहा हूँ कि सरकार तथा काग्रेस के बोच हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निष्पक्ष पच बैठाये जाय, जो समय-समय पर सरकार या काग्रेस की ओर से उसके सामने पेश किये जायं। कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है। यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल यही मामले नेश होगे। संभव हैं, भविष्य में ऐसे अकिल्पत मामले भी खडे हो जाय, जिनके सबंध में समझौते की सीमा के अन्दर होने का दावा किया जा सके। हम यह तरीका रखे कि सरकार और काग्रेस दोनों की ओर से लिखित वक्तव्य पेश हो। दोनो पक्ष के वकील उन विषयो पर अपनी-अपनी दलीले पेश करे और बाद को पंच जो निर्णय करें वह दोनो पक्षों को मान्य हो।

इमर्सन साहब ने शिमला से ३० जुलाई १६३१ को उक्त पत्र का उत्तर देते हुए लिखा कि भारत सरकार ने व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नो के लिए निर्णायक मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पत्र में वर्णीत प्रश्नो पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्खा है कि इन प्रश्नो पर निर्णायक-मण्डल मजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेदारी और फर्जो का उलझन में पड जाना। आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना सभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी मौकूफ हो जाय, और जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करें। ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी बात की कोई गुजाइश नहीं है।

परिषद् से गांधीजी का इन्कार

इस पत्र-व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि समझौते मे कोई दम नही है। उत्तर-प्रदेश में किसानो पर दमन और अत्याचार जारी था। अपने खेतो तथा घरो से निर्वा-सित किसानो की दूर्दशा से उत्तर प्रदेश के नेताओ को विशेष चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। ऐसी दशा में गाधीजी नेउत्तर प्रदेश के गवर्नर सर माल्कम-हेली को एक तार भेजा। लेकिन उसका जवाब निराशाजनक मिला। सभी ओर से ऐसी शिकायते आ रही थी और परिस्थितिया इतनी दिल तोडने वाली थी कि ११ अगस्त १६३१ को गाधोजी वाइसराय को एक तार भेजने पर विवश हो गये। उस तार में उन्होने लिखा कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का जो पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्याये उपस्थित हो गई है। पत्र में हकीकत और कानून दोनो दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनो बातो में अन्तिम निर्णय करेगी। इसका साफ अभिप्राय यह है कि जिन मामलो में सरकार और शिकायत करने वाले दो दल हो, उनमें भी सरकार ही अभियोग लगाये और वही फैसला करे। काग्रेस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। वम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और उत्तर प्रदेश,सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तो मे होने वाले अत्याचारो की रिपोर्ट पर जब में घ्यान देता हू तब मुझे यही प्रतीत होता है कि मै लन्दन न जाऊ, जैसा मैने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पहले मै आपको लिखूगा। मै ऊपर लिखी हुई सब बाते आपके सामने रख रहा हूँ। अन्तिम घोषणा करने से पहले मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूगा।

वाइसराय ने १३ अगस्त १६३१ को गांधीजी के तार का उत्तर देते हुए लिखा कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में मैं खुद दिलचस्पी रखता हू और मैंने आशा की थी कि आप इन विस्तार की बातों से उत्पन्न विवादों के कारण अपने को भारत की उस सेवा से विचत नहीं करेगे, जो आप उस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेकर कर सकते हैं, जो आपके और मेरे समय के भी आग के लिए देश के भाग्य का निपटारा कर देने वाला है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो मैं फौरन ही प्रधान-मत्री को आपके लन्दन न जाने की सूचना दे दूगा। गांधीजी ने १३ अगस्त १६३१ को तार-द्वारा वाइसराय को जो सूचना दी वह लन्दन न जाने के ही सबध में थी।

यद्यपि जून के महीने से यह आशका की जा रही थी कि काग्रेस के गोलमेज-परिषद् में भाग लेने के रास्ते में दिक्कते आएगी, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलझ जायगी। परन्तु प्रयत्न करने पर भी कोई सूरत न निकल सकी। इस तरह जब कि गाधीजी वाइसराय और बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों से पत्र-व्यवहार करने में लगे हुए थे, काग्रेस की कार्य-समिति बदस्तूर अपना कार्य करने में सलग्न थी।

कार्य-समिति तथा महासमिति के निश्चय

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई। उसने 'ब्रिटेन तथा भारत के लेन-देन' पर तैयार की हुई रिपोर्ट को छापने की स्वीकृति दे दी। मौलिक-अधिकार-समिति ने अपनी बैठके मछलीपट्टम में करके जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे कार्यसमिति ने महासमिति के सामने पेश करने का निश्चय किया। हिन्दु-स्तानी-सेवादल को काग्रेस का केन्द्रीय स्वयसेवक-सगठन मान लिया गया और यह निश्चय किया गया कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे वह अपनी ओर से नियुक्त करे। प्रातीय काग्रेस-किमिटियों को यह अधिकार और आदेश दिया गया कि वे भी बाकायदा स्वयं-सेवक-दल बनाएँ। इस दल के सदस्यों के लिए काग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वयंसेवक-दल के नियन्त्रण को मानना जरूरी रखा गया। इसके बाद साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार हुआ और एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ। विदेशी कपड़े और सूत के बहिष्कार की रूपरेखा तैयार की गई। यह भी निश्चय किया गया कि अस्पृश्य-ता-निवारण-समिति को, जो गत वर्ष सिवनय अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। मिल-समिति की तथा मजदूरों की हालत के प्रश्न पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्भव और आवश्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजबीजों के द्वारा ऐसी मिलों में, जिन्होंने काग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हो, मजदूरों को दण्ड दिये जाने या निकाले जाने को रोकने और मजदूरों की स्थिति को अधिक अच्छी करने की कोशिश करे।

महासमिति की बैठक ६, ७ और ८ अगस्त १६३१ को हुई। उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। पहला प्रस्ताव बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के प्रयत्न और बंगाल में जज गालिक की हत्या के सवंध में था। इसके पश्चात् राष्ट्रीय-झंडा-समिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रीय झण्डा तीन रग का और पहले की तरह लम्बाई-चौडाई में समानान्तर होगा। लेकिन उसके रङ्ग कमश ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होगे। सफेद पट्टे के केन्द्र में गहरे नीले रङ्ग का चरखा होगा। रंग गुणो के न कि जातियों के सूचक हैं। केसरिया रङ्ग साहस और बिलदान का, सफेद रङ्ग शान्ति और सत्य का, हरा रङ्ग श्रद्धा तथा वीरता का एवं चर्खा जनता की आशा का प्रतिनिधि होगा। झण्डे की लम्बाई-चौडाई का अनुपात ३:२ होगा। ३० अगस्त रिवन्वार को नया राष्ट्रीय झण्डा फहराने का निश्चय किया गया। इसी के अनुसार

प्रति मास हर रिववार को झण्डा फहराया जाने लगा। मौलिक-अधिकार-सिमिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ और अधिकार एव कर्त्तव्य स्वीकृत हुए।

सीमा-प्रान्तीय कार्येस-किमटी, अफगान-जिरगा तथा खुदाई-खिदमतगारी के सम्वन्ध में यह निश्चय किया गया कि काग्रेस-विधान के अनुसार एक नई प्रान्तीय सस्था स्थापित की जाय जो प्रान्त में काग्रेस का प्रतिनिधित्व करे। यह नई चुनी हुई किमटी प्रान्तीय काग्रेस-किमटी होगी। उस प्रान्त की भाषा में यह सीमा-प्रान्तीय जिरगा कहलायेगी। इसी तरह जिला तथा स्थानीय काग्रेस-किमटिया स्थानीय जिरगे कहे जा सकेगे। यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार कार्य-सिमित के हाल के प्रस्ताव के अनुसार काग्रेस-स्वयसेवक वन जाय। 'खुदाई खिदमतगार' नाम रक्खा जा सकेगा। काग्रेस के विधान, नियम और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण सगठन चलाया जायगा। इसलिए झड़ के तौर पर वस्तुत राष्ट्रीय झडा ही काम में लाया जायगा। कार्य-सिमित की प्रार्थना पर सीमा-प्रान्तीय नेता खान अब्दुलगफ्फारखा ने उस प्रान्त में काग्रेस-आन्दोलन के सचालन का भार अपने कधो पर ले लिया।

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि वह अनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम पर पहुंची है कि समझौते की शतों और राष्ट्रीय हितो को देखते हुए काग्रेस गोलमेज परिषद् में न भाग ले सकती हैं और न उसे लेना ही चाहिए। मिण-भवन (बम्बई) में सारे दिन आशाओं से भरी ऐसी अफवाहें गरम हो रहीं थी कि सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधीजी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन जव गांधीजी रात के दा।। बजे मिण-भवन छोडकर वम्बई-सेन्ट्रल स्टेशन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गये तब सब सन्देह बिलकुल खतम

हो गये।

परिषद् में न जाने के कारण

गाघीजी के गोलमंज-परिषद् में उपस्थित होने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समर्थन कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण था। वस्तुत इमर्सन साहब के ३० जुलाई के पत्र, बम्बई गवर्नर के पत्र तथा सर माल्कम हेली के तार ने, यह निश्चय करने में गाघीजी को बाध्य किया था, लेकिन इनमें सबसे वडा कारण था बारडोली में लगान-वसूली के लिए दमनकारी उपायो का अवलम्बन। २२ लाख रुपये में से २१ लाख दिए जा चुके थे। काग्रेस का कहना था कि लगान चुकानेवाले आपित्त में ग्रस्त है और समय चाहते हैं। परन्तु सरकार ने पुलिस-द्वारा धमिकया देना तथा पुलिस के 'जुल्म' के जोर पर उस साल का तथा पिछले

सालों का बकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि लगान की वसूली में अन्तिम निर्णय काग्रेस का नहीं, बल्कि सरकार और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थीं, जितनी अपने रीव की।

एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण और भी था, जिससे गाधीजी इंग्लैंड नही जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर असारी को गोलमेज-परिषद् का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। स्वभावत काग्रेस उन्हें ले जाना चोहती थी। काग्रेसी होने के अलावा वह भारत की एक बडी पार्टी—राष्ट्रीय मुस्लिम दल-का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं थे। उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्वराज्य के लिए उत्सुक था। लॉर्ड अविन ने गाधीजी के कहने से पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डाक्टर असारी को मनोनीत करने का वचन दिया था। लॉर्ड विलियडन भी यह जानते थे। लॉर्ड अविन के वचन का पालन करने की माग के उत्तर में लॉर्ड विलियडन ने यह दलील दी कि मुसलमान-प्रतिनिधि डॉक्टर असारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है। देश में डॉक्टर अन्सारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। वह साम्प्रदायिकता के प्रवल और निर्भीक विरोधी थे। ऐसे डॉक्टर अन्सारी के चुनाव को वह मुसलमान-प्रतिनिधि कैसे सहन करते? काग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया था, जिसका समर्थन गोलमेज परिपद् मे एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करते। सरकार यह जानती थी। इसलिए वह साफ तौर पर मुसलमान अग को काटकर काग्रेस को बेकार यना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में काग्रेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज-परिपद् के लिए लन्दन जाने से इन्कार कर दिया।

लन्दन के लिए प्रस्थान

गाधीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा वन्द नहीं किया। उनका कहना था कि ज्यों ही रास्ता साफ हुआ, मैं लन्दन की ओर दीड पड़ गा। जो वात प्रत्येक गानितिक विचार के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने तुले तौर पर कह दिया— "यहां के वड़े सिदिलियन नहीं चाहते कि मैं परिषद् में जा सकू और यदि वे चाहते भी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में ,जिन्हें काग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था वर्दायन गती कर सकती।" देश के सिविनियन दड़े जोरों ने यह वात फैला रहे थे कि व्याग्रेस के ना में गाधीजी एक मुकादते की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी विष्यमक संस्था कभी गवारा नहीं की जा सकती। गांधीजी ने वम्बई ने अहमदाबाद

के लिए रवाना होते समय लार्ड विलिंगडन को एक निजी पत्र लिखा कि अपने नेतृत्व में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा और न मैंने कभी पच नियुक्त करने पर जिद की। हा, उसके इस अधिकार का दावा मैंने अवश्य किया है। मैं तो केवल न्याय चाहता हूं। काग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रात काल जो प्रस्ताव पास किया है उसके अनुसार दिल्ली-समझौते का अन्त नहीं समझना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और वह सच्चाई से दिल्ली-समझौते का पालन करना चाहती है।

गाधीजी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर शीघ्र मिले और यदि दिल्ली-समझौते का पालन मजूर है तो शिकायतो पर शीघ्र ही विचार किया जाय, क्योंकि काग्रेसी कार्यकर्त्ता इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि शिकायते दूर नहीं होती तो कम-से-कम आत्म-रक्षा के लिए रक्षात्मक उपाय हाथ में लेने की आज्ञा दी जाय। गाधीजी को इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार काग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्य स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेशानी में डालने अथवा उसे अपमानित करना नहीं चाहते थे।

गाधीजी ने शिमला से प्राप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विरुद्ध आरोप-सूची प्रकाशित कर दी। गाधीजी के पत्र का वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोषजनक न था। उसमें वाइसराय ने यह भी लिखा था कि गोलमेज-परिषद् में काग्रेस का सिम्मिलित न होना समझौते के प्रधान उद्देय को असफल करना है। इस विषय पर वाइसराय से बातचीत करने के लिए गाधीजी ने तार-द्वारा मुलाकात की अनुमित मागी। मुलाकात की अनुमित मिल गई। गाधी जी, श्री वल्लभभाई पटेल, जवाहरलालजी और सर प्रभाशकर पट्टनी वाइसराय से मिले। वाइसराय ने कार्यकारिणी की बैठक की। आखिर बहुत-सी बाधाओं के बाद मामले किसी तरह सुलझाय गये और गाधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गाडी को पकड़ने के लिए रवाना हुए, जो उन्हें २६ अगस्त को रवाना होने वाले जहाज पर सवार करा सके। इस तरह गाधीजी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत के परिणाम-स्वरूप यह फैसला हुआ कि काग्रेस की ओर से गाथीजी गोलमेज परिषद् में भाग ले। इसके अनुसार वह बम्बई से २६ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये।

यात्रा में गांधीजी

गाधीजी के साथ श्री महादेव देसाई, देवदास गाधी, प्यारेलाल, श्रीमती मीराबहन और श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अदन में उनका हार्दिक स्वागत हुआ। अरवो तथा भारतीयों ने उन्हें एक साथ अभिनन्दन-पत्र दिया। रेजीडेन्ट सभा में राष्ट्रीय झण्डा फहराने की अनुमित नही देना चाहता था। गावी जीने स्वय यह गुत्थी सुलझाई। उन्होने स्वागत समित के अध्यक्ष श्री फरामरोज कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिडेण्ट को फोन पर यह सूचित कर दे कि इन परिस्थितियों में गांथोजी अभिनन्दन-पत्र लेना स्वीकार नहीं करेंगे। यह दलील काम कर गई। जहां गांधीजी को मानपत्र देना था उस स्थान पर भारत का राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया और ३२८ गिनी की थैली उन्हें भेट में दी गई।

जहाज पर गांधीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, अपना चरेखा और वालकों के साथ अपना मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करते रहे, जैसे आश्रम में करते थे। गांधीजी को श्रीमती जगलुलपाशा और वफ्द पार्टी के अध्यक्ष नहस-पाशा ने वधाई भेजो। पहले का संदेश तो स्वभावत. हृदयस्पर्शी था, और दूसरे का हार्दिक उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा—

"अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर मैं उसी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाला भारत के सर्वप्रधान नेता का स्वागत करता हू। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह यात्रा सकुशल समाप्त हो और आप प्रसन्नतापूर्वक लौटे। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हू कि आप जव वहा से लौटकर स्वदेश जाने लगे, तव मुझे आपसे मिलने की खुशो हासिल हो। ईश्वर आपको चिरायु करे और आपके प्रयत्नो में आपको व्यापक तथा स्वायी विजय दे।"

मिश्री शिष्ट-मण्डल को पोर्टसईद पर गावीजी से मिलने की आजा नहीं दी गई, लेकिन कैरो पर भारतीयों के शिष्ट-मण्डल को उनसे मिलने दिया गया। यहुत दिक्कत के बाद नहसपाशा का एक प्रतिनिधि गाधीजी से मिल सका। जब गांधीजी मार्सेनीज पहुंचे, तब वहां श्री रोम्या रोला की बहन मेंडलीन रोलां जनफा उत्साहपूर्वक स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। रोम्या रोला अन्यस्य होने के कारण स्वयं उपस्थित न हो सके थे। मेंडलीन रोला के साथ मोशियर प्रिवे तथा उनकी पत्नी भी थी। मो॰ प्रिवे स्विटजरनैण्ट के एक अध्यापक थें, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १६३२-३३ के आन्दोलन में मामूनी तथा सदिख्य अस्यापक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था। कितने ही फ्रासीनी विद्याधियों ने भी माथीजी का अभिनंदन किया।

लन्दन में गांधीजी

एक दिन यूस्टन रोड पर स्थित मित्र-सभा-भवन में दिये गांधीजी के भाषण तथा किंग्स्ले-हाल से न यार्क को बौडकास्ट-द्वारा भेजे गये सदेश की रिपोर्ट 'टाइम्स' में पढकर ४० पौड का चेक ही भेज दिया था। 'चचा गांधी'— हिन्दुस्तानी चप्पल के सिवा नगे पैर, कमीज नदारद, सिर्फ चादर ओढे हुए— ईस्ट-एन्ड के वालको में इतने प्रिय हो गये थे कि वे प्रति दिन प्रात काल आकर उनको घेर लेते थे। गांधोजी और उनकी शाम की प्रार्थनाये, लकाशायर के मजदूरों के सामान्य अतिथि के रूप में गांधीजी, और उनकी ब्रिटिश-सम्राट् से अपनी मामूली पोशाक में भेट—ये सब ऐसी वार्ते हैं जिनका काग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी की हैं।

परिषद् में गांधीजी

गोलमेज परिषद् में गाधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा घ्यान गये बिना नहीं रह सकता। फेडरल स्ट्रक्चर किमटी में दिये गये उनके भाषण को लन्दन में दिये गये उनके अन्य भाषणों की उत्तम भूमिका कह सकते हैं। उन्होंने काग्रेस, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके साधन, उसके उद्देश आदि सबका सिक्षप्त परिचय नपे-तुले शब्दों में दिया। उन्होंने काग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन-पोषणकर्ता मि० ए० ओ० ह्यूम के प्रति श्रद्धांजिल अपित की और काग्रेस तथा सरकार और काग्रेस तथा अन्य दलों के आधार-भूत भेदों का निर्देश किया। उन्होंने कराची का प्रस्ताव पढकर उसकी व्याख्या की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान मन्त्री का वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सघ तथा भारतीय हितों की दृष्टि से सरक्षण, इन तीन कारणों से चित्रित भारतीय घ्येय से बहुत कम है। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बडी आवश्यकता पर भी विचार प्रकट किये।

अल्प सख्यक-सिमिति में भाषण देते हुए गांधीजी ने कई खरी बाते पेश की। उन्होंने असिदग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी माग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रश्न तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया है हमें लन्दन में इसलिए निमित्रत किया गया है कि हमें जाने से पहले यह सतोष हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-युक्त और असली ढाचा तैयार कर चुके हैं और अब उसपर केवल पार्लमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई हैं। उन्होंने सर ह्यूबर्टकार की अल्पसंख्यक

जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यबर्टकार तथा उनके साथियों को इससे जो सतीष हुआ है वह मैं उनसे न छीनूगा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है वह मुर्दे की चीर-फाड़-जैसा ही है। सरकार की यह योजना उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अर्थात् स्वराज्य प्राप्ति के लिए नहीं, किन्तु नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। 'मैं उनकी सफलता चाहता हूँ, लेकिन काग्रेस इससे बिलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आजादी और उत्तरदायी शासन का वृक्ष कभी पनप न सकेगा, अपनी सहमित प्रकट करने की अपेक्षा काग्रेस वर्षों जगल में भटकना स्वीकार कर लेगो। अन्त में उन्होने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ अपना भाषण समाप्त किया, जिस पर कुछ समय बाद उन्होने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। उन्होने कहा कि अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को मैं समझ सका हू, लेकिन अछूतो की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पृत्यता का कलंक निरतर रहेगा। हम नहीं चाहते कि अस्पृश्यों का एक पृथक् जाति के रूप में वर्गी-करण किया जाय। सिक्ख सदैव के लिए सिक्ख, मुसलमान हमेशा के लिए मुसल-मान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। लेकिन क्या अछूत भी सदा के लिए अछूत रहेगे ? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूगा कि हिन्दू-धर्म ही डूब जाय। जो लोग अछूतो के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को नहीं जानते, और हिंदू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहता हू कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर्फ मैं ही अकेला होऊ तो भी, अपने प्राणो की वाजी लगा कर भी, मैं इसका विरोध करूंगा।

सेना के सवाल पर वहस हुई और गाधीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पष्ट वाते कही। लेकिन इससे पहले उन्होने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मैं इग्लैंड में अधिक समय तक ठहरने का विचार रखता हूं, क्योंकि मैं तो लन्दन आया ही इसलिए हू कि सम्मान-युक्त समझौते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करू। उन्होने कहा कि काग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सव प्रकार की जिम्मेदारियों को—रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक—आवश्यक हेर-फेर और व्यवस्था के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य है। उन्होने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना वस्तुत देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हो, मेरे लिए सव विदेशी है, क्योंकि मैं उनसे बोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास आ नहीं सकते और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे काग्रेसियों को अपना देशमाई न समझे। इन सैनिकों और हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।

अंग्रेजी सेना अग्रेजो के स्वार्थों की रक्षा करने, विदेशियों के हमलों को रोकने तथा आन्तरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए रखी गई है। वस्तुत केवल अंग्रेजी सेना ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भारतीय सेना) रखने का भी यहां हेतु है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। लेकिन में यह भी जानता हूं कि वह सेना मेरा आदेश नहीं मानेगों, न प्रधान सेनापित और न सिक्ख या राजपूत ही मेरी आज्ञा मानेगें, किन्तु फिर भी में आशा करता हूं कि ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से में अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूगा। अग्रेजी फौज को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहा अग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, वरन् भारत को विदेशी आक्रमण से बचानें के लिए हो। यह सब मेरा स्वप्न है। में जानता हूं कि में ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों तथा जनता से इस स्वप्न को पूर्ण न करा सकूगा, लेकिन यदि इस समय मेरा यह स्वप्न पूरा न हुआ, और मैं फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की

प्रतीक्षा करूगा। भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरेखे, सिक्ख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते है। राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मा-पोली नही, हजारो थर्मापोलियो के जन्मदाता कहे जाते हैं।

गाधीजी अग्रेजो और उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होने कहा कि हमें अग्रेजो के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का सचार कर देना

चाहिए, जिससे भारत अपने पैरो पर खडा हो सके। यदि अग्रेजो का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर काग्रेस बया-वान में भटकती रहेगी, उसे भयकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा, आप-दाओं के तूफान और गलतफहिमयों के ववण्डर का मुकाबला करना होगा और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौछार भी सहनी पड़ेगी। संरक्षणे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सरक्षण नहीं है, जो साथ-साथ बिटिश-स्वार्थों की भी रक्षा न करें, बशर्तिक हम साझेदारी—इच्छित और सर्वथा वरावरी के दर्जे की साझेदारी—की कल्पना करें। गोलमेज-परिषद् के खुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि आजादी वाद-विवाद से एव सन्धि-चर्चा से मिल सकती है। लेकिन मैं यह जरूर कहूगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिषदों या किमिटियों में फैसले की कसौटी बहुमत नहीं रखी जायगी, तब परिषद् के संयोजक ऐसी किमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'बहुमत की सम्मित' कैसे लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले 'एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं करते, वह 'एक' कौन है ? क्या यहाँ उपस्थित दलों में से काग्रेस भी एक दल है ? मैं तो पहले भी यह दावा कर चुका ह कि काग्रेस ५५ फीसदी जनता की प्रतिनिधि है। अब

मैं यह दावा करता हूं कि अपनी सेवा के अधिकार से काग्रेस राजाओ, जमींदारो

और शिक्षित-वर्ग की भी प्रतिनिधि है। अन्य सव प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं; काग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्या हे जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका मंच सबके लिए एकसा खुला है। फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकमात्र ऐसी सस्या है, जिससे कारआमद फैसला हो सकता है। कुछ लोग अनुभव कर रहे थे कि काग्रेस मुकावले की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। यदि काग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरीले प्याले, गोलियो और भालों के मार्ग को छोडकर अहिंसा- पूर्वक मुकावले की सरकार चला सकती है, तो इसमें बुरा क्या है ? यह ठीक है कि कलकत्ता कारपोरेशन पर एक लाछन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योही उस बात के सम्बन्ध में मेयर का घ्यान आकृष्ट किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में यथोचित परिमार्जन भी किया था। काँग्रेस हिंसा नही, अहिंसा को मानती है, इसलिए सविनय अवज्ञा-आन्दो-लन जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने वरदारत नही किया। परन्तु उसका मुकावला भी नहीं किया जा सकता था—स्वय जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके। १६०८ में जो भारतीयों को देने से उन्कार किया जाता था, १६१४ में वहीं दे देना पडा। बोरसद तथा बारडोली में सत्याग्रह सफल हुआ है, इसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी स्वीकार कर चुके हैं। लॉर्ड अविन ने आडिनेन्सा-द्वारा देश को जूब तपाया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। समय रहते हुए, मैं चाहता ह, आप समझें कि काग्रेस का घ्येय क्या है। परमात्मा के नाम पर मुझ ६२ साल के दुवले-पतले आदमी को थोडा-सा तो मौका दो। मुझे और जिस सस्या का में प्रतिनिधि हू उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान तो बनाओ। यद्यपि आप मुझपर विख्वास करते प्रतीत होते है, तयापि कांग्रेस पर अविख्वास करते हैं। परन्तु एक क्षण के लिए भी आप मुझे उन महान् संस्था से भिन्न न समझिए जिसमें में समुद्र की एक बूद के समान हूं। में काग्रेस से बहुत छोटा हू; और यदि आप मुझपर विरवास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूं कि आप काग्रेस पर भी विदवास की जिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विदवास है पर फिनी काम का नहीं, क्योंकि काग्रेन से जो ऑवकार मुने मिला है उसके तिया मेरे पास कोई अधिकार नही। यदि आप काग्रेन की प्रतिष्ठा के अनुकूत् फाम परेंगे, तो आप आतंकवाद को नमन्कार कर लेंगे ितव आपको उने देवाने के लिए अपने आतकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। क्या आप यह नहीं देनेने कि तम में हैं को बनी हुई रोटी नहीं, बल्कि आवादी की रोटी नाहते हैं, और बबनक रोटी गर्री मिल जाती, ऐने हलारों लोग मौजूद है, जो इन बात के लिए प्रतिज्ञा-प्रार्ट कि इन बक्त तक न तो सुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन में बैठने देते ?

१ दिसम्बर को परिषद् विसींजत। हुई गांघीजी ने सभापित को घन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तो पर जाना होगा। मनुष्य-स्वभाव का गीरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली आधियों से टक्कर लें। में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसको मुझे चिन्ता नहीं है। यदि मुझे आपसे विलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के अधिकारी तो हैं हो। इन भावीसूचक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिषद् से विदा हुए। उस समय स्थित यह थी कि जिन शतों पर काग्रेस गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से एक 'घोर दमन रोक दिया जायगा'—पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बगाल तथा उत्तर प्रदेश की बढती हुई बुरी स्थित से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-नोति को जारी रखना लन्दन में प्रदिशत सहयोग और भारत को स्वतत्रता देने की इच्छा से विलकुल मेल नहीं खाता।

वारडोली में श्रशांत वातावरण

उघर गाघीजी गोलमेज-परिषद् में भाग ले रहे थे, इघर देश का वातावरण विधानत होता जाता था। जब गाधीजी गोलमेज-परिषद् के लिए रवाना हुए थे, तब यह आश्वसन दिया गया था कि बारडोलों में लगान वसूलों के सिलमिलें में पुलिस की ज्यादितयों के आरोगों की जाच होगों। मि० गॉर्डन को सूरत जिलें को माल-गुजारी-कानून के अनुसार अधिकार देकर जाच के लिए खास अफसर नियत किया गैया। जाच ६ अक्तूबर १६३१ को शुरू हुई। श्री भूलाभाई देसाई और सरदार वल्लभ-भाई पटेल उपस्थित थे। दोनो पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानो को अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं हैं, जिन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। जाच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार तथा बम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आज्ञाए प्रचारित की थी, काग्रेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा। काग्रेस ने अभिलिषत कागजो को मागने के कारण बताये और यह भी बताया कि किस किस्म के कागज विरोवी-पक्ष के अधिकार मे है। मि० गॉर्डन ने १२ नवम्बर १६३१ को यह हुक्म दिया कि विचारा-घीन प्रश्न के सिलसिले में अनिश्चित और अयुक्ति-युक्त मागो से सहमत होना असम्भव है। दरअसल सरकार के हाथ में मौजूद कागजो को पेश करने से इन्कार कर देने का अर्थ सरकारी गवाहो पर से जिरह की एक उपयोगी कैंद को हटा देना था और यह भी महसूस किया गया कि इस तरह अधकचरी जाच निरुपयोगी से भी अधिक बुरी है। इस कारण सरदार वल्लभभाई पटेल ने जाच से हाथ खीच लिया।

श्रन्य प्रान्तों की स्थिति

बरडोली की जाच का यह हाल हुआ, अब उत्तर प्रदेश की ओर आइए! उत्तर-प्रदेश में भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। किसानो की-अधिकाशत. ताल्लुकेदारो तथा जमीदारो के अधीनस्थ किसानी की-विपत्ति बढ रही थी। लगान-वसूलो के तरीको में नरमी का नाम-निशान न था। अनेक ग्रामीण क्षेत्रो में तो किसानो पर आनक का राज्य छा गया था। जिन जिलो में किसानो के साथ सस्तिया की गई थी, उन्हें देखने तथा किसानो की स्थिति और विपत्तियो पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये उत्तर प्रदेशीय काग्रेस-कमिटी ने कई जाच कमिटिया विठाई थी, परन्तु उनकी जॉच का फन व्यर्थ हो गया। ऐसी स्थिति मे भी उत्तर प्रदेशीय काग्रेस-किमटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी जिससे समझौते की बातचीत ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानी के लगातार सलाह मागने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मागी हुई रकम दे दे, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनु-चित है और उन किसानो को तबाह कर देगो, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तब काग्रेस ने महासमिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के बाद किसानी की यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दे। फिर भी काग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इंच्छुक और उद्यत है और ज्योही किसानो की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस् लें लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले काग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने काग्रेस का परामर्श नहीं माना । अव उत्तर प्रदेश की काग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये। सरकार ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अख्तियार की। उसने सैकडो काग्रेसी कार्य-कर्ताओं को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारिया इतनी तडाक-फड़ाक हुई कि सभी प्रमुख और उच्च कार्यकर्ता जेलो मे पहच गये।

सघर्ष का तीसरा केन्द्र वंगाल था। अस्यायी सन्धि के समय वहा अत्याचारों के अनेक दृश्य देखने में आये। शायद इनका उद्देश्य था, चटगाव जिले में हुए उत्पातों का वदला लेना। चटगाव शहर और जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जाच करने के लिए एक गैर-सरकारी जाच-किमटी नियुक्त की गई थी। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे वडे हथींडे और लोहे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस गये और उन्होंने मशीनों को तोड दिया तथा प्रेस-मैनेजर एव अन्य कर्मचारियों को मारा-पीटा। दिल्ली में २७, २५ और २६ नवम्बर को कार्य-सामित ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और आतकवाद की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों तथा गुण्डों के साथ

निरपराध जनता की बेइज्जती करने तथा उसे भीषण क्षति पहुचाने के लिए स्थानीय पुलिस तथा मजिस्ट्रेटो की तीन्न निन्दा की। जेलो से बाहर लोगो के साथ जब इस प्रकार आयर्लेण्ड के-से दमन के तौर-तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलो और नजरबन्दों के कैम्पों में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरबन्द कैम्प में जो दु खान्त नाटक खेला गया, उसके फलस्वरूप २ नजरबन्द मर गये और २० घायल हो गये।

भारत के उत्तरी द्वार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वलित कर रक्बी थी। वहाँ खुदाई खिदमतगार अनुशासन एव सगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुलगप्फार खा के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। अगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारी का काग्रेस से सम्बन्ध नहीथा। अस्थायी सधिके समय से ही गाधीजी सीमाप्रान्त जाने और उस सगठन का अध्ययन करने के लिए कई बार लॉर्ड अविन से उन्होने आज्ञा मागी, लेकिन उन्हें आज्ञा नहीं मिली। अन्त में उन्होंने सीमाप्रान्त में श्री देवदास गाधी को भेजा। उन्होने एक आक्चर्यजनक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य-समिति ने विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारो को काग्रेस-सगठन का अग बना कर एक महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया। वैण्ड और बिगुल, सिर से पैर तक लाल पोशाक और एक ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास-जो अपने चरित्र, मंनुष्यता, बलिदान एव सेवा से 'सीमान्त-गाधी' का पद पा चुका था और बहुत जल्दी सब आखो का एक लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा था-ये सब बाते उस सगठन को अर्द्ध-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी। लाल पोशाक में एक लाख सेना-सब पठान, उनपर विश्वास नही किया जा सकता था । सरकार को एक वहाना भी मिल गया कि खान अब्दुल गफ्फारखा सरकार से सहयोग नही करते, क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कुमिश्नर के दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। वह पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं। बस, निरपराध खानसाहव और उनके भक्त तथा उन्ही की तरह उनके निरपराध भाई डॉ॰ खानसाहब गाधीजी के भारत पहुचने से कुछ ही दिन पहले जेल में डाल दिये गये।

गाधीजी जब २८ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार वन चुकी थी। कांग्रेस पर महान संकट: १९३२-३५

: १५:

कांग्रेस पर महान संकट: १६३२-३५

गांधीजो वम्बई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि गाघोजों का स्वागत करने के लिए २६ दिसम्बर को बम्बई में एकत्र हुए । चुगी-दफ्तर के एक भवन में उनका विधिवत स्वागत किया गया। फिर एक जलूस निकाला गया। गाघोजी ने सबसे पहले बम्बई की जनता को अपना भाषण सुनाया। आजाद मैदान में सचमुच उस दिन बहुत भीड थी। गाघोजी ने उसके सामने गम्भीर आवाज में कहा कि मैं गान्ति के लिए अपने बन-भर कोशिंग करूगा और अपनी तरफ में कोई बात उठा न रक्यूगा। गाय ही हिन्दू जाति से अछूतों को जुदा करनेवाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाष्त्र नहीं करूगा, बल्कि मौका पडने पर उसके विरोध में मैं अपनी जान लड़ा दूगा।

तीन दिन तक गाधीजी जुदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों में मिलत रहें और उनकी दुःस कथायें सुनत रहे। बंगाल में अत्याचार हो रहे थे। मुभाप बाबू बंगाल से अपने चार साथियों को लेकर आये थे। उत्तर प्रदेश और तीमाप्रान्त में आर्जिन्स जारी कर दिये गये थे। आरजी मुलह के दिनों में गामन की गाडी एन आर्डिनेन्सों से ही हाकी जा रही थी। देश में भयकर मन्दी और घोर मकट या। कर्नाटक को कोई रिजायत नहीं दो गई थी। आन्ध्र में लगान बटा या जानेवाला या और मद्रास के गयर्नर ने तो यहा तक धमकी दे रती थी कि अगर तीन लगान रोवने की बात करेंगे तो आर्जिन्स जारी कर दिये जायगे। गाधीजी ने एंनी अनेग करण कथाएँ मुनी और फिर उन्होंने भी अपने दुल्हों की गहानी लोगों को गुनायी। वह गोलमेज-परिषद में जाना नहीं चाहते थ। जो बातें रन परिषद में कोने ताली थी उनकी छाया जुताई और अगल्त में ही नजर आने राग गई थी, पर कायन थी कार्य-सिनित ने इस दान पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए।

का भी निश्चय कर लिया था कि आइन्दा काग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायि-कता का समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध राष्ट्र-धर्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इसी तरह पहले की भाति खिलवाड करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मुसल-मान और सिक्ख-मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विवान बने जिसमें किसी प्रकार साम्प्रदायिकता की वू न हो और जो विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वोकार कर लेगे। इन सारे विचारों और अनुभनों के कारण उनके चित्त को बडा क्लेश हो रहा था, पर तत्कालीन परिस्थित का उन्होंने बडी शान्ति और स्थिर चित्त से सामना किया। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने उसका बरावर निर्वाह किया। अब आज उन्हें अपने सामने एक जबरदस्त खाई नजर आ रही थी। सवाल यह था कि इसपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिंदा और मरे हुए आदिमयों से पाट कर पार करना होगा? जब वह अपने काम में भिड़े, उनके हृदय में ये विचार उमड रहे थे। कार्य-सिमिति उनके साथ थी। उन चौदह सदस्यों वाली कार्य-सिमिति की हीनहीं,उन्हें तो सारे देश की हिम्मत थी।

कार्य-सिमिति के आदेशानुसार उन्होने लॉर्ड विलिंगडन को एक तार दिया और उसका जवाब भी आया। जवाब लम्बा और तफसीलवार था। उसमे धमकी भी थी। गाधीजी ने फिर एक तार दिया। मगर कोई नतीजा न निकला। अपने तार में गाधी जी ने लिखा कि अपने साथियों के कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी से मै अपने-आपको बरी नही समझता, पर मै यह स्वीकार करता हू कि मेरे साथियों के कार्यों की और हलचलों की ब्यौरेवार जान-कारी मुझ नहीं है, क्योंकि में भारत में नहीं था और चूकि काग्रेस को कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैने निष्पक्ष भाव से वाइसराय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा। मै वाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा को है वह मेरे सद्भाव और मित्रतापूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइस-राय चाहे तो मैं उनसे कहूगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और हमारी बातचीत पर, उसके विषय-क्षेत्र पर, बगैर कोई शर्त लगाये मुझसे मिलना स्वीकार करे। अपनी तरफ से मैं यह वचन दे सकता हू कि वह जो भी बाते मेरे सामने रखेगे उनपर मैं निष्पक्ष होकर विचार करूगा। बगैर किसी हिचकिचाहट के और खुशी के साथ मैं उन-उन प्रातो में जाऊँगा और अधिकारियो की सहायता से प्रश्न के दोनो पहलुओं का अध्ययन करूगा, और यदि पूरे अध्ययन के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुँचुंगा कि लोग गलती पर है और सरकार का ही पक्ष ठीक है,

की सब सुविधायें दी जाय, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करकें सहायता देने के लिए तैयार रहेगी।

गोलमेज-परिषद् में प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उसपर पालंमेन्ट की कामन-सभा तथा लार्ड-सभा में हुए वाद-विवाद पर भी कार्य-समिति ने विचार किया और अपना यह मत प्रकट किया कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होने वाले सरक्षणों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को काग्रेस सन्तोषजनक नहीं मान सकती। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस बीच यदि आर्डिनेन्सो तथा हाल के कृत्यों के सम्बन्ध में काफी राहत दी जाय, भावी विचारों और परामर्श में काग्रेस के लिए अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सलाह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार है। इन शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य-समिति इसे सरकार की ओर से बिल्लों के समझौते के रद किये जाने की सूचना समझेगी। सन्तोपजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को कुछ निश्चित शर्तों पर फिर सविनय-अवज्ञा, जिसमें लगान-बन्दी भी सम्मिलित हैं, आरम्भ करने के लिए आह्वान करती हैं।

वाइसराय का उत्तर

गाधीजी के तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को वाइसराय के प्राइवेट-सेकेटरी ने तार-द्वारा सूचित किया कि अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखने वाली कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक सस्था की गैर-कानूनी कार्रवाई की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार में विणत इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है कि दिल्ली के समझौते पर पूरी सावधानी और पूरे घ्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिए। काग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उनके सब परिणामों के लिए हम आपको और काग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और उनके दबाने के लिए सरकार सब आवश्यक अस्त्रों का अवलम्बन करेंगी।

गांधीजी का उत्तर

वाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १६३२ को जो तार भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ लेना

रूप से अपनी नीति वदल ली है और केन्द्रीय सुवारों के आश्वासन के साय प्रान्तीय स्वराज्य पर ही मामला टालने की कोशिश की है। यह भी निश्चय है कि काग्रेस के साय लड़ाई अनिवार्य है; तब हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह शुरू हो जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साय ही हमने यह भी सोच लिया है कि इसमें पूरी सफलता तभी मिल सकती है जबकि जितने हो सकें उन सव मित्रों को अपने पक्ष में करले। मुसलमान तो हमारे साथ है ही, जैसा कि अल्पसल्यक समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट है। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसल्यक जातियों का है।

हमें यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सर संपू, जयकर, पैटरो आदि के समान सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय। अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सके तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई मुश्किल वात भी नहीं है। इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि संघ-योजना को नहीं छोड़ा जायगा। हमने सरकार से आग्रह किया है कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उपस्थित करें, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेंगे और इनका सन्तोंथ हो जायगा। जहातक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जवरदस्ती नहीं लादा जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते। मुसलमान तो अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं। अपनी परिस्थित से उन्हें पूरा सन्तोंथ है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि सुधारों का होना जकरीं है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का ही प्रतिपादन करते हैं। हम जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धित में ऐसे हेर-फेर करना भर हैं, जिससे कि उसकी सुचारता बढ़ जाय।

मजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो कुछ देने का वचन दिया था उसके उद्देश को नप्ट करने को टोरी (कजरवेटिव) सरकार और उसके साथियों ने कैसी चेष्टा की, यह उक्त उद्धरण से भली-भाति मालूम हो जाता है। भारत के विरुद्ध उन्नति-विरोधी ब्रिटिशों के बीच जो समझौता हुआ वह एकाएक नहीं हो गया। उसकी नीव तो गोलमेज-परिषद् के दूसरे अधिवेशन से कही पहले हिन्दु-स्तान और इंग्लैण्ड दोनों जगह रखी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गाधीजी और लॉर्ड अविन के वीच समझौता हुआ तव उसके बाद ही भारत में उन सव उन्नति-विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शीध्रता के साथ अपनी शिक्तयों को सगठित किया और भारतीय राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के लिए अपना सम्मिलत गुट बना लिया था। इस षड्यन्त्र की आशिक रचना तो शिमला में ही हुई थी, जो कि भारत-सरकार का सदर मुकाम है।

दमन-चक्र और गांधोजी की गिरफ्तारी

यह सव एक प्रकार की चुनौती थी। कार्य-समिति ने इस चुनौती को स्त्रीकार कर लिया। वस्तुत सरकार ने वही से लड़ाई को फिर से ग्रहण किया जहा पर कि ४ मार्च १६३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्यायी-सिंघ के दिमियान उसने हजारो लाठिया और एकत्र करली थी। यह अवसर सरकार के लिए नये सिरे से लड़ाई की तैयारी करने का था। इस प्रकार अस्यायी-सिंघ का टूटना निन्चित ही था। तीन आर्डिनेन्स तो जारी कर दिये गये थे, और कई जारी कर देने के लिए वाइस-राय की जेव में रखे हुए थे। ४ जनवरी १६३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। काग्रेम को तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक सस्या को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और काग्रेसी लोगों को गिरपतार करके जेलो में भेजा जाने लगा। सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१६३१) के समय आरम्भ में नहीं, बल्कि वाद में जारी हुआ था, लेकिन १६३२ में मत्याग्रहियों को सबसे पहले उसी का मुकावना करना पड़ा। चारो ओर यह बात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिंगडन सार उत्पात को छ सप्ताह में ही समाप्त कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छ सप्ताह का ममय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई थी कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई।

आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके बाल उखाडे गये और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना नाम और पता नहीं बताया था।

श्राडिनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थित वदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये आर्डिनेन्स निकलते गये। हालांकि वे एक साथ नहीं, विल्क भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एक साथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आर्डिनेन्स का जिक तो पहले ही हो चुका है, जो कि उस समय वगाल में जारी किया गया था जविक गांधीजी लन्दन हो में थे। कहा यह गया था कि यह बगाल में आतकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इंससे यह सत्ता प्राप्त हो गई थी कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय प्राप्त करें और उसकी बताई हुई बाते ठीक है या नहीं, इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक या इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान ले सकता था।

उत्तर प्रदेशीय इमर्जेन्सी-आर्डिनेन्स १४ दिसम्बर १६३१ को जारी हुआ। इसके द्वारा प्रातीय सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी अथवा जमीदार को दी जानेवाली किसी रकम को सरकारी पावना करार देकर उसे बकाया मालगुजारी के रूप मे वसूल करे। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि वह सरकारी पावने को न अदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैंद, जुर्माना अथवा दोनो सजाये दी जा सकती थी। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-भाति अदा न करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल कैंद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। किसी जब्त साहित्य के अश दोहराने-वाले को ६ महीने कैंद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत में कानूनों कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थीं। सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ को जारी किये गये। उनमें से एक तो उत्तर प्रदेशी आर्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लहने की वसूली के लिए निकाला गया था। बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रातीय 'इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स' था और दूसरे का 'अनलाफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स'। इनमे से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति किसी भी सन्दिग्ध-व्यक्ति को विना किसी कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढाई जा सकती थी। जिला-मिजरट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायरलेस (वेतार के तार) को निय-न्त्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजो अथवा चिट्टी-पित्रयो को रोक सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था और रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उतरवा सकता था।

४ जनवरी को चार नये आर्डिनेन्स और जारी हुए—(१) इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स, (२) अनलॉफुल इस्टिगेशन आर्डिनेन्स, (३) अनलॉफुल असोसियेशन आर्डिनेन्स और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड वायकाट आर्डिनेन्स। इनमें से पहले आर्डिनेन्स के मातहत तो लोगो को गिरफ्तार करने, वन्द रखने या उसकी हलचलो को नियन्त्रित करने, इमारतो को माग लेने, इमारतो या रेलवे को वर्जित-स्थान करार देने, यातायात को नियन्त्रित करने, सर्व-साधा-रण के व्यवहार की किती चीज को अपने कब्जे मे करने या उसकी खपत व विकी पर नियन्त्रण करने, यातायात के साधनो पर नियन्त्रण करने, शस्त्रास्त्र की विकी पर नियत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमीदारो और अध्या-पको आदि को कानून और व्यवस्था कायम रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, सार्वजिनक उपयोग के कामो पर नियन्त्रण करने, डाक, तार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजो तथा चिट्टी-पित्रयों को रोकने और वीच में गायव कर लेने, रेलो और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके यातायात पर नियन्त्रण करने, समाओं में पुलिस अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही अधिकार दिये गये थे जैसो का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। 'अनलॉफुल इस्टिगेशन आर्डिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इश्तिहारी पावना घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी मे वायक होता उसे ६ महीने कैंद और उसके साथ जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। जिसकी ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी कलक्टर से यह कह सकता था कि इने वर्तार माल-गुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे माल-गुजारी के वकाया के रूप में वनून करवा सकता था। 'अनलॉकुल असोसियेशन आर्डिनेन्स' के मानहन प्रान्तीय-मरकार गैरकानूनी करार दी गई नस्या की इमारत और उनकी चल-सम्पत्ति तथा रुपये-पैसे को अपने कट्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये-पैसे को प्रातीय सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तग करते और उसका वहिष्कार करते या उसे तग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होने थे।

इस प्रकार इन आर्डिनेन्सो के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे। ऐसे आर्डिनेन्सो और दमनकारी अस्त्रो को तैयार करने का विचार तो अस्थायी-सिंघ के पूर्व से ही हो रहा था।

कार्य-समिति की तत्परता

सरकारी आक्रमण ४ जनवरी क बडे सबेरे म० गाघी और राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १६३२ के उपर्युक्त आर्डिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये। पश्चात् कुछ ही दिनो मे, अमली तौर पर, सारे देश मे लागू हो गये। अनेक प्रान्तीय और मातहत काग्रेस-किमटियो, आश्रमो, राष्ट्रीय स्कूलो तथा अन्य राष्ट्रीय सस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतो, फर्नीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कब्जे मे ले लिया गया। देश के खास-खास काग्रेसियो मे से अधिकाश को एकदम जेलो मे ठूस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते काग्रेस के पास न तो नेता रहे, न रुपया-पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इन आकस्मिक और दृढ झपट्टे के बावजूद जो काग्रेसी बच रहे थे वे साधन-हीन नही हो गये थे। जो जहा था वही उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-सिमिति ने तय कर लिया कि १६३० की तरह ही बार खाली होनेवाली स्थानो की पूर्ति न की जाय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिर-पतारी का खेयाल करके, अपने बाद ऋमश कार्य करनेवाले व्यक्तियो की एक सूची बना दी थी। कार्य-सिमिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपूर्द कर दिये और अध्यक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौप दिया, जो कमरा अपने उत्तरा-धिकारियो को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तो मे भी, जहा कही सम्भव हुआ, काग्रेस-सगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलो, थानो, ताल्लुको और गावो तक की काग्रेस-कमिटियो में भी हुआ। यही व्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। शराब और विदेशी कपड़े की दुक़ानो तथा ब्रिटिश माल की निकेटिंग सब प्रान्तो में समान-रूप से लागू हुई। लगानबन्दी उत्तर प्रदेश में काफी बडी हद तक और बगाल मे आशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा। बिहार और बगाल के कुछ स्थानो मे चौकीदारी-टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त तथा वरार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मद्रास प्रेसीडेन्सी और बिहार के कुछ स्थानो मे जगलात के कानून तोड़े गये। गैरकानूनी नमक बनाने, उसे एकत्र करने और बेचने के रूप मे नमक-

कानून भंग तो अनेक स्थानों में किया गया। सभाओं और जलूसों की तो जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभाये हुई और जलूस भी निकाले गये। लडाई की शुरुआत में खास-खास दिनो का मनाया जाना वहुत लोकप्रिय रहा। जैसा कि अभी कह चुके हैं, काग्रेस के दफ्तरो तथा आश्रमों को सरकार ने अपने कब्जे मे कर लिया था। अतः अनेक स्थानो मे उन्हे सरकारी कव्जे से वापस लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आर्डिनेन्स का भग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया था। ये प्रयत्न 'घावो' के नाम से मशहूर हुए। आर्डिनेन्सो के कारण कोई प्रेस काग्रेस का काम नहीं कर सकता था। इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजान्ता हस्तपत्रक, परचे, सवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि निकाले गये। यह मार्के की वात है कि पुलिस के सतर्क रहने पर भी ये सवाद-पत्र और हस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होने रहे। इससे उस समय सारे देश को खबरे मिल जाती थी। डाक और तार विभाग के दरवाजे काग्रेस के लिए बद हो गये थे, इसलिए काग्रेस ने अपनी डाक को खुद ही पहुंचाने की व्यवस्था की। कभी-कभी यह डाक ले जाने वाले स्वयसेवक पकड़े भी गये और तब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। १६३० के आन्दोलन के उत्तराई में वस्तुत यह प्रया प्रारम्भ हुई थी बार १६३२ में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुच गई। और तो और, महासमिति अयवा मान्तीय कमिटियों के देपतरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे विल्क आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायते भी जारी होती रहती थी। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बडा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधि-वेशन का किया जाना था। इसके बाद प्रान्तो तथा जिलो की परिषदो के रूप मे देश-भूर में काग्रेस-सम्मेलनो की झडी लग गई। कई जगह स्वयसेवको ने जजीर खीचकर चलती रेलगाडियो को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम-काज में खनल डालने की कोशिश की। एक वार तो रेनो को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत वडी तादाद में विना टिकट रेल मे जाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदार हलको ने इस चेण्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला। इसलिए वाद में यह नेप्टा वन्द कर दी गई।

वहिष्कार ने वहुत जोर पकडा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उम पर गिवतया केन्द्रित की गई। कई स्यानो में विदेशी कपढे, ब्रिटिश दवाइयो, ब्रिटिश वैको, वीमा-कम्पनियो, विदेशी शक्कर, मिट्टी वा तेल और लाम तौर पर ब्रिटिश माल के वहिष्कार का जोरदार बान्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निरिचन किये गये।

पए तो सयान ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर नेने के

बाद सरकार खामोश अथवा नरम पड गई। आर्डिनेन्सो मे उल्लिखित सब अधि-कारो का उसने उपयोग किया। यहा तक कि दमन के कुछ ऐसे तरोके भी अस्ति-यार किये गये जिनकी उन आर्डिनेन्सो तक मे इजाजत नही थी। गिरफ्तारियाँ बहुत वडी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर्। सजा पानेवालो की कुल सख्या एक लाख से कम न थी। इन कारणो से जेल-अधिकारियो के साथ अक्सर उनका सवर्ष हो जाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजाये उन्हें दो जाती रही जिनकी जेल के नियमो में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई तथा दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगने के भँग से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते है। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत मे भी पहुचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नातिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई, परन्तु सत्याग्रही कैदियों के लाठों से पोटे जाने की घटनाये तो अक्सर ही होती रही। अस्थायी जेलो मे रहना तो बिलकुल ही नाकाविल बर्दाश्त था, क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पडे हुए थे उनसे न तो मई-जून को गरमी का बचाव होता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे वहा तन्दुरुस्ती अच्छी रह नही सकती थी। अनेक जेलो मे, खासकर कैम्प-जेलो मे, कैदियो का स्वास्थ्य बहुत बिगड रहा था । पेचि रा का तो सभी समय जोर था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया तथा फेफडे की नाजुक बोमारियो ने भी बहुतो को दबोचा था। फलत अनेक तो जेलो मे ही मर गये।

लाठी मार-मारकर लोगो की भीड और जलूसो को भग करने का तरीका तो पुलिस ने आरम हो में अिस्तयार कर लिया था। जेलो तथा मार-पिटाई की सिस्तयों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने को भी तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-से उसे बरदाश्त न कर सकेगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारो-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानो की रकम पाच अंको तक चली जाती थी। जहा मालगुजारी, लगान अथवा अन्य करो का देना बन्द किया गया वहा तो ऐसी बकाया रकमो और करो की तथा जुर्मानो की वसूली के लिए न केवल उन्ही लोगो की मिल्कियत पर घावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूल करना वाजिब था, बल्कि साथ में सयुक्त परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके वेच डाली गई। कुर्की और विकी तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहा तो कुर्की के बाद बड़ी-बड़ी कीमत की मिल्कियतों को बिल्कुल कौडी के ही मोल बेच डाला गया। कई स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्च वहा के

निवासियों से वसूल किया गया। विहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहा जहा ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वहा के निवासियों से ताजीरी-कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (बगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकाश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोडकर आस-पास के स्थानों में चले गये।

अखबारों को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से जमानते मागी गई, बहुतों की जमानते जब्त की गई, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमा न कर सकने या प्रेस जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा। इस आतक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं किया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जब कि सरकार ने तो चन्द हफ्ते में ही उसे खत्म कर देने की आशा की थी।

दिल्ली-कांग्रेस : १९३२

इन्हीं दिनों दिल्ली-अधिवेशन भी हुआ। यह १६३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। यह पुसिस को बड़ी भारी सतर्कता के बावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था।

चादनी चौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के बावजूद लगभग ५०० प्रतिनिधि जैसे-तैंसे सभा-स्थान पर जा पहुंचे थे। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेशन की जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिर्फ चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में कही तलाश करती रही और कुछ पुलिस एक जगह अकालियों के जलूस से निपटती रही। पेश्तर इसके कि वह घण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी। अहमदाबाद के सेठ रणछोडदास अमृतलाल उसके सभापित थे। उसमें काग्रेस की सालाना रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई कि पूर्ण-स्वाधीनता ही काग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवशा के फिर से जारी होने का हार्दिक समर्थन किया गया, तीसरे में गाधीजों के आह्वान पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उन्हें वधाई दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदिश्त किया गया, तथा चौथे में अहिंसा में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए काग्रेस को, खासकर सीमाप्रात के बहादुर पठानों को, अधिकारियों की ओर से अधिक-से-

अधिक उत्तेजना की करतूते की जाने प्रभी अहिसात्मक रहने पर वधाई दी गई।

प॰ मदनमोहन मालवीय दिल्ली अधिवेशन के मनोनीत सभापित थे, लेकिन वह तो रास्ते में हो गिरफ्तार कर लिये गये थे। वैसे काग्रेसियो में उल्लेख-योग्य वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्या एव गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद् से लौटने के बाद, वह कभी शांति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादितयों का पर्दाफाश करनेवाल वक्तव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अद्भुत शक्ति से काग्रेस-कार्यकर्ताओं को मोत्साहन प्रदान करते रहे। जब कभी कोई सन्देह अथवा कठिनाई का प्रसग उपस्थित होता, काग्रेस-कार्यकर्ता उन्हों को ओर मुखातिब होते थे और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।

गांधीजी का उपवास

दूसरी गोलमेज-परिषद् में गाधीजी ने अपना यह निश्चय सुनाया था कि अस्पृश्यों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेष्टा की गई तो मैं उस चेष्टा का अपने प्राणो की बाजी लगांकर 3भी मुकावला करूँगा। अब गांधीजी के उस भीषण-त्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुँचा था। लोथियन-कमिटी, मताधिकार और निर्वाचन की सीटो का निर्णय करने के लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुची थी। इसीलिए बहुत सोचने-समझने के बाद, गाधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर को ११ मार्च को एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अस्पृश्यो या दलित-जातियो के लिए पृथक निर्वाचन रखा तो मै आमरण-उपवास करूंगा। सर सेम्युअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रैल १६३२ को भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की लकीर का उदाहरण था। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय सुनाया गया। दलित-जातियो को पृथक् निर्वाचन का अधिकार तो मिला हो, साथ हो आम निर्वाचन मे भी उम्मीद-वारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का उन्हें अधिकार दिया गया। १८ अगस्त को गांघीजों ने अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान मत्री को सूचित कर दिया। उन्होने यह भी कहा कि व्रत यानी उपवास २० सितम्बर (१६३२) के तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया गया। प्रवान-मत्री ने गाधीजी को दलित-जातियो के प्रति शत्रुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। व्रत २० सितम्बर १६३२ को आरम्भ होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और वृत आरम्भ होने में एक सप्ताह था। यह सप्ताह देश ही क्या, ससार-भर के लिए क्षोभ, चिन्ता और हलचल का

सप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमे व्यक्तियो और सस्थाओं ने उस क्षण जो ठीक समझा किया। गाधीजी से भेट करने की अनुमति मांगी गई, पर न मिली । संसार के कोने-कोने से पूना को तार भेजे गये। गांधीजी का सकल्प छुडाने के लिए तरह-तरह की सलाहो और तर्कों से काम लिया गया। सोचा गया, एक परिषद् करना अच्छा होगा। यह बडी अच्छी बात हुई कि दलित जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढाया। रायबहादुर एम० सी० राजा ने पृथक् निर्वाचन को धिक्कारा। सर सप्रू ने गाधीजी की रिहाई की माग पेश की। काग्रेस-वादियों ने भी स्वभावत देश-भर में सगठन करके समझौता कराने को चेष्टा को। मालवीयजी ने तत्काल नेताओं की एक परिषद् बुलाने की बात सोची। इगलैंड में दीनबन्धु एण्डरूज, मि० पोलक और मि० लेन्सबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अग्रेज-जनता का घ्यान आकृष्ट किया। एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा इंग्लैंड-भर मे खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष मे २० सितम्बर को उप-वास और प्रार्थनाये की गईं। इसमें शाति-निकेतन ने भी भाग लिया। वैसे इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन को अस्पृश्यता निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप धारण करते देर न लगी। कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानो मे अस्पृश्यो के लिए मदिर खोले जाने लगे। यह आशा की जाती थी कि गाधीजी उपवास के आरभ होते ही छोड दिये जायगे। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, उन्हें किसी खास स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी हकावट लगा दी जायगी।

पूना-पैक्ट श्रोर उपवास का श्रन्त

पूना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके कम-विकास में पाठकों को ले जाना हमारे लिए सम्भव नहीं है। परिषद् बम्बई में आरम्भ हुई, पर शीघ्र ही पूना में ले जाई गई। डा॰ अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत में शामिल हो गये और श्री अमृतलाल ठक्कर, श्री राजगोपालाचार्य, सर चुन्नीलाल मेहता, पण्डित मालवीय, बिडलाजी, सरदार पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडूं, श्री जयकर, डाँ॰ अम्बेडकर, रायबहादुर एम॰ सी॰ राजा, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, पडित हृदयनाथ कुजरू और अन्य सज्जनों की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिसे उपवास के पाचवे दिन सारे दलों ने स्वीकार कर लिया। दिलत जातियों ने पृथक् निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनों से ही सन्तोष कर लिया। उच्च जातियों के हिन्दुओं ने महत्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किया। निश्चय हुआ कि पूरा समझौता उस समय तक कायम रहे जब तक सब की सलाह से उसमें परिवर्तन

न किया जाय और दलित-जातियों का प्रारम्भिक निर्वाचन दस साल तक जारी रहे। ब्रिटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट के उस अश तक को स्वीकार कर लिया जिस अश तक उसका प्रवान-मंत्री के निश्चय से सम्बन्ध था। जो-जो बाते साम्प्रदायिक निर्णय के वाहर जाती थी, उनपर निश्चय रोक रखा गया। दलित-जातियो के नेताओं को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मत्री के निश्चय के अनुसार उन्हें जितनी जगहें मिलने वाली थी, अब उन्हें उनसे दुगुनी मिल गईं और उन्हें अपनी जन-सख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष वाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय में फिर विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्त मे यह निरुचय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझौते-द्वारा तय किया जाय। २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल द्वारा सम-झौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकूर ने गांधीजी से भेंट की। २६ तारीख की सुबह को इंग्लैंड और भारत में एक साथ घोषणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर लिया गया।

गाधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पशोपेश हुआ। वह चाहते थे कि दलित-जातियों के नेता भी सन्तुष्ट हो जाय। उन्हें अपने भौतिक प्राण बचाने की चिन्ता न थी, बल्कि उन लाखो प्राणियों के नैतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए वह उपवास कर रहे थे। परन्तु अन्त मे प० हृदयनाथ कुजरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गाधीजी को सन्तोष करा दिया। इसपर गाधीजी ने ६ तारीख को शाम के सवा पाच वजे उपवास छोड़ने का निश्चय किया। भजन और धार्मिक क्लोक-पाठ के बाद उन्होने पारण किया। यह ठीक था कि गाधीजी के प्राण वच गये, परन्तु जिस स्वास में वह अपना उपवास भग करने को राजी हुए उसी में उन्होंने यह भी कह दिया कि यदि उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुधार नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया तो मुझे नये

सिरे से उपवास करना पडेगा।

हरिजन-श्रान्दोलन

प्रधान-मत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने और गाधीजी के उपवास छोडने के बाद ही २५ सितम्बर, १९३२ को परिपद् ने बम्बई मे सभा की। परिषद् के सभापति प॰ मदनमोहन मालवीय थे। इसमे एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का निवारण करेगे। जो संस्था बाद को हरिजन-सेवक-सघ के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई। इसके सभापित सेठ घनश्यामदास बिडला और मत्री भारत-सेवक-सिमिति के श्री अमृतलाल ठक्कर हुए। इस प्रकार गाधीजी के पवित्र तप का स्वभावत ही पूरा परिणाम निकला।

अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। खतरा इसी बात का था कि कही युवक जल्दबाजी से काम न ले। इसलिए गाधीजी को लगाम खीचनी पड़ी। हरिजनों के लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू था निक आन्दोलन के लिए ५००० दिये। फादर विन्स्लों ने अपने अन्य सहधीनयों के हस्ताक्षर के साथ एक अपील छपवाकर ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को धिवकारा। उधर मौलाना शौकतअली गाधीजों की रिहाई का आग्रह कर रहें थे और इस बात पर जोर दे रहें थे कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार बातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात २६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्त्तन करके गाधीजों से मुलाकात आदि करने की सुविधाये देती तो साम्प्रदायिक समझौता भी अवश्य हो जाता। परन्तु मुलाकाते बन्द कर दी गईं। गाधीजी अव वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे।

कलकत्ता-कांग्रेस : १८३३

अप्रैल १६३२ के दिल्ली-अधिवंशन की भाति कलकत्ता का अधिवंशन भी निषेधाज्ञा के होते हुए करना पडा। यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया था जब सत्याग्रह-आन्दोलन शिथिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहा दिखाई पडी वह दिल्ली में भी न दिखाई पडी थी। कुछ प्रान्तो ने तो अगने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तो से चुने गयं। इस बात से कि प० मदनमोहन मालवीय ने अधिवंशन का सभापितत्व स्वीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ गया। श्रीमती मोतीलाल नेहरू ने वृद्धावस्था और दुबंलता का घ्यान न करके अधिवंशन में भाग लेने का जो निश्चय किया उससे आनेवाल प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्ति मिली। अधिवंशन कलकत्ता में ३१ मार्च को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ। डॉ० प्रफुल्ल घोष स्वागत समिति के अघ्यक्ष थे। सरकार ने अधिवंशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रखा। पिछत मदनमोहन मालवीय को बीच ही में आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ० सैयदमहमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापित के साथ थे, गिरफ्तार कर लिये गये और सबको आसनसोल की जेल में ले जाया गया। काग्रेस के कार्यवाहक सभापित श्री अणे भी कलकत्ता जाते हुए गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज दिया गया। कलकत्ते में स्वागत-समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। और कई काग्रेस-नेताओ पर प्रतिवन्य लगा दिया गया। श्रीमती नेती सेन गुप्त और डॉ॰ मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिधि

रवाना होने से पहले ही, कलकत्ते के मार्ग मे, गिरफ्तार कर लिये गये। वाकी प्रतिनिधि नगर में पहुचने में सफल हुए। निषेवाज्ञा होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये। शीघ्र ही उनपर पुलिस आ ट्टो और काग्रेस-वादियों के शान्तिपूर्ण-समुदाय पर लाठिया बरसाने लगी। बहुत-से प्रतिनिधि बुरी तरह घायल हुए और श्रीमती नेली सेन गुप्त और अन्य प्रमु व काग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-हारा हान से रोकने की चेष्टा की, परन्तु असफल रही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भोतरी समूह अपनी-अपनी जगहों पर जमा रहा, और वे सातो प्रस्ताव पढकर सुनाये गये और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकाश व्यक्तियों को काग्रेस समाप्त होते ही छोड दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजाये दी गईं। श्रीमती सेन गुप्त को भी छ मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय सीधे कलकत्ता पहुचे और शीघ्र ही देश के सामने इस बात का कि पुलिस ने किस प्रकार अमानुषिकता के साथ काग्रेस भग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होने सरकार को जाच करने की चुनौती दी, पर वह चुनौती कभी स्वीकार न की गई।

गांधीजी का उपवास

कलकत्ता काग्रेस के बाद शोध्र ही देश में एक घटना हुई जो बिल्कुल आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सख्या उत्तरोत्तर बढ रही थी। इन कार्यकर्ताओं को अपना काम पवित्रता, सेवा-भाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गाधीजी ने प मई १६३३ को आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उन्होने कहा कि यह अपनो और अपने साथियो की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानी के साथ काम कर सके, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए मै अपने भारतीय तथा ससार-भर के मित्रो से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करे कि मै इस अग्नि-परीक्षा में संकुशल पूरा उतरू, और चाहे मैं मरू या जियू, मैने जिस उद्देश्य से उपवास किया है, वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयो से अनुरोध करता हू कि वे प्रार्थना करे कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरा ढकना, जिसने सत्य को ढक रक्ला है, हट जाय। एक पत्र-प्रतिनिधि से उन्होने कहा कि किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजको की बौद्धिक या भौतिक शक्तियो पर निर्भर नहीं करती, विल्क आत्मिक-शक्ति पर निर्भर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-पूछा उपाय है।

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमे कहा गया कि उपवास जिस उद्देश्य से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होने वाली मनोवृत्ति को घ्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि

वाला मनावृत्ति की क्यान म रखत हुए, मारत-सरकार न निश्चय किया है कि वह (गावोजो) रिहा कर दिये जाय। तदनुसार गाघीजी म मई को छोड दिए गये। रिहा होते ही गाघीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित रखने की सिफारिश की। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैं इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूं, और जैसा कि कल मुझसे सरदार वल्लभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, मैं इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का सचालन अथवा पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूं? पर साथ ही, रिहाई होने पर अव मैं अपनी थोडो-वहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का अघ्ययन करने में लगाने को बाध्य हू। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हू कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असस्य सत्याग्रहियो की वीरता और आत्मत्याग के लिए मेरे पास साधुवाद के सिवा और कुछ नही है। इतना कहने के बाद मैं यह कहे विना भी नहीं रह सकता कि यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का सचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिना कान छोड़ दो। यदि इससे एक सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आर्डिनेन्स का शासन सम्य-शासन नहीं है तो उसे इस आन्दोलन-बन्दों से लाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियों को विना किसी शर्त के छोड देना चाहिए। अन्त में गाधीजी ने कहा कि मैं शान्ति चाहता हू और सरकार को बता देना चाहता हू कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग न करूगा और यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पडा तो मैं सिवनय-अवज्ञा को वढाने की लुक-छिनकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये विना ही सरकार से कहूगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिन्हें मैं इस समय त्याग-सा आया हू, यर-व जा पहुचा दिया जाय।

सत्यामह स्थगित

गाधीजी की घोषणा के बाद ही काग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह-आन्दोलन छ सप्ताह के लिए स्यगित कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विलम्ब से काम नही लिया।

६ मई को एक सरकारी विज्ञिष्त में कहा गया कि केवल सत्याग्रह स्यगित

करने से वे शर्ते पूरी नहीं होती जो कैंदियों की रिहाई के लिए रखीं गई हैं। सरकार काग्रेस से इस मामले में सौदा करने को तैयार नहीं है। इधर शिमला से यह नकारा-त्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य आया जिसपर श्री विट्ठलभाई पटेल और श्री सुभाष वसु के हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया कि सत्याग्रह वद करने की गांधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति हैं।

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि हमारी यह स्पष्ट सम्मित है कि गाघीजी राजनैतिक नेता की हैसियत से असफल रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम नयें सिद्धातों के ऊपर नयें उपाय को लेकर काग्रेस की कायापलट करें। हमें इसके लिए एक नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गाघीजी से यह आशा करना अनु-चित है कि वे ऐसे कार्य-कम को हाथ में लेगे जो उनके जीवन-भर के सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो। यदि काग्रेस में स्वय ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन हों सके तो अच्छा ही है, नहीं तो काग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बनानी पडेगी।

यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों संभ्रान्त व्यक्तियों की विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पड़ा हो। गांधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट सन्तोष, आस्था और धैंयें के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने ससार की आलोंचना भी सह ली। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २६ मई १६३३ को उन्होंने अपने उपवास का अन्त किया। इस बीच काग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिला है उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हो। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अविष् को कार्यवाहक सभापित ने छ सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया।

पूना-परिषद्

१२ जुलाई १६३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में काग्रसवादियों की अनियमित बैठक हुई। श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिषद् का श्रीगणेश किया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिषद् के सम्मुख सक्षेप में रख दिये। इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिषद् दूसरे दिन के लिए स्थिगत कर दी गई। दूसरे दिन की कार्रवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक लम्बे-चौंडे वक्तव्य-द्वारा किया। इसके बाद परिषद् ने सत्याग्रह को बिना किसी शर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत-सत्याग्रह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। अन्त में परिषद् ने गांधीजी को सरकार से समझौता करने के लिए वाइसराय से मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को

तार देकर शान्ति की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश्य से उनसे मिलने की अनुमित चाही। पर वाइसराय ने उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर दिया जवतक काग्रेस सत्याग्रह-आन्दोलन वापस न ले ले। गाधीजी ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह दिखा देगे कि कुल मिलाकर कार्रवाई सम्मानप्रद समझौता करने के पक्ष में हुई है। पर गाधीजी की शाति-स्थापना की चेंप्टा का कोई उत्तर न मिला और राष्ट्र को अपना सम्मान अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध जारी करने को बाध्य होना पडा। पर सामूहिक सत्याग्रह वन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। कार्यवाहक-समापित के आज्ञानुसार सारी काग्रेस-संस्थाये और युद्ध-समितिया उठा दी गई।

व्यक्तिगत-सत्यात्रह

गावीजी ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान् से मूल्यवान वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था। उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमित्रत किया। उन्होंने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी जगम संपत्ति को कितपय सस्थाओं को सार्वजिनक उपयोग के लिए दे दिया। वह किसी दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुंच में एक पिनत भेजी गई।

सावरमती-श्राश्रम का दान

जव सरकार ने गाधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तव उन्होंने आश्रम को हरिजन-आदोलन को अंपंण कर दिया। इस सम्वन्य में गांधीजी का वह वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १६३० में दण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जवतक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम में वापस न आयेगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ को देकर उन्होंने पार्थिव-जगत से वांच रखने वाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भवत. उनके हृदय में मोह वना रहता था, अंत कर दिया।

गांधीजी की गिरफ़्तारी

१ अगस्त १६३३ को गांधीजी रास नामक गाव की यात्रा करने वाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-वानियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गाधीजी ४ अगस्त की सुवह को छोड दिये गये और उन्हें यरवडा गाव की सीमा छोडकर पूना जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस आज्ञा की निश्चय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के आधे घण्टे के भीतर गाधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें एक वर्ष की सजा दी गई।

व्यक्तिगत-सत्याग्रह की सफलता

जनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत-सत्याग्रह सारे प्रान्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैंकडो कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हो गये। काग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष श्री अणे अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्द्वलिंसह कवीश्वर की बारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी के पहले आज्ञा जारी की कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद और डिक्टेटरो की नियुक्ति का सिलिसला तोड दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत-सत्याग्रह का रूप धारण करले। गाधीजी ने जो मार्ग दिखाया था उस पर १६३३ के अगस्त से १६३४ के मार्च तक देशभर में काग्रेस-कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट ताते ने युद्ध को जारी रखा।

गांधीजी की रिहाई

सरकार ने जेल में गांधीजी को उन सुविधाओं से विचत कर दिया जो मई में उनकी रिहाई से पहले उन्हें दी गई थी। इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर अनशन आरम्भ करना पड़ा। सरकार अड़ी रही। गांधीजी की अवस्था बड़ी शींघ्रता के साथ शोंचनीय होने लगी। अन्त में उन्हें २० अगस्त को, अर्थात् अनशन के पाचवे दिन, पूना के सैसून-अस्पताल में कैंदी की हैसि-यत से पहुचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके प्राण सकट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। जेल से छूटने पर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आप को रिहा न समझना चाहिए और अपनी सजा की अवधि अर्थात् ३ अगस्त १६३४ तक, सयम से काम लेना चाहिए। वह स्वय तो सत्याग्रह न करेगे, पर जो लोग उनसे सलाह मागेगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायेगे और इस अवधि के अधिकाश माग को वह हरिजन-आन्दोलन की उन्नित में लगायेगे।

हरिजन-श्रान्दोलन

गाधीजी ने अपने निश्चय के अनुसार हरिजन-आन्दोलन करने के लिए १६३३ के नवम्बर से देश में दौरा शुरू किया। उन्होने दस महीने के भीतर भारत के

हरेक प्रान्त का दौरा किया। इस दौरे से बहुत प्रचार-कार्य हुआ। उन्होंने लगभग आठ लाख रुपया एकत्र किया। साथ ही दो शोचनीय दुर्घटनाये भी हुई। २५ जून १६३४ को गाधीजी बाल-बाल बच गये। वह पूना म्युनिसिपैलिटी का मान-पत्र ग्रहण करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने उन पर बम फेका। वह उस मोटर मे नहीं थे जिस पर बम फेका गया था, फिर भी उसके बम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया। दूसरी घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई। यहां किसी तेज मिजाज सुधारक ने आपे से बाहर होकर बनारस के पण्डित लाल-नाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गाधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायश्चित्त उसी के विरुद्ध किया गया था।

गाधोजी ने हरिजनोत्थान-कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ। श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-मिन्दर के ट्रिस्टियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १६३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केलप्पन और गाधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवयूर-मिन्दर् के उपासकों की राय ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इसी बोच डा० सुब्बारायन ने मद्रास-प्रान्त के मिन्दरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया। बिल बहुमत से पास हो गया।

बिहार का भूकंप

१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के समाचार पत्रों ने गत तीसरे पहर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुंचाये तब सब लडखड़ा कर रह गये। कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक असम्भव हो गया। हजारों इमारते धूल में मिल गईं और पृथ्वी के गर्भ में समा गईं। पलक मारते हजारों परिवार अनाथ और हजारों स्त्रिया विधवा हो गईं और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच दब कर मर गये। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० वर्ग मील की लगभग डेढ करोड़ जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यों के प्राण गये। लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये। ६४,००० कुएं और तालाब या तो निकम्मे हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकम्मी हो गई। इस भयंकर सकट का सामना करने के लिए बिहार और भारत दोनों पीछे न रहे। चन्दे द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ।

बिहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त तक २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकाश नेता और कार्यकर्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों से पीडितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड पडे।

विहार के विघ्वस्त-प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दबे पड़े हैं, तब उन्होंने स्वयसेवक का विल्ला लगाया, कबे पर फावड़ा रखा और उस स्थान को रवाना हो गये। उनके साथ-साथ स्वयसेवक हाथों में फावड़े लिये मौजूद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावड़े चलाये और मिट्टो की टोकरिया अपने सिरो पर ढोयी। गाधीजी ने एक मास तक उनका पथ-प्रदर्शन किया और उन्हें परामर्श दिया। जबतक वह बिहार में रहे, उन्होंने पीडित नगरों और गावों का दौरा किया और जनता की दयनीय दशा को स्वय देखा। उन्होंने अपने दक्ष कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और उनको सेवाये बिहार को अपण कर दीं।

जवाहरलाल की गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश की सरकार ने जवाहरलाल को ३० अगस्त को छोडा था। इसके कुछ मास वाद ही वह बिहार गये। बिहार का दौरा समाप्त करने पर वह एक बार फिर सरकार के कैंदी बने। जब वह कलकत्ता गये थे, तब उन्होंने बगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे। उन्होंने अपने स्पष्ट भाषणों में, आतकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। बगाल की नौकरशाही को यह सहन न हुआ। जबतक वह बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बगाल-सरकार के औचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने से रोक रक्खा, पर अभी वह अपने घर भी नहीं पहुँचे थे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष सादी कैंद की सजा दी गई।

कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम

जुलाई १६३३ की पूना-परिषद् के बाद से ऐसे काग्रेसवादियों की सख्या में वृद्धि हो रही थी, जिनका यह विचार था कि आर्डिनेन्स-शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको घ्यान में रखकर इस 'निश्चेष्टा' से उद्धार पाने के लिए कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अपनाना आवश्यक है। इस विचार ने सगठित रूप धारण किया और इस प्रकार के विचार रखनेवाले काग्रेसी-नेताओं की एक परिषद् दिल्ली में ३१ मार्च १६३३ को डाँ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुई।

इसमे निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी मंग कर दी गई है उसे दुबारा जीवित किया जाय और मतदाताओं को अच्छी तरह सगठित करने तथा गाधीजी के जुलाई १६३३ वाले पूना-वक्तव्य के अनुसार काग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाय। इस परिषद् ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कौसिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए परिषद् ने निश्चय किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर लड़े जायं: (१) सारे दमनकारी कानूनों को रद कराना और (२) ह्वाइट-पेपरकी योजनाओं को रद कराकर उनका स्थान उन राष्ट्रीय मागों को दिलाना जिनका जिक गांधोजी ने गोलमेज-परिषद् में किया था। परिषद् ने यह निश्चय करने के बाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई और डॉ० विधानचन्द्र राय का एक शिष्टमण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे बातचीत करें और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले।

इस अवसर पर गाधीजी बिहार के भूकम्प-पीड़ित स्थानो का दौरा कर रहे थे और सयोगवश अपना मौन-दिवस (२ अप्रैल, १६३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर बिता रहे थे। यही उन्होने दिल्ली का हाल-चाल जाने बिना ही एक वक्तव्य तैयार किया, जिसे वे प्रेस में देना ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्सारी का सन्देश आया कि कल दिल्ली-परिषद् ने एक शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। गाधीजी ने उस शिष्ट-मण्डल से बात-चीत होने तक वह वक्तव्य रोक रखा और अन्त में अच्छी तरह बात-चीत होने के बाद ७ तारीख को उसे प्रकाशित किया। डॉ० अन्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि गाधीजी ने अपनी हार्दिक और स्वत दी हुई सहायता द्वारा काग्रेस में विरोध और भेदभाव की आशका को दूर कर दिया है। अब कौसिलो के भीतर और बाहर रहकर दुहरा युद्ध किया जाय जिससे शिक्षित समाज और जनता की राजनैतिक निष्क्रियता और अन्ततः कृपित असतोष दूर हो जाय।

महासमिति की बैठक

१६३४ की २ और ३ मई को राची मे एक बैठक स्वराज्य-पार्टी को शक्ति-शाली और सजीव संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश्य से की गई। ३ मई १६३४ को राची-परिषद् ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्य-क्रम निश्चित किया उसमे उन सारे कानूनो और विशेष विवानो को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग मे बाधक हों, रद कराने की बात रखी गई। इस कार्य-क्रम के अनुसार सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई कराना, उन सारे कानूनो और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करने वाले हो, ग्राम-सघटन करना, मजदूर सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मामलो में सुधार करवाना और अन्त में काग्रेस का रचनात्मक कार्यंक्रम पूरा करना कर्तव्य माना गया। इन सब विषयो पर १८ और १६ मई १६३४ को पटना में महासमिति की वैठक में चर्चा हुई। यहा यह बात भी कह देना जरूरी है कि काग्रेस की महासमिति ही एक मात्र एसी सस्था थी जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह वन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि महासमिति पण्डित मदनमोहन मालवीय और डॉ० अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बोर्ड का नाम होगा—'पार्लमेण्टरी-बोर्ड' और इसके प्रधान डॉ० अन्सारी होगे। इसमें २५ से अधिक काग्रेसवादी न रहेगे। यह बोर्ड काग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, उसे रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा। यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। यह अपना विधान तैयार करेगा जो कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रखा जायगा। बोर्ड केवल ज़न्ही उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलों में काग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चत किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेगे।

कार्य•समिति के निश्चय

महासमिति की बैठक के आगे-पीछे काग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी १८, १६ और २० मई को पटना में हुई। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशे की, जिन्हें महासमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्यसमिति ने, महासमिति के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे काग्रेस-वादियों को उसका पालन करने का आदेश दिया। देश-भर के काग्रेसवादियों ने इस निश्चय का पालन किया और २० मई १६३४ को सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। सत्याग्रह-बन्दी के साथ ही कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद स्वभावत ही उठा दिया गया। काग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में सेठ जमनालाल बजाज कार्य-समिति के सभापित बनाये गये, और काग्रेस के नये अधिवेशन तक उन्हें काग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार दिया गया।

पटना के निश्चय के बाद ही काग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया। सत्याग्रह आन्दोलन बन्द हुआ और कौसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। अब केवल गाघीजी ही सत्याग्रह करने के लिए रह गये। गाघीजी ने उत्कल में हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आई। इसके बाद ही से देश-भर के काग्रेसवादियों ने काग्रेस-किमटियों का पुनस्सगठन

आरम्भ कर दिया था। जून लगते-लगते प्रान्तो में काग्रेस-किमिटियां १६३२ के पहले की भाति काम करने लगी। तदनुसार कार्य-सिमित की बैठक १२-१३ जून को वर्धो में और १७-१८ जून को बम्बई में हुई। इन बैठको में नव-सगिठत काग्रेस-किमिटियों के लिए एक रचानात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया। हाथ से कातकर खद्दर तैयार करना और खद्दर तैयार करनेवाले इलाके में उसका प्रचार करना, अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक-द्रव्य-सेवन के त्याग और नशीली वस्तुओं से दूर रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-धन्धों की वृद्धि, ग्राम्य-जीवन का आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और आरोग्य सम्बन्धों दृष्टि से पुनस्सङ्गठन करना, वयस्क गाववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आदि इस कार्यक्रम में सिम्मिलत किए गये। कार्य-सिमित ने सरकार का ध्यान उसकी उस विज्ञाप्त की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार काग्रेस-संस्थाओं पर से तो प्रतिबन्ध उठा लिया गया था, परन्तु खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १६३१ से काग्रेस के ही अंग थे, उसी प्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ था। सरकार ने असंगति से तो नही, पर खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरगे के विरुद्ध जारी की गई निषधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

कार्य-सिमिति की वम्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया। वह यह था कि ह्वाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में काग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए काग्रेस-पार्लमेण्टरी-बोर्ड ने कार्य-सिमिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर एक प्रस्ताव पास किया।

सरदार पटेल की रिहाई

सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को घीरे-धीरे छोड़ना आरम्भ कर दिया था, पर सरदार वल्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल और खान अब्दुलगफ्फार खा को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें से दो को, सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ्फारखा को, उसने जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्खा था। पर ऐसी परिस्थित आ पड़ी कि सरकार को विवश होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल को नाक का पुराना रोग था, जो इघर बहुत बढ गया और जुलाई लगते-लगते रोग ने बड़ी भयंकर अवस्था घारण कर ली। सरकार-द्वारा नियुक्त किये गये मेडिकल-बोर्ड ने वताया कि आपरेशन होना जरूरी है, पर आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतन्त्र होगे। फलतः सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १६३४ को छोड़ दिया।

मालवीयजी श्रौर श्रेण के त्याग-पत्र

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक हुई। इसमें प० मदनमोहन मालवीय और श्री अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई। कार्य-समिति मालवीयजी और श्री अणे का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय की मौलिक नीति को नहीं छोड सकती थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवोय ने काग्रेस पार्लमेण्टरी-बोर्ड के सभापति-पद से इस्तीफा दे दिया और श्री अणे ने पार्लमेण्टरी बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। बगाल को भी शिकायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त जगहे क्यो दी गई? इस प्रकार बगाल का रुख कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय वाले मामले के ही विरुद्ध नहीं था, बल्कि पूना पैक्ट के भी विरुद्ध था।

अब्दुल गम्फार खां की रिहाई

सत्याग्रह-बन्दी के बाद भी सरकार ने दमन-नीति जारी रखी थी। खान अब्दुलगफ्कार खा को जेल में बन्द रखने से लोक-मत बहुत रुष्ट हो गया था। सीमान्त-प्रदेश उन प्रान्तों में से था जिन्होंने १६२० के और १६३२-३४ के युद्ध में पूरा मोर्चा लिया था। युद्धित्रय पठानों के ऑहंसा-त्रत की बडी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोषपूर्वक कष्ट सहे। इसलिए देश में यहा से वहा तक लोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी भी चिन्तित थे। परन्तु जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अब्दुलगफ्कारखा और उनके भाई डॉ० खानसाहब को छोड दिया गया तब जनता को बडी तसल्ली हुई। पर मुक्त होने पर भी उन्हें अपने प्रात और अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी। यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-बन्दी के आदेश का यथावत पालन किया था।

कार्य-समिति की बैठक

कार्य-सिमिति की बैठक २५ सितम्बर को वर्धा में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में काग्रेस की नीति को दोहराया गया। 'आगामी निर्वाचनो' के सम्बन्ध में कार्य-सिमिति ने सारी प्रान्तीय और मातहत काग्रेस-सस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमेण्टरी-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझे। कार्य-सिमिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति काग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उन्हें सहायता न दी जाय। एक दूसरे प्रस्ताव में जजीबार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्यायपूर्ण भूस्वत्व से विचत किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी कष्टो का जिक्र किया गया। श्री अणे के महासमिति की बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। कार्य-सिमिति ने

महासमिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर कई घण्टे तक विचार किया। अन्त मे वह इस नतोजे पर पहुची कि चूँकि कार्य-समिति को अपने निश्चयके औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है और चूिक महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे हैं, इस-लिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। बैठक मे यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यो को कार्य-समिति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक करने की माग पेश कर सकते है। कार्य-समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारो को कार्य-सिमिति के साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी निश्चय का, अन्त करण के विरुद्ध होने के आधार पर पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुची कि चूकि कार्य-समिति ने इस बन्धन-मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। मालवीयजी ने श्री अणे के द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गाधीजी ने यह तजबीज पेश की थी कि व्यर्थ के पारस्परिक तनाव और संवर्ष को वचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवारो की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारो को हटा लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पार्लमे-ण्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहो के लिए मालवीयजी और श्री अणे खडे हो उनके लिए उम्मीदवार खडे न किये जाय। बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि सिन्ध मे और कलकत्ता शहर मे उम्मीदवार खड़े न किये जाय।

गांधीजी श्रीर कांग्रेस

इन्ही दिनो काग्रेस के इतिहास में एक और महत्त्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा आमतौर से की जा रही थी कि गांधीजी काग्रेस त्याग देगे। यह कोरी किम्बदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके जुलाई के मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये थे, और इसके बाद बगाल तथा आध्र से जो लोग किसी-न-किसी कार्यवश उनके पास वर्धा पहुंचे थे, उनसे वह इसकी चर्चा बराबर कर रहे थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को वर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह अफवाह सच थी कि मैं काग्रेस से अप ग स्थूल सम्बन्ध विच्छेद करने की बात सोच रहा हू। वर्धा में अभी हाल में कार्य-समिति और पार्लमेण्टरी-बोर्ड की बैठको में भाग लेने के लिए जो मित्र यहा आये थे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया और उनकी इस बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे काग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद काग्रेस के अधिवेशन के बाद ही होना अच्छा होगा। अन्तिम निश्चय को स्थिगत कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द

आई कि इस बीच मुझे अपनी इस घृारणा की जाच कर लेने का मौका मिल जायगा।

गाधीजी ने यह भी कहा कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वहुत-से काग्रेस-वालो और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बढता हुआ और गहरा अन्तर मौजूद है। वे यदि मेरे प्रति अनुपम भिक्त के बन्धन में न पड़े रहे तो प्रसन्नता के साथ उस दिशा की ओर जायगे जो मेरी दिशा के विलकुल विपरीत है। कोई भी नेता उस विपादारी और भिक्त की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली काग्रेसवादियों द्वारा प्राप्त हो चुकी है, वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा काग्रेस के सामने रखी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भिक्त तथा श्रद्धा से अब और लाभ उठाना उन पर बेजा दवाव डालना है।

मत-भेदो का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने कहा कि चर्बा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है। काग्रेस के बुद्धिजीवी लोगो द्वारा चर्बा कातना लुप्तप्राय हो गया है। साधारणत' उन लोगा का इसमें कोई विश्वास रही रह गया है। काग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है और काग्रेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे हैं कि खादी की घारा के सम्बन्ध में जो पाखण्ड और टाल-मटोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हू। मुझे यह बात मान लेनी चाहिए कि उन लोगो की इस दलील में काफी सचाई है। फिर भी मेरा विश्वास बढता ही रहा है। चर्बा सच्चे अर्थ में मानव-गौरव तथा समानता का शुद्ध चिह्न है। वह खेती का एक सहायक धन्धा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफडा है जिसे काम में न लाने से हम नष्ट हो रहे हैं। काग्रेस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि काग्रेस और देश के करोडो गरीवो के बीच की कडी टूट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न काग्रेस अपने जन्मकाल से करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह धारा बनी रहेगी तो उसका सख्ती से पालन कराना पड़ेगा।

पार्लमेण्टरी-बोर्ड के सम्बन्ध में गाधीजी ने कहा कि काग्रेस के नियत्रण में एक पार्लमेण्टरी-पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक अग है। यहा भी हम लोगों के बीच गहरा मतभेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस जोर सें मैंने इस कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे बहुत-से अच्छे-अच्छे साथियों को व्यथित किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसी हद तक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के आगे जो बुद्धि या अनुभव में बड़ा समझा जाता है दबा देना एक संस्था की निर्विकार उन्नति के लिए हितकर और वाञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक भयकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस प्रकार बार-बार दबाना पड़े। वहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के विषय में हताश हो गये है।

मेरे जैसे जन्मना लोकतंत्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना लज्जा की बात है। मैंने गरीब-से-गरीब मनुष्य के साथ अपने को मिला देने और उससे अच्छी दशा में न रहने की तीव अभिलाषा अपने हृदय में रखी है, और सतह तक पहुचने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किया है। इन कारणों से अगर कोई लोकतत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वह दावा मैं करता हू।

गाघीजी ने यह भी कहा कि मैने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणोय और आत्मत्यागी साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे मेरा मौलिक मतभेद है। किन्तु मैं उनके साहित्य में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपने नैतिक दबाव से नहीं रोकना चाहता। अस्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकाश नहीं तो बहुत-से काग्रेसजनों से कदाचित् भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि इस प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गित में बाघा डालकर मैंने भारी भूल को। पर मैं अनुभव करता हू कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकडा होता तो मैं अपने-तई सच्चा न रहा होता।

अहिंसा के सम्बन्ध में गाधोजी ने लिखा कि १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह अबतक अधिकाश काग्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जबिक मेरे लिए वह एक मूल सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन और व्यवहार के बाद भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हूं। अनुसन्धान का क्षेत्र अवश्य ही परिमित हैं। मनुष्य के जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। माता, पिता, शिक्षक अथवा धार्मिक या लौकिक गुरुजनों की आज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर आ सकता है। इसपर आश्चर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाहे मैं कितना ही अपूर्ण होऊ, मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझ तक ही सीमित रहना चाहिए। सत्याग्रह-आन्दोलन स्थिगित करने के बारे में पटना से जो मैंने वक्तव्य प्रकाशित किया था। अगर हममें पूर्ण अहिंसा का भाव होता तो वह स्वय प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आर्डिनेन्स हमारी किसी कार्य अथवा हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे। वे तो हमारी हिम्मत तोडने के लिए बनाये गये थे। पर यह कहना गलत हैं कि सत्याग्रही दोष से परे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हू कि हम मन, वचन और कर्म से विशुद्ध आहिंसक नही रहे हैं। इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए जीवन अपित है, मुझे पूर्ण निस्संग और स्वतत्र रहने की आवश्यकता है।

स्वराज्य की परिभाषा के सबध में गांधीजी ने कहा कि "पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। १६०८ से मै बराबर कहता आया हू कि साधन और साध्य समानार्थक शब्द है। इसलिए जहा साधन अनेक और परस्पर-विरोधी भी है वहा साघ्य अवश्य भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा । साधनो पर सदा हमारा अधिकार और नियत्रण रह्ता है, पर साघ्य पर कभी नहीं होता। यदि हम समान अर्थ तथा ध्विन-वाले साधनो का उपयोग करते हो तो हमे साघ्य के विश्लेषण में माथापच्ची करने की जरूरत न होगी। पर बहुतेरे काग्रेसवादी इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते । उनका विश्वास है कि साघ्य शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे काम में लाये जा सकते है। इन सब मतभेदो ने ही काग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल वना दिया है। कारण, जो काग्रेस-सदस्य हृदय से उसमे विश्वास किये विना मुह से उसकी हामी भरते है वे स्वभावत उसे कार्य में परिणत नही कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, जो इस समय देश के सामने है—अर्थात् अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, चर्जा और खादी तथा ग्राम-उद्योगों को पुनर्जीवित करने के रूप में सा फीसदी स्वदेशी का प्रचार और भारत के ७ लाख गावो का सगठन । यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को तृष्त करने के लिए काफी होना चाहिए। काग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रतिनिधि सस्था है। उसका जीवन उच्चकोटि की अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है। अपने जन्म-काल से ही उसने जितने तूफानो का सफलता के साथ सामना किया है उतना किसी और सस्था को नहीं करना पड़ा है। अत यदि ऐसी सस्था से मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल कचोटने का भारी कष्ट, विछोह की असहनीय पीडा न सहन करनी पडेगी। और मै तभी ऐसा करूगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि काग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर रहकर मै देश की अधिक सेवा कर सकुगा।

अन्त में गाधीजी ने कहा कि मैं चाहता हू कि मैंने जिन विषयों की चर्चा की है उनकों कार्य रूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके काग्रेस के भाव की परीक्षा करू। पहला सशोधन जो मैं पेश करूगा वह यह होगा कि 'उचित और शान्तिमय' शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 'अहि-सात्मक' शब्द रखें जाय। अगर काग्रेसी वस्तुत हमारे घ्येय की प्राप्ति के लिए सचाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इन स्पष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिये। दूसरा सशोधन यह होगा कि काग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा बटा हुआ २००० तार (एक तार = ४ फुट) सूत हर महीने देने की

रखी जाय और वह सूत मतदाता खुद चर्खें या तकली पर कात कर दें। अगर किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसको कातने के लिए काफी रुई दी जाय ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके। तीसरा संशोधन जो मैं पेश करना चाहता हू वह यह होगा कि किसी ऐसे काग्रेसी को काग्रेस के निर्वाचन में मत देने का अधिकार न होगा जिसका कि नाम ६ महीने तक बरावर काग्रेस रिजस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेवाला न रहा हो। साथ ही मैं यह सशोधन भी चाहूंगा कि ६००० प्रतिनिधियों की सख्या घटा कर इतनी कर दी जाय जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से अधिक न चुना जाय। इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की सख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हो। यह कोई ऐसी आकाक्षा नहीं है, जो पूरी न हो। ३५ करोड की जन-सख्या वाल देश के लिए यह अधिक नहीं है। इस सशोधन के द्वारा काग्रेस को जो वास्तिवक लाभ होगा, उससे सख्या-बल की क्षति-पूर्ति अच्छी तरह हो जायगी। अधिवेशन के ऊपरी ठाट-वाट की रक्षा दर्शकों के लिए उचित प्रवन्ध करके की जायगी, और स्वागत-समिति को अत्यधिक सख्यक प्रतिनिधियों के रहने आदि की व्यवस्था करने में जिस व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पडता है उससे छुटकारा मिल जायगा।

मुझे आशका है कि जिन सशोधनों का मैंने उल्लेख किया है वे वम्बई-काग्रेस में शामिल होनेवाले काग्रेसजनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आये। परन्तु यदि काग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्में रहें, तो मैं इन संशोधनों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल हो, देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूं। जिस नेता के पास अहिसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं है, उसके लिए तो यह वात और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उस में समझौते की गुजाइश नहीं है। काग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुणदोय पर विचार कर ले। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार ही कार्य करें।

वम्बई-कांग्रेस : १८३४

२६ से २८ अक्तूबर (१६३४) तक वम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के शुरू होते ही गाधीजी ने अपने संशोधनों को दो विभागों में बाट दिया, काग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोधनों को उन्होंने कार्य-सिमित के फैसले के लिए छोड़ दिया, पर विधान-सम्बन्धी संशोधिमों पना के बारे में उन्होंने कहा कि उनका पास होना ही इस बात की परख होगी कि काग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियों में विश्वास रखती है अथवा नहीं।

पर आरचर्य की वात है कि कार्य-सिमिति ने उपयुक्त परिवर्तनो-सिहत दोनो प्रकार के सशोधन स्वीकार कर लिये और स्वय काग्रेस ने भी उन्हें मुख्यत. स्वीकार कर लिया, जिससे गाधीजी सतुष्ट हो गये।

लेकिन काग्रेस का नया विवान या पार्लमेण्टरी बोर्ड, रचनात्मक कार्यक्रम एव साम्प्रदायिक निर्णय-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावो की स्वीकृति में प्रस्तावो का पास होना, अधिवेशन के मार्के के निर्णयो मे से नहीं थे। अखिल-भारतोय ग्राम-उद्योग-सघ की स्थापना इस काग्रेस की मुख्य घटना थी, जिसके बारे में यह निश्चय हुआ कि वह गाधीजी की सलाह एव देख-रेख में काम करें और राजनैतिक कहलाई जानेवाली हलचलों से अलग रहे। खद्दर के कार्यक्रम की पूर्ति का यह युक्ति-युक्त परिणाम ही था।

गाघीजी के काग्रेस से अलग होने का प्रश्न भी सामने आया। गाघीजी का उद्देश काग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना था। किसी सस्या की शक्ति उसके सदस्यों को सख्या से नहीं, बिल्क उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमें निहित रहती है, और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बढती जाती है वैसे-वैसे ही, अर्थात् उसी अनुपात में, वह नैतिक-शक्ति भो बढती जाती है। इसी जिम्मेदारी को सभालने के बजाय काग्रेस बहुत काल तक और बहुत अधिक मात्रा में गाघीजी पर ही निर्भर रहती चली आई थी और अपनी शर्तों पर ही गाघीजी का सहयोग चाहती थी। गाघीजी इसके लिए तैयार नहीं थे। काग्रेसी गाघीजी का सहयोग गाघोजी की शर्तों पर ही प्राप्त कर सकते थे। यदि काग्रेस गावीजी की शर्तों को पूरा कर दे तो वह काग्रेस में वापस आने और उसका कार्य सचालन करने के लिए तैयार थे। अपने इन्ही विचारों के कारण गाघीजी काग्रेस से अलग हो गये।

वम्बई-काग्रेस के सभापति वावू राजेन्द्रप्रसाद थे। उनका अभिभाषण उन गिने-चुने नमूनेदार अभिभाषणों में से था जो राजनैतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव छोड देते हैं। उन्होंने क्वेत-पत्र (ह्वाइट पेपर) की तफसीलवार अत्यन्त विद्वता-पूर्ण आलोचना की। उनके तथा स्वागताघ्यक्ष के तत्त्वावधान में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। काग्रेस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मजूर किया गया जो कार्य-समिति तथा महासमिति ने उस वर्ष अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके मुख्य विषय पार्लमेण्टरी-बोर्ड, रचनात्मक कार्य-कम, प्रवासी भार-तीयों की स्थिति, शोक-प्रकाश, स्वदेशों आदि थे। इसके पश्चात् राष्ट्र के त्याग और सविनय-अवशा में राष्ट्र की आस्या विषयक एक प्रस्ताव पास हुआ।

अखिल-भारतीय ग्राम-उँद्योग-सघ के विषय पर खासी बहस और चहल-पहल रही और इस सम्बन्ध में भी एक लम्बा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशो तथा प्रदर्शनो के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। काग्रेस पार्लमेण्टरी वोर्ड पर भी काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। काग्रेस ने वोर्ड की सिफारिश स्वोकार करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लमेण्टरी वोर्ड १ मई १६३५ को भग हो जाय और महासमिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव करे। निर्वाचित वोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। काग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल काग्रेस के वार्षिक अधिकार भी पया। काग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल काग्रेस के वार्षिक अधिकार के अवसर पर पार्लमेण्टरी वोर्ड का नया चुनाव हुआ करें और इस वोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लमेण्टरी वोर्ड को भी वहीं अधिकार दिये गये जो मौजूदा वोर्ड को थे। खहरमताधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक् प्रस्ताव पास किया गया। इन प्रस्तावों के पश्चात् वम्वई-काग्रेस में सबसे पहली वार श्रम-मताधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। वन्त में गाधीजी की अलहदगी पर गाधीजी में विश्वास का एक प्रस्ताव पास किया गया। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था—

"यह काग्रेस महात्मा गाधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह दृढ मत है कि काग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन चूकि उन्हें इस वात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह काग्रेस अपनी इच्छा के विश्व उनके निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी वेजोड सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती है और उनके इस आश्वासन पर संतोष प्रकट करती है कि उनका सलाह-मगविरा और पय-प्रदर्शन आवश्यकतानुसार काग्रेस को प्राप्त होता रहेगा।"

काग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश से जो निमन्त्रण मिला था, वह स्वीकार किया गया।

श्रसेम्बली का चुनाव

वम्बई का अधिवेशन खतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी-जान से कूद पड़ा। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। काग्रेस ने लगभग हरेक 'साधारण' क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार पड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पण्डित मालवीय और श्री अणे के नेतृत्व में काग्रेस से अलग काग्रेस-नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निश्चय किया। जिम क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत का व्यापार-क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्मुखम् चेट्टी खड़े हुए थे। स्नरण रहे कि मर चेट्टी को भारत-सरकार ने एक व्यापार-सन्वि की शत करने के लिए ओटादा भेजा था। ओटावा से लौटने पर वह अमेम्बनी के अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे। उनको एक प्रकार से महान-सरकार तथा भारत-सरकार का समर्थन प्राप्त था।

मद्रास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर वॉबिली के राजा उनके पक्ष में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैंड के इस रिवाज तक को पेश किया गया कि पार्ल-मेण्ट अर्थात् असेम्बली के अध्यक्ष के विरुद्ध किसी को चुनाव न लड़ना चाहिए। सरकारी अफसरों तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया था। काग्रेस सर चेट्टी के विरोधी सामी वेकटाचलम चेट्टी की ओर थी। सामी वेकटाचलम ने सर पण्मुखम् के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती थी। वास्तव में वह सरकार के ऊपर काग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नैतिकवल की, और ओटावा और ब्रिटेन दोनों के ऊपर भारत की विजय थी। दक्षिणभारत और उत्तर-प्रदेश काग्रेस ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया। उत्तर-प्रदेश काग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। वगाल में काग्रेस नेशनलिस्टों की विजय रही। बिहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा आसाम में सब जगह काग्रेस ने वाजी मारी। केवल पजाब में ही काग्रेस पिछंड गई। वहा उसे केवल एक ही जगह मिली। 'साम्प्रदायिक निर्णय' के प्रका के अलावा काग्रेस-नेशनलिस्ट हरेक बात में काग्रेस के साथ थे।

असेम्बली में काग्रेस-पार्टी ने श्री तसद्दुक अहमदला शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता के लिए खड़ा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीद-वार श्री अभ्यकर, शेरवानी व शशमल को खोकर काग्रेस को बड़ी क्षति उज्ञती पड़ी। देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अपित करके ये तीनो वीर अपने जीवन के यौवन-काल में इस ससार से कुच कर गये।

श्रसेम्बली में कार्य

काग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली मे, जिसका अधिवेशन ११ जनवरी को शुरू हुआ, अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-सब के बारे में जो गश्ती-पत्र निकाला था उस पर विवाद उठाने के लिए काग्रेस ने कार्य रोक रखने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खटाई में पड गया। श्री शरत्चन्द्र बसु को नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ५४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरत्चन्द्र बसु जब नजरबन्द थे तब भी वह असेम्बली के लिए निविरोध चुन लिये गये थे। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी। काग्रेस-पार्टी का घ्यान सबसे पहले इस बात की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मोर्चाबन्दी की। काग्रेस ने अपना दूसरा वार ब्रिटेन तथा भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया। समझौता तो किया था ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के ब्यापार की लूट की बाटने के

लिए, पर उसको दे दिया गया बडा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का व्यापारिक समझौता'। वास्तव में समझौते में यह बात खुलासा तौर पर रखी गई थी कि "भारतीय-व्यवसायों को केवल इतना ही सरक्षण दिया जायगा, जिससे कि बाहर से आनेवाला माल भारत में लगभग उसी कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का बना माल यहा बिकेगा, और जहातक सम्भव होगा ब्रिटेन के बने माल पर कम महसूल लगाया जायगा। इस विलक्षण समझौते पर १० जनवरी १६३५ को हस्ताक्षर हुए। बडी कौसिल में इसकी चारों ओर से निन्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में भी विजय रही। सरकार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही विजय हुई। जब रेलवे-बजट पर विचार हुआ तब सरकार को अनेक बार हार खानी पड़ी। साथ ही स्याम के चावल और २५ या ३० अन्य विषयों पर भी विजय प्राप्त हुई थी।

ं कार्य-समिति की पहली बैठक

नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना मे ५, ६ और ७ दिसम्बर १६३४ को हुई। समिति ने श्री बी० एन० शशमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह बड़ी कौसिल के लिए निर्वाचन का फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिथारे थे। कार्य-सिमिति ने ज्वाइण्ट पार्लमेण्टरी किमटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और उसके विरोध में प्रस्ताव पास किया। श्री सुभाषचन्द बसु को स्वतन्त्रता और गित-विधि पर जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी बन्दिशे लगाई गई थी, उन पर कार्य-सिमिति ने क्षोभ प्रकट किया। सिमिति ने सम्मिति प्रकट की कि कौसिलो में गये हुए काग्रेसी सदस्यों को सदा खहर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोध किया कि व इस नियम का पालन कडाई के साथ करे। कार्य-सिमिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने इस आशय का जो आग्रह किया था कि गतनिर्वाचन के अवसर पर दिये गये बगाल के हिन्दुओं के काग्रेस-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्णय के सम्बन्ध में काग्रेस के रख पर दुबारा विचार हो, उसके सम्बन्ध में सिमिति ने यह सम्मिति स्थिर की कि काग्रेस की नीति बम्बई काग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्यारित हुई थी, और सिमिति के अधिकाश सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कार्य-समिति की दूसरी बैठक

कार्य-समिति की दूसरी बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस बैठक मे नागपुर के श्री अभ्यकर और गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य गिडवानी के परलोकवास पर शोक-प्रकाश किया गया। इन दोनो सज्जनो ने वडे कष्ट उठाये थे और देश की सेवा वडी लगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भाति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया।

कार्य-समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय दिवस में जहा तक सम्भव हो कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाय और इस दिन पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया जाय। हडताले न की जाय। उसने यह भी हिदायत दी कि किसी आर्डिनेन्स अथवा स्थानीय अधिकारी की आज्ञा की अवहेलना न की जाय और न सभा में भाषण दिए जाय। राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय और खडे होकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय।

सम्राट् जार्ज के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावत ही कार्य-सिमिति का घ्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव पास

हुआ।

सूती-मिलो के प्रश्न पर भी विचार किया गया और यह तय हुआ कि चूिक अधिकाश सूती मिलो के मालिको ने काग्रेस को दिये वचनो को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समिति की सम्मित है कि काग्रेस अथवा उससे सम्बन्ध रखने-वाली सस्याओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलिसला कायम रखना सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रद समझे जाय। इसके पश्चात् कार्य-समिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट-पार्लमेण्टरी-किमटी की सुधार-योजना की दृष्टि से, और काग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया और निश्चय किया कि बर्मा-प्रान्तीय काग्रेस-किमटी पहले की भाति ही काम करती रहे।

कार्य-सिमिति के निश्चय के अनुसार ७ फरवरी १६३५ को ज्वाइन्ट-पार्ल-मेण्टरी-किमटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एक बार फिर आदर्श और कार्य का, पारस्परिक सहयोग प्रदिश्ति कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ही सभाये की गई हों सो बात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में सभाये की गई। इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो काग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था। रगून में बर्मा-प्रान्तीय-काग्रेस-किमटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने उग का निराला था, क्योंकि रिपोर्ट को रद करने की माग पेश करने में वर्मी और भारतीय दोनो आपस में मिल गए थे।

साम्प्रदायिक समभौते के लिए प्रयत्न

अब हमे उस मेल-सम्बन्धी वातचीत की चर्चा करनी है जो १६३५ की जनवरी

और फरवरी में हुई थी। काग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजनेन्द्र प्रसाद और मुस्लिम लीग के सभापित श्री मुहम्मदअली जिन्ना में, एक ऐसे साम्प्रदायिक समझौते की बातचीत, एक महीने तक चलती रही जो साम्प्रदायिक 'निर्णय' का स्थान ले सके और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्य और कटुता दूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुका-बला करे। बातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनों के लिए बन्द रहकर फिर १ मार्च १९३५ तक जारी रही। पर इस बात-चीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई।

सरकार की दमन-नीति

१६३५ मे भी सरकारी रुख अथवा नीति मे कोई परिवर्तन नही हुआ । काग्रेस को शिक्तशाली शत्रु समझकर उसपर सन्देह की निगाह बनी रही। जरा-जरा-सी बात पर काग्रेस-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता रहा। जिनपर आतंककारी कामो का सन्देह किया जाता था, उन्हें बिना मुकदमा चलाये जेलो मे या घरो मे नजरबन्द रखा जाता था। अनेक स्थानो पर यदा-कदा मकानो की तलाशिया होती थी। महासमिति के तथा बिहार आदि प्रान्तों की काग्रेस-किमटियों के दफ्तरो पर भी निगाह थी। खान अब्दुलगफ्फारखा को बम्बई में भाषण देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई थी और डॉ॰ सत्यपाल को निर्वाचन सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले मे एक साल का दण्ड दिया गया था। बंगाल के नजरबन्दो की सख्या हजारो मे थी। उनके परिवार असहाय अवस्था में थे। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया था। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। नजरबन्दों के परिवारों और आश्रितों के कण्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। इस कार्य की पूर्ति के लिए १६ मई का दिन निर्वेचत किया गया। काग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध मे देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। बगाल की सरकार ने काग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए इडियन प्रेस (इमर्जेन्सी पावर्स) एक्ट की धारा २-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि काग्रेस के अध्यक्ष के आज्ञा-नुसार देश-भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द-दिवस से सबधित देश के किसी स्थान की कोई सूचना पत्रो में प्रकाशित न की जाय। बंगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रखा।

महासमिति की बैठक

महासिमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक मे कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड और निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ो का निपटारा करने के लिए एक सिमति निर्वाचित की और हिसाव-किताव की जाच के लिये आडीटर नियुक्त किये । महासिमिति ने श्री तसद्दुक अहमदखा शेरवानी की मृत्यू पर शोक और वडी कौसिल में काग्रेस-पार्टी के काम पर सतोष प्रकट किया। इनके सिवा सीमान्तप्रदेश में काग्रेस-सस्था के वदस्तूर गैर-कानूनी रहने, वगाल के गिदनापुर जिले की काग्रेस-कमिटियो के निपिद्ध रहने, और वगाल, गुजरात तथा अन्य स्थानो पर खुदाई-खिदमतगार और हिन्दुस्तानी सेवादल आदि के गैर-कानूनी वने रहने की ओर देश का घ्यान आर्कावत किया। उसने वगाल मे प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवको को नजरवन्द रखने की नीति की, और स्वय उन परिवारो के निर्वाह का प्रबन्ध न करने की निन्दा की। उसने कहा कि वगाल की सरकार को या तो इन नजरबन्दो को छोड देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना चाहिए। वगाल की जनता और उसके नजरबन्दो को आश्वासन दिया कि उनके कव्टो के साथ उसकी पूरी समवेदना है। सिमिति ने वगाल-प्रातीय काग्रेस कमिटी को आज्ञा दी कि वह नजरवन्दों की पूरी सूची तैयार करें और उनके नजरवन्द रहने की अवधि और उसके परिवारो की आर्थिक अवस्था से उसे सूचित करे। नजरबन्दो के परिवारो का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्य-समिति की अधीनता में भारतव्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चेय किया गया। फीरोजा-बाद के सामृहिक हिंसात्मक कार्यों के ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ॰ जीवारोम का पूरा परिवार, बच्चो और कई रोगियो सहित, जीवित जला दिया गया था।

इसी अवसर पर जबलपुर में कार्य-सिमिति की भी बैठक हुई, जिसमें काग्रेस के नये विधान के अनुसार प्रतिनिधियों की सख्या निश्चित की गई और महासिमिति के सदस्यों और आगामी काग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न काग्रेस-किमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका बनाई गई। उसमें कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगडों का निपटारा किया गया और काग्रेस तया महासिमिति में बगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर काग्रेस-सस्थाओं के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था।

क्वेटा-भूकम्प

१५ जनवरी १९३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अभी मुश्किल से १८ महीने बीते होगे कि ३१ मई १९३५ को क्वेटा के भूकम्प के कारण देश-भर में शोक छा गया। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कब्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वय अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही था, पर कब्ट-निवारण और सगठित सहायता के उद्देश्य से वाहर से आनेवालों के प्रवेश

के विरुद्ध आज्ञा क्यो दी गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमित न काग्रेस के सभापित को मिली, न गांधीजी को। ऐसी परिस्थित में केवल निषिद्ध-प्रवेश के आसपास के स्थानो पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। काग्रेस के सभापित ने क्वेटा-कष्ट-निवारक-समिति का सगठन किया, जिसकी शाखाये सिंध, पंजाब और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गईं। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी।

पद्-ग्रह्ण का प्रश्न

१६३५ के मध्य में काग्रेसवादियों को, विशेष कर उनकों जो कौसिल-प्रवेश पर अड़े हुए थे, एक और प्रश्न ने उद्विग्न कर रक्खा था, और वह था नये शासन विधान के अन्तर्गत पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जब कि बिल अभी पार्लमेण्ट के सामने पेश ही था, यह प्रसङ्ग छेडा गया। बम्बई-काग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में बिलकुल स्पष्ट था। आगामी अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था। फलत. जुलाई के अन्त में वर्धा में कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय काग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकता है।

देशी राज्य प्रजा-परिषद् श्रीर कांग्रेस

अभी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लामेण्टरी-बोर्ड के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने वकील की हैसियत से देशी-नरेशो को भावी भारत-सरकार क अन्तर्गत सङ्घ शासन के प्रश्न पर सलाह दी और फिर मैसूर में इस विषय पर भाषण भी दिया। इन बातो को लेकर इस वर्ष के आरम्भ में देशी-राज्य-प्रजा-परिषद् में हलचल मच गई। जुलाई में देशी रियासतो की प्रजा के प्रति काग्रेस के रुख पर विचार करने के लिए महासमिति की बैठक की माग हुई। देशी-रियासतो की प्रजा ने अपनी माग गाधीजी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रखी थी, जिसे उन्होंने दूसरी गोलमेज-परिषद् के अवसर पर दिया था अर्थात् 'काग्रेस' ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी राज्यो की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हो और वे सघ व्यवस्था-मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सके।

कार्य-समिति की बैठक

२६, ३० और ३१ जुलाई १६३५ को वर्घा में होनेवाली कार्य-समिति की वैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही अधिकार है जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। इसके अनुसार काग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्वपूर्ण उत्तर-दायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है,और न केवल देशी नरेशों से ही अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, भाषण देने के और लेखो-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के अधिकार देने की अपील की है, विल्क देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण साधनों से किये गए सघर्ष में उसकी सहानुभूति है। काग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ है। पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का सघर्ष जारी रखने का बोझ स्वय देशी-राज्यों की प्रजा पर था। काग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैंत्री-पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती थी। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामर्थ्य काग्रेस को प्राप्त नहीं था।

अन्त मे यह निश्चय किया गया कि चूकि १८८५ में काग्रेस का पहला अधिवेशान हुआ था, इसलिए उसका पचासेवा वर्ष उचित ढग से मनाया जाय। इस उद्देश्य से कार्य-सिमिति ने कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की। वर्घा की बैठक और वर्ष की समाप्ति के बीच में जो थोडा-सा समय रहा उसमे तीन घटनाओ को छोडकर कोई विशेष बात नही हुई। उनमे से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकस्मिक रिहाई थी। वह अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोडा-जेल से छोड दिय गये। उन्हें तुरन्त यूरोप जाना था। शर्त यह थी कि यदि अपनी सजा की मियाद खत्म होने से पहले वह लौट आए तो उन्हें फिर जेल वापस जाना पडेगा। दूसरी घटना गवर्नर जनरल-द्वारा सितम्बर मे किमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि वडी कौसिल ने उसे स्पष्ट बहुमत-द्वारा रद कर दिया था। तीसरी महत्व-पूर्ण घटना १७ और १८ अक्तूबर १६३५ की महासमिति की बैठक थी। यह मद्रास में हुई। मद्रास में देशी-राज्यों के प्रश्न पर कार्य-समिति के वक्तव्य के साथ सहमित प्रकट की गयी और पद स्वीकार करने के प्रश्न पर महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि इस विषय पर काग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूल नही होगा।

अन्त में इस वात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पार्लमेण्ट ने भारत शासन-विधान पास कर दिया और २ जुलाई को उसे सम्राट् की स्वीकृति प्राप्त गई हो ।

: १६:

पद-ग्रहण और त्याग-पत्र : १६३५-३६

हमारी स्थिति

पूर्व निश्चय के अनुसार सन् १९३५ मे न तो काँग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती मनाई गई और न उसका कोई अधिवेशेन ही हुआ। सन् १९३६ में हमको चारो तरफ से घेरते हुए तूफान के कुछ आरिभक लक्षण दिखाई दिये। सन् १९३५ मे एविसीनिया पर इटली ने हमला कर दिया था। भारत मे नागरिक स्वतत्रता विलकुल समाप्त कर दी गई थी। भारतीय जेलों में लगभग २१०० व्यक्ति नजरवन्द थे। गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार से स्वीकृत क्रिमिनल लॉ एमेण्ड-मेण्ट कानून मौजूद था। करीव पाँच सौ अखवारों से जमानते मांगी गई थीं और इसकी वजह से करीब ३५० अखवार बन्द हो गये थे। १६६ अखवारों की जमानतो की रकम २,५०,००० रु० थी। विदेशो में दशा यह थी कि रूस ने वडी तेजी से उन्नति की थी और सारी दुनिया की ऑखे उघर ही थी। इस अर्द्ध-प्राच्य देश से, जिसने गुलामी की जजीरो और पूँजीवाद के वन्द तोडे थे, जब कोई प्रगति की खबर मिलती थी तव भारत के लोगो को, जिनकी लम्बी गुलामी ने आजादी की सारी उम्मीदो को दूर कर दिया था, एक चैन-सा मिलता था। आम जनता के उत्थान की दिशा में इस विशालकाय रूस ने जो नई समाज-व्यवस्था बनाई थी, उसको देखकर यहाँ के लोगो मे वैसा ही आन्दोलन करने, वैसा ही ढाँचा बनाने और वैसी ही सार्वजनिक स्वतत्रता स्थापित करने की तीन उत्कटा थी। भारत की औद्योगिक जनसङ्या वीस लाख से आधक नहीं थी। वास्तव में असली समस्या भारत के दिसयों करोड किसानों की ही थी जो वेकार तो नहीं, पर अर्ध-वेकार जरूर थे। भारत विदेशी शासन से कुचला जा रहा था और वह शासन किसी राष्ट्रीय, निरंकुश तानाशाह के शासन से वेहतर नही था।

वपनी राजनैतिक मुक्ति के लिए भारत ने काँग्रेस-हारा जो योजना चालू की थी, उसको पचास वरस वीत चुके थे। इस लम्बे असे में राष्ट्रीयता का वह सिद्धान्त, जो उनीसवी शताब्दी के बारंभ से ही यूरोप के राजनैतिक विकास में गहरी जह जमा चुका था, सारे भारत में भी समा गया था और उसकी वजह ने राष्ट्रीय जीवन, विचार, आकाक्षा, प्रयत्न, उपलब्धि और बादशें में एक ऐक्य की भावना स्थापित हो चुकी थी। इससे राष्ट्रीयता के अमूर्त विचारों की जगह कुछ ही समय में,

सामाजिक सघर्षों की पायिव घारणाओं ने ले ली। नये आयिक सिद्धान्त उठ खड़े हुए और मानव-समाज का निर्देश करने वाले नये सिद्धान्तों का प्रचार किया गया। काँग्रेस ने आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सलाह दी और भारतीय जनता की दशा सुधारने और साथ ही गरीवी और तकलीफ दूर करने के घ्येय से सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कहा। यह वात घ्यान देने की है कि पूर्ण स्वाधीनता सबधी लाहौर में स्वीकृत प्रस्ताव के छ महीने पहले ही उपर्युक्त प्रस्ताव पास हो गया था। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि काँग्रेस का उद्देश्य सिर्फ राजनैतिक आजादी ही था और एक नया सामाजिक ढाँचा वनाना नहीं था। 'नई समाज व्यवस्था' का नारा, जिसका महायुद्ध के समय से प्रचार बढ गया था, काँग्रेस के कार्यंक्रम में गुथा हुआ था।

भारत मे प्रश्न यह था कि 'नई समाज-व्यवस्था' के उद्देश्य पर पहुँचने के लिए कौन-सा साधन है—हिसा या अहिसा ? वम्बई के अधिवेशन (१९३४) मे महासमिति और विषय-निर्वाचन समिति ने काँग्रेस के उद्देश्य में 'शान्तिपूर्ण और उचित' की जगह 'सत्य और अहिसा' को नही रखा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नही था कि अधिकाश कॉग्रेसियो और आम जनता में अहिंसा के सिद्धान्त की पकड कुछ ढीली हो गई थी, पर देश के तरुण हिसा से शीघ्र सफलता प्राप्त करने की प्रत्याशा और सम्भावना से प्रभावित थे। देश के नौजवानो में चारो तरफ समाजवाद की आवाज थी। विद्यार्थी-सघ और यूथ-लीग की इसी कारण स्थापना हुई थी। कॉग्रेस समाजवादी दल के नाम से केंग्रेस के अन्दर एक पार्टी काम कर रही थी। एक नई पार्टी साम्यवादी पार्टी भी तैयार हो चुकी थी और वह समाजवादी दल से ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनो दल जनता में एक-से सुपरिचित हो गये थे। सरकार जब षड्यत्र के मुकदमे चलाती थी तब ये बाते लोगो में और भी ज्यादा फैलती थी। दक्षिण भारत में समाजवादी दल, साम्यवादी दल के ही रूप में काम कर रहा था। ऐसी दशा में साम्यवादी दल का प्रभाव बराबर बढता जा रहा था। इन्ही परिस्थितियो में लखनऊ-कॉग्रेस का अधिवेशन (अप्रैल १९३६) हुआ।

लखनऊ-काँग्रेस १८३६

इस सारी पृष्ठभूमि को घ्यान में रखते हुए यह प्रश्न सामने था कि लखनऊ में सभापित कौन हो ? गांघीजी घामिक मालूम हो सकते थे और उन्हें राजनीतिज्ञ की जगह सत अधिक आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें राजनीति-चातुर्य नहीं था और उनकी अपनी नीति नहीं थी। गांघीजी के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली काँग्रेसी प॰ जवाहरलाल थे। वह काँग्रेस को अन्दर

से आगे बढने की शक्ति दे सकते थे और बाहर से रोक भी लगा सकते थे। इसके अलावा उनमें हस, जर्मनी, इगलैण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, फास, स्पेन, इटली और मध्य यूरोप की घटनाओं का गहरा अध्ययन करने के कारण वर्तमान समस्याओं को उलझन समझने की शक्ति भी थी। भारत की परिस्थिति से भी वह परिचित थे। इस तरह वह पुराने और नये में एक जोडने वाली कड़ी थे। वह गाधीवाद और साम्यवाद के बीच एक सेतु की तरह थे और इसी कारण लखनऊ में सभापति-पद ग्रहण करने के लिए सब से अधिक उपयुक्त थे। अन्त में वहीं काँग्रेस के सभापित चुने गये।

लखनऊ-अधिवेशन में जो कुछ हुआ उससे जवाहरलालजी को बड़ी भारी और तीखी निराशा हुई। उन्होंने ऐसा महसूस किया, मानो वह अकेले एक तरफ हो, सारी दुनिया दूसरों तरफ। खेतिहर कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव था वह तो उस बडे कान्तिकारी सामाजिक उभाड के कार्यक्रम के लिहाज से, जिसे जवाहरलालजी राष्ट्र से मनवाना चाहते थे, एक बहाना भर था। उस समय उन्होने जिन तीन कट्टर समाजवादियो को कार्यसमिति में लेकर अवसर का ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाया वे थे श्री जयप्रकाशनारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अच्युत पटवर्धन। खेतिहर कार्यक्रम मौके पर लिया गया था। सारे देश मे किसानो में हलचल मची हुई थी और सरकार और जमीदारों की मनमानी लगान-नीति का विरोध हो रहा र्था। जमीदार तालाबो, बन्दो, सिचाई के साधनो, चरागाहो और जगलो पर विशेपाधिकार जता रहे थे। इन वातो के सबध मे काँग्रेस ने कोई अतिम निर्णय नही किया। नए ऐक्ट का प्रश्न भी उसके मामने था। इस नये ऐक्ट पर उसने अपना असन्तोष जताया और उसकी निन्दा की, लेकिन साथ ही यह तय किया कि चुनाव के लिए एक घोपणा-पत्र बनाया जाय और उसकी बुनियाद पर चुनाव लड़ा जाय। पद-ग्रहण करने के प्रश्न पर कॉग्रेस ने उस समय किसी फैसले की जिम्मेदारी लेना मुनासिव नही समझा; क्योंकि आगे की परिस्थिति का कुछ ठीक नही था। इसलिए जसने खेतिहर कार्यक्रम और पद-ग्रहण के सवध में अतिम निर्णय का अधिकार समिति पर छोड दिया। ऐक्ट का प्रमुख दोप यह था कि उसमे न तो आत्म-निर्णय था, न सयुक्त निर्णय, विल्क कुछ और ही निर्णय था। इसके अलावा सरकारी योजनाओं में एक और स्पष्ट दोष या जिसको कि जान-बूझकर रखा गया था। वह यह कि राजसत्ता का घड़ तो था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं या और इस तरह सारे काम अनियत्रित और अमवट थे। न तो उस रारीर का दिमाग था, जो चालक-शक्ति देता और न वह भाग जो विभिन्न प्रान्तो के कामो में मामञ्जस्य वनाये रखता।

इस तरह लखनज-अधिवेशन ने महासमिति को दो महत्वपूर्ण काम सीपे: एक तो ऐतिहर कार्यक्रम की अन्तिम रूपरेखा और दूसरे चुनाव के घोषणा-पत्र

की तैयारी। दोनो बाते परस्पर सबिधत थी। असल मे पहली चीज दूसरी का हिस्सा बनती और दोनो मिलकर वह बुनियाद उपस्थित करती, जिसके अनुसार कांग्रेस चुनाव जीतने पर अगर पद-ग्रहण करती तो अपना वैधानिक काम करती। उस समय इन तीनो बातो में जो गहरा और सजीव नाता था, उसे अनुभव नही किया गया। फिर भी घटनाओ की प्रगति में एक मौलिक कठिनाई थीं। कार्य-समिति के अधिकाश सदस्यों से सभापति का मतभेद था। तीन नये दौस्त जो अन्दर लिये गये थे, उनके साथ कमेटी का एक-चौथाई से ज्यादा हिस्साथा, लेकिन आमतौर पर काग्रेस के फैसले, विचार-विनिमय, और विवाद बहुमत और अल्पमत के अनुसार नहीं होते थे। जवाहरलाल शुरू में ही त्याग-पत्र देना चाहते थे, पर उनसे कह-सुन कर उनको वहीं बनाये रखा गया। बने तो वह रहे, लेकिन दिल में बेचैनी थी। एक ओर सभापति-पद से दिया गया उनका भाषण था, दूसरी ओर गाधीजी थे और कार्य-समिति में उनसे सहमत दस सदस्य। ये लोग एक चट्टान की तरह थे। पन्द्रहवा व्यक्ति जेल में था सुभाषचन्द्र बोस, जो यदि बाहर भी होते तो भी वह किसी एक तरफ न मिलकर अपना अलग ही रास्ता बनाते। सभापति के भाषण मे पूरा साम्यवाद का पक्ष था। एक ऐसे देश मे, जहाँ बहुत अर्से से विदेशी राज्य की गुलामी रही हो, वहाँ उस राष्ट्र के नौजवानो का पुरानी नीति और व्यवस्था से जी ऊव जाता है और शासक राष्ट्र की नीति और व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। ऐसी हालत मे उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे एक ऐसा हल तलाश करे जो दोनों से भिन्न हो।

मुख्य घटनाएँ

लखनऊ और फैजपुर के बीच घटनाओं की एक विशेष प्रगति हुई जिनका उल्लेख आवश्यक है। इनमें से एक अत्यन्त दुखपूर्ण बात तो यह थी कि गुजरात के बुजुर्ग अब्बास तय्यवजी का १० जून १९३६ को मसूरी में स्वर्गवास हो गया और उघर लखनऊ अधिवेशन के कुछ ही बाद यात्रा में डा० अन्सारी की मृत्यू हो गई। १७ मई १९३६ को डा० अन्सारी की मृत्यु पर देश-भर में शोक मनाया गया। कार्यकारिणी की सलाह पर सारे देश में दो दिन और मनाये गये एक तो ९ मई को 'अवीसीनिया-दिवस' मनाया गया और इटली की निन्दा करते हुए अबीसीनिया के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव पास किये गये। कई जगह लीग ऑव नेशन्स की भी निन्दा की गई और यह कहा गया कि उसने अबीसीनिया के साथ विश्वासघात किया है। दूसरा दिन १० मई को मनाया गया। यह था 'सुभाष-दिवस'। सरकार ने श्री सुभाषचन्द्र बोस को कुर्सिओग में उनके भाई के बगले में नजरबन्द कर लिया था। गृह-विभाग के सदस्य ने कहा कि सार्वजिनक हित में उन पर खुला अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इस तरह की यह नजर-

वन्दी थी। देश-भर में सरकार, के इस काम की निन्दा की गई और विरोध में प्रस्ताव पास किये गये। १३ सितबर को यतीन्द्रदास के मृत्यु-दिवस पर काग्रेस के सभापित जवाहरलालजी ने काग्रेसियों और काग्रेस कमेटियों से 'राजबन्दी दिवस' मनाने के लिए कहा। यह सच है कि इस चीज को उसी वक्त कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इससे दोनो तरफ हृदय-परिवर्तन के लिए रास्ता खुला। विन्दयों ने आतकवाद की निर्श्वकता का अनुभव किया और सरकार ने धीरे-धीरे इन लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रिहाई इतने लम्बे अर्से में फैला दी कि इस काम में जो कुछ खूबी और भलमनसाहत थी, वह आधी भी नहीं रही।

विदेशों में जो घटनाएँ हो रही थी, उनकी तरफ भी काग्रेस को उतना ही घ्यान देना जरूरी था, जितना कि घरेलू मामलो पर । एक ओर इटली-द्वारा अबीसीनिया पर बलात्कार था, दूसरी ओर यूरोपीय राष्ट्र निश्चित रूप से अपराधी की मदद कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीयों के दिमाग से अपनी आजादी के सिलिसले में न्याय की रही-सही आशा भी जाती रही। दुनिया में शान्ति चाहने वाले लोग ख़ामोश तो नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज ही क्या थी! जब ६ सितम्बर को विश्व-शांति सम्मेलन की ब्रसैल्म में बैठक हुई तब युद्ध के बादल दुनिया के सिर पर मडराते हुए बहुत नीचे झुक आये थे। स्पेन में हिंसापूर्ण गृह-युद्ध चल ही रहा था और उसके पडोसी अपने आपको तटस्थ बताते हुए भी एक-न-एक पक्ष ले रहे थे।

द्मन-चक

भारत में भी बड़ी उथल-पुथल रही और जबर्दस्त दमन-चक्र चला। तलाशियाँ हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और बड़ी विचित्र आजाएँ जारी की गई। विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों से निकाला गया। मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया गया। यह छूत की वीमारी पाडिचेरी में भी पहुँची, जहाँ फासीसी कब्जा था। साम्यवादी दल का एक घोषणा-पत्र जन्त कर लिया गया। एक लिफाफा जिस पर गाधीजी की तस्वीर बनी हुई थी, डाकखाने से भेजने वालों के पास 'जन्त' लिखकर लौटा दिया गया। प्रजा सिमि, और किसान कमेटियों पर पाविन्दियों लग गईं। कपूरथला, जोघपुर, मैंसूर, वडौदा, सिरोही, मारवाड और राजनादगाँव की देशी रियासतों ने भी दमन-नीति का अनुकरण किया। चारों तरफ इस अँधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी उस वक्त, जब अल्मोंडे से श्वास्त १९३६ को मियाद खत्म होने पर खान अन्दुल गफ्फार खाँ को छोड़ा गया, लेकिन जेल के दरवाजें पर उन्हें यह हुक्म मिला कि वह सीमाप्रांत और पजाव में न घुसे। लाहौर सेण्ट्रल जेल में एक वन्दी और थे श्री परमानन्द, जो

लाहीर पड्यन्त्र केस में सन् १९१४-१५ के बन्दी थे और जिनकी सजा को २३ साल बीत चुके थे। सरकार की तरफ से कामन्स सभा में यह कहा गया कि सरकार का उनको छोडने का इरादा नही है। यह बात ध्यान देने की है कि जुलाई सन् १९३६ में अकेले वगाल में ही ३००० से अधिक लोग नजरवन्द थे और फिर भी दमन चक्र वरावर ज्यादा तेज होता जा नहा था। कम-से-कम ५० काग्रेसियो भीर समाजवादियों को पजाव में इस आशय के नोटिस दे दिये गये थे कि वे अपने गाॅवो को न छोडे। चार अगस्त को एक हुक्म जारी किया गया कि "सूर्यास्त से सूर्योदय के वीच" कोई शख्स, जिसकी उम्र १२ और ३० साल के वीच हों, घूमता हुआ न पाया जाय। यह हुक्म एक साल के लिए या और यह मनाही ढाका मे १९ जगहो और नारायणगंज मे १६ जगहो के लिए थी। इन जगहो मे पार्क, खेलने के मैदान और मन्दिर भी शामिल थे। इस हुक्म को न मानने पर ६ महीने के लिए जेल और जुर्माने की सजा थी। दमन सन् १९३६ में शुरू नहीं हुआ। जिन वातो का ऊपर जिक्र किया गया है वे तो वरावर वहनेवाली नदी की एक बूद की तरह थी। लखनऊ-अधिवेशन के वाद जिस वात पर राष्ट्रपति ने सबसे पहले घ्यान दिया, वह थी 'भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन' की स्थापना। इस सस्या के अवैतिनिक सभापति डा॰ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उसकी प्रमुख श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ऊपर से देखने पर भारत में ऐसी यूनियन की स्थापना, नागरिक स्वतत्रता के सरक्षण की दृष्टि से एक बड़े राष्ट्रीय महत्व की बात थी।

कार्य-श्रौर सेवापॅ

इस साल की घटनाओं में एक खास बात यह थी कि काँग्रेस की पार्लामेण्टरी कमेटी और मजदूर कमेटी ने जिनको पहले अधिवेशन पर नियुक्त किया गया था, नियमित रूप से काम किया। पहली कमेटी का एक बहुत बड़ा काम था अगली फरवरी (सन् १९३७) में प्रातीय धारा-सभाओं के चुनावों के सिलसिलें में घोषणा-पत्र की तैयारी। इन चुनावों में ३।। करोड़ नागरिकों को मताधिकार मिला हुआ था। फिर मुस्लिम और परिगणित जातियों की सीटों के लिए भी चुनाव लड़ने का इरादा था। ऐसी दशा में घोषणा पत्र-द्वारा कांग्रेस का सन्देश, गॉव-गाँव में पहुँचाना था। कांग्रेस महासमिति ने २२, २३ अगस्त १९३६ को बम्बई में इस घोषणा-पत्र को स्वीकार किया।

मजदूर कमेटी ने, जिसके मत्री कृपलानीजी थे, अपना कार्यक्रम बनाया। इसमे मजदूर यूनियनो के सगठनो और औद्योगिक झगडो के बारे मे सूचना एकत्र करना था। यहाँ एक ज्यादा दिलचस्प और अहम बात यह थी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस ने काग्रेस-मजदूर-कमेटी के सदस्यो से मिलने की इच्छा प्रकट की।

इस पर ट्रेड यूनियन काग्रेस, नेशनल फेडरेशन ऑव ट्रेड यूनियन, अ० भा० रेलवे मैन्स फेंडरेशन, अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोसियेशन, अ० भा० पोस्टल और आर॰ एम॰ एस॰ यूनियंन और अ॰ भा॰ प्रेस कर्मचारी फेडरेशन के प्रति-निधियो को कमेटी ने अपनी अगली बैठक के मौके पर बुलाया। इसके अलावा बम्बई में अ० भा० ट्रे० यू० काग्रेस का जो पन्द्रहवा अधिवेंशन हुआ उसमें काग्रेस सभापति को आमित्रत किया। यह जलसा १७, १८ और १९ मई को हुआ। इसकी अध्यक्षा श्रीमती मणीबेन कारा थी। सम्मेलन मे देश के मिल-मालिको का ध्यान इस ओर खीचा गया कि वे मजदूरो को अपना संगठन करने के लिए आवश्यक सुवित्राएँ दे, कायदे से बनी हुई यूनियनो की सत्ता को स्वीकार करे और उनसे समझौते की बातचीत करे। इसके अतिरिक्त वे लोग उन मजदूरो को, जो यूनि-यन में काम करते हो, कोई कष्ट न दे। धारासभाओं में जो कांग्रेस दल थे उनसे मजदूरों के लिए उचित वेतन और उनके साथ सद्व्यव्हार के लिए कानून बनवाने की सिफारिश की गयी। ब्रिटिश और भारत की काग्रेस कमेटियो और रियासतो ंका ध्यान इस ओर खीचा गया कि मजदूरो की हालत सुधारने के लिए कदम बढाने की सख्त जरूरत है और औद्योगिक श्रम की बेहतरी के मामलो में दिलचस्पी लेना आवश्यक है। रेलवे कम्पनियों का काम सरकार के हाथों में आता जा रहा था। सरकारी रेलो में छंटनी हो रही थी और निचले दर्जे के नौकरों के वेतन घटाये जा रहे थे। इस सिलसिले में जो सवाल उठ खडे हुए थे उन पर मजदूर कमेटी और सम्मेलन ने कार्यकारिणी से सिफारिश की कि वह उपयुक्त प्रस्ताव पास करे।

श्रनुशासन का श्रभाव

इस तरह यह जाहिर है कि काग्रेस पालिमण्टरी काम तेजी से बढ रहा था। इस काम को सफलता-पूर्वक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता थी। लेकिन अनुशासन का अभाव चारो तरफ दिखाई दे रहा था। सभापित की स्थित भी विचित्र थी। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा—"सभापित की हैसियत से मैं काग्रेस का प्रमुख कार्य-निर्वाहक था और यह आशा की जा सकती है कि मैं उस सस्था का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन नीति-सबधी कुछ बड़े सवालो पर मैं बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। यह दृष्टिकोण लखनऊ-काग्रेस के प्रस्तावों से प्रकट है। इस प्रकार कार्यसमिति एक साथ मेरे और बहुमत के दृष्टिकोण को नहीं रख सकती थी।" यह एक ऐसी स्थित थी जैसी कि बाद में त्रिपुरी (सन् १९३९) में और अप्रैल १९४२ में महासमिति की इलाहाबाद वाली बैठक के बाद पैदा हुई थी। अपने मित्रो और आलो-चको से जवाहरलालजी ने लखनऊ की अपनी परेशानियों का फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा, "इस विचित्र स्थिति का मेरी समाजवादी निष्ठा से कोई संबंघ नहीं

है। लखनऊ मे जो अन्तर था वह तो केवल राजनैतिक था। लखनऊ के प्रस्तावो में ऐसी कोई बात नही थी, जिसको समाजवादी कहा जा सके। समाजवादियो ने भी यह अनुभव किया कि सबसे अहम प्रश्न था—स्वतन्त्रता का प्रश्न, और उन्होने भी उस पर अपना घ्यान केन्द्रित किया। फूट की वात वेमानी थी। जब स्वत-त्रता की पुकार हमारे खून में हिलोरे ला रही थी तो हममें फूट की वात कैसे उठ सकती थीं ? हम सहमत हो, चाहे हममें मतभेद हो, कभी-कभी हम साथ भी छोड सकते हो, लेकिन आजादी की पुकार में हम सब एक साथ है।" खादी पर उन्होने जो आलोचना की थी, उसके सिलसिले में लोगो को उन्होने फिर जवाब दिया, "मै इस चीज को कई बार साफ कर चुका हूँ कि मै खादी को अपनी आर्थिक समस्याओं का अन्तिम हल नहीं मानता और इसलिए मैं उस हल को दूसरी जगह तलाश करता हूँ। फिर भी मेरा यह विश्वास है कि आज की परिस्थिति में खादी का एक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है और हमें उसे वढावा देना चाहिए।" उन्होने यह भी कहा कि रूस के सामाजिक ढाचे की नीव मे जो मीलिक आर्थिक सिद्धान्त है, मै उसमे विश्वास करता हूँ। उनका ऐसा विचार था कि रूस ने सास्कृतिक, औद्योगिक, शिक्षा-सवधी और सही अर्थों मे असाधारण प्रगति की है, लेकिन इसके माने यह नहीं थे कि रूस में जो कुछ हुआ, उस सबको वह अच्छा समझते और मानते हैं। इसी वजह से उनका कहना यह नहीं था कि रूस का अधानुकरण किया जाय। इसलिए साम्यवाद की जगह उन्होने समाजवाद शब्द का प्रयोग करना उचित समझा, क्योकि साम्यवाद सोवियट रूस का द्योतक था। उनका कहना था-"मै जिस चीज को चाहता हूँ वह यह है कि समाज में से मुनाफे का भाव निकल जाय और उसकी जगह समाज-सेवा की भावना आ जाय। प्रतिद्वन्द्विता की जगह सहयोग ले ले। उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए हो। वजह यह है कि मैं हिंसा से घृणा क्रता हूँ और उसे निद्य समझता हूँ। वर्तमान व्यवस्था हिंसा पर खंडी हुई है। मैं सुदृढ़ और समर्थ व्यवस्था चाहता हूँ, जिसने से हिसा की जड़े निकाल दी गई हो, जहा घृणा लुप्त हो गई हो और उनकी जगह श्रेष्ठतर भावनाओं ने ले ली हो। इस सब को मैं समाजवाद कहता है।"

श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव

इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जार्ज पचम, के मरने पर उनके सबसे बड़े पुत्र एडवर्ड अष्टम वादशाह वने। जब वह वेल्स के राजकुमार थे तभी उनका एक अपना ढग था। उनका समाजवाद की तरफ झुकाव था और वे सामाजिक और राजसी परम्पराओ से घृणा करते थे। दीन-हीन व्यक्तियो के उत्थान से उनकी सजीव सहानुभूति थी और वह वेल्स और

दूसरी जगहों के बेकार लोगों के घर अक्सर मिलने चले जाते थे। जानबूझ कर अपनाये गये बादशाह के इस ढर्र से बड़े-बड़े लोग बिगड़े। मई १९३४ में एक शाही घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि १२ मई १७३७ को बादशाह को ताज पहनाया जायगा। सन् १९३६ में अपनी पार्लीमेण्ट के पहले भाषण में बादशाह ने राजगद्दी के बाद भारत जाने और वहाँ दरबार करने का इरादा जाहिर किया। लेकिन २ दिसम्बर को एक सकट उठ खड़ा हुआ। बात यह थी कि बादशाह ने एक अमरीकी महिला श्रीमती अर्नेस्ट सिम्पसन से विवाह करने की अपनी इच्छा अपने मिन्त्रयों के सामने प्रकट की थी। श्रीमती सिम्पसन पहले ही दो पितयों को तलाक दे चुकी थी। वे दोनों ही जिन्दा थे और उनमें से एक तो ब्रिटिश नागरिक ही था। मिन्त्रयों को यह प्रस्ताव पसन्द नहीं आया। ४ दिसम्बर को कामन्स-सभा में मि० बॉल्डविन ने यह सूचना दी कि सम्राट की सरकार हीनतर स्तर की महिला से विवाह की अनुमित देने के लिए कोई विशेप कानून बनाने को तैयार नहीं है। तब १० दिसम्बर को बादशाह को राजगद्दी छोड़ने के निश्चय का सन्देश सुनाया गया। राजगद्दी-त्याग-बिल दोनों सभाओं में बाकायदा पास हुआ और उसे शाही स्वीकृति मिली। रातोरात अधेरे और मेह में भूत-पूर्व बादशाह को समुद्र पार अपरिचित स्थान के लिए लाद दिया गया।

दूसरी घटना रुस की है। फैजपुर-अधिवेशन से ठीक एक महीने पहले २५ नवम्बर १९३६ को कैमिलन महल में सोवियट रूस के नये विधान पर विचार कर उसे अपनाने के लिए २०४० प्रतिनिधि एकत्र हुए। पिछले बारह बरसो में जो आधिक, राजनैतिक, सामाजिक और सास्कृतिक उन्नति हुई थी, उसकी यह अभिव्यक्ति थी। जरा सी देर में एक विशुद्ध खेतिहर देश, ससार की अत्युन्नत शक्तियों में गिना जाने लगा था और वहाँ खेती के साथ उद्योगों का भी समान रूप से विकास हो गया था। सारे काम आधुनिक वैज्ञानिक ढग से होते थे। नये विधान से नया युग आरम हुआ और राजसत्ता का एक नया सगठन हुआ। सोवियट के आठवे अधिवेशन में स्टैलिन ने वैधानिक कमीशन की स्थापना और उसके काम, पिछले बारह बरसो में रूसी जीवन में हुआ अन्तर, नये विधान की प्रमुख विशेषताएँ, उसकी मध्यवर्गीय आलोचना, उसके सशोधन और वैधानिक महत्व पर जो भाषण दिया, उसका तालियों, नारो और जयकारों से जबर्दस्त स्वागत हुआ।

फैजपुर के सारें वातावरण पर उक्त दोनो समाजवादी हलचलो का प्रभाव पडा। एक तरफ मजदूरो और किसानो के अधिकारो पर जोर दिया जाने लगा, दूसरी तरफ फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाने लगा। फैजपुर-काग्रेस मे विषय-निर्वाचन-समिति के सामने समाजवादी दल ने इस बात पर जोर दिया कि काग्रेस भारतीय जनता की दुनिया के गुलाम लोगो के साथ—चाहे वे उपनिवेशों के हों अथवा तथाकथित आजाद देशों के—सोवियट रूस की जनता के साथ एकता की घोषणा करें। इस बात की आशा स्वाभाविक थी, क्योंकि स्टैलिन ने कहा था, "यह इस वात का प्रमाण है कि जो कुछ रूस में हुआ है, वह दूसरे देशों में भी हासिल किया जा सकता है।" इस पुकार का एक महीने के ही अन्दर काग्रेस समाजवादी दल ने फैजपुर में जवाव दिया।

फैज्पुर-कांग्रेस : १६३७

रूसी विधान के पास होने के चार सप्ताह बाद और एडवर्ड के राजगद्दी छोडन के दो सप्ताह बाद एक वास से बनी बस्ती में जिसका नाम 'तिलकनगर' था, फैजपुर अधिवेशन हुआ। यह अपने ढग का पहला अधिवेशन था। गाघी जी ने स्वय यहाँ की सारी व्यवस्था को वारीकी के साथ देखा था। फैजपुर मे सीभाग्य से चालक-शक्ति शकरराव देव थे, जो गाधीजी के अनन्य और समझदार अनुयायी थे। इसके साथ ही उनमे असाधारण व्यवहार-वृद्धि थी। सभापति प॰ जवाहर लाल नेहरू भी इस वीच मे काफी नर्म हो गये थे। पिछले आठ महीनो में उन्होने जिस असलियत को पकडा उससे उनके और चारो चरफ के वातावरण के बीच जो खाई थी वह पट रही थी। अपने राष्ट्रपित-पद से दिये गए भाषण में उन्होन खान अब्दुल गफ्फार खाँ और हाल में छुटे हुए श्री एम० एन० राय का स्वागत करते हुए यूरोप में फासिस्टवाद के विजयपूर्ण प्रवाह की चर्चा की और उसका ढर्रा बताया। साथ ही इस बात की तरफ भी लोगो का ध्यान आकृष्ट किया कि अगर रोक-थाम न की गई तो उसका लाजिमी नतीजा ससारव्यापी महायुद्ध होगा। उन्होने बताया कि प्रतिकियावाटी शक्तियो की इस प्रतिक्रिया के बीच काग्रेस आज भी भारत में पूरी तरह लोकतत्र लाना चाहती है और उसी के लिए लडती है। वह साम्राज्यवाद-विरोधी है और वह राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे में बड़े-बड़े परिवर्तनों की कोशिश में है। मेरी ऐसी आशा है कि घटनाओं के प्रवाह में समाज-वाद आ जायगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की आर्थिक बीमारी का सिर्फ वही एक इलाज है। इसके बाद वह राष्ट्रीय समस्याओ की तरफ मुडे। उन्होने नये विधान, चुनाव के घोषणापत्र, विधान-परिषद, धारासभा के लिए निर्वाचित काग्रेस सदस्यो के सम्मेलन, सघीय ढाँचे के विरोध की आवश्यकता और एक नये सिरे से विधान बनाने की बातो की चर्चा की। फिर उन्होने पद-ग्रहण के प्रश्न की विस्तार-पूर्वक विवेचना की और इस बात की याद दिलाई कि किस तरह लखनऊ में उन्होंने यह बात साफ की थी कि पद-ग्रहण से विधान को अस्वीकार करने की बात ही उड जायगी। उन्होने आगे कहा, "हमारे सामने असली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक सयुक्त मोर्चा तैयार किया जाय। काग्रेस ऐसा सयुक्त सार्वजिक मोर्चा पहले

भी थी और अब भी है और यह बात लाजिमी है कि जो कुछ काम हो, उसकी धुरी और बुनियाद काग्रेस ही हो। सगिठत मजदूरो और किसानो के सिक्रय सहयोग से यह मोर्चा और भी मजबूत होगा और हमे उसके लिए कोशिश करनी चाहिए।"

काग्रेस ने फैजपुर में एक प्रस्ताव द्वारा देश को चेतावनी दी कि अगर लडाई छिडे तो उसको युद्ध के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा होने वाले अपने धन और जन के शोषण को रोकना चाहिये और यह भी कहा कि उस लड़ाई में न कोई चन्दे दिये जाय, न कर्ज, न लडाई की तैयारियों में ही मदद दी जाय। इसके अलावा देश की सीमाओं में शान्ति और पडोसियों से दोस्ती बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। काग्रेस का ऐसा विश्वास है कि सीमाप्रान्त में जो सरकारी नीति है वह असफल रही है, क्योंकि उसका निर्माण साम्राज्यवादी हितों की दृष्टि से हुआ है। काग्रेस का विश्वास है कि वहाँ के पठानों पर खूखार होने का जो दोप लगाया गया है, वह निराधार है और उन लोगों के साथ दोस्ताना बर्ताव करके उनका सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार की हजारों भारतीयों को अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द रखने की अमानुषिक नीति की भी निन्दा की गई। उनकी छूट और तीन नजरबन्दों की कथित आत्महत्या के सिलसिले में जॉच की माँग की गई और साथ ही अडमान कारावास को बन्द करने के लिए भी कहा गया।

फैज़पुर के सबसे महत्वपूर्ण विषय चुनाव और विधान-परिषद से संबधित थे। इसके अतिरिक्त धारासभा के लिए निर्वाचित काग्रेसियो के सम्मेलन और राज्याभिषेक-उत्सव में साथ देने की बाते भी महत्वपूर्ण थी। पहली अप्रैल १९३७ को एक आम हडताल के लिए कहा गया। यह हडताल इस बात को प्रकट करने के लिए थी कि भारतीय जनता अवाछित विधान के लादे जाने के विरुद्ध है। काग्रेस की दृष्टि से वह विधान भारत की आजादी की लड़ाई के साथ विश्वासघात है और इसका नतीजा यह होगा कि भारतीय जनता के शोषण के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड और भी अधिक मजबूत हो जायगी। भारत अपने लिए स्वय ही विधान बनाने का अधिकार चाहता है। पद-ग्रहण की समस्या को फिर महासमिति के लिये छोड दिया गया, जिसका फैसला चुनावो के बाद करना था। लेकिन इस बीच धारासभा के काग्रेसियो, महासमितियो के सदस्यो और ऐसे व्यक्तियो का, जिन्हें कार्य-कारिणी नियुक्त करे, एक सम्मेलन करने के लिए कहा गया। चुनाव के घोषणा-पत्र का समर्थन किया गया। लखनऊ मे जो खेति-हर कार्यक्रम तैयार किया गया था, उसे कुछ सशोधनो के बाद स्वीकार कर लिया गया। चूकि काग्रेस ने पार्लामेण्टरी कार्य-क्रम बनाया था, इसलिए उस समय सविनय आज्ञा-भग आन्दोलन का कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्रनुशासन के नियम

काग्रेस को मजबूत करने के लिये आम जनता से पोषण प्राप्त करना और राष्ट्रीय सस्था को हर ढग से समृद्ध बनाना था। यह आवश्यकता फेंज़पुर-काग्रेस के पश्चात् चुनाव से पूरी हो गयी। इससे देश मे एक सिरे से दूसरे सिरे तक राजनैतिक जाग्रित का जो तूफान आया, वह सरकारी नजर से भी छिपा न रहा। सरकार ने महसूस किया कि यद्यपि वोट देने का अधिकार आवादी के सिर्फ दसवे हिस्से को मिला था, फिर भी उससे देश में एक क्रांति शुरू हो गई थी। नतीजा यह हुआ कि स्थानीय सरकारों ने काग्रेसी उम्मीदवारों को उनकों जेल की सजा के या किसी और वहाने मताधिकार से विचत कर दिया था। कुछ प्रान्तों में बरावर सिक्रिय हस्तक्षेप किया गया, और शान्तिपूर्ण जलूसो, सभाओं और झडारोहण पर पावन्दियाँ लगा दी गई। बड़े काग्रेसी नेताओं के आने-जाने पर रोक लगा दी गई। खान अब्दुल गफार खा को पजाब और सीमाप्रात में घूसने नहीं दिया गया। कहने की जरूरत नहीं कि जहां इससे सरकारी रुख का पता लगता है वहाँ साथ ही इसका नतीजा यह भी हुआ कि लोगों ने काग्रेसी उम्मीदवारों की मदद में जी-जान से काम किया। इस अवसर पर अनुशासन की अत्यन्त आवश्यकता थी। अत कार्य-कारिणी के अनुशासन सबधी पहले प्रस्तावों को रद करते हुए ये नियम बनाये गये —

(१) काँग्रेस कमेटी, काग्रेस कार्य-कारिणी, किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटी के सदस्य, अथवा काग्रेस के फैसलों के खिलाफ जो जानबूझ कर काम करता हो, जो नियुक्त निर्णायकों और अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, जो काग्रेस फड में गबन, चोरी या हिसाब की गडबड़ी का दोषी हो, जो काग्रेस के सामने प्रतिज्ञा-भंग का दोषी हो, जिसने काग्रेस के मेम्बर बनाने या काग्रेस के चुनाव में बेईमानी की हो, जो जान-बूझकर इस ढग से काम करता हो जिससे कार्यकारिणों की राय में काग्रेस की प्रतिष्ठा और शक्ति को चोट पहुँचती हो और जिसकी वजह से उसकी सदस्यता अवाञ्छनीय हो गई हो उसके विरुद्ध अनु-शासन की कार्रवाई हो सकती है।

(२) जहाँ तक काग्रेस कमेटियो का सवाल है, अनुशासन सबघी कार्रवाई

यह हो सकती है कि उस कमेटी को अधिकारो से विचत कर दिया जाय।

(३) जहाँ तक कार्य-कारिणी या किसी निर्वाचित काग्रेस कमेटी के सदस्य का सवाल है, उसके खिलाफ अनुशासन सबधी कार्रवाई मे उसको उस पद से या सदस्यता मे हटाया जा सकता है और एक ऐसा समय निश्चित किया जा सकता है जब तक न वह किसी पद के लिए चुना जा सकता है और न किसी कमेटी का सदस्य ही हो सकता है।

- (४) जहाँ प्रारंभिक काग्रेस संगठन के सदस्य का सवाल है, उस को निश्चित समय तक किसी चुनाव में खड़ा होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही उस अवधि में सदस्यता के दूसरे अधिकारों से उसे विचत किया जा सकता है और इसके अलावा उसके काग्रेस सदस्य बनने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
- (५) अनुशासन संबंधी कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपराधी कमेटी, या व्यक्ति को, अपनी सफाई पेश करने और अपने विरुद्ध आक्षेपो का उत्तर देने का अवसर दिया जायगा।
- (६) प्रान्तीय काग्रेस कमेटियों की कार्य-समितियों को भी अनुशासन सबधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा जिसका उपयोग वे अपने अधीन सभी कमेटियों और सदस्यों पर कर सकती हैं। अभियुक्त कमेटी और व्यक्ति को कार्य-कारिणी से अपील करने का अधिकार होगा, लेकिन अपील तय होने तक उसे उस आज्ञा का पालन करना होगा जो कि पहले जारी हो चुकी है और जिसके खिलाफ अपील की गई है।
- (७) जब कार्यकारिणों काम न कर रही हो उस समय अनुशासन संबंधी मामलों में जहाँ तात्कालिक घ्यान देने की जरूरत हो राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकता है और यह काम वह कार्य-कारिणों की ओर से और उसी के नाम पर करेगा। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कार्यकारिणों की अगली बैठक पर अपने सारे निर्णय उसके सामने रखने होगे और उसकी स्वीकृति लेनी होगी।

चुनाव में कांग्रेस की विजय

फैजपुर-अधिवेशन के पश्चात् ही चुनाव हुआ। इस चुनाव में काग्रेस के ५८ मुस्लिम उम्मीदवारों ने ४८२ में से २६ सीटें जीती, जिनमें अधिकाश सीमाप्रान्त में थी। ४२४ गैर-काग्रेसी मुसलमान जीते। २ करोड ८० लाख लोगों ने वोट दिये। कुल निर्वाचकों की यह संख्या ५५ फ़ीसदी थी। प्रान्तीय घारा सभाओं में कुल १५८५ सीटे थी। इनमें से ७११ काग्रेस के हाथ में आई और पाँच प्रान्तो—मद्रास, यू० पी०, सी० पी०, बिहार और उड़ीसा में उसका स्पष्ट बहुमत रहा। चार प्रान्तो यानी बगाल, बम्बई, आसाम और सीमाप्रान्त में अकेले, काँग्रेस पार्टी सबसे बड़ी थी। सिघ और पंजाब की एसे-म्बलयों में काग्रेस अल्पसंख्यक थी।

शपथ की समस्पा

चुनावों में काग्रेस की जीत तो हुई पर उसके साथ ऐसी कठिन समस्याएँ आई, जिनको हल करना पूरी तरह काग्रेस के हाथ में नहीं था। इसमें राजभित की

शपथ एक बडी परेशानी थी। बहुत से लोगो की आत्मा इस वात को गवारा नहीं करती थी कि पुराने रवैये के मुताबिक अग्रेज बादशाह के प्रति राजभिक्त की शपथ ली जाय। इस सिलिसिले में शक उठ खडा हुआ था। ऐसी स्थिति में बादशाह के लिए वफादारी की शपथ लेने से पहले ही सम्मेलन ने नये निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और हिन्दुस्तान की जनता के प्रति बफादारी की शपथ दिलाई, जो इस प्रकार थी —

"मैं, जो कि अखिल भारतीय सम्मेलन का सदस्य हूँ, इस वात की जपय लेता हूँ कि मैं हिन्दुस्तान की सेवा करूँगा, घारासभा के वाहर और भीतर, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम करूँगा और हिन्दुस्तानी जनता की गरीवी और उसके शोषण को खत्म करने की कोशिश करूँगा। मैं इस वात की शपथ लेता हूँ कि मैं काग्रेस के आदर्श और उद्देशों को हासिल करने के लिए काग्रेस के अनुसासन में काम करूँगा ताकि हिन्दुस्तान आजाद हो और उसके करोड़ो निवासी जिस बोझ और तकलीफ से पिस रहे हैं उससे छुटकारा पा जाय।"

कांग्रेस को निर्देशक नीति

राष्ट्र के सामने तात्कालिक काम धारासभाओं में काग्रेस नीति को विस्तार-पूर्वक स्पष्ट करना था। इसके लिए सक्षेप में निर्देशक-नीति यह थी—

ें (१) काग्रेस घारासभाओं में नये विधान और सरकार से सहयोग के लिए नहीं, बल्कि उनसे लड़ाई लड़ने के लिए घुसी है। इसलिए काग्रेस अपनी उस बुनियादी नीति पर जमी हुई है कि जब तक परिस्थितियों के कारण परिवर्तन आवश्यक न हो, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की मशीनरी से असहयोग करना चाहिये।

(२) काग्रेस का उद्देश्य है, पूर्ण स्वराज्य। काग्रेस के सारे काम उसी तरफ केन्द्रित है। काग्रेस हिन्दुस्तान में सच्ची लोकतत्रीय सरकार चाहती है, जिसमें राजनैतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथों में हो और उस जनता का सरकारी ढाँचे पर सफल नियत्रण हो।

(३) धारासभाओं में काग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य नये विधान का विरोध करना है, इस नये ऐक्ट के संघीय भाग को लागू होने देने से रोकना है और साथ ही विधान परिषद् के लिए राष्ट्र की माँग पर जोर देना है।

(४) घारासभा के काग्रेसियों को यह बात याद रखनी है कि वे किसी ऐसे काम अथवा जलसे में शामिल न हो, जिससे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शक्ति अथवा प्रतिष्ठा बढती हो।

(५) धारासभा का कोई काग्रेसी ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये हुए किसी

खिताब को स्वीकार नही कर सकता।

(६) हर सदस्य को प्रान्तीय धारासभा में काग्रेस पार्टी के अनुशासन के

साथ काम करना होगा। सरकार अथवा किसी दूसरे समुदाय से बातचीत करने के लिए उस दल के नेता प्रतिनिधित्व करेगे।

(७) घारासभा के अधिवेशन के समय जब पार्टी उसमें हिस्सा ले रही हो,

तव सव सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(८) धारासभा के सारे कांग्रेसी सदस्य खादी की पोशाक में होगे।

(९) प्रान्तीय घारासभाओं में काग्रेस पार्टियों को किसी दूसरे समुदाय से कार्य-कारिणी की अनुमित विना कोई समझौता नहीं करना चाहिए।

(१०) यदि प्रान्तीय धारासभा का कोई सदस्य, जो काग्रेस की तरफ से नहीं चुना गया है, लेकिन जो काग्रेस की शपथ लेकर उसके सिद्धान्तो और अनुशासन को मानने के लिए तैयार है, और पार्टी उसका साथ वाछनीय समझती है तो वह उसको पार्टी में दाखिल कर सकती है। लेकिन यदि कोई ऐसा आदमी है जिसके खिलाफ काग्रेस ने अनुशासन सबधी कार्रवाई की है तो उसको विना कार्य-कारिणी की अनुमित के दाखिल नहीं किया जा सकता।

(११) काग्रेस सदस्यो को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि घोषणा-

पत्र और र्खेतिहर प्रस्ताव में जो कार्यक्रम है उस पर अमल किया जाय।

(१२) वर्तमान एक्ट में सरक्षण तथा गर्वनर और वायसराय के विशेषा-धिकारों के कारण गतिरोध होना अनिवार्य है। काग्रेसी नीति के पालन में यदि ऐसी स्थित पैदा हो तो उससे वचने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

(१३) प्रान्तीय धारासभा के काग्रेसियों को सिविल शासन का व्यय घटाने, तथा व्यापार, तट-कर और मुद्रा पर पूर्ण राष्ट्रीय नियत्रण की माग करनी चाहिये। बोलने और लिखने की आजादी के लिए जोर देना चाहिये। इनके अलावा युद्ध की तैयारियों और युद्ध-ऋणों का विरोध करना चाहिये।

(१४) घारासभा के भीतर और वाहर के काम मे सामजस्य होना चाहिये और जो मागे की जाये उनके पीछे सार्वजनिक समर्थन प्राप्त कर लेना चाहिये।

राष्ट्रीय सम्मेलन

चुनाव में कार्यस की विजय पर चारों तरफ खुिंग्याँ मनाई जा रहीं थी। परन्तु जहाँ आशाएँ थी वहाँ उनके साथ डर भी मिला हुआ था। ऐसी हालत में दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उससे पहले १७ मार्च को महासमिति की बैठक हुई और १७ मार्च को ही गाम को श्री सुभापचन्द्र बोस को विना किसी शतं के छोड दिया गया। पाँच बरम से ज्यादा में वह निर्वासित या नजरबन्द थे। वह जिस समय छोड़े गये उनका स्वास्थ्य बेहद खराब था। उनकी छट पर राष्ट्रपति ने महासमिति की तरफ से उनका स्वागत किया और उनके शीझ रवास्थ्य-छान की शुभ कामनाए की। पद-ग्रहण के सवाल पर महासमिति ने

इस वात का अधिकार तथा अनुमित दी कि जिन प्रान्तों में काग्रेस का बहुमत है वहाँ यदि उस प्रान्तीय धारासभा की काग्रेस पार्टी को इस वात का विश्वास हो और यदि वह इस वात को खुले आम घोषित कर सके कि गवर्नर हस्तक्षेप के अपने विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं करेगा या वैधानिक कार्रवाई में मंत्रियों के निर्णय को नहीं टालेगा तो वहाँ पद-ग्रहण किया जा सकता है। इसके वाद सम्मेलन हुआ और सारे सदस्यों ने एक स्वर से हिन्दुस्तानी में शपथ ग्रहण की। फिर यह राष्ट्रीय मांग पेश हुई .—

"यह सम्मेलन भारत की जनता की इस राय को फिर दुहराता है कि सन् १९३५ के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट से भारत की गुलामी और उसके शोषण

की जड मजवृत होती है।

"यह सम्मेलन इस बात की घोषणा करता है कि भारतीय जनता किसी विदेशी शक्ति या सत्ता के इस अधिकार को नहीं मानती कि वह भारत के राजनैतिक और आर्थिक ढाचे का निर्देश करे।

"यह सम्मेलन भारत के लिए सच्ची लोकतत्रीय राज-सत्ता के पक्ष मे है जिसमें राजनैतिक शक्ति देश की जनता के हाथ में हो। ऐसी राजसत्ता की स्थापना खुद भारतीय जनता ही कर सकती है और इसके लिए जो माध्यम है, वह है विधान-परिषद, जो वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होनी चाहिये और जिसको देश का विधान बनाने का पूर्ण और अन्तिम अधिकार होना चाहिये।

"इसलिए यह सम्मेलन काग्रेस पार्लिमेण्टरी पार्टियों को आदेश देता है कि वे राष्ट्र के नाम पर अपनी-अपनी घारासभाओं में इस विघान के वापस लिए जाने

की माँग करे ताकि हिन्दुस्तानी जनता अपना विधान बना सके।"

नए एक्ट का विरोध

पहली अप्रैल १९३७ आई और चली गई। उस दिन एक तरफ तो शातिपूर्ण हडताल हुई और दूसरी तरफ तीन महीने के लिए जवर्दस्त प्रचार-कार्य शुरू
हुआ। ग्यारह में से जिन छ प्रान्तों में पार्टी का बहुमत था, वहाँ न तो वह पदप्रहण ही करती और न उस तरफ से अपना हाथ ही खीचती। अगर काग्रेस पार्लीमेण्टरी मैदान खाली कर देती तो सरकार अपना काम जानती थी। दूसरी तरफ
अगर काग्रेस पद-ग्रहण करती तो सरकार फौरन नये वातावरण से अपना मेल
विठा लेती। नौकरशाही अपना रग वदलने में होशियार थी। मौका पाने पर
वह पार्टी के लोगों को उखाड फेकती, लेकिन काग्रेस सरकार को मनमानी खेलने
का मौका देने को तैयार नहीं थी। भारत के, शायद दुनिया के, इतिहास में यह
एक पहली सस्था थी जिसने गवर्नर से यह आश्वासन माँगा कि वह अपने विशेषाधिकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा और मित्रयों के वैधानिक काम को नहीं टालेगा।

विशेपाधिकार खुद एक्ट से ही मिले हुए थे और उनको बड़े सोच-विचार के वाद 'विशेष' नाम दिया गयाथा। फिर गवनर इन सरक्षणों को कैसे छोडते जिनकों कानून ने उन्हींमें निहित किया था, जिनकी शासक सत्ता के स्थापित स्वार्थों के लिए आव-श्यकता थी और जिनके बलवूते पर ही असलियत में गुलाम देश की लोकतत्री कार्रवाई को रोका जा सकता था? ऐसे आव्वासनो को माँगने की वैधानिकता पर एक जबर्दस्त लडाई हुई। राष्ट्र के सामने वैधानिकता अथवा अवैधानिकता का प्रश्न नहीं था। जो विधान सामने था उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं था। उस विघान में न तो आत्म-निर्णय की झलक थी, न सयुक्त निर्णय ही था, विलक असल में कुछ और ही निर्णय था जो बाहर से लादा गया था। यदि ऐसे विघान को भारतीय अमल में लाते तो साफ है कि ऐसा वे अपनी खास शर्तो पर ही करते, वरना नये एक्ट के अध्यायो और उसकी घाराओं के अनुसार कानून और विधान अपना रास्ता पकड़ते। अगर गति-रोध होते तो उसमे भारत का क्या दोप ? एक ओर ब्रिटिश सरकार ने जान-वूझकर भारतीय जनता की घोषित इच्छा के विरुद्ध नीति अपनाई थी, दूसरी ओर महासमिति ने नये विधान के विरोध का इरादा किया था। चुनाव के मौके पर निर्वाचन-क्षेत्रो में ये दोनो वाते समझा दी गई थी। गति-रोव होना अनिवार्य था, यह वात साफ कर दी गई थी और साथ ही यह वात भी कि इससे ब्रिटिश-साम्राज्यवाद और भारतीय राष्ट्रीयता का जन्मजात विरोध और उभड़ेगा और तब नये विघान का अलोकतत्रीय और निरकुश स्वरूप और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। इस विधान के निजी गुण-दोष पर भी काग्रेस उसे नही अपना सकती थी। लेकिन जहाँ कानूनी और वैधानिक पक्ष का सवध है वहाँ यह कहना आवश्यक है कि गाघीजी ने यदि काग्रेस के रुख को सही वताया तो वह एक राजनैतिक दल के नेता की हैसियत से नही, विलक एक वैधानिक वकील की हैसियत से, जिसको साम्राज्य के सुदूर प्रदेशो का पर्याप्त अनुभव था। भारत और इगर्लंड में कानूनी लोगों ने विरोध किया। सबसे पहले मत का विरोध सर तेज वहादुर सप्नू ने किया और इस माँग को अमान्य बताया। कानून के ऐसे धुरघर के विरोध में दो कानूनी पंडित सामने आये—एक श्री तारापोरावाल, और दूनरे डा॰ वहादुरजी। उन्होने निञ्चित रूप से अपना सुचिन्तित मत यह बताया कि आरवासनो के लिए काग्रेस की माग किसी भी दृष्टि से कानून या विधान के लिए अमान्य नहीं है । इस समय जब कि भारतीय मेन दो दलों मे बँटा हुआ था, इगलैंड के कानूनों महारथी वेरीडेल कीय ने काग्रेस-मत को मुदृढ किया और उसकी मागो की वैधानिकता का समर्थन किया। इंगलैंड के दैनिक पत्र भारतीय नेताओ के दृष्टिकोणों में दिलचस्पी ले रहे थे। लन्दन के 'न्यूज कोनीकिल' में पं० जवाहर-लाल नेहरू के वयान के जवाब में लार्ड सोयियन ने लिखा कि यह विघान गिटिया पार्लीमण्ट ने अपनी जिम्मेदारी पर बनाया है और इसमें भारतीय स्वशासन की

दिशा में एक रास्ते का सुझाव है। मि० नेहरू और उनके दोस्त दूसरे रास्ते में यकीन करते हैं। विधान इस अनुभव के आधार पर वना है कि तात्कालिक स्व-शासन के सब से बड़े रोड़े खुद भारत में ही है।

गवर्नरों के विशेषाधिकार कुछ समुदायों, स्थापित स्वार्थों और क्षेत्रों से सबित थे। समुदाय थे—अल्पसंख्यक दल, स्थापित स्वार्थ थे—बिटिश स्वार्थ और क्षेत्र थे—बिटिश मारत और भारतीय रियासतों के कुछ छँटे हुए भाग। उस माँग का मतलव यह था कि गवर्नर आस्ट्रेलिया के गवर्नरों की तरह ही काम करे। वह अपनी इच्छा से मित्रयों को पद-च्युत न करे, मंत्रियों की कौसिल में सभापित न वने, शान्ति और सुरक्षा के नाम पर आर्डिनेन्स न वनायें, एडवोकेंट जनरल नियुक्त करने में उसका कोई हाथ न हो और न वह पुलिस के नियम वनायें।

ब्रिटिश मित्रयों का यह कहना था कि जब तक एक्ट में सशोधन न कर दिया जाय, काग्रेस के मागे हुए आश्वासन देना गवर्नर के हाथ की वात नहीं है। दूसरी तरफ कार्यकारिणों को प्रमुख वैधानिकों ने यह परामर्श दिया था कि विधान के अन्तर्गत ऐसे आश्वासन दियें जा सकते हैं। लार्ड जेटलैंड और आर॰ ए॰ वटलर के वक्तव्य से काग्रेस की नाराजगी वढ गई। वजह यह थी कि उस वक्तव्य से गलत-फहमी होती थी और उसमें काग्रेस दृष्टिकोण को तोड-मरोडकर उसके गलत अर्थ लगायें गयें थे। सबसे बड़ी वात यह थी कि जिस ढग से और जिस स्थिति में यह वयान दिया गया था उसमें काग्रेस के प्रति अशिष्टता थी। इसी बीच काग्रेसी बहुमत के प्रान्तों में मित्रमण्डल वनने लगे जो विलकुल अवैधानिक थे, जिनमें स्वतंत्रता की गध भी नहीं थी और जिनमें उन प्रान्तों के सार्वजिनक बहुमत की अवहेलना की गई थी। सारे देश में आम सभाएं की गई और तथाकथित मित्रयों की निन्दा की गई।

पद्-ग्रह्ण का प्रश्न

परस्पर विरोधी राजनैतिक और कानूनी मतो को लेकर तारो और केविलो हारा लडाई होती रही, लेकिन भारत-मत्री या भारत-सरकार पर इसका कोई असर दिखाई नही दिया। इस तरह तीन महीने बीते। तब जून के तीसरे सप्ताह में वायसराय ने एक बयान निकाला। लेकिन उनके बीच में आने से मामले कोई ज्यादा सुघर नहीं गये और न कोई छोटा रास्ता ही निकला। उसका उद्देश्य असहानुभूति का भी नहीं था। काग्रेस ऐसा अनुभव करती थी कि जब तक गवर्नरों से कुछ आखासन न मिले, एक्ट के आधार पर पद-ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वाइसराय पिछले तीन महीनो के अनुभव से यह सिद्ध कर रहें थे कि जिन प्रान्तों में मित्रमडल बने थे वहाँ सरकारी कर्मचारियों से काफी सहयोग मिल रहा था और साथ ही गवर्नर भी सहायता, सहानुभूति और सहयोग के साथ

काम कर रहे थे। वायसराय ने अपने मन में काग्रेस की आशकाओं को मानते हुए यह वताया कि उनके लिए व्यवहार में इस वात का कोई आधार नहीं या कि गवर्नर मित्रमडल की नीति में हस्तक्षेप करेंगे ही, लेकिन उस स्थिति मे क्या होगा, जहां गवनर को निज-निर्णय का अधिकार हो और जहाँ गवनर और मित्रमदल में जबर्दस्त मतभेद हो ? मित्रयो को सारे क्षेत्र मे, यहाँ तक कि विशेषाधिकार के क्षेत्र में भी, परामर्श देने का अधिकार है। ऐसे परामर्श के लिए मत्री घारा-सभा के प्रति उत्तरदायी है। विशेषाधिकार के सीमित क्षेत्र में अपने काम के लिए गवर्नर पार्लामेण्ट के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जव गवर्नर मत्रियो के परामर्श को नहीं मानता तब उस निर्णय की जिम्मेदारी उसी की है। मनी उस जिम्मेदारी से मुक्त हैं और उन्हें इस वात को खुले आम कहने का हक हैं कि उस मामले में जो फैमला हुआ है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। वायसराय ने गाधीजी के इस सहायक सुआव का स्वागत किया और कहा, "गवर्नर और मित्रमटल के नवध टूटने का सवाल तो उस समय ही आना चाहिये जब उनमें वडा जर्वदस्त मतभेद हो। सिर्फ ऐसी ही हालत मे मित्रमंडल को या तो इस्तीफा देना चाहिये या उसको पदच्युत कर देना वाहिये। इस्तीफे में आत्म-सम्मान है और मित्रमटल का स्वेच्छा-पूर्ण काम है। पदच्युत करना अस्वाभाविक है और उसमें हीनता का बोब होता है । दोनो वाते सभव है , लेकिन ऐक्ट की नीयत यह नही है कि गवर्नर के पदच्यत करने की मांग से मित्रमेडल विवंश होकर त्याग-पत्र दे। आमतौर से गवर्नर और मिन-मडल में जो मतभेद होगे वे दोनो ओर की सद्भावनाओं ने आपसी समजीते द्वारा सुलक्ष जाने चाहिये। गदर्नर इस बात के लिए उत्सुक है कि अगड़े न हो और ऐसे अगड़े न होने देने के लिए यह कोई कसर नहीं उठा रुपेगा। उस तरह व्यवहार में कार्य-सवालन गवर्नर के नाम से होगा, लेकिन मित्रमटल के क्षेत्र में कुछ पावन्दियो को छोटकर गवर्नर अपना शासन-सनालन मंत्रियो के परामशै ने ही करेगा । कुछ सीमित और सुनिन्त्रित मामलो में और जगहो की तरह यहाँ भी पत्नी जिम्मेदारी तो मित्रमञ्च की ही होगी, लेकिन गवर्नर अन्तत पार्ली-मेण्ट के प्रति उत्तरदायी होगा। शेष क्षेत्र में वेवल मत्रिमङक की ही जिम्मेदारी रै और तर निर्फ प्रान्तीय धारासभा के सामने ही जवाबदेह होगा। विशेष इत्तर-राजित्य के नामलों में यवनंत्र मित्रमङ्ख के परामर्थं ने भित्र गोगं अपना सवता है ज़ीर ऐसे मामलों में पैस हा उसी के हाथ में होता और उसके दिए वर पालींमण्डे के प्रति इत्तरदायी है। इसका इन् यह नहीं है कि वृद्धन्य आयार है, या इसकी इस बार रा रण है कि अपने विशेष इसरदायित्य के क्षेत्र के शताबा कर प्रान्त हे देनिर एक्त में ह्लाक्षेप वर्गा जा है। यहाँ प्रधाओं ने नहीं, दि प्रपान सिराहर के साम करने की कीति ने जिसन कार में वैद्यानिक प्रकति हुई है। विद्यान में भरतपारण पनिहर्ण तमे की व्यवस्था का अर्थ मह गही है ति हैंसे दानाबारण

परिस्थितियाँ सामने लाने की इच्छा है। उस पूर्णतर राजनैतिक जीवन के लिए, जिसे आपमें से बहुत से लोग जी-जान से चाहते हैं, सबसे छोटा मार्ग इस विधान को अपनाना और उसको उसी के गुण-दोष के अनुसार अमल में लाना है। इस विधान को पूरी तरह अमल में लाने और उसके अनुसार आगे वढने में ही देहाती जनता और समाज के निचले वर्ग के कष्टो को स्थायी रूप से घटाने और उन्हें दूर करने की, सर्वोत्तम आशा निहित है।"

कार्यकारिणी की बैठक

२० जून १९३७ के वाइसराय के भापण के वाद तत्काल जुलाई में काग्रेस की स्थित को काग्रेस की कार्य-कारिणी के उस समय के प्रस्तावों से सिक्षप्त उद्धरण लेकर व्यक्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले १८ मार्च को दिल्ली में महासमिति की जो वैठक हुई थी, उसमें पद-ग्रहण के प्रश्न पर यह कहा गया था कि उन प्रान्तों में जहाँ घारासभा में काग्रेसी बहुमत हो और जहाँ काग्रेस पार्टी के नेता को यह विश्वास हो और इसकी वह खुली घोषणा कर सके कि गवर्नर मित्रयों के वैधानिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वहाँ मित्रमंडल बनाया जा सकता है। इसके अनुसार विभिन्न प्रान्तों के काग्रेसी नेताओं ने आश्वासन मागे और उनके अभाव में मित्रमंडल बनाने की अपनी असमर्थता प्रकट की। इस बीच भारतमत्री, उपमत्री और वाइसराय ने ब्रिटिश सरकार की ओर से उस समस्या पर कुछ बातों की घोषणाएं की जिनके आधार पर कार्य-कारिणी ने ऐसा महसूस किया कि परिस्थितियों का कुछ ऐसा जोड बन गया है कि गवर्नरों के लिए अपने विशेषाधिकारों को उपयोग में लाना सरल न होगा। इसीलिए जुलाई के पहले सप्ताह में वर्धा में कार्य-कारिणी ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास किया —

"इसलिए कमेटी इस नतीजे पर पहुची है कि जहा काग्रेसियो को मित्रमडल बनाने के लिए आमिन्त्रत किया जाय वहाँ उन्हें मित्रमडल बना लेना चाहिये। किन्तु वह इस बात को भी स्पष्ट करना चाहती है कि पद-ग्रहण करके चुनाव के घोषणा-पत्र के अनुसार काम करने और उसकी बातो को ही पूरा करने के लिए कोशिश होनी चाहिये, जिसके अनुसार एक ओर तो नये विधान के सबध में काग्रेसी नीति होगी और दूसरी ओर रंचनात्मक कार्य-क्रम को चलाया जायगा।"

पद-प्रहरा : जुलाई १८३७

वर्धा म कार्य-कारिणी द्वारा पद-ग्रहण का निश्चय करने पर काग्रेसी बहुमत के प्रान्तो के अन्तर्कालीन मित्रमंडलों ने त्याग-पत्र दे दिये। गर्वनरों ने अपने-अपने प्रान्त की काग्रेस-पार्टी के नेताओं को आमिन्त्रत किया कि वे नये मिन्त्रमंडल बनाने में उसकी (गर्वनर की) सहायता करें। मुलाकाते सतोषप्रद हुईं और नेताओं ने मित्रमंडल बनाना स्वीकार कर लिया तथा गर्वनरों

को अपने साथियों के नाम दे दिये। जैसा कि काग्रेस कार्य-कारिणी पहले कह चुकी थी, रहने और सवारी के लिए सरकारी इन्तजाम के अलावा, मित्रयों, प्रमुखों और एडवोकेट-जनरलों का वेतन ५००) रु० प्रति मास निश्चित किया गया।

पद-ग्रहण से राप्ट्रीय जीवन में एक नई प्रिक्रिया आरम्भ हुई। काग्रेसियों को विभिन्न प्रकार के और विभिन्न परिणाम के महत्व के शासन का अनुभव नहीं था। उनमें से कुछ ही लोगों को घारासभा का और उससे भी कम लोगों को सरकारी अनुभव था, किन्तु बड़े प्रान्तों का शासन उनके लिए नयी चीज थी। शासन की जिटलताओं से उनका सम्पर्क न तो गहरा था और न व्यापक। इसके अलावा उनको परस्पर विरोधी हितों में मेल कराना था और विभिन्न माँगों के साथ न्याय करना था।

एक ओर यह बात थी, दूसरी ओर जनता की आशाएं बहुत बढी-चढी थी। किसानों को राहत मिले, कर्ज घटे, मद्य-पान निपंध हो, गैरकानूनी वसूलयावी वन्द हो, घरेलू धंधों और बृहत् परिमाण के उद्योगों को बढाया जाय, शिक्षा का पुनस्सगठन हो, राष्ट्रीय संस्कृति का पुनस्तयान हो, ग्राम-पचायते फिर से कायम हो, न्याय संस्ता और सही हो, नये नागरिक अधिकार और कर्त्तव्यों का स्वरूप सामने आये, हरिजनों और पिछडी हुई जातियों की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दंशा सुवारी जाय, श्रम को देश की संच्ची सम्पत्ति समझा जाय, ये सुवार ये जो मित्रयों को करने थे। इनमें से हर काम के लिए साधनों की जाच करनी थी, योजना बनानी थी और सामाजिक तथा आर्थिक मूल्य के सबध में सार्वजनिक धारणाओं को शुद्ध और उन्नत करना था। लगभग सभी प्रान्तों में राजनैतिक कैदी थे जिनमें कुछ हिसा के दोपी थे। ये लोग काग्रेस के हाथों छुटकारा पाने की बाट जोह रहे थे। काग्रेस की नीयत और उसके ढंग पर, काग्रेस के कट्टर विरोधी तरह-तरह के सन्देह कर रहे थे।

गांधोजी-द्वारा स्पष्टीकरण

विरोधियों से गांधीजी का कहना था कि पद-ग्रहण का अर्थ यह नहीं है कि कागेस एक्ट को अमल में लाना चाहती है। उसका विचार तो यह है कि इस अवसर पर पिक्चम से पूर्व की ओर, पदार्थ से निहित भावना की ओर, मशीन से दस्तकारी की ओर, धन से सेवा की ओर, सजावट से सादगी की ओर और मशीन के पिहये में चरखे के चक्र की ओर दृष्टि को मोट दिया जाय। नारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को इस तरह फिर से जगा दिया जाय कि भारत में अगरेजियन की जगह भारतीयता जा जग्य। वह स्वय पर्याप्त हो, सादा हो, उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो और उसकी राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो और उसकी राष्ट्रीयता में मानवता हो। ऐसी दशा में मिनियों के लिए यह क्षाव्य्यक या कि वे पुराने मूल्यों को छोड़े और नये मूल्य अपनायें।

ऐक्ट पर कानूनी ढग से अमल किया जायगा, इसे और भी स्पष्ट करते हुए गाघीजी ने कहा—"यदि तीन करोड निर्वाचकों के प्रतिनिधियों में अपना विश्वास और अपनी बुद्धि है तो वे इस ऐक्ट के उद्देश्यों को दबा सकते हैं। यह काम बड़ी आसानी से हो सकता है। वे कानून के अन्दर ही इस ऐक्ट का अप्रत्याशित ढग से उपयोग करें और उस ढग से उसका उपयोग ही न करें, जिसकी कि इसके बनाने वालों ने आशा की है।" इस तरह 'कानूनी' शब्द का अर्थ यह था कि ऐक्ट की घाराओं का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके माने ऐक्ट पर अमल करने की सलाह के नहीं थे।

कांग्रेस की प्रारम्भिक कठिनाइयाँ

गाघीजी-द्वारा ऐक्ट के स्पष्टीकरण से सिद्ध है कि काग्रेस के सामने अनेक किठ-नाइयाँ थी। सबसे बड़ी किठनाई प्रान्तीय काग्रेस कमेटियों की स्थित के सबध में थी। उन्हीने चुनाव की तैयारी की थी। उन्होने ही उम्मीदवारों को छाँटा था। इसलिए जनता की दृष्टि में वहीं सार्वजनिक अधिकारों की रक्षक और मित्रयों की सत्ता की प्रतिनिधि थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अधीर जनता ने इन कमेटियों से बहुत-सी मागे की, जिनका मित्रगण निपटारा नहीं कर सकते थे।

काग्रेस चाहती थी कि काग्रेसी मित्रयों के मुश्किल काम को आसान करें और वे धारासभा के बाहर से ही अपने भीतर के साथियों की मदद करे, परन्तु काग्रेस ने अब तक इस दिशा में काम नहीं किया था। पुराने नरमदली लोगों को शासन सबधी अनुभव और ज्ञान था। काग्रेसी पिछले सत्रह साल से लड़ाई और आन्दोलन चला रहें थे। उनका कार्यक्रम सेवा और बलिदान का था। ऐसी दशा में वे काफ्रेन्स और कमीशनों की रिपोर्टों और सरकारी नियमावलियों से अनिभज्ञ थे।

धारासभा के बाहर के काग्रेसियों को जनता के मित्र की तरह काम करना था। उन्हें उन लाखों मूक प्राणियों की आवाज ही नहीं बनना था, बल्कि उन्हें सच और झूठ, जरूरी और बजरूरी को छाट कर रखना था। इस काम के लिए उन्हें पदाधिकारियों का बर्ताव देखना था, जिनकों जनता का दुश्मन न समझकर अब जनता में इस तरह घुला-मिला देना था कि दोनों तरफ एक दूसरे का भरोसा और यकीन हो। मौजूदा शासन में बहुत बुरी बात यह थी कि अधिकारियों और जनता में एक बहुत बडी दूरी थी। दफ्तरी नौकरियों में भी नौकरशाही घुस गई थी। जब तक खुद राष्ट्रीय चरित्र न उठता, ऊपर के नियत्रण और दबाव से यह दोष दूर नहीं हो सकता था।

प्रान्तीय और राष्ट्रीय मामलो में जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभाव में एक दुखद चीज यह थी कि लोग छोटे-छोटे आपसी झगडो और दलबदियों में पड़े हुए थे। मौके-मौके पर यह झगड़े खास तौर से उफन पडते थे। छोटी-छोटी बाते

रचनात्मक कार्यक्रम में वडी भारी मदद मिलती थी। जुलाहों के सरक्षण के लिए सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि हाथबुने कपडे के अलावा और सब तरह के कपडे बेचने वालों के लिए लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। कुछ हडतालों के सिलसिले में समझौता बोर्ड कायम किये गये।

उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए दो कमेटियाँ नियुक्त की गई। किसानों को बेदखल करने के जो मामले चल रहे थे उन्हें फीरन रॉक दिया गया ताकि किसानो को तात्कालिक सुविधा मिले। दूसरी कमेटी ने देहाती कर्ज के सवाल पर ध्यान दिया। कानपुर में मालिको के झगडे को मित्रमडल ने समय पर हस्तक्षेप करके दूर किया । मध्य प्रात में छोटे किसानो को स्थायी रूप से १२॥ फीसदी की छूट दी गई। कर्ज के सिलसिले में समझौता वोर्ड कायम किये गये। क्लबो पर लाइसेस लगाने, विदेशी शराव की दुकानो और देशी शराव के इस्तेमाल को घटाने का प्रस्ताव रखा गया। रचना विभाग के कामो में सार्वजनिक इमारतो की लागात को काफी घटा दिया गया। २४०० गाँवो की, जहाँ पढाई की सुविधाएँ नहीं थी, जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्या मदिर-योजना जोरों से चलाई गई। वगाल काँग्रेस-सचालित प्रान्त नही था। वहाँ नजरवन्द और राजवन्दी सब प्रान्तो से ज्यादा थे। वे सब गाधीजी के हाथो छुटकारे के इन्तजार मे थे। गाधीजी बहुत बुरा स्वास्थ्य होने पर भी कलकत्ते में २५ अक्टूबर १९३७ से १६ नवम्बर तक तीन सप्ताह ठहरे। बगाल के गवर्नर और मित्रमंडल से उन्होने लम्बी वातचीत की । बहुत से निकले हुए नजरबन्दो और राजबन्दियो से गाधीजी मिले । कलकत्ते से लौटते वक्त उन्होने हिजली कैम्प के १६ राजवन्दियों से दो घटे तक बातचीत की। इस समय सरकार ने लगभग ११०० नजरबन्दो की रिहाई की आजा दी।

इस प्रकार कुल मिला कर १९३७ का साल बहुत घटनापूर्ण रहा। काँग्रेस ने उस साल कोई अधिवेशन नहीं किया, लेकिन उसने उस समय में आधी सदी की प्रगति पूरी की। असल में जब मित्रमंडल बनायें गयें तब उसने राष्ट्रीय सगठन की मेहराब की चुनाई की। असहयोग का रास्ता बदला, लेकिन सहयोग का वक्त अभी नहीं आया था। सघ बनाने से ऐक्ट के जिस हिस्से का सबध था उसके विरोध में काँग्रेस के रुख में कोई फर्क नहीं हुआ। जब काँग्रेसी मित्रमंडल बने थे तब संघ बनाने के बारे में जिटिश सरकार ने अपना अगला कदम बताया था। काँग्रेस की निगाह में जिटिश सरकार की ऐसी कोशिश भारत की जनता के लिए चुनौती थीं और उसने प्रान्तीय और स्थानीय काँग्रेस कमेटियो, प्रान्तीय सरकारों और मित्रमंडलों से संघीय ढाँचा लादे जाने के विरोध में अपील की। विशेषकर प्रान्तीय सरकारों को यह हिदायत दी गई कि वे अपनी धारासभा के विरोध को, प्रस्ताव द्वारा प्रकट करे।

कांग्रेस महासमिति के निर्णय

सघीय विधान के बड़े सवाल के अलावा ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता में और बहुत-सी बातों के झगड़ों की वजह से न कोई सहयोग की भावना हुई और न कोई विशेष प्रगति हो सकी। उदाहरण के लिए हजारों नजरबन्द कैम्पो या जेलों में पड़े हुए थे और कुछ अण्डमान में थे। अण्डमान के बन्दियों ने गांधीजी को एक तार में यह सूचना भेजी कि हिसा में अब उनका विश्वास नहीं रहा है। ऐसी हालत में उन्हें नजरबन्द रखने का कोई मौका या बहाना नहीं था। ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और लोग भी थे जिनके खिलाफ हिसा के अभियोग थे। उनके अलावा निर्वासित लोग भी थे, जिनकी रिहाई के बारे में महासमिति ने एक प्रस्ताव पास किया।

पहले सालों में काँग्रेस ने सारे भारत की श्रम-सबंधी समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पद-ग्रहण किया तब इस महत्वपूर्ण विषय को छोड़ना सभव नहीं था। यह चीज राष्ट्रीय जीवन में एक विशेष महत्व की थी—विशेषकर बम्बई प्रान्त में। काँग्रेस ने जो मजदूर-कमेटी नियुक्त की थी उसने बड़े परिश्रम के बाद सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम पेश किया। इसको काँग्रेस महा-सिमित ने अक्टूबर १९३७ में एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया और अपनी यह राय प्रकट की कि अगर काँग्रेसी श्रम-मत्री समय-समय पर सम्मेलनों में भाग लेते रहें तो वह उन्हें एकसी नीति और एकसा कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता देगा।

काँग्रेस के लिए अल्पसंख्यकों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण था। उसने इस सम्बन्ध में अक्टूबर, १९३७ में होने वाली कलकत्ता-महासमिति में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि काग्रेस अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र देना चाहती है जिससे वे राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक और सास्कृतिक जीवन में पूरा-पूरा हिस्सा ले सके। काँग्रेस का उद्देश्य एक स्वतंत्र और अखण्ड भारत है जहाँ कोई वर्ग, समुदाय—बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक—एक दूसरे का शोषण न कर सके और जहाँ राष्ट्र के सारे हिस्से एक साथ मिलकर राष्ट्रीय उन्नति के लिए काम कर सके। अपने इस दृष्टिकोण के अनुसार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव में इन बातों को भी शामिल किया —

- (१) भारत के हर नागरिक को अपनी स्वतन्त्र सम्मति प्रकट करने का अधिकार है।
- (२) हर व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी मत, धर्म या सम्प्रदाय को मान सकता है, लेकिन उससे सार्वजनिक शांति और नैतिकता भग नहीं होनी चाहिये।

(३) अल्पसंख्यकों और विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि का सरक्षण किया जायगा।

(४) कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर है, फिर चाहे उनका कोई धर्म

हो या उनकी कोई जाति हो और वे चाहे स्त्री हो या पुरुष।

(५) किसी व्यक्ति पर उसके धर्म, लिंग और जाति के कारण सार्वजनिक नौकरियो आदि में कोई भेदभाव या पावन्दी नहीं होगी।

(६) किसी सार्वजनिक कुएँ, तालाव, सडक, स्कूल और दूसरे स्थान के लिए

हर नागरिक के समान अधिकार और कर्त्तव्य है।

(७) सब धर्मों के प्रति राजसत्ता तटस्य रहेगी।

(८) प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त होगा।

(९) हरएक नागरिक भारत में कही आने-जाने, ठहरने और वसने के लिए

आजाद है। वहाँ वह जायदाद ले सकता है।

अल्पसल्यको के सवाल के साथ 'राप्ट्रीय गान' का सवाल भी था। कुछ धारासभाओ में कार्रवाई 'वन्दे मातरम्' गान से शुरू हुई। इस गाने के साथ इकबाल के कुछ गाने भी प्रसिद्ध हुए। इनके अतिरिक्त महासमिति ने कुछ दूसरे मामलो पर भी ध्यान दिया। लगभग पच्चीस वरस से आध्र और कर्नाटक इस बुनियाद पर अलग प्रान्त बनाने पर जोर दे रहे थे कि नये प्रान्त भाषा के आधार पर बनाये जाय। कलकत्ते में महासमिति ने पहली बार "काँग्रेस-नीति" निश्चित की कि भाषा के आधार पर फिर से प्रान्त बनाए जायं। उसने बम्बई और मद्रास सरकार से आध्र और कर्नाटक के अलग प्रान्त बनाने पर विचार करने के लिए कहा। इस सिफारिश पर मद्रास की धारासभा ने विभिन्न भाषा क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रान्त बनाने का एक प्रस्ताव पास किया। मद्रास-सरकार और भारत मत्री में लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ। परिणामस्वरूप भारत-मत्री ने उस प्रस्ताव को उस समय रोक दिया। बम्बई ने भी कर्नाटक के सवाल पर उसी समय विचार किया।

घरेलू समस्याओं के बीच काँग्रेस अपने प्रवासी और रियासती भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूली। भारतीय रियासतों का मामला, भारत सरकार के विदेश-विभाग के अन्तर्गत था। १९३७ में जब मैसूर में जबर्दस्त दमन हुआ तब महासमिति ने उसका घोर विरोध किया। उस समय जो प्रवासी जजीबार में थे वे नये कानून के खिलाफ वीरता-पूर्वक लड रहे थे। उन कानूनों से भारतीय हितों को चोट पहुँचती थी और उस देश में बसे हुए भारतीयों का आयात-निर्यात व्यापार बरबाद होता था। वास्तव में जजीबार की समृद्धि में सब से बड़ी सहायता प्रवासी भारतीयों ने ही की थी। उस समय उनके सध्य में सहायता और भारतीय हितों के रक्षण के लिए भारत में लौग के आयात पर रोक लगाना जरूरी समझा

गया। इस पर भारतीय जनता से जजीबार की लौग न इस्तैमाल करने की अपील की गई। यह योजना जोश के साथ अपनाई गई। इससे जजीबार के भारतीयों को इच्छित सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली।

१९३७ में कॉग्रेस का सब से ज्यादा घ्यान आन्तरिक अनुशासन और स्वतंत्रता पर था। इस देश को दो चीजो से दबाकर रखा गया था। एक ओर तो राजभिक्त का पुरस्कार था और दूसरी ओर देशभिक्त के लिए सजा थी। अंगरेजो ने भारत पर नैतिक और वौद्धिक विजय पाने के लिए जो योजना निकाली थी उसमें सबसे पहला नम्बर खिताबो का था। जब उनकी सूची आती तो अखबारो की कई कालमें भर जाती थी। ऐसी सूचिया दो बार निकलती थी—एक तो अंगरेजी नये साल के शुरू में और एक बादशाह के जन्म-दिवस पर। इन खिताबो ने राष्ट्रीय अध पतन में बड़ी भारी सहायता की। नौकरियो और दूसरे इनामो से इनका असर कही ज्यादा था। इस पर महासमिति ने अपना सुचिन्तित मत यह प्रकट किया कि कॉग्रेसी मित्रमंडलो की धारा-सभा में खिताबो को बन्द करने का प्रस्ताव पास किया जाय। मित्रमंडलो को बादशाह को इस बात की सूचना दे देनी चाहिए कि वे आगे इस सिलिसले में सिकारिशे नहीं करेगे।

भारत जैसे बड़े देश में प्रान्तों के सरकारी काम में सामजस्य स्थापित करना और अनुशासन बनाये रखना कोई आसान काम नहीं था—विशेषकर उस समय जब राष्ट्र को शासन-सत्ता का पहली बार स्वाद मिला हो। धारासभाओं की पार्टियों की नेतागिरी में उन बहुत-सी बातों का समावेश था जो ऊपरी तौर से दिखाई नहीं देती थी। पहली बार काँग्रेस ने महसूस किया कि चार आने देकर काँग्रेस सदस्य बनने में एक वह अकुर था जो आगे जाकर प्रधान मन्त्री के रूप में एक सुदृढ वृक्ष हो सकता था। इसलिए जब व्यक्तिगत अधिकारों के झगड़े होते कि कौन नेता हो तो काँग्रेस कार्य-कारिणी ही एक ऐसी सत्ता थी, जो उन अधिकारों पर निर्णय कर सकती थी।

देश की स्थित

अगर कहा जाय कि पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय विचार-धारा में होने वाली हलचले देश में स्थान पाने वाली समाजवादी तथा वर्गवादी विचार-धाराओं के परिणास्वरूप थीं तो यह भी माना जा सकता है कि १९३८ में जो झगड़े उठ खड़े हुए थे, उनकी जड़े पिछले कुछ वर्षों से काँग्रेस के भीतर चलते रहने वाले आपसी विरोधों में मौजूद थी। सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अब भी गांधीजी का ही था। यद्यपि वह काँग्रेस के सदस्य न थे, तो भी शक्ति का सूत्र उन्हीं के हाथों में था। उन्हीं का शक्तिशाली व्यक्तित्व था जो युवा-वर्ग की हिसात्मक नीति पर रोक लगाए हुए था। परन्तु इतने पर भी देश की स्थित सतोयजनक नहीं थी। प्रान्तों में काँग्रेसी

मित्रमंडल स्थापित होने पर भी किसानों को मुक्ति नहीं मिली थी। लोग अचरज करते थे कि अभी जमीदार पहले के ही समान बने हुए है, पुलिस के जुल्म मे भी कोई कमी नहीं हुई है, और बगाल, बिहार तथ पजाब में हिंसात्मक अपराधों के वन्दी अभी तक यातनाएँ भुगत रहे हैं। अण्डमान के वन्दियों ने अनशन कर रखा था और वे दिन प्रति-दिन मृत्यु के निकट पहुँच रहे थे। स्वच्छदता-पूर्वक विचार प्रकट करने के कारण जो लोग जेलो में इतने दिनो से सड रहे थे उनकी सख्या अव भी एक हजार के लगभग थी। अण्डमान से कैदियो की वापसी तथा १,१०० बगाली नजरवन्दो की रिहाई के वाद हलचल में कुछ कमी हुई, परन्तु २० देशभक्तो ने पजाव मे अनशन करके और उसे ३० दिन तक जारी रखकर वातावरण मे सर गर्मी लादी थी और राष्ट्र के अन्त करण में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। असख्य किसान सैकडो मील चलकर गावो से आते थे और अपने सगठन अलग कायम करते थे। ये नये सगठन प्राय काँग्रेस के विरुद्ध होते थे। इसके लिए उन्हें एक उद्देश्य, एक झडा और एक नेता मिल गया था। किसानी की हिमायत कोई नई वात न थी, लेकिन अब तक ऐसा कॉग्रेस ही करती आई थी। इस वार उन्होने लाल रग का सोवियट झडा अपनाया, जिसमे हसिया और हथौडा के चिह्न अकित थे। किसानो और कम्यूनिस्टो मे यह झडा अधिकाधिक चल पडा और पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कहने-सुनने पर भी स्थिति में सुधार नही हुआ। झडे की ऊँचाई तथा प्रमुखता के प्रश्न की लेकर प्राय सभी जगह काँग्रेस तथा किसानो के बीच झगडे हुए। तिरगे झडे का स्थान किसानो के झडे को देने का जो प्रयत्न हो रहा था वह दर-असल समाजवाद का गाधीवाद से सघर्ष था। कुछ प्रान्तो में समाजवादियों ने कम्यूनिस्टो का साथ देना शुरू कर दिया था और कुछ मे वे राष्ट्रीयतावादियो में मिल गये थे। कई प्रान्तो मे प्रान्तीय चुनावो के बीच व्यक्तिगत सघर्षों का दौरदौरा रहा। इनमे कर्नाटक, विहार और उडीसा मुख्य थे।

हरिपुरा-काँग्रेस : १६३=

हिसा और अहिंसा के सघर्ष, जेलो में भूख-हडताल की पृष्ठभूमि और काँग्रेस मित्रमडलो के प्रति असतोष के इस वातावरण में काँग्रेस का इक्यावनवाँ अधिवेशन विट्ठलनगर, हिरपुरा में १९, २० और २१ फरवरी, १९३८ को श्री सुभापचद बोस की अध्यक्षता में हुआ। सुभाष बाबू ने अपनी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि इस वर्ष भारत की जनता में वह ऐसी अवरोध-शक्ति का विकास करने की चेष्टा करेंगे, जिसके फलस्वरूप बिटिश सरकार को राष्ट्र पर अवाछनीय योजना थोपने का विचार त्यागने के लिए विवश होना पड़ेगा। अपने इन प्रयत्नो के दौरान में भारत की जनता अतर्राष्ट्रीय घटनाओ पर दृष्टि रखेंगी और ऐसी नीति से काम

लेगी, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थित से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। अग्रेज राजनीतिज्ञों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस भ्रम में न रहना चाहिए कि काँग्रेस ने विरोध करते हुए भी जिस तरह प्रान्तों में मित्रमंडल कायम करना मजूर कर लिया उसी तरह वह भारतीय शासन कानून के सघ-योजना वाले अश को भी स्वीकार कर लेगी। काँग्रेस साम्प्रदायिक प्रश्न के निवटाने का प्रयत्न करते हुए राष्ट्र में एकता कायम करने पर जोर देगी। वह राष्ट्रीयता की रक्षा करते हुए मुसलमानों से समझौता करने के लिए कोई भी प्रयत्न वाकी न छोड़ेगी। उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि यदि अल्पसंख्यक समान नीति का अनुसरण करने को तैयार हो तो काँग्रेस उनकी सभी उचित माँगे मान लेगी।

जैसा कि पहले कहा गया है हरिपुरा-अधिवेशन का वातावरण ठीक नहीं था। अभी काँग्रेसी मित्रमङलो को कायम हुए सात महीने भी न हुए थे कि प्रान्तीय गवर्नरों से उनका मतभेद हो गया। हरिपुरा में डेलीगेटो के शिविरों में अफवाह फैली हुई थी कि हिंसात्मक कार्यों के लिए सजा पाये हुए राजनैतिक विदयों के छुटकार के प्रश्न को लेकर विहार और उत्तर प्रदेश के मित्रमंडल इस्तीफा दे चुके है। साथ ही रियासतो तथा किसानो की समस्याए भी कम दिलचस्प न थी। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सभी ओर रियासतो में पिछले दो वर्षों में जाग्रति की लहर फैल गई थी। इसके अलावा, किसान नये जोश में आकर ऐसे कार्य कर रहे थे, जो काँग्रेस के आधार-भूत सिद्धान्तों के खिलाफ थे और जिनकी जिम्मेदारी वह नहीं ले सकती थी। अल्पसंख्यकों की समस्या के सम्बन्ध में भी कुछ सनसनी फैली हुई थी। २८ दिसम्बर, १९३७ को मोहम्मदअली पार्क, कलकत्ता मे मुस्निम विद्यार्थी सघ के सम्मेलन में भाषण देते हुए श्री जिन्ना ने काँग्रेस की चूनाती देते हुए कहा था कि "काँग्रेस हाईकमाड का दिमाग ठीक करना पडेगा।" इसके अलावा नजरवन्दो एवं अनगनकारियों का मामला पड़ा हुआ था, जिसके निवटारे के लिए गांघीजी हरिपुरा-अधिवंशन के बाद बगाल जाने वाले थे। ऐसी विरोधी परिस्थि-तियों में भी हरिपुरा-अधिवेशन हुआ। सभापति के भाषण के परचात् स्दर्गीय पण्डित मोतीलाल जी की पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी के देहावसान पर गोक-प्रस्ताव पास हुआ और मिदनापुर जिले की ११० कांग्रेसी मंस्याओ पर लगे प्रतिबन्य का विरोध किया गणा। साथ ही बगारा सरकार के इस तर्क का कड़े राव्दो में प्रतिवाद निया गया कि वहाँ की काग्रेस समितियां बातकवादी सगठन की अग रही है।

कांग्रेस के प्राय सभी अधिवेशनों में प्रवासी भारतीयों का प्रश्न उठाया जाता था। हरिपुरा में भी दक्षिण-पूर्वी अफीका तथा मारीशम और फिजी के प्रवानी भारतीयों के पद, स्थित और अधिकार-सबंधी हास पर नेंद प्रकट किया गया। दक्षिण नार पूर्वी अफीका के मूलनिवानियों के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट फन्ते हुए गाँग्रेस ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की मान अफीका के मूलनिवानियों के प्रति शत्रुता की भावना से प्रेरित होकर नहीं की गई है, विल्क उसका उद्देश्य अफ्रीकावासियों और भारतीयों दोनों ही को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से वचाना है।

परन्तु हरिपुरा-अधिवेशन के समय ससार में विनाशकारी युद्ध के जो वादल छाये हुए ये उनकी तुलना में इन सबका अधिक महत्व न या। चीन, जापान, फिलस्तीन, यूरोप आदि सभी देश युद्ध का स्वप्न देख रहे थे। युद्ध तथा विदेशी सम्बन्धों के बारे में भारतीय राष्ट्र की नीति स्पष्ट थी और हरिपुरा-अधिवेशन में उसे और भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। ससार की इस उयल-पुथल तथा हलचलो के बीच काँग्रेस को हरिपुरा मे अपनी अन्दरूनी कठिनाइयो का सामना करना था। चूँकि काँग्रेस प्रातीय स्वायत्त शासन योजना को अमल मे ला रही थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि वह सघ-योजना को भी कार्यान्वित करेगी, क्योंकि सघ-योजना के दायरे से शासन के कुछ महत्वपूर्ण अगो को छोड दिया गया था। ऐसी परिस्थिति मे जनता की प्रकट की हुई इच्छा के विरुद्ध सघ-योजना लादे जाने के प्रयत्नो का सामना करने के अलावा कॉग्रेस के पास और कोई उपाय नही रह गया था। सघ-योजना से अल्पसल्यको के अधिकारो तथा रियासतो के प्रश्नो का भी सम्बन्ध था। पिछले वर्षो मे अल्पसल्यक समुदायो के अधिकाधिक सदस्य काँग्रेस मे सम्मिलित होकर स्वाधीनता के सग्राम तथा जनसाधारण के शोषण को समाप्त करने का समर्थन कर चुके थे। काँग्रेसी मित्रमडलो की स्थापना से काँग्रेस की सदस्यता मे वृद्धि हुई थी और एक विशेषता यह भी देखने मे आ रही थी कि इन नये सदस्यों में अल्पसंख्यक समुदायों का अनुपात बढता जा रहा था। इसके अतिरिक्त रियासतो का प्रश्न था। रियासती प्रजा अपनी कलकत्ते की सफलता से प्रोत्साहित होकर और आगे वढने की कोशिश करने लगी थी। वह चाहती थी कि कॉग्रेस उसका भी भार वहन करे या कम-से-कम उसके सगठन का ही दायित्व ग्रहण कर ले। हरिपूरा में प्रश्न यही उठा कि रियासतों में काँग्रेस समितियाँ स्थापित करने की अनुमति दी जाय या नही और भारत के सूबो मे कॉग्रेस के जिस विधान के अनुसार कार्य हो रहा था उसे रियासतो की प्रजा पर लागू होने दिया जाय या नही । अत मे एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसके अनुसार जहा एक ओर रियासती मे कॉग्रेस-समितियाँ स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्घ नहीं लगाया गया वहाँ दूसरी ओर यह तय हुआ कि रियासतो की कॉग्रेस-समितियाँ कार्यसमिति के निर्देशन तथा नियन्त्रण में रहकर कार्य करे। मामला यही खत्म नही हुआ। खुले अधिवेशन मे रियासती प्रजा सगठन से बाहर के कुछ लोगों ने इस समझौते से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। परन्तु रियासती प्रजापरिषद के प्रतिनिधियो ने कडाई से इस प्रयत्न को दबा दिया और उपर्युक्त समझौता स्वीकार कर लिया। इससे रियासतो मे दमन चक्र आरभ हो गया। फलस्वरूप जनता में हिसा की ज्वाला उमड पड़ी और

हत्याएँ हुईं। इसके बाद दूर-दूर तक आतक फैल गया और २०००० रियासती प्रजा अपना घरवार छोड कर ब्रिटिश भारत में चली आई। मैसूर की प्रगतिशील रियासत में विदुर अश्वधा की दुर्घटना हुई, जिसमें १० व्यक्ति गोली के शिकार बने और इससे दुगने व्यक्ति घायल हुए। इसके अलावा और भी कई गोलीकाड वहाँ हुए। राजकोट, राजपूताना, मध्यभारत तथा पजाब की रियासतो में सत्याग्रहियों को जेलों में ठूँस दिया गया। इन सभी मामलों में लोगों की आँखें गांधीजी की ही तरफ उठती थी।

प्राय. इतना ही हलचल उत्पन्न करने वाला किसान-आदोलन था। देश में विभिन्न पेशों तथा स्वार्थों के सगठन कायम होने पर काँग्रेस को कभी भी आपित न थी और फिर किसान तो देश की जनता के तीन-चौथाई भाग थे। भारत की स्वाधीनता के व्यापक प्रश्न को देखते हुए यह आवश्यक था कि वे बहुत भारी सख्या में काँग्रेस में सम्मिलित होते और उसके झड़े के नीचे एकत्र होकर, स्वाधीनता सग्राम में भाग लेते। इसके विपरीत, किसानों ने कितनी ही जगह लाल झंडा फहराने और कांग्रेस के प्रति विरोध का रुख धारण करने का निश्चय किया था और वह भी इसलिए नहीं कि उनका काँग्रेस के लक्ष्य से कुछ मतभेद था, बिल्क इसलिए कि काँग्रेस में रह कर उनके निजी स्वार्थों की सिद्धि में बहुत देर लग रही थी। इस जल्दबाजी के कारण किसानों ने, कुछ ऐसे कार्यों में सहयोग किया, जो स्पष्टत. कांग्रेस के आधारभूत सिद्धातों के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायक हुए। हरिपुरा-अधिवेशन ने प्रातीय कांग्रेस कमेटियों को इन तथ्यों को घ्यान में रखने और उपयुक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।

हरिपुरा-अधिवेशन की एक और भी सफलता उल्लेखनीय है। इसका सम्बन्ध कॉग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा के ऐसे सगठन से है जिससे कि भारत में हाल में ही फैली राष्ट्रीयता की आवश्कताएँ पूरी हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षा-वोर्ड की स्थापना की गई और उसे अपना विधान तैयार करने, धन इकट्ठा करने तथा अन्य आवश्यक कार्य करने के अधिकार दिये गये। हरिपुरा-अधिवेशन में एक अन्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसका महत्व युद्ध के वर्षों तथा युद्ध छिड़ने से पूर्व एक वर्ष तक युद्ध की अफवाहों के काल में प्रमाणित हुआ। यह प्रस्ताव 'विदेश नीति तथा युद्ध-सकट' के सबध में था और उसके द्वारा हरिपुरा में काग्रेस ने इस विषय में राष्ट्र की नीति का स्पष्टीकरण किया। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय राष्ट्र अपने पडोसियो तथा अन्य सभी देशों के प्रति मैत्री और शांति के वातावरण में रहना चाहता है। इसलिए भारत में युद्ध की जो तैयारियाँ की जा रही है उन्हें काग्रेस नापसंद करती

है। यदि भारत को युद्ध में फसाने का प्रयत्न किया गया तो इसका विरोध किया जायगा।

कार्य-सिमिति के निश्चय

१९२७ से ही काग्रेस युद्ध के सकट का अनुभव कर रही थी, १९२७ के मद्रासअधिवेशन और हिर्पुरा-अधिवेशन के मव्य के दशक में कितनी ही घटनाएँ हो
गई। काग्रेस यह नहीं समझती थी कि उसमें युद्ध को रोक सकने की सामर्थ्य
है—यह अमम्भव कार्य तो वड़े-से-बड़े लोग भी नहीं कर सकते थे। काग्रेस तो सिर्फ
ऐसे युद्ध के विरुद्ध लोकमत तैयार करना चाहती थी, जो सम्भवत भारत का अपना
युद्ध न हो या काग्रेस के विचार से जो भारत के हितों के विरुद्ध हो। ऐसी परिस्थित में एक विदेश-विपय-समिति नियुक्त की गई, जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय
परिस्थित के सपर्क में रहना, काग्रेस कार्यसमिति को परामर्श देना और हिन्दुस्तान
से बाहर के लोगों को काग्रेस के दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के
सबध में हिरपुरा में पास प्रस्ताव से अवगत कराना था।

प्रातीय स्वायत्तशासन स्थापित होते ही प्रत्येक प्रात के लिए अपने यहा के योग्य व्यक्तियों को अन्य प्रान्तों के अधिक योग्य व्यक्तियों की तुलना में तरजीह देना स्वाभाविक ही था; परन्तु कुछ पेचीदिगियाँ भी थी। १९०५ से पूर्व बगाल, बिहार और उडीसा का एक ही प्रात था। बगाली लोग अधिक शिक्षित होने के कारण प्रात के तीनों भागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हुए, किंतु बाद में ये तीनों भाग तीन पृथक प्रात बन गये। अब प्रश्न यह उठा कि बिहार में बहुत दिनों से बसे हुए बगालियों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाय। इस समस्या ने १९३७-३८ के वर्ष में विशेष महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया। विवाद में बिहार हाईकोर्ट के एक अवकाशप्राप्त जज ने भी भाग लिया। इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार हुआ और कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि (१) प्रात में बसने, (२) नौकरी करने तथा (३)शिक्षा,(४)व्यापार और (५) व्यवसाय के पहलुओ पर विचार करते हुए श्री राजेन्द्रप्रसाद अपनी रिपोर्ट उपस्थित करे। राजेन्द्र बाबू की रिपोर्ट मिलने पर कार्यसमिति ने बारदोली में ११ जनवरी, १९३९ को अपना जो निर्णय दिया उसके अनुसार प्रातीय व्यक्तियों को विशेष महत्व दिया गया।

एक ऐसा ही विषय प्रान्तों में रियासती प्रजा पर लगे प्रतिबन्धों तथा अयोग्यताओं का था। अखिल भारतीय मारवाडी सघ ने इस सम्बन्ध में काग्रेस से अनुरोध किया और तब कार्य-सिमिति ने अपना मत प्रकट किया कि प्रान्तों में रियासती प्रजा को सरकारी, नौकरियों तथा मताधिकार के विषय में जिन प्रतिबन्धों तथा अयोग्यताओं का सामना करना पडता हो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाय।

यद्यपि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र के विस्तार और उसकी सीमाओ की

समय-समय पर व्याख्या होती रही, तथापि वास्तविक जासन के समय ऐसी समस्याएँ उठने लगी, जिनकी कल्पना काग्रेस और सरकार में से किसी ने भी नहीं की थी। ऐसी ही एक अप्रत्याशित समस्या उस समय उठ खडी हुई जब उडीसा का स्थायी गवर्नर सर जान ह्यू वेक छुट्टी पर जाने वाला था। स्थानापन्न गवर्नरी सिविल सिवस के एक सदस्य मि॰ डान को दी गई, जो मित्रयों की अधीनता में काम कर चुका था। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अवाछनीय तथा अन्य देशों में प्रचिलत परम्परा के विरुद्ध थी। इस परिस्थिति में उडीसा के मित्रयों ने इस नियुक्ति का विरोध किया और काग्रेस कार्य-सिमिति ने इस नियुक्ति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया। अन्त में यह राजनैतिक सकट सर जान ह्यू वेक द्वारा अपनी छुट्टी रद्द करा लेने से टल गया।

उत्तरदायी शासन का मतलब यही होता है कि व्यवस्थापिका सभा को मित्र-मडल मे रद्दोवदल करने का अधिकार रहे। यह अवसर सबसे पहले भारत के नये प्रान्त सिन्ध में मार्च, १९३८ में आया, परन्तु सिन्ध में किसी भी दल को वैसा बहुमत नही प्राप्त था, जैसा काग्रेस को छ प्रान्तो मे। इसलिए वहा किसी मित्रमडल को हटाना तो सहल था, किन्तु उसकी जगह नया मित्रमडल वनाना उतना सरल न था। यह समस्या वहाँ उस समय उठी जब वहाँ मन्त्रिमण्डल की पराजय हुई। ऐसी स्थिति में मन्त्रिमण्डल बनना काग्रेस-दल के समर्थन अथवा विरोध पर निर्भर हो गया। इस अवसर पर गवर्नर ने काग्रेस-दल के नेता को इस बात का पता लगाने के लिए बुलाया कि प्रान्त के राजनैतिक सकट के प्रति काग्रेस का क्या रुख है। यह वडी अप्रत्याशित वात थी; क्यों कि घारासभा के ६० सदस्यों में से काग्रेस की शक्ति केवल ८ थी। परन्तु धारासभा में ऐसा कोई भी दल न था, जिसे अकेले वहुमत प्राप्त हो सकता। कार्येस के ८ सदस्य किसी भी दल के साथ मिलकर मित्रमडल नहीं कायम कर सकते थे। उन्होंने नये संयुक्त-मन्त्रिमण्डल का समर्थन करना ही निश्चय किया। नये सम्मिलित दल के नेता सानवहादूर अल्लाहवस्या ने काग्रेस दल के नेता को पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि यदि मैने मित्रमण्डल बनाया तो मेरी नीति काग्रेस के सिद्धान्तो पर आधा-रित होगी। इस परिस्थिति में कांग्रेस दल ने उत्तर दिया कि नये मन्त्रिमण्डल के कानूना तथा शानन-सम्बन्धी कार्यों का विरोध करने की अपनी स्वतंत्रता मुरिसत रखते हुए कुछ अवधि तक वह ऐसा कोई कदम न उठाएगा और न किसी दूसरे दर के ऐसे किसी कार्य का ही समर्थन करेगा, जिसने नये मन्त्रिमण्डल के अपदस्य होने की सम्भावना हो। इसके उपरान्त वह अन्तिम रूप ने अपनी नीति रियर करेगा। इस प्रकार संयुक्त-मन्त्रिमण्डल का रास्ता साफ हो गया। आसाम में भी वहुत कुछ इसी प्रकार की घटनाएँ हुई। परिणाम यह हुआ कि एक समय ११ प्रान्तों में से ८ में काग्रेसी या मिलीजुरू मित्रमंटल नाम करने लगे।

काग्रेस मन्त्रिमण्डलो द्वारा ६ प्रान्तों के शासन में कितनी ही घटनाओं के कारण और कभी-कभी मन्त्रियों की निजी कमजोरियों के कारण विपम समस्याए उठ खडी होती थी। ऐसी ही एक खेदजनक घटना मध्यप्रान्त के मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में उठ खड़ी हुई। वहा न्यायमन्त्री-द्वारा दया के अधिकार का प्रयोग एक ऐसे उच्च स्थिति वाले राजनैतिक वदी के लिए किया गया, जिसे वलात्कार के मामले में सजा की आज्ञा सुनाई जा चुकी थी। सम्वन्यित मन्त्री ने खेद प्रकट किया और इस्तीफा देने को कहा। मध्यप्रान्त का काग्रेस पार्लामेटरी दल तथा दूसरे मत्री इस मत्री के खेद प्रकट करने पर सन्तुष्ट हो गये और उन्होने यह कारणे भी मान लिया कि मामले की गम्भीरता का अनुभव न करने के कारण ही उसने अपने दूसरे साथियो से सलाह नही ली थी, परन्तु कार्य-समिति अधिक ऊँचे दृष्टि-कोण से इस विषय पर विचार करना चाहती थी। इसलिए उसन जनता से अनु-रोध किया कि एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता-द्वारा मामले की जाच-पडताल किये जाने के बाद उसके अन्तिम निर्णय की उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए। फलत मामला कल-कत्ता हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज सर मन्मथनाथ मुकर्जी के सुपुर्द किया गया और उनकी रिपोर्ट जब सम्बन्धित मत्री के आगे उपस्थित की गई तब उन्होंने तुरत इस्तीफा दे दिया। इस तरह एक ओर काग्रेस की नेकनामी पर घटना न लगा और दूसरी तरफ वह व्यक्ति भी जनता की नजर में ऊँचा उठ गया।

दक्षिण भारत मे एक काग्रेसजन पर राजद्रोह के लिए १२४-अ धारा के अनुसार मुकदमा चलाये जाने पर नौजवान और विशेषकर समाजवादी बड़े क्षुट्य थे। कार्यसमिति को १९३८ के आरम्भ मे ही इस सम्बन्ध मे एक प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना समाजवादियों ने अक्टूबर १९३७ में अखिलभारतीय काग्रेस कमेटी की एक बैठक में दी थी। इससे कार्यसमिति को विभिन्न प्रान्तों में पैदा होने वाली परिस्थितियों और साथ की किठनाइयों पर विचार करने का अवसर मिल गया। कार्यसमिति ने जहा एक तरफ काग्रेस-मित्रमंडलों के कार्यों की पुष्टि की, वहा दूसरी तरफ उसने नागरिक स्वतत्रता का क्षेत्र बढ़ा दिया तथा काग्रेस के कार्यक्रम को अमल में लाने के प्रयत्नों का स्वागत किया, परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात कार्यसमिति के बब्दों में "काग्रेस की अहिसा की नीति के अनुसार आचरण करना और हिसा की प्रेरक प्रवृत्तियों तथा काग्रेस-जनों से देश में शान्तिपूर्ण तथा अनुसार कार्यसमिति ने काग्रेस-कमेटियों तथा काग्रेस-जनों से देश में शान्तिपूर्ण तथा अनुसार कार्यसमिति ने कार्यस-कमेटियों तथा काग्रेस-जनों से देश में शान्तिपूर्ण तथा अनुसार कार्यसमिति ने कार्यस-कमेटियों तथा कार्यस-जनों से देश में शान्तिपूर्ण तथा अनुसासनयुक्त कार्य का वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने की अपील की और साथ ही गलत रास्ते पर चलने वाले उन काग्रेस-जनों को चेतावनी दी, जिनमें काग्रेस की अहिसात्मक नीत के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी।

प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

ऐसी स्थिति में परस्पर सहयोग की विशेष आवश्यकता थी। इस आव-श्यकता की पूर्ति के लिए प्रधान मित्रयों का एक सम्मेलन मई १९३८ में हुआ। सातो प्रधानमन्त्रियों तथा उनके कुछ साथियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन मे साधारण कृषि-नीति, श्रमिक तथा औद्योगिक पुर्नीनर्माण, शक्ति के साधनो का विकास, ग्रामसुधार, शिक्षा, राजस्व सम्बन्धी साधन, कर-व्यवस्था तथा अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध मे विचार हुआ। उत्तर प्रदेश ने रचनात्मक कार्य के लिए राजस्व के नये साधनो के सम्बन्ध में और वम्बई ने जेल-सुधार के सम्वन्ध में सम्मेलन ब्लाने की जिम्मेदारी ग्रहण की। प्रत्येक प्रात ने किसी-न-किसी विषय की विशेष छानवीन करने का भार लिया। मद्रास ने मादक वस्तु निषेध, मन्दिर-प्रवेश तथा ऋण-सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में, वम्बई ने मजदूरो की समस्या के विषय में, उत्तर प्रदेश तथा विहार ने भूमि-कर तथा कृषि-समस्याओं के बारे मे, आसाम ने खनिज साधनों के विषय में, उडीसा ने कलापूर्ण दस्तका-रियो के विषय में और मध्यप्रात ने औद्योगिक तथा खनिज साधनों के अध्ययन का दायित्व ग्रहण किया। ये तो सिर्फ सुझाव थे। मद्रास ने जिमीदारी समस्या, वम्बई ने मादक वस्तु निषेध और उत्तर प्रदेश ने जेल सुधार के विषय हाथ में लिये। इस प्रकार प्रधानमित्रयों के इस सम्मेलन से औद्योगिक योजना-निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका कुछ समय वाद श्रीगणेश भी हुआ।

केन्द्रीय सरकार की स्थिति

इस प्रकार जविक प्रातीय सरकारे अपने नये क्षेत्र में अप्रत्याशित विपयों द्वारा जत्पन्न होने वाले विरोध का सामना कर रही थी, काग्रेस के पुराने महारथी केन्द्रीय सरकार से संघर्ष कर रहे थे। केन्द्रीय सरकार भी अभी तक चंद व्यक्तियों का गासन था और वह पहले के ही समान निरकुंग थी। इसलिए उस पर जनता के मत और उसकी अपील का कोई प्रभाव नहीं पडता था। केन्द्रीय असेम्बली का वजट-अविवेशन भारतीय सेना की ब्रिटिश शाखा के यंत्रीकरण के विरुद्ध काग्रेस-दल के एक निन्दात्मक प्रस्ताव से आरम्भ हुआ। पाच ब्रिटिश रेजिमेटों का २ करोड १५ लाख रु० की लागत से यत्रीकरण होने को था और इस रकम में से ब्रिटिश सरकार सिर्फ अस्ती लाख रु० दे रही थी और शेप रकम भारत के मत्ये मढने जा रही थी। यह नीति अनुचित थी, क्योंकि भारतीय धन से भारतीय नेना के अंग्रेज दस्तों का यत्रीकरण किया जा रहा था और यत्रीकरण के इस कार्य-प्रम से भारतीय रेजिमेटों को अलग रखा गया था।

२८ फरवरी को अयं-सदस्य सर जेम्स ग्रिन ने केन्द्रीय वजट उपस्थित किया।

इसके उपरात वजट पर आम वहस आरम्भ हुई। आम वहस आरम्भ होने के समय विरोधी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने एक वक्तव्य दिया कि काग्रेस दल, स्वतन्त्र काग्रेस राप्ट्रीयतावादी दल और डेमोक्टेट दल ने वजट की आम वहस में भाग न लेने का निश्चय किया है। इसलिए सर जेम्स द्वारा कस्टम्स सम्बन्धी माग पेश करते ही विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश करने के स्थान पर मत लेने की माग उपस्थित कर दी गई। माग ४६ के विरुद्ध ६४ मतों से नामजूर करदी गई। अर्थ-सदस्य द्वारा पेश की गई अन्य मागो का भी यही हाल हुआ। बाद में इन नामजूर मागो को गवर्नर-जनरल ने अपने विशेपाधिकार द्वारा मजूर कर दिया। असेम्बली ने इसका जवाब सम्पूर्ण अर्थ-विल को नामजूर करके दिया। सभा ने सिफारिशी अर्थ विल को भी ४८ के विरुद्ध ६८ मतो-द्वारा अस्वीकार कर दिया। वजट पर आम बहस आरम्भ होते ही परिषद से काग्रेस तथा प्रोग्रेसिव दल के सदस्य उठ कर वाहर चले गये।

मजदूर-कमेटी की वैठक

यद्यपि प्रान्तीय सरकारो को मजदूरो की समुचित व्यवस्था करने के लिए काफी अधिकार प्राप्त थें, फिर भी सभी प्रान्तों में एक-जैसी नीति का अनुसरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रान्तो की नीतियो का एकीकरण कर सकती थी। बम्बई सरकार ने अपने यहा मजदूरो-सम्बन्धी कानून का मसविदा वनाया था। मई १९३८ में काग्रेस की मजदूर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कुछ प्रान्तो के प्रधानमन्त्रियो ने तथा अन्य प्रान्तो के प्रधानमन्त्रियो के प्रतिनिधियो न भाग लिया। बैठक में अनुरोध किया गया कि मजदूरों की अवस्था तथा मज-दूर-सभाओं के झगडों की जाँच-पडताल के लिए जो कमेटिया नियुक्त की जाय उनमे सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियो को ही रखा जाय। यह वडी खुशी की बात थी कि वम्बई कपडा-उद्योग-जाच कमेटी की सिफारिशे बम्बई की सरकार ने स्वीकार कर ली और वम्बई प्रान्त के मिल-मालिको ने उन्हें अमल मे लाना मजूर कर लिया । बम्बई मे कानून बनने का कार्य जारी था, जिसमें इस बात का भी प्रवन्ध था कि बीमारी के दिनों में वेतन के साथ छुट्टी दी जाय । बडोदा सरकार ने १ अगस्त १९३८ से रियासत मे ९ घटे का दिन घोषित करके दूसरी रियासतो का पथ-प्रदर्शन किया। बम्बई सरकार ने अपने कारखाना-कानून को उन कारखानो पर लागू करने का निश्चय किया जिनमे १० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे।

उद्योग-मंत्रियों का सम्मेलन

अगस्त १९३७ में ही जबिक काग्रेस को प्रातो में मित्रमंडल स्थापित किये

महीना-भर भी नहीं हुआ था, कार्यसमिति अखिल-भारतीय औद्योगिक योजना के निर्माण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का विचार कर चुकी थी। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जुलाई १९३८ में काग्रस के अध्यक्ष को उद्योग-मित्रयों का एक सम्मेलन बुलाने तथा विभिन्न प्रातो के मौजूदा उद्योगो तथा नये उद्योगो की आवश्यकता के सबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह सम्मेलन दिल्ली मे २ और ३ अक्टूबर १९३८ को हुआ। इसका उद्देश्य कुछ ऐसी समस्याओ पर विचार करना था, जिनका हल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा सामाजिक आयोजन की किसी योजना के लिए आवश्यक था। इन समस्याओं के हल के लिए यह जरूरी था कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करे और विस्तृत जाच-पडतालो के बाद आवश्यक सामग्री का सकलन करे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सुभाष बावू ने स्वाधीन भारत मे राष्ट्रीय पुर्नानर्माण की समस्याओ पर प्रकाश डाला और बतलाया कि कृषि की उन्नति वैज्ञानिक ढग पर कितनी ही क्यो न की जाय, निर्घनता और बेकारी को दूर करने तथा उत्तम वस्त्र, उत्तम मकान, उत्तम शिक्षा और अधिक फुरसत पाने का एकमात्र उपाय औद्योगीकरण ही हो सकता है। यह हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह ऋमिक न होकर रूस की तरह तुरत और बल-पूर्वक होना चाहिए। उन्होने कहा कि घरेलू उद्योग और बड़े उद्योगों में कोई विरोध नहीं है, केवल राष्ट्र को एक ओर यह फैसला कर लेना चाहिए कि औद्यो-गिक कान्ति आवश्यक है और दूसरी तरफ यह कि किस उद्योग का विकास घरेलू आधार पर किया जाय और किसका बड़े आधार पर । इसके बाद उन्होने राष्ट्रीय-योजना निर्माण के कुछ सिद्धान्त बनाये और औद्योगीकरण की समस्याओ के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना की । योजना-समिति में जिन लोगों को रखा गया उनके नामों की घोषणा की गई। समिति के अब्यक्ष पडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किये गये । इसके अन्तर्गत २७ उप-समितियाँ थी और इसने १९३८-३९ से नवम्बर १९४० तक काम किया।

रियासतों की समस्याएँ

अखिल भारतीय क्षेत्र में काग्रेस की दिलचस्पी जिन समस्याओं में थी उनमें रियासतों की समस्या ने सबसे अधिक महत्व धारण कर लिया था। प्रान्तों में स्वायत्त शासन की प्रगति होने से रियासतों में केवल जाग्रति ही नहीं हुई, विल्क ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो गई, जिन पर गाधीजी और कार्यसमिति को विचार करना पडा। दक्षिण में ट्रावनकोर और मैसूर का तत्कालीन इतिहास में मुख्य स्थान रहा। ट्रावनकोर-काग्रेस के उद्देश्य के प्रश्न के बारे में रियासती सरकार और राज्य की काग्रेस के वीच उग्र विवाद चल रहा था। हैदरावाद राज्य ने जरूरत से कही ज्यादा विशेपाधिकार-कानून जारी कर दिए थे। लेकिन जिस

रियासत ने जनता का घ्यान सबसे अधिक आकृष्ट किया था और जो उसकी नजर में सबसे अधिक गिरी वह थी मैसूर। वहाँ 'स्वाधीनता दिवस' के सम्बन्ध में मौखिक चेतावनियो और विनाशात्मक कार्यों के लिए व्यक्तियो से जमानते मागी जा रही थी और उन पर प्रतिवध लगाये जा रहे थे। १९३८ में विदूर-स्वायम् के गोलीकाड से यह नीति अपनी चरम सीमा को पहुँच गई। इसी वीच एक जांच समिति की नियुक्ति हुई। समिति ने निर्णय दिया कि गोली भीड की हिसा से बचने के लिए आत्म-रक्षा के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसी समय गाघीजी ने कार्यसमिति के दो सदस्यो, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य कृपलानी, को भेजा। वे मैसूर काग्रेस के नेताओ तथा दीवान सर मिरजा इस्माइल से मिले। इस वार्ता के परिणामस्वरूप एक समझौते का मार्ग निकाला गया। १७ मई के समझौते में वे सभी मागे स्वीकार कर ली गईं, जिन्हे राज्य-काग्रेस ने अपने शिवपुर वाले अधिवेशन में उपस्थित किया था यह समझौता जेल के कैदियो तथा राज्य के अधिकारियों में हुई वार्ता के कारण हुआ था। सरदार पटेल और आचार्य कृप-लानी ने राज्य और मैसूर काग्रेस के बीच जो यह समझौता कराया था उसे कार्य समिति ने भी स्वीकार कर लिया। मैसूर-सरकार ने इस सम्बन्ध मे एक विज्ञाप्ति प्रकाशित की और जून १९३८ में कार्यसमिति ने महाराज और उन सलाहकारो को समझौते की शतें उत्साह से पूरी करने के लिए वधाई भी दी।

श्रन्तर्राष्ट्रीय सेवापॅ

यद्यपि भारत एक पराधीन देश था, फिर भी काग्रेस उसकी विशेष अंतर-राष्ट्रीय स्थित पर घ्यान रखती थी। पिछले चार वर्ष से चीन भीतरी अशाित तथा बाहरी आक्रमण की आशका से गुजर रहा था। इसलिए चीन की राष्ट्रीय सरकार के लिए एक मोटर, एम्बूलेन्स-दल, आवश्यक डाक्टर तथा नर्स आदि के सिहत भेजने का निश्चय किया गया। भारतीय डाक्टरों का एक दल डा॰ अटल की देखरेख में तैयार किया गया। दो वर्ष तक परिश्रम और लगन से काम करने के बाद डा॰ अटल अपने साथियों के हाथ में काम छोडकर भारत लीट आये। उनके कार्य की सभी जगह प्रशसा हुई। दल के एक सदस्य डा॰ कोटनीस का स्वर्गवास भी हुआ। जजीबार की परिस्थित में भी सुधार हुआ। भारत में जजीबार की लीग का जो बहिष्कार जून १९३८ के मध्य तक किया था उसका प्रभाव पड़ा और जजीबार सरकार तथा प्रवासी भारतवासियों में समझौता हो गया। १९३८ के पतझड में युद्ध के बादल घरने लगे। ब्रिटेन और जर्मनी में उन दिनों जो कुछ हो रहा था। उसकी सूचना कार्यसमिति को प्रति सप्ताह पिडत जवाहरलाल नेहरू से मिल रही थी। नेहरूजी २ जून को भारत से यूरोप के लिए रवाना हुए थे और मसावा में भारतीय व्यापारियों तथा सिकंदरिया में

नहसपाशा तथा दूसरे वफद-नेताओं से मिलने के बाद सीधे बार्सीलोना (स्पेन) चले गये थे। उन दिनों आकाश से जो निर्दयतापूर्ण बम-वर्षा हो रही थी, उसे उन्होंने अपनी ऑखो से देखा था। इसके उपरान्त वह पेरिस गये और वहाँ उन्होंने रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वाधीनता के आदोलन के आदर्शो पर प्रकाश डाला और फासीसियो से सहानुभूति की माग की। इंगलैंड में भी उनका कार्यक्रम विविध प्रकार का था। पेरिस में जुलाई १९३८ को खुले नगरों में बम-बारी के विरुद्ध हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पिडत नेहरू ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। सितम्बर १९३८ में कार्यसिमिति की बैठक दिल्ली में हुई और उसमें युद्ध-संबन्धी परिस्थित पर विचार हुआ।

मुसलिम लीग का रुख

पिछले कुछ समय से साम्प्रदायिक मनमुटाव बढ रहा था, जिसकी चर्चा भी कभी-कभी सुनने में आती थी। १९३८ में जवाहरलाल और जिल्ला के बीच पत्र-व्यवहार हुआ। यह पत्र-व्यवहार बहुत ही उग्र रहा और उसका परिणाम भी कुछ न निकला। एक असाधारण तथा दुखद घटना यह हुई कि राष्ट्रपति की हिसियत से जब सुभाष बाबू चटगाव डिवीजन गये तब मुसलिम लीगियों की एक भीड ने शिष्टाचार और इसानियत को ताक पर रखकर उनके जुलूस पर पत्थर फेके। सौभाग्यवश राष्ट्रपति तथा जुलूस के १४ आदिमयों को साधारण चोटे लगी। श्री जिल्ला ने तो जो स्थिति ग्रहण की थी उससे एक इच भी हटना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। काग्रेस की कार्य-सिमिति ने अपनी दिसम्बर वाली बैठक में श्री जिल्ला के ९ अक्टूबर १९३८ वाले पत्र के सम्बन्ध में निश्चय किया कि उससे साम्प्रदायिक समस्या के निवटारे में कुछ भी मदद नहीं मिल सकती। इसलिए राष्ट्रपति ने १६ दिसम्बर १९३८ के दिन श्री जिल्ला को सूचित कर दिया कि कार्य-सिमिति मुसलिम लीग-कौसिल से वार्त्ता के आधार पर सहमत नहीं हो सकती। इसलिए इस दिशा में और कुछ नहीं किया जा सका।

राजकोट की समस्या

सन् १९३९ का आरभ होते ही देश के सामने दो वडी-वड़ी समस्याएँ आई एक तो र जकोट की समस्या और दूसरी सभापित का चुनाव। काठियाबाढ की ३६० रियासतो में से राजकोट कोई वडी रियासत नहीं थी, परन्तु वह एक प्रकार से पिर्चिमी भारत की रियासतो की राजवानी थी, क्योंकि एजेट-जनरल वहीं रहता था। राजकोट का सम्बन्ध गांधीजी के प्रारम्भिक जीवन से भी था। गांधीजी के पिता इसी रियासत के दीवान रह चुके थे। राजकोट के तत्कालीन ठाकुर साहब की सगाई होने के अवसर पर श्रीमती कस्तूरबा गाघी ही ने उनके माथे पर कुकुम का अभिषेक किया था। इस पृष्टभूमि को देखते हुए यह विधाता का कूर उपहास था कि राजकोट-नरेश को तूफान का केंद्र वन कर ससार के सबसे महान पुरुष से टक्कर छेनी पड़ी। १९३८ में रियासतो प्रजा का सगठन कुछ प्रमुख रियासतो में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहा था। दूसरी रियासतो की तरह राजकोट में भी इस प्रयत्न के दमन की चेप्टा की गई। सत्याग्रह का जोरदार आन्दोलन छिड़ा और इसका उतने ही जोर से दीवान वीरवाला-द्वारा दमन किया गया।

रियासत के अधिकारियो ने राजकोट प्रजापरिषद को गैरकान्नी घोषित कर दिया। इस आदेश के निकाले जाने पर कार्य-समिति का घ्यान इस आन्दोलन की ओर आकृष्ट हुआ। सिमिति ने जहा एक ओर उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिये किये जानेवाले इस आन्दोलन का स्वागत किया वहा दूसरी ओर उसने रियासत के वाहर के लोगो को आन्दोलन मे भाग न लेने का परामर्श दिया। ऐसी स्थिति मे राजकोट के ठाकुर साहव ने सरदार वल्लभभाई पटेल को वम्वई से मुलाकात के लिए बुलाया । २६ दिसम्बर को सरदार पटेल और ठाकुर साहव के वीच समझौते की घोषणा हुई, जिससे राजकोट की प्रजा का सघर्ष समाप्त हो गया। यह सिर्फ राजकोट की जनता की ही नही, वल्कि साधारण रूप से रियासती प्रजा की विजय थी। ठाकुर साहव तथा सरदार पटेल मे ८ घटे के विवाद के वाद जो समझौता हुआ उसके अनुसार ठाकुर साहव ने यह वचन दिया कि हमने दस ऐसे व्यक्तियों की एक सिमिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, जिसमे तीन रियासत के अफसर और सात प्रजा-जन होगे। जनवरी, १९३९ के अत तक यह समिति उचित जाच-पडताल के वाद शासन सुधार की एक ऐसी योजना तैयार करेगी, जिसमे प्रजा को अधिक-से-अधिक व्यापक अधिकार दिये जायगे, किन्तू इन अधिकारों का सर्वोच्च सत्ता के प्रति हमारे उत्तरदायित्व पर या नरेश के रूप में हमारे विशेष अधिकार पर कोई प्रभाव न पडेगा। हमारी यह भी इच्छा है कि अब से हमारे निजी खर्च की रकम नरेन्द्र-मडल की गश्ती विजिप्त के अनुसार निर्घारित की जाया करे। हम अपनी प्रजा को यह भी आख्वासन देना चाहते हैं कि उपर्युक्त समिति जो भी योजना उपस्थित करेगी, उसे विचार करके कार्यान्वित करने का हमने इरादा कर लिया है। यह मान लिया गया है कि शान्ति तथा सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रकार का अवैध आन्दोलन वद कर दिया जायगा और हम आम माफी करके सव राजनैतिक कैदियों को रिहा कर देगे, सब जुरमाने वापस कर देगे और दमनकारी कानूनों को वापस ले लेगे।

समझौता २६ दिसम्बर १९३८ को हुआ था। उसकी शर्तो के अनुसार जब सरदार ने सात नाम भेजे तब रेजिडेट और सपरिषद ठाकुर साहव में सलाह- मशिवरा हुआ। रेजिडेट ने सरदार तथा काग्रेस के विरुद्ध कुछ बाते कही। सर-दार की सूची पर इस मामूली बात को लेकर आपत्ति उठाई गई कि ठाकुर साहब को सूची मिलने से पहले ही नाम प्रकट कर दिये गये। इसके अतिरिक्त यह आपत्ति भी उठाई गई कि ठाकुर साहब अपनी प्रजा के महत्त्वपूर्ण वर्गो, जैसे भय्यत, मुसलिम परिषद तथा दलित जातियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर साहब ने सात नामों में से केवल चार ही मजूर किये और शेष तीन नामों को नामजूर कर दिया। सरदार ने जिन नामों की सिफारिश की थी वे ठाकुर साहब को मान्य न थे। इस प्रकार समझौता भग हो गया। इस विश्वासघात का सामना करने के लिए महात्माजी ने अनशन किया। अनशन अनिश्चित काल के लिए था। वाइस-राय के हस्तक्षेप पर सर मारिस ग्वायर को निर्णय के लिए नियुक्त किया गया। निर्णय गांधीजी के पक्ष में था, कितु गांघीजी ने अपने अनशन में कुछ दबाव का अनुभव किया और फिर उन्होंने निर्णय का लाभ न उठाने का निश्चय किया। यह अनशन त्रिपुरी-अधिवेशन के दिनों में हुआ और इसी बीच समाप्त हो गया।

सभापति का चुनाव

साधारणतया राष्ट्रपति के चुनाव में कोई हलचल नहीं होती थी। अक्टूबर १९३४ मे बम्बई वाले अधिवेशन में नया विधान स्वीकार किये जाने से पूर्व प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियाँ नये वर्ष के लिए राष्ट्रपति के नामों के प्रस्ताव करती थी और फिर वही इनमें से एक का चुनाव कर लेती थी। परन्तु त्रिपुरी अधिवेशन के लिए सभापतित्व के सवाल को लेकर वास्तविक विवाद उठ खडा हुआ। सुभाप बाबू काग्रेस के चुप रहने वाले अध्यक्षों में से थे। उनकी तदुरुस्ती लगातार खराब रही थी और शरीर थक चुका था। फिर भी उनके मस्तिष्क मे थकान न थी और शक्ति भी अक्षुण्ण बनी हुई थी। ऐसी स्थिति मे सितम्बर १९३८ के अन्त मे नजाहिर हुआ कि सुभाष बाबू त्रिपुरी मे भी अध्यक्ष रहना चाहते हैं। राष्ट्र की माग और अभी तक ब्रिटेन द्वारा उसकी पूर्ति न होने के कारण आवश्यक यह था कि राष्ट्रपति का पद किसी मुसलमान को दिया जाय। देश को मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूप में ऐसा मुंसलमान मिल भी सकता था। वह एक बार १९२३ में काग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थें, किन्तु वह विशेष अधिवेशन था। गाधीजी का विचार था कि त्रिपुरी में काग्रेंस के अध्यक्ष मौ० अवुल कलाम आजाद के होने से साम्प्रदायिक समस्या के हल करने में मदद मिलेगी। यही कारण था कि उन्होंने सुभाष बावू को राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से खड़े होने को प्रोत्साहन नही दिया। इसके बावजूद मित्रो ने सुभाष बावू के नाम का प्रस्ताव कर दिया और सुभाष बावू ने खडा होना भी स्वीकार कर लिया। मौलाना की उम्मीदवारी की भी नियमित रूप से घोषणा की गई और जनवरी १९३८ में कार्यसमिति की वार-

दोली वाली बैठक में यह प्राय निश्चित ही था कि मौलाना को चुन लिया जायगा। इन पिक्तियों के लेखक को वार्दोली से रवाना होते समय गांधीजी से सूचना मिली कि यदि मौलाना ने स्वीकार न किया तो वह (गांधीजी) यह काटो का ताज उस (लेखक) के सिर पर रखना चाहते हैं। मौलाना अपनी रजामदी दे चुके थे और बम्बई के लिए रवाना हो चुके थे। अगले दिन बम्बई में मौलाना ने अपनी राय बदल दी और अपनी उम्मेदवारी वापस लेने का फैसला किया। वाद में मौलाना के कहने पर इन पिक्तियों के लेखक का नाम सामने आया और इस तरह लेखक और सुभाष बाबू दो ही प्रतियोगिता के लिए रह गये। इस प्रकार मौलाना के हट जाने पर सुभाष बाबू को अपने प्रतियोगी के विरुद्ध लगभग ९५ मतो से सफलता प्राप्त हुई।

चुनाव का प्रभाव

चुनाव का परिणाम प्रकट होते ही गाधीजी ने घोषणा कर दी कि सुभाष के 'प्रतिस्पर्धी' की पराजय को वह अपनी पराजय मानते है। इससे देश में हलचल मच गई। जिन लोगो ने सुभाष वावू के पक्ष में मत दिया था वे गांधीजी और उनके नेतृत्व मे विश्वास प्रकट करने लगे। इससे एक परेशान करने वाली परि-स्थिति उत्पन्न हो गई। राप्ट्रपति के पद के लिए पहले २९ जनवरी १९३९ को मत लिया गया था, परन्तु एक सप्ताह के भीतर ही स्थिति मे परिवर्तन हो गया इससे नये अध्यक्ष के लिए बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। यद्यपि अध्यक्ष का चुनाव डेलीगटो के बहुमत से हुआ था, तो भी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी मे उसका अल्पमत था। अब प्रश्न यह था कि वह अपनी कार्यसमिति कैसे बनाए? सुभाष वाबू का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था और इन चिन्ताओ का असर भी उनके स्वास्थ्य पर पडा। फलत ९ फरवरी १९३९ को खुले अधिवेशन के प्रस्तावो का मसविदा बनाने के लिए वर्घा में कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें वह न जा सके । कार्यसमिति के १३ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सिर्फ अध्यक्ष और श्रीशरत्चन्द्र बोस ही कार्य-सिमिति मे रह गये। सुभाष बाबू के स्वास्थ्य मे सुधार नहीं हुआ और उनकी बीमारी खुले अधिवेशन में भी चलती रही। अधिवेशन के पाच या छ दिन उन्हें तापमान रहा और अधिवेशन के दूसरे दिन तो वह १०४' व १०५° डिग्री तक चढ गया। बीमारी के कारण तत्कालीन राजनीति में और भी पेचीदगी आ गई।

त्रिपुरी-कांग्रेस : १८३८

त्रिपुरी-अधिवेशन की कार्यवाही अघ्यक्ष के चुनाव तथा गाधीजी के अनशन की परिस्थितियो के कारण फीकी पड गई थी। वातावरण इन दो मुख्य घटनाओ की

प्रतित्रियाओं से व्याप्त था। तीसरी घटना स्वयं मनोनीत अध्यक्ष की बीमारी थी, जिसके कारण वह जानदार जलूस में भाग न ले सके। जलूस में अध्यक्ष को ५२ हाथियों के रूप में वैठाकर निकालने का निश्चय किया गया था और इस जलूस को रेलवे स्टेशन से प्रकृति की गोद में बसे त्रिपुरी के विष्णुदत्त नगर तक निकालने की व्यवस्था की गई थी। नगर नदी के किनारे बनायाँ गया था और वह गांवों तया जंगलों की पृष्ठ-भूमि में बड़ा ही मनोहर लगता था। इस मनोहर दृश्यावली के बीच जलूस अध्यक्ष के चित्र के साथ निकाला गया। इसके बाद प्रतिनिधि गों ने मौ॰ शौकत-अली, सर मुहम्मद इकबाल, बेगम अंसारी, मद्रास के मंत्री श्री के० रामुनी मेनन, जी० एस० कापडिया, बी० राजा राउ, डा० राजवली पटेल और श्री के० नागेश्वर राव पंतलू की दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजिल अपित की। अधिवेशन आरम्भ होने से पहले समस्याओ का स्पष्टीकरण होना था। अ० भा० कांग्स कमेटी की जिस प्रारम्भिक बैठक में प्रवन्व तया नियम सम्बन्धी कार्य होते थे उसी मे इस बार ताकत की आजमाइश हुई। पिछ्ले महीने कार्यसमिति की जो बैठक वर्षा में हुई थी उसमे प्रधानमन्त्री की वार्षिक रिपोर्ट को मनोनीत अव्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण स्वीकार नहीं किया गया था। इसील्ये अ० भा० काग्रेस कमेटी मे जब प्रधानमत्री की रिपोर्ट उपस्थित की गई तब यह आपत्ति उठाई गई कि कार्य-समिति की स्वीकृति के विना अ० भा० काग्रेस कमेटी उस पर विचार नहीं कर सकती। अध्यक्ष ने फैसला दिया कि विधान में यह कही नहीं कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित होने से पूर्व प्रधानमन्त्री की रिपोर्ट पर कार्य-समिति की मंजूरी लाजिमी है। इसलिए कमेटी ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह पहली कशमकश थी। दूसरी कशमकश तब उत्पन्न हुई जुब श्री गोविन्दवल्लभ पत ने अ० भा० काग्रेस कमेटी के १६० सदस्यो की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि चूकि आगामी वर्ष में विकट परिस्थित उत्पन्न हो सकती है और चूकि ऐसे सकट के समय केवल महात्मा गाधी ही काग्रेस तथा देश को विजय-पथ पर ले जा सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यसमिति को उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और इसीलिए कमेटी अध्यक्ष से अनुरोघ करती है कि वह कार्यसमिति का चुनाव गाधीजी की इच्छा के अनुसार करे। प्रश्न यह या कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय या नही। एक वर्ग ने कहा कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार ही नही कर सकती। अध्यक्ष ने भी यही निर्णय दिया। परन्तु उन्होने विषय-समिति मे इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया। अव्यक्ष का भाषण काग्रेस के इतिहास में सब से छोटा था, किन्तु उसमें सुभाष

वावू ने राष्ट्र के आगे अपना दिल खोल कर रख दिया था। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय

Pa

परिस्थित, म्यूनिक का समझौता, मिस्री प्रतिनिधिमडल, गांधीजी का अनशन, कार्यसमिति के सदस्यों का इस्तीफा और रियासतों की हलचल — सभी समस्याओं का जिक्र
किया था। घरेलू राजनीति के सम्बन्ध में उन्होंने वताया कि उसमें निराणाबाद
के लिए स्थान न था, विल्क इससे विपरीत परिस्थित राष्ट्र के लाभ में ही थी जिससे
लोग सफलता की आशाए कर सकते थे। उनका कहना था कि हमें ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी माग एक अल्टीमेटम के रूप में रखनी चाहिए और उनका
उत्तर पाने के लिए समय की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये और यदि इस
निर्धारित अवधि के भीतर सतोपजनक उत्तर न मिले तो हमें अपनी राष्ट्रीय
माग स्वीकार कराने के लिये सामूहिक सत्याग्रह जैसी कार्रवाई करनी चाहिए,
क्योंकि सुभाष बाबू का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय सत्याग्रह
जैसे आदोलन का अधिक समय तक सामना नहीं कर सकेगी। उनके विचार से
निष्क्रिय दृष्टिकोण रख कर सघ योजना लादे जाने की प्रतीक्षा का समय नहीं था,
बिल्क वह सघ-योजना लादे जाने से पूर्व कार्रवाई आरम्भ कर देने के पक्ष में थे।

राष्ट्रीय माग के व्यापक प्रश्न पर त्रिपुरी में हरिपुरा से अधिक और कुछ न कहा गया। उस समय एक तरफ राष्ट्रीय सघर्ष के आसार दिखाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ अतर्राष्ट्रीय युद्ध के वादल घरते आ रहे थे। भारत को इन दोनो ही परि-स्थितियों का सामना करना था और इसीलिए त्रिपुरी में एकता की वृद्धि, फूट की शक्तियों के निराकरण, प्रातीय कार्यों के एकीकरण तथा राष्ट्रीय सस्था की शक्ति वढाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सब कुछ ठीक था। मार्ग स्पष्ट था और मिजल दिखाई देने लगी थी। उस तक पहुचने की बाघाए भीतरी और वाहरी दोनो ही प्रकार की थीं। यदि हमें वाहरी वाघाओं पर विजय पाना था तो भीतरी बाघाओं को तो मार्ग से बिलकुल हटा देना ही जरूरी था। जो अव्यवस्था दिखाई दे रही थी उसमें से काग्रेस व्यवस्था को कैसे खोज निकाले? इस राष्ट्र की डगमगाती नैया का केवट कौन हो । गांधीजी राजकोट में थे और हाल ही में अनिश्चित काल के लिए आरम्भ किये गये एक अनशन को समाप्त कर चुके थे। उनका शरीर त्रिपुरी में नहीं था, किन्तु आत्मा वहीं मौजूद थी। सवाल सिर्फ यही था कि राष्ट्र उन्हें अपना कर्णधार बनाता है या नहीं । त्रिपुरी में प्रतिनिधियों को इसी प्रश्न का फैसला करना था।

अधिवेशन भर सुभाप बाबू बीमार रहे और इधर काफी समय से इस बीमारी में कोई सुधार होता हुआ नही दिखाई दे रहा था, यहा तक कि वह खुले अधिवेशन तक में नही आ पाये थे। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा विषय-समिति की बैठक में वह स्ट्रेचर पर लाये गये थे। उनके स्ट्रेचर पर आने-जाने से दया का सचार होता था, लेकिन जहा तक सिद्धान्तो और नीतियो का सवाल था, दोनो ही पक्ष अडिंग थे। प्रतिनिधियो के एक भाग में गुल-गपाडा मच रहा था। इसके कारण लगभग एक घण्टे तक कार्यवाही न हो सकी। जब शरत बाबू मंच पर आये और उन्होने अनुरोध किया तब शोरगुल कम हुआ। यह उपद्रव प० गोविन्द वल्लभ पत के इस सुझाव पर हुआ कि खुले अधिवेशन में इस अप्रिय प्रसग से बचने के लिए प्रस्ताव को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। परन्तु इस सुझाव का जोरदार विरोध किया गया। सुझाव वापस ले लिया गया और अधिवेशन स्थिगित कर दिया गया। अगले दिन दर्शको को बाहर ही रखा गया और विषय-सिमिति के पडाल में, प्रतिनिधि एकत्र हुए। प्रतिनिधियों के अलावा पडाल में पत्रकार तथा स्वयसेवक भी थे। इस बार प्रबन्ध उत्तम हुआ और खुला अधिवेशन सुव्यवस्थित रूप से हुआ। बाद में जब विषय सिमिति के पडाल में खुला अधिवेशन आरम्भ होने जा रहा था, बगाल के कुछ मित्रों ने पहले वाले सुझाव को मानना स्वीकार किया; किन्तु फिर शोरगुल होने से वह आगे न बढ सका। खैर, खुले अधिवेशन की कार्रवाई आरम्भ हुई और प्रस्ताव, बिना किसी उल्लेखनीय घटना के पास हो गया।

सुभाष बाबू का त्याग-पत्र

काग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। त्रिपुरी में अध्यक्ष की विदाई एक गम्भीर घटना थी। इस अवसर पर परिवार के कुछ लोग, एक या दो डाक्टर या कार्यसमिति के दो सदस्य उपस्थित थे। बड़ी किठनाई से सुभाष बाबू को अम्बुलेस गाड़ी की गद्दी पर रखा गया, जिसमें उन्हें लम्बी यात्रा करनी थी। वह सीघे झरिया के निकट किसी स्थान को गये और वहा स्वास्थ्य सुधार होने में लगभग एक महीना लग गया। प्राय नित्य ही देश में कार्यसमिति के सदस्यों के चुनाव और इस सम्बन्ध में घोषणा की प्रतीक्षा की जाती थी। परन्तु उन्होंने यह घोषणा नहीं की। अन्त में परिस्थिति का सामना करने के लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। काग्रेस के कार्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया था। कार्य समिति के बिना काग्रेस की वही अवस्था थी, जो हाथ-पैर के बिना शरीर की होती है। सुभाष बाबू के रुख से पैदा हुई स्थिति का मुकाबला अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ही कर सकती थी, जिसकी बैठक कलकत्ता में अप्रैल १९३९ में हुई। परन्तु इस बैठक से पूर्व कलकत्ता में सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति में उस वर्ष के लिए नये राप्ट्रपित राजेन्द्र बाबू निर्वाचित हुए।

सुभाष बाबू का विरोधी रुख

पाठको को स्मरण होगा कि जलपाईगिरि (वगाल) के जिला-सम्मेलन मे ब्रिटिश सरकार को छ. महीने का अल्टीमेटम देने और फिर से सत्याग्रह शुरू करने का गुर निकाला गया था। बगाल के लोग ब्रिटिश सरकार से संघर्ष शीघ्र

ही छेडने के पक्ष में थे। किसानों को रियायतें देने के बारे में भी वे सत्याग्रह की धमकी दे रहे थे। बगाल में काग्रेसी मित्रमडल था। ऐसी स्थिति में यदि सत्याग्रह चलाया जाता तो वहा के मित्रयो को सत्याग्रह का सामना करना पडता। इसके अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए छेडा गया सत्याग्रह सम्बन्धित प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के निर्देशन तथा नियत्रण में ही चलता। इन वातों की उपेक्षा करके सुभाष बावू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्ही दिनो काग्रेस के दो दलो मे मनमुटाव बढने का एक और भी कारण उत्पन्न हो गया। यह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा अपनी उसी बैठक में काग्रेस पार्टियो तथा प्रान्तीय कमेटियो को दी हुई सलाह थी। प्रान्तीय कमेटियो को यह आदेश दिया गया था कि उन्हें शासन-सम्बन्धी मामलो में हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि नीति के सम्बन्ध में मन्त्रिमडल या प्रान्तीय कमेटी में कोई मतभेद उठे तो उसे पार्लामेटरी बोर्ड के सुपुर्द करना चाहिए और इस सम्बन्ध में प्तार्वजनिक रूप से कोई बहस न होनी चाहिए। इस नियम के विरोधियो ने जनता के अधिकारो पर कुठाराघात समझा और कहा कि इससे तो प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया मित्रयो तथा धारासभाओ की पार्टियो के अधीन हो गईं। विभिन्न स्थानो की मातहत कमेटियो ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के निश्चयो के औचित्य पर सदेह प्रकट करते हुए प्रस्ताव पास किये और उनकी निन्दा के लिए सभाए बुलाई। उचित तो यह था कि उच्च कमेटी के पास सुझाव भेजा जाता या कोई अनुरोध किया जाता, किन्तु किया यह गया कि सुभाष बाबू और उनके अनुयायियों ने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के उपर्युक्त निर्णयों के बारे मे ९ जुलाई को भारत मे विरोध-दिवस मनाया। इन दिनो गाँधीजी सीमाप्रान्त गये हुए थे और जवाहरलालजी लका जा रहे थे। फिर भी कार्यसमिति की बैठक तुरन्त बुलाना आवश्यक समझा गया । अगस्त १९३९ मे वर्घा मे उसकी बैठक हुई । सुभाष बाबू से स्पष्टीकरण करने को कहा गया, क्योकि उन्होने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था।

कार्य-समिति का निश्चय

सुभाष बाबू की लम्बी सफाई पर कार्यसमिति ने उत्सुकतापूर्वक विचार किया और अन्त में खेद और अनिच्छा के साथ इस परिणाम पर पहुची कि राष्ट्रपति ने जो मुख्य बात कही थी, उसे सुभाष बाबू ने अच्छी तरह नहीं समझा। कार्यसमिति का विचार यह था कि "भूतपूर्व अध्यक्ष की हैसियत से सुभाष बाबू को अनुभव करना चाहिए था कि अध्यक्ष-द्वारा उन्हें जो आवश्यक आदेश दिये गये थे, राष्ट्र के सेवक के रूप में उन्हें पालन करना चाहिए था, चाहे अध्यक्ष के निर्णय से उनका निजी मतभेद ही क्यों न रहा हो। यदि सुभाष बाबू को अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति थी तो वह यह आपत्ति कार्यसमिति या अखिल भारतीय काग्रेस

कमेटी के सामने उपस्थित कर सकते थे, किन्तु जब तक अध्यक्ष के आदेश बने हुए थे तब तक सुभाप बाबू को उन्हें मानना चाहिए था। काग्रेस को ससार की सब से शिक्तशाली साम्राज्यवादी ताकत से टक्कर लेनी है और ऐसे समय में कार्यसमिति सुभाष बाबू का यह तर्क मानने में असमर्थ है कि प्रत्येक सदस्य को काग्रेस के विधान का मनमाना अर्थ लगाने की स्वतत्रता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की स्वतत्रता दी गई तो काग्रेस में अराजकता फैल जायगी और थोड़े समय में उसका खात्मा हो जायगा। इसीलिए सुभाप बाबू को बगाल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए तथा अगस्त, १९३९ से तीन वर्ष के लिए किसी भी निर्वाचित काग्रेस कमेटी में चुने जाने के अयोग्य ठहरा दिया गया। आशा प्रकट की गई कि श्री सुभापचन्द्र बोस अपनी गलती महसूस कर के अनुशासन की कार्रवाई स्वीकार करेगे। परन्तु सुभाप बाबू ने इसके बाद दक्षिण भारत का दौरा किया। इस दौरे में जनता की भारी भीड़ के स्वागत से वह इस भ्रम में पड़ गये कि सब लोग उन्हीं के अनुयायी है और सब-के-सब उस अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लाक) में सम्मिलित हो जायगे, जिसकी स्थापना उन्होने इस्तीफा देने के बाद की थी।

नेहरूजी को लंका-यात्रा

लका के कुछ कानूनों के कारण प्रवासी भारतीयों के लिए चिन्तनीय परिस्थिति पैदा हो गई थी। दो मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों के बीच अनावश्यक झगड़े को रोकने के लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने प॰ जवाहरलाल नेहरू को लका जाने और सम्भव हो तो शान्तिपूर्ण समझौता कराने के लिए नियुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू १६ जुलाई को वायुयान द्वारा कोलम्बो पहुचे। जनता ने, जिसमे सिहल तथा भारतीय दोनों ही थे, उनका शानदार स्वागत किया। लका की राज-परिपद के नेता सर बेरन जयतिलक के कहने पर एक विशेष स्वागत समिति बनाई गई, जिसका आतिथ्य पड़ितजी ने स्वीकार किया।

लका में उनका वडा व्यस्त कार्यक्रम रहा। वह मित्रयो, सीलोन इडियन काग्रेस और सीलोन सेट्रल इडियन असोसियेशन के प्रतिनिधियो तथा अन्य व्यक्तियों से मिले। उन्होने कई सार्वजिनक सभाओं में भापण भी दिये। मित्रयों के साथ अपनी वार्ता में उन्होंने सिहलों तथा लका में वसे भारतीयों को व्यापक दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपने कहा कि हमें जिन महान समस्याओं का सामना करना है उनकी तुलना में वर्तमान समस्याए छोटी एव गौण हैं, इसलिए इस छोटी समस्या को हमें व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारतीयों तथा उनके प्रतिनिधियों से उन्होंने अन्दरूनी मतभेदों को मिटाकर आत्माभिमानी नागरिकों के समुदाय बनने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने

भारतीयों को सलाह दी कि वे लका को अपना घर समझे और सचाई तथा लगन से उसकी सेवा करे।

इस प्रकार समस्या के प्रति इस उच्च दृष्टिकोण के कारण सब तरफ शान्त और अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया, परन्तु मित्रगण भारतीयों को वापस भेजने की योजना में कोई वडा परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं हो सके। योजना में थोडा हेर-फेर करना उन्होंने अवश्य स्वीकार कर लिया और वादा किया कि भारतीयों के लौटाने की वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें विशेप असुविधा न हो। यद्यपि जवाहरलाल जी की यात्रा के कारण दोनों देशों की परम्परागत मैत्री की यादगारे ताजी हो गईं और कटुता में भी कमी हो गईं, लेकिन उसके कारण उद्देश्य की सिद्धि न हो सकी। लका की सरकार का रुख तत्कालीन समस्याओं के सम्बन्ध में इतना हठी रहा कि कार्यसमिति को अपने प्रस्ताव में कहना पड़ा कि यह रुख अन्तर्राप्ट्रीय शान्ति की वृद्धि करने वाला अथवा न्यायपूर्ण नहीं है। समिति ने विचारपूर्वक अपना मत प्रकट किया कि लका के लिए भारत से मजदूरों का जाना एकदम रोक दिया जाय। यहा यह भी वता देना अप्रासिगक न होगा कि १९४० में लका-सरकार का एक प्रतिनिधि मडल भारत सरकार से वार्ता करने के लिए आया और इसका भी कोई भिन्न परिणाम न निकला।

खादी पहनने पर जोर

शिकायते आने पर कि निर्वाचित स्थानो पर चुने गये अथवा उनके उम्मीदवार व्यक्ति आदतन खद्दधारी नहीं है, एक अधिकारपूर्ण घोपणा आवश्यक हो गई। हिरपुरा अधिवेशन समाप्त होते ही कार्यसमिति की बैठक हुई थी और उसमें कहा गया था कि सिर्फ हाथ का कता और हाथ का बुना कपडा ही खद्दर नहीं कहा जायगा, बिल्क उस कपडे को भी खद्दर कहा जा सकता है, जिसे बनाने में कारीगरों को चर्छा सघ द्वारा निर्धारित मजदूरी दी गई हो। जब कार्यसमिति से प्रश्न किया गया कि "हाथ से कती और हाथ से बुनी खादी का आदतन पहनने वाला" किसे कहा जायगा तब कार्यसमिति ने फैसला दिया कि आदतन खादी पहनने वाला वहीं व्यक्ति माना जायगा, जो किसी काग्रेस कमेटी में अथवा किसी पद के लिए निर्वाचित होने के छ महीने पूर्व से खाटी पहनता रहा हो। यह भी निश्चय किया गया कि खादी वाली घारा जिस प्रकार घारासभाओं की सदस्यता के लिए आवेदनपत्र भेजने वालो पर लागू होती है उसी प्रकार वह म्यूनिसिपल तथा स्थानीय वोर्डों के सदस्यों पर भी लागू होगी।

वम्बई मे नशावन्दी-स्रान्दोलन

वम्बई के लिए १ अगस्त का दिन स्मरणीय था। इस दिन बम्बई नगरी तथा

पास की वस्तियों में नशाबदी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पहले दिन एक विशाल जलूस निकाला गया, जो एक भारी सभा में समाप्त हुआ। इस सभा में भाषण करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा—"सम्पूर्ण भारत और वम्बई हमें देख रहा है। सारा ससार जिस दिन की इन्तजारी कर रहा था वह दिन आ गया है। इस देश के लिए यह दिन नशाखोरी की राक्षसी से हमारे छुटकारे का दिन है। आज वम्बई ने अपने पिछले इतिहास का खात्मा करके एक नये अध्याय का आरम्भ किया है।"

गाधीजी ने, जो इस प्रयोग के प्रेरक थे, निम्न सन्देश भेजा-

"मुझे आशा है कि अन्त में वम्बई की सहज सद्भावना की, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है, विजय होगी और सब मिलकर बम्बई मित्रमडल द्वारा आरम्भ किये गये इस साहसपूर्ण सुधार को सफल बनायेगे, जैसा कि इसे होना ही चाहिए। मुझे विश्वास है कि नशाखोरी के अभिशाप से छुटकारा देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।"

जमनालाल वजाज की रिहाई

श्री जमनालाल बजाज की रिहाई भी इस वर्ष की एक प्रमुख घटना थी। कार्यसमिति के एक सदस्य तथा जयपुर प्रजामडल के अध्यक्ष श्री जमनालाल वजाज को जयपुर राज्य मे प्रवेश की निषेध-आज्ञा भग करने के अपराध में पिछली फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह जयपुर अकाल-पीडितो की सहायता का कार्य करने जा रहे थे। आज्ञा उल्लघन करने पर उन पर वाकायदा मुकदमा नहीं चलाया गया, विल्क उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा गया। जेल के किण्टमय जीवन का उनके स्वास्थ्य पर वुरा प्रभाव पडा। जब मामला स्थानीय डाक्टरों की शक्ति के बाहर हो गया तब सेठज़ी को इस शर्त पर छोड़ना स्वीकार किया गया कि वह इलाज के लिए विदेश चलें जाय। जमनालालजी ने इन शर्तों पर छोडा जाना पसन्द नहीं किया। ९ अगस्त १९३९ को छ महीने के अनावश्यक तथा कप्टमय जेल-जीवन के वाद उन्हें विना किसी शर्त के छोड दिया गया।

द्वितीय महायुद्ध श्रोर भारत

पिछले वारह साल से काग्रेस दूसरे यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ने की आशका कर रही थी। आखिरकार १९३९ के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित ने चिन्तनीय रूप घारण कर लिया और युद्ध का संकट उपस्थित हो गया। एक ओर वे राष्ट्र थे, जो लोकतत्रवाद और स्वाधीनता के हामी थे और दूसरी ओर वे राष्ट्र थे जिनके दृष्टिकोण फासिस्ट थे और जिनके आचरण से हमला करने के इरादे के चिह्न दिखाई दे रहे थे। राष्ट्रों के इन दो दलों के वीच

काग्रेस की सहानुभूति स्पष्टतया पहले की ओर थी। परन्तु काग्रेस निञ्चय कर चुकी थी कि वह युद्ध में भारत के ढकेलने के प्रयत्न का विरोध करेगी। १ मई १९३९ को कलकत्ते में होने वाली अपनी बैठक में काग्रेस कमेटी विदेशों को भारतीय सेना की रवानगी के बारे में अपने विरोध को दुहरा चुकी थी, फिर भी सरकार ने मिस्र तथा सिगापुर को भारतीय सेना भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध भेज दी थी। युद्ध-परिस्थित के अलावा केन्द्रीय असेम्बली भी कह चुकी थी कि उसकी अनुमति के बिना सेना विदेश न भेजी जायगी। इस तरह जाहिर था कि ब्रिटिश सरकार काग्रेस तथा असेम्बली की घोपणाओं का अनादर कर ऐसे कार्य कर रही थी, जिनके परिणामस्वरूप भारत के युद्ध में फस जाने की सम्भावना थी। लोकमत की इस अवज्ञा के कारण जवाब में कार्यसमिति ने केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों से असेम्बली के अगले अधिवेशन में भाग न लेने का अनुरोध किया। साथ ही प्रान्तीय सरकारों को चेताबनी दी गई कि काग्रेसी मित्रमंडलों को चाहे इस्तीफा ही देना पड़े, किन्तु उन्हें युद्ध की तैयारियों में हरगिज सहायता न देनी चाहिए।

इसके वाद घटनाचक बहुत तेजी से घूमा। इधर २४ अगस्त, १९३९ को मास्को मे रूसी-जर्मन अनाक्रमण-सिंध हुई और उधर ब्रिटिश विदेश-विभाग ने २५ अगस्त को ब्रिटेन और पोलैण्ड के बीच परस्पर सहायता की घोषणा कर दी। पोलैण्ड के प्रति ब्रिटेन ने जो जिम्मेदारी ग्रहण की थी उसके कारण ब्रिटिश सरकार को जर्मन सरकार से कहना पड़ा कि यदि वह पोलैण्ड के प्रति हमले की कार्रवाई रोक कर सतोपजनक आक्वासन न देगी और पोलैण्ड की भूमि से अपनी सेना न हिटा लेगी तो तीन सितम्बर के ११ बजे से दोनो देशो के मध्य युद्ध की अवस्था आरम्भ हो जायगी। फिर तीन सितम्बर को श्री चेम्बरलेन ने रेडियो पर घोपणा करते हुए कहा कि चूकि ऐसा कोई आक्वासन प्राप्त नही हुआ, इसलिए ब्रिटेन का जर्मनी से युद्ध चालू समझना चाहिए। इस प्रकार युद्ध छिड गया।

तीन सितम्बर की रात को सम्राट ने अपने साम्राज्य के नाम एक सदेश दिया। इसमें उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्वार्थपरता की निन्दा की, जिसने अपनी सिधयों और वचनों को भग कर के दूसरे राज्यों की स्वाधीनता पर आक्रमण करने के लिए पशुबल का सहारा लिया था। इसके उपरान्त वाइसराय ने अपनी घोषणा में उपस्थित समस्या पर प्रकाश डाला और विश्वास प्रकट किया कि भारत पशुबल के विरुद्ध मानवीय स्वाधीनता के लिए लडेगा। उनके सदेश का सबसे उपहासास्पद अथवा सबसे अधिक चोट करने वाला भाग वह था, जिसमें उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया था कि भारत पशुबल के विरुद्ध मनुष्य की स्वाधीनता का पक्ष ग्रहण करेगा और ससार की ऐतिहासिक सम्यता की हैसियत से दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच अपने स्थान के अनुरूप अपने हिस्से का कार्य पूरा करेगा। सचमुच एक

कार्यसमिति की वैठक

इस समय ब्रिटेन एक तरह से अकेला और अमहाय रह गया था। यहा तक कि स्वाधीन उपनिवेशों ने विरोधी भावनाओं का परिचय दिया था। यदि एक ओर आयलैंड ने तटस्य रहने का निञ्चय किया था और दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ एकमत से स्मट्स के पक्ष में फैसला किया था तो आस्ट्रेलिया ने स्वार्थपूर्ण भावना प्रकट की थी और कनाडा ने सुदूर मैत्री का परिचय दिया था। यदि ऐसे समय गाधीजी से नैतिक सहयोग का बचन प्राप्त कर वाइसराय जोरदार और विञ्वासपूर्ण स्वर में उत्सुक समार के आगे घोषणा कर देते कि गाधीजी के इस बचन में वह भारत की ३५ करोड जनता के समर्थन की आशा देख रहे हैं तो मसार के समस्त राष्ट्र और विशेषकर शत्रु-राष्ट्र ब्रिटेन के लिए प्राप्त इस सहायता को देखकर चिकत रह जाते। अत लार्ड लिनलिथगों और ब्रिटेन के सामने यह ममस्या थी कि गाधीजी के इस पूर्ण और हार्दिक समर्थन से सतुष्ट हो जाय और भारत से साधनों और असख्य जनों की भी सहायता प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में प्रज्न यह था कि गाधीजी ने ब्रिटेन के प्रति राष्ट्र की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो आवाज उठाई थीं उसे प्राप्त किया जाय या भारत की सम्पत्त तथा उसकी करोडों जनता की सेना में भरती करने की सुविधा उपलब्ध की जाय।

९ सितम्बर, १९३९ को इस परिस्थिति पर विवार करने के लिए वर्धा मे कार्यसमिति की वैठक हुई। समिति ने पोलैण्ड के प्रति, जो पशुवल का शिकार हुआ था, गहरी सहानुभूति प्रकट की और इगलैण्ड तथा फास जिस उद्देश से युद्ध मे गामिल हुए थे उसकी सराहना की। साथ ही समिति ने इस बात के लिए खेद और आइनर्य प्रकट किया कि जब साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेश अपनी-अपनी पार्लामेन्टो से युद्ध में भाग लेने अथवा न लेने का फैसला कर रहे हैं, तब भारत का युद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भी उसे उसमे भाग लेने के लिए विवश कर दिया गया है । समिति को वाइसराय की इस घोषणा से प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने सघ-योजना को अमल मे लाने की तैयारियो को रोक दिया है, यद्यपि उसने सघ-शासन के सिद्धान्त को अक्षुण्ण वनाये रखा है। समिति का मत है कि केन्द्र में जिम्मेदार शासन के अभाव तथा सघ-योजना स्थगित होने के कारण केन्द्र में एक ऐसी अनुत्तरदायी सरकार रह गई है, जो युद्ध की तैयारियो के सम्बन्ध मे प्रान्तीय सरकारों पर नियत्रण रखती है और इस तरह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे चुपचाप नही छोडा जा सकता। यदि प्रान्तीय सरकारो को सिर्फ प्रान्तीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि युद्ध सम्बन्धी उन नये कार्योके वारे में भी कार्रवाई करनी है, जिनकी अन्तिम जिम्मेदारी प्रातीय सरकारो पर आनी चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार के सम्वन्घ मे उनकी स्थिति साफ होनी चाहिए।

पिछले, खासकर गत महायुद्ध के, अनुभव ने हमें सिखा दिया है कि ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनो या वक्तव्यो पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए समिति सरकार से अनुरोध करती है कि भारत के सम्बन्ध में सिर्फ स्थिति का स्पष्टीकरण ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सिद्धातों पर अमल भी शुरू हो जाना चाहिए। समिति ने घोषणा की कि जब तक स्थिति का स्पष्टीकरण इस भाति नहीं किया जाता तब तक वह देश की सरकार से पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती।

इसके अलावा सत्याग्रह का प्रश्न था। इस प्रश्न का एक पक्ष तो यह हो सकता था कि सत्याग्रह छेडने पर सभव है, सरकार मार्श्नला-ला घोपित कर दे और नेताओ को जेलो मे ठूस दे। दूसरे पक्ष मे तर्क यह दिया गया कि यदि मित्रमडलो को काम करत रहने दिया गया और मन्त्री काग्रेसजनो की गिरफ्तारी का आदेश देने को मजबूर हुएँ तो युद्ध समाप्त होने तक राजनैतिक सगठन के रूप में काग्रेस का खात्मा ही हो जायगा। इस तरह काग्रेस को दो बुराइयो में से एक का चुनाव करना था। गाधीजी की राय थी कि हमें अपना नैतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए और मन्त्रियों को काम करते रहने देना चाहिए। जवाहरलालजी समझौता द्वारा जिस पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीन उपनिवेश पद प्राप्त करने की आशा करते थे, गाधीजों का खयाल था कि इस प्रकार की घोषणा वह मन्त्रियो द्वारा प्राप्त कर सकते थे। दोनो ही अवस्थाओं में इस बात का खतरा था कि हो सकता है कि वादा पूरा न किया जाय, किन्तु गाधीजी के दृष्टिकोण से होने वाली घोषणा के पूरी होने की सम्भावना अधिक थीं। गाधीजी का कहना था कि उस हालत में सिर्फ वातचीत के दिमयान हुए वादे को पूरा करने का ही सवाल न था, बल्कि तब तो एक नैतिक जिम्मेदारी अदा करने की वात उठती थी। गाधीजी कोई राजभितत की भावना के कारण ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि वह हमारी कमजोरी का अनुभव कर रहे थे। वास्तव में गांधीजी किसी प्रस्ताव के आधार पर वातचीत चलाने को तैयार न थे और न वह कोई माग उपस्थित करने के ही पक्ष में थे, यहा तक कि वह अविध निर्धारित करने की वात भी किसी हालत में मानने को तैयार न थे। यदि ब्रिटेन से कुछ मिले तब भी गाधीजी उसे लेने को तैयार न थे। वह सविनय अवज्ञा के भी विरुद्ध थे। सभी जानते हैं कि घोपणा-पत्र के प्रस्ताव के मसविदे के मुख्य भाग से जवाहरलालजी का सम्बन्ध था। गाधीजी ने अनुभव किया कि यदि वह प्रस्ताव पास हो तो जवाहरलालजी को अध्यक्ष वनना चाहिए और उन्हीं को अपनी कार्यसमिति का चुनाव करना चाहिए। गाधीजी अपने अहिसा के सिद्धान्त पर किसी तरह से आच न आने देना चाहते थे। वह सिर्फ मध्यस्य ही वन सकते थे। यही उनकी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अनुभव किया कि कार्यसमिति उनके साथ चलने को तैयार नहीं है।

यदि वह चाहते तो कार्यममिति में वहुमत उनके पक्ष में हो सकता था, किन्तु वह सदा से हृदय के परिवर्तन में विश्वास करते थे। इसीलिए खुद सहमत न होते हुए भी वह चाहते थे कि जवाहरलालजी का मसिवदा मजूर होना चाहिए। उन्हीं को वातचीत करना चाहिए और अध्यक्ष भी उन्हीं को चुना जाना चाहिए। यह सुझाव कुछ विचित्र-सा जान पड़ता था, परन्तु वास्तव में इससे तीन दिन पहले ही राजेन्द्र वावू सेवायाम गये थे और उन्होंने अपना इस्तीफा देने को कहा था। वैधानिक कठिनाई के कारण जवाहरलालजी को अध्यक्ष वनाने का सुझाव आगे न वढ सका। तव युद्ध-समिति नियुक्त करने का एक और प्रस्ताव सामने आया और उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। जवाहरलालजी इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव किया। चुने हुए सदस्य थे वल्लभभाई पटेल तथा अबुलकलाम आजाद। प्रस्ताव का मसिवदा मिति में दूसरी वार पढ़ा गया और कुछ मौखिक नद्योंचनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया गया। ९ सितम्बर से १५ सितम्बर तक कार्यसमिति की बैठक हुई। इसी वीच ११ सितम्बर को सम्राट का सदेश आया, जिसमें भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से सहायता और समर्थन की आशा प्रकट की गई थी।

गांधोजी का वक्तव्य

काग्रेस कार्यसमिति के घोषणा-पत्र पर गाधीजी-हारा विचार कर लेने के वाद उसे प्रकाणित कर दिया गया। गाधीजी का वक्तव्य सक्षेप मे नीचे दिया जाता है —

"कार्यसमिति ने विश्व-युद्ध सकट के स्म्वन्य में जो वक्तव्य जारी किया है उसे तैयार करने में पूरे चार दिन लग गये हैं। सामिति के कहने पर घोपणा-पत्र का मसिवदा पिंडत जवाहरलाल नेहरू ने तियार किया था। मेरा विचार था कि ब्रिटेन को जो भी समर्थन दिया जाय वह विना किसी गर्त के दिया जाय, किन्तु यह देखकर खेद हुआ कि यह विचार सिर्फ मेरा अपना ही था। यह सिर्फ अहिसात्मक आधार पर ही होना सम्भव था। लेकिन समिति को तो भारी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। वह सिर्फ अहिसात्मक दृष्टिकोण कैसे ग्रहण कर सकती थी। सिमिति ने अनुभव किया कि विरोधी की कठिनाई से लाभ न उठाने की शक्ति के लिए जिस अहिसात्मक भावना की जरूरत होती है उसका राष्ट्र में अभाव है। फिर भी, सिमिति जिस नतीजे पर पहुची है उसके कारणो पर रोगनी डालते हुए उसने अग्रेजो के प्रति महान उदारता का परिचय दिया है। इसलिए इस वक्तव्य को इस देश के निवासियों के नाम, अथवा ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनता के नाम नहीं, विल्क ससार के उन सभी राष्ट्रों के नाम जो भारत की तरह पीडित हैं, एक घोषणा-पत्र कहा जा सकता है। इसने कार्यसमिति के द्वारा सम्पूर्ण भारत को इस

वात के लिए मजबूर किया है कि वह सिर्फ अपनी स्वाधीनता का ही खयाल न

करे, विलक दुनिया के सभी शोपित राष्ट्रों की स्वाधीनता का ध्यान रखे। "समिति ने यह वक्तव्य पास करने के साथ ही जवाहरलालजी की मर्जी का एक वोर्ड नियुक्त किया है और उन्हीं को इस वोर्ड का अध्यक्ष वनाया है। इस वोर्ड का काम समय-समय पर वदलने वाली परिस्थित का सामना करना होगा। मुझे आजा है कि इस वक्तव्य का काग्रेस के सभी वर्ग समर्थन करेगे। राष्ट्र के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घडी में काग्रेस को विश्वास करना चाहिए कि यदि कुछ करने की जरूरत हुईं तो कार्रवाई के समय कमजोरी न दिखाई जायगी। यह वडे दु ख की वात होंगी यदि इस समय काग्रेसजन दलगत भीतरी और छोटे-मोटे झगडों में पड़े रहे। यदि समिति की कार्रवाई से कोई वडा या महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है तो प्रत्येक काग्रेसी का हार्दिक सहयोग मिलना बहुत ही जरूरी है। मुझे आगो है कि दूसरे सभी राजनैतिक दल भी ब्रिटिश सरकार से अपनी नीति का स्पव्टीकरण करने और लडाई के दिनों में उस नीति के अनुसार जितनी कार्रवाई सम्भव हो करने की माग में समिति का साथ देगे। अग्रेजो ने लोकतत्रवाद के वारे मे जो कुछ कहा है उससे स्वाभाविक परिणाम तो यही निकलता है कि हिन्दुस्तान व ब्रिटिंग साम्राज्य के दूसरे प्रदेशों को स्वाधीन राज्य घोषित कर देना चाहिए। यदि युद्ध का उद्देश्य इसके अलावा कुछ और है तो पराधीन राष्ट्र ईमानदारी से या अपनी मर्जी से कैसे सहयोग कर सकते हैं। जरू-रत सिर्फ विटिश राजनीतिज्ञो की विचारधारा में मानसिक-क्रान्ति की है। युद्ध से पूर्व लोकतत्रवाद मे विञ्वास की जो घोषणाए की गई थी और जिन्हे अभी तक दोहराया जा रहा है उन्हें अमल में लाने के लिए ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। सवाल यह है कि ब्रिटिश आधुनिक भारत को युद्ध में घसीटना चाहेगा या सच्चे लोकतत्रवाद की रक्षा में उसका सहयोग एक उच्छुक साथी के रूप में प्राप्त करेगा ? काग्रेस का समर्थन इगलैण्ड और फास के लिए सबसे महान नैतिक निधि होगी, क्योंकि काग्रेम के पास देने को सिपाही नहीं है। काग्रेस हिमात्मक साधनों से नहीं लडती। वह तो अहिसात्मक साधनों से ही काम लेती है, फिर चाहे ये साधन कितने ही अपूर्ण या वेटगे क्यो न हो।"

भारत-सरकार का रुख

इस बात को सभी स्वीकार करेगे कि युद्ध उप-मिमिति थोडे ही समय रही और इस थोडे समय में उसने कार्य भी अधिक नहीं किया। रामगढ में यह उप-समिति फिर नियुक्त नहीं की गई। १६ सितम्बर, १९३९ से १९ मार्च, १९४० तक उसने प्राय कुछ भी महत्व का कार्य नहीं किया। २६ सितम्बर १९३९ से अपैल १९४० तक लार्ड जेटलैंड ने कई वक्तव्य दिये। इन वक्तव्यों की ध्वनि

प्रतिक्रियापूर्ण और क्षोभ पैदा करने वाली थी। इनमें इस वात की तारीफ की गई थी कि भारत से सभी वर्गों ने सरकार को सहायता प्रदान की है। यह जित्र-खास तौर पर किया गया कि देशी नरेशों ने धन, सेवाए और सैनिक देने को कह है और देश के सभी भागों से लोगों ने सहानुभूति तथा समर्थन के नदेश भेजें हैं इसके वाद भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा दियें गये वक्तव्य का उल्लेख किया गया और कहा गया कि काग्रेस दोनों देशों के सम्बन्धों के बारे में पेश की गई शर्ते पूरी होने की अवस्था में ही सहयोग करने को तैयार है। लाई जेटलैंड ने लाई सभा की वहस के बीच लाई स्नेल के इन शब्दों को दोहराया कि "काग्रेस के नेताओं ने स्वशासन के अधिकारपूर्ण स्वरूप के सम्बन्ध में अपने दावों को जो फिर से उपस्थित किया है वह स्वाभाविक तो अवश्य है, किन्तु साथ ही असामयिक भी है।" उन्होंने दावों पर जोर डालने के लिए काग्रेस की भर्त्मा भी की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब कि अग्रेज जीवन-मरण के सग्राम में लगे हुए हैं, किसी आन्दोलन के छेडने से उनकी परेशानी वढ जायगी। इसके बजाय उपयुक्त समय आने पर यदि दावों को पेश किया गया तो अग्रेज अधिक चैर्य से काग्रेस की माग सुन सकेंगे।

गांधीजी का उत्तर

गाधीजी ने २६ सितम्बर को वाइसराय से दूसरी मुलाकात की और फिर २८ सितम्बर को उन्होंने लाई जेटलैंड को नीचे लिखा उत्तर दिया —

"लार्ड-सभा में हुई बहस के अवसर पर काग्रेस की निदात्मक तुलनाए करने में जो पुराना जोश दिखाया गया है, उसके लिए मैं तैयार न था। मैं तो यही मानता हूँ कि काग्रेस में सभी आ गये हैं। किसी दूसरी सस्था की निदा किये विना यह कहा जा सकता है कि एकमात्र काग्रेस ही ऐसी गस्था है, जो जाति और धर्म का भेद भुलाकर आधी शताब्दी तक सर्वसाधारण का प्रतिनिधित्व करती रही है। उसका कोई भी स्वार्थ ऐसा नहीं है, जिसका मुसलमानो अथवा रियासती प्रजा के स्वार्थों से विरोध हो। इसी मस्था ने अग्रेजो से अपने इरादे स्पष्ट करने की माग की है। यदि अग्रेज सभी की स्वाधीनता के लिए लड रहे हैं तो उनके प्रतिनिधियों को साफ शब्दों में कह देन। चाहिए कि भारत की स्वाधीनता भी उनके युद्ध-उद्देश्यों में सिम्मिलत है। इस स्वाधीनता के स्वरूप का फैपला खुद भारतीय ही कर सकते हैं। लार्ड जेटलैंड के लिए यह शिकायत करना कि जब ब्रिटेन जीवन-मरण के सग्राम में व्यस्त हो, काग्रेस को अग्रेजो के इरादों के स्पष्टीकरण की माग न करनी चाहिए उचित नहीं हैं। काग्रेस को यह जानने का अधिकार है कि वह जनता से यह कह सकती है या नहीं कि युद्ध के बाद भारत का पद स्वाधीन देश के रूप में होगा अथवा नहीं? इसीलिए अग्रेजो के मित्र की हैसियत से मैं अग्रेज

राजनीतिज्ञों से अपील करता हू कि साम्राज्यवादियों की पुरानी भाषा भूल कर उन्हें उन सभी लोगों के लिए एक नये युग का आरम्भ करना चाहिए, जो अभी तक साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं।"

नेहरूजी का उत्तर

काग्रेस-युद्ध-उप-समिति के अब्यक्ष एक कदम और वढ गये। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति का वक्तव्य सिर्फ भारत की ही तरफ से नहीं, विलक ससार के पीडित लोगो की तरफ से दिया गया है ताकि निराश मानव-समाज को कुछ आजा व्यासके। उन्होने ठीक ही कहा कि लार्ड जेटलैंड उस कल की भाषा मे बोल रहे हैं, जो मर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा भाषण बीस वरस पहले दिया जा सकता था। उन्होने यह भी अभिमानपूर्वक कहा कि हमने सौदा करने की भावना से अपनी मागे नहीं रखी है। हने संसार को स्वाधीनता मिलने और ससार की उस स्वाधीनता म भारत के स्थान का विश्वास होना चाहिए। तभी हमारे और हम से भी अधिक हमारे मस्तिएक और हृदय के लिए युद्ध का कुछ अर्थ हो मकता है, क्योंकि तब हम ऐसे ध्यंय की प्राप्ति के लिए लड सकेंगे, जो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, बल्कि संसार की जनता के लिए भी उपयुक्त होगा। चूकि हम महसूस करते हैं कि वहुत से अग्रेजों के वही आदर्श है, जो हमारे भारत में है, इसलिए हमने उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। लेकिन यदि ये आदर्श है ही नहीं तो हम ठडते किमलिए हैं जिन आदर्शों की खुले शब्दों में घोषणा की जा रही है और जिन पर अमल भी किया जा रहा है उनके लिए स्वाधीन और रजामद हिन्दुन्तान ही लड सकता है। इसके बाद वाइसराय में कम-से-कम ५२ व्यक्ति मिले. जिनमें गांधीजी, राजेन्द्र प्रमाद, जवाहरलाल नेहरू यल्लभ भाई पटेल, नुभाप वाबू, श्री जिन्ना तथा मुसलिम लीग के अन्य नदस्य, नरेन्द्रमटल के अध्यक्ष और भारत के राजनैतिक जीवन के कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति थे।

प्रजा परिपद का वक्तव्य

असिल भारतीय राज्य-प्रजा-परिपद का पिछला अधिदेशन फरवरी १९३९ में लुधियाना में हुआ था और पिछन जदाहरलाल नेहर उसके अध्यक्ष निर्वाचिन हुए थे। इस प्रकार १९३९ के अञ्चूबर में वह काग्रेस की युष्ट उप-समिति तथा देशी राज्य प्रजा परिपद दोनों के अध्यक्ष थे। १९ अक्टूबर को परिपद बी स्थायी निर्मित ने एक वक्तव्य निकाल कर कार्यसमिति के विचारों तथा अधिल भारतीय कार्यस लगेटी के युष्ट विषदक प्रस्ताव का समर्थन किया। वक्तव्य में स्थायी निर्मित ने वहा—"हम भारत की अध्यक्ता तथा समस्त उनता की स्वा-

धीनता में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से सिमिति को सतोप है कि काग्रेस ने इस सकट की घडी मे भारतीय राष्ट्र की लोकतत्रीय स्वाधीनता की माग को अपनी जोरदार आवाज में उपस्थित किया है। इस मिलने वाली स्वाधीनता में रियामती प्रजा बरावरी की हिस्सेदार होनी चाहिए और उसे बरावरी की जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार रहना चाहिए।" इसीलिए काग्रेस नं ब्रिटिश मरकार मे ब्रिटेन के युद्ध और ज्ञान्ति के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पप्टीकरण करने की जो माग की है उसके प्रति समिति अपनी सहमति प्रकट करती है। वक्तव्य मे यह भी कहा गया कि रियासतो के शासको ने जहाँ यूरोप में लोकतत्रवाद की रक्षा के लिए सहायता देने का वचन दिया हे वहाँ उनकी अपनी रियासतो मे नग्न निरकुशता का बोलवाला है। इसलिए समिति ने नरेगों में अनुरोध किया कि वे अपने यहा पूर्ण उत्तरदायी शासन का लक्ष्य स्वीकार करने की घोषणा कर दे और निकट भविष्य मे इस नीति को अधिक-से-अधिक अमल मे लाने का वदन दे। अन्त में स्थायी समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये आधारभूत परिवर्तन नहीं किये जाते और रियासतों का शासन जनता की मर्जी और उसके प्रतिनिधियों की राय से नहीं किया जाता तब तक नरेश प्रजा से सहयोग की आशा नहीं कर सकते ।

वाइसराय का वक्तव्य

अव भारत के भविष्य तथा उसकी वैधानिक उन्नति का सवाल हमारे सामने आता है। इसके उत्तर में वाइसराय ने माटफोर्ड-जासन-सुधार, १९१९ के कानून की प्रस्तावना और लार्ड इविन द्वारा उस प्रस्तावना की व्याख्या से लेकर इस विषय के इतिहास पर प्रकाश डाला। लार्ड इविन ने साफ जव्दों में कहा था कि भारत की उन्नति का लक्ष्य औपनिवेशिक पद है। साथ ही आदेशपत्र का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस साझेदारी को इस सीमा तक बढाया जाय, जिससे भारत स्वाधीन उपनिवेशों के बीच अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। अन्त में वाइसराय ने यह भी कहा कि १९३५ का कानून उस समय प्राप्त होनेवाले अधिक-से-अधिक मतैवय पर आधारित था, किन्तु अब भविष्य में जब कभी भी पार्लामेट द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जायगी तो विचार किया जायगा कि १९३५ के कानून में विभिन्न विस्तार की वाते तत्कालीन परि-स्थित के लिए कहा तक उपयुक्त है। वाइसराय ने यह वादा भी किया कि १९३५ के कानून में स्वाधन करने से पूर्व विभिन्न सम्प्रदायो, दलो और स्वार्थों के प्रतिनिधियो तथा देशी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सलाह-मश्विरा कर लिया जायगा। सक्षेप में, युद्ध की समाप्ति पर सम्राट की सरकार

१९३५ के कानून मे भारतीयों की सलाह से सशोधन करने को तैयार होगी। इसके उपरान्त वाइसराय ने बताया कि युद्ध के सचालन से भारतीय लोकमत

इसक उपरान्त वाइसराय न बताया कि युद्ध के संचालन से मारताय लोकमत का सम्बन्ध कायम रखने के लिए सलाहकार संगठन स्थापित किये जायगे। यहा यह बता देना आप्रसंगिक न होगा कि यह संगठन २० महीने बाद २२ जुलाई १९४१ को कायम किया गया था।

मंत्रिमंडलों के इस्तीफ़ें

पार्लामेंटरी उप-समिति ने कार्यसमिति की अनुमित से मित्रयो तथा प्रातो के काग्रेसी दलो के मार्ग-प्रदर्शन के लिये निम्न आदेश जारी किये —

"कार्य-समिति के प्रस्ताव द्वारा प्रातों की काग्रेसी सरकारों से इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। ये इस्तीफें असेम्बलियों की उन बैठकों के बाद दिये जाने चाहिए, जो महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाई गई है, किंतु ३१ अक्टूबर, १९३९ तक सभी इस्तीफें दे दिये जाने चाहिये।

"मध्य भारत तथा उडीसा की प्रातीय असेम्बलिया नवम्बर के आरम्भ में बुलाई गई है और इन प्रातों की सरकारें उनकी बैठक होने के बाद तक अपने पदों

पर रह सकती है।

"असेम्बलियों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौसिलों के अध्यक्ष तथा सदस्य अपने पदों पर बने रहेगे। इस अवसर पर सिर्फ मित्रयों तथा पार्लामेटरी सेक्रेटरियों ही से इस्तीफा देने की आशा की जाती है।

"असेम्बलियो मे युद्ध-उद्देश्यो के सबध मे जो प्रस्ताव पेश किया जायगा उसमे नई परिस्थिति के कारण उपयुक्त सशोधन भी उपस्थित होने चाहिए।"

मद्रास, मध्यभारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, वबई, उडीसा और सीमा प्रांत की प्रांतीय असेम्बलियो में प्रधान मित्रयो ने निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया —

"यह असेम्बली इस बात पर अफसोस जाहिर करती है कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच होनेवाली लड़ाई में ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी जनता की इच्छा जाने बिना हिस्सेदार बना दिया है और उसने ऐसी कार्रवाई की है और ऐसे कानून पास किये हैं, जिनके कारण प्रातीय सरकारों के अधिकारों तथा कार्यों में कमी होती है।

सरकार की नीति से सहमत नहीं हो सकती।"

प्रधान मंत्रियो ने यूरोप में युद्ध छिडने और उसके परिणामस्वरूप भारत मे

उत्पन्न हुए सकट के समय से कार्यसमिति द्वारा समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाला। असेम्बलियों में मुस्लिम लीग दल ने प्रस्ताव के सबध में एक सशोधन उपस्थित किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

सात प्रातो मे प्रस्ताव अपने मूल रूप मे भारी वहुमत से पास हो गया। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रात मे प्रस्ताव थोड़ सशोधनों के साथ, जिन्हें काग्रेस दल ने स्वीकार कर लिया, पास हुआ। इन आदेशों के अनुसार प्रातीय मित्रमडलों ने एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया। पन्द्रह दिनों के भीतर सभी मित्रमडलों ने इस्तीफें दे दिये। मबसे पहले इस्तीफा मद्रास के मित्रमडल ने दिया था।

१७:

इस्तीफ़ा देने के बाद: १६४०

स्वाधीनता की प्रगित में काग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण मिलल तय कर ली। आठो प्रान्तों में प्रान्तीय मित्रमंडलों ने एक साथ इस्तीफे दे दिये। पचास वर्ष की योजनाओं और तैयारियों के बाद जो कला-कृति तैयार हुई थी, वह एक ही घडाके में तहस-नहस हो गई। क्या इसे काग्रेस फिर से बना सकेगी? क्या फिर कभी काग्रेस शिक्त-सम्पन्न हो सकेगी और हो सकेगी तो कैसे? ये सवाल उस समय शत्रु-मित्र सभी की जवान पर थे। फिर भी काग्रेस को ऐसी आशकाए न थी। उसे आगे आने वाले कष्टो और किठनाइयों का पूरा-पूरा ज्ञान था। ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के लिए कोई समस्या न थी। अलवत्ता हमार दो अन्तरिक शत्रु अवश्य थे काग्रेस अपने प्रति मुस्लिम लीग के रुख का मुकाबला कैसे करेगी और काग्रेस किस हद तक लोगों को अहिसा पर अमल करा सकेगी, जिसका पालन स्वय काग्रेसजनों की ओर से अनिश्चित-सा प्रतीत होता था।

वाइसराय का वक्तव्य

पहली नवम्बर को राजेन्द्र बाबू के साथ गाघीजी को तीसरी बार वाइसराय से मुलाकात करने के लिए आमित्रत किया गया। श्री जिन्ना भी वाइसराय-भवन में उपस्थित थे। गाघीजी और श्री जिन्ना अलग-अलग भी एक दूसरे से मिले। यह बातचीत न सिर्फ नाकामयाब ही रही, बल्कि दोनो पार्टियो के साथ बातचीत करने से वाइसराय को इस समस्या के सम्बन्ध में ऐसे नये विषय उठाने में मदद मिली,

जो पहली बार ही उठाए गए थे और उनसे नई पेचीदिगया और परेशानिया पैदा हो गई थी। वाइसराय ने अपने मिलने वालो के सामने ठोस और लिखित रूप में अपने प्रस्ताव रखे। अपने ५ नवम्बर के वक्तव्य में उन्होने जो कुछ कहा वह सक्षेप में इस प्रकार है —

"३ सितम्बर को युद्ध की घोषणा हुई थी। उसी रात के अपने एक ब्राडकास्ट में मैने सभी दलों और सभी वर्गों से इसके सचालन में सहयोग प्रदान करने की अपील की थी। अगले दिन मैने शिमला में गाधीजी तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि श्री जिन्ना से तत्काल मुलाकात की। नरेन्द्र मडल के चासलर से भी मिला। इसके बाद समस्या विचार-विनिमय करने के लिए काग्रेस और मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटियो के सामने रखी गई। काग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक १५ सितम्बर को हुई। उसने खुले शब्दो मे नाजी आक्रमण की निन्दा की और ब्रिटिश सरकार से असदिग्ध शब्दों मे अपने युद्ध-उद्देश्य घोषित करने, उन्हें भारत पर लागू करने और तत्काल उन्हें कार्यान्वित करने की माग की। इसी प्रकार मुस्लिम लीग की वर्किग कमेटी ने भी १८ सितम्बर को ऐसा ही आश्वासन मागते हुए कहा, "यदि मुसलमानों की ओर से पूर्ण, प्रभावशाली और सम्मानपूर्ण सहयोग अपेक्षित है तो उनमे 'सुरक्षा और सतोष' की भावना पैदा करनी होगी। इसके अलावा उसने काग्रेस-प्रान्तो में मुसलमानो की परिस्थिति का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही उसने वर्तमान विधान में किसी भी परिवर्तन और उसकी स्वीकृति तथा समर्थन के लिए मुसलमानो से पूरा-पूरा सलाह-मशविरा लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर मैने पुन गाधीजी, श्री जिन्ना और नरेन्द्र मडल के चासलर से सपर्क स्थापित किया। मैने यह मानकर कि भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलो के दृष्टिकोणो में स्पष्टरूप से मतभेद हैं, फैसला किया कि मुझे यहा के लोगो की विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखकर मैने सभी दलो, सप्रदायो और हितो के ५० से ऊपर प्रतिनिधियो से मुलाकात की। अभी यह बात चल ही रही थी कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने १० अक्टूबर को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमे वर्किंग कमेटी की माग को दोहराते हुए सम्राट् की सरकार से युद्ध और शान्ति के उद्देश्यो पर प्रकाश डालते हुए एक वक्तव्य देने का अनुरोध किया। कमेटी ने भारत को स्वाधीन घोषित कर देने की भी माग की और यह भी कहा कि उसे तत्काल अधिक-से-अधिक सीमा तक यह पद दे दिया जाय।

'मैने १८ अक्टूबर को सम्राट् की सरकार की ओर से एक घोषणा की। इसमें सबसे पहले इस बात पर जोर दिया गया कि भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। दूसरे, सम्राट् की सरकार लड़ाई के बाद भारतीय नेताओं के परामर्श से वर्तमान विधान की योजना पर पुनिवचार करने के लिए तैयार है। तीसरे, सम्राट् की सरकार युद्ध-संचालन में भारतीय जनता के सहयोग को वहुत

महत्व देती है, और इसी उद्देश्य से उसका विचार एक सलाहकार समिति स्थापित करने का है, जिसकी विस्तृत वातो का फैसला विभिन्न दलो के नेताओं से सलाह-मशविरा कर लेने के वाद होगा। मेरे वक्तव्य के प्रकाशन के वाद काग्रेस विका कमेटी ने २२ अक्टूबर को एक प्रस्ताव पास कर मेरे वक्तव्य को पूर्णत असतोप-जनक वताते हुए प्रान्तो में काग्रेस मित्रमङलो से पद-त्याग करने को कहा। उसी दिन मुस्लिम लीग ने भी कुछ आशकाओं का निवारण करने और वक्तव्यों के सम्बन्ध मे पूर्ण स्पष्टीकरण करने की माग की। इसके बाद मैने गांधीजी, डा॰ राजेन्द्रप्रसाद और श्री जिन्ना को १ नवम्बर को भेट करने के लिए आमित्रत किया और हमने सारी स्थिति पर खुले दिल से विचार-विनिमय किया। मैने उन्हें वता दिया कि केन्द्र मे सहयोग के मोमले मे यदि हम सलाहकार समिति की योजना से आगे नही वढ सके है तो इसका कारण यह हे कि दोनो प्रमुख सप्रदायो मे पहले से कोई ऐसा समझौता मौजूद न था, जिससे वे केन्द्र में मेलजील के साथ काम कर सकते। मैने यह भी कहा कि २२ अक्टूबर को काग्रेस वर्किंग कमेटी और मुस्लिम लीग की ओर से जो घोपणाए की गई है, उनसे साफ तौर पर यह पता चलता है कि इन दोनो वडे दलो के वीच गहरा मतभेद है। इन परिस्थितियो मे मैने अपने मुला-कातियों से अनुरोध किया कि वे आपस में बैठकर एक अस्थायी आधार पर विचार-विनिम्य कर ले जिससे कि बाद में एक दूसरे की सहमित से वे ऐसे प्रस्ताव रख सके, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र मे गवर्नर-जनरल की परिपद् मे कुछ विस्तार हो सके।

"मैने जिन वातो पर विचार करने का सुझाव रखा था उनपर विचार-विनिमय हो चुका है। परन्तु इसका परिणाम मेरे लिए अधिक निरागापूर्ण रहा है। दोनो प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों में बुनियादी मामलों के बारे में अब भी पूर्ण मतभेद विद्यमान है। जब से मैं भारत में आया हूँ, मुझे सब से अधिक चिता एकता स्थापित कराने की रही है। इसलिए मैं समस्त देशवासियों से, बड़े राजनैतिक दलों के नेताओं और उनके अनुयायियों से, अनुरोध कहँगा कि यदि हमें अपनी कठिनाइयों को पार करना है और अपने अभीष्ट परिणाम पर पहुँचना है तो आप मेरी मदद कीजिए। आपकी मदद की मुझे इस समय बड़ी आवश्यकता है।"

महारमा गांधी का उत्तर

महात्मा गाधी ने वाइसराय के उक्त वक्तव्य के उत्तर में कहा—"मैं इसका स्वागत करता हूँ कि वाइसराय महोदय पराजय से हार नहीं मानते हैं। मैं उनके इस दृढ निश्चय का भी स्वागत करता हूँ कि वह एक ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए कटिवद्ध हैं, जिसे सुलझाना असभव-सा हो गया है। समस्या का हल ढूँढ निकालने के सम्बन्ध में वाइसराय महोदय की व्यग्रता में मैं पूरी तरह से भागीदार हूँ।

इसलिए सामान्य उद्देश्य में सहयोग प्रदान करने की प्रतीक्षा किये बिना ही मैं यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि जब तक भारत के बारे में युद्ध-उद्देश्यों की कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाती, जो स्वीकार की जा सके तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। यदि इस बुनियादी सत्य को स्वीकार करने का समय अभी नही आया है तो मै आग्रह करूँगा किं समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्न हमें फिलहाल मुल्तवी कर देना चाहिए। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि भारत की इच्छाओ का खयाल किये बगैर ब्रिटेन अपनी भारतीय नीति के बारे मे अपने इरादो की घोषणा कर दे। एक बार दासता के बधनों से भारत के मुक्त और स्वतंत्र हो जाने की घोषणा कर देने के बाद अस्थायी हल भी आसानी से निकल आयेगा। उस हालत मे अल्पसंख्यको के अधिकारों के सरक्षण का प्रश्न भी आसान हो जाएगा। अल्प-सख्यको को सरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, क्रमश. नही, बल्कि पूर्णरूप से और एकबारगी ही। स्वतत्रता के किसी भी अधिकार-पत्र का कोई महत्व नही होगा यदि उससे अल्पसंख्यको को भी उतनी ही स्वाधीनता नही मिलती जितनी कि बहुमत को। विघान-निर्माण मे अल्पसंख्यक भी पूर्णरूप से भागीदार होगे। यह बात उन प्रतिनिधियों के विवेक और सूझ-बूझ पर निर्भर करेगी, जिन्हें विधान तैयार करने का पवित्र कार्य सौपा जाएगा। ब्रिटेन ने अब तक अपनी ताकत को अल्पसस्यको को बहुसख्यको के विरुद्ध खडा कर के बनाये रखा है। किसी भी साम्राज्यवादी पद्धति मे ऐसा होना अनिवार्य है और इस प्रकार उनमे कोई समझौता हो जाना असभव बना दिया गया है । अल्पसख्यको के सरक्षण का कोई हल निकालने की जिम्मेदारी स्वय विभिन्न दलो पर होनी चाहिए। जब तक ब्रिटेन यह समझता है कि इसकी जिम्मेदारी उसके कन्धो पर है तब तक वह भारत को परतंत्र बनाए रखने की आवश्यकता भी अनुभव करता रहेगा।

"वाइसराय की ईमानदारी में विश्वास करते हुए, जैसा कि मैं करता हूँ, मै अपने सहयोगियों से धैर्य रखने का आग्रह करूँगा। एक तो जब तक (१) वाइसराय समझौता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, (२) मुस्लिम लीग की ओर से मार्ग मे रुकावट पैदा की जाती है और (३) काग्रेसजनों में एकता और अनुशासन की कमी बनी है तब तक सिवनय-कानून-भग-आदोलन नहीं शुरू किया जा सकता।"

राष्ट्रं के प्रतिनिधियों की बैठक

गाधीजी के मैत्रीपूर्ण और आकर्षक वक्तव्य के साथ-साथ काग्रेस और युद्ध-समितियों के अध्यक्षों ने भी अपने-अपने उत्तर दिये। राजेन्द्र बाबू ने इस प्रश्न को और भी स्पष्ट और असदिग्व शब्दों में व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार पर यह दोषारोपण किया कि वह "किसी भी ऐसे विधान को, जिसे सभी भारतीय, जिनमें

अल्पसल्यक भी शामिल हैं, तैयार करेगे और जिसमें अल्पसल्यकों के लिए सरक्षण भी रहेगे, स्वीकार करने और उसे वैधानिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं है।" इस सबध में पिंडत जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य भी कम ठोस और निर्णयात्मक नहीं था। उन्होंने वाइसराय के वक्तव्य पर आक्चर्य प्रकट किया और बताया कि श्री जिन्ना और मेरे दरिमयान यह समझौता हुआ था कि हम जल्दी ही किसी सुविधाजनक समय पर साप्रदायिक प्रक्त पर पूरी तरह से सोच-विचार करेगे। जब तक राजनैतिक कठिनाई दूर नहीं हो जाती तव तक इसका वाइसराय के प्रस्तावों पर कोई प्रभाव नहीं पडता। इसलिए इस सम्बन्ध में इस पर कोई विचार नहीं किया गया।

वास्तव मे यह एक ऐसा प्रश्न था, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। इसलिए काग्रेस वर्किंग कमेटी और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के रूप मे राष्ट्र के प्रतिनिधि एक बार एकत्र हुए। इस बार यह नवम्बर को इलाहाबाद में हुई। प्रतिनिधियों ने देश के सामने अपनी सुनि-रिचत राय रखी। निर्णय में यह कहा गया कि युद्ध की गतिविधि, ब्रिटिश और फेच सरकार की नीति और खासतीर से वह घोपणा, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के सम्वन्ध में की गई है, यह जाहिर करती है कि वर्तमान युद्ध सन् १९१४-१८ के महायुद्ध की भाति साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए लडा जा रहा है और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य इसी तरह कायम रहेगा। इसलिए ऐसी लडाई और नीति से काग्रेस सहयोग नहीं कर सकती और न वह यह बात ही देख सकती है कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए उसके साधनों का शोपण किया जाय। मुख्य प्रश्न के बारे में ब्रिटिश सरकार की ओर से उठाया गया साप्रदायिक प्रश्न और देशी राज्यो की समस्या बिल्कुल वेकार थे। स्पष्टत एक नैतिक प्रश्न के बारे मे ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने इरादो की घोपणा न करने और वेमतलव के प्रश्नो की आड लेने की उसकी नीति से यही जाहिर होता था कि वह भारत में साम्राज्यशाही प्रभुत्व देश के प्रतिकियावादी तत्वो की सहायता से बनाए रखना चाहती है। इस सम्बन्ध में काग्रेस के प्रधान ने ४ नवम्वर १९३९ को वाइसराय को जो जवाव दिया था, उसे स्वीकार किया गया और उसका समर्थन किया गया। साथ ही ब्रिटेन की नीति से साम्राज्यवाद का रग हटा देने के लिए और काग्रेस के लिए भविष्य में सहयोग प्रदान करने के सवाल तथा साप्रदायिक एव अन्य कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से विधान परिषद् का विचार और उसकी योजना को आवश्यक बताया गया । इसके बाद सविनय अवज्ञा के लिए तैयारिया करने की आवश्यकता पर पर्याप्त जोर दिया गया, जिसकी सच्ची कसौटी यह थी कि काग्रेसजन स्वय चरखा चलाए, मिल के कपड़ों की जगह खादी को प्रोत्साहन दे और विभिन्न सस्थाओ में मेल-मिलाप स्थापित करना अपना कर्तव्य समझे।

कार्यसिमिति का रुख

१९३९ के अन्त मे वर्किंग कमेटी ने देश की राजनैतिक परिस्थिति का सिहावलोकन किया। उस समय वातावरण अत्यन्त क्षुव्ध था। अल्पसल्यको का प्रश्न सबसे आगे था और उनमे ,सतोप की भावना पैदा करना साफ तौर से काग्रेस का कर्तव्य था। उनकी तवीयत में सदेह था और यह सदेह काग्रेसी सरकारों के शासन के प्रति उनके आरोपों में से पैदा हुआ था। वास्तव में मुसलमानों के विशिष्ट स्वार्थो-धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक-के सरक्षण के लिए जो आश्वासन जरूरी था, काग्रेस देने को तैयार थी, लेकिन क्या इस प्रकार की घोपणा से अवसर-वादी अल्पसंख्यको के हाथ मजबूत नहीं हो जायेंगे अथवा और नये अल्पसंख्यक नहीं पैदा हो जायेंगे और उनमें आन्दोलन करने की और भी दृढ भावना नहीं भर देगे? कारण कि अपने आन्दोलन में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिल चुकी थी। यदि आप किसी को कुछ रियायते देगे तो उनकी पिपासा और भी बढ जाएँगी, जैसे कि खाने के साथ-साथ भूख भी वढ जाती है। यदि ऐसा नही होना चाहिए तो एक और उपाय यह हो सकता या कि साप्रदायिक प्रश्नो का जिक्र ही न किया जाय-भले ही वह फिलहाल के लिए ही क्यो न हो। समय वडी तेजी से बदल रहा था और उसके साथ परिस्थितिया भी। जो हो, काग्रेस के प्रस्तावों में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक और सास्कृतिक हितो का उल्लेख किया गया था। राजनैतिक शब्द इसमे शामिल नही किया गया, क्योंकि विधान-परिषद् में भी हमें उन्हें सिर्फ ये ही सरक्षण देने थे—राजनैतिक नही। इस प्रकार का कोई समझौता करना हिन्दू-महासभा जैसी सस्था के उपयुक्त हो सकता था, लेकिन यदि काग्रेस मित्रमडली अथवा नौकरियो मे ऐसी राजनैतिक रियायते देने लगी तो वह स्वराज्य की प्रगति में देश को गलत राह पर ले जाएगी। धारासभाओं में विभिन्न दलों का सयुक्त बहुमत होना चाहिये, जिनका निर्वाचन सयुक्त-निर्वाचन-पद्धति के आधार पर हुआ हो और जिनमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख और जैन सभी राष्ट्रवादियों के रूप में हो, वरना काग्रेस एक भारी गलती करेगी और तब उसके लिए पीछे कदम हटाना असभव हो जाएगा। यदि काग्रेस का ऐसा विश्वास नही है तो वेहतर होगा कि वह बियाबान मे चली जाय।

इस समस्या पर आतिरक दृष्टि से विचार करने पर काग्रेस ने अनुभव किया कि जिस सेनापित को उसका नेतृत्व करना है उसके सामने अभी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अग्रेज गलती पर है और उसकी यह कोशिश थी कि वह अग्रेजों की इस 'गलती' को मुसलमानो और सारे ससार के सामने खोलकर रख दे। गाधीजी का तरीका 'आजादी, आजादी' चिल्लाने का नहीं था। उनकी कार्य-पद्धित या कारीगरी यह थी कि उनके किये-कराये काम से 'आजादी' का आभास होता था। हाँ, 'आजादी' शब्द की रट उनमें नहीं होती थी। तात्पर्म यह कि इस प्रकार काग्रेन कमेटी जो प्रस्ताव पान करे उससे सिवनप्र-भग आन्दोलन की भूमि तैयार हो जानी चाहिये और यह प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए, जिसमे लार्ड जैटलैण्ड की उपेक्षा भी न की गई हो, क्योंकि देश में प्रचलित शासन-प्रणाली इन दोनों में ही मूर्तिमान् थी। जब गायीजी ने सर स्टैफर्ड किप्स से लम्बी वातचीत की तब यह सब उनके दिमाग में था।

स्टैफर्ड की वर्घा-यात्रा

ब्रिटिश प्रजातत्र मे उसके कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्नैतिक पदो को प्रमुख वकीलो ने ही सुगोभित किया है। लार्ड रीडिंग, लार्ड वर्कन हेड, सर जॉन साइमन, श्री एस्विवय, श्री लायड जार्ज (सालीसिटर), लार्ड सेंकी-ये सभी अरने समय के प्रमुख वकील थे। सर स्टैफर्ड-क्रिप्स भी उसी वर्ग के प्रहरान वकीलों में से थे, और १९३९ के पतज्ञड में जब वह वर्वा गए, उनकी गणना व्रिटेन के प्रमुख वकीलों में होती थी। लन्दन से प्रस्यान करने से एक सप्ताह पहले उन्होने वकालत छोड दी थी। उसी समय से वह अपना सारा समय सार्वजनिक जीवन में लगा रहे थे। उन्होंने वताया कि हाल में ब्रिटेन के लोगो की सहसा ऐसी धारणा हो गई है कि भारत से समझौता कर लिया जाय और भारतीयों की आका-क्षाओं को पूरा कर दिया जाय। ऐसे सकट के समय में ब्रिटेन भारत को अपना विरोधी नहीं वनाना चाहता। उन्होने एक और दिलवस्प वात यह भी कही कि भारत की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जी झ ही यहां एक सर्वेदलीय प्रति-निधि-मडल आ रहा है। उनके इस कथन से क्या हम यह खेयाल कर सकते थे कि यह प्रतिनिधि-मडल एक जांच-पडताल करने वाले कमीशन के रूप में भेजा जा रहा था ? वास्तव में काग्रेस को ऐसे सर्वदलीय प्रतिनिधि-मडलो के सम्बन्ध में काफी सन्देह और अविश्वास था। उसने स्टैफर्ड किप्स का एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वागत किया जिसने सन को सन और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत थी। सर्वदलीय प्रतिनिवि-मंडल तो सिर्फ लीपापोती का काम करेगा । साइमन कमीशन भी तो सभी दलो का एक ऐसा ही प्रतिनिधि-मडल था। वास्तव में यह समय टालने की एक चाल थी। भारत की माग थी कि तुरन्त ही युद्ध के उद्देशों की घोवणा कर दी जाय और उन्हें ईमानदारी के साथ भारत पर लागू किया जाय। इसके विपरीत सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल भेजने की योजना एक ऐसी चाल थी, जिसके जिये ब्रिटिश राजनीतिजो को पार्लिमेट में सर सेम्युअल होर द्वारा अपनाई गई इस स्यिति को-जिसने न तो साफ तौर पर 'ना' ही की गई थी और न प्रकट रूप से 'हा' ही की गई थी-एक व्यावहारिक रूप देना था। इगलैण्ड दोनो में से एक भी बात नहीं कहना चाहता था; क्योंकि वह कोई बड़ी कीमत देकर

भारत की न तो सद्भावना हासिल करना चाहता था और न उसे खोना चाहता था।

स्टैफर्ड किप्स ने गाधीजी, जवाहरलाल और सरदार पटेल के साथ काफी लम्बी बातचीत की और इगलैण्ड वापस जाते हुए वह गाधीजी-द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत और लम्बा मसविदा भी अपने साथ लेते गये। इसके साथ ही सर स्टैफर्ड की छोटी-सी यह हवाई यात्रा भी खत्म हो गई।

कार्यसमिति की बैठक

गाधीजी का ऐसा खयाल था कि यद्यपि हम समझौते से काम चला सकते हैं, तथापि यह समझौता अग्रेजो और हिन्दुओं के दरमियान नहीं हो सकता। यह तो हिसा होगी। यही वजह थी कि वह अपने ही तरीके की विघान-परिपद् की कल्पना कर रहे थे। जहां तक संविनय-अवज्ञा आन्दोलन का प्रश्न था उनका खयाल था कि काग्रेस जनों को देश की जनता को उनकी इच्छा से अपने साथ लेना होगा, मशीन के कल-पुर्जे की तरह नही। उनका तो यह भी खयाल था कि काग्रेसी सदस्यो को असेम्बली में जाना और उसके द्वारा काम करना चाहिए और काग्रेस की सदस्यता के सम्बन्ध में सबकी एक राय होनी चाहिए। यह ठीक है कि काग्रेस मित्रमडल छोडकर बाहर मैदान में आई थी, लेकिन इसकी वजह यह थी कि हमारी ताकत घटती जा रही थी, कारण कि ब्रिटिश सरकार अपने उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल कर रही थी। केन्द्रीय असेम्बली से हम उसी हालत में बाहर आये जब हमने महसूस किया कि हम अपनी शक्ति बढाने की बजाय उसे घटा रहे है। इसका मतलब यह नहीं था कि हम सभी चीजे निषिद्ध करार दे रहे थे। गांधीजी सब प्रकार की दोस्ती बनाए रखना चाहते थे। अगर दूसरा पक्ष शत्रु और विपाक्त बनता जा रहा था तो इसका मतलब यह था कि वह संविनय-भग को निमत्रण दे रहा था। उसके चाहते ही हम उसके लिए उद्यत थे। जो लोग १९३९ के अन्त में राष्ट्र की नौका को खे रहे थे, उनके मस्तिष्क मे ऐसे ही विचार उठ रहे थे। १८ दिसम्बर को कार्यसमिति की बैठक हुई और उसने भारतमत्री की उन घोषणाओं पर खेद प्रकट किया, जिनमे उन्होने साप्रदायिक प्रश्न को उठाकर प्रधान समस्या पर परदा डालने की कोशिश की थी और जनता का घ्यान इस वास्तविक तथ्य से हटाने का प्रयत्न किया था कि ब्रिटिश सरकार अपने युद्ध उद्देश्यों की घोषणा करने में असफल रही है, खासकर भारत की स्वतत्रता के बारे में। जब तक विभिन्न दल तीसरे दल पर आश्रित थे तव तक साप्रदायिक प्रश्न कभी भी सन्तोषजनक रूप से नहीं हल हो सकता था। विटिश सरकार चूँकि यहा से हटना नहीं चाहती थी अथवा शक्ति नहीं छोडना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वह विभिन्न दलों में परस्पर फूट डालने के उद्देश्य से साप्रदायिक प्रश्न का सहारा ले। अत सिर्फ विधान-परिषद् ही एकमात्र ऐसा मार्ग रह गया था, जिसके जिरये कोई अन्तिम समझौता हो सकता था। काग्रेस तो यह वात वहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी थी कि सवद्ध अल्पसख्यको के अधिकारो की इस तरह से रक्षा होनी चाहिए कि उन्हें सन्तोप हो जाय और यदि इतने पर भी मतभेद रह जाएँ तो उनका निपटारा एक निष्पक्ष पच द्वारा करा लिया जाय।

राष्ट्र के नाम काग्रेस कार्यसमिति ने अन्तिम सदेश वर्ष के अन्त में सक्षिप्त और जोरदार शब्दों में दिया था। यह सदेश वास्तव में राष्ट्र को कमर कस लेने और आगामी लड़ाई के लिए किटवढ़ हो जाने का था। यह लड़ाई की तैयारी का आह्वान था। यही आह्वान स्वतत्रता-दिवस मनाने के अनुरोध और उस दिवस की प्रतिज्ञा में शामिल कर लिया गया था, जो २६ जनवरी के दिन नये सिरे से पढ़ी जानी थी। इसलिए इस आशय का प्रस्ताव पास किया गया —

"काग्रेस कार्यसमिति सब काग्रेस कमेटियो, काग्रेसजनो और मुल्क का घ्यान इस बात की ओर आकिपत करती है कि २६ जनवरी, १९४० को व्यवस्थित रुप से सजीदगी के साथ बाजादी का दिन मनाने की आवश्यकता है। १९३० से ही यह दिन देशभर में वरावर मनाया जा रहा है और हमारी स्वाधीनता के सग्राम में इसका खास स्थान बन गया है। चूंकि इस समय भारत और ससार एक सकटपूर्ण घड़ी में से गुजर रहे हैं और हमारी आजादी की लड़ाई और भी तीव्र रूप में जारी रहने की सम्भावना है, इसलिए इस बार इस दिन के मनाने का एक खास महत्व है। इसके कारण उसे इस तरह मनाना चाहिए कि न सिर्फ राष्ट्र का आजादी लेने का सकल्प ही उससे जाहिर हो, बिल्क लड़ाई की तैयारी और अनुशासन में रहकर काम करने की प्रतिज्ञा की भी घोषणा हो जाय।"

स्वतत्रता-दिवस की प्रतिज्ञा इस प्रकार थी ---

"हमारा विश्वास है कि ससार के दूसरे लोगो की भाति भारतीय जनता का भी यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे आजादी मिले। वह अपनी मेहनत का फल भोगे और जीवन के लिए आवश्यक चीजे उसे इतनी मिले, जिससे उसे अपने विकास की पूरी सुविवा हो जाय। हमारा विश्वास है कि कोई सरकार प्रजा के इन अधिकारों को छीने और उसे सताए तो प्रजा का भी यह हक हो जाता है कि वह उस सरकार को वदल दे या मिटा दे। हिन्दुस्तान में अग्रेजी सरकार ने भारतीय प्रजा से उसकी आजादी ही नहीं छीनी है, विलक जनता के शोषण पर अपनी वुनियाद रक्खी है और हिन्दुस्तान को आर्थिक, राजनैतिक, सास्कृतिक और आव्यात्मिक दृष्टियों से तवाह कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अग्रेजों से नाता तोडकर पूर्ण स्वराज्य हासिल करना ही चाहिए।

"हमारा यकीन है कि आमतौर पर किसी भी अहिसात्मक कार्रवाई के लिए और खासकर अहिसात्मक सविनय-भग जैसी सीधी लडाई के लिए खादी, कौमी एकता और अस्पृश्यता निवारण के रचनात्मक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सचालन आवश्यक है। हम जात-पात या धर्म का भेदभाव छोडकर अपने देशवासियों में सद्भाव फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगे। हमारे धार्मिक विश्वास भले ही अलग-अलग हों, हम आपसी व्यवहार में भारतमाता की सन्तान की भाति काम करेगे, क्योंकि हम सदका एक ही राष्ट्र है और सब के राजनैतिक तथा आर्थिक हित समान है।

"हम प्रतिज्ञा करते है कि काग्रेस के सिद्धान्तो और नीतियो का कडाई के साथ पालन करेगे और भारत की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए जब कभी भी काग्रेस हमे

बुलाएगी, हम सदा उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेगे।"

केन्द्रीय असेम्बली में शामिल होने के सवाल पर समिति ने फैसला किया कि जहां अपनी सीटों को कायम रखने के लिए उपस्थित होना जरूरी हो, वहां उपस्थित रहा जाय, अन्यथा अनुपस्थित जारी रक्खी जाय।

वाइसराय का वक्तव्य

हर वार जब कभी काग्रेस की कार्यसमिति ने कोई घोपणा की और अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया तव उसके बाद या तो वाइसराय ने अथवा भारतमंत्री ने या दोनो ही ने कोई-न-कोई घोषणा की। परन्तु किसी भी हालत में सरकारी घोपणा काग्रेस द्वारा समय-समय पर पास किये गये प्रस्तावो या वक्तव्यो मे उठाए गए प्रवनो का उत्तर नहीं होता था। व्रिटिश सरकार के इन प्रतिनिधियो की यह आदत-सी वन गई थी कि वे एक ही राग अलापते रहते थे। यह राग कभी तो कर्णकटु और तीक्षण होता था और कभी उसमें से मधुर झकार सुनाई देती थी। यह मानना पडेगा कि १० जनवरी १९४० को वाइसराय ने वम्वर्ड के 'ओरियेण्ट नलव' में जो भाषण दिया उसका स्वर अव तक के भाषणों की अपेक्षा कम कडा, कम तीक्ष्ण था। पिछले महीने की घटनाओ और उनके फवलस्हप होने वाले परिवर्तनो का उल्लेख करने के बाद वाइसराय ने यह विश्वास प्रकट किया कि प्रान्तीय स्वायत्त-शासन के सचालन में जो रुकावट या गतिरोव पैदा हो गया है, वह अस्थायी होगा और जल्दी ही विवान का सचालन सभव हो सकेगा। केन्द्र में मित्रयों का सहयोग प्राप्त न कर सकने, नामान्य सरकार के रूप में रियासतों का सहयोग न पाने, सुनिश्चित आधार पर सभी अल्पसंख्यको का प्रतिनिधित्व हासिल न कर पाने और भारत की एकता को वनाए रखने की असमर्थता पर खेद प्रकट करने के बाद वाडनराय ने कहा कि "भारत में उनका उद्देश्य वेस्टिमिस्टर के कानून के तरीके का औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है।" आगे चलकर उन्होंने एक वार फिर मुस्लिम और अछूत अल्पसस्यको का रोना रोया। उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के प्रति न्याय होना चाहिए और सम्राट् की सरकार ऐसा करने पर कटिवढ़ है। लेकिन उन्होने विभिन्न दलों के मित्रो

से अनुरोध किया कि वे यह विचार कर देखे कि क्या वे इकट्ठे नहीं हो सकते और आपस में कोई समझौता नहीं कर सकते। जहां तक उद्वेय का सम्बन्ध है, उन्होंने आश्वासन दिया कि सम्राट् की और उनकी सरकारे वर्तमान परिस्थित और औपनिवेशिक स्वराज्य मिलने की अवधि को कम-से-कम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। वाइसराय के भाषण का अन्तिम पैरा न केवल आग्रहपूर्ण विक करणाजनक भी था। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आपके सामने हैं। राजनैतिक दलों और उनके नेताओं पर वहुत भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उन्होंने भूतकाल में मेरी मदद की है और आज मैं उनसे फिर अपनी और भारत की सहायता करने की प्रार्थना करता हूँ।

यह जाहिर है कि मघुर और आकर्षक भाषा का प्रयोग करने पर भी वाइसराय के भाषण का भाव पहले जैसा ही कठोरतम था। उनके भाषण की मुख्य वातें थी अल्पसंख्यक, मुस्लिम और परिगणित जातिया, सरकारी आइवासन, विभिन्न दलों के बीच न्याय और आपसी समझौता, यहा तक कि इस राग की तर्ज भी वहीं पुरानी थी। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि ओरियण्ट-क्लव के भाषण के तुरन्त बाद ही वाइसराय ने एक भाषण वडौदा में दिया, जिसमें उन्होंने लोगों का घ्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि जल्द-से-जल्द औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने का तरीका भारत-विधान की सघ-योजना थी, जो उस समय खटाई में पड़ी थी। उनका खयाल था कि यदि सभी सम्बद्ध वर्ग उसे स्वीकार कर ले तो उससे बहुत-सी समस्याए आसानी से मुलझ जाएगी।

वाइसराय से गांधीजी की भेंट

कांग्रेस के प्रधान ने १४ जनवरी के अपने उत्तर में यह वात स्पष्ट कह दी कि हमारा घ्येय वेस्ट मिस्टर के किस्म का औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं, विशुद्ध स्वाधीनता है। विभिन्न दलों के नेता देश की सारी आवादी के विश्वस्त प्रतिनिधि नहीं हैं और इन्हीं परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए कांग्रेस ने खूब सोच-विचार के बाद विधान-परिपद् को इस समस्या का एकमात्र मार्ग वताया है। निश्चय ही यह कोई 'निकटतर मार्ग' नहीं है, क्योंकि इसके अन्तर्गत जिस कार्यप्रणाली पर अमल होगा और उसके बारे में जैसी कार्रवाई की जायगी, उससे तो यह मार्ग विशेष रूप से लम्बा हो जाएगा। इसके बाद वाइसराय ने ५ फरवरी को गाधीजी को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया। वाइसराय तथा गाधीजी की यह चौथी मुलाकात थी। उनमें ढाई घण्टे तक खुलकर बातचीत हुई जिसका आशय निम्नलिखित विज्ञिप्त से स्पष्ट हो जाता है—

वाइसराय महोदय के निमत्रण के जवाब में आज गांधीजी उनसे मिलने आए। बहुत देर तक दोनों में मित्रतापूर्ण वातचीत होती रही। इस बातचीत के दौरान में दोनों ने सारी स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। गाधीजी ने बातचीत के शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें काग्रेस कार्यसमिति की ओर से कोई हिदायत नहीं मिली है और किसी तरह का कोई बन्धन अपने ऊपर लेने का उन्हें हक नहीं है। अपनी वैयक्तिक हैसियत, से ही वह कुछ कह सकते हैं।

वाइसराय महोदय ने सम्राट् की सरकार के इरादो और प्रस्तावों पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सब से पहले इस बात पर जोर दिया कि उनकी यह दिली ख्वाहिश है कि भारत यथाशी घ्र औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा हासिल कर ले और वह चाहते है कि इसकी प्राप्ति मे वह यथाशक्ति भारत की मदद करे। -उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसे विषयों की पेचीदिंगियों और मुश्किलों की तरफ गांधीजी का घ्यान आकृष्ट किया, जिनपर विचार-विनिमय करना जरूरी था—खासकर औपनिवेशिक स्वराज्य में रक्षा का प्रश्न । उन्होंने यह बात साफ तौर से बताई कि सम्राट् की सरकार समय आने पर सभी दलो और हितो के सलाह-मशविरे से इस सारे ही विषय की जाच-पडताल करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सम्राट् की सरकार इस सक्रमण काल को यथासभव कम-से-कम करना चाहती है। उन्होने बताया कि पिछले नवम्बर में उन्होने जिस आधार पर और जिस तरीके पर गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् में विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था-वह अब तक ज्यो-का-त्यो बना है और सम्राट् की सरकार उस पर तत्काल अमल करने को तैयार है। यदि सम्बद्ध दलो की सलाह हो तो सम्राट् की सरकार सघ-योजना पर भी फिर से विचार करने को तैयार है, जिससे कि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य मिल सके और लडाई के बाद युद्धकाल की समस्याओ पर आसानी से समझौता हो सके।

गाधीजी ने इन प्रस्तावों को पेश करने की भावना को पसन्द किया, परन्तु उन्होंने कहा कि मेरी राय में इस समय इनसे काग्रेस दल की पूर्ण माग पूरी नहीं होती। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि अच्छा यह होगा कि फिलहाल हम इस सम्बन्ध में और बातचीत स्थिगत कर दे, जिससे कि उन कठिनाइयों को सुलझाने में मदद मिल सके, जो इस समय पैदा हो गई है। वाइसराय महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया।

ज्यों-ज्यो बातचीत आगे बढी, इस समस्या पर बहुत गहराई से खोजवीन होने लगी। मानो सरकार और जनता साथ मिलकर एक कुआँ खोद रहे थे और ज्यों-ज्यों उसकी तहें खुलती जाती थी, उनमें से आशाओं के झरने प्रवाहित हो रहे थे। इन झरनों से मानो लोगों को जीवन प्राप्त होने और उनकी स्वतत्रता की पिपासा तृप्त हो जाने वाली थी, लेकिन बात वास्तव में ऐसी थी नहीं। इस सह-योग के प्रयास में एक ऐसी अवस्था आ गई, जब गांधीजी ने उस गुप्त स्रोत और झरने की असलियत खोलकर वाइसराय के सामने रख दी। ६ फरवरी, १९४० के अपने एक वक्तव्य में गांधीजी ने बताया कि वाइसराय के प्रस्ताव का उद्देख भारत के भाग्य का अन्तिम निर्णय ब्रिटिंग सरकार के हाथों में देना था, जबिक काग्रेस का घ्येय आत्मिनिर्णय के सिद्धान्त पर अमल करने का था। स्वतंत्रता की वास्तिवक कसौटी यही थी, दोनो विचारधाराओं में यही मुख्य भेद था। गांधीजी के विचार से इसे दूर किये विना कोई गान्तिपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण समझौता सभव नहीं था। एक बार ऐसा हो जाने पर राष्ट्र की रक्षा, अल्पसंख्यकों, नरेशों और यूरोपियनों के स्वार्थों के प्रश्न अपने आप सुलझ जाएँगे। गांधीजी और वाइसराय न इन सभी वातो पर मित्रों के रूप में विचार-विमर्श किया। लेकिन दोनों के दृष्टिकोणों में भारी अन्तर था। इतने पर भी उन दोनों ने वतौर दोस्तों के ही एक-दूसरे से विदा ली।

कार्यसिमिति की वैठक

काग्रेस का अगला अधिवेशन विहार में रामगढ में होने वाला था। उसका समय बहुत निकट आ रहा था। एक पुरानी प्रया के अनुसार—आगामी अधिवेशन से काफीं समय पहले कांग्रेस कार्यसमिति की वैठक युलाई जाती थी। चुनांचे इसके अनुसार इस वार भी २८ फरवरी १९४० को पटना मे काग्रेस कार्यसमिति की एक वैठक हुई। कुछ लोगों के खयाल के मुताबिक रामगढ काग्रेस उस समय की यद्धकालीन चर्चाओं के दरिमयान प्राय एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी। लेकिन यह वात ऐसी नही थी। काग्रेस ने बहुत-से विभाग खोल रखे थे, जैसे प्रचार, अल्पसख्यक, हरिजन और चर्खा जिनके जॉरिये वह अपना पुन सगठन कर रही थी। इन विभागो का उद्देश्य सत्याग्रह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश को तैयार करना था, क्योंकि सभी का खयाल था कि इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह ही था। गाधीजी अपने अहिसात्मक सिद्धान्तो, और किस तरीके से उन्हें सामूहिक और वडे पैमाने पर कार्यान्वित करके देश को मुक्ति दिलाई जा सकती है, के बारे में बहुत कुछ लिख चुके थे। पटना में उन्होंने अनुभव किया कि काग्रेसजनों में इतना मतभेद और अनुशासन-हीनता है कि सर्विनय-अवज्ञा का परिणाम ठीक नही होगा। इसके विपरीत लोगो कहना था कि अगर सिविल-नाफरमानी शुरू कर दी जाय तो ये सब मतभेद दूर हो जाएँगे। इन दोनो दलो के दरमियान एक दल और था, जिसका विचार था कि काग्रेस को इस समय अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख देनी चाहिए और साफ-साफ कह देना चाहिए कि वह क्या करेगी। जनता को साफ साफ पता होना चाहिए कि अगर आसमान भी टूट पड़े तो हमारी स्थिति यह होगी, वरना जनता में अरक्षा की भावना पैदा हो जायगी जो स्वय इस आन्दोलन के लिए घातक होगी। इस तरह की विचारधारा का मुख्य कारण यह था कि लोगो

को सन्देह होने लगा था कि क्या आज से तीन महीने पहले देश की अधिक तैयारी नहीं थी और क्या वे उस स्थिति से पीछे नहीं हटते जा रहे हैं। हो सकता है कि हम सिवनय अवज्ञा आज प्रारम्भ न करे, हो सकता है कि इसे हम कल भी न करे, लेकिन हमें सन्देह की इस भावना की रोक-थाम करके कोई अन्तिम निर्णय अवश्य करना चाहिए। लड़ाई के कारण यह सकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी और अग्रेजों का उद्देश्य यथासभव अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हर हालत में उसे सुदृढ तो करना था ही। हमारे रास्ते में सिर्फ एक बड़ी रुकावट साम्प्रदायिक समस्या खड़ी कर दी गई थी जिसका उद्देश्य काग्रेस के रास्ते में रोड़े अटकाना था। ऐसी स्थिति में रामगढ़ अधिवेशन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से जब काग्रेस कार्य-समिति की पटना में बैठक हुई तब उसने केवल एक ही प्रस्ताव तैयार किया, जिसका सम्बन्ध भारत और युद्ध से था।

रामगढ़-कांग्रेस : १८४०

रामगढ में मार्च १९४० में होनेवाली काग्रेस के ५३वे अधिवेशन के प्रधान के लिए सिर्फ मामूली-सा चुनाव हुआ। १५ फरवरी १९४० को सभी प्रान्तों में प्रतिनिधियों ने प्रधान के निर्वाचन के लिए अपने-अपने वीट डाले और मौलाना आजाद, श्री० एम० एन० राय के मुकाबले में १८६४ वोटों से काग्रेस के प्रधान चुने गए। श्री राय को १८३ वोट मिले।

रामगढ का नाम मजहर नगर रखा गया था और सदा की भाति यहाँ भी सब उत्सव बडी धूम-धाम से मनाए जाने का आयोजन किया गया। खुले अधि-वेशन को छोडकर विपय-निर्वाचन सिमिति, प्रदर्शनी, सार्वजिनक सभाएँ इत्यादि का सारा कार्यक्रम निर्विद्म सपन्न हुआ। लेकिन खुले अधिवेशन का आयोजन इस पठार की एक सुरम्य तराई में किया गया। प्रकृति कुद्ध हो गई, उसने रौद्र रूप धारण कर लिया और सारे मैदान में घुटनो तक पानी चढ आया। इसका कारण यह था कि ठीक उसी समय, जब कि काग्रेस का अधिवेशन होना था, जोर का तूफान आया और वर्जा होने लगी। काग्रेस के महार्थियों ने इसका बहादुरी से मुकाबला किया। इसी प्रलय की घडी में स्वागत-सिमित के प्रधान और अधिवेशन के प्रधान ने कमश अपनी-अपनी कार्रवाइया की। वेशक उनके अभिभाषण विना पढे ही पढे हुए मान लिए गए। उस दिन का मुख्य प्रस्ताव पडित जवाहरलाल ने पेश किया और उसे अगले दिन के लिए मुल्तवी कर दिया गया। अगले दिन काग्रेस अधिक सौभाग्य-शालिनी रही और उसे अधिवेशन के लिए काफी समय मिल गया। अधिवेशन आसानी और धूमधाम से हो गया। अधिवेशन का आयोजन झण्डे वाले मैदान में किया गया था, जहा जमीन ऊँची और सूखी थी। काग्रेस का यह ऐतिहासिक निर्णय, जिसका समर्थन गाधीजी ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में

किया था, लोगो ने झण्डे के नीचे बैठकर पूरी गभीरता और सजीदगी से किया। मजहर-नगर के सिहद्वार के सामने ३० फुट ऊँचे एक स्तभ पर यह झण्डा फहरा रहा था। इस स्तभ का रग भूरा और पीला था और इसके बनाने में अशोक-स्तभ की नकल की गई थी।

राजेन्द्र वावू का श्रभिभापण

रामगढ का अधिवेशन रामगढ के राजा के एक जगल की देहाती वस्तियों में किया गया था। और इस अवसर के सर्वथा उपयुक्त श्रीयुत राजेंद्र वावू को काग्रेस के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए चुना गया था। उनके अभिभाषण में युक्तियों और विभिन्न घटनाओं का वर्णन वडें ही बढिया तथा मोहक टग से किया गया था। उन्होंने एक धर्मोपदेश का वर्णन करते हुए कहा —

"कभी-कभी हम भूतकाल से शिक्षा लेकर वडे प्रेरित और प्रभावित हो उठते हैं। यह प्रकरण समाप्त करने से पहले मैं ऐसी ही एक घटना आपके सामने रखूगा। किसी जमान में राजा अजातशत्रु दक्षिण विहार में राज्य करते थे और उत्तर विहार में विजियो का सुसमृद्ध प्रजातन्त्र था। अजातगत्रु विजियो को जीतकर उनका प्रदेश अपने राज्य में सम्मिलित कर लेने के लिए वड उत्सुक थे। एक वार गीतम बुद्ध अजातशत्रु की राजधानी राजगिर (राजगृह) आये और गिद्धकूट (गृद्धकूट) पूर्वत पर ठहरें। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास यह जानने के लिए भेजा कि विज्यों के विरुद्ध उनकी जो योजना और चाल है, उसके सवध मे उनकी क्या राय है । जब बुद्ध को अजातशत्रु के इरादो का पता चला तब उन्होने अपने शिष्य आनन्द से सात प्रश्न किये और उनका उत्तर मिलने पर उन्होंने अजात-शत्र के प्रश्न का जवाब दे दिया। उन्होंने पूछा, "आनन्द! क्या तुमने सुना है कि बज्जी लोग अपनी सभाएँ अक्सर बुलाते हैं और लोग उनमें काफी सख्या में शामिल होते हैं?" आनन्द ने उत्तर दिया, "प्रभु! तथागत! मैने सुना है कि विज्जियों की सभाएँ बहुधा होती है और उनमें लोग काफी सख्या में भाग लेते हैं।" बुद्ध ने कहा, " हे आनन्द । जब तक बुज्जियों की सभाएँ बहुधा होती रहेगी और उनमें लोग काफी संख्या में भाग लेते रहेंगे तब तक तुम यह आशा कर सकते हो कि केवल उनकी अभिवृद्धि ही होगी, विनाश नहीं।" उन्होंने इसी प्रकार के छ' और प्रश्न किये और उनका सतोषजनक उत्तर मिलने पर कहा, "जब तक वज्जी एक जगह मिलकर बैठते रहेगे, एक साथ मिलकर काम करते रहेगे और अपने राप्ट्रीय कर्तव्यो का पालन एक साथ मिलकर करते रहेगे, जब तक वे कानून बनाए बिना कोई मनमाने आदेश नही जारी करेगे और न अपने कानूनो का अतिक्रमण करेगे, जब तक वे अपने बनाए नियमों के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करते रहेंगे, जब तक वे अपने बड़ो का आदर-सम्मान करेगे और उनकी मान्य राय को मानते

रहेगे, जब तक अपनी स्त्रियों के प्रति कठोर अथवा उद्ग्डतापूर्ण बर्ताव नहीं करेगे, जब तक वे अपने चैत्यो (धार्मिक और राष्ट्रीय मिदरो) को आदर-सम्मान करते रहेंगे और धार्मिक प्रयोजन से दी गई उनकी सपत्ति उनसे नही छीनेगे, जब तक वे अपने अर्हतो (आत्मत्यागी विद्वानो) की रक्षा करते रहेगे और बाहर के अर्हतों को अपने देश में प्रवेश करने की आज्ञा देते रहेगे, अपने राज्य के अईतो को आराम से जीवन व्यतीत करने देगे, तव तक उनकी समृद्धि होती रहेगी, वे सपन्न होते रहेगे। इसलिए तुम्हे उनकी किसी प्रकार की क्षति की आशा नहीं करनी चाहिए।" जब अजातशत्रु ने यह सुना तब उसे विश्वास हो गया कि उसके लिए अपनी सेनाओं के बल पर विजयों को जीतना असभव है। आज भी ये सातो नियम, जिनके ऊपर राष्ट्रों का उत्थान-पतन निर्भर रहता है और जो आज से २,५०० वर्ष पूर्व लागू किये गये थे—कितने सच्चे और शाश्वत है। राजगिर की पहाड़ियों में गिद्धकूट का यह पर्वत आज भी हमे उनका स्मरण दिला रहा है। किसी भी जीवित समाज में मतभेद का होना सर्वथा स्वाभाविक ही होता है। क्या आज हम काग्रेस के बारे में यह कह सकते हैं कि हम एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ मिलकर बात करते है और एक साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्यों का पालन करते हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि हम अपने ही बनाए हुए नियमो का उल्लघन नहीं करते? क्या हम अपने ही बनाए हुए नियमों के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य करते हैं? क्या हम विश्वास और निश्चय के साथ यह कह सकते है कि हम अपने बड़ों का आदर-सत्कार करते हैं, उनकी मान्य सलाह पर ध्यान देते है और उसे स्वीकार करते हैं ? विजियों की ताकत इन्हीं बुनियादों पर निर्भर थीं । यदि हम भी इन प्रश्नों का उत्तर 'हा' में दे सके तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। एक बार बुद्ध ने भिक्षुओं को विजियों की सभाओं को दिखाते हुए कहा था, "तुम इस सभा को देखों। इससे तुम यह अनुमान लगा सकते हो कि देवताओं की सभा किस प्रकार की होगी।" क्या हमारे लिए इस प्रकार का सगठन करना और अपने इस राष्ट्रीय संगठन को इस प्रकार चलाना सभव नहीं है कि जिससे गांधीजी हममे अनुशासन की कमी और हिसा की शिकायत करने के बजाय अपने आश्रम की कन्याओं को सबोधित करते हुए ऐसे ही उपदेश दे, जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षओं को दिये थे?"

मिलाना त्राज़ाद का भाषण्]

राष्ट्रपित मौलाना आजाद का माषण उच्चकोटि का था। उन्होंने कहा— "आज हमारा काफिला एक बडी नाजुक घड़ी में से गुजर रहा है। इस तरह की नाजुक घडी में कठिनाई यह रहती है कि उसमें परस्पर विरोधी सभावनाओं की आशका बनी रहती है। बहुत सभव है कि यदि हम कोई ठीक कदम उठाएँ तो अपने उद्देश्य के बहुत निकट तक पहुँच जाएँ और दूसरी ओर यदि हम कोई गलत कदम उठा बैठे तो उससे हम नई किठनाइयो और उलझनो में फँस जायाँ।" आगे उन्होने विस्तार से काग्रेस की माग, उस पर ब्रिटिंग सरकार के जवाब और अब तक काग्रेस-द्वारा उठाए गए कदमो का जिक करते हुए कहा—"हमारी स्थिति विल्कुल साफ है। हम ब्रिटिंग साम्राज्यवाद को विजयी और मजबूत होता हुआ नही देखना चाहते और इस तरह अपनी गुलामी की अविष को भी नही बढाना चाहते। १९३७ में हमने जो अस्थायी और आधिक सहयोग का हाथ बढाया था, उसे हमने युद्ध की घोपणा के बाद खीच लिया। स्पष्ट है कि हमारा इरादा असहयोग की दिशा में आगे कदम बढाना है। जिस स्थिति में हम आज हैं, हमें यह फैसला करना है कि हमें इस दिशा में आगे वढना चाहिए या पीछं कदम लौटाना चाहिये लेकिन एक दफा कदम उठा लेने पर उसे पीछे नही हटाया जा सकता। कदम रोकने का मतलव पीछे हटना हैं और हम पीछे हटने से इन्कार करते हैं। इसलिये हम सिर्फ आगे ही कदम बढाना चाहिए और हम थागे ही आगे चलेंग तब आप सब मेरे साथ इसमें पूरी तरह से गरीक हैं।

गांधीजी की चेतावनी

इस वात को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पहले से ही पटना में तैयार कर लिया गया था, रामगढ की गतिविधि इतनी शान्त न थी जितनी कि आशा की जाती थी। लेकिन इस थोड़े से दरमियानी अरसे में भी विचार-धारा वडी तेजी से प्रवाहित हो रही थी। श्री जिन्ना का दो राप्ट्रो का सिद्धात उनके दिमाग में पनपने लगा था, जो अपने आपको पाकिस्तान की सूरत में प्रकट कर रहा था। साम्प्रदायिक झगडे, जिनके पैदा हो जाने की आशका सिवनय भग के कारण की जा रही थी, पहले ही शुरू हो चुके थे और सक्खर का दगा अपने पूरे वेग से प्रारभ हो चुका था, जिसमे ४०० आदमी मारे गए और हजारो घायल हुए थे। यह दगा उस समय देश के इतिहास मे पाशविकता, कूरता और रक्तपात मे अपना सानी नही रखता था। जहा तक लडाई के जमाने में सविनय भग आन्दोलन प्रारम करने का प्रश्न था, रामगढ अधिवेशन के समय प्रादेशिक और जातिगत सिद्धात के आधार पर देश के विभाजन की माग और साम्प्रदायिक कलह की समस्या ऐसी नही थी जिस पर शान्त चित्त से विचार किया जा सकता था। जबकि समस्याएँ ऐसी थीं तब घटनाओं के सिहावलोकन से भी कोई आश्वासन नही मिल सकता था। गाधीजी को तो सभी ओर अनुशासन-हीनता ही दिखाई दे रही थी। उनकी मुख्य कठिनाई थी—सगठन। "मै इस तरह के सगठन के वल पर कैसे लड़ सकूगा ?"—यही एक विचार था जिस पर वह अपने आत्मनिरीक्षण के समय

सोचते थे और विचार-विनिमय में बराबर इसी पर चर्चा करते थे। संगठन की ऐसी हालत देखते हुए उन्होंने अनुभव किया कि वह काग्रेस-जनों से कह दें कि उन्हें वडा खतरा नजर आ रहा है और इस तरह के सगठन के बल पर किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो क्या फिर उन्हें काग्रेस के बिना ही अकेले जूझ पड़ना चाहिए ? उन्होंने गभीरतापूर्वक अध्ययन किया कि वह इस नेतृत्व से अलह्दा हो जाने का प्रस्ताव करे। यह निश्चय ही एक नई बात थी, क्योंकि पटना में उनकी विचार-धारा इस प्रकार की नहीं थी। इस स्थिति को हम सक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं। लोग गांधीजी से पूछ रहे थे, "आप आन्दोलन कब करेंगे?" और गांधीजी इसके जवाब में उनसे कह रहे थे, "जब तुम तैयार हो जाओगे।" रामगढ से सिर्फ चार महीने पहले एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जो प्राय स्वीकार कर लिया गया था। इसमें सब कुछ गांधीजी पर छोड़ देने को कहा गया था। गांधीजी सिर्फ यह चाहते थे कि लोगों के अन्दर से यह धारणा दूर हो जाय कि वह शींघ्र ही आन्दोलन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वातावरण इसके अनुकूल न था, न उनके पास पर्याप्त सामग्री ही थी। यहा तक कि इस काम के लिए उनके पास आदमी भी नहीं थे। अन्त में रामगढ में पटना वाला प्रस्ताव ही पास हुआ।

विषय-निर्वाचन-समिति में और खुले अधिवेशन में गाधीजी ने जो बाते कहीं और उसके एक सप्ताह बाद उनकी ओर से देश को जो चेतावनी दी गई उसका

साराश इस प्रकार है --

"मै आप लोगों से मुलाकात करने और आपसे अपना परिचय ताजा करने आया हूँ। मै आपसे सीधा सम्पर्क कायम करना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि मेरी और आपकी एक दूसरे के सबध मे क्या स्थित है। आपने प्रस्ताव प्राय सर्वसम्मित से पास किया है। बहस के दौरान मे आपस मे से कुछ लोगों ने जो वाते कही है उनका मै उत्तर देना नही चाहता। लेकिन मै यह जरूर कहना चाहता हूँ कि अब मै बड़ी सख़्ती से काम लूँगा। इसलिए नहीं कि सख्ती मुझे पसन्द है, बिल इसलिए कि एक सेनापित को, जिसे अपनी फौज की रहनुमाई करनी है, पहले से ही सेना को अपनी शर्ते बता देनी चाहिए। इस बार मै देखता हूँ कि पहले की अपेक्षा-आज हम लोग चारो ओर से कठिनाइयों से कही ज्यादा घिरे हुए हैं। कठिनाइयों भीतरी और बाहरी दोनों तरह की हैं। ब्रिटिश सरकार विश्वव्यापी युद्ध मे फॅसी हुई है और अगर हम भी उससे लड़ाई ठान ले तो स्वाभाविक है कि हम काफी कष्ट मोल ले लेगे। यह हमारी पहली कठिनाई है, लेकिन मुझे जो चीज भयभीत कर रही है—वह है हमारी भीतरी कठिनाई। मैने अक्सर कहा है कि अगर आन्दोलन ठीक आधार पर चले तो बाहरी मुश्किलों से सत्याग्रही को कभी डरने की जरूरत नहीं है। हमारी भीतरी कठिनाई यह है कि हमारी काग्रेस के

रजिस्टर ऐसे सदस्यों से भरे पड़े हैं जो यह जानकर वड़ी सहया में भरती हो गए है कि काग्रेस में घुसने का अर्थ सत्ता हामिल करना है। इस कारण जो पहले काग्रेस में शामिल होने का कभी विचार भी नहीं करते थे वे भी अब उसमें आ गए हैं और उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। काग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। लोग दलों में वँट हुए हैं और उनमें लड़ाई झगड़े हैं। प्रजातत्र तो मेरी कल्पना मे ऐसे दलो का निर्माण नहीं है, जो आपस में इस हद तक लडते-झगडते रहे कि उससे सगठन ही नप्ट हो जाय। और फिर हमारी सस्या तो लोकवादी और लडाकू दोनो ही है। हमारी लडाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब हम एक सेना के रूप में आगे बढते हैं तब हम लोक-वादी नहीं रहते। वतीर सिपाही के तब हमें सेनापित से आदेश लेना पडता है और उसे विना किसी हिचकिचाहट के मानना पड़ता है। सेना में तो जो कुछ सेनापित कहे, वही कानून होता है। में आपका सेनापित हूं। इसका यह मतलव नहीं कि मैं आपको अपनी भावनाओं के वारे में अन्यकार में रखूँ। लेकिन मुझे अपने जैसे कमजोर सेनापित की मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। मेरे पास कोई अविकार नहीं है। मेरा एकमात्र वल आपका प्रेम है। एक प्रकार से यह वडी भारी चीज है, लेकिन दूसरी प्रकार से वह निर्यंक भी है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल में सबके लिए प्रेम है। शायद आप भी ऐसा ही कहते हो, लेकिन आपका प्रेम कियात्मक होना चाहिए। आपको आजादी की प्रतिज्ञा मे बताई गई शतों को पूरा करना चाहिए। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उन शर्तो को पूरा नही कर सकते तो मेरे लिए आन्दोलन गुरू करना सभव न होगा। आपको कोई और सेनापित तलाश करना होगा। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अपना नेतृत्व करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जब आपने मुझे अपना सेनापित बनाया है तव आपको मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। इसमे कोई तर्क नहीं चल सकता। चूँकि मेरी एकमात्र ताकत प्रेम है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप धैर्य रखें। प्रेम के साथ धैर्य का होना अनिवार्य है। मैने अपने मित्रों को चर्छे के सवध में टीका-टिप्पणी करते सुना है। मुझे मालूम है कि आप सब जेल जाने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपना हक और योग्यता हासिल करनी होगी और जेल जाने की कीमत चुकानी होगी। आपको मुजरिम के तौर पर जेल नहीं जाना है।

"मैं १९१८ से ही बागी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं साम्राज्य का इतना राजभक्त था कि मैंने लार्ड चेम्सफोर्ड को लिखा कि मैं साम्राज्य का उतना ही राजभक्त वनना चाहता हूँ, जितना कोई अग्रेज हो सकता है। मैंने यह इसलिए लिखा, क्योंकि सत्य पर मेरा यकीन है। सत्य ही मेरा ईश्वर है और यदि मैं अपने प्रति सच्चा होना चाहता था तो मैं इससे भिन्न लिख ही कैसे सकता था। आपका मार्ग सत्य और अहिंसा से अलग हो सकता है, पर मेरा तो वही पुराना रास्ता है। आप लोगो की तरह ही मनुष्य होने के नाते मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैने कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया कि मैं महात्मा हूँ। ईश्नर की नजरों में हम सब समान हैं। मेरे लए हिन्दू, मुसलमान, पारसी और हरिजन सभी एक-से हैं। कायदे आजम जिन्ना के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ तब कोई हल्की वात कह नहीं सकता। वह भी तो मेरे भाई हैं। वास्तव में मुझे खुशी होगी अगर वह मुझे अपनी जेब में रख सके। एक समय था, जब मैं यह कह सकता था कि एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है, जिसका मुझ पर विश्वास नहीं। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि आज ऐसी बात नहीं हैं। उद्दें के पत्रों में जो कुछ छपता है वह सब मैं नहीं पढ़ता, लेकिन शायद उनमें मेरे लिए ज्यादातर गालियाँ ही रहती हैं। इसका मुझे दु ख नहीं हैं। मेरा अब भी यहीं विश्वास है कि हिन्दू-मसलमानों के समझौता के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। शायद आप पूछेगे, "तो ऐसी हालत में आप लड़ाई की बात क्यों करते हैं?" मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि यह लड़ाई विधान-परिपद के लिए है। यदि मुसलमानों के वोट से विधान-परिपद में आने वाले मुसलमान यह घोपणा करते हैं कि हिन्दू-मुसलमानों में कोई बात सामान्य नहीं है तो मैं उस हालत में सब आशाए छोड़ दूँगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे आग्रह कहँगा, क्योंकि वे कुरान- शरीफ पढते हैं और मैंने भी उसका थोड़ा-वहुत अध्ययन किया है। मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वर हिन्दू-मुसलमानों में कोई भेद नहीं करता।

"किसी ने कहा है कि सिवनय भग से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव में 'सामूहिक' शब्द का जिक नहीं किया गया। यदि यह सामूहिक सिवनय भग नहीं होना है तो फिर मुझे आपके सामने आने की क्या पड़ी थीं ? यदि यह सिवनय भंग सामूहिक न होगा तो क्या मुट्ठी भर लोगों का होगा ? तब आप मुझे इस प्रकार आपसे तर्क करते नहीं पायेगे। आप शायद इन बातो पर गभीरता से विचार न करते हो, पर इस सिवनय भग के खयाल में ही मेरा मन आठों पहर जाग्रत रहता है। मेरा मन तो आपकी मदद और सहयोग से इस महान् परीक्षा को ही कार्यान्वित करने की बात सोचा करता है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत का ही लाभ होगा, विक सारी दृनिया का कल्याण होगा।

"अव हिदायतों की वात सुन लीजिए। हर कागेस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी वन जाना चाहिए और जिन लोगों का सबके प्रति सद्भाव पैदा करने में विश्वास हो, जिनमें किसी भी रूप में छुआछूत की भावना न हो, जो नियमित रूप से कातते हो और जो सब तरह का कपड़ा छोड़कर आदतन खादी पहनते हो, उन सबके नाम लिख छेने चाहिएँ। मैं आया रखता हूँ कि जो लोग अपनी कमेटियों में इस तरह नाम लिखाएँगें वे अपना सारा फाल्तू समय रचनात्मक कार्यक्रम में लगाएँगे। अगर यह आया सच्चाई के साथ पूरी की जाएगी तो ये सत्याग्रह कमेटियाँ कताई के घर वन जाएँगी और वहा काम-ही-काम दिखाई देगा। ये चर्छा-नघ की शाखाओं

के साथ मिलकर और उनकी सलाह के अनुसार इतने व्यावसायिक ढग से काम करे कि कमेटियों के इलाके में एक भी काग्रेसी ऐसा न वच रहे, जो खहर के सिवाय और कोई कपडा पहनता हो। मैं आजा रखूँगा कि प्रान्तीय दफ्तर अखिल भारतीय महासमिति के सत्याग्रह कमेटियों के काम की प्रगति के वारे में व्यवस्थित समा गर भेजते रहे। नाम लिखाने वाले सत्याग्रही रोजनामचा रखें और नित्य जो काम करे, उसमें लिखते जाय। अपनी कताई के अलावा उनका काम यह होगा कि चवन्नी—मेम्बरों के पास जाय और उन्हें खादी इस्तेमाल करने, कातने और अपने नाम लिखाने को समझाएँ। मेम्बर ऐसा करे या न करे, उनके साथ सपकं जरुर वना रहना चाहिए। हरिजनों के घर भी जाते रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी दिक्कते मिटानी चाहिएँ। यह कहने की तो जरुरत ही नहीं कि नाम उन्हीं के लिखने चाहिए, जो जेल के कष्ट उठाने को रजामन्द और समर्थ हो। सत्याग्रही कैदियों को अपने या अपने आश्रितों के लिए किसी तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

"यह तो हुई वात सत्याग्रह में भाग लेने वालों की। लेकिन उनसे भी कहीं वडा वर्ग ऐसे स्त्री-पुरुषों का है, जो भले ही काते नहीं या जेल न जाय, मगर उनका सत्याग्रह के दोनों मुख्य सिद्धान्तों पर विश्वास है और वे लडाई का स्वागत करत है और उसकी सफलता चाहते हैं। इन्हें मैं निष्क्रिय सत्याग्रही कहूँगा। अगर ये लोग खुद जेल न जाकर या मजदूरों या विद्यार्थियों की हडतालों में मदद न देकर या जल्दबाजी न कर के लडाई के प्रवाह में दखल न दे तो उनकी मदद सिक्य सत्याग्रहियों के बराबर ही गिनी जायगी। जो बहुत उत्साह या और किसी कारणवश इन हिदायतों के खिलाफ चलेगे, वे लडाई को हानि पहुँचाएँगे और सभव है, उसे बीच में ही रोक देने को मुझे मजबूर कर दे।

"मरे दिमाग में यह बात विलकुल स्पप्ट है कि यदि राजनैतिक विचार रखने वाले हिन्दुस्तानियों का सहयोग मिल जाय तो भारत को शुद्ध अहिंसा के जिये आजादी हासिल होना पूरी तरह सभव है। हम जो अहिंसा का दभ करते हैं उस पर दुनिया का विश्वास नहीं है। दुनिया की बात जाने दीजिए, मैं तो सेनापित बन बैठा हूँ। मैंने ही बार-बार स्वीकार किया है कि हमारे दिलों में हिंसा है और अक्सर आपस के व्यवहार में एक दूसरे के साथ हम हिंसक हो जाते है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जब तक हममें हिंसा है तब तक मैं नहीं लड सकूँगा। लेकिन जिस सूची के बनाने की मैंने तजवीज की है यदि वह सच्ची हुई और साहस कर के बाहर रहने वाले लोगों ने लडाई के सीधे प्रवाह में बाधा न डाली तो मैं जरूर लडूँगा।"

प्रतिक्रिया की भावना

गाधीजी की योजना निश्चित रूप से जिन सिद्धान्तों पर आधारित थी उनमें से

एक सिद्धान्त कातना था और दूसरा अग्रेजो को भारत से निकाल बाहर करना नहीं, बल्कि उनका हृदय-परिवर्तन करके उन्हें भारत का सेवक बनाना था। इसका अर्थ यह नहीं था कि वह साम्राज्यवाद के पक्ष में थे। उन्होंने स्वय कहा, "यदि मेरा प्रेम गुलाब की पखुडियों की तरह मुलायम है तो वह काच के टुकड या पत्यर से ज्यादा कठोर भी हो सकता है।" उनकी पत्नी और सब से बड़े बेटे को कठोर प्रेम का आस्वादन करना पडा था। गाधीजी ने कहा, "मेरा खयाल है कि मैने सुभाष बाव को हमेशा के लिए पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे यह शिष्टता छोडनी पड़ी। उनके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उसके लिए मुझे दु ख और खेद के साथ स्वीकृति देनी पड़ी।" इसी तरह से उन्होंने डा० खरे और वीर नरीमैन के विरुद्ध की गई अनुशा ,नत्मक कार्रवाई के सम्बन्ध में भी अपनी सहमति प्रदान करने के लिए खेद प्रकट किया। अग्रेजो के प्रति भी उनका रवैया ऐसा ही था। चर्खा उनके प्रेम के कार्यक्रम का एक प्रधान अग बन गया था। उनके विचार से यदि कोई हिसा का मुकाबला हिंसा से करने की व्यवस्था करता है या सोचता है तो उसका परिणाम यहाँ सभव है कि उसका जीवन सकटपूर्ण बना रहेगा और उसे अपनी रक्षा के लिए बड़े-बड़े शहर और शस्त्रागार वनाने पड़ेगे। भारत का प्राचीन देहाती प्रजातत्र अहिंसा पर आधारित सभ्यता का प्रतीक था। चर्ले का यही सिद्धान्त है। एक सप्ताह बाद गाधीजी ने फिर इसी विषय को उठाया और बताया कि किस प्रकार श्री जयप्रकाशनारायण और उत्तर प्रदेग के शिक्षामत्री श्री सपूर्णानन्द ने प्रतिज्ञा-पत्र में किये गए सशोधनो का विरोध किया है। रामगढ अधिवेशन तक और उसके बाद भी सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करने के सम्बन्ध मे उन्होनं जिस हिचकिचाहट और अन्यमनस्कता का परिचय दिया, उसका एक कारण यह भी था। स्वाधीनता-दिवस पर देश में कही-कही अनुशासन-भंग की घटनाए देखने में आई। सवाल यह नहीं था कि अनुशासन-भग की ये घटनाएं कितनी थी, विलक प्रश्न तो उसके पीछे काम करने वाली प्रचलित भावना का था। ज्यों-ज्यों रामगढ अधिवेशन करीव आ रहा था—विरोव-प्रदर्शन के सम्वन्य मे वडी-वडी अफवाहें सुनाई दे रही थी और यहाँ तक कहा जा रहा था कि गायद काग्रेस-नगर में विस्फोट हो जाय। सौभाग्य से रामगढ अधिवेशन के समय ऐसी आजकाएँ निर्मूल सावित हुई। लेकिन रामगढ को अग्नि-वर्षा और विस्फोट की वजाय वर्षा का सामना करना पडा।

कांग्रेंस-विरोधी सम्मेलन

साम्यवादियो, समाजवादियो, राष्ट्रीय प्रजातत्रवादियो, किसानो और अग्रगामी दल वालो के विरोध और मतभेदों का ऊपर जिक्र किया गया है। वाद के दोनों दल तो संयुक्त रूप से काग्रेस का विरोध करने पर उत्तर आए और उन्होने किसान-नगर नामक स्थान पर सुभाप वावू की अव्यक्षता में एक समान्तर सम्मेलन किया। उनका उद्देश्य काग्रेस कार्यसमिति के पटना वाले प्रस्ताव का, जिसे रामगढ अधिवेशन में पेश किया जाना था, विरोध करना था। इससे वे यह साबित करना चाहते थे कि जिन लोगों का यह खयाल था कि काग्रेस ने समझौता न करने का रवया अखितयार किया है, वे गलती पर है। उन्हें इस प्रस्ताव में खासकर उसके दूसरे भाग में बहुत-सी खामिया नजर आईं, जिनके कारण उसका महत्व ही जाता रहा था। सुभाप वाबू ने वताया कि इस प्रस्ताव के पास होते ही गाधीजी यह कहने लगे हैं कि उन्होंने भविष्य के लिए समझौते का दरवाजा वन्द नहीं कर दिया है। सविनय भग के बारे में गाधीजी के विचारों से उन्हें सन्तोप नहीं हुआ। सुभाप वाबू ने कहा, "अगर इस देश में साम्राज्यवाद के साथ समझौता होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में भारतीय वामपक्षियों को न केवल साम्राज्यवाद से ही जूझना पड़ेगा, वित्क उसके भारतीय सहयोगियों से भी टक्कर लेनी होगी। इसका परिणाम तो यही होगा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली राष्ट्रीय लड़ाई स्वय भारतीयों की घरेलू लड़ाई में ही परिवर्तित हो जायगी।"

यह सम्मेलन काग्रेस के अधिवेशन से पहले ही हुआ और इसमे वडी सस्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने घोषणा की कि वे लडाई के लिए तैयार है।

सम्मेलन का उद्देश्य देश की उन सभी साम्राज्यवादी ताकतो का सगठन् करना था, जो साम्राज्यवाद से सुलह न करने पर आमादा थी। सुभाष वाबू ने एक ओर तो काग्रेस के प्रस्तावों और कार्यसमिति के सदस्यों के वक्तव्यों और दूसरी ओर गाधीजी तथा वामपक्षी नेताओ के वक्तव्यो की परस्पर विरोधी वातो पर प्रकाश डाला । उन्होने विधान-परिषद् की माग को अनुचित बताते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह से नरम दल वाले लोग पृथक् निर्वाचन और धारासभाओं के मौजूदा मताधिकार को ही विधान-परिषद् का आधार मानने को तैयार है। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास करके इसके प्रधान और स्वागत-समिति से सीधी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक अखिल भारतीय युद्ध-समिति बनाने को कहा और यह आन्दौलन अप्रैल में ही छेड देने को कहा। प्रस्ताव में चर्खा कातने और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देने की निन्दा की गई और भारतीय जनता को चेतावनी दी गई कि उसे विधान-परिषद् की उपहासास्पद माग के भ्रमजाल में पडकर गुमराह नही होना चाहिए। नागरिक अधिकारो की स्वतन्त्रता पर किये गए आक्रमणो के विरुद्ध एक जोरदार आन्दोलन आरम्भ करना चाहिए और स्वतत्रता-प्रेमियो को देश की उस गरीव और जागरूक जनता—िकसानो और मजदूरो-के साथ घनिष्ठ-सपर्क स्थापित करना चाहिए, जो आर्थिक स्वतत्रता के लिए हमारी इस लडाई में शामिल हो रही है। इस काम में जितनी ही देर होगी

जनता में उतनी ही निराशा फैलेगी, उनका नैतिक बल उतना ही कम होता जायगा और वे उतना ही अधिक असमजस में पड़ जाएँगे। स्थानीय सम्रामों को और जोरदार बना दिया जाना चाहिए और जहाँ-कही जरूरी समझा जाय और सभव हो, नये आन्दोलन छेड देने चाहिएँ। अन्त में सुभाष बाबू ने लोगों से आन्दोलन के लिए तैयार रहने की अपील की।

गांधी-सेवा-संघ का श्रधिवेशन

२० फरवरी, १९४० को ढाका मे मिलकन्दा मे गाधी-सेवा-सघ का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गाधीजी ने ग्राम-उद्योग-प्रदिश्तनी का उद्घाटन किया। उनके भाषण से पहले विरोधी नारे लगाए गए और बहुत से गाधी-विरोधी मे परचे वाटे गए। इस घटना का जिक करते हुए गाधीजी ने कहा, "अभी मैंने कुछ लोगो को 'गाधी-वाद का विनाश हो' के नारे लगाते हुए सुना है। जो लोग गाधीवाद को घ्वस करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा हक है। आपको विरोधी नारो अथवा उसके विरुद्ध लगाए गए नारो से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप उन्हें शान्ति से सहन करे। जो लोग गाधीवाद के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की पूरी आजादी दीजिए। मैं नहीं जानता गाधीवाद से उनका मतलव क्या है। मैंने कोई नई बात नहीं कही। मैंने तो सिर्फ जो कुछ पहले से मौजूद है, उसे नई शक्ल में पेश करने की कोशिश की है।" गाधीजी ने सेवासघ के सदस्यों को सलाह दी कि वे 'राजनीति' को विल्कुल भूल जाएँ और सघ के सदस्य के नाते उसमें भाग लेना वन्द कर दे। सघ का कोई भी सदस्य काग्रेस का सदस्य नहीं वन सकता। सिर्फ डा॰ राजेन्द्र प्रसाद और सरदार वल्लभभाई पटले को इस बारे में छूट दे दी गई। गाघीजी और उनके सहयोगी कलकत्ता होकर वापस लीट और दूसरे ही स्टेशन पर किसी अजात व्यक्ति ने उनके डिव्ये में एक जूता फेका।

लार्ड जेटलैएड का वक्तव्य

रामगढ के बाद के जमाने में या यो किहये कि काग्रेस के नये साल के मौके पर भी पिछले सालों की तरह ही ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने वे ही वाते दोहराई, जो वे पिछले कई महीनों से कहते चले आ रहे थे। श्री एमरी के भारतमत्री बनने से पहले लाई जेटलैंण्ड ने अपने पद से अवकाश लेने के पूर्व वही पुराना राग फिर अलापा कि हमारा उद्देश्य भारत पर जबरदस्ती कोई बात लादना नहीं है विक हम तो समझौते से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। भारतीयों को अपने लिए उपयुक्त विधान स्वय ही तैयार करना चाहिए, लेकिन पिछले दों सो साल से ब्रिटन का भारत के साथ जो सम्बन्ध चला बा रहा है, उसे देखते हुए वह एकदम उससे अपना

नाता नहीं तोड सकता। देशी राजाओ, रक्षा के प्रश्न, अल्पसंख्यको, ब्रिटिश हितों और आठ करोड मुसलमानों की दुहाई देने के बाद उन्होंने रामगढ में उठाये गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अगर सत्याग्रह शुरू किया गया तो सरकार को विवश होकर उसका पूरी तरह से मुकावला करना पड़ेगा। अन्त में उन्होंने सवाल किया कि क्या काग्रेस देश की उस एकता के प्रश्न पर विवार करना वन्द कर देगी, जिसके लिए वे स्वय इतने उत्सुक हैं? इस सवाल के जवाव पर ही भारत का भाग्य आश्रित है। लार्ड जेटलैण्ड ने यह वक्तव्य भारतीय विवान की घारा ९३ के अन्तर्गत स्थापित की गई सरकारों को जारी रखने के लिए पार्लामेण्ट की स्वीकृति के समय दिया।

हमारी स्थिति

ऐसी स्थिति में सत्याग्रह अनिवार्य होता जा रहा था। काग्रेस ने रामगढ के बाद देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर भी विचार किया। गांधीजी की हिदायतों के मुताबिक प्रान्तीय काग्रेस कमेटियों ने सत्याग्रह कमेटियों के रूप में अपना काम जोरों से शुरू कर दिया और वे सिक्रय तथा निष्क्रिय सत्याग्रहियों की भरती में जुट गईं। उन्हें यह हिदायत भी की गई कि वे अपने आन्तरिक मामलों और रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति का भी विचरण तैयार करती रहें। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि काग्रेस कमेटियों के जो सदस्य निर्धारित प्रतिज्ञा लेन में असमर्थ हो और काग्रेस के अनुशासन में रहते हुए आन्दोलन की जिम्मेदारी अपने कन्थों पर न उठा सकते हो, उन्हें काग्रेस में अपने पदों से हट जाना चाहिये। सिवनय भग शुरू होने से पहले इन शर्तों की पूर्ति अत्यावश्यक बताई गई थी।

अप्रैल, १९४० में जो स्थिति पैदा हो गई थी, नि सदेह वह वडी विकट थी। देश की नैय्या अज्ञात दिशा में वही चली जा रही थी, क्यों कि उसके कर्णधार को अपने लक्ष्य का ज्ञान न था। राजनैतिक दल रक्षात्मक खेल खेल रहे थे। दोनों ही दल आक्रमण करने में आनाकानी कर रहे थे—इसका कारण डर, कायरता या कमजोरी नहीं शी, बिल्क दोनों ही दल वास्तव में लड़ना नहीं चाहते थे। वे इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली कटुता, प्रतिशोध की भावना और स्थायी शत्रुता से बचना चाहते थे। जहाँ तक काग्रेस का सवाल है, उसने साफ-साफ कह दिया था कि अगर अग्रेज भारत के ऊपर से अपना साम्राज्यवादी पजा उठा ले तो वह उनके प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाने को तैयार है। इस बीच एक तरह से अग्रगामी दल ने अपना अल्टीमेटम देकर सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार इसके परिणामस्वरूप होने वाली जोरदार प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा कर सकती थी, लेकिन इसके विपरीत वह इस दल को कोई भी कार्रवाई नहीं करने देना चाहती थी। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय सप्ताह में देश के एक दल को

अनिवाय परिस्थितियों में संग्राम छंड देना पड़ा। देश के उन अधिकाश काग्रेसजनों के सामने, जिन्हें काग्रेस कार्यसमिति के आदेश-पालन में दृढ विश्वास था, यह समस्या थी कि ऐसे नाजुक मौके पर उन्हें क्या करना चाहिये। उनका नेता, उनका संगठन और उनके लिए आदेश मौजूद थे और इनके फलस्वरूप देश को गांधीजी की शर्तों के अन्तर्गत आगामी संग्राम के लिए स्त्री-पुरुषों को तैयार करना था। इस नाजुक घड़ी में जल्दबाजी करना तबाही को बुलावा देना था।

इस जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य की शासँन-व्यवस्था में बडी-बडी घटनाएँ हुई। ब्रिटेन के मित्रमंडल में परिवर्तन हुआ। १० मई १९४० को लाई जेटलैण्ड की जगह श्री एमरी नियुक्त किये गये। इससे पहले वे ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में कई पदों पर रह चुके थे। १९३९ के पतझड में जब एडवई टाम्सन वर्घा आये थे तब उन्होंने कहा था कि भविष्य में ब्रिटेन के छ राजनीतिज्ञ भारत की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगे। इनमें से एक श्री एमरी और दूसरे श्री विस्टन चिल थे। श्री चिल के बारे में कुछ अग्रेजों का मत था कि वह भारतीय स्थित पर काबू पा लेगे। वह या तो भारतीयों को अपना विश्वासपात्र बना लेगे और या फिर समझौते के सारे दरवाजे बन्द कर के कहेगे, "माईल-ला"—और कोई बात नहीं सुनाई जाएगी। इसलिए यह कहा जा रहा था कि भारत की स्थित अब त्रिशकु की भाति बीच में ही लटकी नहीं रहेगी। उसके बारे में अच्छा या बुरा कोई भी निर्णय कर लिया जायगा। सात महीने से अग्रेज ऑखमिचौनी कर रहे थे; पर अब स्थित बदल गई थी और सीधी-सादी वात करने वाला व्यक्ति रगमच पर विद्यमान था। इसलिए गतिरोध का भी अन्त होने वाला था।

सम्राट का संदेश

परन्तु भारत के भाग्य में तो सिवाय निराशा के और कुछ नहीं था। ब्रिटेन की सरकार में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही दो उल्लेखनीय घोषणाएँ हुईं। एक घोषणा सम्राट् द्वारा की गई और दूसरी श्री एमरी द्वारा। महारानी विक्टोरिया की मृत्य के बाद से २४ मई प्रतिवर्ष साम्राज्य-दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसकी नीव अर्लमीय ने डाली थी। पिछले चालीस बरस से यह दिन । नाया जा रहा था और १९४० का यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन ब्रिटेन के सम्राट् ने नीचे लिखा सदेश ब्राडकास्ट किया—

''आज मै इस साम्राज्य के सम्बन्ध मे एक बिल्कुल नई कल्पना पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। अब इसका महत्व अधिक स्पष्ट और असिदग्ध नजर आता है। इस समय इसका सघर्ष एक दूषित और निन्दनीय व्यवस्था से हो रहा है, जिसके साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। हमारे शत्रु हमारे खिलाफ एक शब्द—साम्राज्यवाद—का प्रयोग करते है। इससे उनका मतलव अधिकार और दूसरे

के प्रदेश पर कब्जा है। परन्तु हम जो इस साम्राज्य के स्वतन्त्र वासी हैं, इस शब्द का प्रयोग उन्हीं को मुँह तोड जवाव देने के लिए करते हैं। उनकी ही भावनाएँ दूषित हैं। हमारा उद्देश्य तो हमेशा से शान्ति रहा है।"

श्री एमरी का वक्तव्य

श्री एमरी ने घोषणा की: "पिछली सरकार की भाति हमारी नीति का उद्देश्य भी ब्रिटिश कामनवेल्य (राप्ट्रमडल) के अन्तर्गत भारत को स्वतन्त्र और वरावरी का दर्जा देना है।" आपने यह वात भी स्वीकार की कि भारतीय परिस्यि तियो और भारतीय दृष्टिकोण के उपयुक्त कोई विवान तैयार करन की जिम्मेवारी स्वय भारतीयो पर ही है । कामन सँभा में, अप्रैल, १९४० में लार्ड जेटलैण्ड के शन्दों को दोहराते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का इरादा वर्ष के अन्त में वर्तमान योजना की अन्तर्निहित नीति और अन्य वातो के वारे में फिर से जाच-पडताल करने का है और हमारी नीति भारत के सिर पर कोई वात लादने के वजाय उससे समझौता करने की है। उन्होने कहा, ''मेरी राय में भारत के लिए सर्वोत्तम विधान परिषद् विभिन्न प्रान्तो के १० या १२ प्रतिनिधियो द्वारा तैयार की जानी चाहिये, जिसमें यूरोपियनो सहित सभी वर्गों के लोग हो। भारत की आन्तरिक, वाहरी और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति इस वात की इजाजत नही देती कि उसके लिए भी अन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशो-जैसी वियान परिषद् वनाई जाए। यह प्रश्न किये जाने पर कि इस नाजुक घडी मे भारतीयों के लिए क्या सलाह दे सकते हैं, श्री एमरी ने कहा, "अगर काग्रेस वाइसराय से सहयोग करके काम कर सके तो मुझे इससे वडी खुशी होगी। लेकिन अगर काग्रेस ने वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल कोई काम किया तो यह निस्तिदेह वड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा।"

स्टैफर्डिकिप्स के विचार

यह स्पष्ट हो गया था कि लडाई के फलस्वरूप मिलने वाली आजादी में से भारत को कुछ नही मिलेगा, बिल्क उसे तो उसका पूरा वेग सहन करना पड़ेगा। उसे युद्ध के प्रहार ही सहन करने होगे। सिर्फ सर स्टैफर्डिकप्स ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत से लौटने पर भारत के बारे में कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। २६ अक्टूबर, १९३९ को कामन सभा में दिये गए उनके वक्तव्य का काफी महत्व था, क्योंकि उसमें उन्होंने भारत और उसकी समस्याओं के निराकरण का एक उपाय विधानपरिषद बताया था। उनका कहना था कि सभी श्रेणियों के भारतीयों में यह भावना जोर पकड रही है कि पालिमेण्ट भारतीय समस्याओं पर बहुत

कम, घ्यान देती है। काग्रेस की माग वस्तुत राष्ट्रीय माग है। इसमें सभी विचारो

कें लोग शामिल हैं और यह भारतीय जनता की घोषणा है, लेकिन इतने पर भी आशका की जाती है कि शायद ब्रिटिश सरकार भी इसकी उपेक्षा कर दे। इसका परिणाम सिवनय भग आन्दोलन होगा, क्योंकि काग्रेस का यकीन है कि इस प्रकार सारी जनता की नैतिक शिक्त इस माग के पीछे होगी। काग्रेस का अन्तिम हिथ-यार सारे देश में एक व्यापक हडताल की घोषणा होगी। किसानों और मजदूरों का ऐसा विचार है कि काग्रेस उन्हें जमीदारों और पूजीपतियों के पजे से नजात दिलाएगी और ठीक यही एक कारण है कि काग्रेस का उनके ऊपर वड़ा असर हैं। आज अधिकाश भारतीय बड़ी आनुरता से काग्रेस की ओर देख रहे हैं और इस प्रतीक्षा में हैं कि वह उन्हें क्या आदेश देती हैं। वे भारत के विभाजन के लिए श्री जिन्ना की योजना का विरोध करते हैं। गाधी जी को शान्तपूर्ण नीत पर पूरा यकीन है और उनका विचार है कि हिसात्मक उपायों से नैतिक ताकत कमजोर पड़ती है और उससे सत्य की अजय शक्ति में अविश्वास की भावना प्रकट होती है। मैं सरकार पर जोर दूगा कि वह असदिग्ध रूप में यह घोषणा कर दे कि लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद एक साल के अन्दर उसे स्वराज्य दे दिया जायगा और मिरा विश्वास है कि अगर इस किस्म की कोई घोषणा की जाय तो उससे साप्र-दायिक समस्या भी सुलझ जाएगी और सभव है कि जब तक लड़ाई खत्म न हो जाय काग्रेस भी शान्त होकर बैठ रहे।

लार्ड प्रिवीसील के कथन का प्रतिवाद करते हुए सर स्टैफर्ड किप्स ने कहा कि साप्रदायिक प्रश्न की किठनाई के कारण भारत के लिए केन्द्रीय सरकार की स्थापना का कोई सन्तोषजनक तरीका ढूढ निकालना जिटल हो गया है। यही बात पोलैण्ड के बारे में भी कही जा सकती थी, जहाँ रूसी, यहूदी, जर्मन और पोल रहते हैं। यही बात चेकोस्लोवािकया के लिए भी कही जा सकती थी, जहाँ सूडे-टन, चेक, और स्लोवाक रहते हैं, और अगर यह दलील प्रजातत्र की बिना पर पेश की जाय तो मैं इसे समझने में असमर्थ हूँ, क्यों कि इस तरह से एक अल्पसंख्यक जाति को सरक्षण देने के लिए बहुसंख्यक जाति को उसके उचित अधिकारों से विचत किया जाता है। यह आवश्यक हो सकता है कि बहुमत के कुछ अधिकारों में सशोधन किया जाय और उसे इस पर सहमत कर लिया जाय, जैसा कि काग्रेस ने स्वे च्छा से किया है, लेकिन आपके लिए बहुमत से उसके अधिकार इसलिए छीनना न्यायसगत नहीं कहा जा सकता कि आप अल्पसंख्यकों के सरक्षण का दावा करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में बहुमत को अल्पमत में परिवर्तित करते हैं।

अगर आप प्रजातत्रात्मक सरकार के समर्थक है तो अल्पमत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह बहुमत का शासन स्वीकार करे और यही बात हम आये दिन इस देश_मे देख रहे हैं। अगर आप प्रजातत्र को मानते हैं, अगर आप प्रजातत्र- पद्धित को अपनाना चाहते हैं, जिसका मतलव यह होता है कि आप यह जान सकें कि कौन-सा वर्ग, अथवा जाति या दल वहुमत मे हैं, तो आपको इस पद्धित का परि-णाम भी स्वीकार करना होगा। और इस वक्त, आप चाहे या न चाहे, काग्रेस दल का ब्रिटिश भारत में वहुमत है।

यह वताने से पूर्व कि इस स्थिति को सुलझाने के लिए हमें कीन-से व्यावहारिक तरीको को अपनाना चाहिये, मैं एक और विषय का जिक करना चाहता
हूँ। अगर हम इस वक्त भारत को स्वराज्य देने से इन्कार करते हैं तो उसका
यूरोप की परिस्थित और यूरोप में हमारी किठनाइयो पर क्या प्रभाव पड सकता
है? मेरा खयाल है कि यह प्रभाव तीन तरीको से पड सकता है। पहला तो यह
कि स्वय हमारे ही लोगो पर यह प्रभाव पड़ेगा कि हम आजादी और जमहूरियत
के बारे में जो कुछ कहते हैं, उस पर यकीन नही किया जा सकता। इससे हमारे
युद्ध-प्रयत्न की एकता और उसकी प्रगति कम हो जाएगी। दूसरा यह कि तटस्थ
देशों में, खासकर अमरीका में, जहाँ बहुत से लोग भारत की समस्याओं में गहरी
दिलचस्पी रखते हैं तटस्थता की नीति और ब्रिटश-विरोधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन
मिलेगा। तीसरा यह एक विरोधी और असहयोगी भारत। हमें यह न भूलना
चाहिए कि भारत के इस रख के परिणामस्वरूप सघर्ष के खतरे हैं। और इससे हमें
अपनी कठिनाइयाँ सुलझान में मदद मिलने के बजाय सभवत रकावटो का ही
सामना करना पड़ेगा।

. .मेरा सुझान यह था कि अगर हम यह दाना करते हैं कि हम लड़ाई प्रजातत्र और आजादी के लिए लड़ रहे हैं और नहीं चीज हम ब्रिटिश साम्राज्य के एक हिस्से पर लागू नहीं करते तो भारतीय जनता कहेगी कि "यह एक और उदाहरण है जब ब्रिटेन ने कहा कुछ हैं और किया कुछ और ही है।" इसलिए मेरे खयाल से हमें यह फैसला करना है कि क्या हम नास्तव में भारत की जनता को स्वराज्य देना चाहते हैं—और मुझे यकीन है कि अगर हमने ऐसा ही किया तो वह देश हमारा एक शक्तिशाली सहयोगी राष्ट्र वन जाएगा और भविष्य में सदा के

लिए दोस्ती का हाथ बटाएगा।

काग्रेस ने हमसे अपने युद्ध-उद्देश्यो और भारत के बारे में अपने इरादो पर प्रकाश डालने को कहा है—ऐसी हालत में हमारा क्या जवाव होना चाहिए? मेरा सुझाव है कि हमें यह फैसला अवश्य करना चाहिए और अभी करना चाहिए।

फ्रांस के पतन का प्रभाव

इसके वाद ५ जून को यह घोपणा की गई कि ब्रिटिश-राजदूत ने मो० मोलो-तोव को सुचित कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार का इरादा सर विलियम सीड्स

की जगह सर स्टैफर्ड किप्स को मास्को मे ब्रिटिश-राजदूत नियुक्त करने का है और उनका पद साधारण राजदूत का होगा, जिसे को असाधारण कार्य न करना होगा। रूसी सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सर स्टैफर्ड किप्स की नियुक्ति ब्रिटिश राजनीति का एक महान् आश्चर्य था। ३९ की सिंदयों मे वह कलकत्ता देखने गए और वहा से चुगिकग गए और हवाई जहाज से चीन का दौरा करके मास्को होते इए इग्लैण्ड वाप्स पहुचे। मई के अन्तिम सप्ताह और जून १९४० के पहले सप्ताह में भारत में जो बेचैनी और आन्दोलन देखने में आया उसका वास्तविक कारण उस समय फास में होने वाली घटनाओं और युद्ध की प्रगति की प्रिनिकिया था। फास उस समय युद्ध का प्रधान केन्द्र बन चुका था। वहा कालचक्र बड़ी तेजी से चल रहा था। डेजिंग का पतन, चेकोस्लोवाकिया की पराजय, पोलैण्ड का विनाश, हालैण्ड, बेल्जियम और नार्वे का आक्रमण—ये सभी युद्ध की उस प्रगति की शृखलाएँ थी, जिसकी इतिश्री १४ जून को जाकर फास के पतन के रूप में हुई। १४ जून को काग्रेस की कार्यसमिति का जलसा हो रहा था और फांस के पतन की खबर १५ और १६ जून को रेडियो के जिरये जनता तक पहुची। अब आगे क्या होगा? हिटलर को रोका नहीं जा सकता था? इंग-लैंड पर आक्रमण उसके दिमाग में उस समय चक्कर लगा रहा था। फास के पतन से उसकी डीग और बन्दर-भभिकयों को और भी प्रोत्साहन मिला। अगर इग-लैण्ड पर आक्रमण होता है तो भारत की स्थिति क्या होगी ? पिछले १५० वर्षी से भारत इगलैण्ड के साथ बधा हुआ था। काग्रेस के लिये अपनी स्थिति के बारे में इतना अधिक सोवने की आवश्यकता नहीं थी, जितना कि इस बात पर जोर देने की थी कि भारत का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है। एक सन्ताह तक के गहरे सोच-विवार के बाद काग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमे बहुत से महत्वपूर्ण विषय उठाए गये।

कार्यसिमिति के निश्चय

काग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया कि उसकी बैठके थोडी-थोडी देर बाद हुआ करेगी। उसने अपने सदस्यों को हिदायत की कि वे शी झ बुलाए जाने के लिए हमेशा तैयार रहा करे। इसके अलावा कार्यसमिति ने जुलाई, १९४० के अन्त में अखिल भारतीय महासमिति की बैठक बुलाने का भी फैसला किया। इन बातों का लोगो पर बडा प्रभाव पडा और उन्होंने स्थिति की गम्भीरता का अनुभव किया। इस बीच काग्रेस अपनी अधीनस्थ सभी कमेटियों को सगठन का काम जोरों से चालू रखने और अपनी परीक्षा के समय के लिए प्रारम्भिक तैयारियाँ करने के लिए प्रोत्साहित करती रही। बडी सख्या में प्रतिज्ञापत्र जारी किये गये और कार्यसमिति ने अपनी ओर से श्री आर० एस० पण्डित को स्वयसेवक-आन्दो-

लन की प्रगति के सम्बन्ध में पूरी-पूरी और वास्तिवक जानकारी हासिल करने के लिए सभी प्रान्तों का दौरा करने का आदेश दिया। काग्रेस-सगठन के अन्तर्गत अनुशासन वनाये रखने के सम्बन्ध में अधीनस्य समितियों से पाक्षिक रिपोर्ट भेजने को कहा गया। •खादी को प्रोत्साहन देने, हरिजनों और अल्पसर्यकों के साय घनिष्ठ सपर्क-स्थापन, काग्रेस कमेटियों के दफ्तरों की कार्यकुशलता, सत्याग्रह की तैयारी के सम्बन्ध में काग्रेस के सदस्यों और जनता की प्रतिक्रिया, इस दिशा में मातहत कमेटियों और स्थानीय सस्याओं के सहयोग, प्रचार-कार्य और प्रान्तों के ट्रेनिंग कम्पों (शिक्षण-शिविरों) के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई।

यूरोप की लडाई में जो आश्चर्यजनक घटनाएं घट रही थी उन्हें देखते हुए काग्रेस महासमिति की बैठक बुलाना आवश्यक हो गया था। इसके अलाब काग्रेस कार्य-समिति ने जो नया कदम उठाया था उसकी भी उसे स्वीकृति लेनी थी और खास कर रामगढ के प्रस्ताव को घ्यान मे रखते हुए उसे इस समस्या के विभिन्न पहलुओ की फिर से जाच-पडताल करनी थी। इसलिए कार्यसमिति को अपनी बैठक ३ जुलाई को दिल्ली में बुलानी पड़ी।

दिल्ली में पुरानी कठिनाइया फिर से नये रूप में और नये जोर में प्रकट हुई। गांघीजी अहिंसा के प्रश्न को फिर से सामने लाए। उन्होंने सिमिति का घ्यान इस ओर आकृष्ट किया कि २१ जून को वर्वा में उसने जो वक्तव्य दिया था उससे काग्रेसजनों में भ्रम फैला हुआ है। इसिलए गांघीजी चाहते थे कि कार्यसिमिति फिर से यह ऐलान करे कि जहा तक अन्दरूनी फसाद का सवाल है उसका मुकावला करने के लिए वह सिर्फ अहिंसा और काग्रेस के अनुशासन में वैंघे हुए काग्रेस के स्वयसेवकों पर ही आश्रित रहेगी और हमारे स्वयसेवक सिविक गांडों तथा अन्य ऐसे ही सगठनों से केवल अहिंसा के आधार पर ही सहयोग करेगे। जहा तक बाहरी हमलें के मुकावले का सवाल है, गांधीजी का विचार था कि इससे पहले इस प्रश्न पर विचार करने का काग्रेस को कभी मौका नहीं मिला था, परन्तु यह खयाल करके कि यूरोप के राष्ट्र हिंसा के वल पर अपनी रक्षा करने में असमर्थ सावित हुए हैं, काग्रेस का फर्ज हो जाता है कि वह इस बारे में भी कोई फैसला करे। जब तक ऐसा मौका न आये काग्रेस को सारी स्थित पर खुले दिमाग से सोच-विचार करना चाहिये। इसका मतलव यह था कि काग्रेसी सैनिक ट्रेनिंग या उन कार्रवाइयों में भाग न ले जिनका उद्देश्य भारत को लडाई के लिए तैयार करना था।

वर्धा की तरह दिल्ली में भी स्वयं गांघीजी ने एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया, लेकिन इस बार भी उनके प्रस्ताव की जगह ७ जुलाई, १९४० को एक नया प्रस्ताव पास किया गया। काग्रेस कार्यसमिति ने सारी स्थिति की फिर से

इस्तीफ़ा देने के बाद

समीक्षा करते हुए अनुभव किया कि इस समय ब्रिटेन और भरते की किन सम-स्याओं का सामना करना पड रहा है उन्हें सुलझाने का एक मैं के उपाय ब्रिटेन-द्वारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति है और इसे तत्काल कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उसे केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिये, जो यद्यपि एक अस्थायी साधन के रूप में बनाई जाए, तो भी वह इस तरह से स्थापित की जाय कि उसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सभी निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे और इसके अलावा प्रान्तों की जिम्मेदार सरकारों का सहयोग भी उसे मिलता रहे।" कार्यसमिति ने ऐलान किया कि अगर इन उपायों को अपनाया गया तो काग्रेस देश की रक्षा के लिए प्रभावशाली सगठन में पूरा-पूरा सहयोग देने को तैयार हो जायगी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितनी बार गलत-फहमियाँ फैली और उसका गलत अर्थ किया गया, उतनी ही बार उनका फिर से विश्लेषण करना भी आवश्यक हो गया।

मौलाना त्राज़ाद श्रौर जिन्ना साहब

अब हम कुछ देर के लिए अपने मुख्य विषय को छोडकर एक और विषय उठाना चाहते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह से पूर्व दिल्ली में पज़ाब और बगाल के प्रधान मित्रयों तथा काग्रेसी नेताओं के बीच कुछ बातचीत हुई। स्वय मौलाना आजाद सर सिकन्दर से मिल चुके थे। श्री जिन्ना ने इसका विरोध किया और यह कहा कि लीग की विकंग कमेटी के पीठ-पीछे प्रधानमित्रयों को बातचीत करने या सुलह-सफाई करने का कोई अधिकार नहीं है और न उन्हें इसकी इजाजत ही दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में काग्रेस के प्रधान की हैसियत से मौलाना साहब ने श्री जिन्ना को एक तार भेजने का साहस किया और उनसे प्रार्थना की कि वह इसे गोपनीय समझे। परन्तु श्री जिन्ना ने उसका तुरन्त उत्तर देकर दोनो तार अखबारों को प्रकाशनार्थ दें दिये। दोनो तार नीचे दिये जाते हैं।

श्री जिन्ना के नाम मौलाना आजाद का तार यह था—"मैने आपका जुलाई का वक्तव्य पढा है। दिल्ली के प्रस्ताव में काग्रस ने जिस राष्ट्रीय सरकार का जिन्न किया है उससे उसकी मुराद निश्चित रूप से सयुक्त मिन्नमण्डल है, किसी दल विशेष की सरकार नहीं। लेकिन क्या लीग की स्थिति यह है कि वह दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों पर आश्रित सरकार को छोडकर कोई और अस्थायी सरकार वनाना स्वीकार नहीं कर सकती? अगर यह बात ऐसी ही है तो कृपया तार द्वारा इसे स्पष्ट कर दीजिए।"

श्री जिन्ना ने यह उत्तर दिया—"मुझे आपका तार मिला। मैं इसे गोपनीय नहीं रख सकता। चूकि आप पूरी तरह से मुस्लिम भारत का विश्वास खो बैठे है, इसलिए मैं आपसे पत्र-व्यवहार-द्वारा या किसी और तरीके से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ। क्या आप यह महसूस नहीं कर सकते कि आपको काग्रेस का प्रधान महज एक दिखाने के रूप में बनाया गया है, जिससे कि काग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय नजर आए और वाहरी मुल्कों को घोखा दिया जा सके? आप न तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं और न हिन्दुओं के ही। आप दोनों में से किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। काग्रेस एक हिन्दू सस्था है। अगर आप में आतमसम्मान की भावना है तो आप फीरन इस्तीफा दे दे। अब तक आपने लीग के खिलाफ अपना पूरा जोर लगाया है। आप जानते हैं कि आप इसमें बुरी तरह असफल रहे हैं। अब आप इसे छोड दीजिए।"

महासमिति की वैठक

पूना में काग्रेस महासमिति ने केवल ७ जुलाई १९४० के दिल्ली-प्रस्ताव का ही समर्थन किया और यह स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्त लड़ी जानेवाली लड़ाई में काग्रेस अहिंसा के सिद्धान्त पर कड़ाई से अमल करती रहेगी, फिर भी मौजूदा हालतों में वह भारत की राप्ट्रीय रक्षा के मामले में इस सिद्धान्त को लागू नहीं कर सकती। महासमिति ने इस वात पर भी जोर दिया कि काग्रेस का सगठन अहिंसा के आधार पर ही जारी रहना चाहिये और काग्रेस के सभी स्वयसेवक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते समय अहिंसा पर चलने को बाध्य हैं और इस सिद्धात के अलावा किसी और सिद्धात पर काग्रेस का कोई भी स्वयसेवक-सगठन नहीं कायम हो सकता। आत्मरक्षा के लिए और भी ऐसे जो स्वयसेवक-सगठन होगे और जिनके साथ काग्रेस को सहयोग करना होगा—उन्हें भी अहिंसा पर दृढ रहना होगा। इस सम्बन्ध में काग्रेस कार्यसमिति ने देश की राजनैतिक स्थित पर वर्धा में एक उपयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया था। जिसे पूना में काग्रेस महासमिति के अधिवेशन के समय सदस्यों में क्यापक रूप से प्रचारित किया गया था।

पूना में कार्यसमिति का प्रस्ताव कोई सुगमता से नहीं पास हो गया था। प्रस्ताव के हक में ९७ और उसके खिलाफ ६३ वोट पडे। विरोधियों में कुछ उल्लेखनीय नाम ये हैं वाबू राजेन्द्र प्रसाद, डा० प्रफुल्ल घोष, आचार्य कृपलानी श्री शक्रराव देव और श्री हरेकृष्ण मेहताव। राजेन्द्रबाबू ने प्रस्ताव के विरोध में भाषण दिया।

कार्यसमिति के मत-भेद के बारे मे और जिस तरीके से यह प्रस्ताव महा-समिति मे पास हुआ था उसके सम्बन्ध मे अनावश्यक रूप से कोई बात गुप्त नहीं रखी गई थी। विभिन्न दल खुले रूप में सामने आए। यदि रायवादियों का नारा बिना शर्त सहयोग का था तो श्री राजगोपालाचारी शर्त के साथ सहयोग देने के पक्ष में थे। यदि पडित जवाहरलालजी कुछ शर्ती पर नैतिक सहयोग के पक्षपाती थे तो गाधीजी बिना शर्त के नैतिक सहायता के। वह स्वय पूना में नहीं आए थे। लेकिन पूना के बाद उन्होंने विशुद्ध अहिसा के पक्षपातियों और शेव लोगों का अन्तर स्पष्ट रूप से बताया था।

गांधीजो का कांग्रेस से संबंध-विच्छेद

जब पूना मे दिल्ली का प्रस्ताव पास हुआ तब देश भर मे खलवली मच गई और आत्मनिरिक्षण किया जाने लगा। एक तरफ तो वे लोग थे जिन्हें इस वात का सन्तोप था कि अहिसा की दुर्बोधता, उसकी आध्यात्मिकता और प्रतिदिन के जीवन की उसकी अवास्तविकता का अब देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन देश की अधिकाश जनता को इस पर खेद हुआ। गाधीजी पिछ्ले २० साल से देश का नेतृत्व कर रहे थे और उनके नेतृत्व में देश ने दो ही दशको में इतनी उन्नति करली थी जितनी दो शताब्दियों में की जा सकती थी। उन्होने शक्तिशाली ब्रिटेन को भारतीय जनता से समझौता करने पर विवश कर दिया था। इसलिए अब इस नाजुक घडी मे उनका काग्रेस से अलग हो जाना देश को बहुत खेदजनक प्रतीत हुआ। लेकिन क्या वस्तुतः स्थिति ऐसी ही थी,? नहीं। अब भी देश को उनका नेतृत्व प्राप्त था। लेकिन यह समय तो एक नए युग का सदेश लेकर आया था। गाथीजी को पराजित नहीं होना पडा था, बल्कि उन्हें तो ससार के सामने एक नये रूप से प्रकट होना था। महान् पुरुषों के जीवन में अक्सर ऐसे ही अवसर आया करते हैं, जब उन्हें कसौटी पर परखा जाता है। इस परिक्षा के सायन होते हैं वड़े-वड़े ख़तरे और महान् अवसर। स्थायी नेतृत्व का रहस्य इसमें है कि नेता यह जानता हो कि वीच का मार्ग कब अिंदियार किया जाना चाहिये। वह यह जानता हो कि सयम से कैसे काम लेना है। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए ३१ जुलाई, १९४० को गांधीजी ने जो लेख लिखा उसमे उन्होने कहा—"१९३४ में वम्बई में मैं काग्रेस से इसलिए वाहर आया कि उसकी अधिक सेवा कर सकूँ। वाद कि घटनाओं ने सावित कर दिया कि मेरा काग्रेस से पृथक् होना उचित था। इस समय भी मैं जो काग्रेस से अलहदा हुआ हूँ, उसका भी यही मकसद है।"

जिस प्रकार प्रकृति का एक ही स्पर्श सारे संसार को एकता के सूत्र में पिरो देता है, उसी तरह विटिश नौकरशाही के एक ही स्पर्श ने सारे भारत को एक परिवार वना दिया था। ऐसे समय में जब कि काग्रेस जैसी सुदृढ चट्टान में एक मामूली-सा छिद्र हो जाने पर ऐसा खतरा प्रतीत हो रहा था कि वह एक वड़ा भारी दरार वन जाएगी—अर्थात् काग्रेस में बहुत भारी मतभेद पैदा हो जाएगा—श्री एमरी ने कामन-सभा में भारत की स्थित के सम्बन्ध में श्री सोरेन्सेन के बहुत ही संगत प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे सब की आँखे खुल गईं। श्री एमरी ने

भारत की परिस्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने उसकी कोई कद्र ही नहीं की। परन्तु गांधीजी ने श्री एमरी को चुनौती देते हुए उनके इस दृष्टिकोण को गलत बताया। गांधीजी ने स्वय बताया कि काग्रेस से अलग हो जाने पर भी मेरा खयाल है कि जनता का एक वडा हिस्सा अब भी मेरा मार्ग-दर्शन चाहता है और वह तब तक चाहता रहेगा, जब तक कि मेरे लिये यह समझा जायगा कि मैं हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा सत्याग्रह की भावना का अधिक प्रतिनिधित्व करता हूँ। गाधीजी ने वताया कि व्रिटिश इतिहास की इस अत्यन्त नाजुक घड़ी में काग्रस ने ब्रिटिश सरकार को परेशान न करने के ख्याल से जिस सयम से काम लिया है उसका कम अन्दाजा लगाकर भारत-मत्री ने वडी भारी भूल की है। उनका खयाल था कि अगर यह सयम न रहे तो मुमिकन है कि आग भडक उठे और उसका कैसा असर पडे,यह कोई नही जान सकता। सत्याग्रह का शस्त्र ऐसा है कि उसका उपयोग अन्दरूनी कम-जोरियो के वावजूद किया जा सकता है। इसलिए सत्याग्रह को स्थगित करने का आखिरी उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश सरकार को परेशान न किया जाय। लेकिन काग्रेस के इस सयम की भी एक हद है। काग्रेसियों में यह शक बढता जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार काग्रेस के इस सयम का फायदा काग्रेस को कुचलने के लिए उठा रही है। उदाहरण के तीर पर वे बड़ी सख्या में काग्रेसियों की गिरफ्तारियों की वात कहते हैं। गांधीजी ने आगे चलकर कहा, "अगर यह सावित हुआ कि मेरा यह सन्देह दृढ आघार रखता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह शुरू करने से नहीं रोक सकती। लेकिन यह मेरी प्रायना और कोशिश है कि उसे तब तक बचाऊँ जब तक ग्रेट ब्रिटन पर से विपदाओं के वादल न उठ जायेँ।"

वाइसराय का वक्तव्य

खतरे की इस घण्टी पर अपने विचार प्रकट किये हुए गांधीजी को अभी मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा कि वाइसराय महोदय ने ८ अगस्त का अपना प्रसिद्ध वक्तव्य प्रकाशित कर दिया। इसकी एक अग्रिम प्रति उन्होंने ४ अगस्त को उटकमड से काग्रेस-प्रधान को भेज दी थी और २० अगस्त के लगभग उन्हें मुलाकात करने का निमत्रण दिया था। यह वक्तव्य बहुत वडा और विस्तृत था। इसमें विभिन्न राजनैतिक नेताओं से मुलाकात करने और सम्राट् की सरकार से सलाहमशवरा करने के बाद कुछ प्रतिनिधिक भारतीयों को अपनी शासन-परिपद् में शामिल होने का निमत्रण देने और एक युद्ध सलाहकार परिषद् की स्थापना करने की बात कहकर उन्होंने अल्पसल्यकों और उचित समय आने पर ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के अन्तर्गत नयी वैधानिक योजना बनाने के सम्बन्ध में की जाने वाली

व्यवस्था पर प्रकाश डाला। वाइसराय का वक्तव्य अप्रत्याशित था। इससे नरम और उदार दलवालों को सन्तोष हुआ, पर काग्रेस को नहीं। अगर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, प्रांतों में फिर से मंत्रिमण्डल स्थापित हो जाय, विधान-परिषद् की माग मान ली जाय, ब्रिटिश सरकार तुरन्त ही उसका आयो-जन करें और अगर देश की प्रजातत्रात्मक सरकार के सचालन में अल्पसंख्यकों और राजाओं को भारत की भावी प्रजातत्रात्मक सरकार को रद करने का अधिकार न दिया जाय तो शायद काग्रेस इन प्रस्तावों पर सोच-विचार कर सके। लेकिन काग्रेस की यह स्थिति फास के पतन से पहले की थी। अब फांस के पतन के बाद जब कि साम्राज्यवाद कमजोर हो चुका था और काग्रेस स्पष्ट एव असदिग्ध शब्दों में पूर्ण स्वतत्रता की घोषणा कर चुकी थी, वाइसराय महोदय एक ऐसी विधान-परिषद् का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसकी माग सितम्बर, ४२ में की गई थी। जब उसकी माग की गई थी तब उसे ठुकरा दिया गया था। अब जब कि काग्रेस तत्काल पूर्ण स्वाधीनता की माग कर रही है तब वाइसराय महोदय स्वतत्र और बराबर की साझेदारी का राग अलापने लगे थे।

मौलाना श्राज़ाद श्रीर वाइसराय

वाइसराय ने मौलाना आजाद को इस बारे में जल्दी ही जवाब भेजने से पहले—और अगर सभव हो सके तो २१ अगस्त से पहले-पहले—मुलाकात के लिए बुलावा भेजा, जिससे वह यह जान सके कि काग्रेस के लिए उनकी केन्द्रीय सरकार और युद्ध सलाहकार परिषद में शामिल होना सभव हो सकेगा अथवा नहीं। उन्होंने लिखा, "मेरा खयाल है कि काग्रेस की ओर से कोई नियमित जवाब भेजने से पहले शायद आपके लिए इस सम्बन्ध में मुझसे और बातचीत करना सुविधाजनक हो।" वाइसराय चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इन फैसलों को अमल में लाया जाय। उन्होंने बताया कि मेरा खयाल अगस्त के अन्त या सितम्बर के मध्य तक इन दोनों सस्थाओं में लिये जानेवाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा कर देने का है। काग्रेस के प्रधान ने वाइसराय से पूछा कि जब सरकार ने पहले से ही एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला कर लिया है तब फिर उस हालत में और बातचीत करने से लाभ क्या होगा? इसके जवाब में वाइसराय ने लिखा—"सम्राट् की सरकार की नीति मेरे वक्तव्य में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। मुझे आशा है कि काग्रेस के लिए इन शर्तों के अन्तर्गत मेरे साथ केन्द्रीय सरकार और युद्ध सलाहकार परिषद में शामिल होना सभव हो सकेगा।" इसके साथ ही उन्होंने दुबारा उन्हें निमंत्रण देते हुए लिखा— "अगर अपना निश्चित जवाब भेजने से पहले आप इस विषय पर और बातचीत करना चाहे तो कर सकते हैं।" ८ अगस्त की घोषणा की शर्तों के अन्तर्गत काग्रेस के

प्रधान न कोई और वातचीत करना लाभदायक नहीं समझा। चूिक इस घोषणा में राष्ट्रीय सरकार का तो कोई उल्लेख तक भी न था, इसलिए मौलाना साहव ने यह निमत्रण अस्वीकार कर दिया।

वाइसराय के वक्तव्य और काग्रेस के प्रधान के बीच उनके पत्र-व्यवहार के कुछ देर बाद ही भारत-मत्री ने १४ अगस्त को पार्लिमण्ट में एक घोपणा की। वाइसराय की ८ अगस्त बाली घोपणा और पार्लिमण्ट में भारत-मंत्री के वक्तव्य पर अगर एक साथ विचार किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये दोनों घोपणाए भारत की राजनैतिक पिरिस्थित, उसके वैधानिक पहलू और केन्द्रीय सरकार के तत्काल पुर्नीनर्माण के सम्बन्ध में एक अधिकृत निर्णय के रूप में थी। पहली वार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर लगाया जानेवाला यह आरोप स्पष्ट कर दिया कि वह जबतक उसका वस चलेगा सत्ता हस्तान्तरित नहीं करेगी। इसका तो साफ मतलब यह हुआ कि मौजूदा नौकरशाही और गैर-जिम्मेवार हुकूमत तबतक जारी रहेगी जबतक कोई भी दल या राजे (अपनी प्रजा को छोडकर) अथवा विदेशी स्वार्थ भी भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वारा बनाए गए किसी भी विधान पर आपित उठाते रहेंगे। १८ अगस्त, १९४० को वर्ध में कार्यसमिति की जो बैठक हुई उसके फैसले का यही तत्त्वमात्र था। एक वार फिर गांधीजी और कार्य-समिति को एक कडी परीक्षा में से गुजरना पडा।

गांधीजी के नेतृत्व की मांग

पूना के बाद की परिस्थित और सरकारी ऐलान वास्तव में इतने सरल न थे, जितने कि ऊपर से दिखाई देते थे। समय-समय पर पेचीदा और जिटल समस्याओं का खड़ा हो जाना अनिवार्य था। यह सच है कि भारतीय माग को घृणापूर्वक ठुकरा दिया गया था और जिन लोगों ने यह माग की थी और जिन्होंने इस पर आपित्त उठाई थी, वे सभी व्यग्रता से गांधीजी की ओर देख रहे थे। इसलिए सर्वथा स्वाभाविक था कि इस सम्बन्ध में उनकी सलाह ली जाती। इसी प्रकार यह भी सर्वथा स्वाभाविक था कि गांधीजी यह महसूस करते कि उनके लिये नये वातावरण में ऐसी सलाह देना असभव था।

आप पूना-प्रस्ताव की उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जबतक यह प्रस्ताव कायम था, राष्ट्रीय सगठन को बढाने की शक्ति का कायम रहना सभव न था। गांधीजी का दृढ विचार था कि उक्त प्रस्ताव वर्धा, दिल्ली और पूना में की गई भारी गलती या भूल का परिणाम था। वह जान-बूझकर पूना में काग्रेस महासमिति की बैठक में नहीं शामिल हुए, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण उन लोगो पर किसी किस्म का दबाव पडे। अत पूना के प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये बिना उनके लिए कार्यसमिति का मार्ग-प्रदर्शन करना कठिन था।

सारी स्थिति को घ्यान में रखते हुए हर एक ने यह महसूस किया कि गांधीजी को इस बारे में पूरी आजादी देनी चाहिये और इसके लिए शायद वे कार्यसमिति से अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहें। लेकिन यह भी महसूस किया गया कि यह संशोधन नयी कार्यसमिति को करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कार्यसमिति के अधिकाश संदस्य पूना प्रस्ताव के समर्थक थे।

कमेटी के सामने कई रास्ते थे। एक रास्ता यह था कि कार्यसमिति को स्यगित करके सारा काम गांधीजी को सौप दिया जाय, दूसरा यह कि जो लोग कार्य-समिति से पृथक हो जाए, उनकी जगह ऐसे नये सदस्य लिए जाएँ जिन्हें उनपर विश्वास हो। एक और कठिनाई यह थी कि सत्याग्रह किस वात को लेकर शुरू किया जाय? गाधीजी आजादी को इसका केन्द्र-विन्दु नही वनाना चाहते थे। वह तो यह चाहते थे कि सारी बात उन्ही पर छोड दी जाय और यह फैसला वही करें कि सत्याग्रह गुरू करने का तात्कालिक कारण क्या हो। वह किस विना पर छेडा जाय। देश की स्थिति गम्भीर थी। जो नीजवान काग्रेस के स्वयसेवक होते और उसके कार्य में प्रमुख भाग लेते थे, उन्हें सैकडो की तादाद में जेल में ूसा जा रहा था। कोई दो हजार से ऊपर नवयुवक जेल में जा चुके थे। सभी जगह मजदूर-संगठन का काम करनेवालो को पकडा जा रहा था। सम्मेलनों पर प्रति-बन्ध लगाए जा रहे थे। लोगों को घरों में नजरवन्द रखना आम वात हो गई थी। इन आदेशो का कडाई से पालन किया जा रहा था। लोग घडाघड गिरफ्तार हो रहे थे और राजवन्दियों को विना मुकदमा चलाए नजरवन्द किया जा रहा था। जिलों में लोगों पर इस तरह के प्रतिवन्य लगाए जा रहे थे—(१) उन्हें प्रति सोमवार कोतवाली में हाजिरी देनी पडती थी, (२) उन्हें किसी राजद्रोहात्मक आन्दोलन या युद्ध-विरोधी प्रचार में भाग लेने की इजाजत नहीं थी, (३) किसी स्कूल या कालेज के विद्यार्थियों से किसी तरह की वातचीत, पत्र-व्यवहार या मपर्क नहीं रख सकते थे, (४) किसी तरह की सभा में गरीक नहीं हो सकते थे, और (५) अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो रवाना होने से कम-मे-कम २४ घण्टे पहले उसकी इत्तली पुलिस-याने में और इसके साथ ही समय की भी सूचना देनी पटती थी। २ जुटाई, १९४० को स्वय मुभाषचन्द्र वोस को भारत-रक्षा कानून के मातहत कलकत्ता में एल्गिन रोट पर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह परिस्थिति को वरदास्त करना मुस्किल हो गया था।

महासमिति की वैठक

इस गभीर परिस्थिति पर मोच-विचार करने के लिए १५ मितम्बर को बम्बई में काग्रेस महासमिति की एक बैठक बुटाई गई। १५ और १६ मितम्बर, १९४० को बम्बई में काग्रेस महासमिति ने पिछले दो महीनों में देश की जो हालत हो गई थी उस की समीक्षा की और यह घोपणा की कि दिल्ली का प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति पूना में दी गई थी, अब अमल में नहीं रहा और वह खत्म हो गया। इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा कि काग्रेस ने अब तक स्वय अपने ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा रखा था—जिस सयम से वह चल रही थी, उसका मतलव यह नहीं था कि वह अपनी हस्ती ही मिटा देना चाहती है। काग्रेस का यह इसरार है कि अहिसा के अनुसार अपनी नीति पर चलने की उसे पूरी आजादी रहे, परन्तु काग्रेस की यह मर्जी नहीं है कि मजबूरी की हालत में भी वह अपना अहिसात्मक विरोध उस हद के पार ले जाय जितनी आजादी की रक्षा के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार सितम्बर के मध्य में भारत के इतिहास में एक नया अव्याय शुरु हो रहा था। लड़ाई को गुरु हुए एक साल और १५ दिन हो चुके थे। हर सभव कोशिश की गई था कि ब्रिटेन की मुसीबत के दिनों में कोई सग्राम न शुरू किया जाय, यहा तक कि गांधीजों के नेतृत्व की भी उपेक्षा कर दी गई थी। आखिर यह प्रतिज्ञा पूना में तोड़ दी गई, परन्तु उसका फल अभी सामने नहीं आया था। अब सिर्फ यह बाकी रह गया था कि फिजूलखर्च पुत्र अपने विवेक और अपनी कांबलियत का गर्व गवाकर खाली हाथ और पछताता हुआ, विश्वसनीय होकर और मिन्नते करता हुआ फिर से अपने पिता के पास वापस चला आए। दुनियावी विचारों में फसी हुई सन्तान अपने पिता की चेतावनी या डाट-डपट को बहुत अविक नैतिक समझ सकती है, लेकिन उनकी बेवकूफी या भूल जल्दी ही भुला दी जाती है। अगर इस बात की आम चर्चा न हुई होती कि गांधीजी फिर से सेनापित बन रहे हैं और जल्दी ही ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जायगी तो बम्बई में बहुत अधिक खीचातानी हुई होती। अब सिर्फ राष्ट्र को अपने अटूट आज्ञापालन का परिचय देना होगा।

कार्यसमिति का निश्चय

उक्त परिस्थितियों में कार्यसमिति ने दो महत्वपूण प्रस्ताव पास किये, एक सिवनय अवज्ञा के स्थिगत करने के सम्बन्ध में और दूसरा केरल प्रान्त की परिस्थिति के बारे में। कार्यसमिति चाहती थी कि उसके सत्याग्रह शुरू करने से पहले देश में पूरी शान्ति और व्यवस्था कायम रहें और वातावरण अहिसात्मक बना रहें। लेकिन १५ सितम्बर को केरल में पुलिस के एक सब-इस्पेक्टर को पत्थरों से मार डाला गया था। इस घटना के कारण काग्रेस बहुत अधिक परेशान थी। इसलिए उसने केरल प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के खिलाफ अनुशासन-भग की शिकायतों और १५ सितम्बर को सभाओं में जो गडबड हुई थी, उसकी जाच-पडताल करने के लिए एक समिति वहाँ भेजनी आवश्यक समझी। आगे कार्य-समिति ने सभी काग्रेस-सगठनों से आग्रह

किया कि वे "सविनय अवजा"—चाहे वह व्यक्तिगत हो या किसी और किस्म की—तव तक के लिए वन्द कर दें जब तक कि उन्हें गांधीजी की ओर से कोई निश्चित हिदायत न दी जाय। गांधीजी वाइसराय के साथ अपनी आगामी मुलाकात की सफलता के लिए इसे आवश्यक समझते थे। रिजस्टरशुदा और गैर-रिजटरशुदा काग्रेसजनो और काग्रेस से प्रेम रखनेवाले सभी स्त्री-पुरुपों के अनुशासन की कसीटी के रूप में भी उन्हें यह आवश्यक प्रतीत होता था। वह मानते थे कि यदि सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करना पड़े तो उसकी सफलता के लिए थोडे समय तक आज्ञा-पालन की शिक्षा लेना बहुत जरूरी और अनिवार्य है।

86

सत्याग्रह और उसकी प्रगति : १९४०-४१

गांधीजी का पत्र

ऐसे समय में जब कि दुनिया भारी संहार और सर्वनाश में जुटी हुई थी, सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो शान्ति और सद्भावना का युगो पुराना सन्देश लिए सम्य मानवता के बीच अपना सिर ऊँचा किय खडा था। ऐसे ही नुअवसर पर गांधीजी की ७२ वी शुभ वर्षगांठ आई। ७१ वे जन्मदिन के अवसर पर गांधीजी ने लड़ाई छिड़ते ही हिटलर के नाम अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था। यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सालभर में भी अधिक समय तक कोशिया करते रहे और इस बीच उन्होंने 'प्रत्येक अग्रेज के प्रति' अपना प्रसिद्ध पत्र लिया, जिसमें उन्होंने कहा—"भरा प्रत्येक अग्रेज ने, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिन्से में क्यों न हो, निवेदन है कि वह राष्ट्रों के पारस्परिक सबधों और दूसरे मामलों का फंतला करने के दिए युद्ध का मार्ग छोड़कर अहिंगा का मार्ग स्वीकार करे। आपके राजनीतिशों ने यह घोषणा की है कि यह युद्ध प्रजातन के निटान्त की रक्षा के लिए लटा जा रहा है। परन्तु मैं आपने यह कहना है कि इस यद्ध के नमाप्त होने पर जीत चाहे लिस पक्ष की हो, प्रजातन्त्र का वहीं नामोनिशान भी व निरोग। यह युद्ध मनुष्य-लाति पर एक अभिशाप और चेनावनी के रूप में उत्तरा है। यह शापर मह है। आज तक बभी इन्सान इन्सानिदन को इस ज्वर नहीं भूना था, जितना कि एक इस युद्ध के असर ने अल रहा है। आइ

इन्सान की करतूते हैवान को भी शर्मिन्दा कर रही हैं। मैं प्रकृति की इस चेतावनी का अर्थ युद्ध छिडते ही समझ गया था। मगर मेरी यह हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आपसे कुछ कहूँ, किन्तु आज ईश्वर ने मुझे हिम्मत दे दी हे और मौका भी अभी हाथ से निकल नहीं गया है। आप लोग नाजीवाद का विनाश करना चाहते हैं, मगर आप नाजीवाद की कच्ची-पक्की नकल करके उसका कभी नाश नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि विटेन हारे। मगर मैं यह भी नहीं चाहता कि वह पाश्विक वल की परीक्षा में जीते, भले ही वह पश्वल वाहुवल के रूप में प्रदिश्त किया जाय या वृद्धि-वल के रूप में। आपका वाहुवल तो जगत्प्रसिद्ध है। क्या आपको यह प्रदर्शन करने की जरूरत है कि आपका वृद्धिवल भी तवाही करने में सबसे ज्यादा शिक्तशाली है मुझे आशा है कि आप लोग नाजियों के साथ इस किस्म के मुकावले में उतरना अपनी वेइज्जती समझेंगे।

'मै दावा करता हूँ कि मै ब्रिटेन का आजीवनऔर नि स्वार्थ मित्र रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था कि मै आपके साम्राज्य पर भी मुग्ध था। मैं समझता था कि आपका राज्य हिन्दुस्तान को फायदा पहुँचा रहा है। मगर जब मैंने देखा कि वस्तुस्थित ऐसी नही है, इस रास्ते से हिन्दुस्तान का भला नही हो सकता, तब मैंने अहिंसक तरीके से साम्राज्यवाद का सामना करना शुरू किया और आज भी कर रहा हूँ। मेरे देश की किस्मत में आखिर कुछ भी लिखा हो, आप लोगो के प्रति मेरा प्रम वैसे ही कायम है और रहेगा। मेरी अहिंसा सार्वभौम है और वह सारे जगत् के प्रति प्रेम मागती है और उस जगत का आप लोग कोई छोटा हिस्सा नहीं हैं। आप लोगो के प्रति अपने प्रेम के कारण ही मैंने यह निवेदन किया है।"

च्यक्तिगत सत्याग्रह का श्रारंभ

गाधीजी के उक्त पत्र का अग्रेजो पर कोई प्रभाव नहीं पडा। उन्होने देखा कि लडाई की लपटे यूरोप में दूर-दूर तक फैलती जा रही थी और इनके कारण ब्रिटेन का दिल भारत के प्रति नरम होने के बजाय और भी सख्त और कठोर होता जा रहा था। वह इतना निर्मम और निर्दय बनता जा रहा था, जिसकी कल्पना तक भी नहीं की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में देश घीरे-धीरे सत्याग्रह-संग्राम की तीसरी मजिल तक पहुँच गया और १७ अक्तूबर को सत्याग्रह-संग्राम की रणभेरी बज उठी। श्री विनोबा ने वर्धो से पाच मील दूर अपने निवास-स्थान पवनार गांव में १७ अक्तूबर को युद्ध-विरोधी एक भाषण देकर सत्याग्रह का श्रीगणेश कर दिया। न तो सभा पर ही कोई रोक लगाई गई और न श्री विनोबा को ही पकडा गया। हा, इतना अवश्य हुआ कि देशभर के अखबारों को चेतावनी दे दी गई कि वे उनके भाषण अथवा उनके कार्यक्रम के बारे में कोई समाचार न छापे। श्री विनोबा पैदल चलकर गाव-गाव में भाषण देते रहे। आखिरकार

२१ अक्तूबर को उन्हें गिरफ्तार करके तीन महीने की सादी कैंद दी गई। सजा पानेवाले दूसरे व्यक्ति पिडत जवाहरलाल थे। जवाहरलाल ने प्रान्त के विभिन्न जिलो का दौरा अभी खत्म ही किया था। उन्होंने मौजूदा परिस्थिति पर सभी तरह के बहुत से भाषण दिये। उन्हें वर्धा आने को कहा गया था जहाँ की वापसी पर उन्हें ३१ अक्टूबर, १९४० को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस मिजस्ट्रेट के यहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया, उसने उन्हें ४ साल की सजा दी। १७ नवम्बर को सरदार पटेल भी हिरासत में ले लिये गये। उन पर कोई इलजाम नहीं लगाया गया और न मुकदमा ही चलाया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अनिश्चित अविध तक के लिए नजरबन्द कर दिया गया। देश के विभिन्न भागों में सत्याग्रह करने वाले लोगों की भरमार थी। गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला, जिसमें उन्होंने इस वात पर एक दफा फिर जोर दिया कि लोग नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किसी किस्म का प्रदर्शन न करे। बाद के सप्ताह में देश के विभिन्न भागों में वहुत से प्रसिद्ध नेता गिरफ्तार कर लिये गये। बडे बड़े शानदार प्रदर्शन कही भी नहीं हुए।

नवम्बर के अन्त तक अधिकांश मत्री और पार्लामेटरी सचिव तथा अखिल भारतीय महासमिति के बहुत से सदस्य जेलो में जा चुके थे। नये वर्ष के प्रारंभ में काग्रेस के प्रधान पकड लिये गये। इसके अलावा इसी वर्ष जमीयत-उल-उलेमा ने भी सत्याग्रह आन्दोलन में शरीक होने का फैसला कर लिया। उधर उत्तर-पिंचमी सीमा-प्रात के प्रधान मत्री डा० खान साहब सत्याग्रह करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गये, पर बाद में रिहा कर दिये गये। मध्य-प्रात में सरकार ने स्त्री सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना बन्द कर दिया।

आन्दोलन शुरू होने से पहले प्रत्येक सूबे मे उसके सवध मे वडी सावधानी के साथ जाच-पडताल कर ली गई। ज्यो-ज्यो कार्यसमिति, व्यवस्थापिका सभाओं और अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति के सदस्य अपने को गिरफ्तारी के लिए पेश करते रहे त्यो-यो आन्दोलन जोर पकडता गया। कुछ प्रातो मे सरकार ने सदस्यों को सत्याग्रह करने से पहले ही नजरवन्द कर दिया। श्री वल्लभ भाई, श्री भूलाभाई, श्रीमती सरोजिनी और वम्बई के भ्तपूर्व मित्रयो, स्पीकर और वम्बई की कौसिल के प्रधान—इन सभी व्यक्तियों को नजरवन्द कर दिया गया। सद्रास में वहाँ के मित्रयों ने सत्याग्रह किया और उन्हें दण्ड दिया गया। सिर्फ स्पीकर, चीफ पार्लामेटरी सेकेटरी और चार-पाँच दूसरे व्यक्ति नजरवन्द कर लिये गये। इसी प्रकार संयुक्त-प्रात, मव्य-प्रात और विहार में भी कुछ मित्रयों को नजरवन्द कर लिया गया। आसाम और उडीना में उन्हें सजा दी गई, परन्तु उत्तर-पिवचमी सीमा-प्रांत में न तो मित्री और न कोई अन्य ही पकड़ा गया। राजेंद्र वावू चूिक बीमार थे, इसिलए उन्हें जेल जाने की इजाजत नहीं दी गई। जेल जाने के थोड़ी देर वाद

श्रीमती सरोजिनी देवी वीमार पड गईं, इसिलये उन्हें रिहा कर दिया। श्री कृपलानी काग्रेस के दफ्तर का काम करते रहें और निरन्तर गांधीजी की मदद करते रहें। वह देश का दौरा करते रहें और सत्याग्रह का मुख्य भार अपने कथों पर उठाते फिरे। उनकी पत्नी श्रीमती सुचिता देवी जेल चली गईं। सन् १९४१ की गींमयों में श्री जमनालाल जी को सख्त वीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। स्वयं राष्ट्रपित को अचानक गिरफ्तार करके सजा दे दी गई। वाकी का आन्दोलन विधिवत् चलता रहा और उसमें योजना के अनुसार प्रगति होती रही। स्वयं गांधीजी जेल नहीं गये।

सन् १९४० समाप्त हो रहा था। युद्ध को चलते हुए १६ महीने हो चुके थे। इस दौरान मे यूरोप को महान् विनाश का सामना करना पड़ा। भारत अभी तक इस सर्वनाश से बचा हुआ था। युद्ध की भयकरता अभी हिन्दुस्तान तक नहीं पहुँच पाई थी। फिर भी एक गुलाम देश को—जिसे कहने और करने की कोई आजादी नहीं थी—लड़ाई में उसकी मर्जी के खिलाफ ढकेल दिया गया। भारत में भरती का काम, धन-सग्रह और गोला-बारूद का उत्पादन पूरे वेग से होता रहा।

नरम दल - सम्मेलन

विटेन के खिलाफ काग्रेस की ओर से लडी जानेवाली इस लडाई के वडे नाटक के सबध में हमें कुछ जरूरी घटनाओं का भी जिक्र करना है। इस नाटक के साथ हिन्दू-मुस्लिम समस्या का भी गहरा सवध है। यह समस्या काग्रेसी-मित्रमण्डली के इस्तीफे के बाद सामने आई, परन्तु इसके बाद से यह ज्यादा जोर पकड गई। डा० सप्रू ने मार्च मे इस सबध मे हस्तक्षेप करना शुरू किया। वह सरकार के विश्वस्त व्यक्ति थे। नमक-सत्याग्रह के समय जुलाई १९३० में भी श्री सप्र और श्री जयकर ने सरकार और काग्रेस में समझौता कराने की कोशिश की थी। उसके बाद फरवरी और मार्च १९३१ मे गाधी-इरविन समझौते की बातचीत के समय भी आपने श्री जयकर और माननीय शास्त्रीजी के साथ मिलकर दोनो पक्षो मे समझौता कराने मे बडा महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। इसलिए मार्च १९४१ में उनके द्वारा फिर से समझौते की कोशिश करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने मार्च, १९४१ में बम्बई में नरमदल के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया। इसके वह सभापति थे। सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करके गॅवर्नर जनरल की शासन-परिषद के पुनर्निर्माण की जोरदार माग की और आग्रह किया कि इसमें (१) सभी भारतीय सदस्य लिये जाएँ तथा अर्थ और रक्षा विभाग भी भारतीयों के हाथों में ही दे दिये जायँ, (२) युद्धकाल में यह परिषद सामूहिक रूप से सम्राट के प्रति जिम्मेदार हो और (३) इसका दरजा वही हो जो अन्य स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशो की सरकारो का है अर्थात् ब्रिटिश सरकार

को घोषणा कर देनी चाहिये कि लडाई खत्म होने के बाद एक निश्चित अविध के अन्दर हिन्दुस्तान को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा।

हिन्दू-मुस्लिम-समस्या

उदार और नरमदली नेताओं के इस सम्मेलन के अलावा एक घटना और भी है जिसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। गांधीजी चूकि स्वतंत्र थे और जेल नहीं गये थे—इसलिए सर तेजबहादुर सप्रू का उनसे और श्री जिन्ना से लिखा-पढ़ी करना स्वाभाविक और सरल था। इसके अलावा वह अपने वम्बई-सम्मेलन को निर्दल सम्मेलन का रूप देने के लिए भी व्यग्र थे। वह श्री जिन्ना को अपने पक्ष में ले लेना चाहते थे और ऐसा करना उनके लिए न्यायोचित भी था।

डा॰ सप्रू ने यह काम "ट्वेन्टीयथ सेचुरी" नामक पत्रिका में एक लेख लिखेकर शुरू किया। इसमें भारत की वैधानिक समस्या का विवेचन करते हुए डा॰ सप्रू ने बताया कि साम्प्रदायिक प्रश्न के सम्बन्ध में कोई समझौता करने की जिम्मेदारी स्वय भारतीयों की है। यह लेख पढ़ने के बाद गांधीजी ने डा॰ सप्रू से कहा कि वह इस सम्बन्ध में श्री जिन्ना से मिले। डा॰ सप्रू ने कहा कि यह अधिक अच्छा होगा अगर गांधीजी श्री जिन्ना से मिले और अगर वह (गांधीजी) चाहे तो मैं इसका प्रबन्ध करने की कोशिश कहाँ। परन्तु गांधीजी को आशका थी कि इस तरह अगर वह श्री जिन्ना से मुलाकात करें भी तो शायद उसका कोई फल न निकले, क्योंकि श्री जिन्ना चाहेंगे कि वह (गांधीजी) उनसे एक हिन्दू नेता की हैसियत से ही कोई बातचीत करें। इस सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने जो पत्र लिखा—उसकी बात गांधीजी के लिए पहले से ही भाप लेना, निस्सदेह एक बड़ी बुद्धिमत्ता थी। कहने का मतलब यह है कि श्री जिन्ना ने (जैसी कि आशका की गई थी) डा॰ सप्रू के पास इसी आशय का एक पत्र लिखा। इस तरह यह योजना वही ठप्प हो गई।

श्री एमरी का भाषण

२२ अप्रैल को श्री एमरी ने कामन-सभा में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने विगत मार्च के बम्बई के निर्दल नेता-सम्मेलन के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। डा॰ सप्रू और उनके प्रस्तावों की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने प्रस्तावों को इस आधार पर नामजूर कर दिया कि उनके अनुसार वर्तमान सरकार में सशोधन की बात न कहकर उसकी जगह नयी सरकार बनाने की बात कही गई थी और यह लडाई के दौरान में सभव नहीं था। उनके फलस्वरूप आन्तरिक वैघानिक समस्याए पैदा हो जायँगी और भावी विघान के सम्बन्ध में भी और नई समस्याएँ खडी हो जायँगी। आगे उन्होंने कहा कि "मैं यह बात विना किसी प्रकार की अभद्रता के कहूँगा कि वाइसराय के प्रस्तावों पर अमल करना इसलिये मुल्तवी

नहीं किया गया कि उनकी निन्दा की गई है, बिल्क खास तीर पर इस वजह से कि मुसलमानों और हिन्दुओं के अपनी-अपनी स्थितियों के वारे में किये गये दावों में कोई सामजस्य स्थापित करना कठिन है।" मार्च, १९४१ में निर्दल नेताओं के इस सम्मेलन की समाप्ति पर श्री जिन्ना ने इसकी तुलना डच सेना से करते हुए कहा कि, "इसमें सभी सेनापित हैं—सिपाही एक भी नहीं।"—अर्थात् सम्मेलन में सभी नेता हैं—लेकिन उनके पीछे चलनेवाला या उनकी वात मानने वाला एक भी व्यक्ति देश में नहीं है। उनके इस एल से श्री एमरी को वडी मदद मिली और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि वास्तव में वम्बई प्रस्ताव के समर्थक कौन लोग हैं।

श्री एमरी ने कामन-सभा को याद दिलाया कि वगाल, आसाम, सिन्व और पजाव मे प्रान्तीय सरकारे अपना-अपना काम करती है और इन चारो प्रान्तो में ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या का तीसरा हिस्सा रहता है। वडे खेद की वात हे कि शेप सात प्रान्तों के २०,००,००,००० निवासियों को कांग्रेस के हाईकमाण्ड ने स्वायत्त शासन की परम्परा का जारी रखने की मनाही कर दी। भारत की वैधानिक प्रगति के सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि सारे ही विधान में सशोधन किया जा सकता है, वशर्ते कि भार-तीयों में आपस में यह समझौता हो जाय कि वे अपने लिए किस किस्म का वियान चाहते हैं। युद्धकाल में भारत-सरकार के ढाचे में कोई परिवर्तन करना सभव नहीं है, परन्तु भारतीय नेताओ-द्वारा इसी समय आपस में कोई प्रारम्भिक वातचीत शुरू करने में कोई रुकावट नही पैदा हो सकती। श्री एमरी ने कहा, "मुझे डर है कि काग्रेस यह मानने को तैयार नहीं कि इस समय कोई और ऐसा विधान नहीं वन सकता जिसके अन्तर्गत समस्त भारत पर इतनी अधिक मात्रा मे नियत्रण रखा जा सके जितना कि भारत को वर्तमान विधान के अन्तर्गत प्राप्त है। इस दिशा में हम एक महत्त्वपूर्ण लक्षण यह देख रहे है कि श्री जिन्ना की यह माग जोर पकडती जा रही है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भागो को शेष भारत से पूर्णत पृथक् करके वहा पूर्ण रूप से स्वतत्र रियासते कायम कर दी जायेँ जिन्हे रक्षा, विदेश और आर्थिक मामलो पर पूरा-पूरा नियत्रण प्राप्त हो।

"तथाकथित पाकिस्तान योजना के मार्ग मे जो बडी-बडी व्यावहारिक किठ-नाइया हैं उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नही है और न मैं १८ वी सदी के भारतीय इति-हास के 'अन्धकारपूर्ण' पृष्ठों का उल्लेख ही करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि बाल्कन राष्ट्रों की जनता को कितने भयकर परीक्षण में से गुजरना पड रहा है, और इससे हम जान सकते हैं कि भारत की एकता को भग करने का कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है।" श्री एमरी ने खेद प्रकट किया कि नवम्बर में वाइसराय को शासन-परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी कोशिशे छोड़ देनी पड़ी; क्योंकि मुस्लिम-लीग ने खास तौर पर हिन्दुओं के मुकाबले में एक निश्चित प्रतिनिधित्व की माग की और भविष्य के लिए भी यही शर्त रखी। परन्तु वाइसराय महोदय ने उसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

गांधीजी का वक्तव्य

कामन सभा मे श्री एमरी के भाषण के सम्बन्ध में गाधीजी ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया —

"भारत के सम्बन्ध में कामन-सभा की लम्बी बहस पढ़कर मुझे हु ख हुआ। कहा तो ऐसा जाता है कि मुसीबत से लोगों के दिल नरम पड़ जाते हैं और वे सचाई का महत्व समझने लग जाते हैं, परन्तु साफ जाहिर है कि ब्रिटेन आज जिस भारी संकट में से गुजर रहा है उसका श्री एमरी पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका हृदय आज भी चिकनी-मिट्टी के घड़े-जैसा बना हुआ है। उनके कान पर जू तक नहीं रेगती। उनकी इस निर्भयता को देखकर मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है कि चाहे काग्रेस को कितनी ही मुसीबते क्यों न झेलनी पड़े, उसे अहिसा की नीति पर ृढता से अमल करना चाहिए। भारत की मौजूदा परिस्थित के प्रति श्री एमरी ने जो अवहेलना प्रदिश्ति की है उससे उन्होंने ब्रिटेन की कोई मदद नहीं की। वह इस बात की बड़ी डींग हाक रहे हैं कि ब्रिटिश-राज ने भारत में शान्ति स्थापना की है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अहमदाबाद और ढाका में क्या हो रहा है है इन दोनो स्थानो पर शान्ति बनाये रखने की जिम्मे-दारी किस पर है नेरा खयाल है कि वह मुझे यह कहकर टालने की कोशिश न करेंगे कि बगाल में तो स्वायत्त-शासन कायम है। वह जानते हैं कि इस तरह की सकटपूर्ण परिस्थितियों में इन कठपुतली मित्रमंडलों के हाथ में कितनी ताकत रहती है, फिर चाहे ये मित्रमण्डल काग्रेस के हो, लीग के हो अथवा किसी और दल के।

"श्री एमरी ने यह बात फिर दोहराकर भारतीय जनता का अपमान किया है कि भारत के राजनीतिक दलों के लिए आपस में समझौता करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है और ब्रिटेन तो सिर्फ संयुक्त भारत की ही बात सुनेगा। मैं बार-बार यह बात साबित कर चुका हूँ कि ब्रिटेन की यह परपरागत नीति रही है कि भारतीय दलों में एकता न हो सके। ब्रिटेन का आदर्श सदा से यही रहा है कि लोगों में फूट डालकर अपना राज बनाये रखे। भारतीयों की पारस्परिक फूट की जिम्मेवारी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की है और जब तक हिन्दुस्तान गुलाम रहेगा, यह भेदभाव और आपस की फूट भी बनी रहेगी। मैं वादा करता हूँ कि अगर अग्रेज हिन्दुस्तान से चले जायँ तो काग्रेस, लीग और अन्य दल अपने हितों के खयाल

से एक-दूसरे से मिल जायेंगे और खुद ही भारत के लिए अपने ढग की कोई मुनासिव सरकार बना लेगे। हो सकता है कि हमारी यह सरकार वैज्ञानिक ढग की या पिंचमी ढाचे की न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से स्थायी होगी।

"मैने जब भारत की समृद्धि के सबध में उनका बयान पढ़ा तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। भारत की जनता धीरे-धीरे मुफलिसी की ओर बढ़ती जा रही है। उसे तन ढकने को कपड़ा और भरपेट खाना भी मयस्सर नहीं होता। इसकी वजह यह है कि देश पर एक ही आदमी की हुकूमत हे और वह लाखों का वजट तैयार करता है। में दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह बात हिन्दुस्तान की भूखों जनता की समृद्धि की सूचक न होकर इस बात की सूचक है कि आज हिन्दुस्तान कियेन के पैरो तले रौदा जा रहा है। हर हिन्दुस्तानी का, जो हमारे किसानों की मुसीबत को जानता है, फर्ज हो जाता है कि इस स्वेच्छाचारी-शासन के खिलाफ बगावत का झण्डा खड़ा करे। सौभाग्य से हिन्दुस्तान की मानवता शान्तिपूर्ण है और में उम्मीद करता हूँ कि इसी शान्तिपूर्ण तरीके से वह अपनी किस्मत का फसला करेगी और अपने पैदायशी हक को हासिल करेगी।"

शासन-परिपद का विस्तार

इसी बीच २२ जून को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। फलत भारत की परिस्थित का स्वरूप भी बदल गया। सरकार इस बात से बडी परेशान थी कि लडाई भारत के द्वार तक आ पहुँची थी। यद्यपि पार्लमेण्ट मे प्रति सप्ताह मजदूर-दलीय सदस्य, श्री एमरी को यह समझाने की कोशिश करते रहते थे कि अन्तर्राप्ट्रीय परिस्थित बदल गई है, इसलिए ब्रिटेन की भारतीय नीति में भी परिवर्तन होना आवश्यक है, परन्तु वह ऐसी बाते वया माननेवाले थे। २१ जुलाई को इन सात भारतीयो— सर सुलतान अहमद, सर होमी मोदी, सर अकबर हैदरी, श्री अणे, श्री एन० आर० सरकार, श्री राघवेन्द्र राव और सर फिरोजखा नून को वाइसराय की शासन-परिषद में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। इनके अलावा श्री रामस्वामी मुदालियर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वाइसराय की शासन-परिषद में आठ भारतीय, तीन यूरोपियन सदस्य और प्रधान-मत्री हो गये और यह दावा किया गया कि इस शासन-परिषद के विस्तार का उद्देश्य युद्ध-रत राष्ट्र के लिए कार्यकुशल सरकार की स्थापना करना है तथा ये परिवर्तन मौजूदा विधान के अन्तर्गत किये गये हैं और इनके कारण भविष्य के वैधानिक निर्णय पर जो राजनैतिक दलो के पारस्परिक समझौते से किया जाएगा—किसी किस्म का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शासन-परिपद के इस विस्तार और राप्ट्रीय सुरक्षा-परिषद् की स्थापना के पीछे काम करनेवाली नीति का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया कि उक्त

दोनों वाते महज युद्धकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई हैं और इनका मकसद किसी राजनैतिक दल की माग को पूरा करना नहीं है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी राजनैतिक मांग को न तो ओझल ही किया गया है और न उसके विरुद्ध कोई कदम उठाया गया है। इसके साथ ही २२ जुलाई को भारत-मत्री श्री एमरी ने भारत और युद्ध की परिस्थिति के वारे में पार्लमेण्ट में एक क्वेत-पत्र उपस्थित किया। यह क्वेत-पत्र न्यूनाधिक रूप में पिछले ग्यारह महीनों की घटनाओं का सिंहावलोकन और वाइसराय-द्वारा जारी की गई विज्ञिप्त की पुनरावृत्ति मात्र था।

विस्तार के प्रति प्रतिक्रिया

वाइसराय की शासन-परिषद् के विस्तार पर जो प्रतिक्रिया हुई वह वडी दिलचस्प थी। श्री जिन्ना इस बात से तिलमिला उठे कि वाइसराय ने स्वय लीग के प्रधान और उनकी कार्य-समिति से सलाह-मशिवरा लिये वगैर ही उनके आदिमियों से बातचीत की। उन्होंने वगाल, पजाब और आसाम के प्रधान मित्रयों के खिलाफ अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करने की धमकी दी। भारत की दिलत जातियों के नेता डा० अम्बेदकर पर इसकी

भारत की दिलत जातियों के नेता डा॰ अम्बेदकर पर इसकी प्रतिक्रिया बड़ी आश्चर्यजनक हुई। उन्होंने कहा—"मुसलमानों को लगभग हिन्दुओं जितना अर्थात् ४३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर ६ करोड दिलतों का अपमान किया गया है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। दिलत वर्ग भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक महत्त्वपूर्ण और प्रधान अग है। किसी भी वैद्यानिक परिवर्तन के लिए उसकी सहमित आवश्यक है। महामाननीय श्रीनिवास शास्त्री जैसे अनुभवी और कुशल व्यक्ति का कथन था कि मुझे तो इस घोषणा से कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने न तो अपनी स्थिति ही सुदृढ बनाई और न किसी भी अंश में जनता की माग ही पूरी करने का प्रयत्न किया। दूसरी ओर गांधीजी का विचार था कि इससे काग्रेस की स्थित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न उससे काग्रेस की माग ही पूरी होती है। सिक्खों ने इसे अपनी सारी जाति का अपमान समझा क्योंकि उनका एक भी आदमी केन्द्रीय मिन्त-मण्डल में नहीं लिया गया और खासकर उस हालत में जबिक इस विस्तार का असली उद्देश्य सरकार के युद्ध-प्रयत्न को प्रोत्साहन देना था।

श्री चर्चिल का वक्तव्य

लडाई के तीसरे साल के शुरू में जबिक यूरोप की ताकतें पिछले सालों की परिस्थितियों के सिंहावलोकन में लगी हुई थी, काग्रेस को अपना आन्दोलन छेडे अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सत्याग्रह आन्दोलन का सूत्रपात १७ अक्टूबर १९४० को किया था। गाघीजी के सामने पीछे कदम हटाने का कोई सवाल ही नही उत्पन्न होता था। समय और वैर्य इन दो मुस्य वातों को घ्यान में रखकर वह आगे वढ रहे थे। उन्होंने शत्रुओं की वदनामी या गाली-गलीज की परवाह नहीं की। लड़ाई शुरू हुए दो साल हो चुके थे, पर परिस्थित वैसी ही बनी थी। सिर्फ पत्र-प्रतिनिधि ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये भविष्यवाणिया कर रहे थे कि नयी शासन परिपद के पद सभाल लेने पर राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जायगा। यहा तक कहा गया था कि नये सर्दस्यों में इस सम्वन्ध में परस्पर पत्र-व्यवहार भी चल रहा है। लेकिन जेल के बन्दियों के लिए इन अफवाहों का कोई महत्व नहीं था। लगता है इन्हीं जकाओं और भविष्य-वाणियों को खत्म कर देने के खयाल से श्री चिंचल ने ९ सितम्बर को पार्लामेट में एक वड़ा उल्लेखनीय भाषण दिया। सभी शकाओं का विवरण करते हुए उन्होंने कहा —

"हमारी इस सयुक्त घोषणा का उस नीति से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न वक्तव्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है जो समय-समय पर भारत, वर्मा अथवा ब्रिटिश साम्प्राज्य के दूसरे हिस्सों में वैधानिक सरकार की उन्नति के वाद दिये गए हैं। हमने अगस्त १९४० की घोषणा में भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत स्वतंत्र और समान साझेदारी का पद प्राप्त करने में मदद देने का वादा किया है। हाँ, अलवत्ता ऐसा करते समय हमें भारत के साथ अपने पुराने सम्बन्धों के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली जिम्मेदारियों और उसकी बहुतसी जातियों, स्वार्थों और धर्मों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को ध्यान में अवश्य रखना होगा।

"उन इलाको मे जिनकी जनता ब्रिटिश सम्प्राट् के प्रति वफादार हैं, प्रगति-शील सस्थाओं के विकास से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह समस्या उनसे बिलकुल अलग हैं। हमने इन विषयों पर जो स्वयपूर्ण हैं, सर्वथा असदिग्ध शब्दों में अपनी घोषणाए कर दी हैं। इनका सम्बन्ध उन देशों और जनता के हालात से हैं जिन पर युद्ध का प्रभाव पड़ा हैं। इस सयुक्त घोपणा को आजादी और न्याय की जिस भावना से प्ररणा मिली हैं, उसके साथ इनका पूर्ण मेल हैं।

"भारत पर अपना शासन और अधिकार बनाये रखना ब्रिटेन के पूजीपतियों के हित में है।"

जब गाघीजी से कहा गया कि श्री चिंचल के भाषण पर उनकी क्या राय है तब उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनके विचारों से उनका मौन रहना और उनके द्वारा चलाया गया आन्दोलन श्री चिंचल के भाषण का स्पष्ट प्रत्युत्तर था।

सत्याग्रह-त्रांदोलन की वर्षगांठ

१९४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को शुरू करने और उसे

आगे चलाने के लिए गाधीजी के पास अपनी निञ्चित योजना मौजूद थी। राष्ट्र के लिए वह सीभाग्य की बात थी कि गाघीजी जेल नहीं गए और वह स्वतंत्र रहकर इस आन्दोलन का नियत्रण और सचालन करते रहे। वह अनेक वाघाओं और किताइयों के रहते हुए भी प्रमुख काग्रेसजनों के साथ अपना सपर्क और पत्र व्यवहार जारी रख सके। राजनीतिक नजरवन्दों की वजह से प्रारम्भ में ही जेले भरने लगी। शुरू शुरू में तो उन्हें १० ६० और ५ ६० के हिसाव से भत्ता भी दिया जाने लगा, किन्तु कुछ ससय वार ही यह भत्ता वन्द कर दिया गया और सब से बड़ी बात यह हुई कि उन्हें दो श्रेणियो—'ए' और 'वी' में विभक्त कर दिया गया। पहली श्रेणी के आदिमयों को ०-४-३ फी आदमी के हिसाव से स्थान मिलत था और दूसरी श्रेणी के कैदियों को ०-१-४ फी आदमी के हिसाव से। जब बार-वार अनुरोध करने का भी कुछ फल न निकला तब कही-कही भूख हडताल भी की गई। यह एक वडी असाधारण बात थी कि सीधे-साधे मामलों का निवटारा सीधे और सरल तरीकों से नहीं किया जाता था। जेलों में पत्र वहुत देर के बाद मिलते थे, कभी-कभी महीने के बाद और इसी प्रकार जेलों से बन्दियों के पत्र भी उनके घरवालों को बहुत देर से पहुँचते थे।

सत्याग्रहियों को दी जानेवाली संजाओं के मामले में सरकार ने विभिन्न समय पर विभिन्न नीति से काम लिया। शुरू-शुरू में संजाएं कड़ी दी गई और भारी-भारी जुर्माने किये गए। इस आन्दोलन के प्रारंभ में ही दी गई संजाओं में भारी अन्तर था। उदाहरण के तौर पर पिडत जवाहरलाल नेहरू और श्री विनोवा भावें को दी गई संजाओं को ही देख लीजिए। पहले व्यक्ति को दूसरे के मुकावले में सोलह गुना संजा दी गई। आझ जैसे प्रान्त में ही अकेले कुल मिलाकर १,१८,९६० रु० १२ आ० जुर्माना किया गया। सबसे अधिक गिरफ्तारिया उत्तर प्रदेश में हुई। फरवरी के मध्य तक वहा, १,४९५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। सबसे अधिक जुर्माना आझ प्रान्त में हुआ। वहा केवल रान्याग्रहियों पर कुल मिलाकर ७६,५३३ रु० जुर्माना किया गया।

मार्च के प्रारम तक सत्याग्रहियों को न पकड़ने की नीति काफी व्यापक रूप धारण कर चुकी थी। पहले तो गांधीजी ने गैर-गिरफ्तारण्या सत्याग्रहियों को यह हिदायत दी कि वे मार्ग में युद्ध-विरोधी प्रचार करते हुए दिल्ली की ओर कूच करे, लेकिन वाद में उन्होंने हिदायत दी कि गिरफ्तार न होनेवाले को चाहिये कि दिल्ली रवाना होने से पहले वे अपने गांव के घर-घर में जाकर और प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर अपना प्रचार करें। उनकी योजना यह थी कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा ताल्लुका चुन लिया जाय जहां तहसील के हर गांव में, हर घर में और हर नागरिक में जोरदार प्रचार किया जाय। उनकी मारी योजना का उद्देश्य वाणीस्वातत्र्य का अधिकार प्राप्त करना था।

गाधीजी की हिदायते हर समय उपलब्ध हो सकती थी और वे प्रत्येक क्षण इस आन्दोलन की नब्ज देखते रहते थे। इतवार के दिन सत्याग्रह नही होता था। वहे दिनों में २३ दिसम्बर से लेकर ४ जनवरी तक सत्याग्रह-आन्दोलन स्थिगत रखा गया और ५ जनवरी को इतवार था। फरवरी के शुरू से ही ये अफबाहे सुनने में आ रही थी कि शायद गाधीजी गिरफ्तार कर लिये जाय। परन्तु चाहे कुछ भी हो, जब तक गाधीजी स्वय कुछ विरोधी कार्रवाई में भाग न लेते, सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की मूर्खता नहीं कर सकती थी। जून १९४१ तक सत्याग्रह की दूसरी अवस्था खत्म हो गयी थी। इसलिए अखिल भारतीय काग्रेस महासमित के जनरल सेकेटरी आचार्य जे० बी० कुपलानी ने महात्मा गाधी के परामर्श से १७ जून, १९४१ को सत्याग्रहियो और काग्रेस कमेटियो के पथ-प्रदर्शन के लिए नीचे लिखी हिदायते जारी की

(१) जेल से रिहा होकर आनेवाले सत्याग्रही को यथासभव शीघ्र ही फिर दुवारा सत्याग्रह करना चाहिए। अगर किसी खास वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे चाहिये कि वह सबद्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के प्रथान के जरिये गांधीजी से इस बारे में छूट देने के निमित्त आवेदनपत्र भेज दे। इसमें उसे इस छूट की वजहें भी देनी चाहिये।

(२) जिस तारीख को सभावित सत्याग्रही का नाम गाधीजी के पास स्वी-कृति के लिए भेजा जाय उसी दिन से उसे अपना निजी काम स्थिगत करके नीचे लिखे रचनात्मक-कार्यक्रम की १३ मदो में से किसी एक को या ज्यादा को लेकर पूरी तरह से उसमे जुट जाना चाहिये —

(क) हिन्दू-मुस्लिम अयवा साप्रदायिक एकता, (ख) अस्पृश्यता-निवारण, (ग) मद्यनिषेध या शराबवन्दी, (घ) खादी, (च) दूसरे ग्रामोद्योग, (छ) गाव की सफाई, (ज) नयी या बुनियादी तालीम, (झ) प्रौढ शिक्षा, (ट) स्त्रियो की उन्नति, (ठ) स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, (ड) राष्ट्र-भाषा का प्रचार, (ढ) स्वभाषा-प्रेम और (त) आर्थिक समानता का यत्न।

(३) प्रत्येक समावित सत्याग्रही से यह आशा की जाती है कि वह अपने पास एक डायरी रखे जिसमे वह अपने प्रतिदिन के काम का ब्योरा लिखे और १५ दिन के बाद उसे सबद्ध प्रान्तीय काग्रेस कमेटी के पास भेज दे।

(४) अगर कोई सत्याग्रही, जिसने अपना नाम पहली शर्तो और प्रतिबन्धों को घ्यान में रखकर सूची में लिखाया था—अब इन नयी शर्तों को मजूर करने में अपने को असमर्थ समझता है तो उसे चाहिये कि वह अपना नाम वापस ले लें और अगर वह ऐसा करता है तो उसमें कोई अपमान-जनक बात नही है। वह यथाशिक्त किसी और तरीके से देश की सेवा का काम जारी रख सकता है।

(५) जिन सत्याग्रहियो ने अपने नाम दर्ज करा दिये हैं वे स्थानीय संस्थाओ

कं चुनाव नहीं एउ सबते। जो लोग सन्यायहियों की सूची में नाम दर्ज कराने से पहले इन चुनावों में उम्मीदवार खड़े हो गए थे उन्हें चाहिये कि या तो व चुनाव से हट जाए अथवा मत्याग्रह न करें। एक मत्याग्रही की हैसियत से वे दोनों जगहो पर नहीं ग्ह सकते।

(६) जेल-मुक्त होनेवाला कोई भी सत्यायही जो किसी स्वानीय गस्था का सदस्य है तब तक उसनी बैठकों में भाग नहीं के सकता, जदनक कि गाधीजी

उसे उसके लिए विशेष रूप ने अनुमृति न दे दें।

(७) गिरपतार न किये जानेवाले सत्याग्रही जो अपने-अपने जिलो का दौरा कर रहे है तथा वे नत्याप्रही जिनका नाम स्वीकार कर लिया गया है—स्थानीय सस्याओं की बैठकों में भाग नहीं के सकते।

(८) वर्षा-त्रद्रतु में, अगर कोई स्त्याग्रही चाहे तो अपने गाव के अलावा किसी और गाव अववा गावों के समूह में ठहर नकता है और दही उने मत्याग्रह

अंद रचनात्मक-कार्य करते रहना चाहिये।

सत्यागह-जैसे महान् और न्यापक तया राष्ट्रव्यापी बान्दोलन के दौरान मे नगय-समय पर धोडी-बहुत अनुचित परिस्थितियों का पैदा हो जाना नर्बधा न्या-शाविक ही पर । एक ऐसी ही नर्ज बात यह पैदा हो गई घी कि छोग पासिक उत्नवो के अवसर पर और मन्दिरों पर राष्ट्रीय अग्न लहराना चाहते थे। 'राष्ट्रीय' नण्या बौर 'हिन्दू' पताका के प्रयन के सम्यन्य में 'निमोना हिन्दू-महाराभा के समेहरी के नाम गाणीजी ने जो पत्र मेला उनमें उन्होंने किया --

मिनट तक इस सभा में भाषण किया। अपने भाषण के दौरान में गांघीजी ने सत्या-ग्रह की प्रगति पर सतोष प्रकट करते हुए कहा —

"अन्त में मैं लोगो पर फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह की लडाई कष्ट उठाने और त्याग करने की लडाई है। हिसा-जैसी पैशाचिक युद्धकला में जैसा कि आजकल यूरोप में देखने में आ रहा है लोगो को मजबूरन कष्ट सहन करने पड रहे हैं। परन्तु हमारे सघर्ष में इतने बड़े पैमाने पर कप्ट झेलने का सवाल नहीं पैदा होता। इसमें तो हमें सिर्फ वारम्बार जेल ही जाना है। अगर हम इस मामूली से कष्ट को भी बरदास्त नहीं कर सकते तो हमारे लिए स्वराज्य की चर्चा करना विलकुल बेकार है।"

विभिन्न दलों के मत

सत्याग्रह-आन्दोलन की इस वर्षगाठ का इसलिए इतना महत्व न था कि उसके परिणाम-स्वरूप लोगो मे भावोद्रेक को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बहुत से महत्त्व-पूर्ण नेता जेल से रिहा होकर आ रहे थे। १९ अक्टूबर तक कार्यसमिति के ग्यारह सदस्य मुक्त होकर वर्धा पहुँच चुके थे। उनके अलावा और भी नेता वहाँ मौजूद थे। यद्यपि कोई भी दल सरकार के रुख और उसकी कार्रवाई का समर्थक नही था, तथानि उनका दो बातो के बारे में आपसी मतभेद था एक तो यह कि काग्रेस के साधारण रुख का समर्थन वे अपने-अपने दृष्टिकोण से करते थे और दूसरे गति-रोघ का अन्त करने के लिए उनके अपने-अपने सुझाव थे। कुछ दल तो पूर्णत भारतीय शासन-परिपद् के हामी थे और कुछ दूसरे यह चाहते थे कि शासन-परिषद् का स्वरूप तो यही बना रहे, लेकिन वह सम्राट् और वाइसराय के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होनी चाहिये। डा॰ सप्रू के नेतृत्व मे निर्दल नेताओ की माग यह थी कि उपर्युक्त आधार पर शासन-परिषद् के निर्माण के अलावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध समाप्त होने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देन के सम्बन्ध में भी घोषणा कर देनी चाहिये। निर्दल नेता निरन्तर गाधीजी से यही कह रहे थे कि वे सत्याग्रह-आन्दोलन वापस लेले। मुस्लिम-लीग का दृष्टिकोण विल्कुल निराला ही था। उसने इस सिलसिलेमे पाकिस्तान का सर्वोल खडा कर दिया और यह फैसला किया कि जब तक इस प्रश्न का निपटारा न हो जाय तब तक शासन-परिषद् अथवा सुरक्षा-परिषद् से असहयोग किया जाय । २६ अक्टूबर से केन्द्रीय असेम्बली का अधिवेशन शुरू हो रहा था। इससम्बन्ध में लीग का रुख क्या होगा, इस बात की देश में बड़ी चर्चा थी।

नरम दलवालो की नीति यह थी कि वे पृथक् पृथक्षटनाओं के सम्बन्ध में अपने पितृत्र और जोरदार विचार प्रकट करके सन्तोष कर लेते थे। लेकिन समस्या को हल करने की कोई उपयुक्त योजना नहीं सुझाते थे,। इनके अलावा देश में

साम्यवादी दल-साम्यवादी नेता अलग-अलग अपनी हैसियत से, उसके सदस्य की हैसियत से नही-समाजवादी दल, अग्रगामी दल और किसान सभा वाले अपने विचार सार्वजनिक रूप से नहीं जाहिर कर रहे थे। उन्हें ऐसा करने का मौका भी नही मिला था। लेकिन इनमें से कुछ कार्यकर्ता मुख्य रूप से अपना कार्य कर रहे थे और ये सभी दल ब्रिटेन के विरोधी थे। प्रश्न यह था कि उन्हें अपने दृष्टिकोण मे परिवर्तन करना चाहिये या नहीं ? कुछ लोग यह कह रहें थे कि उन्हें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करके युद्ध-प्रयत्न मे सिक्रिय रूप से जोरदार मदद करनी चाहिये। दूसरा पक्ष यह कहता था कि रूस को तो पूरी मदद दी जाय, लेकिन ब्रिटेन को नही। अखिल भारतीय किसान-सभा न यद्यपि अपने "पितृदेश" की यथासभव मदद करने का समर्थन किया, तथापि इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि भारत में उनकी स्थित बड़ी शोचनीय है और इसलिए उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से रूस की कोई मदद करना सभव नहीं है। सिक्खों और हिन्दू-महासभाइयों ने युद्ध-प्रयत्न में पूरी-पूरी मदद की। इधर तो ये विरोधी विचारधाराएँ, वाद-विवाद और विचार-विनिमय हो रहे थे, उधर काग्रेस निश्चल भाव से अपना मस्तक ऊँचा किये अपने निर्धारित कार्यक्रम पर अग्रसर हो रही थी। उसे पूरा यकीन था कि लड़ाई में मदद न करते हुए या ब्रिटेन को परेशानी में न डालने की उसकी जो नीति है, वह सही और समयानुकूल है। सत्याग्रह-आन्दोलन में इस दूषित विचार के लिए कोई स्थान ही नहीं था कि दुरमन की मुसीबत से फायदा उठाया जाय। गाधीजी को इस बात पर कोई यकीन नहीं था कि सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगे।

इसी बीच कुछ ऐसी शिवतयाँ जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नही था, सत्याग्रह के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने को बाध्य कर रही थी। अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी ने एक व्यापक और विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया जो उन लोगों की इस युक्ति का प्रत्युत्तर था कि कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाय और आन्दोलन की पिछले साल की प्रगति-समीक्षा की जाय। गांधीजी ने अपने वक्तव्य में अपने शाश्वत सिद्धान्तों को दोहराते हुए कहा कि "सिविल नाफरमानी को छोड़ देना बेवकूफी होगी। सिविल नाफरमानी स्वय पूर्ण रूप से एक अहिंसात्मक कार्रवाई है। हिसा के मुकाबले में यह परम कर्तव्य वन जाता है, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती।"

जेल से रिहाइयाँ

अचानक २७ अक्टूबर, १९४१ को सारे भारत मे यह समाचार प्रकाशित हुआ कि वेलीर सेंट्रल जेल से कुछ नजरवन्द कैंदी छोड़े जा रहे हैं जिनमें मद्रास की

व्यवस्थापिका सभा के अव्यक्ष और छ अन्य सदस्य भी शामिल है। इस समाचार के तुरन्त बाद ही कैंदियो को पहली नवम्बर को रिहा कर दिया गया। सरकार ने बहुत से साधारण सत्याग्रहियो को भी आमतौर पर पहली वार सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार करना छोड दिया। इसके अतिरिक्त किसी-किसी को दूसरी वार और किसी को तीसरी वार सत्याग्रह करने पर भी गिरफ्तार नही किया। मद्रास मे इन रिहाइयो के वाद वम्वई के प्रघान मत्री और एक-दो और आदिमियो को तथा और जगह भी एकाध आदिमयों को रिहा कर दिया। वात दरअसल यह थी कि सभी हल्को के लोगो द्वारा जिनमें कामन सभा के कुछ सदस्य भी शामिल थे, यह मार्ग की जा रही थी कि पडित जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे कैदियो को रिहा कर दिया जाय जिससे कि देश मे गितरोव का अन्त करने के लिए नया प्रयत्न करने के अनुकूल वातावरण पैदा हो सके। इसी वीच भारत-सरकार ने अचानक नई दिल्ली से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमे वताया गया कि भारत-सरकार को इस वात का यकीन है कि भारत के सभी जिम्मेवार व्यक्ति युद्ध मे विजय प्राप्त होने तक युद्ध-प्रयत्न में सहायता करने का दृढ निश्चय किये हुए है। इसलिए वह इस नतीजें पर पहुँची है कि सविनय-भग-आन्दोलन के उन कैदियो को जिनका अपराध सिर्फ रस्मी तौर पर अयवा साकेतिक रूप मे था, रिहा किया जा सकता है। इनमे पडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अवुल कलाम आजाद भी शामिल है। इसके अनुसार उन्हें तत्काल ही रिहा कर दिया गया। जैसी कि आशा थी, गांघीजी ने अप नी स्थिति और स्पष्ट कर दी और काग्रेस के अध्यक्ष की रिहाई को घ्यान में रखते हुए कहा कि काग्रेस की भावी नीति का निर्णय अखिल भारतीय काग्रेस महामिति और कार्यसमिति ही करेगी। गाघीजी का नीचे दिया गया वक्तव्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि आजतक उन्होंने यह नहीं कहा कि यह वक्तव्य काँग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में अन्तिम घोषणा है।

गांधीजी का वक्तव्य

गाधीजी ने कहा—"मैं अपने विद्यार्थी-जीवन से अपने को ब्रिटिश जनता का मित्र समझता रहा हूँ और अभी तक समझता हूँ, लेकिन इस मित्रता का यह तात्पर्य नहीं कि मैं यह खयाल करना छोड़ दू कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत को अपना कीतदास समझते हैं। भारत को आज जो आजादी मिली हुई है, वह गुलामो-जैसी आजादी है, बराबरी के दरजेवालो की वह आजादी नही, जिसे हम दूसरे शब्दों में मुकम्मिल आजादी कहते हैं।

"श्री एमरी की घोषणाओं से हमारे घाव और हरे होते हैं, क्योंकि वह उन

पर नमक छिडकने की कोशिश करते हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मुझे रिहाइयो के प्रश्न की समीक्षा करनी है।

"अगर भारत-सरकार को ऐसा यकीन है कि देश के सभी उत्तरदायी लोग युद्ध-प्रयत्न में सहयोग देने का दृढ निश्चय किये हुए हैं तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि सविनय-भग के कैदियों को जेलों में बन्द रखा जाय, क्यों कि वे इस कथन के अपवाद हैं। मैं तो इन रिहाइयों का सिर्फ एक ही मतलब समझ सका हूँ और वह यह है कि सरकार यह उम्मीद करती है कि उनके विचार बदल जाएगे। मुझे उम्मीद हैं कि इस बारे में सरकार को बहुत शीघ्र ही निराश होना पढ़ेगा।

"सत्याग्रह-आन्दोलन खूब सोच-विचार करने के बाद ही शुरू किया गया था। यह बदला लेने की भावना से नहीं प्रारंभ किया गया था। यह इसलिए शुरू किया गया था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा कि काग्रेस ब्रिटिश जनता और ससार के सामने अपना यह दावा साबित कर देना चाहती है कि देश का एक बड़ा भाग जिसका काग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, लड़ाई का सर्वथा विरोधी है। वह निश्चित रूपसे जानती है कि भारत को इस लड़ाई के फ़लस्वरूप आजादी नहीं मिलेगी।

"काग्रेस का यह दावा है कि वह देश की करोड़ो मूक जनता का प्रतिनिधित्व, करती है। उसने गत बीस वर्षों से अहिसा पर चलते हुए ही भारत की आजादी हासिल करने की कोशिश की है और यही उसकी निरन्तर नीति भी रही है। इसलिए सत्याग्रह को, चाहे वह फिलहाल प्रतीक स्वरूप ही क्यो न हो, बन्द करने का मतलब यह होगा कि उसने नाजुक घड़ी में आकर अपनी नीति छोड़ दी।

"सरकार यह दावा करती है कि काग्रेस के विरोध करने पर भी उसे भारत से यथेष्ट सैनिक और धन मिल रहा है। इसलिए काग्रेस का विरोध सिर्फ एक नैतिक विरोध ही है। मैं तो इससे बिल्कुल सतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसी नैतिक प्रदर्शन से समय आने पर हमें स्वाधीनता मिल जाएगी, फिर ब्रिटेन में चाहे किसी भी दल का प्रभुत्व क्यों न हो।"

नेहरूजी का संदेश

स्वाभाविक तौर पर यह आज्ञा की जा रही थी कि मुक्त हुए नेता धुआधार भाषण देगे। इनमें से सर्वप्रथम पिंडत जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें ४ दिसम्बर, १९४१ को जेल से मुक्त किया गया। उन्होंने रिहा होने के बाद ही अपने सभी सहयोगियो और मित्रो का हार्दिक अभिवादन करते हुए उनके नाम निम्नलिखित अत्यधिक हृदयस्पर्जी, क्रान्तिकारी और जोरदार सदेश भेजा —

"एक विदेशी हुकमत के कहने पर जेल जाने और उससे वाहर आने में मुझे

किसी किस्म की खुशी नही महसूस होती। जेल की तग चहारदीवारी में से निकलकर भारत जैसे विशाल कैंदखाने में आना कोई खुशी की वात नही है। निश्चय ही एक समय ऐसा आएगा जब हम गुलामी की इन बेडियों को तोडकर आजादी के साथ सास ले सकेंगे। परन्तु अभी वह दूर है और हमें इस तुच्छ-से परिवर्तन पर प्रसन्न नहीं होना चाहिये।

"इस ससार में जहाँ असीम दुखो, हिंसा, घृणा और सर्वनाश का साम्राज्य छाया हुआ है, हम आराम और चैन से क्यों कर वैठ सकते हैं। इस भारत में जहा विदेशी और स्वेच्छाचारी शासन हमें दवाकर और जकड़ कर रखता है, हमें शान्ति नहीं मिल सकती। इसलिए स्वतंत्र भारत तथा स्वतंत्र ससार के हितों को अग्रसर करने का हमें निरतर आह्वान करना है। जो व्यक्ति इस आह्वान को मुनना चाहते हैं, उनके लिए यह मौजूद है।"

गांधीजी का वक्तव्य

गाघीजी ने अपने वक्तव्य में कहा —

"इस समय सत्याग्रहियो की शीघ्रता के साथ जो रिहाइया हो रही है, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें अखिल भारतीय महासमिति की बैठक अवश्य बुलानी चाहिये, क्योंकि सरकार का प्रत्यक्ष रूप से यह ख्याल है कि उसमे वम्बई के उस प्रस्ताव को वापस ले लिया जायगा जिसकी विना पर मैने सत्याग्रह-आन्दोलन चलाया है। इसलिए मैंने मौलाना साहव से काग्रेस कार्यसमिति और अखिल भारतीय महासमिति की वैठक बुलाने को कहा है, लेकिन जब तक वह फैसला बदल नहीं दिया जाता, तब तक सत्याग्रह-आन्दोलन जारी ही रहना चाहिये। मै यह मानता हूँ कि सरकार-द्वारा सत्याग्रही बन्दियो की मुक्ति के कारण सत्याग्रह का सचालन कठिन अवश्य हो गया है, लेकिन अगर हमें अपने मकसद तक पहुँ-चना है तो हमें हरेक मुश्किल का मुकाबला करना होगा। यह मुश्किल तो उस मुश्किल के मुकाबिले में कुछ भी नहीं है जिसका सामना शायद हमें अपनी स्थिति सुघर जाने पर करना होंगा। अखिल भारतीय महासमिति की वैठक होने तक काग्रेस-कार्यसमिति और भारतीय महासमिति के सदस्यों को तथा जो लोग वम्बई के प्रस्ताव को वदलना चाहते हैं, उन्हें किसी भी हालत में सत्याग्रह नहीं करना चाहिये। इसके अलावा सत्याग्रह-आन्दोलन निर्वाध रूप से चलता रहना चाहिये। साकेतिक-सत्याग्रह का एक खास मतलब है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो उन काग्रेसजनो को भी भाषण देने पर पकड सकती है, जिनका इरादा सत्याग्रह मे भाग लेने का नहीं है। औरों का तो क्या कहना, सरकार ने इसी तरह से मौलाना साहब और पडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया था। मैं यह वात स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि मुझे किसी बाहरी कारण के आधार पर

सत्याग्रह-आन्दोलन मुल्तवी कर देने का कोई हक नही है। यह काम तो काग्रेस का है।"

कार्यसिमिति की बैठक

जैसा कि स्वय गाधीजी ने सकेत किया था, सत्याग्रहियों की रिहाई के बाद पहला काम शी छ ही कार्यसमिति की बैठक बुलाने का था और इसके बाद अखिल भारतीय महासमिति की बैठक बुलाकर उसमें काग्रेस की भरती-नीति पर सोच-विचार करके कोई फैसला कर लेना था। तदनुसार कार्यसमिति की बैठक २३ दिसम्बर, १९४१ को बुलाई गई। कार्यसमिति की बैठक बारदोली में गाधीजी के निवास-स्थान पर हुई। उसका निर्णय अप्रत्याशित परन्तु उचित ही था।

उसका मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार था .--

"समिति गांधीजी के नेतृत्व और राष्ट्र-द्वारा इस आन्दोलन में दिए गए सहयोग की सराहना करती है और उसकी कद्र करती है। उसकी राय है कि इससे जनता की शक्ति बढ़ी है। ब्रिटेन ने भारत की आजादी का विरोध किया है और वह भारत में यहा की जनता की आकाक्षाओं को ठुकराकर, पूर्णत स्वेच्छा-चारी शासन पर अमल करता रहा है। प्रजातन्त्र और स्वाधीनता के उद्देश्य और लड़ाई के फलस्वरूप वह जिस सकट में फसा हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए भी उसकी नीति और मनोवृत्ति में किसी किस्म का परिवर्तन देखने में नहीं आया और जो परिवर्तन हुए भी हैं उनके कारण परिस्थिति बिगड़ी ही है, सुधरी नहीं हैं।

"हाल में राजनीतिक बन्दियों की जो रिहाई हुई है, वह महत्वहीन है, क्योंकि यह कार्रवाई जिन परिस्थितियों में की गई है और इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर जो घोपणा हुई है उससे साफ जाहिर है कि इसका सम्बन्ध नीति में किसी परिवर्तन से नहीं है, फिर भी कार्य-सिमिति उस नयी परिस्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहती है, जो इस लड़ाई के विश्वव्यापी रूप धारण कर लेने तथा उसके भारत के द्वार तक आ पहुँचने के कारण पैदा हो गई है। भारत का सारा वातावरण अग्रेजों के विरोध और उनके प्रति अविश्वास की भावना से ओतप्रोत है और बड़े-बड़े व्यापक वादों से भी इस परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ सकता और न भारत स्वेच्छा से, अभिमानी साम्राज्यवाद की कोई मदद ही कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद और तानाशाही में किसी किस्म का अन्तर, नहीं है।

"इसलिए सिमिति की राय है कि १६ सितम्बर १९४० को अखिल भारतीय महासिमिति ने बम्बई में जो प्रस्ताव पास किया था और उसमें काग्रेस की जो नीति बताई गई थी, वह अभी तक कायम है।" इसके अलावा कार्य-सिमिति ने और भी कई प्रस्ताव पास किये। राजेन्द्र बाबू, सरदार पटेल, श्री कृपलानी और डा॰ घोष ने एक वक्तव्य निकाल कर अखिल भारतीय महासिमिति की आगामी बैठक मे स्वतत्र रूप से अपने-अपने विवेक के अनुसार काग्रेस की भावी नीति पर विचार प्रकट करने का आग्रह किया।

वारदोली-प्रस्ताव का प्रभाव

तत्काल ही इस प्रस्ताव की ओर इगलैण्ड के लोगो का घ्यान आकृष्ट हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोई प्रतिक्रिया या प्रभाव देखने में नही आया। भारत-मत्री ने ९ जनवरी, १९४२ को कामन सभा में भाषण देते हुए कहा, "दिसम्बर के अन्त में भारत के राजनीतिक दलों ने जो प्रस्ताव पास किये हैं और इस सम्बन्ध में राजनीतिक नेताओं ने जो विभिन्न वक्तव्य दिये हैं, उनकी ओर मेरा घ्यान आकृष्ट हुआ है, लेकिन मुझे खेद है कि हाल में वाइसराय ने समान सकट को देखते हुए भारतीय जनता से सहयोग और एकता की जो अपील की थी, उसके सम्बन्ध में इन दलों ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया।

श्री चिंचल अभी अमरीका में ही थे जब कि उन्हें बारदोली के प्रस्ताव का समाचार मिला और एक सवाल का जवाव देते हुए उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल इस वारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरा भारत की घटनाओं से कोई सपर्क नहीं रह सका। २२ जनवरी, १९४२ को कामन सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए श्री एमरी ने कहा कि मैं भारत की राजनीतिक स्थित के बारे में कोई और वक्तव्य नहीं देना चाहता। २७ जनवरी १९४२ को कामन सभा की एक वहस में हिस्सा लेते हुए श्री पेथिक लारेस ने कहा, कि मेरे विचार में भारतीय समस्या का कोई सन्तोषजनक हल ढूढ निकालना युद्ध-प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण अग है और प्रधान मंत्री को भारतीय जनता तथा उसके राजनीतिक नेताओं को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि देश के सभी लोगों की हार्दिक इच्छा यह है कि लडाई के बाद उन्हें औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय। श्री एडगर ग्रेनविल (उदार राष्ट्रवादी) ने यह आशा प्रकट की कि सरकार भारत के सभी साधनों का एकीकरण करने में सफल हो जाएगी और प्रधान मंत्री यह घोषणा कर देगे कि दूसरे स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों की भाति भारत का प्रतिनिधि भी लन्दन के युद्ध-मित्रमण्डल में ले लिया जाएगा।

३ फरवरी को एक बार फिर लार्ड सभा में एक गरमागरम वहस हुई, जिसमें लार्ड फैरिगटन (मजदूर-दल) ने प्रमुख भाग लिया। उन्होने सरकार का ध्यान उस वक्त की जरूरी समस्या की ओर आकृष्ट किया और यह शिकायत की कि सरकार में आत्म-सतुष्टि की भावन । घर कर गई है और परिस्थित हर रोज नाजुक होती जा रही है, लेकिन इतने पर भी उसका मुकाईला करने की

कोई कोशिश नहीं की जाती। मेरा सबसे पहला सुझाव यह हे कि सरकार यह घोषणा कर दे कि वह भारत को भविष्य में नहीं, बल्कि इसी वक्त स्वराज्य दे देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह घोषणा की हे कि अगर भारत के दोनों दलों में कोई समझौता हो जाय तो वह उसका समर्थन करेगी, लेकिन मेरे स्याल से यह कुछ अनुचित रवैया है। मुस्लिम लीग ने, जो कि मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, कागज पर अपनी मांगे लिखकर रख दी हैं और स्पष्ट है कि काग्रेस उन्हें किसी भी हालत में मजूर नहीं कर सकती। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकती और यह आवश्यक है कि विटेन के लोगों को भी यह बात आसानी से समझ लेनी चाहिए और उन्हें उग्र विचारोवाले मुसलमानों के हाथ का खिलौना वनकर भारतीयों के समझौते के मार्ग में रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिये।

लार्ड हेली ने कहा कि यह वक्त छोटी रस्मी वातों का नहीं है। हमें सीरिया की तरह ही भारत के वारे में भी कोई स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। लार्ट हेली ने पूछा कि भारतीय रियासतों की स्थित क्या होगी? और क्या अब हमें मुसलमानों की यह वात मजूर कर लेनी चाहिए कि संयुक्त भारत के टुकडे-टुकडे कर दिए जायें? उन्होंने कहा कि मेरे खयाल से तो सम्राट् की सरकार को एक ऐसी सतोपजनक घोषणा कर देनी चाहिए जिसके अन्तर्गत या तो कोई तारीख निश्चित कर दी जाय अथवा कोई ऐसा तरीका वताया जाय जिससे कि भारत के दोनों दलों में कोई समझौता हो सके।

लार्ड नभा में भारत-विषयक बहुस के दौरान में उप भारत-मन्नी ड्यूक आफ डीवनशायर ने जो भाषण दिया उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता हे कि साम्राज्य के लिए भारी खतरा पैदा हो जाने पर भी अपनी भारत-विषयक नीति के सम्बन्ध में विटेन की मनोदृत्ति में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया है। उन्होंने कायेस का असर घटाकर और मुस्लिम लीग का असर बढ़ाकर दिवाने की कोशिय की। उन्होंने कहा, "ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम लीग का अमर और उसकी ताकन निरित्त रूप से बढ़ रही है और इस वन्त काग्रेस की ताकत कम हो रही है। काग्रेस के दावे को चुनौती दी जा रही है और महान् मुस्लिम जाति हमेशा ही उसके दावे को चुनौती देती रहेगी।"

वने रहना था। ब्रिटेन और अमरीका में होनेवाली प्रतिक्रियाओं और आलो-चनाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता था। उघर अन्य महासागर के पार न्यूयार्क का घ्यान गांधी और चांगकाई शेंक के मिलन की ओर आकृष्ट हो गया और "न्यूयार्क टाइम्स" ने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवादी इस समय केवल समय की प्रतीक्षा में वैठे हैं। आग वह प्रश्न करता है कि "क्या भारत की जागृति का समय निकट आ गया है ? इस वारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि अब चीन और भारत अग्रेज के घर पानी नहीं भरते, वे अव उसकी कठपूतली नही रहे।"

चांगकाई शेक का स्वागत

९ फरवरी, १९४२ को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक घटना हुई जव कि भारत ने जनरल चागकाई शेक, मदाम चागकाई शेक और उनके सैनिक अफसरो का भारत के वाइसराय के अतिथियों के रूप में स्वागत किया। एक विज्ञापन में वताया गया कि "जेनरलिस्सिमो चागकाई शेक भारत और चीन से सम्बन्ध रखनेवाले समान विषयो के सम्बन्ध में भारत-सरकार और खासतौर पर भारत के प्रधान सेनापित से सलाह-मशविरा करने आए हैं। उन्हें आशा है कि भारत में अपने प्रवास की अवधि में उन्हें भारत के प्रमुख सार्वजनिक नेताओं से भेट करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।"

आधुनिक चीन के उद्धारक के नाम भारत के विभिन्न भागों से उनका स्वागत करते हुए बहुत से सन्देश भेजे गए। ब्रिटेन और अमरीका के समाचारपत्रों ने इस अभूतपूर्व और अप्रत्याशित घटना पर वडी प्रसन्नता प्रकट की। पडित जवा-हरलाल नेहरू ने उनके साथ कई बार भेट की । पहले तो स्वय अकेले, फिर कागेस के प्रधान मौलाना आजाद के साथ और बाद में अपनी बहन और पूत्री के साथ। यह आशा की जाती थी कि जेनरिलिस्सिमो गाधीजी से भी मुलाकात करेगे, लेकिन ऐसा न हो सका।

१९ फरवरी, १९४२ को शान्तिनिकेतन में जनरिलिस्सिमो चागकाई शेक और मदाम चागकाई शेक का खूब धूम-धाम से स्वागत किया गया। रथीन्द्रनाथ

के स्वागत-भाषण का उत्तर देते हुए जेनरलिस्सिमो ने कहा —

''इस अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मे महाकवि के निवास-गृह पर आकर मुझे और मदाम चागकाई शेक को बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए हम आपके आभारी है। हमने महाकवि के साक्षात् दर्शन तो नहीं किये हैं, लेकिन अपनी इस सस्था में जो जीवन वह डाल गए हैं, उसे देख-कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। "हमें पूर्ण आशा है कि इस सस्या के अध्यापक और छात्रगण, जो यहाँ एकत्र

है, इस संस्था की परपरा को बनाए रखने का प्रयत्न करेगे और उस महान् कर्म को जारी रखेगे जिसकी आधार-शिला आपके गुरुदेव रख गए हैं। जिस प्रकार हमारे सनयात सेन ने हममे विश्ववयापी भ्रातृत्व का बीज बोया था और नवीन चीन के यश को बढाया था उसी प्रकार आपके गुरुदेव ने आपके महान् देश के अध्यात्म को उन्नत करके एक नयी जागृति पैदा कर दी है।" आगे उन्होने कहा—"अपनी सहृदयता और चीन-वासियो की शुभकामनाओ के अतिरिक्त मैं आपके लिए चीन से और कुछ नहीं लाया हूँ। भगवान् करे आप उस विशाल कार्य को पूरा कर सके जिसे पूरा करने का भार आपके महान् नेताओ ने समस्त राष्ट्र के कन्धो पर छोडा है।"

जनरिलिस्सिमी चागकाई शेक और उनके साथी कलकत्ता से स्पेशल गाडी में शान्ति-निकेतन पहुँचे थे। उनके साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू भी थे।

बोलपुर स्टेशन पर उनका स्वागत किव की पौत्री श्रीमती प्रतिभा टैगोर, प्रिसिपल क्षितिमोहन सेन और विश्वभारती के प्रधान सेकेटरी श्री अनिलचन्द्र ने किया। वहाँ से वे सब लोग सीधे मोटर-द्वारा उत्तरायण पहुँचे जहाँ श्री रथीन्द्र-नाथ टैगोर ने उनकी आवभगत की।

किव के अन्तिम निवासस्थान "उदीची" में कुछ देर तक विश्राम करने के बाद मार्शल चागकाई शेक और मदाम चागकाई शेक ने शान्ति-निकेतन के कला-विभाग का निरीक्षण किया। मध्याह्मोत्तर उनका स्वागत सिह-सदन में किया गया। जब सम्मानित अतिथि अपने-अपने स्थानो पर बैठ गए, तब समारोह वैदिक मंत्रो से प्रारम्भ हुआ। इसके बाद उन्हें पुष्पमालाएँ पहनाई गईं और उनके मस्तक पर भारतीय विधि के अनुसार चदन का तिलक लगाया गया। विश्व-भारती की ओर से जेनरिलिस्सिमों को एक जोडा रेशमी धोती तथा एक चादर और श्रीमती चागकाई शेक को एक सुन्दर रेशमी साडी भेट की गई।

विश्व-भारती की ओर से मार्शल चागकाई शेक और श्रीमती चागकाई शेक का अभिनन्दन करते हुए श्री रथीन्द्रनाथ टैगोर ने चीन के प्रति महाकि रवीन्द्र-नाथ की असीम सहानुभूति और प्रेम का उल्लेख किया और कहा कि अन्तिम समय तक किव ने आपके देश की निर्जाति के सम्बन्ध में गहरी दिलचस्पी ली और वह आपकी जनता के महान् गुणो और जीवन मृत्यु के महान् सघर्ष में भी ज्ञान के प्रति उनके आराम की प्रशसा करते नहीं थकते थे श्रीमती चागकाई शेक ने पृथक् रूप से उत्तर देते हुए कहा—''जब से जापान ने चीन पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया है, हमारे हजारो छात्रों को बमो, टैको और तोपों का सामना करना पड़ा है। शत्रु ने उनके घरों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है। लेकिन जैसा आपको ज्ञात है, हमारे छात्र सैकडों मील पैंदल चलकर सरकार द्वारा देश के भीतरी भागों में स्थापित नये शिक्षालयों में पढने के लिए गए हैं। उन्होंने चीन के मस्तिष्क को जागरूक वनाए रखा है और देश-भिक्त की ज्योति को अपूर्व द्युति के साथ प्रज्ज्विलत रखा है। इस शान्तिमय भूमि में जहाँ जापानी सैनिकवाद का कोई खतरा नहीं है, आपके लिए यह समझना कठिन होगा कि इसका क्या अभिप्राय है।"

शान्तिनिकेतन की छात्राओं ने केसरिया साडियों में मार्शल चागकाई शेंक को "गार्ड आव आनर" दी। पडित जवाहरलाल नेहरू ने इस "गार्ड आव आनर" का निरीक्षण किया।

मार्शल चागकाई शेक और श्रीमती चागकाई शेक ने कला-भवन और श्री-भवन का निरीक्षण किया। चीन-भवन में दोपहर वाद चाय दी गई। भवन चीनी चित्रो से कलापूर्ण ढग से सजाया गया था। वाद मे वे उत्तरायण गए जहा उनके मनोरजन का प्रवन्ध किया गया था।

मार्शल चांग का सन्देश

मार्शल चाग दो सप्ताह तक भारत में रहे। इस बीच उन्होंने सर्वोच्च सैनिक अधिकारियो तथा भारतीय मित्रो से वात-चीत की। चलते समय उन्होने जो सन्देश दिया वह सक्षेप में इस प्रकार है—"वर्तमान अन्त-र्राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण संसार दो भागों में विभक्त हो गया है। एक अत्याचारी दल और दूसरा अत्याचार-विरोधी दल। उन सव लोगो को अत्या-चार-विरोधी दल में सम्मिलित होना चाहिये जो आतकवाद के विरोधी हैं और अपने देश तथा मानव-समाज की स्वतत्रता के लिए यत्न कर रहे हैं। वीच का कोई मार्ग नहीं है और न घटना कम की प्रतीक्षा करने का अवसर है। मानव-समाज के भविष्य के लिए यह वडा महत्त्वपूर्ण कार्य है। हमारे सामने न तो किसी एक व्यक्ति या देश की स्वतत्रता का प्रश्न है और न किन्ही दो राष्ट्रों के निवासियों के वीच की किसी खास समस्या से इस प्रश्न का कोई सबध है। इसलिए जो भी राष्ट्र आतकविरोधी मोर्चे में सम्मिलित होगा वह किसी खास देश के साथ नही, बल्कि सारे मोर्चे के साथ ही सहयोग करेगा। इस प्रकार हम यह विश्वास कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता के इतिहास में प्रशान्त सागर का युद्ध एक युगान्तकारी घटनाकम है। लेकिन जिन साधनो के द्वारा ससार के लोग अपनी स्वतत्रता प्राप्त कर सकते हैं, वे अतीत में काम में लाए जानेवाले साधनों से भिन्न हो सकते हैं । आतकवाद-विरोघी राप्ट्रो को आशा है कि नये युग मे स्वतत्र ससार की रक्षा के लिए, जिसमे भारत का अपना स्थान होगा, भारत के निवासी अपनी इच्छा से वर्तमान युद्ध में पूरी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। ससार के लोगो का बहुत वडा भाग भारतीयो की स्वतत्रता की माग से पूर्ण सहानुभूति रखता है। यह सहानुभूति इतनी मूल्यवान है तथा इसे प्राप्त करना इतना कठिन है कि इसकी

कीमत धन या साज-सामान की दृष्टि से नहीं कूती जा सकती। इसलिए इस सहानुभूति को बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

"वर्तमान युद्ध स्वतत्रता और गुलामी का, प्रकाश और अन्यकार का, अच्छाई और वुराई का तथा आतकवाद और उसकी विरोधी शक्ति का युद्ध है। यदि आतकवाद-विरोधी मोर्चा युद्ध में पराजित हो गया तो ससार की सम्यता को सौ वर्ष पीछे ढकेल देनेवाला धक्का लग जाए ז और मनुष्य-समाज के कष्टो का पारा-वार नहीं रहेगा। "वर्वरता और पाशविक दल के इस युग में चीनियो और उनके आर्य भारतीयो को चाहिए कि अटलाटिक अधिकार-पत्र तथा २६ राष्ट्रो के सयुक्त घोषणापत्र मे प्रतिपादित सिद्धातो का वे एक होकर समर्थन करे और आतक-विरोधी मोर्चे का साथ दे। मुझे आशा है कि भारत के निवासी पूर्ण रूप से मित्र-राष्ट्रो अर्थात् चीन, ब्रिटेन, अमरीका और रूस का साथ देगे और स्वतत्र ससार की रक्षा के लिये तब तक कन्धे-से-कन्धा भिडाकर लडते रहेगे जब तक कि पूर्ण विजय न प्राप्त कर ली जाय और जब तक कि वे इस सकट-काल के अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पूरा न कर ले।

''अन्त मे, मुझे पूरी आशा और दृढ विश्वास है कि हमारा महान् मित्र ब्रिटेन भारतीयो की मांग की प्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें शीघ्र-से-शीघ्र वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करेगा जिससे कि वे अपनी आत्मिक तथा भौतिक शक्तियो को और भी अधिक उन्नत कर सके और इस प्रकार यह अनुभव कर सके कि वे सिर्फ आतकवाद के विरोधी राष्ट्रों की विजय के लिए ही युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह भी अनुभव करें कि उनका यह सहयोग भारतीय स्वतत्रता के उनके सघर्ष में भी एक युगान्तकारी घटना है। क्रियात्मक दृष्टि से मेरे विचार में यह सब से अधिक बुद्धिमतापूर्ण नीति होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के यश को

चतुर्दिक प्रसारित कर देगी।"

हिज एक्सलेसी जेनरिलस्सिमो चागकाई शेक का भारतीयो के प्रति यह सन्देश मूल रूप से चीनी भाषा मे था, परन्तु उसका अग्रेजी मे अनुवाद श्रीमती चागकाई शक ने किया जो अखिल भारतीय रेडियो के कलकत्ता स्टेशन से ब्राडकास्ट किया गया था।

गांधीजी से भेंट

चागकाई शेक की भारत-यात्रा जितनी अप्रत्याशित थी उतनी ही गोपनीय थी। जहा तक गैर-सरकारी क्षत्रों का सम्बन्व है श्रीमती चागकाई शेक ने सद से पहले पडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी गति-विधि के वारे में पूछताछ की। इसके वाद ही दूसरा समाचार पडित नेहरू को कलकत्ता से यह मिला कि जेनर-लिस्सिमो और उनकी पत्नी कलकत्ता पहुंच गए हैं। अब तक यह एक रहस्य

बना हुआ है कि क्या चीन के ये दोनो महान् नेता भारत-सरकार के आग्रह करने पर यहा आए थे अथवा स्वय अपनी मर्जी से ? सभवत पहली बात ज्यादा ठीक हो। जो कुछ भी हो, हम यह वात कभी नही भूल सकते कि उन्हें गांधीजी से मुलाकात करने में कितनी कठिनाई अनुभव करनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने पूछा कि क्या कलकत्ता में गांधीजी के लिए भेट करना उपयुक्त रहेगा। गांधीजी ने डरते-डरते उन्हें पत्र लिखा। इस पर जेनरलिस्सिमो ने उत्तर दिया कि मेरे ऊपर आपके पत्र का इतना गहरा असर पड़ा है कि में हर हालत में आप से मुलाकात करने को उत्सुक हूँ। आखिर कलकत्ता में इस मुलाकात का प्रवन्ध किया गया। दोनो नेताओं ने एक-दूसरे से मुलाकात और लम्बी हार्दिक बातचीत की।

जैसा कि अब पता चला है कि चागकाई शेक यह कहते थे कि भारत को बिना शर्त युद्ध में सहयोग देना चाहिये। दूसरी तरफ गाधीजी इस बात पर दृढ थे कि किसी भी हालत में हम लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। इसिलए दोनों के एक राय होने की गुजाइश न थी। हा, इतना अवश्य था कि दोनों के बीच ऊँची सस्कृति की एक अटूट कड़ी थी, जो चीन और भारत को एक दूसरे से बाघे हुए थी। श्री जिन्ना भी चागकाई शेक से मिले, परन्तु उनकी मुलाकात के बक्त गाधीजी की तरह श्रीमती चागकाई शेक ने दुभाषिये का काम नहीं किया, बिल्क चागकाई शेक के एक कर्मचारी ने ही यह जिम्मेवारी निभायी।

२१ फरवरी, १९४२ को रात्रि के समय उक्त दोनो महानुभावो ने कलकत्ता रेडियो स्टेशन से भारतीयो के नाम अपना सदेश ब्राडकास्ट किया। जेनर-लिस्सिमो ने भारतीयो के नाम जो सन्देश दिया वह सर्वथा समीचीन था। उन्होंने यह आशा प्रकट की कि ब्रिटेन भारत में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तन कर देगा।

सन्देश का प्रभाव

नि सन्देह जेनरिलिस्सिमो की यह भारत-यात्रा सामिरक दृष्टि से बडी महत्वपूर्ण थी। परन्तु इसके अलावा न केवल चीन और भारत के लिए ही उसका सास्कृतिक महत्व था, बिल्क समस्त ससार के लिए था। बिटेन के समाचारपत्रो ने इस अवसर से लाभ उठाते हुए यह प्रश्न किया कि "अगर ब्रिटेन चीन का सम्मान कर सकता है तो कोई वजह नहीं कि हम भारत के साथ समानता के आधार पर अपनी दोस्ती का हाथ न बढाए ?" लगभग इसी समय यह फैसला हुआ कि भारत-सरकार को ब्रिटेन के युद्ध-मिन्त्रमण्डल में अपना एक प्रतिनिधि भेजने का निमत्रण दिया जाना चाहिये। भारत में इसकी प्रतिक्रिया मिश्रित-सी रही, क्योंकि यहां ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि यह प्रस्ताव महज एक पुरानी

प्रथा की पुनरावृत्ति मात्र है, क्यों कि इससे पहले पिछली लड़ाई में भी तात्कालिक प्रधान मत्री लॉयड जॉर्ज ने शाही युद्ध-मित्रमंडल में उपनिवशों के प्रधान मित्रयों के साथ-साथ एक भारतीय प्रतिनिधि को भी ले लिया था। यह भी स्मरण रहे कि किस प्रकार लॉयड जॉर्ज ने राजकीय युद्ध-सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय प्रतिनिधि को भी वही स्थान दिये जाने का फैसला किया था जैसा कि उपनिवेशों के प्रधान मित्रयों को प्राप्त था। १९१४-१८ के युद्ध में भारत के प्रतिनिधि सर एस॰ पी॰ सिन्हा थे। यह सावित करने के लिए कि इस सम्बन्ध में क्या ब्रिटेन के इरादे सच्चे थे, श्री एमरी से पूछा गया कि क्या भारतीय प्रतिनिधि को भी वही दरजा हासिल रहेगा जो स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मित्रयों को प्राप्त है दस पर श्री एमरी ने कहा 'हां'। उन्होंने इस सुझाव का समर्थन किया। "मैचेस्टर गार्जियन" ने यह सुझाव दिया कि वाइसराय को इस अवसर से लाभ उठाकर एक ऐसे भारतीय को नामजद करना चाहिये, जिसे स्वयं भारत भी अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर सके।

सेठ जमनालाल की मृत्यु

११ फरवरी, १९४२ को महान् दानवीर राजनीतिज्ञ और क्रियाज्ञील व्यक्ति सेठ जमनालाल बजाज का सहसा देहावसान हो गया। वह वर्षों से काग्रेस के कोषाध्यक्ष और एक अनुभवी तथा पुराने सार्वजिनक कार्यकर्ता थे। उनकी मृत्यु वर्षा में अपने निवास-स्थान पर हृदय की गित के वन्द हो जाने से हो गई। अपने देशवासियों के लिए उनकी एक अमूल्य देन वर्धा में अछूतों के लिए श्री लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है, जिसकी स्थापना १९२८ में की गई थी। देश में अपने ढग का यह एक ही मंदिर है। यदि इस नश्वर जगत् में जीवन की सफलता का मूल्याकन जीवन की अविध की वजाय व्यक्ति के नैसींगक गुणों के आधार पर किया जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपने त्याग, आत्मोसर्ग, सयम, निर्मोही और विरक्त तथा विनम्न स्वभाव, सद्भाव और मनुष्यमात्र के प्रति अपने प्रेम-भाव के कारण अपने जीवन को सफल कह सकता है और वह व्यक्ति है—सेठ जमनालाल वजाज। वह यद्यपि ५२ वर्ष तक ही जीवित रहे, फिर भी इस थोडे में समय में ही उन्होंने देश के जीवन में प्रमुख स्थान बना लिया था।

भावी कई पीढ़यो तक वह धनिक-वर्ग के लिए आदर्श वने रहेगे।

१९.

खुला विद्रोहः १६४२

क्रिप्स-सिशन

१९४२ के प्रारम्भ से ही भारत और ब्रिटेन दोनो ही जगह काफी राजनीतिक सरगर्मी देखने में आई। रूस से लौटने के बाद सर स्टैफर्ड किप्स की जान मे चार चाँद लग गये। सभी व्यक्ति उनकी ओर उत्सुकता-भरी दृष्टि से देखने लगे। भारतीय समस्या के हल के लिए सभी व्यक्ति उनका मुह ताकने लगे। आम लोगो का यह खयाल था कि सर स्टैफर्ड किप्स ही एक ऐसे व्यक्ति है, जो भारतीय प्रश्न पर नये दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं। इससे ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्यान वहुत ऊँचा हो गया था। श्री एमरी, श्री ईडन, श्री लिटलटन और श्री एटली को वह अपने से वहुत पीछे छोड गए थे। वह भारत के गतिरोव के वारे मे पहले ही एक वक्तव्य देकर उसके लिए आवश्यक परिवर्तनो का प्रस्ताव कर चुके थे। यह आशा की जा रही थी कि स्वय प्रधान मत्री श्री चींचल भारत के सम्बन्ध मे कोई घोषणा करने वाले हैं । १० मार्च, १९४२ को सर स्टैफर्ड किप्स ने भी इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा की कि सभा की अगली बैठक में प्रघान मन्त्री भारत के सम्बन्व में एक वक्तव्य देगे। इसके वाद ही यह नोषणा की गई कि सर स्टैफर्ड किप्त एक खास उद्देश्य को लेकर भारत जा रहे है। उनका भारत-आगमन इस दृष्टि से वहुत ही उपयुक्त था कि वह इस बात की कोशिश करेगे कि अल्पसंख्यक देश की राजनीतिक प्रगति में नाहक रुकावट न पैदा करते रहे और न वहुसख्यक अल्पसख्यको के हितो की उपेक्षा करे। निस्सदेह यह एक उच्च उद्देश्य था। ११ मार्च १९४२ को श्री चिंलल ने कामन सभा में भाषण देते हुए जो बाते कही वे यहाँ सक्षेप मे दी जा रही है।

प्रधान सन्त्री का वक्तव्य

श्रीचर्चिल ने नहा-

"जापानियों की प्रगित के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि शत्रु से देश की रक्षा करने के लिए हमें भारत के सभी वर्गों का सगठन करना चाहिये। अगस्त, १९४० में हमने भारत के सम्बन्ध में अपने उद्देश्यों और नीति के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हुए एक घोषणा की थी। सक्षेप में उसका आश्य यह था कि लडाई खत्म होने के बाद यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य दे

दिया जाएगा और उसका दरजा इस देश के तथा अन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों के समान रहेगा। इसके अलावा स्वय भारतीय पारस्परिक समझौत-द्वारा देश के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेंगे जो देश के सभी मुख्य वर्गों को स्वीकृत होगा। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें अल्पसख्यकों के हितों का ध्यान रखना होगा, जिनमें दिलत जातिया भी शामिल हैं। इसके अलावा रियासतों के साथ हमारी जो सिन्ध्या है उनका तथा भारत के साथ अपने पुरातन सम्बन्धों के कारण हमारी जो जिम्मेवारिया है उनका भी हमें खयाल रखना होगा।

"चुनाचे हमने युद्ध-मित्रमण्डल के एक सदस्य को भारत भेजने का फैसला किया है जिससे कि वह वहा जाकर भारतीय नेताओं के साथ निजी बातचीत द्वारा इस बात की तसल्ली कर ले कि हमने जो फैसला किया है और जो हमारे खयाल से न्यायोचित है तथा इस समस्या का अन्तिम हल है, सफल हो जाएगा। अर्थात् भारतीय उसे स्वीकार कर लेगे। हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्व के स्वतत्रता के सग्राम में भारत को प्रमुख भाग लेना है और उसे चिरकाल से युद्ध-रत बहादुर चीनी जनता का भी हाथ बँटाना है। भारत एक ऐसा अड्डा है जहाँ से हम अत्याचार और आतक की प्रगति पर जोरदार प्रत्याक्रमण कर सकते हैं।"

क्रिप्स के प्रस्ताव

सर स्टैफर्ड किप्स ने ब्रिटिश सरकार की ओर से नीचे लिखे प्रस्ताव प्रकाशित किये —

"भारत के भविष्य के सम्वन्ध में दिये गए वचनों के पूरे होने के विषय में जो चिन्ता प्रकट की गई है उस पर विचार करते हुए सम्राट् की सरकार स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में उन उपायों को वता देना आवश्यक समझती है, जो भारत में शिद्यातिशी प्रस्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए वह करना चाहती है। ऐसा करने में उसका उद्देश एक नवीन भारतीय सघ को जन्म देना है। यह सघ एक स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश होगा और ब्रिटेन तथा साम्राज्य के अन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों से उसका सम्बन्ध सम्राट् के प्रति समान राजभिक्त-द्वारा कायम रहेगा। यह भारतीय सघ पद की दृष्टि से पूरी तौर पर ब्रिटेन तथा अन्य स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के समान होगा और आन्तरिक शासन तथा वैदेशिक समस्याओं के सम्बन्ध में भी वह किसी प्रकार से भी पराधीन न होगा। इसलिए सम्राट् की सरकार निम्न घोषणा करती है—

(क) युद्ध वन्द होने के वाद तुरन्त ही भारत के लिए नवीन शासन-विधान का निर्माण करने के उद्देश्य से वाद में विणित आधार पर एक निर्वाचित सस्या कायम की जाएगी। (ख) विघान वनानेवाली सस्था में देशी रियासतो-द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था जिस प्रकार से की जाएगी, उसका वर्णन नीचे किया गया है।

(ग) सम्राट् की सरकार इस प्रकार तैयार किये गए विघान को स्त्रीकार करके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर केवल उसी अवस्था में लेती है जब कि निम्न शर्तें भी पूरी होती हैं—

(१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नये विवान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का अधिकार रहे, किन्तु साथ में यह व्यवस्था भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त वाद में चाहे तो विधान में सम्मि-लित कर लिया जाय।

"नये विघान में सम्मिलित न होनेवाले ऐसे प्रान्तो को, यदि वे चाहे, सम्राट् की सरकार नया विघान देना स्वीकार करेगी और उनका पद भी पूर्ण रूप से भारतीय सघ के ही समान होगा। यह विघान उस क्रम से मिलते-जुलते ढंग पर तैयार होगा, जिसका उल्लेख यहा किया गया है।

(२) सम्राट की सरकार तथा उस विघान-निर्मात्री सस्था के बीच एक सिंध होगी। अग्रेजो से भारतीयो के कन्धो पर पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित होने की सभी आवश्यक समस्याओं का पूर्ण समावेश इस सिंध में रहेगा। सम्राट् की सरकार-द्वारा दिये गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए सिंध में जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रवन्ध रहेगा, किन्तु उसमें ऐसा कोई प्रतिवन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय संघ के ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों से अपने भावी सवध निश्चित करने के अधिकार में कमी होने की सभावना हो।

"देशी रियासते नये विधान के अनुसार चलना चाहें अथवा नही, नयी परि-स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए उनकी सन्धियो की व्यवस्था में सशोधन करना

आवश्यक होगा।

(घ) यदि प्रमुख सप्रदायों के नेताओं ने युद्ध समाप्त होने तक और किसी प्रणाली के विषय में मिलकर निश्चय न कर लिया, तो विधान-निर्मात्री संस्था का निर्माण इस प्रकार होगा—

"प्रान्तीय चुनावों के परिणाम ज्ञात होते ही (युद्ध समाप्त होने पर प्रान्तीय चुनावों की आवश्यकता पड़ेगी) प्रान्तों की निम्न धारा-सभाओं के सपूर्ण सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मडल की हैसियत से वैठेगे और आनुपातिक प्रति-निधित्व के आधार पर विधान-निर्मात्री सस्था का चुनाव करेगे। निर्वाचक मडल में जितने व्यक्ति होगे उसकी दशमाश संख्या इस विधान-निर्मात्री संस्था में होगी।

"ब्रिटिशं-भारत की तरह देशी राज्यो से भी अपनी जन-सख्या के अनुपात से

प्रतिनिधि नियत करने को कहा जाएगा और उन प्रतिनिधियों के अधिकार विटिश भारत देः प्रतिनिधियों के समान रहेंगे।

(उ) भारत के सम्मुख जो सकट-काल उपस्थित है उनके बीच में और जब तक कि नया विधान त्यान् नहीं होता तब तक सम्माद की सरकार भारत की रक्षा, नियत्रण और निवेंगन का उत्तरदायित्य सपूर्ण विश्वयुद-प्रयत्नों के एक अग के रूप में अपने हाथ में रवेगी। किन्तु भारतीय जनता के सहयोग ने देश के सपूर्ण भीनक, नैतिक तथा आर्थिक साधनों को सगिवित करने की जिम्मेदारी भारत-सरकार पर रहेगी। सम्राद की सरकार की उच्छा है, और वह भारतीय जनता के विविध वर्गों के नेताओं का आह्मान करती है कि वे अपने देश, दिद्या राष्ट्र-मंग्रह तथा मित्रराष्ट्रों के सलाह-मगिविरे में तुरन्त और प्रभावीत्यादक दम में भाग के। उस प्रकार एक महान् कार्य के सम्पादन में दे रचनात्मक और गिविय सहायना प्रदान कर नकेंगे, जो भारत की भावी स्थानीनता के लिए बहुत ही महत्त्य-पूर्ण है।"

किप्स की नेतायों से भेंट

सिमिति १० अप्रैल तक किप्स-प्रस्तावो पर सोच-विचार करती रही। लेकिन १० अप्रैल को काग्रेस के प्रधान की सर स्टैफर्ड किप्स के साथ अन्तिम मुलाकात के बाद काग्रेस का यह भ्रम दूर हो गया। निस्सन्देह यह एक वडी विचित्र-सी वात है कि जिस आधार को लेकर विभिन्न दलों में यह वातचीत शुरू हुई थी अन्त में वहीं आधार एक मृगमरीचिका सावित हो और सारी वातचीत उस पर आकर टूट जाय।

क्रिप्स योजना का अन्त

सर स्टैफर्ड किप्स के प्रस्ताव ३० मार्च, १९४२ को प्रकाशित हुए। उस समय वह बड़े विचित्र और अनोखे प्रतीत हुए। उनमे प्रत्येक दल को खुश कर्नेवाली बाते थी। काग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावो की पूर्व-भूमिका में औप-निवेशिक स्वराज्य, वेस्टींमस्टर कानून, पृथक् होने का अधिकार और सर्वोपिर वात विधान-परिपद् का उल्लेख या जिसे प्रारंभ में ही ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल से पृथक् हो जाने की घोषणा कर देने का अधिकार दिया गया था। मुस्लिम-लीग के लिए सब से बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय संघ से अलग हो जाने का हक था। नरेशों को न केवल इस वात की आजादी थी कि वे चाहे तो इस सघ में शामिल हो या न हो बल्कि विघान परिपद् में रियासतो के प्रतिनिधि भेजने का एकमात्र अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। रियासतो की जनता की बुरी तरह उपेक्षा की गई थी और यहा तक कि उन्हें यह हक भी नही था कि वे गुलामो की तरह अपने मालिको के साथ भी वहा जा सके। कार्यसमिति को ब्रिटेन की इस योजना का रहस्य समझने में वहुत देर नहीं लगी। इससे साफ जाहिर था कि ब्रिटेन का इरादा सत्ता हस्तान्तरित करने का विल्कुल नही था। आजादी के सवाल को टाल-मटोल कर खटाई में डालने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा तीसरी बात यह थी कि रियासतो की जनता को विधान परिषद् मे अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से विचत कर दिया गया था। इससे रिया-सतो की जनता में बेचैनी और क्षोभ फैल जाना स्वाभाविक और अनिवार्य था। चुनाचे लोक-परिषद् के प्रधान पडित जवाहरलाल ने सारी स्थिति पर प्रकाश डॉलते हुए इस सम्बन्ध में सर स्टैफर्ड किप्स को लिखा और यह सुझाव पेश किया कि इस विषय पर और सोच-विचार करने के लिए उन्हें उक्त परिषद् के उप-प्रधान से भेट करनी चाहिये। फलत ३१ मार्च को परिषद् के उप-प्रधान ने सर स्टैफर्ड किप्स से बातचीत की। उन्होने बताया कि किस प्रकार ज्योही एक बार ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाएगा, देशी नरेश भी स्वत वाइसराय और राजनीतिक विभाग के नैतिक प्रभाव में आ जाएगे और वे स्वयमेव रियासतो की जनता के प्रतिनिधियो को विधान-परिषद् में भेज देगे।

परन्तु देशी राज्यों की जनता के राजनीतिक कण्टों के निवारण के लिए यह एक अप्रत्याशित औपभ्रं थी जिसे जल्दी से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। यह एक ऐसा प्रस्ताव था, जिसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। सर स्टैफर्ड किप्स का यह कहना था कि रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने जो सिंघया कर रखी है, उनकी शर्तों के अन्तर्गत उसके लिए रियासतों को विधान-परिषद् में जनता के प्रतिनिधि भेजने की किसी खास प्रणाली पर अमल करने के लिए मजबूर करना सभव नहीं था। परन्तु उनके पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था कि ५६२ रियासतों में से केवल तीस-चालीस रियासतों को छोडकर बाकी किसी भी रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार की कोई सिंध नहीं थी। शेष के साथ तो उसके सम्बन्ध केवल सनदों और समझौतों पर आधारित थे।

अब समझौते के प्रमुख और महत्त्वपूर्ण पहलू अर्थात् रक्षा के प्रक्त पर विचार कीजिए। ब्रिटिश मित्रमण्डल ने भारत के विभिन्न दलों की मजूरी के लिए सर स्टैफर्ड किप्स के जरिये जो प्रस्ताव यहाँ भेजे थे, उनमे रक्षा के प्रश्न को छुआ तक नहीं गया था। परन्तु वात यही तक सीमित नहीं थी। दिल्ली के अपने पहले ही पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में सर स्टैफर्ड किप्स ने साफ-साफ शब्दों में यह कह दिया था कि अगर सभी दल एक साथ मिलकर रक्षा-विषय को भारतीयो के सुपुर्व करने की माग करे तब भी उसे उन्हें हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मामला विल्कुल साफ था। इसीसे प्रभावित होकर काग्रेस ने क्रिप्स-योजना को ठुकरा देने का फैसला किया। जब समाचारपत्रो की इस सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणियों का ज्ञान सर स्टैफर्ड किप्स को हुआ तब उन्होने पहली अप्रैल को विनम्रतापूर्वक काग्रेस के प्रधान और पडित जवाहरलाल को लिखा कि मेरी यह इच्छा है कि आप लोग इस प्रश्न पर प्रधान सेनापति से वातचीत करे। दूसरे दिन उन्होंने एक और पत्र लिखा जिसमे यह आग्रह किया कि यदि काग्रेस कार्यसमिति ने इन प्रस्तावों को ठुकराने का ही फ़ैसला कर लिया हो तो भी उसे अपना निर्णय तव तक नहीं प्रकाशित करना चाहिये, जब तक कि मैं काग्रेस के प्रधान से मुलाकात न कर लू। परन्तु इससे पूर्व सर स्टैफर्ड किप्स ३० मार्च को काग्रेस के प्रधान को लिख चुके थे कि न काग्रेस के प्रधान और न पंडित जवाहर-लाल नेहरू की प्रधान सेनापित से हुई मुलाकात का और न उनसे सर स्टेफर्ड किप्स की मुलाकात का कोई ऐसा परिणाम निकला जिससे प्रभावित होकर कार्यसमिति अपना निर्णय वदल लेती। लेकिन उसने १० अप्रैल तक अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया।

इसी वीच काग्रेस कार्यसमिति द्वारा किप्स-प्रस्तावो को ठुकरा दिये जाने पर सर स्टेफर्ड किप्स ने रक्षा-व्यवस्था के विषय मे एक और हल पेश किया जो कांग्रेस को सर्वया अमान्य था, इसलिए उसने इस वार भी उसे ठुकरा दिया। इस सुझाव का विस्तृत उल्लेख उस पत्र में किया गया है, जो उन्होने ७ अप्रैल, १९४२ को काग्रेस के प्रवान को लिखा था। इसके अनुसार प्रधान मत्री युद्ध-सस्दय के रूप में वाइसराय की शासन-परिपद् में बने रहेगे और युद्ध-सम्वन्धी सभी कार्रवाइयों का नियत्रण उनके हाथ में रहेगा। वाइसराय की शासन-परिपद् में रक्षा-विभाग का सदस्य एक भारतीय भी रहेगा, जिसके अधीन ये विपय होगे — जनसपर्क-विभाग, सैन्य-विघटन और युद्धोत्तर पुर्नीनर्माण, पेट्रोल का नियत्रण, पूर्वी देश-समूह परिपद् का प्रतिनिधित्व, सैनिको की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था, कैण्टीन (उपाहार-गृह) सगठन, कुछ गैर-टेकनिकल शिक्षण सस्थाए, सेना के लिए स्टेशनरी और छपाई आदि की व्यवस्था, विदेश से आनेवाले सभी शिप्ट-मडलो और अफसरो के लिए आवश्यक प्रबन्ध की देखरेख—यदि वह चाहे तो उनके आगमन पर आपत्ति भी उठा सकता है—खतरेवाले इलाको से लोगो का स्थानान्तरण, सिगनल-व्यवस्था का एकीकरण तथा आर्थिक सुख-सुविधा की व्यवस्था।

इस प्रकार साफ जाहिर है कि सर स्टैफर्ड किप्स ने ७ अप्रैल के अपने सुझाव में जिस दुहरी शासन पद्धति की योजना का प्रस्ताव किया था उसकी जगह अब इस नये सुझाव के अनुसार, उन दायित्वों को छोडकर जो प्रधान सेनापित शासन परिपद् के युद्ध-सदस्य के रूप में स्वय उठाते हैं, रक्षा-विभाग के अन्तर्गत शेप सव विषय प्रतिनिधित्व-प्राप्त भारतीय को पूर्ण रूप से सौप दिये जाएगे। एक तरह से यह कार्यों का विभाजन न होकर उनके उत्तरदायित्व का बँटवारा था। १० अप्रैल को इसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में सर स्टैफर्ड क्रिप्स से जो मुलाकात की गई उसके दौरान में उन्होंने कहा कि ये विषय युद्ध-विभाग के सदस्य के रूप मे प्रधान सेनापति की अधिकार-सीमा मे होगे, परन्तु जब उनसे विषयो की तालि-काओ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने को कहा गया तब उन्होने फिर १० अप्रैल वाली उन तालिकाओ का उल्लेख किया जो नामजूर की जा चुकी थी। जिन कारणो से अन्त मे जाकर किप्स-प्रस्ताव अस्वीकार किये गए उनमे से एक मुख्य बात यह भी थी। दूसरा कारण धारासभा के प्रति मित्रमडल के उत्तरदायित्व की प्रश्न था। सर स्टैफर्ड किप्स ने इस बात से साफ इन्कार कर दिया कि उन्होंन २५ मार्च की अपनी मुलाकात के दौरान में मौलाना आजाद से बातचीत करते समय 'मित्रमडल' शब्द का प्रयोग किया था और यदि काग्रेस इस तरह का उत्तर-दायित्व चाहती है तो उसे अपनी यह माग वाइसराय के सामने रखनी चाहिये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्य समिति तीन बार इन प्रस्तावों को ठुकरा चुकी थी, लेकिन सर स्टैफर्ड किप्स इसे समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे। पहली बार उसने २ अप्रैल को इन प्रस्तावों को नामजूर किया था। इसके बाद किप्स ने कार्यसमिति के पास अपना रक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव खुला विद्रोह: १९४२

भेजा और उसे भी काग्रेस ने ७ अप्रैल को रद कर दिया। लेकिन इस बार कर्नल जॉनसन ने इसे पत्रों में न प्रकाशित करने का आग्रह किया। इसके बाद रक्षा-व्यवस्था के सम्बन्ध में कर्नल जॉनसन ने एक और सुझाव पेश किया। उसके सम्बन्ध में कई सशोधन पेश किये गए। पर अन्त में १० अप्रैल को उसे भी कार्य-समिति ने नामजूर कर दिया। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि किप्स-योजना रक्षा और मित्रमडल के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर आकर असफल हो गई।

लार्ड हेलीफैक्स का भाषए

भारत में किप्स-योजना की बातचीत अभी चल ही रही थी कि ७ अप्रैल की रात्रि को न्यूयार्क के टाउनहाल में भाषण देते हुए भारत के भूतपूर्व वाइसराय लार्ड इरविन और अमरीका के तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत लार्ड हेलीफैक्स ने यह सभावना प्रकट करते हुए कि सम्भवत भारतीय प्रवक्ता किप्स प्रस्तावों को ठुकरा दे, कहा —

"अगर हमारा प्रयत्न असफल रहा तो ब्रिटिश सरकार को बड़े-बड़े सगिठित भारतीय दलो की सहायता अथवा सहयोग के विना ही विवश होकर अपने कर्त्तव्य का पालन करना पड़ेगा। भारत के सबसे बड़े सुसगिठित राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सहयोग से हम विचत रहे हैं। काग्रेस समस्त भारत का एक छोटा-सा भाग है और भारत के अन्य दल और सस्थाएँ, उसका यह एकमात्र दावा कि वह सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मानने को तैयार नहीं हैं।"

यह भाषण ७ अप्रैल को दिया गया और यह निश्चित है कि ऐसा भाषण देने के लिए लार्ड हेलीफैक्स को आवश्यक हिदायते लन्दन से ही प्राप्त हुई होगी। लन्दन में ब्रिटिश सरकार ने किप्स-योजना की असफलता को निश्चित समझ लिया था और इसकी सूचना उसने न्यूयार्क को भी दे दी। दूसरी वात यह है कि ब्रिटेन अमरीका को खुश करने की फिक्र में था। इसी उद्देश्य के लिए लार्ड हेलीफैक्स के उक्त भाषण की व्यवस्था भी की गई थी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति-पूर्ण न होगा कि मूल किप्स-योजना का असली मकसद भी अमरीका के जनमत को सतुष्ट करना ही था।

क्रिप्स का विरोधी रुख़

चाहे युद्ध की परिस्थित में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा कोई और वजह हुई हो, लेकिन यह एक सचाई है कि १० अप्रैल की गाम को सर स्टैफर्ड किप्स के रुख में पूर्ण परिवर्तन हो गया और वह इस वातचीत को वन्द कर देने के लिए व्यग्न और चितित-से दिखाई दिये। इघर इस वातचीत का खत्म होना था कि सर स्टैफर्ड किप्स ने विरोधी रुख अस्तियार कर लिया और

वह काग्रेस पर इलजाम-पर-इलजाम लगाते चले गए। १० अप्रैल की शाम को ज्यो ही काग्रेस के प्रधान और पिडत नेहरू सर स्टैफर्ड किप्स के यहा से वापस लौटे त्यो ही सर स्टैफर्ड किप्स फौरन श्री जिन्ना की कोठी पर दौडे गए। अगले दिन कार्यसमिति को उनकी तरफ से एक कटु पत्र मिला जिसमें उन्होंने काग्रेस पर यह दोप लगाया कि वह अल्पसंख्यको पर शासन करना चाहती है और उन्हें दबाकर रखना चाहती है। यह बड़े आश्चर्य की वात थी कि उन्होंने ऐसा पत्र लिखा, क्योंकि काग्रेस ने तो इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा था कि उसे या मुस्लिम लीग अथवा अन्य राजनीतिक दलों को कितने-कितने स्थान मिलने चाहिए। न कभी काग्रेस ने यही सुझाव पेश किया था कि प्रधान सेनापित के अलावा राष्ट्रीय सरकार के १४ सदस्यों में से उसे बहुमत दिया जाना चाहिये। इंग्लैण्ड वापस पहुँचने पर सर स्टैफर्ड ने काग्रेस पर एक और दोप यह लगाया कि वह लड़ाई के दौरान में ही विधान में परिवर्तन करना चाहती है, यद्यपि इस दिशा में कभी कोई कोशिश नहीं की गई थी।

किप्स की वापसी

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश मित्र-मण्डल के प्रस्ताव अगस्त १९४० के प्रस्तावो का ही एक परिवर्द्धित सस्करणमात्र थे। हम इसे यो भी कह सकते हैं कि ये विटिश मित्र-मण्डल के निर्जीव और मृत शिश् के समान थे और सर स्टैफर्ड किप्स नयी दिल्ली में वीस दिन तक इस। प्राणहीन शिशु में कृत्रिम उपायो से जीवन-सचार करने की चेप्टा कर रहे थे। उसमे जीवन फूकने की उन्होने लाख कोशिश की, पर सब वेकार गया। वीच-वीच मे कभी उसमे थोडा स्पन्दन और गति का अनुभव होने लगता था। परन्तु काग्रेस कार्यसमिति ने ३१ मार्च, १९४२ को इस शिशु के मरने की घोषणा कर दी थी-अर्थात् उन प्रस्तावी के प्रकाशित होने से पहले ही उसने उन्हें असफल कर दिया, केवल सर स्टैफर्ड किप्स के अनुरोध और निवेदन करने पर उसने अपनी ओर से उनके ठुकराए जाने का सँमाचार प्रकाशित नही होने दिया। इसके बाद उसे अनेक तरह की छोटी-मोटी रिआयते देकर फुसलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका परिणाम जले पर नमक छिडकने-जैसा ही हुआ। दरअसल ईमानदारी से गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं की गई। ८ अप्रैल तक यही स्थिति रही। इसके बाद उन्हें फिर नामजूर कर दिया गया और अब उनकी सफलता की कोई आशा न रही। उस शिशु के पुनर्जीवित होने की सब आशाओ पर पानी फिर गया। लेकिन इसी बीच एक अमरीकी डाक्टर कर्नल जॉनसन आ गया। पहले डाक्टर सर स्टैफर्ड किप्स ने उससे इस शिशु के बारे में सलाह-मशविरा किया। परन्तु इस नये डाक्टर का नुसखा भी बेकार रहा और अन्त मे ११ अप्रैल को इस

शिशु को जमीन में दफ़ना दिया गया—अर्थात् ११ अप्रैल को किप्स-प्रस्तावों के अन्तिम रूप से असफल हो जाने की घोषणा कर दी गई। सर स्टैफर्ड किप्स ने भी अपने प्रस्ताव ११ अप्रैल को वापस ले लिए और १२ अप्रैल को वह इंग्लैण्ड लीट गए। फिर भी श्री चिंचल और श्री एमरी यही घोषणा करते रहे कि प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों कायम हैं और उनमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं किया गया है।

विफलता के कारण

भारत के सभी प्रमुख दलो और सार्वजनिक सस्थाओं ने किप्स-प्रस्तावों को नाम-जूर कर दिया था। परन्तु प्रत्येक की वजह अलग-अलग थी। यह स्थिति विलकुल साइमन-कमीशन-जैसी थी। उस समय भी १९२७-२९ में विभिन्न दलो और सार्वजनिक सस्थाओ ने अलग-अलग वजहो से उसका वहिप्कार किया था। काग्रेस-द्वारा किप्स-योजना को नामजूर किये जाने की मुख्य वजह यह थी कि उनके अनुसार शासन-परिपद् धारासभा के प्रति जिम्मेदार नहीं थीं। इसके अलावा ऐसा करने के दूसरे और गौण कारण ये थे—एक तो प्रान्तों को भारतीय सघ से अलग हो जाने की आज्ञा दे दी गयी थी, दूसरे भारतीय रियासतो की जनता को इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रतिनिधित्व नही दिया गया था। उसके लिए उसमें कोई गुजाइश नहीं थी। तीसरे, रक्षा और युद्ध-विभागों को सुरक्षित विषय मानकर उन्हें भारतीयों को देने से इन्कार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थिति यह थी कि वह इस योजना को केवल उस हालत में स्वीकार करने को राजी थी जब काग्रेस भी उसे स्वीकार कर लेती। उसने इन प्रस्तावो को इस वजह से नामजूर कर दिया कि उनके अनुसार प्रान्तो को सघ से अलग होने का पूरा और साफ-साफ शब्दों में कोई अधिकार नहीं दिया ग्या था और न ही उनसे पाकिस्तान की माँग ही पूरी होती थी। हिन्दू-महासभा ने उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उनमें भारत के विभाजन की गुजाइश रखी गई थी, हालाँकि इस वात की वडी अस्पप्ट-सी सभावना थी। दलिंत वर्ग का यह कहना था कि हमें काफी सरक्षण नही दिये गये। भारतीय ईसाइयो और मजदूरों ने उसे उसी विना पर नामजूर कर दिया जिस पर काग्रेस ने किया था। सिर्फ रेडिकल डेमोकेटिक दल ही एक ऐसा दल या जिसने उसे स्वीकार किया। रियासतो को उससे कोई सरोकार नहीं या क्योंकि चाहे वे भारतीय संघ में शामिल होती या न होती; उनके लिए तो नयी परिस्थिति में अपने सविजन्य अधिकारो में संसोधन करना ही था। रही रियासतो की जनता, उसके लिए उसमे कोई गुंजाइया नहीं थी। इसलिए वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती यी।

सामृहिक श्रान्दोलन का निश्चय

भारत से लन्दन लीटकर सर स्टैफर्ड किप्स ने अमरीका के नाम जो भाषण व्राडकास्ट किया उसकी वडी जोरदार प्रतिक्रिया हुई। इस भाषण में किप्स ने कहा, "हमने प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताओं को तत्काल वाइसराय की शासन-परिषद् में ऐसा प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया जैसा कि आपके उन मित्रयों को प्राप्त है जो आप (अमरीका) के राप्ट्रपित को परामर्श देत हैं।" उन्हें इतने से ही सतोप नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि काग्रेस अल्पसंख्यकों पर छा जाना चाहती है। उसने गांधीजी के इशारे पर ही इन प्रस्तावों को ठुकराया। गांधीजी ने इन प्रस्तावों को एक दिवालिए बैंक की गैर-मियादी हुंडी कहा है। राजनीतिज्ञों, पत्रकारों, लेखकों और प्रचारकों ने उन्हों असत्य और वेवुनियादी वातों को लेकर झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया।

परन्तु गाधीजी गिरे हुए राजनीतिज्ञ नही थे। उनका सिद्धान्त असत्य का मुकावला सत्य और अन्वकार का मुकावला प्रकाश तथा मृत्यु पर जीवन द्वारा विजय पाने का था। इसिलए उन्होंने अप्रैल, १९४२ के अन्त में अपना आन्दोलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा—"भारत के लिए चाहें इसका कैसा भी परिणाम क्यों न हो, उसकी और ब्रिटेन की भी वास्तिविक सुरक्षा इसी में है कि अग्रेज व्यवस्थापूर्वक और समय रहते भारत से चले जाएँ।" यह कोई पहला मौका नहीं था जब कि गाधीजी ने अग्रेजों से भारत को छोड़ कर चले जाने को कहा हो। २२ अप्रैल १९४१ को श्री एमरी के उत्तेजनापूर्ण भायण का प्रत्युत्तर देते हुए गाधीजी ने कहा था, "आखिर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यह बात क्यों नहीं मान लेते कि यह भारत का घरेलू मामला है वे भारत से एक बार हट जाए, में बादा करता हू कि काग्रेस, लीग और देश के दूसरे सभी दल तब यह अनुभव करने लगेगे कि सब का भला इसी में है कि हम सब आपस में मिल जाएँ।" गाधीजी का दृढ विश्वास था कि ब्रिटेन के इस देश में बने रहने से जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलता है।"मुझे यकीन हो गया है कि अब वह वक्त आ गया है जब अग्रेजों और भारतीयों को एक-दूसरे से सर्वथा किनारा कर लेना चाहिए। अगर अग्रेज भारत से तत्काल और व्यवस्थित रूप में, पूर्णत हट जाए तो उससे मित्र-राष्ट्रों का लक्ष्य एकदम पूर्ण नैतिक आधार पर अधिष्ठित हो जाएगा।"

आगे चलकर गांधीजी ने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमें जापा-नियों का विशुद्ध अहिसात्मक असहयोग के आधार पर विरोध करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि उन्हें किसी भी तरीके से जापानियों की मदद नहीं करनी चाहिये। और न जापानियों के प्रति किसी प्रकार का दयालुतापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, उन्हें तो करोडो प्राणियों की आहुति देने को तैयार रहना

की घारासभा और काग्रेस की प्रारंभिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें। १५ ज्लाई को उन्होने ऐसा ही किया भी।

कार्य समिति का प्रस्ताव

जुलाई, १९४२ में कार्यसमिति का एक लम्वा अधिवेशन हुआ जो ६ जुलाई से लेकर १४ जुलाई तक जारी रहा। उस समय ससार की सुरक्षा और नाजीवाद, फासिस्टवाद, सैनिकवाद तथा साम्राज्यवाद के अन्त के लिए भारत में तत्काल ब्रिटिश शासन का अन्त नितान्त आवश्यक समझा जा रहा था। सितम्बर १९३९ से लेकर अक्ट्वर, १९४० तक काग्रेस ने ब्रिटेन को परेणानी में न डालने की नीति अख्त्यार की थी और फिर अक्ट्वर, १९४० से लेकर अक्ट्वर, १९४१ तक उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के जिरये अपना विरोध प्रकट करते हुए जान-बूझ कर सयम से काम लिया था। लेकिन ब्रिटेन पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार से भारत से हट जाने की जो माग की जा रही थी उसके पीछे भी सद्भावना थी और उसके फलस्वरूप देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना में मदद मिलती। ब्रिटिश सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का जोरदार आग्रह किया गया—

"जो घटनाए प्रतिदिन घट रही है और भारतवासियो को जो-जो अनुभव हो रहे हैं उनसे काग्रेसी कार्यकर्ताओं की यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि भारत मे ब्रिटिश शासन का अन्त अति शीघ्र होना चाहिये। यह केवल इसलिए नहीं कि विदेशी सत्ता अच्छी-से-अच्छी होते हुए भी स्वय एक दूपण और परतत्र जनता के लिए अनिष्ट का अबाध स्रोत है, बलिक इसलिए कि दासत्व-श्रुह्खला मे जकडा हुआ भारत अपनी ही रक्षा के काम मे, और मानवता का विध्वस करने वाले युद्ध के भाग्य-चक्र को प्रभावित करने में, पूरा पूरा भाग नहीं ले सकता। इस प्रकार भारत की स्वतत्रता न केवल भारत के हित मे आवश्यक है, बल्कि ससार की सुरक्षा के लिए और नाजीवाद, फासिस्टवाद, सैनिकवाद और अन्य प्रकार के साम्राज्यवादो एव एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के आक्रमण का अन्त करने के लिए भी। ससारव्यापी युद्ध के छिड़ने के बाद से काग्रेस ने यत्नपूर्वक परेशान न करने वाली नीति को ग्रहण किया है। सत्याग्रह के प्रभावहीन हो जाने का खतरा उठाते हुए भी काग्रेस ने इसे जान बूझ कर साकेतिक स्वरूप दिया ओर यह इस आशा से कि परेशान न करनेवाली इस नीति के यौक्तिक पराकाप्ठा तक पहुँचने पर इसका यथोचित समादर किया जायगा और वास्तविक सत्ता लोकप्रिय प्रतिनिधियो को सौप दी जायगी जिससे कि राष्ट्र विश्व भर मे मानव स्वतत्रता, जिसके कुचल दिये जाने का खतरा उपस्थित है, प्राप्त करने के कार्य में अपना पूरा सहयोग देने में समर्थ हो सके। इसने यह आशा भी कर रखी थी कि ऐसा कोई भी

कार्य नहीं किया जायगा जिससे भारत पर ब्रिटेन के आधिपत्य के और भी दृढ होने की सम्भावना हो।

"किन्तु इन आशाओं को चकनाचूर कर डाला गया है। किप्स की निष्फल योजना ने स्पष्ट रूप से दिखला दिया है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सर स्टैफर्ड किप्स के साथ वार्ता करने में काग्रेस-प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय माग के अनुरूप कम-से-कम अधिकार प्राप्त करने का जी-तोड प्रयत्न किया, पर सफलता न गिली। इस असफलता के परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन के विरुद्ध विद्वेष-भावना में शीध्रता के साथ और व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और जापानियों को सैनिक सफलता से विशेष सन्तोष प्राप्त हुआ है।

"कार्यसमिति इस स्थिति को घोर आशका की दृष्टि से देखती हैं, क्यों कि यदि इसका प्रतिरोध न किया गया तो, अनिवार्य रूप से इसका परिणाम आक्रमण को निष्क्रिय भाव से सहन करना होगा। समिति की धारणा है कि सब प्रकार के आक्रमणों का प्रतिरोध होना ही चाहिए, क्यों कि इसके आगे झुक जाने का अर्थ अवश्य ही भारतीयों का पतन और उनकी परतत्रता का जारी रहना होगा। काग्रेस नहीं चाहती कि मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर जो बीती है वही भारत पर भी बीते। इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी अन्य विदेशी सत्ता की चढाई या आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति का सगठन करे। ब्रिटेन के विरुद्ध जो विद्देष-भावना वर्तमान है उसे काग्रेस सद्भावना के रूप में परिणत कर देगी और भारत को, ससार भर के राष्ट्रों और अधिवासियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के सयुक्त उद्योग और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले कष्ट और क्लेशों में स्वेच्छापूर्वक भाग लेने को प्रेरित करेगी। यह केवल उसी अवस्था में सम्भव है जब भारत स्वतंत्रता के आलोक का अनुभव करे।

"काग्रेस-प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने का शक्ति-भर प्रयत्न किया है, किन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह काम असम्भव हो गया है और वर्तमान अवास्तिविकता के स्थान पर वास्तिविकता की स्थापना तभी हो सकती है जब विदेशी प्रभुता और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय और भारतीय जन, जिनमें सब दलों और समुदाओं के व्यक्ति होगे, भारतीय समस्याओं का सामना करें और पारस्परिक समझौते के आधार पर उनका हल हुँ विकाले।

"तव सम्भवतः वर्तमान राजनीतिक दल जो प्रधानतः ब्रिटिश-सत्ता को अपनी ओर आकृष्ट करने और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से सगठित हुए हैं, अपनी कार्रवाई वन्द कर देंगे। भारत के इतिहास में, फिर यह बात पहले-पहल अनुभव की जायगी कि भारतीय नरेश, जागीरदार, जमीदार और सम्पत्तिवान तथा धनिकवर्ग उन श्रमजीवियों से अपना धन और सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, जो खेत-खिलहान, कारखानों और दूसरे स्थानों पर काम करते हैं और जो वास्तव में शक्ति एवं सत्ता के अधिकारी हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के हटा लिए जाने पर देश के जिम्मेदार स्त्री-पुरुप एक साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण करेंगे जो भारत के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी और वाद में ऐसी योजना को जन्म देगी जिससे विद्यान-निर्मात्री-परिपद् की रचना हो सकेगी जो राष्ट्र के सब वर्गों के स्वीकार करने योग्य भारतीय शासनविद्यान का निर्माण करेगी। स्वतत्र भारत के प्रतिनिधि और ब्रिटेन के प्रतिनिधि दोनो देशों के सहयोग और भावी सम्बन्ध को स्थिर करने के लिए, आक्रमण का सामना करने के सामूहिक कार्य में सहयोगियों के रूप में, परस्पर वार्तालाप करेगे।

"काग्रेस की हार्दिक इच्छा है कि वह, जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के वल पर भारत को आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य वनाए। भारत से ब्रिटिश सत्ता के उठा लिए जाने का प्रस्ताव पेश करने में काग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि इससे ब्रिटेन अथवा मित्रराष्ट्रों के युद्ध-कार्यों में बाधा पहुचे या इससे जापान या धुरी-समूह के किसी अन्य राष्ट्र को भारत पर आक्रमण करने या चीन पर दबाव बढाने को प्रोत्साहन मिले। और न काग्रेस मित्रराष्ट्रों की रक्षा-शक्ति को हानि पहुचाने का इरादा रखती है।

"इसलिए जापानियों के या किसी और के आक्रमण को दूर रखने या उसका प्रतिरोध करने के लिए, तथा चीन की रक्षा और सहायता के लिए काग्रेस भारत मे मित्रराप्ट्रो की सशस्त्र सेनाओ को टिकाने के लिए, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, राजी है। भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह कभी नहीं है कि भारत से सारे अग्रेज और निश्चय ही वे अग्रेज विदा हो जाय जो भारत को अपना घर वना कर वहा दूसरो के साथ नागरिक और समानाधिकारी वन कर रहना चाहते है। यदि इस प्रकार का हटना सन्द्रावनापूर्वक सम्पन्न हो तो इसके परिणामस्वरूप भारत में स्थायी शासन की स्थापना और आक्रमण का प्रतिरोध करने तथा चीन को सहायता देने में इस सरकार तथा सयुक्त राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो सकता है। काग्रेस इस वात को समझती है कि ऐसा मार्ग गहण करने में खतरे भी उपस्थित हो सकते हैं। किन्तु स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए और खासकर वर्तमान सकटापन्न स्थिति मे देश एव ससार भर मे कही अधिक खतरो और विप-दाओं से घिरे हुए स्वतत्रता के विशालतर आदर्श को वचाने के लिए, किसी भी देश को ऐसे खतरो का सामना करना ही पडता है । अस्तु, जब कि कागेस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर है, वह जल्दबाजी में कोई काम करना नही चाहती और न ऐसा मार्ग ग्रहण करना चाहती है जिससे मित्रराष्ट्रो को परेशानी हो। इसलिए यदि ब्रिटिश सरकार इस अत्यन्त यौक्तिक और उचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, जो न केवल भारत के, बल्कि ब्रिटेन के और उस स्वतत्रता के हित में है जिससे मित्रराष्ट्र अपने को सिश्लष्ट घोषित करते हैं, तो काग्रेस को ब्रिटिश सरकार

खुला विद्रोह: १९४२

के इस कार्य से प्रसन्नता होगी। अतए न, यदि यह अपील व्यर्थ गई तो काग्रेस वर्तमान स्थित के स्थायित्व को, जिससे परिस्थित का घीरे-घीरे विगड़ना और भारत की आक्रमण-विरोधी शक्ति और इच्छा का दुवंल होना स्वाभाविक है, घोर आशका की दृष्टि से देखेगी। उस स्थित में काग्रेस का अपनी समस्त अहिसात्मक शिक्त का, जो सन् १९२०—जबिक इसने राजनीतिक अधिकारों और स्वाधीनता के समर्थन के लिए अहिसा को अपनी नीति के एक अग के रूप में स्वीकार किया था—के वाद सचित की गई है, अनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक सघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी करेगे। चूंकि, जो प्रश्न यहा उठाए गए हैं वे भारतीय जनता एव मित्रराष्ट्रों की जनता के लिए सुदूरव्यापी तथा अत्यन्त महत्व के हैं, इसलिए कार्यसमिति अन्तिम निर्णय के लिए इन्हें अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सुपुर्द करती है। इस कार्य के लिए ७ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक होगी।"

महासमिति का प्रस्ताव

इस प्रस्ताव को पास किए दो महीने गुजर चुके थे और इस अवधि में जो घटनाए हुई थी उनके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय महासिमिति के पास इसके सिवा और कोई चारा ही नही था कि वह अपने वम्बई वाले अधिवेशन में कार्यसिमिति के प्रस्ताव को पास करे। उसने यह प्रस्ताव कुछ साधारण हेर-फेर के साथ पास कर दिया। यह साधारण परिवर्तन भी उसमें इसलिए किया गया कि कुछ बातों पर अधिक जोर दिया जा सके और कुछ बातों को अधिक स्पष्ट किया जा सके। कार्यसिमिति की सिफारिशों पर ७ और ८ अगस्त, १९४२ को अखिल भारतीय महासिमिति द्वारा बम्बई में जो प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार था—

"अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ के प्रस्ताव के विषयो पर, जो कार्यसमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, और वाद की घटनाओ पर, जिनमें युद्ध की घटनावली, ब्रिटिंग सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गयी आलोचनाए सम्मिलत हैं, अत्यन्त सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय है कि वाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस वात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिंग शासन का तात्कालिक अन्त, भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए अत्यन्त वावश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्वल वनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातत्र्य के बादर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी गिक्त में क्रिमक हास उत्पन्न करता है।

"इसलिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा लेने की माग को दुहराती है। भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतन्त्र भारत मित्र-राष्ट्रो का मित्र वन जायगा और स्वातन्त्र्य-सग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीक्षाओ और दू ख-सूख में हाथ वटायेगा। अस्थायी सरकार देश के मुख्य दलो और वर्गो के सहयोग से ही बनायी जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जुली सरकार होगी जिसमे भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उसका प्रथम कर्त्तव्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा अहिसात्मक शक्तियो द्वारा मित्रराष्ट्री से मिल कर भारत की रक्षा करना, आक्रमण का विरोध करना, और खेतो, कार-खानो तथा अन्य स्थानों में काम करनेवाले इन श्रमजीवियो का कल्याण और उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति और अधिकार के वास्तविक पात्र है । अस्थायी सरकार एक विघान-निर्मात्री-परिपद की योजना वनायेगी और यह परिषद भारत-सरकार के लिए एक ऐसा विवान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। काग्रेस के मत से यह विद्यान सध-विषयक होना चाहिए जिसके अन्तर्गत सघ मे सम्मिलित होने वाले प्रान्तो को शासन के अधिकतम अघिकार प्राप्त होगे । अवशिष्ट अधिकार भी इन प्रान्तो को प्राप्त होगे । भारत और मित्रराष्ट्रो के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतन्त्र देशो के प्रतिनिधियो द्वारा निश्चित कर दिये जायगे जो अपने पास्परिक लाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिए परस्पर वार्तालाप करेंगे। स्वतन्त्रता भारत को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के वल पर आक्रमण का कारगर ढग से विरोध करने मे समर्थ वना देगी।

"भारत की स्वतन्त्रता विदेशी आधिपत्य से अन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति का प्रतीक और प्रारम्भ होगी। वर्मा, मलाया, हिन्दचीन, डच द्वीप समूह, ईरान और ईराक को भी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियन्त्रण में जो देश हैं उन्हें वाद को किसी औपनिवेर्शिक सत्ता के अधीन नहीं रखा जायगा।

"इस सकट-काल में यद्यपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी को प्रधानत भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिये तथापि कमेटी का मत है कि ससार की भावी शान्ति, सुरक्षा और व्यवस्थित उन्नति के लिये स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्वसघ बनाने की आवश्यकता है। अन्य किसी बात को आधार बना कर आधुनिक ससार की समस्याए नहीं सुलझाई जा सकती। इस प्रकार के विश्वसघ से उसमें सम्मिलित होनेवाले राष्ट्रों की स्वतत्रता, एक राष्ट्र द्वारा

दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अल्पसख्यको का सरक्षण, पिछडे हुए समस्त्रक्षेत्रो और लोगो की उन्नति और सब के सामान्य हित के लिए विश्व-साघनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्वसघ स्थापित हो जाने पर समस्त देशों में नि शस्त्रीकरण हो सकेगा। राष्ट्रीय सेनाओ, नौसेनाओं और वायुसेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और विश्व-रक्षक सेना विश्व में शान्ति रखेगी और आक्रमण को रोकेगी।

"स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्वसघ मे प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित होगा और अन्तर्रा-ष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने मे अन्य देशों के साथ समान आधार पर सहयोग करेगा।

"ऐसे सघ का द्वार उसके आधारभूत सिद्धान्तो का पालन करनेवाले समस्त राष्ट्रो के लिये खुला रहना चाहिये। युद्ध के कारण यह सघ आरम्भ में केवल मित्रराष्ट्रो तक ही सीमित रहेगा। यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, घुरी राष्ट्रो की जनता पर और आगामी शान्ति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा।

"परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अनुभव करती है कि युद्ध की दु खद और व्याकुल कर देने वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात् और विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारे विश्वसघ बनाने की ओर कदम उठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण आलोचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है। ऐसी दशा में न तो नित्य बढते जाने वाले खतरे का कोई प्रतिकार ही किया जा सकता है और न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्यसमिति ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्यसमिति ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से जो सच्ची अपील की थी उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। बहुत से विदेशी क्षेत्रों में की गई आलोचनाओं से प्रकट हो गया है कि भारत और विश्व की आवश्यकताओं के विषय में अज्ञानता फैली हुई है। कभी-कभी तो आधिपत्य बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊच-नीच का प्रतीक वह विरोध भी दिखाया गया है जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ज्ञान रखनेवाली कोई भी अभिमानी जाति सहन नहीं कर सकती।

"इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातन्त्र्य का घ्यान रखते हुए अखिल भारतीय कार्यस कमेटी फिर ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों से अपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और जासनिप्रय सरकार के विश्व अपनी इच्छा प्रदिश्ति करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है जो उस पर आधिपत्य जमाती है और जो उसे अपने तथा मानव-समाज के हित का घ्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसलिए कमेटी भारत के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिसात्मक प्रणाली से और अधिक-से-अधिक विस्तृत परिमाण पर एक विशाल नग्राम चालू करने की स्वीकृति देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों

के शान्तिपूर्ण सग्राम में सचित की गई समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह सग्राम निश्चय ही गाधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करने और प्रस्तावित कार्रवाइयों में राष्ट्र का पय-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

"कमेटी भारतीयों से उन खतरों और किठनाइयों का, जो उनके ऊपर आयेंगे, साहस और दृढतापूर्वक सामना करने तथा गांधीजी के नेतृत्व में एक बने रह कर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पालन करने की अपील करती है। उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार है। ऐसा समय आ सकता है जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुचना सम्भव न होगा और जब कोई भी काग्रेस समिति कार्य नहीं कर सकेगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए अपने-आप काम करना चाहिए। स्वतन्त्रता की कामना और उसके लिए प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पय-प्रदर्शक वनकर उस किठन मार्ग पर अग्रसर होते जाना चाहिए जहा विश्राम का कोई स्थान नहीं हैं और जो अन्त में भारत की स्वतन्त्रता और मुक्ति पर जाकर समाप्त होता है।

"अन्त में यह बताया जाता है कि यद्यपि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में अपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि कमेटी समस्त सबद्ध लोगों के लिए यह विल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल सग्राम आरम्भ करके वह काग्रेस के लिए कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तब उस पर समस्त भारतीयों का अधिकार

होगा ।"

७ और ८ अगस्त को जब अखिल भारतीय महासमिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तब उसके सदस्यो और जनता दोनो में ही बडी उत्तेजना पाई जाती थी। सभामडप कमेटी की बैठक के बजाय काग्रेस का एक छोटा-सा अधिवेशन प्रतीत हो रहा था, जिसमें करीब बीस हजार आदमी सम्मिलित हुए थे। उक्त प्रस्ताव पडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया और यह प्रस्ताव केवल १३ विरोधी मतो से पास हो गया। प्रस्ताव के विरोधियों में १२ साम्यवादी और तरहवें व्यक्ति एक साम्यवादी के पिता थे।

गांधीजी का भाषण

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गांधीजी ने अपना भाषण दिया। उन्होंने कहा — "मैं इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, सेनापित अथवा नियत्रक के रूप में नहीं, बल्कि आपके तुच्छ सेवक के रूप में और जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा वहीं मुख्य सेवक माना जायगा। मैं तो राष्ट्र का मुख्य सेवक हूँ। मेरी अत्तरात्मा कहती है कि मुझे अकेले ही ससार से लोहा लेना पड़ेगा। वह मुझसे यह भी कहती है कि जबतक तुममें निश्शक होकर ससार का सामना करने की ताकत है, तबतक तुम सुरक्षित हो, भले ही दुनिया तुम्हें किसी और नजर से देखे। गांधीजी ने सवाल किया—आखिर आज भारत की आजादी मांग कर काग्रेस ने कौन-सा अपराध किया है विया ऐसी मांग करना गलती है, क्या उस सस्था पर सन्देह करना ठीक है मुझे आशा है कि इंग्लैण्ड ऐसा नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि अमरीका के राष्ट्रपित भी ऐसा नहीं सोचेंगे और चीन के सर्वोच्च प्रधान सेनापित मार्शल चांगकाई शेक भी, जो इस समय अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जांपानियों के साथ भीषण युद्ध कर रहे हैं, काग्रस के बारे में ऐसे। कोई बात नहीं सोचेंगे। अगर ससार के सभी राष्ट्र मेरा विरोध करे; यदि समस्त भारत भी मुझे समझाने की कोशिश करे तो भी मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं हूँगा। मैं आगे ही कदम बढाता जाऊँगा—सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि सारे ससार के लिए।"

गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी विश्वद रूप से प्रकाश डालते हुए साफ-साफ शब्दो में कहा, "पाकिस्तान के सवाल पर मेरे मन मे कोई भ्रम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान हिन्दुस्तान के बाहर नहीं बन सकता। हम सभी को एक-दूसरे के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर देश की आजादी की कोशिश करनी चाहिए। मैं बडा उतावला हूँ। आजादी सबके लिए है, किसी एक जाति या कौम के लिए नहीं। किसी भी कौम को हिन्दुस्तान की हुकूमत सौप देने की जो मांग मौलाना साहब ने ब्रिटेन के सामने पेश की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अगर मुसलमानोको हुकूमत सौप दी जाय तो उससे मुझे कोई रज नहीं होगा। अब की जो लडाई छिडेगी, वह तो सामूहिक लडाई होगी। हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है। हमारी तो खुली लडाई है। हम एक सल्तनत का मुकाबला करने जा रहे हैं और हमारी लडाई बिलकुल सीधी लडाई है। इस बारे में आप किसी भ्रम में न रहे। दिल में कोई उलझन न रखे। लुक-छिप कर कोई काम न करे। जो लुक-छिपकर काम करते हैं, उन्हें पछताना पडता है।"

गांधीजी की हिदायतें

गाधीजी ने सार्वजिनक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि आन्दोलन शुरू करने के पूर्व वह वाइसराय को एक पत्र लिखकर उनके जवाब की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। उनका खयाल था कि इसमें शायद दो-तीन सप्ताह लग जायें। इस बीच उन्होंने देशवासियों को सलाह दी कि वे काग्रेस के १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में अपनी शक्ति लगाएँ। इसके अलावा उन्होंने लोगों को नीचे लिखी हिदायते भी दी.— १—अखवारों को स्वतत्रतापूर्वक और निर्भीक होकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। उन्हें सरकार से डरना नहीं चाहिए और न किसी से रिश्वत लेनी चाहिए। अधिकारियो-द्वारा अपना दुरुपयोग किये जाने की अपेक्षा काम वन्द कर देना कही अधिक अच्छा होगा और तव उन्हें अपनी डमारतो, मशीनो और वडे-बडे कारोवार की कुरवानी देने को तैयार रहना चाहिये।

२—राजाओं को सबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा—"राजाओं को स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। उन्हें समय की गित को पहचान कर अपने जासन की बागडोर अपनी प्रजा को सींप देनी चाहिये और इसकी सूचना सरकार के राजनीतिक विभाग को भी दे देनी चाहिये।"

३—आन्दोलन के स्वरूप और उसे किस ढग से चलाना चाहिये, इस बारे मे गाधीजी ने कहा "गुप्त रूप से कोई काम न कीजिये, यह पाप है। लुक-छिपकर कोई आन्दोलन न चलाइये।"

४—विद्यार्थियो और शिक्षको को सबोधित करते हुए गाधीजी ने कहा कि 'वे अपने अन्दर आजादी की भावना को घारण करे,' काग्रेस के साथ खड़े रहें, यह कहने की हिम्मत दिखाये कि वे काग्रेस के हैं, और अगर जरूरत आ ही पड़े तो वे अपने घन्ये और 'कैरियर' को खुशी-खुशी छोड़ दें।

५—सरकारी नौकरों का जिक करते हुए गांधीजों ने उन्हें सलाह दी कि "उनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वे फौरन ही अपनी नौकरियों से इस्तीफ दें दें, लेकिन उन्हें सरकार को यह तो लिखकर दें ही देना चाहिए कि वे काग्रेस के साथ हैं।"

नेताओं की गिरफ्तारी

इस बात के बावजूद कि एक-के-बाद-एक सभी काग्रेसी प्रवक्ताओं ने पहले सरकार से समझौता करने पर जोर दिया, सरकार ने उनकी वातो पर कोई ध्यान न देकर उलटे जनता पर अपना जोरदार दमन-चक्र चलाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पौ फटने से पहले ही काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों और वस्बई के ४० प्रमुख नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें विक्टोरिया टरिमनस स्टेशन पर पहुँचा दिया, जहाँ उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन तैयार खडी थी। यह सारी कार्रवाई उसने इतनी तेजी और अप्रत्याशित ढग से की कि कुछ लोग अपने साथ अपनी ऐनक, बटुआ, कपड़े, पुस्तके और इसी प्रकार का अन्य आवश्यक सामान भी ले जाना भूल गए। श्री प्यारेलाल और बा को भी गिरफ्तार करके गांघीजी के नजरबन्द कम्प में भेज दिया गया। कार्यसमिति के सदस्य किस जेल में नजरबन्द किये जाएँगे, इस सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी सतर्कता से काम लिया और इस खबर को प्रकाशित नही होने दिया। लेकिन अखबारों में यह छप गया

कि गांधीजी को पूना में आगा खा के महल में नजरबन्द किया जा रहा है। गांधी जी, उनके दल और श्रीमती सरोजिनी देवी को चिचवाद नामक स्थान पर गांडी से उतार कर यरवडा जेल के पास एक बँगले में ले जाया गया। बम्बईवाले दल को किकीं में गांडी से उतार कर यरवदा भेज दिया गया और कार्यसमिति के सदस्यों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन ढोड पहुँची, जहाँ से उसने मद्रास-बम्बई वाली लाइन पर स्थित अहमदनगर का रुख किया। अहमदनगर में चाँदबीबी के किले में बडे लम्बे-चौडे हालवाले एक बडे और अलग भवन में इन लोगों को लाकर नजरबन्द कर दिया गया।

गांधीजी का वक्तव्य

गाधीजी की गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित किया गया उनका लेख सक्षेप में इस प्रकार है:—

"हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा की कार्य-सिमिति ने पूर्ण स्वतन्त्रता के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव पास किया है उसके सम्बन्ध मे अपनी स्थिति को स्पष्ट करना मेरे लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि वह मेरी ही प्रेरणा से पास किया गया है। आप मुझसे बिल्कुल अपरिचित नहीं है। पश्चिमी देशो मे शायद अमरीका ही एक ऐसा देश है, जहाँ मेरे अधिक-से-अधिक मित्र हैं, और ग्रेट ब्रिटेन भी इसका अपवाद नहीं है। इसके सिवा, थोरो के रूप में आप ही ने मुझे एक ऐसा शिक्षक दिया, जिसके "सविनय अवज्ञा का कर्तव्य" (डच्टी आफ सिविल डिसओबीडियन्स) नामक निबन्ध के द्वारा मुझे अपने उस कार्य का वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हुआ था, जो मै उन दिनो दक्षिण अफ्रीका मे कर रहा का वज्ञानिक समयन प्राप्त हुआ था, जा म उन ादना दावण वकाका न कर रहा था। ग्रेट ब्रिटेन ने मुझे रिस्किन जैसा गुरु दिया, जिसके "सर्वोदय" यानी "अनटू दि लास्ट" ग्रथ ने मुझमे इतना परिवर्तन किया कि मै एक ही रात मे बिल्कुल बदल गया। मैंने वकालत छोडी, शहर मे रहना छोडा, और मै एक देहाती बनकर डरबन से दूर एक ऐसे चक पर रहने लगा जो नजदीक के रेलवे स्टेशन से भी तीन मील दूर था। रूस ने टाल्सटाय के रूप मे मुझे वह गुरु दिया, जिससे मुझे अपनी अहिसा का एक बुद्धिसम्मत और तर्क-शुद्ध आधार प्राप्त हुआ। उन्होंने दक्षिण अफीका के मेरे उस आन्दोलन को, जो उस वक्त शुरू ही हुआ था, और जिसकी अद्भुत सम्भावनाओं को उस समय तक मै जान भी नहीं पाया था अपना आशीर्वाद दिया था । इसलिए आप यह समझ सकेंगे कि इस वक्त जो कदम मैंने उठाया है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन के और पश्चिमी देशों के खिलाफ दुश्मनी का कोई भाव नहीं है। "अनटू दि लास्ट" में दिये गए "सर्वोदय" के सन्देश को अच्छी तरह पचाने और आत्मसात् करने के बाद मैं उस फासिस्टवाद या नाजीवाद के

अनुमोदन के समर्थन का दोपी नही वन सकता, जिसका ध्येय व्यक्ति का और उसकी स्वतन्त्रता का दमन करना है। "मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे निर्माण की इस पाइवेंभूमिका के

घ्यान में रखकर हिन्दुस्तान से हट जाने के मेरे उस सूत्र को पढेंगे, जो ऑमतौर पर्वावित इंडिया" यानी "भारत छोडो" के नाम से पुकारा जाता है। इस सूत्र के पूर्वापर सम्बन्ध को घ्यान में रखते हुए इसका जो अर्थ निकल सकता है, उतना हूं अर्थ आप इससे निकालिये—उससे ज्यादा नही। मेरा दावा है कि मैं अपने वचपन से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ। मेरे लिये यह अत्यन्त स्वाभाविक वस्तु थी। मेरी भित-भाव युक्त खोज के कारण "ईश्वर सत्य है" के प्रचलित वचन के वदले यह दिव्य अर्थवाला वचन प्राप्त हुआ कि "सत्य ही ईश्वर है।" इस वचन के कारण मैं मानो ईश्वर को अपने सामने साक्षात् खडा पाता हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि वह मेरे रोम-रोम में व्याप्त है। अपने और आपके बीच इसी सत्य को साक्षी रखकर मैं वलपूर्वक यह कहता हूँ कि अगर मुझे अचानक यह बोध न हुआ होता कि ग्रेट ब्रिटेन और मित्र-राष्ट्रों के हित के लिये यह जरूरी है कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान को बन्धन से मुक्त करने के अपने कर्तव्य का साहसपूर्वक पालन करे तो मैंने अपने देशवासियों को यह सलाह कभी न दी होती कि वे ग्रेट ब्रिटेन को हिन्दुस्तान सेअपनी हुकूमत उठा लेने को कहे और इसके खिलाफ पेश की जानेवाली किसी भी मांग की परवाह न करे।

"अगर ब्रिटेन ने इस सर्वोत्तम न्याय से काम लिया तो आज हिन्दुस्तान में उसके खिलाफ जितना भी असतोष बढ रहा है, वह सब मिट जायगा। अपने इस एक कार्य-द्वारा वह बढते हुए दुर्भाव को सब्भाव में बदल डालेगा। इस पर आप विचार की जिए। बिना किसी शर्त के हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को भान लेने की जो माग काग्रेस कर रही है, उसमे अनुचित क्या है कहा जाता है कि 'यह उसका वक्त नहीं है।' हम कहते हैं, 'हिन्दुस्तान की आजादी को पान लेने का यही मनोवैज्ञानिक मुहूर्त है, क्योकि उसी एक हालत में जापानी हमलो का अचूक प्रतिकार किया जा सकता है।"

श्री एडगर स्तो का मत

श्री एडगर स्नों की यह राय थी कि अमरीकी जनता ने अभीतक यह महसूस नहीं किया कि भारत का विरोध हमारे लिए कितना निर्णायक और घातक साबित हो सकता है। अब तक जर्मनी ने जितने भी देशों पर अधिकार किया है, उन सब की अपेक्षा यह देश कही बडा है। इसकी जन-शक्ति नाजी साम्राज्य की तुलना में दुगुनी है। इसके साधन अपार हैं। ब्रिटेन, रूस और आस्ट्रेलिया को छोडकर यह देश मित्रराष्ट्रों का सब से बड़ा औद्योगिक अड्डा है। पश्चिमी गोलाई से बाहर होने के कारण यह दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमारा अन्तिम मजबूत अड्डा है। ऐसे महान् देश और जाति के सर्वसे वडे नेता गांधीजी है। पिछले वीस वर्षों में यदि 'काग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक' वन गई है तो इस पर हमे कोई आश्चर्य नही होना चाहिए। परन्तु वाइसराय महोदय मेरे इस विचार से सहमत नही है। यह सत्य है कि गांधीजी के वचन सूत्रवद्ध होते हैं। उनके विचारों में जो पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है, उसे भारतीय जनता अपनी प्रेरणा-शक्ति से समझ लेती है, क्योकि गाधीजी मे, आपको रहस्यवाद, आघ्यात्मवाद और परपरागत भावनाओ के साथ 'राजनीतिक यथार्थवाद' का सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। वास्तव मे उनके 'भारत छोडो' आन्दोलन के सिद्धान्त पर हमे इसी दृष्टिकोण से सोच-विचार करना चाहिए। 'साम्राज्य छोडिए और भारत को अपने पक्ष मे कीजिए' इस विषय का प्रतिपादन करते हुए आपने लिखा कि एक मुख्य वात जिसे हमे समझ लेना चाहिए यह है कि गाधींजी के कुछ विचार और वक्तव्य हमें चाहे कितने ही अनोखें क्यों न प्रतीत होते हों, परन्तु उनका भारत के राष्ट्रीय नेता होने की उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता। विल्क उसके विपरीत उन विचारों के कारण भारतीय जनता में उनकी स्थिति और भी अधिक सुदृढ हो जाती है। वे ही आत्मा है और वे ही विचार-शक्ति । वे एक महान् आत्मा है, जिसकी अधिकांश भारतीय पूजा करत है। गाधीजी में भारतीय जनता को अन्धविश्वास है।

सरकार का दमन-चक

परन्तु ब्रिटेन पर इनमें से किसी बात का भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसके अभिमान और प्रतिष्ठा को इस बात से ठेस पहुंचती थी कि एक परतत्र राष्ट्र अपनी स्वाभाविक गुलामी और परवशता को छोड़कर युद्ध के नगाड़े बजा रहा है। एक ऐसे संगठन के शान्तिद्रत का, जो उन्हें युद्ध की धमकिया देता रहा हो—भला वह क्योकर स्वागत कर सकता था। इससे उसके वडण्पन को धक्का लगता था। सरकारी आदेश था कि तीन बजने से पहले-पहले "सव" को गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया जाय। इसलिए पूर्व-निर्घारित योजना के अनुसार जो कुछ वम्बई में हुआ वही देश के सभी भागो—देशी राज्यों और प्रान्तो, शहरों और कस्वों में हुआ। काग्रेस कमेटिया गैर-कानूनी घोषित कर दी गईं। काग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा करके उनमें ताले टाल दिये गए। काग्रेस की कार्रवाइयों पर पावदियां लगा दी गईं। अखिल भारतीय महासमिति के जो सदस्य अपने घरों को दापस लौट रहे थे, उन्हें गाडियों में मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया गया। वम्बई में पुलिस ने काग्रेस-भवन, असिल भारतीय महासमिति के भव्य और विजाल पड़ाल तथा ग्वालिया तालाव के त्रीडा-मैदान पर कब्जा कर लिया। सभी प्रकार के जुलूस और सभाएँ निषद्ध घोषित कर दी गईं और शहर की नार्रा पुलिन, रिजर्वं

पुलिस और सैनिक दस्तो को एकत्र कर लिया गया। काग्रेस के स्वयसेवको और देशसेविकाओ ने निर्धारित समा पर अपना उत्सव मनाया, परन्तु पुलिस ने अश्रु-गैस छोडकर और लाठी-चार्ज करके उन्हें तितर-वितर करने की चेष्टा की। पडाल पर लहराते हुए राष्ट्रीय झडे को नीचे गिरा दिया गया और जो स्वयसेवक उसकी रक्षा के लिए आगे वढे उन पर मार-पीट की गई। काग्रेस कार्यसमिति, अखिल भार तीय महासमिति और वम्बई प्रात में वम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया अवैध घोषित कर दी गई। इसी प्रकार उत्तर-पित्नमी सीमा प्रान्त के अलावा शेप सभी प्रान्तो की प्रान्तीय काग्रेस कमेटिया गैर-कान्नी करार दे दी गई। शायद इतना ही काफी नही था। केन्द्रीय सरकार ने नयी दिल्ली से ८ अगस्त के अपने एक आदेश के अन्तर्गत अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की ओर से चलाए गए सार्वजनिक आन्दोलन अथवा इस आन्दोलन के विरुद्ध सरकार-द्वारा अपनाए गए उपायो से सम्बन्ध रखनेवाले किसी वास्तिवक समाचार का (जिनमे सदस्यो द्वारा दिये गए भाषणो अथवा वक्तव्यो के विवरण सम्मिलित हैं) किसी भी मुद्रक, प्रकाशक अथवा सपादक-द्वारा मुद्रण अथवा प्रकाशन विजत कर दिया।

सरकार ने काग्रस के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना खेद, क्षोभ और प्रस्ताव में निहित चुनौती का मुकावला करने का अपना दृढ निश्चय प्रकट करने में विलव नहीं होने दिया। वस्तुत देखा जाय तो सरकार ने अपनी तैयारिया उसी समय से शुरू कर दी थी, जब उसने देश के राजनीतिक-जीवन में उथल-पुथल के प्रारिभक चिह्न देखे थे, क्योंकि १४ जुलाई, १९४२ के वर्धा-प्रस्ताव के थोड़ी देर बाद ही उसने १७ जुलाई १९४२ को एक गश्ती चिट्ठी जारी की जो बाद में "पकल गश्ती चिट्ठी" के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहा हम उस चिट्ठी का सक्षेप में उल्लेख करना उचित समझते हैं।

पकल की गश्ती चिट्ठी

यह स्मरण रहे कि बम्बई में अखिल भारतीय महासमिति के अधिवेशन से कुछ ही समय पहले अखिल भारतीय काग्रेस महासमिति के कार्यालय की तलाशी लेकर गांधीजी-द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मसविदे की प्रतियो पर कब्जा करके सरकार ने उन्हें छाप दिया था। इसके अलावा उसने इस सम्बन्ध में, इलाहाबाद की वैठक में काग्रेस-कार्यसमिति के सदस्यों के भाषणों का अपूर्ण और अनियमित विवरण भी प्रकाशित किया था। इस सबध में भारत-सरकार के सेकेंटरी सर फेडरिक पकल की एक गोंपनीय और महत्वपूर्ण गश्ती चिट्ठी गांधीजी के हाथों में पड गई और उन्होंने इसके साथ भूमिका के रूप में अपनी एक टिप्पणी जोडकर

वम्बई मे उसे विस्तृत रूप से प्रचारित कर दिया। इस गक्ती न्विट्ठी का साराश इस प्रकार है ---

१--७ अगस्त को बम्बई में होनेवाले अखिल भारतीय महासमिति के अधिवेशन में अभी तीन सप्ताह और है। इस बीच मुख्य समस्या काग्रेस के प्रस्ताव में वर्णित ठोस सुझावो के विरुद्ध प्रचार और उस प्रस्ताव के अन्त में गांधीजी के शब्दों में 'खुले विद्रोह' की जो धमकी दी गई है उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करना है। हमें (१) उन लोगो को प्रोत्साहन देना है जिनके सहयोग पर हम यकीन कर सकते हैं, (२) जो लोग अभी तक दुविधा में पड़े हैं, उन्हें अपने साथ मिला ले, और (३) काग्रेसजनो में दृढ निश्चय की भावना को रोके। ऐसा करने मे हमारा एक उद्देश्य तो यह है कि काग्रेस पर दबाव डाला जाय कि वह अपना कदम पीछे हटा ले और दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हमें काग्रेस के खिलाफ कोई कार्र-वाई करनी ही पड़े तो हमें देश के अन्दर और वाहर से जनता का समर्थन प्राप्त हो सके। कृपया आप लोग सभी उपलब्ध साधनो द्वारा जोरदार प्रचार करे जिससे कि प्रभावशाली व्यक्ति और प्रमुख गैर-काग्रेसी सगठन काग्रेस के प्रस्ताव के अन्तर्गत वर्णित योजना का खुले रूप मे और तर्क के आधार पर विरोध करे। आजकल धुरीराष्ट्रो के रेडियो-स्टेशन से जो प्रचार हो रहा है, उसके मुख्य पात्र काग्रेस के नेता होते है। इससे साफ जाहिर है कि भारत के दुश्मन काग्रेस के प्रस्तावों में अपना हित-साधन समझते हैं। मित्रराष्ट्रो की विजय के अलावा भारत के पास अपने उद्देश्य-प्राप्ति का कोई और साधन ही नही है। गुलामो की दुनिया में आजाद भारत का होना असम्भव है।

२—काग्रेस प्रस्ताव एक दल का घोषणापत्र है। यह काग्रेस की आवाज है, भारत की नहीं। इसमें काग्रेस के अलावा सभी दलों और लोगों की अवहेलना की गई है। जहाँ तक युद्ध का प्रश्न है, मुसलमान, सिक्ख, साम्यवादी, रायवादी, सगठित मजदूर, किसान सभाएँ और विद्यार्थियों के प्रमुख सगठन काग्रेस के विरोधी हैं। लोग स्वेच्छा से सेना में भरती हो रहे हैं। इससे सावित हो जाता है कि युद्ध के प्रश्न पर काग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। किप्स-प्रस्तावों की जो गलत व्याख्या की गई है, उसे भी घ्यान में रखिए, क्योंकि उनके अनुसार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य अथवा आजादी देने का वादा किया गया है। इस बात पर भी जोर दीजिए कि काग्रेस जो स्वयं तो विशुद्ध रूप से एक स्वेच्छाचारी सस्था है और जिस पर वड़े-वडे उद्योगपितयों और मध्य वित्तवाले लोगों का कब्जा है—मजदूरों को सत्ता हस्तान्तरित करने का स्वाग रचती है। इस समय मजदूरों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और अस्थायी युद्ध-सरकार पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें इसी समय मताधिकार नहीं दिया जा सकता।

३—प्रस्ताव के अन्तर्गत जिस ठोस रूप में ये सुझाव पेश किए गये हैं, वे एक-दम अस्पष्ट और अव्यावहारिक हैं। काग्रेस के प्रस्तावों में ऐसी कोई भी वात नहीं पाई जाती जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुकूल हो। उसका उद्देश्य अस्थायी काग्रेसी सरकार के हाथों में सत्ता सौप देना है और उसके वाद यह सरकार खुद फैसला करेगी कि भविष्य के लिये कौन-सी व्यवस्था आवश्यक है। इस वात को ध्यान में रिखिए कि पहले तो ब्रिटिश राज के यहाँ से हट जाने को कहा गया है और उसके वाद अस्थायी सरकार बनाई जाने की। इस सक्तान्ति-काल में क्या होगा? अस्थायी सरकार किस तरह से और कौन बनाएगा और वह किस विधान के अन्तर्गत अपना काम करेगी? काग्रेस ने अन्य महत्त्वपूर्ण तत्वों की सहायता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और ये तत्व इस वात को कभी वरदान्त नहीं करेंगे कि अस्थायी रूप से भी काग्रेस को सत्ता सौप दी जाय।

४—इस प्रस्ताव में एक और उल्लेखनीय वात यह है कि यद्यपि इसमें आक्रमण का प्रतिरोध करने की वड़ी लम्बी-चौड़ी डीग हाकी गई है, फिर भी इसमें इसका जिक तक भी नहीं किया गया कि इस प्रतिरोध का स्वरूप क्या होगा और सारे प्रस्ताव में जान-वृझ कर हिंसा या अहिंसा का उल्लेख नहीं किया गया। प्रस्ताव में 'आक्रमण के निष्क्रिय प्रतिरोध' की निन्दा की गई है, लेकिन पिछले कई वर्षों से गाधीजी इसी बात का ही तो प्रचार करते रहे हैं। वर्धा में निराशानाद और पराजय की जो भावना पाई जाती थी और जो अधिकाश काग्रेसियों में अब भी पाई जाती है—उस पर १२ जुलाई के 'हरिजन' में श्री महादेव देसाई ने एक उल्लेखनीय लेख में काफी प्रकाश डाला है। इसका उल्लेख आपको अग्रेजी 'हरिजन' के २२६वे पृष्ठ पर "निराशा का खेल" नामक शीर्षक-पैरे में मिलेगा। पढ़े-लिखे लोगों के साथ वातचीत करते समय इस लेख का उल्लेख करना उपयोगी साबित होगा।

५—प्रस्ताव के अन्त में जो धमकी दी गई है वह अस्पष्ट है। वाद में गांधीजी और मौलाना आजाद ने उसका खुलासा करते हुए यह कहा है कि उसका मतलब व्यापक पैमाने पर एक सार्वजनिक आन्दोलन से है। अगर काग्रेस की वात न मानी गई तो वह सन्तोष करके नहीं बैठ रहेगी और दूसरों को अपना काम नहीं करने देगी, विल्क वह भारत को जापान और जर्मनी के हवाले कर देगी।

६—राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चे से हमे पूरा-पूरा लाभ उठाकर इन प्रस्तावो का विरोध करना चाहिए, जिनसे केवल युद्ध-प्रयत्न को ही नुकसान पहुँच सकता है। स्थानीय प्रचार-कार्य के लिए हम भाषणो, स्थानीय-पत्रो के नाम पत्रो, परचो, व्यग्यचित्रो, पोस्टरो और लोगो में जाकर बातचीत करने के साधनो से काम ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में केद्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनो को आवश्यक हिदायते दे दी जायेगी।

काग्रेस ने अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में वास्तव में अभी विस्तृत बातों का कोई फैसला नहीं किया था। गांधीजी ने केवल इतना कहा था कि अहिंसा और सत्य के आधार पर अबतक के व्यक्तिगत और सार्वजिनक आन्दोलनों में जिस कार्यक्रम को अपनाया गया है, उसकी सब बातें इस आन्दोलन में भी रहेगी। परन्तु सरकार इतनी उत्तेजनापूर्ण कार्रवाइया कर रही थी कि उनसे जनता को हिसा और तोड-फोड की उन सभी कार्रवाइयों के करने का प्रोत्साहन मिलता था, जिनकी उसे आशका थी और जिन्हें आधार बनाकर वह अपनी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध कर रही थी। तात्पर्य यह है कि सरकार ने जनता को अराजकता और अव्यवस्था फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे यकीन था कि वह अहिसात्मक सार्वजिनक सिवनय अवज्ञा आन्दोलन की अपेक्षा जनता की अराजकता को अने बल-प्रयोग से सुगमता से दबा लेगी।

कांग्रेस पर दोषारोपण

इसके बाद ही इस बारे में भारत-सरकार ने ८ अगस्त को अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से सपरिषद् गवर्नर-जनरल को मालूम रहा है कि काग्रेस ने अवैध और कुछ दिशाओं में हिंसक कार्यों के लिए खतरनाक तैयारियाँ की हैं, जिनका उद्देश्य और बातों के अलावा यह भी है कि यातायात और सार्वजनिक उपयोग के साधनों में विघ्न डाला जाय, हडतालों का सगठन किया जाय, सरकारी कर्मचारियों को राजभिक्त से विमुख किया जाय और रक्षा के उपायों में, जिनमें रगक्टों की भरती भी शामिल हैं, बाधा पहुँचायी जाय। वास्तव में तथ्य तो यह है कि काग्रेस कार्यसमिति ने आन्दोलन का कोई भी कार्यक्रम तैयार ही नहीं किया था। सरकार ने अपनी सूचना की अधिकार-सीमा के बाहर जाकर काग्रेस पर उस समय ऐसा दोपारोपण किया जिस समय देश में कोई भी ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण काग्रेसजन बाहर नहीं था जो सरकार के इन इलाजामों का प्रत्युत्तर देता।

आगे चलकर सरकार ने अपने इसी प्रस्ताव में काग्रेस की मांग का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि उस पर सोच-विचार ही नहीं किया जा सकता, क्यों कि इसकी स्वीकृति से भारत में अव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी और मानव-स्वतन्त्रता के सार्वजिनक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उद्यम वह कर रही है वह विल्कुल ही ठण्डा पड़ जायगा। सरकार का यह एक अनोखा तर्क था, क्यों कि मानव-स्वतन्त्रता के सार्वजिनक उद्देश्य में भारत की अपनी स्वतन्त्रता भी तो सम्मिलित थी। वास्तविकता यह थी कि सरकार ने कांग्रेस की स्थिति वडी डाँवाडोल बना रखी थी। काग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत छोडों नारे का अर्थ वह नहीं है जो सरकार ले रही है।

सरकार के उक्त प्रस्ताव के अलावा काग्रेस और उसके नेता गान्वीजी पर अर्द्ध-सरकारी हल्को की ओर से यह दोप भी लगाया गया कि काग्रेस ने हाल में अपनी पिछले बाईस वर्ष की नीति परिवर्तन करके यह कहना शुरू कर दिया है कि आजादी मिलने के बाद साम्प्रदायिक ऐक्य स्वय ही स्थापित हो जायगा, जबिक इससे पहले वह यह कहा करती थी कि स्वाधीनता की प्राप्ति से पहले साम्प्रदायिक ऐक्य अत्यावश्यक है। यह भी कहा गया कि लडाई के जमाने मे कोई वैधानिक परिवर्तन सम्भव नही हैं। परन्तु इन तर्कों मे हमें कोई जान नही दिखाई देती। इनसे केवल यही प्रकट होता है कि ब्रिटेन सत्ता हस्तान्तरित करने को तैयार नही थी। ऐसी स्थिति में काग्रेस ने जो कदम उठाया वह विल्कुल ठीक और उचित था। जिस दिन गान्धीजी और उनके साथी गिरफ्तार किए गये थे और सरकार ने अपना दमन-चक्र चलाया था---उसी दिन से देश के विभिन्न वर्ग उनकी रिहाई और फिर से समझौते की वातचीत शुरू करने की माँग करने लगे थे। यह माँग भारत के प्रमुख उद्योगपतियो या व्यापारियो की ओर से नही की जा रही थी, विल्क साम्य-वादियों की ओर से की जा रही थी—जो युद्ध-प्रयत्न में सित्रय भाग लेने के समर्थक थे। इसके अलावा यह माँग ट्रेड यूनियन काग्रेस, नरम दल, मिल-मालिको और लखपतियो, सिक्लो, भारतीय ईसाइयो, एग्लो-इण्डियन एसोसिएशन, स्यानीय वोर्डो, म्युनिसिपैलिटियो, धार्मिक सस्याओ, हिन्दू महासभा, विशेष प्रयोजन के लिए आयोजित सभाओ, प्रमुख व्यक्तियो तथा डा॰ सप्रू और श्री जयकर सरीखे निर्वल नेताओं की ओर से की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इन माँगी। सुझावो और अनुरोघो की कोई परवाह नही की और वह मदान्ध होकर दमन-चक चलाती रही।

द्मन-चक्र का प्रभाव

९ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने पहला हमला काग्रेस के स्वयसेवकों की रैली पर किया। उसने राष्ट्रीय झण्डे को नीचे गिरा दिया और लोगों को चेतावनी दी कि वे उस मैदान में एकत्र न हो। इस झण्डे का उद्घाटन उसी दिन प्रात पण्डित नेहरू द्वारा किया जाना था। पुलिस की चेतावनी के बाद-जूद श्रीमती आसफअली ने झण्डा फहराया और इन गिरफ्तारियों की घोषणा की। प्रान्त भर में और वम्बई नगर में सार्वजनिक सभाओं, जमघटों और जुलूसों पर प्रतिवन्य लगा दियें गयें और इनके लिए अधिकारियों से पहले से अनुमित प्राप्त कर लेना आवश्यक घोषित किया गया। शस्त्रास्त्रों को लेकर चलना निषद्ध कर दिया गया और एक पखवार के लिए कुछ इलाकों में लोगों को शाम के ७–३० वर्ज के बाद और सुबह ६–० वर्ज से पहले अपने घरों से बाहर निकलने की मनाही कर दी गई। पहले ही दिन पुलिस और सेना ने लोगों पर लाठी-चार्ज किया, उनपर अश्र-

खुला विद्रोह: १९४२

गैस छोडी और उन्हें गोलियों का शिकार बनाया। बम्बई-जैसे निषेघात्मक आदेश एक-साथ ही सभी प्रान्तों में लागू किये गये। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने यहाँ काग्रेस कार्यसमिति, अखिल भारतीय महासमिति तथा सभी प्रान्तीय, जिला, नगर, तहसील, वार्ड और मण्डल काग्रेस कमेटियों को अवैध घोषित कर दिया और १९३२ के सयुक्त प्रान्तीय विशेषाधिकार कानून को प्रान्त के सभी जिलों पर लागू कर दिया। इलाहाबाद में स्वराज्य-भवन पर कब्जा कर लिया गया। मध्यप्रान्त में नागपुर काग्रेस समाजवादी दल, नागपुर हिन्दुस्तान लाल सेना और हिन्दुस्तान लाल सेना को भी गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उडीसा की सरकार ने न केवल काग्रेस कमेटियों को ही गैर-कानूनी घोषित किया, बिल्क उनके दफ्तरों और अन्य सम्बद्ध सस्थाओं को भी, जिनकी सख्या ३८ थी, घोषित क्षेत्र करार दिया। यही हाल लाहौर, नयी दिल्ली और कराँची में भी हुआ। मद्रास में भी तीनो प्रान्तीय काग्रेस कमेटियाँ और उनकी सस्थाएँ गैर-कानूनी घोषित कर दी गईं। बंगाल, आसाम और पटना में भी इसी तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये गये और पटना का 'सदाकत-आश्रम' भी एक घोषित क्षेत्र करार दिया गया।

खुला विद्राह

इस प्रकार वास्तविकता यह थी कि काग्रेस पर एक-तरफा हमला कर दिया गया, नेता और उनके अनुयायी युद्ध की घोषणा होने से पहले ही युद्ध-बन्दी बना लिये गये। ऐसी स्थिति में आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि सैनिक इस युद्ध-कला के सिद्धान्तों पर उचित रूप से अमल करेगे। जनता ने समझा कि उन्हें ऐसा मौका जीवन में शायद फिर कभी न मिल सके, इसलिए वह काबू से वाहर हो गई। सभाओ, जुलूसो, प्रदर्शनो, मिलने-जुलने की स्वतन्त्रता और वाणी स्वातन्त्र्य पर लगाये गये प्रतिबन्धो की तनिक भी अवज्ञा करने पर जब अधिकारियो-द्वारा जनता पर न केवल लाठी-चार्ज द्वारा, बल्कि राइफलो, रिवाल्वरो, मशीनगनों की मार और बमवर्षा की गयी तब वह गुस्से से पागल हो उठी। नेताओं की गिरफ्तारी को मुश्किल से १२ घण्टे भी नही हुए थे कि सरकार ने इंट-पत्थरो और गोलियो की बौछार की वहीं पुरानी कहानी दुहरानी शुरू कर दी। इस तरह एक विषाक्त और दूषित चक्र चल पड़ा जिसे देखकर नागरिक न तो चुप ही बैठ सकते और न उसे रोक सकते थे। जनता की भीड चलती हुई रेलों पर पत्थर बरसाने लगी, गाड़ियों और कारों को रोकने लगी, रेलवे स्टेशनो को नकसान पहुँचाने लगी, उनमे अथवा उनकी सम्पत्ति को अग्नि की भेट करने लगी, अनाज की दूकाने लूटी जाने लगी, टेलीफोन के तार काटे जाने लगे, कारो के टायरो को खोल दिया गया और उन्हें बेकार कर दिया गया तथा विक्टोरिया, बैलगाड़ी तथा तॉगेवालों को परेशान किया जाने लगा। जनता की इन ज्यादितयों को आर्डिनेन्स-द्वारा निषिद्ध घोषित किये

जाने पर भी देशभर में हडताले हुईं, जिनमें स्कूल, कालेजो और विश्वविद्यालय के छात्रों ने विशेष रूप से भाग लिया। विद्यार्थियों ने पिकेटिंग करने में भी प्रमुख भाग लिया। शिक्षण संस्थाएँ और यूनिवर्सिटियाँ बहुत शीघ्र ही खाली हो गई और देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अर्थात् अलीगढ को छोडकर ढाका से दिल्ली तक और लाहौर से मद्रास तक सभी शिक्षा-सस्थाएँ वन्द हो गईं। बनारस विश्वविद्यालय पर सेना ने आन्दोलन के शुरू में ही कब्जा कर लिया था। इस आन्दोलन के शुरू में रेल की पटरियो और फिश-प्लेटो को उखाडने की घटनाएँ भी देखने में आई, जिनके कारण रेलवे-यातायात पगु वना दिया गया। उदाहरण के तीर पर कई दिन तक मद्रास मेल नहीं चल सकी और बाद में कुछ समय तक रात्रि के समय वह बन्द कर दी गई। वित्रगुन्ता से लेकर वेजवाडा तक का १३० मील का रेल-मार्ग बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया । विहार में लगभग दो सप्ताह तक मुगेर का वाहरी दुनिया के साथ सब प्रकार का सम्पर्क कटा रहा। जहाँ तक रेलों की अव्यवस्था का प्रश्न है, सबसे अधिक गडवड विहार में रही। अहमदाबाद में सभी मिलें वन्द रही, लेकिन वम्बई मे केवल तीन-चार मिलें ही वन्द रही। म्युनिसिपैलिटियो के असस्य विजली के वल्व, आग वुझाने के केन्द्र और म्युनिसिपैलिटियो के छकडे चकनाचूर कर दिये गये। बी० बी० एण्ड सी० आई० के दादर रेलवे स्टेशन के पास ९ अगस्त को एक कार को अग्नि की भेट कर दिया गया। ९ अगस्त को वी० वी० एण्ड सी० आई० और जी० आई० पी० रेलो की सभी गाडिया लगभग एक घण्टे तक पूरी तरह वन्द रही। सरकार ने इस गडवड का डट कर मुकावला किया । गडवड शुरू होने के दूसरे दिन १० अगस्त को बम्बई में पुलिस और सेना को सुबह १० वजे से लेकर शाम के ४ वजे तक लगभग १० बार भीड पर गोली चलानी पडी । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ९ अगस्त, रिववार के दिन बम्बई-नगर के उपद्रवों में ९ व्यक्ति मारे गए और १६९ घायल हुन जिनमे २७ पुलिस के सिपाही भी थे। ११ अगस्त मगलवार के दिन पुलिस ने मुंबह से लेकर दोपहर के २-३० वजे तक बम्बई में लगभग १३ वार गोली चलाई। इसी प्रकार १० अगस्त तक पुलिस ने पूना, अहमदाबाद, लखनऊ और कानपुर मे भी गोली चलाई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आर्डिनेन्स लागू किया जिसके अन्तर्गत यह ऐलान किया गया कि आग लगाने या किसी विस्फोटक द्वारा शरारत फैलाने पर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकेगा और उसे ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत दी जाने वाली साघारण सजा के अलावा कोडे लगाए जाने की भी सजा दी जा सकेगी । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी इमारत, मोटर-गाडी, मशीन इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, जो सरकारी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई हो अथवा की जाने वाली हो, अथवा किसी रेलवे स्टेशन, ट्राम, संडक, पुल, नहर इत्यादि को नुकसान पहुचाएगा अथवा बलात्कार करेगा,

किसी इमारत में चोरी करेगा या डाकेजनी करेगा तो उसे भी अपराधी घोषित कर दण्ड दिया जा सकेगा। मध्य-प्रान्त में स्थानीय संस्थाओं को काग्रेस के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए भंग कर दिया गया और इसी आधार पर दूसरे प्रान्तों में भी ऐसा किया गया। पुलिस ने पूना, नयी दिल्ली और नासिक में भी गोली चलाई। रेलवे स्टेशनों, इन्कमटेक्स के दफ्तरों, स्कूल और कालेज की इमारतों, डाकखानों और रेल के मालगोदामों में आमतौर पर आग लगाई गई। बिहार में एक भीड ने सेकेटेरियट पर हमला करने की कोशिश की। इस पर गोरखा सैनिकों ने गोली चलाई, जिससे पाच आदमी मारे गए और १९ घायल हुए। सरकार की अराजकता के विरोध स्वरूप बिहार और बम्बई के एडवोकेट जनरलों तथा बम्बई के सरकारी वकील ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।

बम्बई-शहर में यतायात'रोक दिया गया। यहां तक कि प्राइवेट कारों को भी तब तक नहीं गुजरने दिया गया जब तक कि उसमें बैठी हुई सवारियों में कम-से-कम किसी एक ने गांधी टोपी न पहनी हो। ट्राम-पटरियों को बारीक पत्थरों से पाट दिया गया, जिन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता था। सडकों के जकशनों पर लटकी हुई जजीरों को खोल कर उनके साथ ट्रामों को बॉध दिया गया और उनके मार्ग में कहीं से लाकर बड़े-बड़ें दरवाजे गांड दिये गए, जिनके कारण ट्रामों का वलना और भी कठिन हो गया। यह भी पता चला कि रेल की पटरियों पर तेल आदि लगा कर उन्हें पूरी तरह से चिकना कर दिया गया।

सी० पी० रामस्वामी का इस्तीका

अभी इन घटनाओं को हुए तीन सप्ताह भी पूरे नही हुए थे कि भारत में और भी घटनाए हुईं, जिनपर हम विचार करना आवश्यक समझते हैं। इस सम्बन्ध में सब से अधिक उल्लेखनीय घटना वाइसराय की शासन-परिषद् से सर सी॰ पी॰ रामस्वामी अय्यर का इस्तीफा था। उन्होंने ५ सितम्बर को अपना पद सभाला था। शासन-परिपद् की बैठक में जब वह पहली बार ही शामिल हुए तब उन्हें गांधीजी और कार्यसमिति की गिरफ्तारी से सम्बन्ध रखने वाली इस नीति पर सोच-विचार करना पड़ा कि क्या इन लोगों को अखिल भारतीय महासमिति की बैठक से पहले गिरफ्तार कर लिया जाय अथवा बाद में ? उस समय परिषद् के सम्मुख एकमात्र विचारणीय विपय यही था। सरकार ने आन्दोलन को कुचल देने के सम्बन्ध में पहले से ही कानून और आर्डिनेन्स तैयार कर लिए थे। सर सी॰ पी॰ ने स्वेच्छा से सूचना विभाग को चुना था और अपना पद सभालने से पहले उन्होंने अपने कर्तव्यो पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की थी कि मैं गांधीजी से मिल कर समझौता करने की चेष्टा करूँगा। लेकिन यह सब निष्फल रहा। गृह-विभाग ने सर सी॰ पी॰ के विचारों को पहले ही

भाँप लिया था और उसने उनके पद सँभालने से पहले ही सूचना-विभाग के कार्य-क्षेत्र को सकुचित और सीमित बनाकर अपने फैसले कर लिए थे। इसलिए सर सी॰ पी॰ आते ही दुविधा में पड गए। परन्तु शिष्टाचार का तकाजा था कि वह जल्दवाजी से काम न ले। फलत १५ दिन के वाद यह वहाना वनाया गया कि रियासतों के हितों को देखते हुए उनका सरकारी पद पर वने रहना उचित और लाभकारी प्रतीत नहीं होता। हिमालय की चोटी पर वैठने की वजाय उनकी आवश्यकता कुमारी अन्तरीप में अधिक है। इसलिए उन्होंने ट्रावन्कोर वापस चले जाने का फैसला किया, परन्तु इसके लिए कोई वजह भी तो चाहिए थी। इसलिए इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी ओर से जो वक्तव्य दिया और सरकार ने अपनी ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की, उन दोनों में ही वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश की गई।

महादेव देसाई की मृत्यु

जहा एक तरफ सरकार की मनमानी और हिसात्मक कार्रवाइयों के कारण समाज के परेशान करने वाले तत्व प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो कर उसका मुकावला कर रहे थे और सार्वजिनक सुरक्षा-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, वहा दूसरी तरफ आगा खाँ महल में नजरवन्द गांधीजी तथा उनके सहयोगियों और कार्यसमिति के सदस्यों के, जिन्हें किसी अज्ञात स्थान में नजरवन्द रखा गया था, स्वास्थ्य के वारे में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही थीं। इसके अलावा जनता को इस वात से भी गहरी चिन्ता हो रही थीं कि क्या गांधीजी अनशन करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ऐसा करने की घोषणा की थी। और अगर कही उन्होंने अनशन किया तो उसका क्या परिणाम होगा? इस प्रकार जब कि देश भर में इस सवध में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही थीं, श्री महादेव देसाई के अचानक निधन का समाचार प्राप्त हुआ। इन गिरफ्तारियों को हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि देश पर ऐसा गहरा वज्रपात हुआ।

श्रमरीका में प्रतिक्रिया

यदि अगस्त १९४२ का आन्दोलन और गांघीजी तथा कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी लडाई के शुरू में हुई होती तो निस्सदेह अमरीका में उसकी प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया से सर्वथा विभिन्न होती जो वास्तव में हुई। कारण यह है कि ज्यो-ज्यो लडाई ने जोर पकडा, अमरीका ने ब्रिटेन के साथ अपने आर्थिक सम्बन्ध फिर से स्थापित किए। लेकिन वह अभी तक पहली लडाई के अनुभव को नहीं भूला था। उसे मालूम था कि उस वक्त ब्रिटेन के और उसके आर्थिक सम्बन्ध कैसे थे और ब्रिटेन उसे उसका कर्ज अदा नहीं कर सका था। इसलिए इस बार उसने ब्रिटेन को

बडी कडी शर्तों पर माल देना मजूर किया। पहले तो वह उसे "नकद चुकाओ और माल उठाओं" के सिद्धात पर माल देता रहा । लेकिन बाद में जब ब्रिटेन की अमरीका में लगाई हुई सिक्योरिटिया भी खत्म हो गई तब उसने उधार-पट्टे की एक नयी प्रणाली निकाली। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप ब्रिटेन और अमरीका में घनिष्ठ व्यापारिक और आर्थिक सपर्क स्थापित हो गया और पर्लहार्बर पर जापानी आऋमण होने (७ सितम्बर, १९४१) तक उन दोनों की यह घनिष्ठता निरन्तर बढती ही गई। परन्तु इस घटना के बाद से इन दोनों राष्ट्रों में न केवल खरीद और विकी और उधार-पट्टे की व्यवस्था ही चलती रही, बल्कि उनके उद्देश्यो, आदर्शो, हितो और कार्यक्रम में भी एकता और तारतम्य स्थापित हो गया। तात्पर्य यह कि १९३९-४० से १९४१ तक अमरीका कुछ हद तक ब्रिटेन पर अपना प्रभाव डालता रहा। यह प्रभाव ऐसा ही था जैसा कि एक दुकानदार का अपने गाह्क, अथवा साहूकार का अपने कर्जदार या जमीदार का किसान पर होता है। लेकिन जब अमरीका लडाई के अखाडे में कूद पडा तब उसकी भी गिनती बहुत से युद्धलिप्त राष्ट्रों में होने लगी। और लडाई से उसका भी उतना ही सम्बन्ध हो गया जितना ब्रिटेन का, क्योंकि जापान ने फिलिपाइंस पर अपना कब्जा कर लिया था और वह प्रशात मे विशेषकर न्यूब्रिटेन और न्यूगिनी तथा आस्ट्रेलिया के आस-पास के टापुओ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर अमरीका पर आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा था। इसलिए ऐसी हालत में यह सवाल ही नही उठ सकता था कि अमरीका भारत की वैधानिक प्रगति अथवा उसकी स्वतत्रता के बारे में ब्रिटेन पर प्रभाव डालेगा, यद्यपि ब्रिटेन के विवेकशील व्यक्ति और भारत-स्थित अमरीका के पत्रकार यह आशा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, काग्रेस अपने इरादो और निर्णयो के बारे में अमरीका और चीन दोनों को ही सूचित कर देना अपना परम कर्तव्य समझती थी। यही वजह है कि बम्बई में अखिल भारतीय महासमिति की बैठक में गांधीजी, काग्रेस के प्रधान और पडित जवाहरलाल ने इन राष्ट्रो के अध्यक्षो को इस सम्बन्ध मे पत्र लिखने की बात पर इतना जोर दिया था।

जहा तक सवाल ब्रिटिश सरकार का है वह अच्छी तरह जानती थी कि भारतीय समस्या का केन्द्र जहा एक ओर लन्दन के बजाय दिल्ली बनता जा रहा था, वहा दूसरी तरफ न्यूयार्क भी बन रहा था। इसी वजह से उसने अमरीका में आई० सी० एस० के एक योग्य व्यक्ति श्री बाजपेयी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना आवश्यक समझा। इस प्रकार लार्ड हेलीफेक्स अमरीका में ब्रिटेन के राजदूत और सर गिरजाशंकर बाजपेयी भारत-सरकार के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए। लार्ड हेलीफेक्स ने अमरीकी जनता के सामने काग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की और ब्रिटेन तथा उसके एजेण्ट किप्स के पक्ष का समर्थन किया। प्रत्यक्ष है कि ब्रिटेन इसी नीति पर आचरण करना चाहता था। परन्तु काग्रेस को अपना सदेश अमरीकन जनता तक पहुचाने के लिए ब्रिटेन की उदारता, अमरीका की रियासतों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और भारत-स्थित अमरीकी सवाद-दाताओं की सद्भावना पर निर्भर रहना पडता था। पता चला है कि जब अमरीकी सवाददाता भी वम्बई-प्रस्ताव के सम्वन्ध में अपने सदेश और समाचार अमरीका न भेज सके तब उनमें से एक सवाददाता वायुयान-द्वारा चीन पहुचा और वहा से उसने अपना सदेश अमरीका भेजा।

जिस प्रकार ब्रिटिश और भारत सरकार ने अपने-अपने प्रतिनिधि अमरीका भेजे—उसी प्रकार समय-समय पर उसके प्रतिनिधि भी भारत अति रहे। वम्बई-प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही प्रधान रूजवेल्ट के एक और प्रतिनिधि श्री लीचिलन क्यूरी नयी दिल्ली में पधारे (९ अगस्त, १९४२) और पता चला कि उन्होने वाइसराय के साथ वड़ी देर तक वातचीत भी की। उनके वाद श्री विलियम फिलिप्स आए। १९४२ की गर्मियों के प्रारम्भ में भारत-स्थित अमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों में एक उल्लेखनीय व्यक्ति लुई फिशर भी थे, जो भारत में यद्यपि काफी देर तक रहे, फिर भी उन्होने यहा रहते हुए अपने विचारों के सम्बन्ध में कोई वात प्रकट नहीं होने दी,। लेकिन अमरीका पहुच कर उन्होंने भारत के पक्ष में जोरदार आन्दोलन किया और भारत की समस्या को तर्क संगत और निष्पक्ष भाव से अमरीको जनता के समक्ष उपस्थित किया। जुलाई १९४२ में जब वह भारत से अमरीका के लिए रवाना हुए तब अपने साथ प्रधान रूजवेल्ट के लिए गांधीजी का एक सदेश भी लेते गए और उसे अमरीका के राप्ट्रपित के पास पहुचा दिया। इसमें गांधीजी ने प्रधान रूजवेल्ट से प्रार्थना की थी कि भारत की स्वतत्रता की माग के सम्बन्ध में जो गतिरोध पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिए आपको मध्यस्थ बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश वह १३ अप्रैल, १९४५ को अपनी इहलीला समाप्त कर परलोक सिधार गए।

इसके वाद से नौ महीने से भी अधिक समय तक एक तरफ ब्रिटिश सरकार और भारत-सरकार और दूसरी ओर प्रमुख पत्रकारों और प्रचारकों में भारतीय समस्या के बारे में अमरीकी जनमत को शिथिल करने और अमरीका के प्रधान को प्रभावित करने की जोरदार होड लगी रही। भारत से इगलैण्ड वापस जाने के कुछ समय बाद ही सर स्टैफर्ड किप्स ने 'न्यूयार्क टाइम्स' में एक लेख लिखा और इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध अमरीकी सवाददाता श्री एडगर स्नो ने भी भारत के पक्ष में बहुत से लेख लिखे। दिसम्वर १९४२ के प्रारम्भ में श्री लुई फिशर ने भारत के बारे में स्वय अमरीका में जो भाषण दिये उनके कारण उस देश में ब्रिटेन के एजेण्टो और उसके राजदूत ने जो भ्रमजाल फैलाया था उसका सारा रहस्य खुल गया और जनता के सामने भारत की वास्तिवक स्थित उपस्थित हो गयी। अमरीका की प्रसिद्ध पित्रका 'एटलाटिक मैंगजीन' ने लिखा—"भारतीय समस्या

को हल करने का एक रचनात्मक तरीका यह है कि मित्रराष्ट्र सयुक्त रूप से यह घोषणा कर दे कि यदि लडाई में उनकी जीत हुई तो उनका उद्देश्य क्या होगा। भारत की समस्या साघारण समझौते का ही एक अग होना चाहिए।"

सिर्फ अमरीका मे ही ऐसे विचार नहीं प्रकट किये गए बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाघीनता-प्राप्त उपनिवेश कैनेडा के एक प्रमुख राजनीतिक दल 'कोआपरेटिव कामनवेल्थ फेडरेशन' ने भी अपने यहा के प्रधान मत्री श्री मेकेजी किंग से आग्रह किया कि वह मित्रराष्ट्रों के द्वारा "इस समय और युद्ध के बाद भारत में स्वायत सरकार की स्थापना" के लिए फिर से समझौते की बातचीत शुरू करने पर जोर दे। इस प्रकार बम्बई-प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी को अभी मुश्किल से दो ही महीने हुए होगे कि अक्टूबर, १९४२ में अमरीका में भारत के पक्ष में एक जोर-दार लहर दौड गई। नोबेल-पारितोषिक-विजेता श्रीमती पर्ल वक और प्रसिद्ध चीनी लेखक लिन युताग ने भी भारत के पक्ष में अपनी जोरदार लेखनी उठाई। इनके अलावा जगह-जगह पर श्री वेडेल विल्की ने ब्रिटेन और अमरीका दोनो की ही टीका-टिप्पणी की। इन आलोचनाओं का सम्य ससार पर बहुत अधिक असर पडा। इन्ही दिनो न्यूयार्क मे 'फ्री वर्ल्ड एसोसियेशन' के तत्वावघान मे 'फ्री वर्ल्ड काग्रेस' का एक अधिवेशन हुआ। एसोसियेशन की ओर से एक भोज दिया गया । इस अवसर पर अमरीका के उप-प्रधान श्री वालेस ने एक अत्यन्त विवेकयुक्त और दूरदिशतापूर्ण भाषण दिया, जिसका मुख्य विषय, "जन क्राति" अथवा "साधारण व्यक्ति का देश" था। कहा जाता है कि इस भाषण के परिणामस्वरूप अमरीका और विदेशों मे न केवल सयुक्त राष्ट्रो के उद्देश्यो के प्रति विलक साधारण मानव के अधिकारों के प्रति भी गहरी दिलचस्पी और जाग्रति पैदा हो

अमरीका की विभिन्न रियासतों के भूतपूर्व गवर्नरों, राष्ट्रपति-पद के उम्मीद-वारों और उस महान् प्रजातत्र के उप-प्रधानों ने ही भारत और प्रजान्त के देशों के पक्ष का समर्थन नहीं किया, विल्क अमरीका के मजदूरों ने भी उन्हें सामयिक सहायता प्रदान की। अमरीका के शिक्तजाली मजदूर संगठन—औद्योगिक संघ काग्रेस ने वोस्टन में अपने वार्षिक सम्मेलन में एकमत से भारत की आजादी की माग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। वोस्टन, शिकागों, न्यूयार्क, वाशिगटन, मेक्सिकों और कैनेडा सभी जगह भारतीय प्रवन की चर्चा हुई। फिलि-पाइस राष्ट्र-मण्डल में नवम्बर, १९४२ में वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रधान हज-वेल्ट ने पहली वार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा की जिससे अटलाटिक अधिकार-पत्र की कुछ अस्पष्ट घाराओं के सम्बन्ध में अमरीका के इरादों पर प्रकाश पडा।

इस प्रकार इन बड़े-बड़े प्रय्नो को अपने गर्भ में लिए १९४२ समाप्त हुआ और

१९४३ का श्रीगणेश हुआ । नये वर्ष के प्रारभ मे २६ जनवरी को अमरीका के कई शहरो मे भारतीय-स्वाधीनता-दिवस मनाया गया। इस साल न्यूयाकं और वाशि-गटन दोनों ही शहरो में इस अवसर पर प्रदर्शन किये गये। इस अवसर पर कुछ बडे-बडे प्रोफसरो ने भारतीय समस्या के बारे में अपने स्वतन्त्र और निर्भीक विचार जनता के सामने रखे। प्रोफेसर फेडरिक समन ने 'दि टाइम' नामक पत्रिका में "भारत को बचाने के लिए" शीर्षक से एक लेख में लिखा-"भारत इस वात की कसौटी हे कि क्या हममे जीवित रहने की सामर्थ्य है।" हारवर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और हारवर्ड-रक्षा-दल के प्रवान श्री राल्फ वार्टन पेरी ने अमरीका के स्थायी असिस्टेण्ट सेकेंटरी श्री सुमनर वेल्स को एक पत्र लिखा जिसमे उन्होने भारतीय गतिरोव को दूर करने में अमरीका की असफलता और हस्तक्षेप न करने की नीति की आलोचना की। प्रिस्टन यूनिवसिटी के प्रोफेसर वाल्टर फेल्पो हाल ने 'करेण्ट हिस्ट्री' पत्रिका में अपने एक लेख मे इस बात पर जोर दिया कि भारत में जो-कुछ हो रहा है उससे केवल अकेले ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि सभी सयुक्त राष्ट्रों का घनिष्ट सपर्क है। उन्होंने लिखा कि "उनके नाम पर एक तरफ ब्रिटेन को अपना वाइसराय भारत से बुला लेना चाहिए, काग्रेस-दल के साथ फिर से समझौता करना चाहिए और अमरीका तथा चीन के एक पचायती वोर्ड की सहायता से इस समस्या का हल ढूँढना चाहिए और दूसरी तरफ भारत से कहना चाहिए कि वह अपने असहयोग-आन्दोलन को वन्द कर दे, युद्धकाल तक के लिए उपर्युक्त पंचायती-वोर्ड का फैसला मान ले और सैनिक और गैर-सैनिक सभी तरीको से जापानियो को वर्मा और चीन से मार भगाने मे कोई कसर न उठा रखे।" आगे आपने कहा कि "भारतीय लोग प्रतिदिन अधिकाधिक विटिश-विरोधी बनते जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलव यह नही कि वे जापानियो के हामी या पक्षपाती भी वनते जा रहे हैं। उन्हें ब्रिटेन की सद्भावना में जो थोडा-बहुत विश्वास था, उसे भी वे अब खोते जा रहे हैं। भारत की इस उदासीनता और वेरुखी से युद्ध-प्रयत्न मे वाघा पहुँचती है।"

भारत में रूजवेल्ट के निजी दूत श्री फिलिप्स ने मुस्लिम लीग के मन्त्री और वाद में उसके अध्यक्ष, हिन्दू महासभा के कुछ व्यक्तियों, कुछ वडे-चडे सार्वजिनक व्यक्तियों, कुछ निर्दलीय नेताओं तथा सिखों, हरिजनों और भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वह निस्सदेह एक कूटनीतिज्ञ थे। भारतीय समस्या के बारे में वह अपने विचारों को सकतमात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे। केवल एक ही बार उन्होंने अपने इस नियन्त्रण को कुछ ढीला किया। गांधीजी के उपवास के शुरू में ही (१० फरवरी, १९४३ को) उन्होंने अपना निर्धारित दौरा स्थिगत कर दिया और इसी उपवास के दौरान में जो ३ मार्च को समाप्त हुआ, श्री फिलिप्स ने इसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली स्थित के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर कहा कि

"भारतीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर अमरीका और ब्रिटेन के बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी सोच-विचार कर रहे हैं।"

प्रशान्त-सम्मेलन में प्रतिक्रिया

इस प्रकार ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, भारत के सम्बन्ध में अमरीका की दिलचस्पी घटने के बजाय बढ़ती ही गई और १९४२ में भारत के सम्बन्ध में अमरीका में 'अमेरिकन राउण्ड टेबल' नाम से एक नये राष्ट्रीय सगठन की स्थापना हुई। इस सगठन ने २९ अक्टूबर, १९४३ को प्रधान रूजवेल्ट से आग्रह किया कि वह भारत और ब्रिटेन में समझौता कराने की कोशिश करें।

चीन में प्रतिक्रिया

दूसरे महायुद्ध का एक प्रत्यक्ष और तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि भारत और चीन एक-दूसरे के बहुत निकट-सपर्क में आ गए। सितम्बर, १९३८ में पड़ित जवाहरलाल नेहरू की चुगिकग-यात्रा और १९४२ में मार्शल और श्रीमती चागकाई शेक की भारत-यात्रा के फलस्वरूप विश्व के दो बड़े-बड़े एशियाई राष्ट्रों की सस्कृति और अकाक्षाओं को एकता के सूत्र में नये सिरे से बाधने में बड़ी सहायता मिली। चीनियों ने भारत की माग का समर्थन किया। गांधीजी की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद १२ अगस्त को चुगिकग के एक सन्देश में कहा गया—"गांधीजी की गिरफ्तारी, उपद्रवों और रक्तपात का समाचार जानकर यहां बहुत शोक हुआ है। मौजूदा लडाई के पीछे तो यह भावना काम कर रही है कि आजांदी के लिए लडी जानेवाली लडाई पर किये गए आक्रमण का डट कर प्रतिरोध किया जाए। इसके बिना मौजूदा लडाई एक बेमानी चीज है। भारत की आजांदी की लडाई सयुक्त-राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों के सर्वथा अनुरूप है और इसलिए कोई वजह नहीं कि हम भारत के प्रति सहानुभूति क्यों न प्रकट करे।"

द्तिण अफ्रीका में प्रतिक्रिया

दक्षिण अफीका में गांधीजी ने सत्य और अहिसा सबधी अपने प्रारम्भिक परीक्षण किय थे, और बाद में उन्होंने इन्हीं परीक्षणों को राष्ट्रीयता और विश्व-जातीयता की बडी-बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए भारत में एक विशाल पैमाने पर कार्यान्वित किया था। जनरल स्मट्स उनसे परिचित थे। लन्दन के एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "गांधीजी को 'पचमागी' कहना महज एक बेवकूफी है। वह एक महान् व्यक्ति हैं। वह ससार के एक महापुरुष हैं और उन्हें इस तरह की श्रेणी में किसी सूरत में भी नहीं रखा जा सकता। वह आध्यात्मिकता के आदर्शों में रगे हुए हैं।

यह सन्देहास्पद हो सकता है कि क्या हमारी इस कठिन दुनिया में उन आदर्शों पर हमेशा अमल किया जा सकता है, लेकिन इसमें तो किसी को कोई सन्देह हो ही नहीं सकता कि गाधीजी एक महान् देशभक्त, महापुरुप और एक महान् आध्या-रिमक नेता है।"

विदेन में प्रतिकिया

भारत-मन्त्री श्री एमरी ने लन्दन में तुरन्त ही दो ब्राडकास्ट-भाषण दिये। एक भाषण उन्होंने ९ अगस्त, १९४२ को ब्रिटेन के लोगों के नाम और दूसरा १० अगस्त को अमरीका के लोगों के नाम ब्राडकास्ट किया। अपने पहले ब्राडकास्ट में श्री एमरी ने सर स्टैफर्ड किप्स के मिशन का हवाला देते हुए कहा कि भारत के उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रवन्य और युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की वातचीत मुख्यत काग्रेस-नेताओं के दुराग्रह अथवा "सव कुछ दीजिए या कुछ भी नहीं" वाले रख के कारण असफल हो गई। आगे आपने कहा कि ब्रिटेन के प्रस्तावों को ठुकरा देने का परिणाम यह हुआ है कि उससे भारतीय लोकमत अत्यधिक निराश हुआ है और काग्रेस के नेतृत्व में उसका विश्वास बुरी तरह से उठ गया है।

भारत की घटनाओं के बारे में ब्रिटेन की जनता और विभिन्न हलको की प्रतिक्रियाए भिन्न-भिन्न थी। वहा के न केवल सरकारी और गैर-सरकारी हलको की प्रतिक्रियाए ही एक-दूसरे के विपरीत थी, विल्क समाचार-पत्रो मे भी मतैक्य न था। इस युग के प्रारभिक-काल में लन्दन के सुप्रसिद्ध पत्र 'टाइम्स' का रुख विल्कुल असाधारण रहा। उसने अपनी परपरा को तिलाजिल देकर सत्य की खोज और इस मामले के पक्ष-विपक्ष के सम्बन्ध में निष्पक्ष जाच-पडताल करने पर जोर दिया । 'माचेस्टर गार्जियन' की भाति उसने भी तत्कालीन सरकार की सर्वतोमुखी दमन-नीति का समर्थन न कर युगो से चली आने वाली दमन और समझौते की दुहरी नीति का प्रतिपादन किया। उसने लिखा कि "किसी रचनात्मक नीति के बिना दमन-नीति युद्ध और शान्ति दोनो ही मे असफल और बेकार सावित होगी। इतना ही नही, वह उससे कही अधिक खतरनाक भी साबित हो सकती है। 'माचेस्टर गार्जियन' ने ब्रिटेन, गैर-काग्रेसी भारतीयो और मित्रराष्ट्रो से भी अनुरोध किया कि आप हमे इस झगडे को निबटाने में मदद दें जिसकी वजह से हम सभी को नुकसान पहुच रहा है। ब्रेल्सफोर्ड-जैसे सुप्रसिद्ध लेखक ने 'रेनाल्ड्स न्यूज' और श्री लियोनल फील्डन ने 'आब्जर्वर' मे लिखे गए अपने लेखो मे यह सुझाव रखा कि "गाधीजी को विडसर अथवा चेकर्स मे अतिथि के रूप मे आमित्रत कर सरकार को उनसे समझौता कर लेना चाहिए।" इनके अलावा कलकत्ता के बिशप और भारत के लाट-पादरी डा० फौस वेस्टकॉट ने भी ब्रिटिश सरकार से काग्रेस के साथ समझौता कर लेने का जोरदार आग्रह किया। लाट-पादरी ने इस

वात पर ज़ोर दिया कि काग्रेस के नेताओं के अन्तिम वक्तव्यों में अव भी समझौता करने की 'दृढ भावना' पाई जाती है। आपने आगे कहा कि "दमन-नीति के परिणामस्वरूप सरकार को समझौते की कोशिशों को नहीं छोड़ देना चाहिए। स्वयं काग्रेस के भीतर ऐसे शक्तिशाली तत्व मौजूद हैं जो युद्ध-प्रयत्न में सिक्रय रूप से भाग लेने और मित्रराष्ट्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करने के पक्ष ही हैं। इस वक्त सभी को समान रूप से युद्ध-प्रयत्न के लिए संगठित करने का एक में तरीका है कि देश के राजनीतिक दलों के वास्तिवक नेताओं को एक ऐसी शासन-परिषद् स्थापित करने के लिए कहा जाय जिसे वास्तिवक अधिकार प्राप्त हो।" १२ अगस्त, १९४२ को ब्रिटेन के मजदूर-दल ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उसने कहा—बरसों लेबर-पार्टी का यह सुनिश्चित मत और दृढ धारणा है कि भारतीयों को स्वभाग्य-निर्णय का पूर्ण अधिकार है। अब ब्रिटिश सरकार और पार्लामेण्ट ने भी स्पष्ट रूप से भारतीयों के इस अधिकार को मान लिया है। मजदूर दल को यकीन है कि युद्धोत्तर-कालीन ससार में स्वतत्र भारत की स्थापना निश्चित है और इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार-द्वारा किसी प्रकार के विलम्ब या टालमटोल की नीति की सम्भावना नहीं है।

एबरडीन में ७ सितम्बर को श्री एटली ने अपने एक भाषण में कहा कि भारतीय समस्या के समाधान में हमने वहुत-सी गलतिया की हैं, लेकिन हमने एक शताब्दी से भी अधिक समय तक भारत में आन्तरिक शाति और अच्छे शासन-प्रबन्ध को बनाए रखा है और पिछले पचीस साल में भारत ने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी प्रगति की है। इस दिशा में और प्रगति इसलिए नहीं हो सकी कि एक तो भारतीयों में आपस में कोई समझौता नहीं हो पाया और दूसरे ३० करोड़ की आबादीवाले देश में प्रजातत्र की स्थापना में काफी कठिनाइया है।

सितम्बर में जब पार्लमेण्ट का अधिवेशन हुआ तब श्री चिंकल ने भारत के बारे में एक वक्तव्य दिया जो उनके पिछले सभी वक्तव्यों से बाजी ले गया। उन्हें भारत, काग्रेस अथवा गांधीजी से कोई विशेष प्रेम नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश गांधीवाद को धराशायी कर पैरो-तले कुचल देना था। १० सितम्बर १९४२ को उन्होंने कहा—"काग्रेस पार्टी के सिवा और जिन लोगों का उससे बुनियादी मतभेद है वे ब्रिटिश-भारत के ९ करोड मुसलमान हैं (इस अवसर पर एक सदस्य ने कहा, 'यह एक वेहूदा बात हैं' और इस पर 'शान्ति, शान्ति' की आवाजे सुनाई दी) जिन्हें आत्मिनणिय का पूरा-पूरा हक है। इसके अलावा दिलतवर्ग अथवा ५ करोड़ 'अछूत'—जिन्हें अछूत इसलिए समझा जाता है कि उनके स्पर्शमात्र से उनके धर्म-बन्धु हिन्दुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और देशी नरेशों की ९॥ करोड़ जनता, जिनके साथ हमने सिधया कर रखी हैं, काग्रेस की विरोधी हैं और उनका उससे किसी किस्म का कोई सबंध नहीं हैं। इस प्रकार

भारत की कुल ३९ करोड की आवादी में से केवल इन तीन वर्गों की २३ करोड ५० लाख जनता ही उसके विरुद्ध है। इसके अलावा इसमें ब्रिटिश भारत के हिन्दुओ, सिक्खों और ईसाइयों के बहुत-से वे वर्ग शामिल नहीं हैं, जिनका काग्रेस की वर्तमान नीति से विरोध है। यह जरूरी है कि हमें ब्रिटेन में और दूसरे देशों में इन मुख्य तथ्यों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आधार-भूत तथ्य के विना भारतीय समस्या अथवा ब्रिटेन और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करना सभव नहीं है। अब काग्रेस बहुत-सी बातों में गांधीजी की अहिंसा को तिलाजिल देकर खुले रूप में एक क्रान्तिकारी आन्दोलन की शक्ल में प्रकट हुई है। उसके इस आन्दोलन का उद्देश यातायात के साधनो—रेल और तार आदि को पगु बना देना और साधारणत अव्यवस्था फैलाना, दुकाने लूटना तथा पुलिस पर हमले और कूरता पूर्ण अत्याचार करना है। इस सारे कार्यक्रम का मकसद अथवा उसका परिणाम भारत पर जापान के आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षाच्यवस्था के मार्ग में अडचन पैदा करना है।

"अत गाधीजी और दूसरे बड़े-बड़े नेताओं को नजरवन्द कर लिया गया है और उन्हें हर किस्म की सहूलियतें और आराम पहुँचाने की कोशिश की गई है। जब तक यह सकट दूर नहीं हो जाता उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। वास्तव में यह बड़े सौभाग्य की बात है कि लड़ाकू जातियों के ऊपर काग्रस का कोई प्रभाव नहीं है, क्यों कि ब्रिटिश फौजों के अलावा हिन्दुस्तान के बचाव की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं जातियों पर हैं। इनमें से बहुत-सी जातियों का हिन्दू-काग्रेस से गहरा मतभेद है और वे यह कभी भी गवारा नहीं करेगी कि काग्रेस उन पर हुकूमत करें अथवा उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ इस तरह से गुलाम बनाया जाय।"

आगे श्री चिंचल ने कहा—"भारत में अनिवार्य सैनिक सेवा अयवा भर्ती नहीं है, लेकिन फिर भी दस लाख से भी ज्यादा भारतीय इस विश्व-युद्ध में सयुक्त-राष्ट्रों की मदद के लिए स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। भारतीय सैनिकों ने लड़ाई के विभिन्न अखाड़ों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं और यह वड़े सतोष की बात है कि इन पिछले दो महीनों में, जब कि काग्रेस भारत-सरकार के खिलाफ अपनी शक्ति का सगठन करती रही है, १,४०,००० से भी अधिक नये रगस्ट स्वेच्छा से सेना में भरती हुए हैं और उन्होंने सम्राट् के प्रति वफादारी की शप्य ली है। इस तरह अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने पिछले सब रेकार्ड तोड़ दिये हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे तो यही साबित होता है कि काग्रेस भारतीय सेना को उसके कर्तव्य-पथ से विमुख करने में असफल रही है। वह उसे अपने मायाजाल से प्रभावित नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, भारतीय सरकारी अफसरों अथवा स्वय भारतीय जनता को प्रभावित करने में भी वह बुरी तरह असफल रही है।

"३९ करोड जनता का संपूर्ण शासन-प्रबन्ध स्वय भारतीयों के ही हाथों में है और भारतीय सिविल सिवस में अग्रेजों की संख्या ६०० से भी कम है। सभी सार्वजिनक सिवसे इस समय अपना काम कर रही हैं। पाच प्रान्तों में, जिनमें दो सबसे बड़े प्रान्त भी शामिल हैं और जिनकी आबादी ११ करोड़ है, धारासभाओं के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीय मित्रमङल काम कर रहे हैं। शहरों और देहातों के बहुत-से स्थानों में जनता ने नागरिक अधिकारियों का हाथ बँटाया है।

"यातायात के साधनों को काट देने से सबध रखनेवाला काग्रेस का विद्रोह अब असफल होता जा रहा है। आग लगाने और लूटमार की कार्रवाइयों को दबाया जा रहा है और जानमाल का वहुत ही कम नुकसान हुआ है। इतने विशाल और विस्तृत देश में ५०० से भी कम जाने गई हैं और नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए ब्रिटिश-सेना के केवल थोड़े से ब्रिगेड ही इधर-उधर भेजने पड़े हैं। अधिकाश जगह भारतीय जनता ने बलवाइयों की खूब खबर ली है और उन पर काबू पा लिया है।

"मुझे पूरा यकीन है कि यह सभा चाहेगी कि मैं बहादुर भारतीय पुलिस और भारतीय सरकारी वर्ग के प्रति, जिनका व्यवहार साधारणतः बडा प्रशसनीय रहा है, उनकी दृढता और राजभिक्त के लिए आभार प्रकट करू। सक्षेप में, सबसे बडी और उल्लेखनीय बात, जोिक काग्रेस के इस हिसात्मक आन्दोलन से स्पष्ट हुई है, यह है कि काग्रेस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह एक कमजोर जमात है और वह देश के साधारण जीवन को व्यवस्थित करने में नाकामयाब रही है।

"इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बता दू कि बहुत-सी सेनाएं भारत पहुच गई हैं और इस वक्त उस देश में श्वेत सैनिक इतनी बड़ी सख्या में मौजूद हैं, जितने पहले कभी नहीं रहें, यद्यपि देश की विशालता और भारी जनसख्या को देखते हुए वे अब भी बहुत थोड़े हैं। इसलिए मैं इस सभा को सूचित कर देना चाहता हू कि भारत की मौजूदा स्थिति से हमें अनुचित रूप से घबराना या निराश होना नहीं चाहिए।"

२९ सितम्बर को लन्दन में युद्ध की परिस्थित का सिहावलोकन करते हुए श्री एमरी ने कहा, "किसी भी दल-द्वारा लादा गया विधान कभी टिक नहीं सकता, लेकिन गांधीजी और काग्रेस के सगठन का नियत्रण करनेवाले उनके मुट्ठीभर साथियों का असली मकसद यही है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने हाल में बड़े पैमाने पर तोड-फोड का आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया था और इस तरह वे भारत-सरकार से घुटने टिकवा लेना चाहते थे। उससे न केवल तात्कालिक युद्ध-प्रयत्न के लिए भारी खतरा पैदा हो जायगा, विलक भारत की भावी स्वतन्त्रता और एकता भी खतरे में पड़ जायगी।"

इंग्लैण्ड और भारत में ही नहीं, विल्क अमरीका और दूसरे मुल्को में भी श्री चिंचल के उक्त भाषण पर गहरा खेद प्रकट किया गया। पार्लमेण्ट के सदस्य श्री ऐलन और विरोधी-दल के नेता और भूतपूर्व मत्री ग्रीनवुड ने प्रधान मत्री के भाषण की आलोचना करते हुए उसे एक तरह से "उत्तेजनात्मक और विरोध-मूलक" बताया जिससे 'लाखों ही लोगों को धक्का' पहुँचेगा। चर्चिल के उक्त भाषण के सम्बन्व में टिप्पणी करते हुए 'टाइम्स' ने अपने एक अग्रलेख मे लिखा-"काग्रेस सभी विवेकशील भारतीयो अथवा शायद उनके वहुमत का भी प्रतिनिवित्व नहीं करती। यद्यपि यह ठीक है कि केवल काग्रेस के दृष्टिकोण का ख्याल करते हुए ही कोई समझीता करना सभव नहीं है तथापि यह भी उतना ही सही है कि उसकी उपेक्षा करके कोई समझौता नहीं हो सकता।" 'माचेस्टर गाजियन' ने लिखा कि "उन्होने भारतीय स्थिति की कुछ ऐसी सहल बातो का, जिसका प्रचार अमरीका में हो चुका है, खण्डन किया है। यदि चर्चिल के वक्तव्य को अन्तिम वाक्य मान लिया जाय तो उससे न केवल ब्रिटेन, विलक मित्रराष्ट्रो को भी गहरी निराशा होगी।" इसी विपय को लेकर २८ सितम्बर को उसने फिर लिखा, "भारत के मामले में ब्रिटिश राजनीतिज्ञता की साख को घीरे-घीरे वट्टा लग रहा है। हम अमरीका और चीन को यह यकीन दिलाने में असफल रहे हैं कि हम अब तक अपने उदार विचारो पर दृढ वने हुए है। भारत मे तो श्री चर्चिल के भाषण ने केवल घाव पर नमक छिडकने का काम किया।" सायकाल के समय प्रकाशित होने वाले दैनिक मुस्लिम पत्र 'स्टार आफ इडिया' ने लिखा कि भारत में श्री चिंचल के भाषण से इतना अधिक क्षोभ फैलेगा जितना कि उनके यह कहने पर भी नही फैला था कि अटलाटिक अधिकार-पत्र भारत पर लागू नहीं होगा, क्योकि वह एक ऐसे कट्टर साम्राज्यवादी है, जिन्हे दूसरे देशो को स्वाधीन करने की अपेक्षा साम्राज्य मे शामिल करने की अधिक लालसा और उत्सुकता रहती है।" 'अमृत वाजार पत्रिका' ने लिखा—"यह भाषण आदि से लेकर अन्त तक उत्ते-जनापूर्ण है। इससे अराजकता को प्रोत्साहन मिलता है और यह भारत की प्रगति-शील शक्तियों को चुनौती है।" 'सिविल ऐन्ड मिलिटरी गजट' ने लिखा-''प्रत्येक वास्तविक राष्ट्रवादी और देशभक्त भारतीय यह कह सकता है और उचित रूप से कह सकता है कि भारत ने तो रोटी मागी थी लेकिन उसके बदले में उसे मिला पत्थर। साथ ही हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से राष्ट्रवादी भार-तीयों के दिलों में ब्रिटेन के लिए अत्यधिक सम्मान और प्रेम है और वे मित्रराष्ट्रो की असदिग्ध रूप से हार्दिक सहायता करना चाहते हैं। यह कहकर काग्रेस को बदनाम करने या उसकी मान-प्रतिष्ठा घटाने की कोशिश करना कि केवल थोडे से लोग ही उसके समर्थक है, सिवाय मूर्खता के और कुछ नही है।"

श्री चिंचल ने गैर-काग्रेंसियों में ९ करोड मुसलमानो, ५ करोड़ अछूतो और

९।। करोड रियासती जनता की गिनती की थी। बेहतर होता, अगर इसमें वह उन १० करोड लोगों को भी शुमार कर लेते जो राजनीतिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं और इस तरह उन्हें तसल्ली हो जाती कि काग्रेस के साथ केवल ५ करोड़ लोग हैं और इस प्रकार भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण की निर्थकता प्रमाणित हो जाती।

अक्तूबर १९४२ के अन्त मे पार्लमेण्ट मे भारत-विषयक वहस होने से पहले ही १० अक्तूबर को 'न्यू स्टेट्समैन ऐण्ड नेशन' ने भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए वास्तविक कोशिश करने पर जोर देते हुए लिखा कि क्या भारत में गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता? हमारी राय में अमरीका की मेन्यस्थता के जरिये भारतीय समस्या को सुलझाने का प्रस्ताव ठुकरा कर हमने गलती की है। 'टाइम्स' ने लिखा कि ब्रिटिश सरकार को अपना प्रयास नही छोडना चाहिए और वाइसराय की शासन-परिषद् के उन पाच स्थानो पर भी जिन पर इस समय अग्रेज है-भारतीयों को ही नियुक्त कर देना चाहिए। कठि-नाई तो यह है कि कोई भी भारतीय जिसे अपने देशवासियो का विश्वास प्राप्त नहीं है अथवा जिसे किसी दल का समर्थन प्राप्त नहीं है, वाइसराय की शासन-परिषद में नहीं शामिल हो सकता और उसमें ऐसे भारतीयों को लेने से कोई लाभ नहीं जो सिवाय अपने किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस दिशा में एकमात्र उचित तरीका यह होगा कि श्री राजगोपालाचारी, सर तेजवहादुर सप्र अथवा सर सिकन्दर हयात खा जैसे किसी योग्य भारतीय राजनीतिज्ञ से राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए कहा जाय। भारतीयों को शक है कि हम उन्हें सत्ता सीपने को तैयार नहीं है, इसलिए जब तक हम उपर्युक्त कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम नही जान सकेंगे कि भारत के विभिन्न दल देश की रक्षा के लिए सगठित होकर कोई कार्रवाई करना चाहते है या नही।

पहली अक्तूवर को श्री एमरी से कामन-सभा में यह सवाल पूछा गया कि भारत के कितन प्रभावशाली व्यक्तियों अथवा सगठनों ने काग्रेसी विन्दियों के साथ सम- भीते की वातचीत करने के बारे में मुनासिव सहूलियते देने को लिखा है। उनसे यह भी पूछा गया कि पिडत नेहरू इस वक्त कहा है और क्या उनके साथ लिखा- पढ़ी की जा सकती है? इसके जवाव में श्री एमरी ने कहा कि मुझे इस वारे में किसी ने नहीं लिखा, पिडत नेहरू को घरेलू मामलों के बारे में अपने पिरवार-वालों से पत्र-व्यवहार करने की इजाजत है, लेकिन मैं यह बताने को तैयार नहीं कि वह कहा है। जब उनसे यह पूछा गया कि भारत में उपद्रव फैलानेवाली भीड पर वायुयानो द्वारा जो वम-वर्षा की गई है उसके बारे में वह पूरा हाल बताएँ और भविष्य में इन तरीकों से काम न ले तब श्री एमरी ने कहा, "पिछले सप्ताह भारत की केन्द्रीय असेम्बली में सराकरी तौर पर जो वक्तव्य दिया गया है और जो यहां

के पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, मैं उससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। इसमें वताया गया है कि हाल के उपद्रवों में पाच दफा भीड पर वायुयान से मंशीन-गन-द्वारा गोली-वर्षा करनी पड़ी है और यह गोली उस वक्त चलाई गई जबिक विहार में १८ सितम्बर को एक वायुयान दुर्घटना में चालक के मर जाने पर उस वायुयान के कर्मचारियों को भीड ने मौत के घाट उतार दिया। जिन इलाकों में व्यापक रूप से रेलमार्गों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और जहा वाढ के कारण फौजों के यातायात में कठिनाइया पैदा हुई वहा तोड-फोड के काम को रोकनें के लिए वायुयानों की सहायता लेना आवश्यक समझा गया।" भारत की वर्तमान और निकट-भविष्य की परिस्थित के वारे में ब्रिटिंग सरकार और भारत-सरकार की नीति का जिक्र करते हुए श्री एमरी ने कहा कि जहाँ तक काग्रेस का सवाल है उसके नेताओं ने स्वय अपनी नीति से सादित कर दिया है कि उनके साथ कोई वात-चीत नहीं हो सकती।

२९ अक्टूबर को 'माचेस्टर गाजियन' मे वर्टरैण्ड रसल और उनकी पत्नी ने लिखा कि अग्रेज पूरी तरह से यह अनुभव नहीं कर रहे कि अमरीका में भारतीय गति-रोध के बारे में कितनी बेचैनी और उत्तेजना पाई जाती है। उन्होने इस बात पर जोर दिया कि न केवल भारत, विलक अमरीका और दूसरे मित्र-राष्ट्रो को यकीन दिलाने के लिए भी ब्रिटेन को इस मामले में कुछ-न-कुछ अवश्य करना चाहिये। उसी दिन श्री वर्नन वार्टलेट ने भारतीय गतिरोध के निराकरण के लिए 'न्यूज कानिकल' में लिखा—"श्री एटली और श्री एमरी दोनों ने ही पिछले महीने यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार अब तक किप्स-योजना पर कायम है। लेकिन उन्हें अपने इन आक्वासनो के समर्थन मे ऐसा कोई वैधानिक कदम उठाना चाहिए या शाही घोषणा कर देनी चाहिए कि लडाई के वाद यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को आजादी दे दी जायेगी। यही नही, इस अन्तर्कालीन अविध मे उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे भारत समान-शत्रु के विरुद्ध अपना पूरा सहयोग प्रदान कर सके।"१५ नवम्बर को "दमन के वाद—अब क्या?" शीर्षक से हेरल्ड लास्की ने अपने एक लेख में लिखा—"यह कहा जा सकता है कि काग्रेसी नेता इस समय नजरबन्द है। इसलिए यह साबित करने के लिए कि हम वस्तुत समझौता करना चाहते हैं और सम्मेलन को सफल बनाने के इच्छुक हैं, हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिये। अगर यह तर्क और युक्ति दी जाय, जैसी कि सर स्टैफर्ड किप्स दे रहे हैं कि यदि इस वक्त सत्ता एक भारतीय सरकार को सौप दी जाय तो उससे देश में अव्यवस्था और अराजकता फैल जायगी, तो क्या यह नही हो सकता कि हम किसी भारतीय को वाइसराय नियुक्त कर दे । अगर हिन्दू वाइसराय की नियुक्ति पर कोई एतराज उठाया जाता है तो आप समझौते से किसी सुप्रसिद्ध मुसलमान को वाइसराय बना दे । अगर यह कहा जाय कि लडाई

के खत्म होने तक अन्तर्कालीन मित्रमडल की अवधि अनिश्चित प्रतीत होती है तो आप यह कर सकते हैं कि दो-दो साल के लिए वारी-बारी से दोनो जातियों की सरकार स्थापित कर दे। यह सम्मेलन ही इस वात का फैसला कर ले कि प्रधान-मन्त्री किसे वनाया जाय और रक्षा-मन्त्री उससे भिन्न सप्रदाय से लिया जाय। इसके अलावा रक्षा-विभाग पर व्यापक रूप से मंत्री का अधिकार रहे और उसके वारे में किप्स-प्रस्तावों की तरह तू-तू मैं-मैं न की जाय।"

लन्दन में इडिया लीग की एक वैठक में एक प्रस्ताव-द्वारा भारत को आजाद करने, वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और उसके साय तत्काल समझौते की वातचीत शुरू करने की माग की गई। यह प्रस्ताव पालंमेण्ट के प्रसिद्ध मजदूरदलीय सदस्य श्री आर॰ उन्लू सोरेन्सन ने पेश किया था। इसी समय कामनसभा में श्री एमरी से पूछा गया कि अब तक क्यो वाइसराय की शासन-परिषद् के उन तीन स्थानो पर, जहां इस समय यूरोपियन सदस्य आसीन हैं, भारतीयों को नियुक्त करके उसका पूर्णत भारतीयकरण नहीं किया गया? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि युद्धकालीन परिस्थितियों का मुकावला करने के लिए और कार्य-कुशलता के विचार से वाइसराय ने अपनी शासन-परिषद् में विस्तार कर लिया है। उन्हें सन्तोप हैं कि वाइसराय की शासन-परिषद् के मौजूदा सदस्य अपने काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। मौजूदा यूरोपियन सदस्य इनलिए अब तक वने हुए हैं कि इन जगहों के लिए योग्य भारतीय नहीं मिल रहें हैं।

सत्य के बारे में ब्रिटिश राजनीतिजों के अपने मापदं हैं जिन्हें समजना बहुत कि है। बहुत अरला हुआ, लाई लिटन ने कहा था कि "राजनीति सत्य को लिपने का विज्ञान और कला है।" लेकिन उसके बाद से वह ख़ुठ को सत्य नाबित करने का विज्ञान और कला वन गई है। अन्यथा हमारे लिए श्री एमरी के ये उत्तर समजने कि हो जाते हैं, जो उन्होंने अक्तूबर में एक अमरीकी रेडियों जालों के के प्रन्तों के सिलसिले में दिये थे। यह पूछे जाने पर कि क्या श्री निचल ने भारत को अटलाटिक अधिकार-पत्र से बचित करने की घोषणा की है, श्री एमरी ने कहा कि "इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई।" उन्होंने कहा कि विटिश नीति उनत चार्टर की घारा ३ के अन्तर्गत निहित सिद्धान्तों के सर्वया अनुरुप है और 'इन नीति का सूत्रपात हमने पचीस पर्प पूर्व किया था, जिसे क्रमशः उत्तर किया जाना था।" उनमें पूछा गया कि "क्या आप जो कुछ कह ख़े हैं भारतीयों को उस पर बजीन हैं?" उन्होंने जवाब दिया. "हां, उन्हें बकीन हैं।" 'मानेस्टर गाजियन' ने इन विश्वय पो फिर उठाया और इस बान पर जोर दिया कि अधिनार पत्र भारत पर भी लागू विचा जाना चाहिए। उमने किना—"जब कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं—कैना कि उनके कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं—कैना कि उनके कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं—कैना कि उनके कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं—कैना कि उनके कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं—कैना कि उनके कि सरगर भारत दी महागता करने जा उपाय इट रही हैं

लिए सर्वया उचित है—उसे चाहिए कि वह अटलाटिक अधिकार-पत्र के इस पेचीदा सवाल का भी फैसला कर दे।"

नवम्बर में वहत-सी आश्चर्यजनक और परस्पर विरोधी वातें देखने में आई। श्री सी॰ राजगोपालाचार्य ने समझौते के लिए अपना आन्दोलन जारी रखने के उद्देश्य से जुलाई में मद्रास असेम्बली और काग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अक्तूबर में उन्होने पासपोर्ट और वायुयान से लन्दन जाने की इजाजत मागी जिससे कि वे समझीते के वारे में अपनी शर्ते अधिकारियों के सामने रख सके और उन्हें यकीन दिला सके कि उन पर अमल करना सभव है। लेकिन उन्हें ये सहलियते देने से इन्कार कर दिया गया। पर इससे पूर्व भी सरकार, भारत के लोट पांदरी, डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी, भारत में राप्ट्रेपति रूजवेल्ट के विशेष दूत श्री विलियम फिलिप्स और स्वय श्री राजगोपालाचार्य को गांधीजी से मिलने की इजाजत देने से इन्कार कर चुकी थी। श्री राजगोपालाचार्य के साथ उसने जो सलूक किया वह उसी नीति का एक अग था। राजाजी को इगलैंण्ड आने के लिए सुविघाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के चालीस से अधिक प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से एक पत्र श्री एमरी को भेजा गया। इन लोगों में लॉर्ड मॉर्ले और स्ट्रावोली, जी० डी० एच० कोल, हेरल्ड लास्की, जुलियन हक्सले, बेल्सफोर्ड, प्रोफेसर जोड और मैडम एलिजावेथ कैडवरी और लेडी लिटन-जैसी प्रमुख महिलाए भी शामिल थी। परन्तु ब्रिटिश सरकार की नीति का आभास तो हमें प्रधान मत्री चिंचल की उस घोषणा से मिलता है जो उन्होंने लार्ड मेयर के वार्षिक भोज के अवसर पर दिये गए अपने भाषण में की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर अफ्रीका अथवा दुनिया के किसी भी हिस्से में ब्रिटेन किसी प्रदेश

पर कब्जा नहीं करना चाहता।
श्री चिंचल ने कहा, "हम इस लडाई में लाभ अथवा प्रभुता-विस्तार की दृष्टि से नहीं, बल्कि केवल प्रतिष्ठा और न्याय की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य-पालन के उद्देश्य से लगे हुए हैं।परन्तु मैं यह वात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इस बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हम अपना साम्राज्य वनाए रखना चाहते हैं। मैं सम्राट् का प्रवान मत्री ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिए नहीं बना। अगर कभी ऐसा होता है तो उसके लिए किसी और आदमी को जन्म लेना होगा और प्रजातत्रात्मक पद्धित के अन्तर्गत इस काम के लिए राष्ट्र से परामर्श लेना पड़ेगा। मैं इसे अपने लिए बड़े गौरव की बात समझता हूँ कि मैं इस विस्तृत राष्ट्रमण्डल तथा उन राष्ट्रों और विभिन्न जातियों के समूह का सदस्य हूँ जो ब्रिटेन के प्राचीन राजतत्रवाद से सम्बद्ध हैं और जिसके बिना शायद पृथ्वी पर अच्छाई का लोप हो जाता। इस डगमगाते हुए ससार के बीच हम मुक्ति की एक दृढ चट्टान की तरह खड़े हैं।"

श्री चिंचल का भाषण १० नवम्बर को हुआ था और उसी दिन सम्राट् ने पार्लमेण्ट को स्थगित करते हुए निम्न भाषण दिया —

"मेरी प्रजा और हमारे सहयोगियों का उद्देश्य जहा-कही भी स्वाघीनता पर आक्रमण हो उसकी रक्षा करना और शत्रु के प्रदेश पर आक्रमण करना है जिससे कि हम यथा-शक्ति शीघ्र-से-शीघ्र उन देशों और शक्तियों को, जो इस समय शत्रु के कब्जे में हैं, स्वतत्र करा सके।

"ब्रिटेन में मेरी सरकार ने भारत के नरेशों और जनता से साफ तौर पर कह दिया है कि वह लडाई समाप्त हो जाने के तत्काल बाद ही स्वयं भारतीयो-द्वारा तैयार किए गए विधान के आधार पर ब्रिटिश-राष्ट्रमडल के अन्तर्गत भारत को पूर्ण स्वाधीन देखना चाहती है। इस बीच भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने देश के शासनसूत्र और युद्ध के सचालन में पूर्णरूप से भाग लेने का निमत्रण दिया गया था। मुझे अत्यन्त खंद है कि अभी तक उन्होंने हमारा यह निमत्रण स्वीकार नहीं किया। मेरी हार्दिक आजा है कि वे बुद्धिमत्ता से काम लेकर स्वयं आपस में कोई समझौता करके जल्दी ही इन कठिनाइयो पर काबू पा लेगे।"

प्रधानमंत्री के भाषण के कारण सोया हुआ ब्रिटेन एक बार फिर सजग हो उठा। इसके कुछ दिनो वाद ही ब्रिटेन के गृह-मन्त्री हर्वर्ट मौरीसन ने भी भारत के लोगों के लिए 'ब्रिटेन की देन' का जिक किया, लेकिन उससे भी भारत का घाव भरने में मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों को स्वय अपना विधान बनाने की पूरी आजादी दे दी है, चाहे उसका परिणाम पूर्ण स्वाधीनता ही क्यों न हो। लड़ाई के बाद उन्हें अपने देश के भाग्य का निर्णय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, वशर्ते कि लड़ाई के दौरान में वे सयुक्त-राष्ट्रों की विजय-प्राप्ति में कोई अड़चन न पैदा करे। क्या आप मुझे इतिहास में कोई और ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब कि किसी शासक ने अपनी गुलाम प्रजा को इस तरह की आजादी देने की बात कही हो? आप इसका क्या मतलब लेते हैं? मैं तो कम-से-कम इसका मतलब यह लेता हूँ कि इस तरह से ब्रिटेन ने अपने उन उद्देशों का एक और सबूत पेश किया है जिनसे प्ररित होकर वह इस लड़ाई में शामिल हुआ है। समय-समय पर गाधीजी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ बाहर के

समय-समय पर गांधीजी और विकिग कमेटी के सदस्यों के साथ बाहर के लोगों का सपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये गए। नवम्बर के अत में कामन-सभा में श्री एमरी से यह सवाल किया गया कि क्या इस देश के किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को इस समय नजरवन्द काग्रेसी नेताओं के साथ पत्र-व्यवहार करने की इजाजत दी जाएगी, क्या ये नेता इस देश के किसी गैर-सरकारी आदमी से लिखा-पढ़ी कर सकते हैं अथवा उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जा सकेगी और क्या उन्हें कोई सार्वजनिक घोषणा करने की भी आजादी होगी? इनके जवाव में श्री एमरी ने कहा, "मुझे पता चला है कि इन नजरवन्द भारतीय नेताओं को केवल अपने

परिवारवालों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आज्ञा है और वह भी केवल घरेलू मामलों पर ही। मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता कि उन पर से ये प्रतिवन्य कव तक हटाए जा सकेंगे। क्या भारतीय नेताओं को कोई सार्वजनिक घोषणा करने की इजाजत दी जा सकेंगी या नहीं—यह इस पर निर्भर करेगा कि वह घोषणा किस तरह की है।"

इस आपत्काल में भी भारत को उसके पुराने शुर्भाचतको—अर्यात् इगलैण्ड के सुह द सघ ने नहीं भुलाया। सघ के वयोवृद्ध कर्णघार श्री कार्ल हीय ने भारतीय स्थित के बारे में 'स्पेक्टेटर' में एक जोरदार पत्र लिखकर अपना क्षोभ प्रकट करते हुए भारतीय समस्या को सुलझाने की हार्दिक अपील की। श्री वेडलिवल्की ने प्रधान मत्री चिंचल की ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण वनाए रखनेवाली घोषणा का मुहतोड जवाव दिया। इसके अलावा लार्ड केनवोर्न ने ब्रिटेन की युगो पुरानी औपनिवेशिक नीति के बारे में जो कुछ कहा, उसकी भी कडी प्रतिक्रिया हुई। उधर अमरीका के समाचार-पत्रों ने भी ब्रिटेन की खूब खबर ली। 'टाइम्स' ने औपनिवेशिक व्यवस्था के भविष्य के सम्बन्ध में अपने एक लेख में 'अतीत की मनोवृत्तियों को छोड देने' की जोरदार अपील की। ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के सम्बन्ध में श्री चिंचल की घोषणा की न केवल भारत में ही विलक्त सारे पूर्व में अर्थात् सुदूर-पूर्व, निकट-पूर्व और मध्य-पूर्व में कडी आलोचना हुई और उससे इन देशों में गहरी वेचैनी पैदा हो गई।

इस प्रकार नवम्बर भी बीत गया और वहे दिन आ गए। पर भारत को इससे क्या, उसके दिन तो अभी नही फिरे थे। लाई लिनलियगो का कार्य-काल और छ. महीने तक अर्थात् अक्तूबर १९४३ के अन्त तक के लिए वढा दिया गया। ब्रिटिश सरकार-द्वारा 'वाइसराय के कार्यकाल की अवधि' का बढाना, पार्लमेंट में श्री चिंचल और श्री एमरी के प्रतिक्रियावादी और दुराग्रहपूर्ण भाषण, श्री राजगोपालाचर्य को गांधीजी से मिलने की इजाजत न देना और भारतीय जनमत की तिनक भी परवाह न करके फेडरल-कोर्ट (सघ-न्यायालय) में प्रधान न्यायाधीश के पद पर एक अगरेज की नियुक्ति—इन सभी बातो से 'न्यूज क्रानिकल'— जैसे गभीर और शान्तिप्रिय पत्र को भी यह लिखना पड़ा कि "भारत-द्वारा किंप्स-योजना को ठुकरा देन के परिणामस्वरूप निराश होकर ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में और कोई रचनात्मक प्रयत्न करने की कोशिश नहीं की । प्रोफेसर वुड ने जिनकी ऐसी दृढ धारणा थी, लिखा कि, "जब गांधीजी के मित्र और प्रशसक भारत-सरकार से उनसे (गांधीजी) बातचीत करने का अनुरोध करते हैं, तब उससे यह जाहिर होता है कि वे यह आग्रह इसलिए नहीं कर रहे कि गांधीजी की साख को बनाए रखे, बल्क इसलिए कि वे गांधीजी की नैतिक प्रतिष्ठा से कितना अधिक प्रभावित हुए हैं। मेरी दृष्टि में गांधीजी एक महान् आध्यात्मिक और

नैतिक नेता है और इसीलिए मेरा दृढ विश्वास है कि भारत के वर्तमान गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न उन्हीं की ओर से होना चाहिए।"

काग्रेस की दृष्टि से प्रत्येक नये वर्ष की महत्वपूर्ण और पितृत्र घटनाओं में 'स्वाधीनता-दिवस' विशेष महत्व रखता है। पिछले सालों की भाति १९४३ में भी यह दिवस २६ जनवरी को लन्दन के स्वराज्य-भवन में डा॰ एस॰ वी॰ वार्डन की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके दो दिन बाद श्री सोरेन्सन ने कामन-सभा में श्री एमरी से गैर-काग्रेसी प्रतिनिधियों पर से काग्रेस नेताओं से मुलाकात करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध उठा लेने का आग्रह किया जिससे कि वे सम्भावित राजनीतिक परिस्थित पर सोच-विचार कर सके।

प्रथम महायुद्ध की भाति इस बार दूसरे महायुद्ध में भी ब्रिटिश-सरकार ने दिखावे के तौर पर भारत के दो प्रतिनिधि अपने युद्ध-मन्त्रि-मण्डल मे लिए। ये प्रतिनिधि वाइसराय की शासन-परिषद् के सदस्य सर रामस्वामी मुदालियर और जामनगर के जामसाहब थे। इंग्लैण्ड में भारत के ये दोनों प्रतिनिधि वहाँ की विभिन्न औद्योगिक सस्थाओ और युद्धकेन्द्रों का निरीक्षण करने में व्यस्त रहे। हिज हाईनेस जामसाहब तो जनवरी १९४३ में स्वदेश लौट आए। इंग्लैण्ड के लिए इन महानुभावों के प्रस्थान करने से पूर्व यह कहा जा रहा था कि सर राम-स्वामी मुदालियर वहा जाकर भारतीय गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न करेगे। इसलिए इंग्लैण्ड में उन्होंने इस बारे में जो कुछ भी किया हो, भारत को उसकी कोई सूचना न होना स्वाभाविक ही था। लेकिन जामसाहब ने इगलैण्ड पहुँचते ही एक भाषण दिया जिसमे आपने वाइसराय की शासन-परिषद् के पूर्ण भारतीय-करण पर जोर दिया। प्रत्यक्ष था कि वह पत्थर की दीवार से अपना सिर टकरा रहे थे। अपने चाचा की मृत्यु के कारण उन्हें शीघ्र ही भारत वापस आना पडा। भारत लौटने पर उन्होने ८ फरवरी, १९४३ को नयी दिल्ली के एक पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में स्पष्ट रूप से बताया कि युद्ध-मन्त्रि-मण्डल की बैठको में किसी राजनीतिक अथवा वैधानिक समस्या पर सोच-विचार नही किया गया, क्योकि उसका मुख्य काम तो केवल युद्ध जीतना है।

फरवरी का महीना सारे संसार के लिए सनसनीपूर्ण और वेचैनी का रहा, क्योंकि १० फरवरी को गांधीजी ने सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति उपवास प्रारंभ किया और वे तीन सप्ताह की कठोर तपस्या के बाद ३ मार्च को इसमें सफलता-पूर्वक उत्तीर्ण हुए।

कांग्रेस-विरोधी पुस्तिका

इस प्रकार एक महीने तक वातावरण पृष्टितः कान्त वना रहा। केवल २२ फरवरी १९४३ को यह ज्ञान्ति भग हुई जब कि सरकार ने भारत में भारत

उपद्रवो के लिए काग्रेस का उत्तरदायित्व' शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की और उसके कुछ सप्ताह बाद ही इस वारे में ब्रिटेन में एक श्वेतपत्र भी छपा। सरकार के दृष्टिकोण से यह प्रकाशन सर्वया सामियक था, क्यों कि अप्रैल में पार्लमेंट में होनेवाली भारत-विषयक बहस के लिए वह पार्लमेंट के सदस्यों के हाथों में यह सामग्री पहुँचा देना चाहती थी। उक्त पुस्तिका में कहा गया कि अब तक जानी गई और प्रमाणित सपूर्ण घटनाओं को दृष्टि में रखकर केवल यही बात युक्तिसगत मालूम पडती है कि ९ अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद व्यापक रूप से फैलनेवाले ऐसे उपद्रवों को काग्रेस ने पैदा किया और उनका पय-प्रदर्शन किया, जो कुछ क्षेत्रों में खुले विद्रोह के सिवा और कुछ न थे। इस पुस्तिका की टीका टिप्पणी करते हुए 'न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशन' ने अपने एक अगलेख में लिखा कि "भारत-सरकार ने यह व्वेत-पत्र छापकर कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक गांधीजी पर व्यक्तिगत रूप से अभियोग लगाने की कोशिश की गई है और इसके अलावा वह केवल एक प्रचार-सम्बन्धी पुस्तिका है।"

'टाइम्स' सिहत ब्रिटेन के शेष पत्रो ने प्रत्यक्ष रूप से गाधीजी और काग्रेस के खिलाफ जहर उगला। 'उपद्रवो के लिए काग्रेस का उत्तरदायित्व' शीर्षक पुस्तिका ऐन उस मीके पर प्रकाशित की गई जब कि २१ दिन के दौरान में गांधीजी का भाग्य पलडे में झूल रहा था और ठीक उसके एक महीने बाद उक्त खेत-पत्र प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन से लगभग पन्द्रह दिन पहले वम्बई मे निर्दल नेताओं का एक सम्मेलन हुआ। उन्होने समझौते की कोशिश की और इस काम में उन्हें कुछ सफलता भी मिली। वाइसराय ने उनसे मिलने का वादा कर लिया और उन नेताओ से कहा गया कि वे अपना मामला एक विचार-पत्र के रूप में पेश करें। लेकिन इस श्वेत-पत्र के कारण उनकी सब कोशिशो पर पानी फिर गया। उक्त पुस्तिका छापने का उद्देश्य गाधीजी की रिहाई के लिए की जाने वाली व्यापक मांग और उनके प्रति प्रकट की गई सहानु-भूति पर तुषारापात करना था। इसके बारे मे यदि हम किसी कागेसी की प्रतिकिया प्रकट करें तो उसे पक्षपात पूर्ण समझा जायगा, लेकिन यहाँ हम 'स्टेट्समैन' मे 'हमारे भारतीय प्रेक्षक' द्वारा प्रकाशित 'राजनीतिक आलोचना' को उद्धृत करना उचित समझते हैं, क्योंकि उसे अधिक निष्पक्ष खयाल किया जा सकता है ---

"लन्दन में प्रकाशित किया गया श्वेत-पत्र सर्वथा असामयिक है। यह एक ऐसे अवसर पर छापा गया है जब कि जेल के बाहर के हल्को में काग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत का आग्रह ही नही, बल्कि प्रार्थना भी की जा रही है। इसके अलावा जो लोग गांधीजी से मिल कर आये हैं, उनका भी

साफ तौर पर केवल यह कह देना चाहिए कि मेरी नीति का आधार अव तक डा॰ डूलिटिल और टा॰ वर्नाडों के सिद्धान्त हैं।" उप-प्रधान मन्त्री श्री एटली ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि "मैं समझता हूँ श्री गोखले, श्री राजगोपालाचार्य, पडित नेहरू और श्री जिन्ना आदि जो वास्तव में प्रजा-तन्त्र वादी हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को अमल में ला सकते हैं।" श्री गोखले १९ फरवरी, १९१५ को परलोक सिधार चुके थे, किन्तु श्री एटली-द्वारा उनके उल्लेख से पता चल जाता हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशाल ब्रिटिश साम्प्राज्य के उप-प्रधान-मंत्री कितना ज्ञान रखते हैं।

लार्ड सभा मे विचार

लार्ड सभा की वहस यद्यपि अधिक दिलचस्प रही, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं पहुँचा। इस सम्बन्ध में हम दो भाषणों का उल्लेख करना चाहते हैं। लार्ड फेरिंगडन (मजदूर-दल) ने कहा कि उन काग्रसी नेताओं के साथ समझौता करने का आधार प्रस्तुत है जिनमें से बहुतों के उद्देश्य ब्रिटिश सरकार-जैसे ही हैं। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि गाधीजी डिक्टेटर हैं अथवा काग्रेस एक वर्गवादी सस्था है। श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य भारतीय नेताओं के गाधीजी से मिलने के लिए वाइसराय की अनुमित न मिलने की उन्होंने अलोचना की। उन्होंने यह सुझाव रखा कि ब्रिटिश सरकार समस्त दलों के नेताओं को लन्दन में निमित्रत करे जिससे यह मालूम किया जा सके कि कोई उपाय निकल सकता है या नहीं। यदि सभव हो तो इसमें मित्रराष्ट्रों की सरकारों का भी सहयोग ले लेना चाहिए।

लार्ड सेम्युएल ने कहा, "भारतीय-विधान के अनुसार जब प्रजातन्त्र पर आधारित उन व्यवस्थापिका सभाओ का निर्वाचन हुआ, जिनके प्रति विभिन्न प्रान्तीय सरकारे उत्तरदायी है तब उदार दल ने इस पर अत्यधिक सतोष प्रकट किया था। हमने इसे वैधानिक प्रजातन्त्र-प्रणाली की सब से बडी विजय कहा था, जेसी कि अब तक किसी भी पूर्वी देश में नहीं देखने में आई। जब मैं भारत गया था तब मेरा यह खयाल नहीं था कि प्रान्तीय विधान इतनी आश्चर्यजनक सफलता के साथ अपना काम कर रहे होगे।"

लार्ड सभा में ६ अप्रैल १९४३ को लार्ड सेमुएल ने जो भाषण दिया था, उसका उत्तर देते हुए गाधीजी ने १९ मई, १९४३ को उन्हें एक पत्र लिखा जिसे सरकार ने लार्ड सेम्युएल तक नहीं पहुँचने दिया।

भारत-सरकार की प्रतिक्रिया

काग्रेस-नेताओ की गिरफ्तारी के पाँच सप्ताह बाद १५ सितम्बर को केन्द्रीय असेम्बली का अधिवेशन शुरू हुआ और इसके एक सप्ताह बाद राज-परिषद् का। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पार्लमेण्ट और केन्द्रीय असेम्बली के अधिवेशन किसी पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार साथ-साथ ही शुरू हुए। कहन का तात्पर्य यह है कि पार्लमेण्ट का अधिवेशन भारत की केन्द्रीय घारासभाओं के शुरू होने से ठीक कुछ समय पूर्व आरम्भ हुआ। भारत के गृह-सदस्य सर रेजिनाल्ड का अनुमान था कि इन दगों के कारण कुल मिलाकर हानि एक करोड रुपयों से भी अधिक होगी और उन्होंने इन उपद्रवों के कुछ खास पहलुओं का जिक्र करते हुए यह बात मानन से इन्कार किया कि ये दंगे काँग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यकायक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हुए हैं। उन्होने ऐसी बाते गिनाई जो उनकी राय में यह साबित करती थी कि इन उपद्रवों के पीछे अत्यन्त दुर्भावना के साथ पहले से ही कोई सगठन अवश्य था। उन्होने कहा, "अभी मै यह नही बता सकता कि इस सगठन को प्रेरणा कहा से प्राप्त हुई। अभी हमे ऐसी कितनी ही वातो की जानकारी प्राप्त करना शेष है, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। किन्तु इन उपद्रवो से काग्रेस का सम्बन्ध रहने के विषय में जो सन्देह शेष रह गया हो उसे काग्रेसियो, विशेषकर बिहार के काग्रेसियों के उन भाषणों से असंख्य उदाहरण दे कर निर्मूल सिद्ध किया जा सकता है, जिनमे साधारण जनता को हिसा और विध्वस करेने के लिए खुलेआम उकसाया गया था। इसके अतिरिक्त बम्बई की बैठक के तत्काल बाद किंतने ही काग्रेसी नेता लापता हो गए और वे किन्ही ऐसे कारणों से लापता है, जिनका स्वय उन्हीं को पता है। इसलिए अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर इन गम्भीर घटनाओं के लिए हम काग्रेस को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकते।" आगे चल कर उन्होंने कहा कि अगर काग्रेस को थोडा और समय मिल जाता तो उससे हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती और अपरिमित क्षति होती। उन्होने विनाश के इस नग्न नृत्य तथा भारत-वासियों के जीवन और धन की इस हानि पर गहरा खेद प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बातो से स्वय भारतवासियों की हानि होगी और उन्ही की कठिनाइया बढेगी। उन्होने यह भी बताया कि सम्पूर्ण मुस्लिम-समुदाय और परिगणित जातिया इनसे विल्कुल अलग रही है। साथ ही इस बात पर भी प्रसन्नता प्रकट की कि न केवल पुलिस, वरन् समस्त सरकारी कर्मचारियो ने उन्हें आतिकत करने के समस्त प्रयत्नों के बावजूद दृढता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। बहुतेरों ने तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण तक दे दिये है।

बहस की बहुत-सी वातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यह एक तरफा चीज थी, इसलिए इसमें विवेकहीनता का होना अनिवार्य था और एक तरह से यह अभियुक्त की अनुपस्थिति में धारासभा के सामने उस पर दोषारोपण करना और मुकदमा चलाना था। काग्रेस-सदस्यों की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर सरकार ने ऐसे वक्तव्य दिये, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

यह एक वडी उल्लेखनीय वात है कि एक ओर जब पार्लमेट में भारतीय स्थित के सम्बन्ध में कितनी ही बहसे हो रही थी और कितने ही सवाल पूछे जा रहे थे तथा भारत-मत्री और उप-भारत-मत्री को वक्तव्य देने पड रहे थे और घोपणाए करनी पड रही थी, दूसरी ओर वाइसराय महोदय विल्कुल मीन वारण किए हुए थे और उन्होने उपद्रवो के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नही कहा। अन्त में १७ दिसम्बर् १९४२ को उनका मौन भग हुआ जब कि उन्होने व्यापारमडल-सघ के वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया। फेडरेशन के सम्मुख अपने लम्बे भाषण मे वाइसराय महोदय ने देश की राजनीतिक, औद्योगिक और सैनिक स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए अपनी उन असफल कोशिशो का जिक्र किया जो उन्होने भारत के विभिन्न समूहो और दलो के दरिमयान समझौता कराने के लिए की थी । उन्होने यह भी कहा कि उनका कार्यकाल दस महीने तक के लिए यद्यपि वढा दिया गया है, तयापि वह समझौता कराने के लिए अपनी कोशिशो में कोई शिथिलता नही आने देंगे। उन्होने भारत से यह यकीन करने का अनुरोध किया कि अगर अपने गासन काल के इन अगले दस महीनो में वह भारत के विभिन्न दलों की मौजूदा खाई को पाटने में सफल हो गए तो उनसे अधिक भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नही होगा। आगे चल कर उन्होने यह भी कहा—"लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि देश के सभी सम्बद्ध वर्गों और दलो में वास्तविक समझौता हुए विना केवल कृतिम एकता से काम नही चल सकता। उससे तो लाभ के वर्जाय हानि हो सकती है। किसी बाहरी दबाव के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले मतभेद उन मतभेदो की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं, जो सर्वविदित हैं और जिन्हें दूर करने की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। केवल विभिन्न दलो और विभिन्न समुदायों के पारस्परिक समझौते-द्वारा ही हम अपना वाछित उद्देश्य हासिल कर सकते हैं और इस समझौते का आघार पारस्परिक विश्वास, एक-दूसरे की ऐतिहासिक प्रयाओं के प्रति सम्मान और उदारता का वर्ताव और भावी योजनाओं में एक-दूसरे के न्यायोचित दावो की पूर्ति होनी चाहिए। क्या हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति की कोशिश नहीं करनी चाहिए ? अगर हमें उसे हासिल करने के लिए किसी कुर्वानी की जरूरत पड़े तो क्या हमे वह कुर्वानी नही करनी चाहिए?"

किसी व्यक्ति के कथन की परीक्षा हमेशा उसके व्यवहार और आचरण से होती है। वाइसराय महोदय ने भारत की एकता पर जोर दिया है। क्या यह एकता कोरा सिद्धान्तवाद या कोई काल्पनिक चीज है जिसके लिए उन्हें इतनी लम्बी-चौडी वाते करनी पड़ी और इतनी वाक्यपटुता दिखानी पड़ी अथवा क्या यह सुलह-सफाई, समझौते और आदान-प्रदान की भावना के लिए विभिन्न दलों से आग्रह था? क्या यह उपदेश विभिन्न दलों से तत्काल अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुचने का अनुरोव था? जो लोग गितरोव के हल के लिए वाइसराय पर आशा लगाए बैठे

थे उन्हें निराण होना पडा, बयोकि उन (वाइसराय) के कयन और व्यवहार, पित्रत प्रार्थना और व्यवहारिक कार्यक्रम में कोई सामजस्य नहीं था। फरवरी, १९४२ में केन्द्रीय अनेम्बली में श्री नियोगी के उस प्रस्ताव पर बहुत घर हुई जो उन्होंने उनके पिछले अधिवेशन में पुलिस हारा 'हाल के उपद्रवो' को शान्त करने के लिए की गई 'ज्यादितयो' की जाच-पड़ताल के सम्बन्ध में सभा के सदस्यों की एक समिति स्थापित करने के बारे में पेश किया था। दहस का उत्तर देते हुए गृह-सदस्य ने कहा कि अपने कर्मचारियों पर प्रतिवन्ध लगाए जाने की नभी कोशिशों का सरकार विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हमें सार्वजिन कर्मचारियों की मभी न्यायोचित कार्रवाइयों का समर्थन फरना नाहिए और सरकारी पर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी जाद-पड़ताल की गई जिसका प्रस्ताव किया गया है तो कानून और व्यवस्था को मुरक्षित रसना असभद हो जायगा। दृह निर्में और राजभक्त पुलिन और सरकारी कर्मचारियों के विना इस मभा अथदा ऐसी ही जान्य सस्याओं के किसी आदेश को कार्यन्वित करना असम्भद हो जायगा। धारत-सरकार-आरा उपवर्षों के नम्बन्ध में प्रकाशित की गई प्रकाशित की गई पुल्तिका जी

व्यवहार में व्यापक सशोधन करने की सिफारिश और केन्द्रीय असेम्वली के सदस्यों को जेलों में जाकर राजनीतिक विन्दियों से मुलाकात करने के लिए इजाजत देने का आग्रह किया गया था, ताकि उन पर लगाए गए प्रतिवन्य कम किये जा सके ओर उन्हें आवश्यक सुविधाए प्रदान की जा सके। इस प्रस्ताव के बारे में सरकार के एख का स्पष्टीकरण करते हुए गृह-सदस्य सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने कहा, "मौजूदा आन्दोलन के सिलसिले में नजरवन्द किये गए मुरक्षा-विदयों पर लगाए गए प्रतिवन्धों में फिलहाल किसी किस्म की नरमी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी तक लडाई जारी है।"

यह प्रसग समाप्त करने के पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्य में वाइसराय की शासन-परिपद् के कितपय भारतीय सदस्यों के विचारों का सक्षेप में उल्लेख करना सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है। राजपरिपद् में २४ सितम्बर १९४२ को भाषण देते हुए माननीय सर जोगेन्द्रसिंह ने कहा —

"हमे काग्रेस और लींग को भुला देना चाहिए। हमे उन सिद्धातों के पीछे पड़ कर अपना और समय नहीं गवाना चाहिए, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। राजाओं और जनता के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और वर्तमान गतिरोध को दूर कर के एक संयुक्त मांग पेश करनी चाहिए।"

दिसम्बर मे, वम्बई के भारतीय व्यापार-मडल द्वारा पेश किये गए मानपत्र

का उत्तर देते हए माननीय श्री एन० आर० सरकार ने कहा —

"आदर्शवाद की बात एक ओर रहने दीजिए, केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनो ही सरकारों के शासन-सचालन में, और अपने जीवन के सर्वोत्तम भाग में देश के व्यापारिक-क्षेत्र में मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण उन्नित् करने के उद्देश्य से भारत के लिए अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।"

ओटावा मे २२ दिसम्बर को भाषण देते हुए न्निटेन के युद्ध-मन्त्रिमंडल में भारत के प्रतिनिधि सर ए० रामस्वामी मुदालियर ने कहा, "भारत की जनता अपने राजनीतिक पद के निर्धारण के लिए अत्यधिक व्यग्र है और उसमें पाए जानेवाले मतभेद का आधार उस उद्देश्य के सम्बन्ध में न होकर उसे प्राप्त करने के विभिन्न साधनों के सम्बन्ध में है।"

गैर-सरकारी प्रतिक्रिया

किसी भी अवसर पर जनता ने काग्रेस के प्रति इतनी गहरी सहानुभूति प्रकट नहीं की थी, जितनी इस बार, जबिक काग्रेस-द्वारा अपना आन्दोलन शुरू करने से पहले सरकार ने उस पर एक जोरदार आक्रमण कर देश में हिंसा और दमन का साम्राज्य स्थापित कर दिया था। यह केवल पीडित लोगो के प्रति सहानुभूति ही नहीं थी, विल्क सरकार से एक जोरटार मांग थी कि वह स्वय अपने पदा किये हुए गितरोय का निराकरण करें और यह माग ऐसे प्रमुख व्यक्तियों और वटी-वड़ी मस्याओं की ओर से की जा रहीं थीं जो कुछ समय पूर्व तक भारत में ब्रिटिश सरकार की ढाल वने हुए थे। सर शादीलाल, सर चिमनलाल सीतलवाड, सर तेजवहादुर मप्रू, सर ए० दलाल, सर मिर्जा इस्माइल, सर एस० राधाकृष्णन्, राइट आनरेवल बी० श्रीनिवास गास्त्री और राइट आनरेवल श्री एम० आर० जयकर जैसे वडे-बटे व्यक्तियों, व्यापारमडलो, व्यापारमण्डल-सघो, ट्रेड यूनियनो, पारमी-सघो, वगाल और पजाव के यूरोपियन एसोसियेशनो, विहार और वम्बई के एडवोकेट जनरलो, श्री विश्वास सरीखे हाईकोर्ट के जजो, कलकत्ता के लाट-पादरी जैमे प्रमुख धार्मिक नेताओं, ईसाई और साम्यवादी नेताओं, निर्दल नेता-सम्मेलन और महिला सम्मेलन प्रभृति देश की प्रमुख सस्थाओं के एकस्वर होकर सरकार से स्थिति पर पुन विचार करने और गितरोध को शिघ्र ही दूर करने का आग्रह करने पर भी यदि सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती तो साफ जाहिर है कि उनके दिमाग में कोई ऐसा वहा विकार या खराबी आ गई थी कि वह स्वय अपने भूतपूर्व समर्थकों की भी वात मानने को तैयार नहीं थी।

और एडवोकेट जनरल का नाम मोतीलाल सी॰ सीतलवाड था, जो सर चिमनलाल सीतलवाड के पुत्र थे और जो पाच साल तक इस पद पर काम कर चुके थे। दूसरे एडवोकेट विहार के श्री वलदेवसहाय थे, जिन्होने अपने इस्तीफे के थोड़ी देर वाद ही सुलह-सफाई के सम्बन्ध में जोरदार अपील की।

इस सम्वन्य में महाराजा होल्कर ने भी एक अत्यन्त रोचक और दिलचस्प वक्तव्य दिया। भारतीय व्यापार-मण्डल के प्रघान श्री जे० सी० सीतलवाड ने गाघीजी और नेहरूजी जैसे नेताओ को जेल में बन्द कर दिये जाने की निन्दा करते हुए उन लोगो के रुख पर खेद प्रकट किया जो इस आन्दोलन के लिए इन नेताओ को वदनाम कर रहे थे और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्ही पर डाल रहे थे। १५ दिसम्बर १९४२ को निर्दल सम्मेलन की स्थायी समिति ने भी एक जोरदार वक्तव्य प्रकाशित किया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस की जनरल कौसिल ने ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनो और मजदूर दल से महात्मा गाघी, मीलाना आजाद और दूसरे काग्रेसी नेताओ को तत्काल रिहा करने और भारतीय जनता को तत्काल सत्ता सौपने की भारतीय माग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से अनुरोध करने की अपील की, क्योंकि नेताओं के जेल में रहते हुए किसी किस्म का समझौता सम्भव नही था। वम्बई के रहनेवाले ६०० से भी ऊपर पारिसयों ने अपने हस्ताक्षरो से एक वक्तव्य जारी किया जिसमे उन्होने यह घोषणा की कि भारत के नये विवान मे उन्हें किसी किस्म के भी सरक्षण नही चाहिए। यह वक्तव्य कामन-सभा में दिए गए श्री सी० आर० एटली के उस वक्तव्य के जवाव में था, जो कि उन्होने भारतीय स्वाधीनता के बारे में दिया था जिसमें उन्होने कहा था-"भारत में सिक्खो, पारसियो, नरेशो और रियासती जनता जैसे वहुत से बडे प्रभावगाला अल्पसंख्यक मीजूद है, जिनके हितों की ओर हमें खास तौर पर घ्यान देना है।" नवम्बर मे एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन के सम्मुख सर ्तेजबहादुर सप्रू ने यह सुझाव रखा कि वाइसराय को चाहिए कि वह राष्ट्रीय आदोलन के अध्यक्ष के रूप में सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाए, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस-चासलर सर एस० राधाकृष्णन ने २९ नवम्बर को विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर अभिभाषण देते हुए कहा-"हमें सदियो की अपनी निद्रा का त्याग कर अपना मस्तक ऊँचा उठाना चाहिए।" वगाल चेम्बर की वार्षिक साधारण बैठक के अध्यक्षपद से भाषण देते हुए श्री आर्० आर० हैडाऊ ने कहा, "भारत-द्वारा पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में हमारा उससे कोई झगडा नहीं है, लेकिन उसी प्रकार हम यह वात भी रहस्य के गर्भ में छिपाकर नहीं रखना चाहते कि हमने भारत की उन्नति में जो महान् भाग लिया है और अब तक ले रहे हैं, उसके लिए हमें पूर्ण आश्वासन और सरक्षण दिया जाय।" नवम्बर के मध्य में 'हिन्दू' के बम्बई-स्थित सवाददाता

खुला विद्रोह: १९४२

से अपनी एक भेट में डा॰ अम्बेडकर ने यह राय प्रकट की कि इस वक्त भारत में कोई राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान राजनीतिक गितरोध की वजह इस देश के बहुसख्यक और अल्पसख्यकों का पारस्परिक अविन्वास है और भारत की भावी स्थिति को सुलझाने के लिए हमें युद्ध समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना बेहतर है। बाद में डा॰ अम्बेडकर ने गांधीजी और श्री जिन्ना की तुलना करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताओं को भारतीय राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। डा॰ अम्बेडकर के इस वक्तव्य का जवाब देते हुए प्रोफेसर अब्दुल मजीद खाँ ने कहा — "गांधीजी की श्री जिन्ना से तुलना करते समय डा॰ अम्बेडकर स्वय अपनी ही वाक्पटुता के चक्कर में फँसकर अपने को भूल गए। बास्तव में इन दोनों में किसी तरह की तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है और दोनों एक-दूसरे से सर्वथा विभिन्न हैं। कितने अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि डा॰ अम्बेडकर दूच और पानी में भी भेद न कर सके।"

अब हम सिन्ध की सब से अधिक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहते है। २६ सितम्बर, १९४२ को सिन्च के प्रधान मन्त्री खान वहादुर अल्लाहबस्य ने ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोघ स्वरूप वाइसराय को एक पत्र लिखा जिसमे उन्होने अपनी 'खान वहादुर' और 'ओ० वी० ई०' की उपाधियों के परित्याग करने की घोषणा की थी। २६ सितम्बर को एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में अपने इस निर्णय की घोषणा करते हुए सिन्ध के बड़े वजीर ने कहा कि ब्रिटेन की नीति, ''भारत मे अपने साम्राज्य को कायम रखने, और इस देश को परतत्र बनाए रखने, उसके राजनीतिक और साम्प्रदायिक मतभेदो को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करने और राष्ट्रीय ताकतो को कुचल कर अपने ही स्वार्यों को पूरा करने की है।" इस सम्मेलन में उन्होने वाइसराय के नाम भेजे गए अपने पत्र को भी पढ़कर सुनाया। एक सवाल के जवाव में उन्होने कहा कि उन्होने एक ओर साम्राज्यवाद और दूसरी ओर नाजीवाद और फासिस्टवाद से दुहरा युद्ध करने की ठान ली है। उन्होंने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है और प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य हैं कि वह अपने देरा पर आक्रमण करने वाली किसी भी शक्ति का उटकर मुकावला करते हुए देग की रक्षा करे।

मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया

जैसी कि आगा थी, कांग्रेस के प्रस्तावित लान्दोठन के सम्बन्ध में लीग की प्रतिक्रिया बनुक्ल अयवा तटस्य नहीं हो सकती थी। लीग काग्रेम का ज्ला विरोध ही नहीं कर रहीं थी, बल्क वह कार्यम-द्वारा आजादी प्राप्त करने के प्रत्येक व्यावहारिज प्रयास का भी विरोध करनी थी, जब काग्रेस के प्रति उसे अपने इतने विरोध

से ही सतोप न हो सका, तब १९४१ में मद्रास में होने वाले अपने वार्षिक अधिवेशन में उसने अपने घ्येय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना अथवा मुस्लिम-बहुल प्रान्तों का एक पृथक् स्वायत्त-शासन प्राप्त सघ बनाना भी शामिल कर लिया। दिन-प्रति-दिन, सप्ताह-प्रति-सप्ताह और मास-प्रति-मास लीग का सारा प्रयत्न और घ्यान पाकिस्तान की ओर लगने लगा और बहुत सी घटनाओं के कारण लीग का प्रभाव बढ गया। पाच प्रान्तों में स्वायत्त-शासन-प्रणाली के अन्तर्गत मित्र-मडल बनाने के फलस्वरूप कुछ सीमा तक उसकी शक्ति और भी वढ गई।

मुस्लिम लीग की विकित कमेटी ने २२ अगस्त, १९४२ को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें उसने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के लिए आत्म-निर्णय का अधिकार प्रदान करने और पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसलमानों के मतदान के बाद तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करने की माग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी से देश में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जिससे कि देश की रक्षा और युद्ध के सफल सचालन के लिए भारत के सभी साधनों का सगठन किया जा सके। इसके कुछ समय बाद ही २५ अगस्त को अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय की शासन-परिषद् के रक्षा-सदस्य सर फीरोज खा नून ने भारत को पाच स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों में विश्वविद्यालय उपविदेशों में विश्वव

"मै चाहता हूँ कि ब्रिटिश भारत पांच स्वाघीनता-प्राप्त उपनिवेशो मे विभक्त कर दिया जाय — (१) बगाल और आसाम, (२) मध्यप्रान्त, उत्तर प्रदेश और बिहार, (३) मद्रास अर्थात् द्राविडी, (४) बम्बई अर्थात् महाराष्ट्र और (५) पजाव, विलोचिस्तान, सिन्ध और उत्तर-पिश्चम सीमा प्रान्त । ये पाचो उपनिवेश न्यूजीलैण्ड, जिसकी जनसख्या १५ लाख है, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जिनमे से प्रत्येक की जन-सख्या ७० या ८० लाख है, की भाति पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं। किन्तु कुछ ऐसी भी बातें हैं, जिनके लिए एक केन्द्रीय सत्ता और सब उपनिवेशों की तरफ से सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। ये विषय, मेरे विचार से रक्षा, कस्टम (आयात-निर्यात-कर), पर-राष्ट्र सम्बन्ध और मुद्रा हैं। इन चारो विषयो के प्रबन्ध के लिए मैं एक केन्द्रीय सरकार की रचना का पक्षपाती हूँ, जिसमे पाचो उपनिवेश-सरकारो-द्वारा नामजद किए हुए प्रतिनिधि सम्मिलित हो। ये प्रतिनिधि तब तक अपने पदो पर बने रहेंगे जब तक कि नियुक्त करने वाले अधिकारी अपने उपनिवेशो में शासनारूढ रहेंगे। परन्तु यह बात इस मह-त्वपूर्ण शर्त के साथ लागू होगी कि यदि किसी समय किसी उपनिवेश को केन्द्रीय

शासन के सचालन से असतोष होगा तो उस उपनिवेश को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्र से पृथक हो जाय, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी रहेगी कि इस खुला विद्रोह: १९४२

प्रकार पृथक् होने वाला उपनिवेश मतभेद दूर हो जाने पर फिर केन्द्र में प्रविष्ट हो सके।"

वम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने कहा.---

"मुझे अत्यत खेद है कि आखिरकार काग्रेस ने रणभेरी छेड ही दी और उसने देश के विभिन्न व्यक्तियो, दलो और सगठनो-द्वारा दी गई चेताविनयो की तिनक भी परवाह न कर एक अत्यन्त खतरनाक सामूहिक आन्दोलन शुरू कर दिया। यह यकीन करना असम्भव है कि काग्रेस के नेता यह बात न जानते थे कि इस तरह के आन्दोलन का परिणाम हिंसा, रक्तपात और बेगुनाह लोगो का विनाश होगा। यह और भी अधिक खेदजनक है कि यह आन्दोलन इस सकटपूर्ण घडी में शुरू किया जा रहा है और इसका वास्तविक उद्देश्य सगीनो का भय दिखा कर जबरदस्ती अपनी मागे मनवाना है और अगर काग्रेस के इस धृष्ठतापूर्ण रुख और उसकी मनमानी एवं उत्तरदायित्विवहीन चुनौती से डर कर उसे खुश करने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण और दूसरे सभी प्रकार के हितो का विशेषकर मुस्लिम भारत के स्वार्थों का बिलदान होगा।" सितम्बर में एक भेट में उन्होने कहा —

"अखिल-भारतीय महासमिति की अन्तिम बैठक के अन्तिम अधिवेशन में गांधीजी ने यह बात बहुत जोर देकर कही थी कि केवल काग्रेस ही भारत की एकमात्र प्रतिनिधि-सस्या है। यही बात पण्डित नेहरू ने भी कही, लेकिन वह उनसे भी आगे बढ गए और कहा कि मुस्लिम-लीग एक प्रतिक्रियाबादी सस्या है और मुस्लिम जनता उसके साथ है तथा काग्रेस ही समस्त देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सस्या है। यह बात केवल भारत में ही नहीं कहीं गई, बिल्क इसका ढिढोरा सारी दुनिया में पीटा गया और चूँकि उन देशों की जनता भारत की वास्तिविक परिस्थित से परिचित नहीं है, इसिलए वह इस पर यकीन कर लेती है। यह दूषित और सगिठत प्रोपेगैंडा जनता को धोखें में रखने की गरज से किया जाता है और अगर आप श्री चिंचल का भाषण पढ़ कर देखें तो आप जान जाएगे कि उन्होंने काग्रेस के इस दावे का खण्डन किया है।"

युद्ध-प्रयत्न के सम्वन्व में एक अमरीकी सवाददाता के प्रश्न के जवाव में श्री जिन्ना ने निम्न वक्तव्य दिया — "मुस्लिम-लीग युद्ध-प्रयत्न में सहयोग नहीं दे रही है। इसकी वजह यह नहीं है कि वह इसका विरोध करती है, विल्क यह है कि वह तब तक युद्ध-सचालन में हार्दिक सहयोग और सहायता प्रदान करने को तैयार नहीं है जब तक कि जनता यह न अनुभव करने लग जाय कि देश के शासन-संचालन में उसका वास्तविक हाथ है। परन्तु हम ब्रिटिश सरकार की नीति की चाहे कितनी ही निन्दा क्यों न करे बयवा उस पर कितना ही खेद क्यों न प्रकट करें, पिछले तीन साल में हमारी हाउत एक खरवूजे जैसी रही है। चाहे खरवूजा छुरी पर रहे बयवा

छुरी खरवूजे पर रहे-दोनो ही तरह से नुकसान तो वेचारे खरवूजे का ही है। गला तो उसीका कटेगा। मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार की नीति से तंग बा कर मैं गुस्से में कल से यह कहने लगू कि 'ब्रिटिश सरकार को परेशान करो और उसके साथ असहयोग करो'—तो आप यकीन रिखए कि इसकी वजह से आज की अपेक्षा हमें पाच सौ गुना अधिक मुसीवतें झेलनी पडेंगी। यह सवाल कोई बन्द्रको का नहीं है, इस तरह से तो मुसलमानों के पास पाच सौ गुना ज्यादा वन्दूकें हैं। मैं यद्यपि हिन्दुओं को भला-बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन भारत में कोई भी विवेकशील व्यक्ति आपको यह वता देगा कि यह तो उन (हिन्दुओ) का स्वभाव ही है और उन्हें इसी वातावरण में पाला-पोसा गया है । लेकिन में स्वय अपने से ही पूछता हू कि क्या यह ठीक है कि हम पाच सौ गुना अधिक तकलीफें दे सकते हैं, पर सवाल तो यह है कि बाखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? मुझे तो इसके केवल दो ही परिणाम दिखाई देते हैं--पूर्व, परिचम, दक्षिण अय्वा उत्तर किसी भी दिशा से विदेशी आक्रान्ता इस देश पर छा जायगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर भला मेरी कुर्वानियों से क्या लाम होगा ? और अगर दूसरे दल मेरे साथ नहीं है तो इसका परिणाम गृह-युद्ध होगा। दूसरा परिणाम मुझे यह दिखाई देता है कि अगर मुसलमान इस विद्रोह की आग लगाते हैं और वे ब्रिटिश सत्ता को पंगु बना देने के काम में सफल भी हो जाते हैं,तव भी मेरा खयाल है कि उसकेपरिणामस्वरप भारत के टुकडे-टुकडे हो जायगे। चाहे मैं ब्रिटेन की नीति की कितनी ही निन्दा क्यों न करूँ और इस वारे में जोरदार विचार प्रकट करूँ, फिर भी जब मैं इन परिणामो की वात सोचता हूँ तब मै इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मेरी स्थिति खरवूजे से भिन्न नही है।'

श्री जिन्ना का सब से अधिक अनोखा रख उस वक्त प्रकट हुआ जव कि उन्होंने 'न्यूज क्रानिकल' के सवाददाता से एक भेंट में १३ अक्टूबर को जोरदार शब्दों में यह कहा कि "भारत कभी भी अपनी समस्याओं का हल ढूँढने में सफल नहीं हो सका है, और अतीत में सदैव बिटेन ने अपना हल भारत के ऊपर लादा है। इस समय वह ब्रिटेन से यह पक्का वादा ले लेना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद उन्हें पाकिस्तान मिल जायगा और इसके बदले में वह एक अस्थायी सरकार में इस शर्त पर शामिल होने को तैयार होगे कि उन्हें भी हिन्दुओं जितनी ही सीटे मिले।" आगे उन्होंने कहा, "अगर ब्रिटिश सरकार कल ही ऐसा कोई आश्वासन दे दे तो मेरा खयाल है कि हिन्दू-भारत इस प्रत्यक्ष और अनिवार्य परिणाम को स्वीकार कर लेगा।"

इस समय सर सिकन्दर हयात खा ने पजाब की अन्त साप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए एक हल निकाला। उनकी योजना के अन्तर्गत पंजाब को दो हिस्सो में बाँट देने की बात कही गई थी—पूर्वी और पश्चिमी भाग। परन्तु यह विभाजन उसी हालत में किया जाना था जब वर्तमान मताधिकार के आधार पर निर्वाचित आगामी प्रान्तीय धारासभा के ७५ प्रतिशत सदस्य यह फैसला करें कि पजाब प्रस्तावित सघ में शामिल नहीं होगा। उस अवस्था में धारासभा के मुसलमान और गैर-मुसलमान सदस्य ६० प्रतिशत बहुमत से यह फैसला कर लें कि क्या उन्हें अपने-अपने सम्प्रदाय के लिए पृथक्-पृथक् राष्ट्र स्थापित करने चाहिए या नहीं। परन्तु इसका फैसला जनता की मतगणना के जरिये ही किया जाय और केवल वही लोग इसके लिए वोट दे जिन्हें ऐसा करने का हक हासिल हो। यदि मुस्लिम-बहुल आवादी वाला पश्चिमी प्रदेश प्रस्तावित संघ से अलग रहने का फैसला करें तो पूर्वी पजाब के हिन्दू और सिक्ख बहुल इलाके को भी हक हो कि वह अपनी इच्छा से भारतीय सघ में शामिल हो जाय। लेकिन इतने पर भी सर सिकन्दर ने एक ही राष्ट्र का प्रतिपादन करते हुए गुरु नानक के जन्म-दिवस पर दिसम्बर १९४२ में कहा कि, "हम एक ही राष्ट्र है और हमारा एक ही देश है।" दिसम्बर में भारत और इंग्लैण्ड दोनो ही जगह मुगल सम्राट् अकबर की ४०० वी सालगिरह मनाई गई। लन्दन के समारोह में श्री एमरी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीयों को अकबर की नीति पर चलने की सलाह दी।

इन्ही दिनो सर मोहम्मद जफरुल्ला खा प्रशान्त सघ के सम्मेलन में भाग लेने अमरीका गए हुए थे। न्यूयार्क से केनेडा जाते हुए उन्होने भारतीय समस्या को सुलझाने के लिये दो तरीके बताए। उन्होने कहा कि पहला तरीका यह है कि काग्रेस उत्तर-पूर्व और उत्तर-पिक्चम के इलाकों में पाकिस्तान की स्थापना के सम्बन्ध में श्री जिन्ना की माग स्वीकार कर ले। दूसरा यह कि अग्रेजों को भारत छोड़ कर चले जाने की माग करने से पूर्व महात्मा गांधी, पिडत नेहरू और उनके अन्य सहयोगियों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि "मुसलमानों का डर उचित है और इसिलए उन्हें एक ऐसा समझौता कर लेना चाहिए जिसके अन्तर्गत मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था कर दी गई हो।"

लीग के सभी अनुयायी उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। एक विचारपत्र में मुसलमानों की ओर से भारत में ब्रिटिंग हुकूमत खत्म किये जाने, नेताओं की रिहाई और जिन्ना से काग्रेस के साथ फिर समझौते की वातचीत शुरू करने की माग की गई। इसके अलावा इसमें तत्काल काग्रेस और लीग में समझौते और एकता की आवस्यकता और इस संकटपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में विदेशी आक्रमण के विरद्ध भारत की रक्षा के लिए एक अस्यायी राष्ट्रीय मरकार की स्थापना की भी जोरवार माग की गई।

नवम्बर १९४२ के मध्य में दिल्ली में श्री जिन्ना ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान हासिल करने के लिए कटिवद्ध रहने की अपील करते हुए कहा कि या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेगे और या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देगे।
१९१७ में श्री जिन्ना एक सयुक्त भारत के जवरदस्त हामी थे, लेकिन १९४२ में
हम देखते हैं कि वह अपने इस उच्च आदर्श से कितना नीचे गिर गये थे। १९४२
(दिसम्बर) में कलकत्ता के फेडरेशन आफ (यूरोपियन) चैम्बर्स आफ कामलं
के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय ने भारत की 'भौगोलिक एकता' पर जोर
देकर मुस्लिम लीग की माग पर पानी फेर दिया था। इसके वाद भारत ने प्रस्थान
करने से पूर्व नरेन्द्र मण्डल के सम्मुख दिए गए अपने भाषण में भी लार्ड लिनलियगों
ने भारत के लिए सघ-योजना का जोरदार समर्थन कर लीग के इस आदर्श पर
अपना अन्तिम प्रहार किया था। इसी वीच सिन्च में श्री अव्हुल मजीद और सिन्ध
असेम्बली के दो और सदस्यों ने मुस्लिम लीग से इस्तीफा दे दिया।

आजाद मुस्लिम कान्फ्रेस ने दिल्ली में हुई अपनी एक बैठक मे निम्न प्रस्ताव पास किया—"आजाद मुस्लिम वोर्ड की यह सभा भारत के लोगो से अपील करती है कि वे इस महान् सकट के अवसर पर देश और जाति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अन्तर्साप्रदायिक एकता और विश्वास की दृढ भावना पैदा करने के लिए अपनी कोई कसर न उठा रखें। साप्रदायिक समस्या के निवटारे के सिलिस में काग्रेस इतना आगे वढ चुकी है कि उसके नेताओं के साथ और समझौता करके युद्धोत्तरकालीन वैचानिक फैसले में किसी भी सप्रदाय के हितो और अधिकारों को नुकसान पहुचाए बिना ही युद्धकाल तक के लिए एक अस्थायी सयुक्त सरकार की स्थापना की जा सकती है।"

भारत की भावी स्थित से सम्बन्ध रखनेवाली सपूर्ण समस्या के प्रति श्री जिन्ना के एख का उनके धर्मावलवियों की एक बड़ी सख्या समर्थन नहीं कर रहीं थीं और इसकी पुष्टि इस वात से हो जाती है कि पाकिस्तान की योजना के खिलाफ लड़ने के लिए जून १९४३ के मध्य में शेख महम्मद एम० एल० सी० की अध्यक्षता में 'मुस्लिम मजलिस' नाम से एक नये मुस्लिम सगठन की नीव रखीं गई जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में था। अखबारों के नाम जारी किये गए अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा—"पिछले दो वर्षों से श्री जिन्ना ने बारंबार कोई-न-कोई वहाना करके काग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और उन्हें यह बताने की कोशिश भी नहीं की कि पाकिस्तान की योजना या मुसलमानों के लिए आत्मिनर्णय के अधिकार से उनका वास्तिवक अर्थ क्या है। काग्रेस से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की उनकी माग के कारण उनके कट्टर समर्थकों को भी यकीन हो गया है कि श्री जिन्ना को न तो भारत की आजादी की परवाह है कि भारत की आजादी और पाकिस्तान को खो देने का खतरा उठा कर भी किसी-न-किसी प्रकार उनकी मौजूदा अनुचित स्थित बनी रहे। इस मजलिस के तीन

उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य भारतीय-समस्या का हल ढूँढने के लिए अन्य दलों के साथ मिलकर देश के वर्तमान गितरोध को दूर करना हे, दूसरा उद्देश्य भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक स्वतत्रता की प्राप्ति और तीसरा न केवल भारत के मुसलमानों की जन-सख्या को देखते हुए ही, विल्क भारत में मुसलमानों की विशिष्ट परिस्थिति और इस उप-महाद्वीप में उसके महत्व का खयाल रखते हुए उनके अधिकारों का सरक्षण करने की व्यवस्था है। इसके अलावा मजिलस का एक और उद्देश्य भारत के विभाजन का विरोध करना है, क्योंकि यह न केवल अव्यावहारिक और भारत की आजादी को नुकसान पहुचाने वाला है, विल्क उनमें भारतीय मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुचेगा।

हिन्दू-सभा की प्रतिक्रिया

समय-समय पर भारतीय राजनीतिक आकाश मे विभिन्न राजनीतिक अथवा सामाजिकता-युक्त राजनीतिक सस्थाओं ने जन्म लिया है। इनमें से पुरानी राष्ट्रीय महासभा और सब से छोटी एव नवीनतम सस्था हिन्दू महासभा है। २९ दिसम्बर १९४२ को कानपूर में उसका २४ वा अधिवेशन हुआ था । जिस प्रकार काग्रेस और लीग को भारत-सरकार ने सदा से अधिकृत संस्थाओं के रूप में स्वीकारकर लिया था, उसी प्रकार उसने ८ अगस्त १९४० वाले वक्तव्य मे पहली वार हिन्दू महासभा को भी एक अधिकृत सस्था मान लिया था। गाधीजी और उनके साथियो की गिरफ्तारी के अवसर पर श्री सावरकर ने हिन्दुओ को सलाह दी कि वे ''काग्रेस-आन्दोलन में किसी प्रकार की भी मटद न करें।" इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं थी, क्योकि वह भारतीय राप्ट्रवाद के स्थान पर हिन्दुत्व और हिन्दू साप्रदायिकता का प्रचार करते रहे थे। काँग्रेस के जेल जाने के बाद मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में मित्रमङ्ल बनाने में उन्होने विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग कारणों से हिन्दुओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन इन सभी मामलो मे वास्तव मे वह मुस्लिम लीग की नीति का अनुसरण कर रहे थे। लीग की भाति उन्हें भविष्य के बजाय अपने तात्कालिक उद्देश्य की अधिक परवाह थी, भारतीय आजादी के वजाय साप्रवायिक लाभ का अधिक ध्यान था और ब्रिटेन के विरद्ध लड़ने के बजाय उसके नाथ मिल कर काम करने की नीति अधिक पसन्द थी।

भारतीय ईसाइयों की प्रतिक्रिया

जैसी कि आशा की जाती थी, अगस्त-प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारतीय ईसाइयों की पितिजिया अच्छी और सनोपजनक रही। मार्च में दिल्ली में होनेवाले अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन के २५ वे अधिवेशन के नाम अपने स्वागन-सन्देश में सर फेटरिक जेम्स ने कहा कि यह सम्मेलन भारत में सुलह-सफाई कराने के लिए एक सर्वथा उचित साधन सिद्ध हो सकता है। काफ्रेस के मम्मुख भापण देते हुए पण्डित कुजरू ने कहा कि एक ऐसे समय में जब कि देग के विभाजन का धतरा बढता जा रहा हे, केवल यही एकमात्र सस्था है जो देग की एकता का प्रतिपादन करती हुई साम्प्रदायिक हितो का धयाल न कर के देग के हितो को मर्वोपिर स्थान देने को तैयार है। इसके अलावा भारतीय ईसाई स्वय भी चूकि एक अल्पसत्यक हैं, इसलिए वे साधारणत दूसरे अल्पमतो की कठिनाइयो और दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सर महाराजिसह ने अध्यक्षपद से भापण देते हुए माप्रदायिक समस्या को सुलझाने, गांधीजी को रिहा करने, भारतीय राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए सभी प्रमुख दलों की एक गोलमेज-परिपद बुलाने और लडाई के समाप्त होने तक पाकिस्तान के बारे में अन्तिम निर्णय स्थिगत करने की जोरदार अपील की। इसके अलावा सम्मेलन ने यह सुझाव भी पेश किया कि अगर विभिन्न सम्प्रदायों में कोई समझीता न हो सके तो 'इस समस्या का फेसला एक अन्तर्राष्ट्रीय पच से करा लिया जाय।' साप्रदायिक समस्या को मुलझाने के अलावा सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार से लडाई खत्म हो जाने के बाद दो साल के भीतर भारत को पूर्ण आजादी देने की स्पष्ट घोषणा करने के लिए भी कहा।

: २0:

ःडपवास और उसके वाद : १६४३

उपवास का श्रारंभ

गाधीजी और उनके सहयोगियों को जेल में गए हुए लगभग छ महीने होने को आए थे। वम्बई में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने अपने मित्र वाइसराय को पत्र लिखने की घोपणा की थी। स्वतंत्र रहते हुए उन्हें जो बात लिखने की इजाजत नहीं दी गई थी, उसे उन्होंने आगाखा महल से एक नजरबन्द कैदी की हैसियत से लिखने का साहस किया। उसी वक्त किसी तरह यह खबर समाचार-पत्रों को भी लग गयी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उन्होंने क्या लिखा है और न कोई यहीं कह सकता था कि जो कुछ उन्होंने सितम्बर १९४२ में लिखा है, वह वहीं है जो वह जेल से बाहर रहने पर ९ अगस्त को लिखते। इस दौरान में गाधीजी और उनके अनुयायियों पर अनेक तरह के लाछन और दोप लगाए गए। उन्हें झूठा कहा गया। उनके इरादों और मकसदों के बारे में सन्देह प्रकट किया गया। जनता को बताया गया कि वह

चुपचाप आदोलन की तैयारिया कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने जरूरी हिदायते भी जारी की हैं। उन्होंने अनैतिकता से काम लिया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए इन सब बातों का खण्डन करना उनका आवश्यक कर्तव्य हो गया था। लेकिन वह ऐसा करने में स्वतन्त्र नहीं थे, यद्यपि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि उन्हें अपने विचारों का खण्डन-मडन करने की पूरी स्वतन्त्रता है, तथापि सिद्धात-प्रिय और सत्य, अहिसा एवं प्रेम के पुजारी व्यक्ति के पास एक उच्च शक्ति का सहारा लेने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था। इस उच्च शक्ति का सहारा उन्होंने उपवास के रूप में लिया।

गांवीजी के उपवास का समाचार पहले-पहल जनता को केवल १० फरवरी और विकंग-कमेटी के सदस्यों को अहमदनगर किले में ११ फरवरी को मिला। यदि उनकी गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के भीतर ही उनके सेकेटरी श्री महादेव देसाई की अचानक मृत्यु न हो गई होती तो वह यह उपवास बहुत पहले ही गुरू कर देते। इस सबब में ५ फरवरी १९४३ को लार्ड लिनलियगों ने गांघीजी को जो पत्र लिखा उसके निम्न अब से उन (लिनलियगों) की निर्भयता और निर्दयता पर प्रकाब पडता है —

"आप इस वात का यकीन रिखए कि काग्रेस के ऊपर जो इलजाम लगाए गए है, उनका उसे एक-न-एक दिन जवाब देना ही होगा और उस समय आपको और आपके साथियों को, अगर हो सके तो, दुनिया के सामने अपनी सफाई देनी पढ़ेगी। और यदि इस दौरान में किसी ऐसी कार्रवाई के जिरये, जिसकी आप इस समय कल्पना कर रहे प्रतीत होते हैं, अपने आपको इस तरह से आसानी से वचा लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट बतादूं कि फैसला आपके खिलाफ जायगा।" परन्तु इस निन्दनीय आरोप के बावजूद भी गांधीजी ने अनवन आरम्भ किया।

उपवास को प्रगति

गावीजी के उपवास की सूचना जनता को जल्दी-से-जल्दी उसके दूसरे दिन और साधारणत तीसरे दिन मिली। सौभाग्यवश श्रीमती कस्तूरवा गावी और मीरावेन के अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू भी इस अवसर पर गावीजी के पास थी। आगाखा महल से कुछ ही दूर यरवडा जेल में डा॰ गिल्डर भी नजरवन्द थे। इस मौंक पर उन्हें ११ फरवरी को आगाखा महल जाने की इजाजत दें दी गई और इस प्रकार डा॰ गिल्डर भी गावीजी के पास पहुंच गए। गावीजी को केवल दो घण्टे के लिए हर रोज वाहर बरामदे में लाया जाता था। उपवास के चीथे दिन से उनका जी सचलने और नीद न अने के कारण १५ फरवरी को उनकी होएत १४ फरवरी की तरह सन्तोपजनक नहीं थी। बेचैनी रहने

और पानी पीने में कठिनाई होने के कारण घीरे-घीरे गायीजी की हालत विगडने लगी। १५ फरवरी को डा० विवानचन्द्र राय भी पूना पहुँच गए और वह ३ मार्च तक वही रहे। कान, नाक और गले के एक विशेषज्ञ टा॰ माडलिफ ने भी गाधीजी की परीक्षा की। उपवास के दूसरे सप्ताह में गावीजी की आम हालत के बारे में चिन्ता होने लगी। १६ फरवरी के वार्द में नित्य प्रति उनकी मालिक की जाने लगी। अगले दिन हृदय-गति मन्द पडने लगी। १९ फरवरी के वाद से छ डाक्टरो-श्री एम० डीं० डी० गिल्डर, मेजर-जनरल कैण्डी, बम्बई के सर्जन-जनरल, डा० वी० सी० राय, लेपिटनेन्ट-कर्नल भण्डारी, आई० जी० पी०, डा० सुजीला नायर और लेपिटनेन्ट-कर्नल बी० जे० जाह के हस्ताक्षरों से बम्बई-सरकार की ओर से गाधीजी के स्वास्थ्य के बारे में बुलेटिन प्रकाशित होने लगे। गाधीजी बोलना नही चाहते ये और न वह अपने दर्गको से मिलना चाहते थे। यह देखकर डाक्टरों को वडी चिन्ता होने लगी। १९ तारीस को गांधीजी को श्री मोंदी, श्री सरकार और श्री अणे के इस्तीफे की सूचना दी गई। इससे वह कुछ मुस्कराए। २० फरवरी के बुलेटिन में बताया गया कि गाधीजी की हालत राराव होगई है और वहुत गम्भीर है। २१ फरवरी को अर्थात् उपवास के बारहवे दिन बताया गया कि वै दिन भर बहुत वेचैन रहे। दोपहर को ४ वजे उनकी हालत खतरनाक हो गई और वह प्राय वैहोग हो गए। उनकी नव्ज इतनी हल्की होगई कि उसे प्राय पहुंचानना कठिन हो गया। बाद मे वह नीवू के मीठे रस के साथ पानी पी सकने ने समर्थ हो सके। उस दिन वह खतरे से बाहर हो गए और रात को ५॥ घण्टे सोए। २२ फरवरी को गायीजी का मीन दिवस था। वह आराम अनुभव कर रहे थे और अधिक प्रसन्न दिलाई देते थे, लेकिन हृदय कमजोर था। तीँसरे सप्ताह का प्रारभ होने पर पेशाव की शिकायत धीरे-धीरे दूर होने लगी और वह अधिक खुग नजर आने लगे। २५ फरवरी को गाधीजी बहुत प्रसन्न थे। उस दिन प्रात काल उन्होने स्पज स्नान किया और मालिश की। दो दिन तक नीवू का मीठा रस और पानी पीने के बाद गाधीजी ने इसकी मिकदार कम करदी। २७ तारीख के बुलेटिन मे बताया गया कि गाधीजी आज उदासीन-से दिखाई देते थे, लेकिन अगले दिन वह सजग और अधिक खुश थे। पहली मार्च को सोमवार था। यद्यपि वह खुश दिखाई देते थे तथापि मुलाकात करनेवालो के कारण वह थकावट महसूस कर रहे थे। ३ मार्च को सुबह ९ वर्ज गाबीजी ने अपना उपवास खोला। लेकिन सरकार यह सहन नहीं कर सकती थी कि उस दिन खुशिया मनाई जाया। इसलिए उसने दर्शको को उनसे मिलने की इजाजत नही दी। दर्शको की सख्या कम होने के कारण इस समारोह में अधिक गम्भीरता आ गई, लेकिन गांधीजी से मिलनेवाली ने शहर में अन्यत्र एक सभा की जिसमें गांधीजी की दीर्घायु के लिए कामना की

गई। इस सभा में श्री अणे भी उपस्थित थे। इसके वाद गावीजी के स्वास्थ्य में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई।

इंग्लैएड में उपवास की प्रतिक्रिया

मार्च के पहले सप्ताह में गाधीजी के उपवास समाप्त होने के परिणामस्वरूप विटेन की जनता का ध्यान पुनः भारतीय गतिरोध को दूर करने की ओर आकृष्ट हुआ। 'माचेस्टर गाजियन' ने अपने एक सपादकीय लेख में लिखा —

"यह सौभाग्य की वात है कि हमारे और भारत के टरम्यान अन्तिम मैत्री स्थापित होने की आजा से गांधीजी जीवित रहे। परन्तु यह सत्य है कि भारत

की राजनैतिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।"

गांधीजी ने हाल के उपद्रवों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से साफ इन्कार कर दिया था, इस पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा—"काग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से सरकार ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे देश के विद्यमान् खिचाव में कभी हो जाती। स्थिति को सुधारने के लिए न तो कुछ किया गया है और न किया जा रहा है और अब गांधीजी जो उपवास करने जा रहे हैं भले ही भारत-सरकार उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, परन्तु हो सकता है कि भारत पर उसका व्यापक प्रभाव पड़े।" पार्ल्यामेट के बहुत से मजदूरदली सदस्यों ने भारत की परिस्थिति, विशेष कर उपवास के समय गांधीजी को नजरबन्द रखने के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की। वाइसराय की शासन-परिषद् के तीन सदस्यों के इस्तीफ का समाचार मिलने के बाद इनमें से लगभग १५ सदस्यों ने १७ फरवरी को कामन-सभा के कमेटी रूम में एक बैठक की। लन्दन में इंटिया लीग द्वारा आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए लाई स्ट्रैंबोल्गी ने कहा कि अगर कही उपवास के परिणाम स्वरूप गांधीजी की जान जाती रही तो उन्हें आशका है कि हिन्दुओं के साथ ब्रिटेन के भांवी सम्बन्ध बहुत कट और खतरनाक हो जाएगे।

२५ फरवरी को एक जिप्ट मण्डल ने, जिसमें श्री कैनन हार्लण्ड और पार्त्याने के मजदूर-दल के बहुत-से सदस्य भी शामिल थे श्री एमरी से भेट की और उनसे गांधीजी को रिहा करने और गांधीजी तथा काग्रेसी नेताओं में पारस्परिक मपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कामन-सभा में एक प्रध्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा कि ब्रिटिश-सरकार भारत-सरकार के इस फेनले से पूर्णत महमत है कि इस प्रकार गांधीजी-द्वारा विना गर्त अपनी रिहाई की कोशिश के आगे घुटने न टेके जांधी।

उपवार की नमाप्ति पर वहन कम जिटिंग-पत्रों ने कोई राय जाहिर की। 'डेलीमेल और 'डेली टेटिग्राफ' ने इसे विटिश-सरकार की विजय दताया।

उदार-दली पत्र 'रटार' ने कहा कि उपवास के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनोकामना पूरी नही हो सकी। इडिया लीग-द्वारा आयोजित एक सभा मे ३ मार्च को भाषण देते हुए लार्ड स्ट्रैवोल्गी ने कहा कि अब जबिक गाबीजी का उपवास खत्म हो गया है, काग्रेस के नेताओं और भारत के अन्य समुदायों के माथ तुरन्त ही नये मिरे से समझौते की वात-चीत शुरू कर देनी चाहिए और गायीजी की रिहाई इस दिशा में पहला कदम हो मकता है। प्रोफेसर लास्की ने ९ मार्च, १९४३ के 'रेनाल्ड्स न्यूज' में लिखा "बिटिश मरकार निस्सन्देह मौभाग्यशालिनी है कि उपवास के दौरान में गाधीजी की मृत्यु नहीं हुई, अगर कही ऐमा हो जाता तो हमारे इन दोनो देशों के दरम्यान बहुत भारी गलतफहमी पैदा हो जाती जिसे दूर करना असम्भव हो जाता।" लार्ड हेरिगडन, श्री एडवर्ड थानमन, श्री लारें महाउसमन और कंण्टरवरी के डीन ने गायीजी को तत्काल रिहा कर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सदेश भेजे।

श्रमरीका में उपवास की प्रतिकया

अमरीका में उपवास की विभिन्न प्रतिकिया हुई। अमरीका के सभी प्रमुख पत्रों में गांधीजी के उपवास और वायसराय के साथ उनके पत्र-व्यवहार का विस्तृत विवरण प्रकाशित हुआ। १२ फरवरी तक न्यूयार्क और वाशिगटन के किसी भी पत्र ने इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की। अमरीका की प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों ने कहा कि उनके पास गांधीजी की कार्रवाइयों के अध्ययन करने का समय नहीं हैं और इसिलए वे इस सम्बन्ध में कोई राय प्रकट करने को तैयार नहीं है।

गायीजी के उपवास के सम्बन्ध में २२ फरवरी को अपने सपादकीय लेख में टिप्पणी करते हुए 'न्यूयार्क टाइम्स' ने लिखा, "भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना सारा • जीवन लगा दिया है, उसकी चरम सीमा अब उपवास में जाकर समाप्त हो रही प्रतीत होती है। पिछले सप्ताह गायीजी की गम्भीर अवस्था के कारण एक बडा सकट पैदा हो गया है।" २० फरवरी को अमरीका के स्वराष्ट्र-मत्री श्री कार्डल हल और ब्रिटेन के राजदूत लार्ड हेली-फेक्स ने एक-दूसरे से बातचीत की, और श्री हल ने गायीजी के उपवास से पैदा होनेवाली परिस्थित के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता प्रकट की।

भारत में उपवास की प्रतिक्रिया

उपवास की महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम प्रतिक्रिया भारत मे यह हुई कि १७ फरवरी १९४३ को श्री एच० पी० मोदी, श्री एम० एस० अणे और श्री एन० आर० सरकार ने सरकार-द्वारा गाधीजी को रिहा न करने के विरोध में वाइस-राम की शासन-परिषद् से इस्तीफा दे दिया। इस नयी परिस्थिति पर सोच-

विचार करने के लिए १९ फरवरी को नयी दिल्ली में नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण रखनेवाले लगभग १५० प्रमुख नेताओं को, जिनमें श्री जिन्ना भी शामिल थे, बुलाया गया। लेकिन श्री जिन्ना ने यह कहकर इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया कि "गाधीजी के उपवास के कारण पैदा होनेवाली परिस्थित पर सोच-विचार करने का काम वास्तव में हिन्दू-नेताओं का है।"

इस सम्बन्ध में सब से पहले अपने विचार प्रकट करनेवाले सार्वजिनक नेता हिन्दू-महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी थे। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा—"महात्मा गांधी के बिना भारतीय समस्या कभी नहीं सुलझ सकती।" भारतीय व्यापार और उद्योग-सघ के प्रधान श्री जी०एल० मेहता ने वाइसराय के नाम अपने तार में कहा—"उपवास करने के बारे में यदि गांधीजी के फैसले में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था, तो कम-से-कम सरकार को उन्हें विना शर्त रिहा कर देना चाहिए था।" पिष्डत मदनमोहन मालवीय ने २० फरवरी को ब्रिटेन के प्रधान मत्री श्री चिंचल को इस नाश्य का एक तार भेजा कि भारत और इंग्लैण्ड के भले के लिए में आप से गांधीजी को मुक्त कर ढेने की यह अतिम क्षण अपील करता हूँ। यदि कही गांधीजी का जीवन जाता रहा तो भारत और इंग्लैण्ड के पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिए भारी खतरा पैदा हो जायगा। श्री आर्थर मूर ने भी एक वक्तव्य में कहा कि इस समय, जब कि गांधीजी का जीवन खतरे में है, सरकार उन्हें छोडकर कोई खतरा नहीं उठाएगी और न उसकी प्रतिष्ठा पर ही कोई आच आएगी।

परन्तु इन प्रार्थनाओं के वावजूद भी भारत-सरकार ने एकदम अप्रत्याशित रुख धारण कर लिया। उसने आदेश जारी कर दिया कि उपवास तोड़ने के समय गाधीजी के पुत्रों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं रह सकता और गायीजी का अथवा ऐसे दूसरे किसी भी व्यक्ति का, जिसकी उन तक पहुंच है कोई भी वक्तव्य तब तक प्रकाशित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे पहले से प्रातीय प्रेस-सलाहकार को न दिखला लिया गया हो। यह प्रतिबन्ध छ: महीने और २१ दिन तक जारी रहा।

गाधीजी के उपवास के वाद फिर वहीं पुराना सवाल जिसके कारण उन्होंने उपवास किया था, सामने आया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक और चितित था कि अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार अब कुछ झुक जायगी और नरम पड जायगी? क्या वह अपने किए पर पश्चात्ताप करेगी? क्या उसके कठोर हृदय में परिवर्त्तन हो सकेगा? क्या वह अपना दुराग्रह छोड देगी? इस प्रमग में हम जार्ज वर्नार्ड गा का एक वक्तव्य उद्घृत करना उचित समझते हैं जो उन्होंने मई १९४३ के अन्त में दिया था। उन्होंने कहा—"आप मेरा हवाला

देकर यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण पक्ष (टोरी) के प्रतिक्रिया-वादी और दुस्साध्य लोगों के कहने में आकर गावीजी को जेल में बन्ट करके एक मूर्खतापूर्ण और भारी भूल की है। उसने ब्रिटेन के वनिकवर्ग के साथ मिलकर हिटलर के खिलाफ इस देश की नैतिक स्थिति विल्कुल खत्म कर दी है। मम्राट् को चाहिए कि वह गाधीजी को विना गर्त मुक्त करके उनमे अपने मित्रमडले के मानसिक विकार के लिए क्षमा-याचना करे। उस तरह जहा तक हो सकेगा भारतीय स्थिति को सुलजाया जा सकेगा।" निस्मदेह ये बडे महत्त्वपूर्ण शब्द है। लेकिन यूरोपीय महाद्वीप पर राजनीतिज्ञता यदि खत्म नहीं हो चुँकी थी तो कम-से-कम उसका दिवाला अवश्य निकल चुका था।

निर्द्लीय नेताओं का प्रयत्न विफल

भारत में गावीजी की प्राण-रक्षा मे जितनी खुशी हुई थी उससे अधिक नहीं तो कम-से-कम उतनी ही खुशी ब्रिटेन में इस वात से हुई कि अनशन असफल रहा। भारत के लिए यह जिन्दगी और मौत का सवाल या और ब्रिटेन के लिए सफलता या असफलता का। इस बात के यकीन मे कि अनशन असफल रहा, अगेजो की अभिमान-भावना तुष्ट हुई, उन्हें सतोप हुआ और ब्रिटेन और साम्राज्य के शत्रु की दुर्गति से उन्हें ऑमिश्रित हर्प हुआ।

अनगन के बाद २० मार्च को दिल्ली में नेताओं का जो सम्मेलन हुआ या उसके अध्यक्ष के रूप मे डा० सप्रू को उत्तर देते हुए वाइसराय ने सरकार की नीति स्पप्ट करते हुए कहा ---

"यदि दूसरी तरफ गावीजी पिछले अगस्तवाले काग्रेस के प्रस्ताव को रद करने और हिंसा के लिए उत्तेजक अपने शब्दो-जैमे 'खुला विद्रोह' आदि की काग्रेस अनुयायियो को दी गयी 'करो या मरो' सलाह की और अपने इस कथन् की कि नेताओं के हट जाने पर साधारण व्यक्ति स्वय ही निर्णय करे, निन्दा करने को तैयार हो और साथ ही काग्रेस और वह भविष्य के लिए ऐसा आव्वासन देने को तैयार हो, जो सरकार को मज़र हो, तो इस विषय पर आगे विचार किया जा सकता है। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता और काग्रेस अपने रख पर कायम रहती है, तब तक सरकार का पहला फर्ज हिन्दुस्तान की जनता के प्रति है और अपने इस फर्ज को वह पूरी तरह से अदा करना चाहती है। यह कहा गया है कि इस तरह फर्ज अदा करने से कटुता और दुर्भावना में वृद्धि होगी। सरकार इस सुझाव को निराधार मानती है और यदि इसमें कुछ आधार हो भी तो सरकार

अपनी जिम्मेदारी निवाहने के लिए वह मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है।" फिर भी अखिल भारतीय नेताओं ने हिम्मत करके ९ मार्च १९४३ को एक

सम्मेलन किया और निम्न वक्तव्य निकाला ---

"हमारा मत है कि पिछले कुछ महीने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और काग्रेस को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। हममें से कुछेक को गाधीजी से हाल ही में जो बातचीत करने का मौका मिला है उसके कारण हमारा विश्वास है कि इस समय मुलह की बाते जरूर कामयाव होगी। हमारी तरफ से वाइसराय से अनुरोव किया जाना चाहिए कि वह हमारे कुछ प्रति-निधियों को गाधीजी से मिलने की अनुमति प्रदान करे ताकि हाल की घटनाओं के सम्बन्ध मे वह उनकी प्रतिक्रिया का प्रमाणित विवरण प्राप्त कर समझौता कराने का प्रयत्न कर सके।" इस वक्तव्य पर ३५ नेताओं के हस्ताक्षर थे जिन में सर तेजबहादुर सप्रू,श्री एम० आर० जयकर,श्री भूलाभाई देसाई,श्री सी० राजगोपालाचारी और सर जगदीशप्रसाद के नाम विशेष रूप मे उल्लेखनीय है। इससे आगा की जाती थी कि आवश्यक अनुमति मिल जायगी। परन्तु उसकी जगह वाइसराय का एक लम्बा उत्तर मिला, जिसमे अनुमति देने से इकार कर दिया गया। तब वाइसराय के पास एक डेप्टेशन ले जाने का फैसला किया गया। वाइसराय ने १ अप्रैल को चार प्रतिनिधियो के एक डेपुटेशन से मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उन्होने एक आवेदनपत्र भी भेजने का अनुरोध किया। डेपुटेशन को सूचित किया गया कि डेपुटेशन से अपना आवेटनपत्र पढने को कहा जायगा और फिर वाइसराय अपना उत्तर पढ देगे। दूसरे शब्दो में, इस प्रश्न पर कोई बातचीत न होगी। यह सूचना मिलने पर डेपुटेंगन ने स्वयं उप-स्थित होने की आवश्यकता न समझी और वाइसराय को सुचित भी कर दिया। वाइसराय ने पहली अप्रैल को आवेदनपत्र का उत्तर दिया।

नेताओं के आवेदनपत्र का उत्तर देते हुए वाइसराय ने कहा ---

" मैं पहले ही बता चुका हू कि गांधीजी या काग्रेस की तरफ से मस्तिष्क या हृदय के परिवर्तन का कोई सबूत अभी या पहले नहीं भिला है। अपनी नीति त्यागन का अवसर उन्हें पहले भी था और अब भी है। आपके अच्छे इरादों तथा समस्या के सफल निवटारे के लिए आप की चिन्ता की कद्र करते हुए भी गांधीजी तथा काग्रेसी नेताओं से मिलने की विशेष सुविधा मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी ऊपर बतायी जा चुकी है।"

इस प्रकार अखिल भारतीय निर्दलीय नेताओ-द्वारा गाधीजी से सम्बन्ध स्थापित करने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए।

राजाजी श्रीर पाकिस्तान

यह कोई नहीं कह सकता कि श्री राजगोपालाचार्य ने श्री जिन्ना से दो बार बात करने के बाद जब समझौता होने की आशा दिलाई उस समय उनके पास क्या गुप्त योजना थी। नेता-सम्मेलन के समय समझौते की जो आशा उठी थी,

उस पर वाइसराय ने वाहरी नेताओं को गाबीजी से मिलने की अनुमति न देकर पहले ही तुपारपात कर दया था। किन्तु राजाजी का उत्माह इतने पर भी कम न हुआ और उन्होने १० मार्च को सर्वटल नेता-सम्मेलन का आयोजन किया। पर इस वार भो नेताओ को गावाजी से मुलाकान करने की अनुमति नही प्राप्त हुई। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब किसी भ्रम के कारण हो रहा था। राजाजी शायट यही खयाल करते ये कि समस्या का हल पाकिस्तान की गृत्थी को सहानुभूति-पूर्वक सुलझाने से हो सकता है। पाकिस्तान के विचार को मि० जिन्ना ने कोई शक्ल नहीं दी थी, पर राजाजी कुछ अधिक स्पष्टता से सोचने लगे थे। पाकिस्तान का आयार 'दो राप्ट्वाला सिद्धात' या, जिसे राजाजी ने मजुर कर लिया था। राजाजी का खयाल या कि पाकिस्तान को जैसे ही माना गया वैसे ही वाकी परि-णाम अपने आप निकल आएँगे। १२ अप्रैल को वगलीर में मुहम्मद साहव के 🕞 जन्म-दिवस पर राजाजी ने पाकिस्तान के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट किये। उन्होने कहा कि राजनीतिक अडगे को दूर करने का तरीका पाकिस्तान को मान लेना है और यह भी कहा कि पाकिस्तान हिन्दुओं के सामने उसकी इतनी उरावनी गक्ल में रखा गया है कि वे उससे अनावश्यक रूप से भयभीत हो गये है। उन्होंने यह भी कहा --

"मैं पाकिस्तान का इमिलए समर्थक हू कि मैं ऐसे राज्य की स्थापना नहीं चाहता जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही का सम्मान न किया जाता हो। मुसलमानों को पाकिस्तान ले लेने दो। यदि हिन्दू-मुसलमानों में समझोता हो जाता है तो देश की रक्षा हो जायगी। यदि अग्रेजों ने और कोई कठिनाई उठाई तो हम उस पर भी विजय कर लेगे। मैं पाकिस्तान का समर्थक हूँ, किन्तु मेरे खयाल में काग्रेस पाकिस्तान को नहीं मानेगी। काग्रेस के बाग में फूल लग हुए हैं, किन्तु बाग के फाटक बद है और मुझे निकट जाकर उन्हें चुनने नहीं दिया जाता।"

जिन्ना साहव का मत

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का २४ वा अधिवेशन दिल्ली में १९४३ के ईस्टर-सप्ताह में हुआ था और श्री जिन्ना उसके अध्यक्ष थे। श्री जिन्ना ने अपने भाषण में गांधीजी से अपने को पत्र लिखने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था —

"ब्रिटिंग सरकार सभी की उपेक्षा करने की जो नीति वर्त रही है उससे लड़ाई में कामयावी हासिल नहीं की जा सकती। यह वात जितनी ही जल्द मह-सूस कर ली जाय उतनी ही जल्द इससे सभी का लाभ होगा। यदि लड़ाई में हमारी हार होती है तो वह इस देश में सरकार की गलत नीति के कारण होगी। भारत की खाद्य-स्थिति, आर्थिक अवस्था तथा मुद्रा-प्रबंध बड़ी सकटपूर्ण स्थिति में पहुच चुके हैं और इस विषय में सरकार की हाथ-पर-हाथ रख कर बैठ रहने की नीति से उस युद्ध-प्रयत्न को हानि पहुच सकती है, जो लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए अत्यावश्यक हैं।"

भाषण का पूरा विवरण दिल्ली के एक अग्रेजी दैनिक "डॉन" ने, जिससे स्वय मि॰ जिन्ना का सम्बन्ध था, प्रकाशित किया था। जहा तक गाधीजी से किये गये अनुरोध का सम्बन्ध है, पूरे विवरण में भी वह उसी तरह दिया हुआ है, जिस तरह वह सिक्षप्त विवरणों में दिया हुआ है। मि॰ जिन्ना ने कहा था —

"इसलिए काग्रेस की स्थित वैसी ही है, जैसी पहले थी। सिर्फ यह दूसरे शब्दो और दूसरी भाषा में बताई गई है, किन्तु इसका मतलव है अखड हिन्दुस्तान के आधार पर हिन्दू-राज और इस स्थित को हम कभी स्वीकार न करेंगे। यि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर मुसलिम लीग से समझौता करने को तैयार हो जायँ तो मुझसे अधिक और किसी को खुशी न होगी। मैं आपसे कहता ह कि हिन्दू और मुसलमान दोनो ही के लिए वह बडा शुभ दिन होगा। यदि गाधीजी इसका फैसला कर चुके हैं तो उन्हें मुझे सीधा लिखने में दिक्कत ही क्या है? (हर्षध्विन) वह वाइसराय को पत्र लिख रहे हैं। वह मुझे सीधा क्यो नहीं लिखते? वाइसराय के पास जाने, डेपुटेशन भेजने और उनसे पत्र-व्यवहार करने से लाभ ही क्या है? आज गाधीजी को रोकनेवाला कौन हैं? मैं एक क्षण भी विश्वास नहीं कर सकता—इस देश में यह सरकार चाहे जितनी शिक्तशाली क्यो न हो और हम उसके विरुद्ध चाहे कुछ क्यो न कहे, मैं नहीं मान सकता कि यदि मेरे नाम ऐसा पत्र भेजा जाय तो सरकार उसे रोकने का साहस करेगी। (जोरो की हर्ष-ध्विन)

''यर्दि सरकार ने ऐसा कार्य किया तो यह सचमुच बहुत ही गम्भीर वात होगी। परन्तु गाधीजी, काग्रेस या हिन्दू नेताओं की नीति में परिवर्तन होने का कोई लक्षण

मुझे नही दिखाई देता।"

गांधीजी के पत्र पर रोक

पाठकों को स्मरण होगा कि जब मि॰ जिन्ना से गांधीजी के अनंजन के दिनों में नेता-सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया था तब उन्होंने यह कहकर सम्मेलन में भाग लेने से इकार कर दिया था कि गांधीजी ने यह खनरनाक अनंजन कांग्रेस की मांग पूरी कराने के लिए किया है और यदि दवाव में आकर इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो इसके परिणामस्वरूप मुसलमानों की मांग नप्ट हो जायगी और इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने से भारतीय मुसलमानों के हितों की हानि होगी। गांधीजी ने मि॰ जिन्ना के भाषण का विवरण समाचारपत्रों

मे पढ़ने ही उन्हें पत्र लिखने की अनुमनि के जिए भारत-सरकार को लिया। पत्र को वाकायदा पूना से वस्वर्य-सरकार के पास और उनके पास से भारत-सरकार तक पहुचने में तीन सप्ताह का समय लग गया होगा। मर्ट के अनिम दिनों में अववारों में भारत-सरकार की एक विज्ञाप्ति प्रकाशित हुई। उससे जनता में बड़ी सनसनी फैल गयी। विज्ञाप्ति में यह नहीं बताया गया कि गांधीजी-द्वारा मिं० जिन्ना को लिखे गये पत्र में क्या था। उसमें सिर्फ यहीं वहां गया था कि गांधीजी मिं० जिन्ना में मिल कर बड़े प्रसन्न होगे। भारत-सरकार ने बड़ा निराला और पेचीदा रास्ता अस्तियार किया। उसे या तो गांधीजी का पत्र मिं० जिन्ना के पास भेज देना चाहिए था या उसे रोक लेना चाहिए था। परन्तु सरकार ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। सरकार ने यहीं कहा कि गांधीजी ने इस आध्य का अनुरोध किया है, किन्तु दूसरी विज्ञाप्ति में बताये गये कारणों से सरकार उस पत्र को मिं० जिन्ना के पास भेजने में असमर्थ हैं। सरकार ने विज्ञाप्ति की एक प्रतिलिपि मिं० जिन्ना के पास भेज दी।

भारत में प्रतिक्रिया

गाधीजी के लिखे पत्र को मि० जिन्ना के पास भेजने से इन्कार करने से लन्दन के सरकारी हल्को मे जो प्रतिकिया हुई उस पर 'रायटर' के राजनीतिक सवाद-दाता ने प्रकाश डाला था। उसने लिखा कि "भारत मे हुए इस निश्चय का विटिश-नरकार पूरी तरह समर्थन करेगी। सरकारी तौर पर यह कहा गया कि भारत की हिफाजत और युद्ध को सफलतापूर्वक चलाये जाने का महत्व सबसे अधिक होने के कारण गाधीजी या किसी दूसरे नजरवन्द काग्रेमी नेता को युद्धकाल के दरिमयान राजनीतिक बातचीत में भाग लेने की मुविधा तव तक नहीं दी जा सकती जब तक वे युद्ध-प्रयत्न के प्रति असहयोग करने और उसके खिलाफ आन्दोलन करने की नीति का त्याग नहीं करते, या विज्ञाप्ति के गव्दों में, जब तक उनके देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हानि का खतरा बना हुआ है।" 'माचेस्टर गार्जियन' ने लिखा—"भारत-सरकार का यह निश्चय अपनी पहले की नीति के अनुसार हो सकता है, लेकिन शासन-कार्य में अपरिवर्तनशीलता ही एकमात्र गुण नहीं होता और न्याय का तकाजा तो यह कहता है कि भारत-सरकार कितनी हीं बार अपने वचन से टल गयी है। सरकार दूसरे नेताओं को गाधीजी से मिलने की इजाजत क्यो नही देती, जिससे देखा जा सके कि क्या परिणाम निकलता है।"

गाधीजी का पत्र भेजने से भारत-सरकार के इन्कार करने पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मि० एम० ए० जिन्ना ने 'टाइम्स आफ इण्डिया' पत्र को एक वक्तव्य देते हुए कहा—"गाधीजी का यह पत्र मुसलिम लीग को ब्रिटिश

सरकार से भिडा देने की एक चाल है, तािक उनकी रिहाई हो सके और उसके वाद वह जैसा चाहे कर सके।" उन्होंने यह भी कहा कि "मैंने अखिल भारतीय मुसलिम लीग के दिल्लीवाले अधिवेशन में जो सुझाव रखे थे उन्हें मजूर करने या अपनी नीित में परिवर्तन करने की कोई इच्छा गांधीजी की नहीं जान पडती।" आगे उन्होंने यह भी कहा कि "उस भाषण में मैंने कहा था कि अगर गांधीजी मुझे पत्र लिखने, ८ अगस्त को काग्रेस के प्रस्ताव में बताये कार्यक्रम को समाप्त करने और इस प्रकार कदम पीछे हटाकर अपनी नीित में परिवर्तन करने और पाकिस्तान के आधार पर समझौता करने को तैयार हो तो हम पिछली बातों को भूलने को तैयार है। मेरा अब भी विश्वास है गांधीजी के ऐसे पत्र को रोकने की हिम्मत सरकार नहीं कर सकतीं।

"गाधीजी या किसी भी दूसरे हिन्दू नेता से मिलने के लिए मैं खुजी से तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन सिर्फ मिलने की इच्छा प्रकट करने के लिए ही पत्र लिखने से मेरा मतलब न था और अब सरकार ने गाधीजी के एक ऐसे ही पत्र को रोक लिया है। मुझे भारत-सरकार के गृह-विभाग के सेकेटरी से २४ मई को सूचना मिली है, जिसमें लिखा है कि गाधीजी ने अपने पत्र में सिर्फ मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है और सरकार ने यह पत्र मेरे पास न भेजने का निश्चय

किया है।"

दिल्ली के 'डॉन' में प्रकाशित मि० जिन्ना के भाषण के विवरण तथा खुद जिन्ना साहब द्वारा दिए गए सक्षेप मे एक बडा भारी फर्क है। पहले विवरण मे मि॰ जिन्ना की माग सिर्फ यही थी कि गाधीजी पाकिस्तान के आधार पर उन्हे लिखे। इसका मतलब यही हो सकता था कि गाधीजी को पाकिस्तान के सिद्धान्त तथा नीति के सम्बन्ध मे बातचीत करने को रजामन्द होना चाहिए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जबतक मि० जिन्ना ने लफ्ज पाकिस्तान को दोहराने के सिवा उसके अर्थ या विस्तार के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। इसके अलावा, उन्होने बम्बई-प्रस्ताव वापस लेने और हृदय-परिवर्तन का सवूत देने की बात कहाँ कही थी? शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार गाधीजी से हृदय-परिवर्तन को कहती थी और उससे भी अधिक शक्तिशाली मि० जिन्ना उसे दोहराते थे। प्रति-हिंसाशील ब्रिटिंग सरकार आश्वासन और गारिण्टयाँ माँगती है और अधिक प्रतिहिसाशील मि० जिन्ना कहते थे कि गायीजी को कदम पीछे हटाने और वम्वई-वाले प्रस्ताव के कार्यक्रम तथा नीति मे परिवर्तन करने के लिए तयार रहना चाहिये। क्या उन्होंने मूल भाषण में यह मुझाव पेश किया था? सच तो यह है कि मि० जिन्ना अपने वक्तव्य में कुछ जरूरत से ज्यादा वढ गये थे। गायीजी के पत्र को सरकार ने जिस हिकारत की नजर से देखा था उसकी अग्रेजी और उर्दू के पत्रो में एक समान निन्दा की गयी थी। परन्तु मि० जिन्ना के तर्कों का सब से सम्मान-

पूर्ण और जोरदार उत्तर भारत-सरकार के अवकाशप्राप्त आर्ट० मी० एस० सदस्य सर जगदीश प्रसाद ने दिया। उन्होने कहा —

"भारत-सरकार-द्वारा महात्मा गावी को मि० जिल्ला के उिए पत्र लिखने

की अनुमित न देने पर मि० जिन्ना ने जो वनतव्य दिया है वह इस अम्बीकृति से भी अथिक विचारणीय है। कभी-कभी मि० जिन्ना का अनगंछ प्रताप उन्हें परेनान करनेवाली हालत में जाल देता है। अभी हाल में अपने दिरलीवाले भाषण में उन्होंने यह असर पैदा करने की कोशिश भी वी कि अब वे इतने ताकतवर हो गये हैं कि खुद ब्रिटिश-सरकार भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कायदे-आजम ने महान्मा गांधी को सीधा उन्हों को लिखने की दावत दी थी और कुछ जान के साथ फरमाया था कि सरकार में इस चिट्ठी को रोकने की जुरत नहीं है। चिट्ठी लिखी गयी और उसे रोक लिया गया। अब मि० जिन्ना एक चतुर खिलाडी की तरह इस अप्रिय परिस्थित से बचने के लिए उस पत्र के लेखक की ही निन्दा कर रहे हो। वह जानते हैं कि वह बिना किसी दिक्कत के ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गांधीजी को जवाब देने का अवसर नहीं मिलेगा।"

४ जून को कराची में मि॰ जिन्ना ने पत्र गरों के बीच कहा कि हिन्दू-पत्रों ने उन्हें गलत समझा है, उनके भाषण से गलत उद्धरण दिये हैं और जान-बूझकर भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया है। परन्तु वे ब्रेलवी, गौकत अमारी, हैंदराबाद के डा॰ लतीफ और इनायतुल्ला पा मगरिकी-जैमें आलोचकों से अपनी रक्षा न कर सके। अल्लामा मगरिकी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर काग्रेस पाकिस्तान मानने को तैयार है तो फिर उस समझौते की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी माग मि॰ जिन्ना ने कां है। मगरिकी ने यह भी कहा कि मि॰ जिन्ना को अपने मूल प्रस्ताव पर ही जमना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की बात तो कही गयी थी, पर वम्बईवाले प्रस्ताव को वापस लेने को नहीं कहा गया था। उर्दू-पत्रों ने एक स्वर से गायीजी के पत्र के सम्बन्ध में सरकार के एख की निन्दा की और फिर मि॰ जिन्ना के भी वक्तव्य की छीछालेदर की।

इंग्लैएड में प्रतिक्रिया

१९४३ की गर्मियों से इंग्लैंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के सालाना जलसे हुए। भारत में हुई हलचलों तथा टच्नीशिया की विजय में चौथे भारतीय डिवी-जन के हिस्से की वजह से भारत का सवाल महत्वपूर्ण वन गया और उस पर इन जलसों में विचार हुआ।

भारत के प्रति जो व्यवहार हुआ उसके लिए मजदूर-दल को नही—मजदूरों को दुख हुआ। १४ से अधिक श्रमजीवी सस्थाओं ने विटसन टाइड सम्मेलन (१३ जून) में प्रस्ताव पेश करने के लिए सूचनाए भेजी। एक भी प्रस्ताव में दल के नेताओं की, जो मित्रमंडल के सदस्य थे, प्रश्नसा नहीं की गयी, बिल्क हिन्दुस्तान का सवाल हल न करने के लिए उनकी निंदा की गई। उन सभी ने एक स्वर से भारत में फिर से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया और सबसे अधिक इस अ वश्यकता पर जोर दिया कि काग्रेसजनों को छोड दिया जाय।

जुलाई, १९४३ में इंग्लैंड की कितनी ही सस्थाओं ने, जिनमें इडिया लीग, ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी और इंजीनियरों की सम्मिलित यूनियन भी थी, जोरदार शब्दों में भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू करने की माग की और कहा कि उनमें से जो अभी जेलों में हो उन्हें रिहा कर दिया जाय। मेंसर्स लिडसे ड्रनड ने महात्मा गांधी के उन लेखों, भाषणों तथा वक्तव्यों के चुने हुए अश एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये, जो उन्होंने अगस्त १९४२ में अपनी गिरफ्तारी से पहिले दिये थे। पुस्तिका में प्रकाशक ने साथ में कोई टिप्पणी या भूमिका तक नहीं दी थी और उसका उद्देश्य सिर्फ जनता का ज्ञान-वर्द्धन था।

सर रिचार्ड आकलैंड के नेतृत्व में जो नई कामनवेल्थ पार्टी सगठित हुई वह भी भारत के सवाल में दिलचस्पी रखनेवाली सस्थाओं के साथ मिल गई। जुलाई के पहिले सप्ताह में प्रधानमंत्री चिंचल ने गिल्ड हाल में एक भाषण दिया। यह भारत के सम्बन्ध में उनका पहला भाषण था, जिसमें उन्होंने प्रतिक्रियावादी रुख नहीं प्रकट किया था। बाद में ब्रिटिश कौसिल आफ चर्चेंज ने भी भारत को सहायता का वचन दिया। प्रोफेसर जोड, प्रोफेसर हेरल्ड लास्की, मि० क्लीमेंट डेवीज, आर्क डीकन आफ वेस्टमिनिस्टर, सर रिचार्ड ग्रेगरी, सर अर्नेस्ट बेनेस्ट, प्रोफेसर नारमन बेनविच तथा बरिमघम और ब्रेडफोर्ड के बिशप एव दूसरे कितने ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से ६ अगस्त को एक अपील निकाली गयी कि नेताओं की गिरफ्त री की पहली साल-गिरह के अवसर पर भारत-सम्बधी नीति में संशोधन किया जाय। सर आलफेंड वाटसन-जैसे कट्टरपथी ने भी भारत के साथ समानता का व्यवहार किये जाने का अनुरोध किया और कहा कि अब अग्रेंजों को चाहिए कि वे अपने को भारत में "मेहमान" माने और बड़प्पन की भावना त्याग दे।

ं मंत्रिमंडलों की स्थिति

काग्रेसी नेताओं के जेलों में बन्द होने के बाद देश में मित्रमंडलों की क्या स्थिति थी, इस पर भी हमें लगें हाथों विचार कर लेना चाहिए। जिन सूवों में लीग की हुकूमत थी उनमें बंगाल की अहमियत सबसे ज्यादा थी। दिसम्बर, १९४१ में फजलुल हक ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और गवर्नर ने उनसे अपनी वजारत नये सिरे से कायम करने को कहा था। नयी वजारत बनाते समय फजलुल हक ने कुछ लीगी वजीरों से अपना पीछा छुडाया था। लीग वाले इसे आसानी से नहीं सह सके। उन्होंने डेढ साल तक इन्तजार किया और

इस अरसे में बहुत-पुछ हो गया। लडाई बगाल की पूर्वी सरहद तक आ गई। फेनी और चटगाय जापानी बटमारों के निजाने बन गये। अन्न के मसके वी वज्ह में मुल्क के दूर-से-दूर के हिस्से भी लडाई की दिवात महसूस अरने लगे। अप की बेहद कमी के अलावा वजीरों के काम में गवर्नर की रोजमर्रा की दस्तवाती ने भी उनके बीरज का खात्मा कर दिया। मिदनापुर के अन्याचारी तथा दाम के गोलीकाण्ड के लिये नार्वजनिक जाच की माग की गई, जिसे प्रवानमंत्री ने तो मजूर कर लिया, पर गवर्नर ने मजूरों नहीं दी। इसी बीच मिया फजलूल हुई की स्थिति पुन नित्यय हो गयी। कुछ तो भीतरी हमलो की वजह से और कुछ कामन-सम्बन्धी ऐने कार्यों के नारण, जो उन्हे नरने ही नाहिए थे, दिसम्बर, १९४२ ना नकट उत्पन्न हुआ। लीग पार्टी उनके शासन-प्रयत्न पर जोरदार हमले करने लगी। फिर भी फजलुल हर अपनी जगह पर नायम रहे। फरवरी १०४३ में मिया हक को दोतरफें हमलो का सामना करना पडा। गवर्नर उनके अधिकारी में जो हस्तक्षेत्र करते जा रहे थे वह उनके लिए असहनीय होता जा रहा या और दूसरी तरफ वह असेम्बर्छ। में इस पर रोजनी भी नहीं टाल सकते थे। आजिर् कार विवश हो कर ३० मार्च, १९४३ को उन्होंने उस्तीफा दे दिया और इनके २९ दिन बाद २८ अप्रैल, १९४३ को नर नजामुद्दीन की नरकार कायम हुई। प्रान्तीय असम्बर्ली की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में हुई। उसमें जिन दो महत्व-पूर्ण घटनाओं ने सनसनी पैदा कर दी यी उनमे वजट नी ममस्या पहली यी। दूसरी घटना मि० फजलुल हक द्वारा गवनर की उस स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्रवाई का रहस्योद्घाटन थी। इससे प्रकट हो गया कि किस तरह उन्होने कानून और विधान को उठा कर ताक पर रख दिया था और सेकेटरियेट की महायता से निरकुश शासक की तरह कार्य किया था। सब से बुरी बात तो यह यी कि मित्री के अधीन कर्मचारी गवर्नर के कहने पर मित्रयों की मर्जी के खिलाफ आदेश निका-लते थे। नये प्रयानमत्री को भी १९४४ के फरवरी तथा मार्च महीनो में वैसे ही सक्ट से गुजरना पड़ा । इसी बीच सर जान हर्बर्ट की मृत्यु हो गयी और मि० केसी गवर्नर नियुक्त हुए। उन्होने चुपचाप असेम्बली को स्थगित कर दिया।

युद्ध छिड़ने के समय से सिंघ की राजनीति वड़ी ढुलमुल थी। इस प्रान्त में दूसरे किसी प्रान्त के मुकाबले में मित्र-मडल जल्दी-जल्दी बदले गये। पहले बदे-अली खा का, फिर हिदायतुल्ला का, फिर अल्लाहबच्चा का, फिर हिदायतुल्ला का दूसरा और फिर तीसरा—इस तरह कितने ही मित्र-मडल कायम हुए और भग हुए। सिंच की इस पेचीदी राजनीति का एक परिणाम यह भी हुआ कि सीमा-प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खा की रिहाई के बाद सिंच के छ प्रमुख कांग्रेसी जेलों से छोड़ दिये गये।

मुस्लिम लीग ने अगली वजारत सीमाप्रान्त मे बनायी थी। प्रान्तीय असेम्बर्ली

उपवास और उसके बाद: १९४

में उसका बहुमत होने या न होने का सवाल नही था, किन्तु प्रान्तिक की स्वान ही यह कार्य कर डाला और सरदार औरगजेब को अपना प्रधानिक वनिया। औरगजेब की वजारत कायम होने पर प्रान्तीय असेम्बली के जो कई उप-चुनाव हुए थे उनमें से एक असेम्बली के एक सिख-सदस्य की मृत्यु से खाली हुई सीट के लिए हुँआ था। कुछ अज्ञात कारणो से यह उप-चुनाव हिन्दू तथा मुस्लिम सीटो के उप-चुनावो के साथ नही हुआ। गोिक सार्वजनिक रूप से इसका कोई कारण नही वताया गया, फिर भी उस पर प्रकाश पड ही गया। चुनाव २५ फरवरी, १९४४ को हुआ जिसमे काग्रेसी उम्मीदवार ने अपने विरोवी सरदार अजीतसिह के उम्मीदवार को ८१ वोट से हरा दिया। इस घटना के एक वर्ष बाद १२ मार्च १९४५ को सीमाप्रान्तीय असेम्बली में औरगजेब खा की वजारत के खिलाफ अवि-इवास का प्रस्ताव १८ के विरुद्ध २४ वोटो से पास हो गया। मार्च के महीने में भारत में काग्रेस की नीति में पहली बार परिवर्तन दिखाई दिया। औरगजेब खा की वजारत की हार का वही परिणाम हुआ, जो वैवानिक दृष्टि से होना चाहिए था। गवर्नर को प्रान्त के भूतपूर्व प्रधान मत्री डा० खान साहब को बुलाना पड़ा, जिनके अविश्वास के प्रस्ताव के कारण औरगजेब खा के मित्रमंडल का पतन हुआ था डा० खानसाहब इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होने १६ मार्च को पद ग्रहण करने के बाद बताया कि उन्होंने प्रान्त की जनता की इच्छा के ही अनुसार कार्य किया है।

सीमाप्रात में काग्रेस के शक्ति-ग्रहण करते ही जनता में प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी। जनता के मस्तिष्क में प्रश्न उठा कि सीमाप्रान्त के 'अच्छे' उदाहरण का अनुसरण अन्य प्रातों को करना चाहिए या नहीं, और इस सवाल को गोपीनाथ वारदोलोई तथा रोहिणी दत्त-द्वारा आसाम के प्रधान मंत्री सर मुहम्मद सादुल्ला को दी गयी चुनौती के कारण और भी बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार १५-६-४५ को काग्रेस कार्य-समिति की रिहाई से पूर्व ही परिस्थिति ठीक होने लगी

पंजाब में सर सिकन्दरह्यात खा की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण जो स्थान खाली हुआ उसकी पूर्ति कर्नल खिज्यह्यात खा ने की। इससे लीग और यूनियनिस्ट पार्टी की शक्तियों में सघर्ष आरम्भ हो गया। इसी समय पजाव में मि० जिन्ना ने एक विजेता के रूप में प्रवेश किया। वह देखना चाहते थे कि पजाव की वजारत दरअसल एक लीगी वजारत है या नही। कर्नल खिज्यह्यात खा को वजारत के रगढग में तब्दीली करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया। लेकिन सर छोटूराम पजाव-वजारत को लीगी वजारत का नाम देने के खिलाफ थे और उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसी कोशिश की गयी तो वह वजारत का साथ देना छोड़ देगे। कर्नल खिज्य के एक तरफ कुआँ था तो दूसरी तरफ थी खाई। गीकि खिज्यह्यात खा ने मसलिस लीग के मन पर शाकर पाकिस्तान का

समर्थन पहली वार किया, फिर भी मित्रमडल का पुनिनर्माण करने या कम-मे-कंम उसे लीग के पथ पर लाने का मि॰ जिन्ना का प्रयत्न असफल हो गया। जिन्ना साहव की न्यूनतम माग यही थी कि मित्रमडल का नाम यूनियिनस्ट से लेगी कर दिया जाय, किन्तु पजाव का मुरिलम-हो कमत यूनियिनस्ट पार्टी भग करने या सर छोटूराम वगेरह से ताल्लुक तोडने के यिलाफ था। ऐसी स्थिति में कायदे-आजम ने पजाव की वजारत तथा असेम्बली को अल्टीमेटम दिया कि २० अप्रैल को लाहीर वापिस आने तक उन्हें इस मवाल का आखिरी फैनला कर लेना चाहिए। किन्तु दुर्गपति कर्नल खिष्मह्यात खा तिवाना ने, जो अनावस्यक वातो की अपेक्षा कार्य में अधिक विश्वास रखते थे, दुश्मन को गहरी शिकस्त दी और लाहीर के किले को अछूता रखा।

पहले उड़ीसा में काग्रेस का बहुमत या। काग्रेम के कुछ सदस्य जेल में रहने के समय पालेंकामेडी के महाराज के नेतृत्व में अल्पसत्यक दल ने एक मित्रमङल कायम किया। यह मित्रमङल थोडे हा समय तक चला।

अब हम आसाम को लेते हैं। आसाम उन प्रान्तों में नहीं है, जिनमें १९३७ में काग्रेस का वहुमत था। परन्तु सर सादुल्ला के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर जब उनके मित्रमंडल का पतन हो गया तब वार्दोलोई मित्रमंडल उसकी जगह कायम हुआ, जिसमे प्रवानमन्त्री वार्दोलोई तथा एक अन्य मत्री ही काग्रेसजन थे। कुछ अन्य मत्री काग्रेस में सिम्मिलित हो गये थे। जब वार्दोलोई ने अन्य काग्रेसी मित्रिमण्डलो के साथ १९३९ में इस्तीफा दिया तब सादुल्ला-मिन्त्र-मण्डल फिर कायम हुआ और उसने अपनी शक्ति बढा ली। १२ मार्च, १९४५ को आसाम-मन्त्रिमण्डल प्रान्तीय असेम्वली में हार गया ओर उसे इस्तीफा देना पडा। फिर सरकारी पक्ष ने मिली-जुली वजारत बनाने के लिए काग्रेसी दल की शर्ते स्वीकार कर ली। निश्चय हुँआ कि नयी वजारत को सभी दलो का समर्थन तथा विश्वास प्राप्त हो। सरकारी दल ने सर सादुल्ला को विरोधी दल से अन्य विषय तय करने का भी अधिकार दे दिया। जिन शर्तों को स्वीकार किया गया उनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों से रोक हटाया जाना तथा सरकार की नाज वसूल करने तथा उसे उपलब्ध करने की नीति में परिवर्तन मुख्य थी। भूतपूर्व प्रचानमंत्री श्री गोपोनाथ वार्दीलोई ने सर मुहम्मद सादुल्ला से तय कर लिया था कि यदि उपर्युक्त शर्ते मान् ली जाय तो काग्रेस पद-ग्रहण न करके भी मौजूदा वजारत का नैतिक समर्थन करने को तैयार हो जायगी। वाद में यह समझौता भग हो गया और शिमला-सम्मेलन के समय आशा की जाने लगी कि आसाम में मिली-जुली काग्रेसी वजारत कायम हो सकेगी।

१९४३ और १९४४ में स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक अडगा दूर करने के जिन प्रयत्नों को सरकार से प्रोत्साहन मिल रहा था उनका मुख्य उद्देश्य प्रान्तों

में वजारते कायम करना था। इरादा यह था कि सूबो में वजारते कायम होने के बाद कहा जायगा कि राजनीतिक अडगा समाप्त हो गया। मध्यप्रान्त में वार्ता लीगी तथा गैर-लीगी मुसलमानों के एक ही वजारत में शामिल करने में किटनाई होने के कारण भग हो गयी। इसके अलावा लीग किसी ऐसी वजारत में भी शामिल नहीं होना चाहती थी, जिसमें काग्रेस और हिन्दू-महासभा का सहयोग प्राप्त न हो। सध्यप्रान्त, बिहार, उत्तर प्रदेश और महास में मित्रमंडल कायम करने का कोई वाकायदा प्रयत्न नहीं किया गया। वजारत बनाने में बिहार को कोई अधिक सफलता नहीं हुई।

प्रान्तीय असेम्बलियों के काग्रेसी सदस्यों तथा काग्रेसी नेताओं के जेल में बद होने के कारण अन्य राजनीतिक दलों को मित्रमंडलों के निर्माण के लिए खुला मैदान मिल गया। इसी कारण हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग में एक विरोधी सहयोग भी स्थापित हो गया। १९३७ के आम चुनाव में ७३, १९, ४४५ मुस्लिम बोटों में लीग को केवल ३,२१,७७२ वोट यानी कुल डाले गये मुस्लिम बोटों में से उसे सिर्फ ४ प्रतिशत बोट ही मिले थे। ९२ प्रतिशत मुस्लिम आबादीवाले सीमाप्रान्त में लीग को कुल मुस्लिम बोटों में से सिर्फ ५ प्रतिशत ही प्राप्त हुए थे। फिर भी सरकार की कृपा से सीना के प्रान्तों में लीगी प्रधान मित्रयों या लीगी विचार-वाले प्रधान मित्रयों के नेतृत्व में मित्रगडल बनने के लिए खिचडी पकने लगी। यह दृश्य हिन्दू-महासभा के लिए असहनीय था। इसिलए चुनाव में लीग से अधिक असफल होने के बावजूद हिन्दू महासभा के नेता हिन्दू-बहुमतवाले प्रान्तों में मीठे सपने देखने लगे।

'सर्वेन्ट्स आफ इडिया सोसाइटी'-जैसी नर्म तथा सयत विचारवाली सस्था ने ज्न, १९४४ के दूसरे सप्ताह में होनेवाली अपनी वार्षिक बैठक में राज-नीतिक परिस्थिति, तत्कालीन गित-अवरोध, नयी वजारते कायम करने और समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में होनेवाले आन्दोलन पर विचार किया। सोसाइटी ने अपने प्रस्ताव में धारा ९३ के अनुसार जासित कुछ प्रान्तों में बहुमत प्राप्त किये विना ऐसे मित्रमडल कायम करने के प्रयत्नों की निदा की, जो गवर्नरों की सहायता से और काग्रेसजनों की अनुपस्थिति में ही कायम रह सकते थे। ऐसी वजारतों में मत्री गैर-सरकारी सलाहकार से अधिक और कुछ न होते, क्योंकि वे अपने पदों पर बहुमत की जगह सरकारी समर्थन के बल पर कायम रहते। इन मित्रमंडलों की स्थापना से अतर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भ्रम फैलता और ऐसा लगता जैसे प्रान्त में लोकतत्रवादी जासन चल रहा हो।

जबिक तटस्थ दलो का मत इस प्रकार प्रकट हो रहा था, काग्रेसी मत बिहार तथा मध्यप्रात में ऐसे अनियमित मित्रमंडल स्थापित करने के विरुद्ध प्रकट हुआ। अब सभी काग्रेसी सदस्य जेलो में नहीं थे। कुछ अपनी मियाद खत्म कर चुके थे, कुछ नजरवदी से छूट चुके थे, कुछ जेल गये नहीं थे और कुछ को सरकार ही ने गिरफ्तार नहीं किया था। विहार तथा मध्यप्रात में जो काग्रेसी एम० एल० ए० जेलों के बाहर थे उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ न करके मिलकर और सलाह करके ही कोई कार्य करना चाहिए। जून के मध्य में बिहार असेम्बली के काग्रेसी सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें मित्रमडल वनाने से इन्कार कर दिया गया। इसी प्रकार नागपुर से श्री कालण्या ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके वजारत कायम करने से इन्कार कर दिया।

लार्ड वेवल की नियुक्ति

विदेशी सरकार मुसीवत के वक्त एक दिमागी चाल यह चलती है कि वह जनता का ध्यान नाराजी की वजह से हटा कर किसी ऐसी वात की ओर यीवती है, जिसकी ओर वह सहज ही में आकर्षित हो जाय। ऐसे वक्त जब कि सब का रोप एक ऐसे वाइसराय के व्यक्तित्व में केन्द्रित था, जो अपने कार्यकाल का डचोड़ा समय पूरा कर चुका हो, अखवारों में उसके उत्तराधिकारी के चुनाव की चर्चा वार वार होने लगी। कम-से-कम लोग इस सोच-विचार में तो पड ही गये कि शायद नया वाइसराय इससे अच्छा हो या वह नयी नीति पर ही अमल करने लगे। उस समय लार्ड लिनलिथगों के उत्तराधिकारी के लिए जितने नाम लिये जा रहे थे उनमें से आर्किवालड वेवल चुने गये।

सर आर्किवाल्ड वेवल अवकाश ग्रहण करनेवाले वाइसराय की अघीनता में प्रधान सेनापित के रूप में काम कर चुके थे। पर नागरिक वेवल ने सैनिक वेवल को गलत सावित कर दिया। अब सवाल था कि यह लेखक और चरितकार, यह योद्धा और रणनीति-विशारद, यह बहुभापा-भाषी, जो स्टालिन से रूसी भाषा में बात चीत कर चुका है और रूसी भाषा में ही रूस में व्याख्यान दे चुका है, और यह फील्ड-मार्गल, जो सिगापुर के पतन से ३६ घटे पहले टूटी पसली लिये जान बचा कर भाग चुका है—भारत को निराशा के उस गड़ है से निकालने के लिए क्या करेगा, जिसमें उसके अब तक के अभिमानी शासको ने उसे डाल रखा था।

देश की स्थिति

जिस समय लार्ड लिनलिथगो अपने पद से अवकाश लेकर अपने साढे सात वर्ष के कार्य का सिहावलोकन करते हुए विदाई ले रहे थे उस समय देश के राष्ट्रीय जीवन या उसके अभाव की ये विशेषताए दिखायी दे रही थी। ज्यादातर सूबो में दफा ९३ का शासन चल रहा था और जिन सूबो में वजारते काम कर रही थी उनमें भी शासन प्राय गवर्नरों का ही था। केन्द्रीय असेम्बली की वैठक के समय भी आर्डिनेस निकाले जाते थे। अन्न का प्रवन्ध बहुत बुरा था। इसी

तरह कपडे का भी कुप्रवन्य रहा। उर्ठान्ते की न्यास्थ्य तया सफाई-सम्बन्धी हालत अनहनीय थी। पूर्वी बगाल में सेना ने किसानों की नावे छीन ली थी और वे निव्यों के पार जाने में असमर्थ थे। बगाल में चावल का मूल्य ३५ ६० मन तक पहुच चुका था, जबिक वेजवाटा में सिर्फ ८ रू० मन ही था। देश में सभी तरफ अकाल और बाढ का दौरदीरा था। मबने महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार तथा जनता में विरोध की भावना लगातार बढ़ती जाती थी। जहा तक वैधानिक समस्या का सम्बन्ध है, गित-अवरोध पहले ही के समान बना हुआ था। नवीनता सिर्फ मि० चिंचल का एक भाषण था, जिसमें उन्होंने अपने हमेशा के रूप को एक अण के लिए त्याग कर भारत के बारे में फरमाया था कि "इस विशाल महाद्वीप को हाल ही में बिटिंग राष्ट्र-मंडल में पूर्ण सन्तोप प्राप्त होगा।" इस घोषणा से कुछ ही पूर्व लाई वेवल ने, जो उत्त समय सिर्फ सर आर्किवाल्ड वेवल थे, कहा था कि भारत की राजनीतिक उन्नति में युद्ध के कारण बाबा नहीं पडी है और मुजपर भारत का जो ऋण है, उसे चुका सकने की मुझे पूरी आबा है। इस क्यन से लोगों को उम्मीद हो चली थी कि जायद नये वाइसराय सुलह के युग का श्रीगणेंग करे।

उस स्थल पर यह बता देना लानकर होगा कि हमारी राष्ट्रीय माग बना भी और इस माग तक ऊपर बताये गये प्रस्ताव या निर्देल-नेताओं की योजना नहीं पहुनती भी। हमारी राष्ट्रीय माग तो यह थी कि ब्रिटेन पहले तो भारत की रवाबीनता की घोषणा करें और फिर भारत तथा इन्लंड के बीच एक सिंध हो, जिसमें वर्तमान परिस्थित तमा स्वतन्त्र भारत के बीच के परिवर्तन-काल को सब बाते निन्चित की जायं। इस बीच के बान में एम अन्यायी सरकार रहें, जो युद्ध-सचालन में वाधा खडीन करने का बचन दे और युद्ध-मचालन का कार्य पहले की व्यवस्था के अनुसार प्रभान सेनापित की देश-रेख में और बाद में हुई व्यवस्था के अनुसार पूर्वी एनिया कमान की देख-रेख में होता रहे।

गांधीजी की गिरफ़्तारी की वर्षगांठ

हुई, और इन सभाओं में राजनीतिक बिदयों और विशेषकर गांधीजी तथा काग्रेस-नेताओं की रिहाई की माग की गयी। लदन में भी कितनी सभाएँ हुई, जिनमें से एक में स्वाधीनता के अनन्य प्रेमी सोरेसन ने कहा, कि भारत की परिस्थिति का सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस की जरूरत हैं। सालगिरह के मौके पर श्रीमती सरोजनी नायड़ ने भी समाचारपत्रों में वक्तव्य दिया।

प्रशान्त-सम्मेलन श्रीर भारत

इस समय छोटे-बडे, अगेज, भारतीय, इग्लैंड, हिन्दुस्तान तया अमरीका-सभी तरफ से भारत की राजनीतिक परिस्थित के सम्बन्ध मे विचार प्रकट किए जाने लगे थे । आन्दोलन वापस लेने तया वाइसराय के सिहासन तक नतमस्तक होकर पहुँचनेवाले लोगो ने यह कहना शुरू कर दिया था कि गाधीजी ने अपने साथियों की सलाह के खिलाफ खिलाफत का पक्ष लेकर तथा सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन छेडकर वडी भारी भूल की है। परन्तु यह भारत के लिए सौभाग्य की वात थी कि ऐसे विचार रखनेवाले भारतीय महानुभावो की तुलना में 'स्टेट्समैन के भूतपूर्व सपादक आर्थर मूर-जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के लोग भी थे जिन्होने अपनी अन्तर्भेदिनी दृष्टि-द्वारा समस्या को विश्लेपण कर उसे हल करने का रास्ता निकाल लिया था। लाहौर के 'ट्रिव्यून' मे एक विगेप लेख लिखकर उन्होंने कहा कि भविष्य की तुलना में वर्तमान का महत्व ही अधिक है। उन्होने काग्रेस के इस रुख का समर्थन किया कि उसकी तात्काल्कि उत्तरदायित्व की माग पूरी करने से साम्प्रदायिक प्रतियोगिता ममाप्त हो जाती है, परन्त्र भावी वैधानिक योजना की जो वात वाइसराय ने उठायी है उससे देश में आपसी झगडे फैलने की सम्भावना है। इन्ही दिनो (अगस्त १९४३) महामाननीय गास्त्रीजी ने प्रशान्त-सम्मेलन में गाधीजी के उपस्थित होने पर जोर दिया।

प्रशान्त-सम्मेलन की रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि उसकी सिफारिशो तया उसके फैसलो का हवाला देकर मित्रमंडल अपनी स्थित मजबूत करना चाहता था। इसीलिए प्रशान्त-सम्मेलन को गैर-सरकारी संस्था भी बताया जा रहा था, गोकि उसमें सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। सर रामस्वामी मुदालियर और सर मुहम्मद जफरुल्ला खा को सरकारी प्रतिनिधि माना गया या नही, यह तो स्पष्ट नहीं है, किन्तु एक 'भारतीय प्रतिनिधि' द्वारा सम्मेलन की कार्रवाई तथा भारतीय गोलमेज बैठक में प्रकट किए गए प्रतिकियावादी विचार इन्हीं दो महानुभावों में से किसी एक के थे। पूर्ण अधिवेशन में जो निश्चय हुए वे इसी भारतीय प्रतिनिधि के प्रतिकियावादी विचारों के परिणाम थे। सुद्र ववेवेक जाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रकार किया गया था उसे देखते हुए उनसे यही आशा की जा सकता थी। वाइसराय की शासन-परिषद्

का भारतीयकरण प्रगतिनील कदम तो जरूर जान पडा होगा, लेकिन उसकी असली अहमियत भी किसी की नजर से छिपी न होगी। एक जाच-कमीशन की नियुक्ति और उसका मार्ग-प्रदर्शन करने के लिए सयुक्त-राष्ट्र-सघ की एक सलाह-कार-समिति की सिफारिशे उन लोगों के लिए भले ही पर्याप्त हो, जिन्हें भारत के हाल के इतिहास का कुछ ज्ञान न हो, किन्तु उन लोगों के लिए जो साइमन कमीशन, चारो गोलमेज परिपदो, शिक्षा-सम्बन्धी हर्टजोग-समिति, आर्थिक-व्यवस्था सम्बन्धी ओटो राथफील्ड-समिति, देशी राज्यो-सम्बन्धी बटलर-मिति, लोथियन मताधिकार समिति, सयुक्त पार्लीमेटरी समिति वगैरह के काम को १९२७ से १९३५ तक देख चुके हैं, प्रशान्त-सम्मेलन की यह नयी समिति भी निरुद्देश्य ही थी। फलत प्रशान्त-सम्मेलन की सिफारिशों का असर कुछ भी नहीं हुआ। भारत की राजनीतिक समस्या वहीं रही, जहां वह पहले थी।

लार्ड वेवल का रख

मनोनीत वाइसराय ने १६ सितम्बर को अपने सम्मान में पिलग्निमों के द्वारा दिए गए एक भोज के अवसर पर अपने भावी कार्यक्रम की एक झलक दी। इसके उपरान्त ईस्ट इडिया एसोसियेकन में भी लार्ड वेवल के सम्मान में एक समारोह हुआ। लार्ड महोदय ने सामने आनेवाली किठनाइयो तथा खतरों का जिक किया और साथ ही इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इग्लैड की सभी वर्ग की जनता में भारत के प्रति सद्भावना वर्तमान है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय भारत के सामने एक वडा अवसर है। यदि मैं भारत को सन्मार्ग पर लाने में उसकी कुछ सहायता कर सकूँ नो इससे अधिक अभिमान और प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई न होगी।

लार्ड वेवल को अपनी उपाधि जिस विचेस्टर के लिए मिली उसके वारे में उन्होंने एक नयी बात भी कही—"भारत में हमने व्यवहार करने और एक या दो बार निर्णय करने में गलतिया की है, किन्तु ये गलतिया हमने लोभ या भय से प्रेरित होकर नहीं की है। दूसरी तरफ भारत को ज्ञान्ति प्रदान कर, उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित कर और उसे स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता के पथ पर ले जाकर हमने उसका जो कल्याण किया है, इसे अच्छे ज्ञासन व सुप्रबंध का एक सर्वोत्तम नम्ना कहा जा सकता है।"

मज़दूर-दल का रुख़

दिल्ली में नये वाइसराय की नियुक्ति से ज़िटेन में मजदूर दल एक बड़ी किट-नाई में पड गया। अनुदार-दलवाले तो स्पष्ट रूप से अपरिवर्तनवादी, प्रतिक्रिया-वादी और पिछडे हुए थे और मि॰ चिंचल के नेतृत्व में घोषित कर ही चुके थे कि

वे साम्राज्य का दिवाला निकालने के पक्ष में किसी भी तरह नहीं हैं। उदारदल-वाले सिर्फ नाम के ही उदार थे ओर उनकी सस्या भी पर्याप्त न थी। जिस मजदूर-दल ने दो बार हकूमत सभाली थी वह अपने को अनुदार-दल के बीच घिरा और कमजोर पा रहा था। दल में तीन वर्ग थे। सबसे प्रभावशाली वर्ग नर्म विचार-वालो का था और उसके नेता एटली, मारीसन, वेविन, ग्रीनवुड और रिडले थे। मध्यवर्ग के नेता सोरेमन और वाये या उग्र वर्ग के नेता श्री कोवे थे। मजदूर-दल में पहले वर्ग का ही जोर अधिक था ओर वह हिन्दुस्तान के सवाल पर सरकार को किसी परेशानी में नही डालना चाहता था। इसीलिए इस वर्ग का एक डेपु-टेशन लार्ड वेवल से मिला और उसने उन्हें वताया कि राजनीतिक अडगा दूर करने का जो भी प्रयत्न वह करेगे उसका पूरा समर्थन मजदूर-दल करेगा। इसलिए मजदूर-दल वालो ने और कुछ नहीं तो कम-से-कम यह जाहिर तो कर ही दिया कि नंकारात्मक प्रतिक्रियावाद ब्रिटेन क विचारो का सच्चा प्रतीक नही है, इसलिए आगे कदम उठाकर वे विरोधी दलवालो को खुश ही करेगे। इसके विपरीत मध्यम वर्ग नकारात्मक नीति से सतुष्ट होनेवाला न था। वह ब्रिटेन की यह नैतिक जिम्मेदारी महसूस करता था कि परिस्थिति को विपम बनानेवाले कारणो को हटाना और भारत की आकाक्षाओं तथा मागों को पूरी करने के लिए प्रयतन-शील होना उसी का काम है। यह वह भी कहता था कि परिस्थिति बदल जाने और सुदूरपूर्व के युद्ध के रुख में परिवर्तन के कारण काग्रेसी नेता भी अपनी नीति में रहोबदल करने की जरूरत महसूस कर सकते है। मजदूर-दल का मध्यम वर्ग नया विधान लागू होने तक ऐसी अस्थायी सरकार की स्थापना पर जोर देना चाहता था, जिसके प्रति वाडसराय अपना नकारात्मक अधिकार काम मे न ला सके। मि० कोवे का दृष्टिकोण काग्रेस के प्रति रिआयत करने का नही, विलक उनके अधिकारो का था। वह भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा करने, राष्ट्रीय-सरकार की तुरत स्थापना तथा राजनीतिक विदयो की रिहाई और सद्भावना

बढाने के अन्य उपाय करने के पक्ष में थे।
जब कि एक तरफ मजदूर-दल की कार्यसमिति तथा पार्लीमेटरी समिति की भारत-सम्बन्धी उप-समिति में विचार हो रहा था, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन-दल इसके मुकाबले में अच्छे दृष्टिकोण का परिचय दे रहाथा। ट्रेड यूनियन-दल के नेता मि० डोबी ने भारत-सम्बन्धी नीति में परिवर्तन की माग जोरदार शब्दों में उप-स्थित की और कहा कि भारत का दुर्भिक्ष बहुत कुछ शासन-सम्बन्धी अव्यवस्था तथा जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण हुआ है। इस बार पादरियों की उत्सुकता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। भारत की मिशनरियो-द्वारा भेजी गयी सूचना के आधार पर मेथडिस्ट गिरजा की एक जिला शाखा-द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव मि० एमरी के पास भेज दिया गया।

लार्ड लिनलिथगो का कार्य-काल

भारत से लार्ड लिनलिथगो की विदाई-द्वारा १८५७ के गदर के समय से अव-तक की वाइसरीयी का सब से लम्बा काल समाप्त हो गया। दरअसल उनका कार्य-काल दूसरे किसी भी वाइसराय की तुलना में अधिक था। वह भारत में लार्ड कर्जन की अपेक्षा छ महीने ज्यादा रहे थे। लार्ड लिनलिथगों के कार्य-काल का दूसरा महत्व यह था कि दूसरे वाइसरायों की अपेक्षा उनका कार्य-काल सबसे नाटकीय था। नाटक जिस तरह सुखात हो सकता है उसी तरह दुखान्त भी हो सकता है। लार्ड लिनलिथगों जिस नाटक के नायक थे वह दुखात ही था। वह देखने में हृष्ट-पुष्ट, स्वभाव से अज्ञानी, राजनीति में कट्टरपर्था, दृष्टिकोण में साम्राज्यवादी, कुछ अभिमानी और रीति-रिवाज को वहुत माननेवाले व्यक्ति थे। उन तक पहुँचना कठिन था। उनके व्यवहार में शिप्टाचार की मात्रा अधिक होती थी और वह दूसरों से मिलना-जुलना कम पसद करते थे। वात को राक्षेप में कहना पसद करने पर भी वह उसे घुमा-फिराकर ही कह पाते थे। कभी-कभी उनके कार्य निरुद्देश्य तथा प्रभावहीन भी हुआ करते थे। यदाकदा उनसे हृदय-हीनता भी टपकती थी। स्पष्टवादिता के अभाव के कारण लोग उनके इराडो पर सदेह करने लगे थे। यह शक यहा तक वटा कि जब वह भारत की भौगोलिक और आधिक एकता गर जोर देते थे और देश में सघ-विधान स्थापित करने का आग्रह करते थे तब लोग आञ्चर्य करते थे, क्यों कि उन्होंने अपनी नीति के द्वारा देश में हिन्दू-मुसलमानो के वीच, प्रातो और रियासतो के वीच, सवर्ण हिन्दुओ और परिगणित जातियों के बीच और प्रातों व परिगणित प्रदेशों के बीच जिस भेदभाव को प्रोत्साहन दिया था उससे उनके एकता स्थापित करने के आग्रह का समर्थन नहीं होता था। लाई लिनलिथगों ने नरेशों को बढावा देकर उनका काग्रेस के ही नहीं, बेल्कि लोकतत्रवाद के भी विरुद्ध उपयोग किया था। उन्होंने अपनी जासन-परिषद् में ऐसे व्यक्तियों को रखा जो काग्रेस के कट्टर विरोधी थे या उने छोड चुके थे। उन्होंने मि० एमरी के गव्दों में "देश के सब से महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेताओं को जेल में टूंस दिया था और फिर यह धिकायत भी की थी कि वह मुस्लिम लीग से समेझीता नहीं करते।" उन्होने काग्रेमी नेताओं और लीगी नेताओं के बीच चिट्ठी-पत्री तक वद कर दी थी और फिर आरोप लगाया था कि वै मेल-मिलाप नहीं करते। उन्होने अगस्त १९४२ में महान्मा गाधी को मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी और उनकी सरकार ने सेना नथा पुलिस की हिंसा के कारण देन में असाध।रण उपद्रव फेलाने विवे थे। बगान और उँडीना में जब लावां व्यक्ति भसमरी के शिजार हो रहे थे तद उन्होंने उनकी सहानभनि में न तो एक मध्य वहा और न कोई अपील ही निकाली। अपने नायं-काल के जैनिम

दिनो में लाट साहव १६ अक्टूबर को 'सवर्वांसव एक्टिविटीज आर्डिनेन्स' के रूप में हिन्दुस्तान को अपना आखिरी तोहफा दिया।

इस प्रकार भारत की आर्थिक व्यवस्था तथा राजनीति से पिछला सम्बन्ध होने के कारण लार्ड लिनलियगो से वाइसराय का पद सभालने के समय जो आजा की गई थी वह पूरी नही हुई। महात्मा गाधी से मेत्री का जो दावा उन्होने किया था उसके पीछे गत्रुता की भावना छिपी हुई थी। उन्होने भारत को एक ऐसे युद्ध मे, जो उसका अपना युद्ध न था, व्यस्थापिका सभा को सूचित किये विना ही फँसा दिया। उनके इस कार्य की लदन के 'टाइम्स' तक ने निदा की। उन्होने २१ दिन के अनशन के अवसर पर गाधीजी को आगाखा महल में उनके भाग्य के भरोसे छोड दिया। गायीजी ने जब सद्भावना प्रकट करने के लिए एक पत्र मि० जिन्ना को लिखा तब लार्ड लिनलियगो ने उसे रोक दिया। सब से वडा विरोधा-भास तो यह है कि जिस वाइसराय का कृषि से इतना सम्बन्ध रहा उसी के काल में बहुत दिनों से भूली हुई दुर्भिक्ष की विभीपिका का सामना देश को करना पडा। तात्पर्य यह कि वह अपने पीछे इतिहासकार के लिए निराशाओ तथा निरर्थक प्रयत्नो का लेखा ओर उत्तराधिकारी के लिए असुविवापूर्ण विरासत छोड गये और इस तरह उन्होंने भारतीय समुद्रतट से नही-विल्क दिल्ली की कब्रो से विदाई ली। उनका न किसी ने सम्मान किया, न किसी ने उनके लिए ऑसू वहाये और न किसी ने उनके गुणानुवाद ही गाये।

: २१ :

अगला कदम: १६४४

वेवल का व्यक्तित्व

विल्ली में लार्ड लुई माउटबेटन के अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अचानक पहुचने के बाद १७ अक्टूबर, १९४३ को लार्ड वेवल भी पहुच गये। लार्ड वेवल का आगमन अप्रत्याशित न था, किन्तु इस पद का कार्य-भार सभालने के लिए वायुयान-द्वारा भारत पहुँचनेवाले पहले वाइसराय थे। लदन से रवाना होते समय उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों से कहा था—"मेरे सामने इस वक्त एक बहुत वडा सवाल है।" इससे जाहिर होता है कि भारत के वाइसराय का पद-ग्रहण करते समय लार्ड वेवल अपनी जिग्मेदारी कितनी अधिक महसूस कर रहे थे। इस सवाल की एक झलक मि॰ एमरी ने उस समय पार्लीमेंट में दी थी, जब उन्होंने

आजा प्रकट की थी कि नये वाइसराय विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य सद्-भावना स्थापित करने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे। यह जाहिर था कि सवाल बहुत टेढा और नाजुक था। यह किठनाई पिछले वाइसराय ने उत्पन्न करवी थी। यह भाव प्रकट किये विना ही कि पुरानी नीति में परिवर्तन किया जा रहा है, नयी नीति आरम्भ करने के लिए असाधारण राजनीतिज्ञता अपेक्षित थी—खासकर एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पिछले वाइसराय की अधीनता में काम कर चुका हो। यह कार्य सहल न था, किन्तु उसे करने के लिए जिस आत्म-विश्वास, विवेक और दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, वह उनमें भरपूर था। भारत में आते ही उन्होंने गवर्नमेंट हाउस के उस राजकीय शिष्टाचार को कम' कर दिया, जिसका लार्ड लिनलियगों को इतना चाव था।

एमरी का वक्तव्य

जिस दिन लार्ड वेवल भारत पहुचे उसी दिन मि० एमरी ने काग्रेस के विरुद्ध अपने आरोपों को दोहराया ताकि लार्ड वेवल उन्हें भूल न जाय। अपने आरोपों में उन्होंने सारी जिम्मेदारी काग्रेस पर लाद दी। उनके आरोप इस प्रकार थे —

"(१) काग्रेस योजना के सघवाले हिस्से का आरम्भ से ही विरोध करती आयी है, (२) काग्रेस ने रियासतो में असतोष पैदा करके नरेशों की हिचिकचाहट वढा दी है और (३) मुसलमान अब तक सघ-योजना के विरुद्ध नहीं थे, किन्तु प्रातों में काग्रेस के तानाशाही रगढग देखकर वे भी उसके कट्टर-विरोधी हो गये है।" मि० एमरी ने यह भी कहा कि इस आशका के कारण कि केन्द्र में काग्रेसी मत्री केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार मत्रियों के रूप में काम न करके कांग्रेस-कार्यसमिति और गाधीजी के आदेशों के अनुसार कार्य करेगे, मुस्लिम लीग तथा नरेश दोनों ही १९३५ के विधान की सघ योजना के विरुद्ध हो गये है।

साथ ही मि॰ एमरी ने पहली वार स्वीकार किया कि देश के सब से महत्व-पूर्ण राजनीतिक दल के जेल में वट होने के कारण उसका दूसरे दल में वातचीत चलाना असम्भव हो गया है। उन्होंने यह भी कहा—"लाई लिनलिथीगों का विचार ठीक हैं कि जो लोग युद्ध के समय खुलेआम विद्रोह को प्रोत्माहन देने के लिए नैयार थे उन्हें यह मुविया नहीं मिल सकती। 'इसके उपरात उन्होंने लाई लिनलिथिगों के साथ किया गया निर्णय मुनाया और कहा कि "उन्हें अपने पिछले कार्यों के लिए पञ्चात्ताप करना चाहिए। इसके वाट ही उन्हें भारत के भावी नियान के निर्माण में हिस्सा लेने की अनुमिन दी जा सकनी है।'' इसके टाद उन्होंने भविष्य के वारे में कहा, 'अब यह देखना शेप हैं कि विदेश में हमारी विजय के साप ही भारत की आनरिक स्थित में ऐसा मुधार होता है या नहीं, जिसले कि भारतीय नेताओं को आपस में नमझीता करने के लिए राजी किया जा नके, क्योंदि इसी आधार पर शासन की स्थायी व्यवस्था खडी की जा सकती है। यदि ऐसी प्रगति हुई तो निस्सदेह वाइसराय, सम्राट की सरकार और भारतीय जनता उसमे प्रोत्साहन प्रदान करेगी।"

वेवल की कठिनाइयां

ऊपर जो उद्धरण दिये गये हैं, उनसे स्पष्ट हैं कि 'नेताओं' से भारत-मत्री का तात्पर्य उन लोगों से नहीं था, जो वाहर थे, किन्तु उनसे था जो जेलें में थे। परन्तु इस पहेली का कुछ उत्तर नये वाइसराय को नहीं मिला कि जेल से बाहर आये विना कागेसी नेता अन्य लोगों से समझौता कैसे कर पायेगे?

यदि सच पूछा जाय तो भारतमत्री का यह वक्तव्य लार्ड वेवल के नाम एक आदेश-पत्र था, जिसमें लार्ड वेवल को काग्रेस के विरुद्ध चेतावनी दी गयी थी और गाधीजी तथा दूसरे काग्रेमी नेताओं के क्षमा-प्रार्थना करने और अगस्तवाले प्रस्ताव को वापस लेने तक वाइसराय को अपने विशेषाधिकारों से काम लेने को कहा गया था।

इस सम्बन्ध में महामाननीय बी० एस० बास्त्री ने मि० एमरी, लार्ड वेवल तथा गाधीजी के नाम तीन खुले पत्र लिखे। इन पत्रो को उन्होने स्याही की जगह अपने रक्त से लिखा था। इनमें उन्होंने अपनी आत्मा निकाल कर रख दी थी और अनुरोध किया था कि इन तीनो व्यक्तियों को अपने अवसर तथा अधिकारों का उपयोग भारत तथा ब्रिटिंग राष्ट्रमण्डल की गौरव-वृद्धि के लिए करना चाहिए। उन्होंने एमरी को वर्साई की सिध का स्मरण दिलाया और कहा कि मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी को जिस प्रकार अपमानित किया उसका परिणाम प्रतिहिसा एवं प्रतिशोध की नीति के रूप में दिखाई दिया। लार्ड वेवल से उन्होंने मि० एमरी की सलाह न मानने तथा गतिरोध समाप्त करने का उपाय शीध्र करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने गाधीजी से "एक योजना तथा एक नीति" पर जमें रहने के सिद्धात को त्यागने तथा समय के अनुसार नीति में परिवर्तन करने का अनुरोध किया।

इस प्रकार लार्ड वेवल-द्वारा वाइसराय का पद सभालते ही लोगो ने अनेक सुझाव तथा अनुरोध उपस्थित करने आरम्भ कर दिए, जिनमें कहा गया कि उन्हें अपने तात्कालिक कार्यक्रम में क्या गामिल करना चाहिए और क्या नहीं। यदि एक आवाज गतिरोध समाप्त करने के प्रयत्नों के विरुद्ध आई तो कितनी ही आवाजे ऐसे प्रयत्न आरम्भ किये जाने के पक्ष में उठी। पृथ्वी पर गाति और मनुष्य-जानि में सद्भावना की वृद्धि के लिए भी बहुत-कुछ कहा गया।

वेवल का कार्य

विना मागे, परम्परावश या शिष्टाचार के कारण जो सलाह दी जाती है

उससे लोग बहुत कम प्रभावित होते है। लार्ड वेवल इसके अपवाद नहीं थे। उनके अपने विचार, अपने सिद्धात, कर्तव्य के सम्बन्ध में अपनी निजी भावना और अपनी रुचि थी। सब से पहले उनका ध्यान बगाल की भुखमरी की तरफ गया। इसलिए सब से पहले उन्होने इसी समस्या को हाथ में लिया। उन्होने स्वा-स्थ्य-जाच तथा २६ अक्तूबर, १९४३ को गुरू होने वाली उन्नति समिति की वैठक के लिए जो सदेश दिया उसमें उन्होने गन्दी बस्तियो तथा उनमें रहनेवालो को नये सिरे से बसाने की समस्या, जल का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, मलेरिया-निवारण के लिए देशी कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग, मच्छरदानियों का अधिक उपयोग, स्कूलो में दवाखाने खोलने, अधिक डाक्टर-उपलब्ध करने, गावो मे डाक्टरों तथा नर्सों का प्रबन्व करने, देशी दवाओं को प्रोत्साहन देने और अनुसवान-सगठनों की चर्चा की। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात वगाल के पीडितों के लिए दी गयी रकमों की व्यवस्था के लिए एक विशेष कीप का खोला जाना था। लका की सरकार ने वाइसराय को इस कोप के लिए २७ लाख रुपये भेजे थे। दूसरा अच्छा कार्य २४ अक्तूवर को लार्ड वेवल की अविजापित कलकत्ता-यात्रा थी। इसकी सभी तरफ़ कद्र की गयी—खासतौर पर जेल में बन्द उन काग्रेसी विदयो द्वारा जो सीखचो के भीतर रहकर वगाल की वरबादी का दृश्य दीनता-पूर्वक देख रहे थे और जिसकी तरफ शासन-व्यवस्था का प्रधान होते हुए भी युद्ध-प्रयत्न में व्यस्त भूतपूर्व वाइसराय ने कुछ ध्यान नही दिया था। नय वाइसराय ने प्रयान सेनापित को सब से बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए सेना के साधन, विशेषकर अन्न के यातायात के लिए, उपलब्ध करने, सहायता के केन्द्र खोलने और इन केन्द्रों के लिए अन्न का सकलन करने का आदेश दिया। इन उपायों की सूचना २८ अक्तूबर को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में दी गयी और इसी मे योजना को कार्यान्वित करने के कार्यक्रम पर विचार किया गया।

लार्ड वेवल के कार्य-काल की एक विशेष घटना गवर्नरों का वाइसराय से परामर्श के लिए एकत्र होना भी थी। पिछले दस वर्षों में वाइसराय के लिए गवर्नरों को परामर्श के लिए बुला भेजना एक साघारण घटना हो गयी थी। ऐसा उस समय विशेप रूप से किया जाता था जब दमनकारी उपाय करना होता था या उन्हें हटाना होता था। परन्तु उन दिनो गवर्नर वाइसराय से दो-दो या तीन-तीन की टोलियों में मिलते थे। नवम्बर, १९४३ के गवर्नर-सम्मेलन की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि ग्यारह-के-ग्यारह गवर्नर दिल्ली में उपस्थित हुए और ऐसे सम्मेलन बीस महीनों में तीन हुए।

यह अच है कि वाइसराय ने गवर्नरों का सम्मेलन जल्दी ही बुलाया, पर उसंका कुछ भी परिणाम न निकला। लोकमत में अज्ञान्ति के लक्षण दिखाई देने लगे। लोग सोचने लगे कि वाइसराय के विचारों में कोई ऐसी वात नहीं हैं, पिस से राष्ट्र के राजनीतिक आदर्शों की तुष्टि हो सके। वगाल के लिए अझ उपलब्ध करने की समस्या की बहुत समय से उपेक्षा की गयी थी। नए वाइसराय ने उसकी तरफ घ्यान देकर सिर्फ अपने साघारण कर्तव्य का ही पालन किया था। लेकिन लाई वेवल के सार्वजिनक आचरण में एक परिवर्तन दिखाई दिया। उन्होंने अखिल-भारतीय समाचारपत्र-सम्पादक-सम्मेलन की स्थायी समिति को एक भोज दिया। यह समाचारपत्रों के लिए सद्भावनापूर्ण सकेत था। वाइसराय ने समिति के एक सदस्य को बताया कि उन्हें इंग्लैंड तथा भारत से परामर्श के कितने ही पर्र मिले थे। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी तरफ से कुछ कहने से पहले मैं इन विचारों का अव्ययन करना चाहता हूँ।

मुस्लिम लीग की स्थिति

एक बार फिर १९४३ के नवम्बर महीने में मुस्लिम लीग की काँमिल तया कार्यसमिति की बैठके दिल्ली में हुई। अप्रैल के महीने में लीग के पूरे अधिवेशन में जैसी चुनौतिया और धमिकया दी गयी थी वैसी इस बार नहीं दी गयी। पिछले १२ महीनों में जो लाभ हुए थे उनकी हिफाजत की ही तरफ इस बार अधिक ध्यान दिया गया था। कहा गया कि लीग के प्रभाव में पाच वजारते काम कर रही है। पाचो प्रवान मित्रयों को लीग के अध्यक्ष तथा कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने के लिए बुलाया गया। जनता यह भी नहीं जानती थी कि पाचो प्रान्तों के लिए राजनीतिक और आर्थिक सुधार के क्या कार्यक्रम तैयार किये गये है। फिर भी यह जाना जा सकता था कि दल के सगठन को सब से अधिक महत्व दिया गया। लीग अब तक काग्रेस के सगठन की निन्दा करती थी, लेकिन अब उसने अपना भी सगठन काग्रेस के ढग पर किया। लीग की कार्यसमिति को समाचारपत्र 'हाई कमाड' कहने लगे। कहा गया कि सभी लीगी प्रान्तों को एक नीति, एक कार्य-क्रम और एक ही अनुशासन का पालन करना चाहिए।

जहा तक वजारतों का सवाल है वहाँ तक यह कहा जा सकता है कि पजाब, सिय, सीमाप्रान्त, वगाल और आसाम में से किसी एक भी प्रान्त की असेम्बली में मूल लीगी सदस्यों का बहुमत नहीं था। पाचो वजारते ब्रिटिंग सरकार के कृपापूर्ण प्रभाव में कायम हुई थी। सरकार ने युद्धकाल में वजारते कायम करके राजनीतिक अडगा भग करने और काग्रेस का सफाया करने की सोची थी। इन पाच प्रान्तों से बाहर और कहीं भी ब्रिटिंग सरकार का यह पड्यत्र सफल नहीं हो सका। ब्रिटिंश सरकार ने हिन्दुस्तान के सवाल को जो ताक पर रख दिया था उस पर मुसलमानों में आम असतोप फैलने लगा था। यह लीग की कांसिल तथा कार्यसमित के सदस्यों के रुख से स्पष्ट था। यही मुस्लिम एम० एल० प्र

अगला कदम: १९४४

के आचारण तथा पत्रकारों के लेखों से जाहिर होता था। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज में वास्तविक राष्ट्रीय जागृति के स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे थे।

पमरी से इस्तीफा देने की सांग

लार्ड वेवल के भारत पहुचने के कुछ सप्ताह के अदर ही साम्राज्य के इति-हास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाए होने लगी। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल मे परिवर्तन की जो अफवाहे उड रही थी उनमें मि० एमरी, सर जेम्स ग्रिग और लार्ड साइमन के नाम भी लिए जा रहे थे। ब्रिटेन भर की राजनीतिक तथा औद्योगिक सस्थाए मि० एमरी की भारत-सम्बन्धी नीति—विशेषकर उनके अकाल-सम्बन्धी कुप्रवध के विरोध में प्रस्ताव पास कर रही थी। हाल ही में जिन सस्थाओं ने मि॰ एमरी को अपदस्थ करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये थे उनमें माचेस्टर नगर-मजदूर-दल, ग्रीनफर्ड की सम्मिलित इजीनियर्स यूनियन, ट्रासपोर्ट जनरल वर्कर्स की नम्बर १ हल्के की समिति, म्यूनिसिल कर्मचारी य्नियन की बर्नले शाखा, राज-मजूरो की सम्मिलित यूनियन की सेट ऑलवस शाखा और लेनाक खनक यूनियन की केस्टन शाखा मुख्य थी। वरिमवम् अनुदार सघ की तरफ से होनेवाली एक सभा में जब मि॰ एमरी व्याख्यान देने गये तब उन पर बेहद आवाज-कशी की गयी। यहाँ तक कि पुलिस न होती तो गम्भीर उपद्रव हो जाता। अत में मि॰ एमरी को भाषण दिये बिना ही सभा से उठकर चले जाना पड़ा। कई मिनट तक भारतम्त्री ने सभा से शान्त हो जाने की प्रार्थना की, लेकिन लोग चुप न हुए और अन्त में सभा भग हो गयी। ट्रासपोर्ट ऐड जनरल वर्कर्स यूनियन ने, जिसे ससार की सबसे बडी ट्रेड यूनियन कहा जा सकता है, सर्वसम्मति से मि० एमरी के इस्तीफ की माग की।

वेवल का भाषण

लार्ड वेवल के शासन के पहले छ महीने भारत के लिए और खुद लार्ड वेवल के लिए परीक्षा के दिन थे। राजनीतिक परिस्थिति में सुधार के लिए लोकमत की माग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही थी, परन्तु उन्होंने अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया था। श्री राजगोपालाचार्य का प्रस्ताव था कि किप्स-योजना पर फिर से विचार किया जाय। थी एन० आर० सरकार ने किप्स-प्रस्तावों के ही आधार पर काग्रेस को नयी नीति ग्रहण करने की सलाह दी। महामाननीय शास्त्रीजी ने भारत को स्वाबीनताप्राप्त उपनिवेश माने जाने का अनुरोध किया।

इन्ही दिनो ब्रिटिश समाचार-पत्रो में एक खबर छपी कि चागकाई शेक ने चुंगिक में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर जापान को पराजित करने के लिए युद्ध में सहयोग करने के लिए कहा है। च्यागकाई शेक के पत्रों का सवाद छपा ही या कि वाइसराय उडीसा और आसाम का दौरा समाप्त करके कलकत्ता आये और उन्होंने २० दिसम्बर को असोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स के वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया —

"मैंने भारत की वैयानिक तथा राजनीतिक समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है—इसिलए नहीं कि ये समस्याए हमेगा मेरे विमाग में नहीं रहती, इसिलए भी नहीं कि भारत की स्वगासन-सम्बन्धी आकाक्षाओं के प्रति मेरी महानुभूति न हो ओर इसिलए भी नहीं कि मेरे विचार में युद्ध के दरिमयान राजनीतिक प्रगति होना असम्भव है उसी तरह जिस तरह में यह नहीं मोच सकता कि युद्ध के खत्म होने से ही राजनीतिक अडगे का कोई हल निकल आएगा, बिल्क इसिलए कि मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में कुछ कहकर में उनके निबटारे का रास्ता साफ नहीं कर सकता। अभी तो में अपनी गिक्त उस काम में ही लगाना चाहता हूं जो मेरे सामने हैं। इस समय भारत के पास सकल्प-शक्ति और बुद्धिमत्ता का जो खजाना हे उसका उपयोग उसे युद्ध में विजय प्राप्त करने, घरेलू आर्थिक मोचें का सगठन करने और गान्ति की तैयारी करने में ही लगा देना चाहिए।

"भारत का भविष्य इन महान समस्याओ पर ही निर्भर है और इन समस्याओ को निवटाने के लिए मुझे प्रत्येक इच्छुक व्यक्तित के सहयोग की जरूरत है। यह तो मेरा विश्वास नहीं है कि शासन-सम्बन्धी कार्यों से राजनीतिक मतभेदों का निवटारा होना सम्भव हैं, किन्तु यह विश्वास अवश्य हैं कि शासन-सम्बन्धी महान् लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि हम अभी ऐसे समय सहयोग करेगे, जबिक देश के लिय सकट उपस्थित हैं, और उन लक्ष्यों के सम्बन्ध में सहयोग करेगे जिनके वारे में विभिन्न राजनीतिक वलों के वीच कोई मतभेद नहीं हैं, तो हम ऐसी परिस्थित उत्पन्न करने के लिए बहुत-कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक गतिरोध का हल हो सकेगा। सरकार के प्रधान और भारत के पुरान और सच्चे दोस्त के नाते में अपने कार्यकाल में देश को उसके उज्ज्वल की ओर ले जाने के लिए भरपूर प्रयत्न करूगा। हमारा रास्ता न तो सरल हैं और न उसे छोटा करने के लिए पगडडिया ही है। फिर भी यदि हम अपनी समस्याओं के निवटारे के लिए मिलकर प्रयत्न करे तो उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में हम निश्चन्त हो सकते है।"

ब्रिटिश राजनीतिक्षों का विरोधी रुख़

इस भाषण की भारतीय पत्रो तथा जनता ने बडी ही कटु आलोचना की। वाइसराय ने जो यह कहा कि 'अभी राजनीतिक समस्याओं के निबटारे के सम्बन्ध में कुछ कहकर उनका हल आसान नहीं बनाया जा सकता," इससे उनका मतलब क्या था ? कुछ ने 'कहने' तथा दूसरों ने 'अभी' पर ज्यादा जोर दिया। यदि 'कहना' ठीक न था तो कम-से-कम कुछ 'करना' तो चाहिए था। यदि अभी कुछ नहीं होना था तो 'भविष्य' का इतजार किया जा सकता था। इस प्रकार अगले वर्ष (१९४४) की १५ फरवरी तक राष्ट्र को इतजार मे रखा गया। इस दिन वाइस-राय को केन्द्रीय धारासभाओं के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना था। हरेक को यही आज्ञा थी कि इस भाषण में वह राजनीतिक परिस्थिति के विषय में कोई महत्वपूर्ण घोपणा करेंगे। राजनीतिक गतिरोध अभी वना हुआ था और कलकत्ते मे वह कहं चुके थे कि अभी कुछ कहने से परिस्थिति के हल को आसान नही बनाया जा सकता। यह भी सम्भव था कि मि० एमरी ने समस्या को हल करने की कोई योजना भेज दी हो, जिसे अब वाइसराय थोडी-थोडी करके अमल में लाने जा रहे हो। परन्तु उच्च अग्रेज कर्मचारियो में घबराहट फैली हुई थी—न जाने वेवल क्या करने जा रहे है। जिस तरह भारतीयों के मन में योजना के खोखलेपन का भय लगा हुआ था उसी तरह उच्च अग्रेज कर्मचारी उसके ठोस होने की सम्भावना से भयभीत थे। ब्रिटेन में कितने ही शक्तिशाली गुट प्रगतिशील उपायों को निष्फल करने के लिए पड्यत्र कर रहे थे। उनके उर्वर मस्तिष्क एक ऐसे राजनीतिक संगठन की कल्पना कर रहे थे, जिसकी सहायता से साम्राज्य को कायम रखते हुए भारत की स्वाधीनता के मार्ग में रोडे अटकाए जा सके। प्रातों में नये प्रदेश सिम्मिलित करने की योजना प्रोफेसर कूपलैंड की थी। लार्ड हेली प्रादेशिक गुट सगिठित किये जाने की बात कह रहे थे। भारतमत्री मि० एमरी ऐसे शासन-परिपदो की बात सोच रहे थे, जिन्हे हटाया न जा सकेगा। दूसरे शब्दो में ब्रिटेन को भारत में एक अनिश्चित समय तक रहना चाहिए, तािक यहा के विभिन्न दल एक-दूसरे को हडप न जाय। इनके अतिरिक्त श्री प्रो० एव० एडवर्ड-जैसे पत्रकार-जगत् में काम , करनेवाले राजनीतिज्ञ भी बोले, जिन्होने 'वर्ल्ड रिव्यू' में लेख लिखकर सुझाव उपस्थित किया था कि ब्रिटेन को दिल्ली अपने अधिकार मे रखना चाहिए और वहा से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच शाति बनाए रखनी चाहिए और देश भर की रक्षा का भार भी उसे अपने ही कथो पर बनाये रखना चाहिए। ब्रिटिश पत्रो में इन प्रतिकियापूर्ण वक्तव्यो को तो प्रमुख स्थाग दिया गया, किन्तु भारत की आर्थिक तथा कृषि-सम्बन्धी परिस्थिति पर थोडा भी प्रकाश न डाला गया। अमरीका का लोकमत कुछ तटस्थ लेखको की पुस्तको-द्वारा प्रकट हुआ, किन्तु इन लेखको का राजनीतिक प्रभाव अधिक न था।

स्वाधीनता-दिवसः १६४४

अन्य वर्षो की तरह १९४४ में भी स्वाबीनता-दिवस आया। श्रीमती सरो-जिनी नायडू स्वास्थ्य बिगडने के कारण २१ मार्च, १९४३ को जेल से छूटी थी। करीब १० महीने बाद ७ जनवरी, १९४४ को श्रीमती नायडू ने अपना मुँह खोला। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी स्वावीनता-दिवस के अवसर पर देश भर में गिरफ्तारिया हुई, किन्तु इनकी सख्या पिछले साल में कम थी। स्वावीनता-दिवस-समारोह के सिलिसले में सिर्फ वम्बई में लगभग ६० गिरफ्तारिया हुई, जिनमें १७ महिलाए, १ वालिका व १ वालक था। दूसरी जगहों में भी लोगों को पकड़ा गया।

स्वाधीनता-दिवस की प्रतिज्ञा में समय-समय पर रहोबदल होता रहा है। गोकि भाषा में परिवर्तन कर दिया गया था, फिर भी विदेशी चगुल में छुटकारा पाकर स्वाधीनता की प्राप्ति करने के राष्ट्र के दृट मकल्प में कोई कमी नहीं हुई थी। यह सकल्प वरावर हमारे सामने उस प्रकाश-स्तम्भ के समान रहा, जो अधकार, तूफान, समुद्री चट्टानो व वर्फीले पहाडों के वीच है। यद्यपि कार्य-समिति के सदस्य स्वाधीनता-समारोह में भाग लेने के लिए जनता के मध्य उपस्थित न थे, फिर भी साधारण काग्रेसजन ने झड़े को ऊचा रखा। जहा दिवस मनाने पर पावदी नहीं थी, वहा सार्वजनिक रूप से और जहा पावदी थी वहा अपने घर्म में सदा ही इस पवित्र त्यौहार को मनाया गया, क्योंकि घरों में कड़े-मे-कड़े कानून और अत्याचारी से अत्याचारी शासक की पहुच नहीं हो सकती थी। नौकरशाही ने मद्रास, वम्बई, दिल्ली, आसाम, विहार और उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता समारोह पर रोक लगा रखी थी। किन्तु एक लोकप्रिय सरकार को यह पावदी लगाने का गर्व सिर्फ सिध में ही हासिल हुआ था। सिध सरकार ने जनता के लिए यह आदेश निकाला —

"प्रतिज्ञा को पढना, या प्रकाशित करना या स्वाधीनता-दिवस मनाने के लिए अपील करना किमिनल ला एमेडमेट ऐक्ट के अतर्गत जुर्म माना जायगा और यह जुर्म करनवाले पर मुकदमा चलाया जायगा।" २६ जनवरी को लाहौर स्टेशन पर पहुचने के समय पजाव सरकार ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के खिलाफ एक आदेश जारी किया। यह आदेश चीफ सेकेटरी की तरफ से आना चाहिए था, किन्तु इस पर पजाव पुलिस के सी० आई० डी० विभाग के डिप्टी इस्पेक्टर-जनरल की तरफ से घसीटाराम नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। कहा जाता है कि घसीटाराम डिप्टी इस्पेक्टर-जनरल सी० आई० डी० के दफ्तर में एक कर्मचारी था। जब यह आदेश श्रीमती नायडू को पढकर सुनाया गया तब उन्होंने उसको पीठ पर लिख दिया कि अपने डाक्टर की हिदायत के मुताविक मेरा इरादा पहले ही से किसी सभा में भाषण करने या जुलूस में भाग लेने का नहीं हैं और इसलिए जहा तक मेरा सम्बन्ध है मेरे लिए आदेश का अस्तित्व न होने के समान है। आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वह अपने डिब्बे से वाहर निकली तब उनके मुँह से सहसा निकल पडा—"पजाब बडा दिलचस्प सूवा है और यहा की पुलिस तो और भी दिलचस्प है।"

अगला कदम: १९४४

गतिरोध दूर करने की लालसा

वेवल आये, वेवल ने देखा, पर वेवल परिस्थित पर विजयी नहीं हुए। इसके लिए हम लार्ड वेवल को दोप नहीं दे सकते, किन्तु हमें खेद तो सिर्फ इतना ही है कि उनके भापणों को देखते हुए परिणाम अधिक नहीं निकला। वाइसराय के रूप में लार्ड लिनलिथगों कुछ दु खी और निराश होकर ही भारत से विदा हुए थे। कम-से-कम उन्हें इस वात से तो धीरज मिल सकता था कि नाकामयावी ने उनका पत्ला मीयाद खत्म होने के दिनों में ही पकड़ा था। परन्तु लार्ड वेवल के माथ यह वात न थी। उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी से यह दुर्भाग्य प्राप्त किया था। इसलिए उन्होंने सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न तो आरम्भ कर दिया था, किन्तु वह सहयोग की कीमत चुकाने के लिए तयार न थे। वह तो अपनी ही शर्तों पर सहयोग चाहते थे। या कम-से-कम वदनामी के कारण को मिटाने के लिए उत्सुक थे। परन्तु काग्रेस सिर्फ अपनी शर्तों पर ही सहयोग करना चाहती थी। इमलिए उनको सहयोग के सम्बन्ध में काफी निराद्या हुई।

यदि अग्रेजों में गितरोध दूर करने की इच्छा होती तो इसमें किठनाई कुछ भी न थी। भारत में तथा इग्लैंड और अमरीका के विवेक गील हलकों में यह वात समान रूप से अनुभव की जाती थी। भारत में सर जगदी गप्रसाद, डा॰ सप्र और प्रोफेसर वाडिया-जैस व्यक्तियों के स्पष्ट वक्तव्य मौजूद थे। सभी तरफ घीरज का अन होने लगा था और अवैर्य नहीं तो कम-से-कम लोगों में आञ्चर्य फेलने लगा था। नेताओं की जेल से रिहाई के बारे में सरकार की घोषणाए खास तौर पर कुछ कर देनेवाली जान पड़ती थी। जो लोग नेताओं को रिहाई के विरुद्ध थे उन्हें जेल से बाहरवाले नेताओं के साथ जेल के भीतरवाले नेताओं का सम्मेलन करने का प्रस्ताव मूर्जतापूर्ण लगना था। उधर भारन में नरम-से-नरम विचारवाले नेता देश में बढ़नी हुई राजनीतिक विचारों में भरे हुए भारतीयों को सतुष्ट करने के लिए कुछ न किया तो यह अमतोप और भी वह जायगा। उधर इग्लैंड में पादरी लोग इस आश्वका ने चिन्तित हो रहे थे कि कही भारत में नाराजी इननी अधिक न फैल जाय कि बाद में अनेक प्रयत्न करने पर भी उसे दूर न किया जा मके।

जिन्ना साह्य का मत

वेन्द्रीय धारासभाओं के समक्ष लाई वेबल का भाषण हुए एक पत्यवारा बीत चुका था. पर अभी देश को उसके सम्बन्ध में मि० जिल्ला की प्रतिक्रिया का कुछ पता नहीं चला था। अपनी आदन के मुनाबिक मि० जिल्ला कही एक महीने बाद बादमगय या भारतमदी के भाषण पर मन प्रकट किया करने थे। परन्तु 'न्यूज कानिकल' के दिल्ली के प्रतिनिधि के मि॰ जिन्ना से मुलाकान करने की वजह से इस बार लोगों को अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। यह मुलाकात २९ फरवरी को हुई और इसमें मि॰ जिन्ना स्पष्ट और जोरदार जब्दों में बोले। मि॰ जिन्ना के पिछले वक्तव्यों और मुलाकातों के वावजूद पाकिस्तान-योजना पर अभी तक अस्पष्टता और रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था, किन्तु इस मुलाकात में यह पर्दा हट गया। उन्होंने देज की राजनीतिक अवस्था पर विचार प्रकट करते हुए 'न्यूज कानिकल' लदन के प्रतिनिधि को जो वक्तव्य दिया, वह इस प्रकार हैं —

मि० जिल्ला ने कहा—"सरकार वर्तमान परिस्थित से सतुष्ट जान पडती है और वह कोई कदम नहीं उठाना चाहती। काग्रेस गैर-कानूनी घोषित कर दी गयी हैं और उसने अपनी तरफ से किमी हृदय-परिवर्तन का परिचय नहीं दिया है।"

प्रश्न—"सरकार काग्रेस से वातचीत क्यो नही गुरू करती? या वह श्री राजगोपालाचार्य-जैरो किसी व्यक्ति को, जिसने आपकी पाकिस्तान की मान के सिद्धात को—हिन्दू और मुसलमानो के दो पृथक् राज्यो को मान लिया है, गायोजी से मिलकर उन्हे अपने मत मे परिवर्तन करने के लिए राजी करने का मीका क्यो नहीं देती?"

मि० जिल्ला—"इसका मतलव यह हुआ कि जब तक गांधीजी को राजी नहीं किया जाता तबतक सरकार हमारी उचित माग को स्वीकार न करेगी। यह तर्क हम नहीं मान सकते। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं कह सकता कि उसकी नीति क्या है, किन्तु यदि सरकार आपके सुझाव को मान ले तो इसका मतलब यह होगा कि जीत कांगस की हुई है और सरकार कांग्रेस के विना आगे नहीं बढ सकती।"

प्रश्न-"िकया क्या जाय?"

मि॰ जिन्ना—"यदि निटिश सरकार सच्चे हृदय से भारत मे शान्ति स्थापित करने को उत्सुक हैं तो उसे भारत को दो स्वाधीन राष्ट्रों में बाट देना चाहिए— पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिसमें देश का एक चौथाई भाग शरीक होगा, और हिन्दुस्तान हिन्दुओं के लिए जिसमें समस्त भारत का तीन-चौथाई भाग होगा।

प्रश्न-- "परन्तु भारत् को दो देशो मे बाटकर कमजोर वनाना या शत्रु के

आक्रमण का शिकार बना देना कभी वाछनीय नहीं हो सकता।"

मि० जिन्ना—"मैं नहीं मानता कि भारत को जबर्दस्ती एक रखकर उसे अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि इस हालत में उस पर आक्रमण का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि हिन्दू और मुसलमानों में कभी सद्भावना नहीं हो सकती। हिन्दू और मुसलमानों के लिए एक ही देश में रहना या शासन सघ में सहयोग करना असम्भव है। ब्रिटेन वर्षों से हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र का

अगला कदम : १९४४

रूप देने के लिए प्रयत्नशील रहा है, किन्तु उसे असफलता ही मिली है। अब उसे भारन में दो राष्ट्रों का अस्तित्व मान लेना चाहिए।"

प्रश्न—"पर आप जानते हैं कि काग्रेस और हिन्दू इसे कभी न मानेगे। यदि सरकार इस प्रकार की कोई योजना अमल में लाती है तो हिन्दू और काग्रेस सत्याग्रह शुरू कर देते हैं और तब हिसा और गृह-युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।"

मि॰ जिन्ना—"नही, ऐसा कुछ नही होगा। यदि ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलग-अलग कायम कर दे तो काग्रेस और हिन्दू उसे तीन महीने के भीतर स्वीकार कर लेगे। दूसरे लफ्जो में सरकार चाहे तो काग्रेस की गेखी कुछ ही समय में भुला सकती है। सच तो यह हैं कि मुस्लिम बहुमतवाले पाच प्रान्तो में पाकिस्तान के सिद्धान्त के अनुसार पहले ही कार्य हो रहा है। इसके मुस्लिम लीगी मित्रमडलो में हिन्दू मंत्री भी कार्य कर रहे है। पाकिस्तान से सभी का लाभ है। निश्चय ही हिन्दुओ को इसमें कोई आपित्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीन-चौथाई भारत पर उनका अधिकार रहेगा। उनका देश, भूमि और जनसख्या के विचार से, रूस और चीन को छोड़ कर संसार में सबसे विशाल होगा।"

प्रश्न—"परन्तु गृह-युद्ध छिडने में कोई कसर न रहेगी। आप एक भारतीय अल्सटर को जन्म देगे, जिस पर हिन्दू अखड भारत का नारा उठाकर आक्रमण कर सकते है।"

मि॰ जिन्ना—"इससे मैं सहमत नहीं हूं। परन्तु नये विधान के अतर्गत एक परिवर्तनकाल भी होगा और इस काल में, जहां तक सशस्त्र सेना और विदेशी सम्बन्धों का ताल्लुक हैं, ब्रिटिश सत्ता सर्वोपिर रहेगी। परिवर्तन-काल की लम्बाई इस बात पर निभेर रहेगी कि दोनो राष्ट्र ब्रिटेन के साथ अपने सम्बन्ध तय करने में कितना समय लगाते हैं। अन्त में दोनो भारतीय राष्ट्र ब्रिटेन से उसी प्रकार संधि करेगे, जिस प्रकार मिस्र ने स्वाधीनता प्राप्त करते समय की थी।"

प्रवन—"यदि उस समय ब्रिटेन ने तर्क उपस्थित किया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान पडोसियो के रूप में नहीं रह सकते और भारत से अपना अधिकार न हटाया जाय तव क्या होगा ?"

मि॰ जिन्ना—"यह हो सकता है, पर इसकी सम्भावना नहीं जान पडती। यदि ऐसा हुआ भी तो हमें वह आंतरिक स्वाधीनता मिली होगी, जिससे आजकल हम विचत है। एक पृथक् राष्ट्र और स्वाधीन उपनिवेश के रूप में हम ब्रिटिश सरकार से समझौता करने की उत्तम स्थिति में रहेगे जो कम-से-कम वर्तमान गतिरोध से तो अच्छी ही होगी।"

प्रश्न—"जब ब्रिटेन यह कहता है कि वह भारत को जल्दी-से-जल्दी स्वाधीनता देना चाहता है तब क्या आप उस पर विश्वास करते हैं ?"

मि॰ जिल्ला-"मै ब्रिटेन की नेकनीयती पर उस वक्त यकीन करगा जब वह भारत का बटवारा करके हिन्दू और मुसलमान दोनो को आजादी देगा। १८५८ में जान ब्राइट ने कहा या—इंग्लैंड कव तक हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना चाहता है ? क्या साबारण बुद्धि रखनेवाला कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि भारत-जैसा विशाल देश, जिसमे वीस विभिन्न राष्ट्र और वीसियो विभिन्न भाषाए है, कभी एक, अखड साम्राज्य के रूप में रह सकता है?" प्रश्न--- "क्या आप दिल्ली में वाडसराय से मिलेंगे?"

मि॰ जिन्ना--"यदि वाइसराय मुझसे मिलना चाहेगे तो मै उनसे वडी प्रसन्नतापूर्वक मिलूंगा। किन्तु अभी जो कुछ कह चुका हू उसमे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता।"

जिन्ना साहव के मत की त्रालोचना

मि० जिन्ना से जो प्रश्न किए गए थे वे ऐमे थे कि उनका वही उत्तर दिया जा सकता था, जो मि० जिन्ना ने वास्तव मे दिया था। ये उत्तर निञ्चित ओर स्पप्ट थे, जबिक मि० जिन्ना के पिछले कथन अस्पष्ट तथा अनिश्चित हुआ करते थे। १७ फरवरी, १९४४ को मि० जिन्ना ने माग की थी कि अग्रेजो को भारत का वटवारा करके चले जाना चाहिए और लार्ड वेवल का भाषण एक प्रकार से मि० जिन्ना की उस माग का जवाव था। लार्ड वेवल ने अपने इस भाषण में "भोगोलिक एकता" कायम रखने का अनुरोव किया था। मि० जिन्ना ने 'न्यूज ऋंगिकल' के प्रतिनिधि को जो वक्तव्य दियाँ उसमें उन्होने अपना विचार बदलकर यह कर दिया कि 'दिश का बँटवारा करके यही वने रहो।'' यह नारा लीग के स्वाबीनता के ध्येय की सबसे बड़ी आलोचना है। जरूरत पड़ने पर अग्रेज भारत में ही रह जायगे और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की रक्षा करेगे। मि० जिन्ना को यह भी विश्वास था कि यदि पाकिस्तान की स्थापना की गयी तो काग्रेस और हिन्दू न नो सत्याग्रह करेंगे और न गृह-युद्ध ही छेडेगे। मि० जिन्ना का मतलब दूसरे गेंव्दो मे यही था कि अल्पसख्यक वहुँसख्यक को जबर्दस्ती अपनी वात मानने के लिए विवश करेंगे। उनके इस मत से स्पष्ट था कि वह भारत में अग्रेजो के इशारे पर चल रहे थे और लीग ब्रिटेन की दोस्ती का पार्ट अदा कर रही थी। यदि लीग ने एकता की जगह बँटवारे को पसद किया तो इसके समर्थन में कुछ कह सकने की गुँजाइश हे, किन्तु जब उसने स्वाधीनता और स्वतत्रता की तुलना में पराधीनता और दासत्व को पसद किया-गोकि लीग का ध्येय स्वाधीनता घोषित किया जा चुका है-तो काग्रेस के विरुद्ध यह शिकायत करने का कुछ भी आधार नही रह जाता कि उसका बम्बईवाला प्रस्ताव लीग के विरुद्ध था। काग्रेस ने सर स्टेफर्ड किप्स के आगमन के समय दिल्ली मे एक प्रस्ताव पास करके अपना यह निज्वय जाहिर किया या कि "वह किसी प्रदेश की जनता को उसकी मर्जी के खिलाफ भारतीय सम में सम्मिलित करने की स्थिति की कल्पना नहीं कर सकती।" परन्तु मि॰ जिन्ना इससे सतुष्ट नहीं हुए। इस स्थिति की तुलना फिलिस्तीन की वेलिंग वाली घटना से की जा मकती है। उसमें न तो यहूदी अरबो की अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानते थे और न अरब ही खुछे शब्दों में स्वीकृति देते थे। इसी तरह न तो मुस्लिम लीग ही काग्रेस-द्वारा सिद्धात की अप्रत्यक्ष स्वीकृति को मानने को तैयार हुई और न काग्रेस ने ही साफ लफ्जों में स्वीकृति प्रदान की।

सहयोग की भावना

राजनीति में कभी-कभी ऐसे लोगों को मिलकर काम करना पडता है, जिन्हें मामूली तीर पर एक-दूसरे के विरुद्ध ही कहा जायगा। इन विरोधी दलों में विचारों या सिद्धातों का मेल नहीं होता, बिल्क किमी तीसरे दल के विरोधी होने के कारण उनका हित एक-दूसरे से मिल जाता है। ऐसी घटनाए वजट के ही समय दिखायी देती है। इस दृष्टि से १९४४ का वजट विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस अवसर पर काग्रेस तथा लीग के एक-दूसरे के निकट आने के लक्षण दिखायी देने लगे। लाहीर में कायदे-आजम ने भी अपने ढग से इसका पूर्वाभास दिया। २३ मार्च को लीग के मन्त्री सर यामीन खा ने केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रक्षा-नियमों में सशोधन प्रस्तुत करते समय काग्रेस तथा लीग की एकता के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया। इसका उद्देश्य दुनिया को यही दिखाना था कि काग्रेस अथवा लीग में से एक को भी सरकार पर विश्वास नहीं है। सर यामीन खा ने ऐसा कह कर सिर्फ अर्थ-सदस्य या ब्रिटिश सरकार को ही ताना नही दिया, उन्होंने अग्रेजों के दिमाग में एक तथ्य भरने का प्रयत्न भी किया। कई सप्ताह की जवानी लडाई वे बाद जब केन्द्रीय असेम्बली में वजट पर बोट लेने का दिन आया तब उसके पक्ष में ५५ और विषक्ष में ५६ बोट आये।

वजट की नामजूरी में एक उल्लेखनीय वात यह थी कि मि॰ जिन्ना न तों असेम्बली में आये और न उन्होंने भाषण अथवा वोट ही दिया था। इन प्रकार असेम्बली का यह अधिवेशन प्रमन्नतापूर्वक समाप्त हुआ। काग्रेस और लीग ने निर्फ मिलकर दुश्मन को ही शिकस्त नहीं दी थी, विल्क काग्रेस की तरफ से भूलाभाई देमाई ने लीगी व स्वतव सदस्यों को जो दावते दी और नवावजादा लियाकत अली जा ने काग्रेसियों एव स्वतव सदस्यों को जो दावते दी उनमें भी मेल-मिलाप के दृश्य दिखाई दिये। माथीपन की यह भावना वहना अच्छा ही था. क्योंकि सद्भावना के वटने में विभिन्न दलों के मनमुटाव दूर होने वा रास्ता खुल सकता था। श्रीमती सरोजिनी नायह ने इस मेल-मिलाप में आगे वटकर भाग लिया। फर्ट अनवारों में तो यहा नक छप गया था कि दोनो दलों में किननी ही महत्वपूर्ण

बातों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। उधर वाउसराय ने ६९ दिनों में भारत के ग्यारहो प्रातों का दौरा कर लिया था। इस दौरें का मुख्य उद्देश्य खाद्य-स्थिति का अध्ययन करना और साथ ही देश के विभिन्न भागों में सैनिक स्थिति को देखना भी था। इस दौरें में लार्ड वेवल ने राजनीतिक समस्या पर न तो कुछ कहा और न मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य से हुई वातचीत के अतिरिक्त किसी राजनीतिक वार्ता में ही भाग लिया।

गांधीजी की रिहाई की मांग

लार्ड वेवल को भारत आये हुए छ महीने और वाइसराय के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा हुए एक साल का समय बोत चुका था। उन्हें भारतीय राज-नीति का अनुभव भी कम न था, क्योंकि इन्जैंड में भारतमत्री के कार्यालय में रहकर उन्हें साम्राज्यवाद के रहस्यों का जान पूरी तरह हो चुका था। इस प्रकार लार्ड वेवल अपने कार्यकाल का दसवा हिस्सा इन छ महीना में समाप्त कर चुके थे। देश की आर्थिक, मामाजिक, मैनिक और राजनीतिक समस्याओ का निकट से अध्ययन करने के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न वाकी न छोडा था। गोकि सैनिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का समय नहीं रहा था, फिर भी सैनिक विषयों में लार्ड वेवल की दिलचस्पी बनी रही। अगर्चे वह फील्डमार्गल की वर्दी छोडने की बात कह चुके थे फिर भी दौरों के मध्य वह सैनिक मामलों में विशेष दिलचस्पी लेते थे। परन्तु राजनीतिक गतिरोध के सम्बन्ध मे लार्ड वेवल का दृष्टिकोण मानने के लिए भारत, इंग्लैंड या अमरीका का लोकमत तैयार न था। हिन्दुस्तान के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ अपने गातिपूर्ण जीवन को त्यागकर सोई हुई ताकतो को जगाने और कुछ न करने की नीति के खतरे से आगाह करने के लिए मैदान में आ गये थे। महामाननीय ज्ञास्त्रीजी का मकसद सिर्फ गाधीजी की रिहाई या राजनीतिक अडगे को दूर करना न होकर कुछ आगे की वातो का खयाल करना था। इसके उपरात भारत के वयोवृद्ध मनीपी महामना पडित मदनमोहन मालवीय ने भी गाधीजी और उनके साथियो की रिहाई की विवेकपूर्ण माग उपस्थित की यी। उन्होने अपनी माग उस उत्तर पर आधारित की थो जो सरकार-द्वारा लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में गाधीजी ने दिया था। जब कि एक तरफ इस प्रकार की सस्थाए अपनी आवाज शासको के कानो तक पहुचाने का प्रयत्न कर रही थी, जेल के वाहर के काग्रेसियो—विशेषकर उत्तर प्रदेश के काग्रेसियो ने मिलकर महात्मा गाधी के नेतृत्व मे विश्वास प्रकट किया और रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

गांधोजी की रिहाई

आखिरकार चमत्कार हुआ, लेकिन उसका एक दुखद पहलू भी था। दूसरी

परिस्थितियो में गाधीजी की रिहाई एक खुशी की घटना ही मानी जाती और कहा जाता कि ब्रिटेन के युद्ध-मन्त्रिमडल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। परन्तु उनकी रिहाई उनकी वीमारी और आसन्न-संकट के कारण हुई। एक मप्ताह पहले उनकी तन्द्रस्ती विगड़ने के बारे में जो समाचार छपे उनके कारण देश भर में घबराहट फैल गयी और वाइसराय के पास रिहाई के लिए तार-पर-तार पहुचने लगे। ब्रिटेन और अमरीका के दूरदर्शी लोग भी अगान्त हो गये। गाधीजी १४ अप्रैल को बीमार पडे। उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जो पहला बुलेटिन निकला उसमे डरानेवाली कोई बात न थी, पर उसी दिन उनकी हालत एकाएक विगडने की सूचना भी मिली। पाल्यमिट मे उनके स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल भी किया गया, जिसके जवाव में मि० एमरी ने कहा कि गावीजी की वीमारी ऐसी सगीन नही है कि उन्हें फौरन रिहा किया जाय। इसमें कोई शक नहीं कि चिंचल, एमरी और वेवल किमी-न-किसी तरह राजनीतिक अडगे को दूर करने के लिए उत्मुक थे, पर उनकी एक भी माग पूरी नहीं हो रही थी। दूसरे तरीको के नाकामयाव होने पर वाइसराय के रुख में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था और वह इस पर उतर आये थे कि काग्रेसजनो को खुद ही फैसला करके व्यक्तिगत रूप से वम्बईवाले प्रस्ताव के विरुद्ध मत प्रकट करना चाहिये। परन्तु काग्रेसजन जितना ही विचार करते थे उतना ही प्रस्ताव पर कायम रहने का उनका इरादा पक्का होता था। इतना ही नही, एक आर्डिनेस के अतर्गत काग्रेसजनो पर कुछ आरोप लगाये गये, किन्तु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब क्या होना चाहिये ? १५ जनवरी से ६ महीने के लिए नजरवदी के जो आदेश विये गये थे वे समाप्त हो रहे थे और विन्दियों को आदेशों की अविध वढाये विना जेलों में नहीं रखा जा सकता था। इस कठिनाई को हल करने के लिए प्रकृति या ईव्वर का वरद हस्त आगे वडा। पहले जो बुलेटिन जल्दवाजी में प्रकाशित किया गया उसमे "चिन्ता की कोई बात नहीं" और "मब ठीक है" की व्विन थी। इसके बाद जो मूनना पकाशित हुई उसमे घवराहट थी और एकाएक आगाखा महल का फाटक कोल दिया गया। इ मई. १९४४ के दिन गाधीजी को उनके दल के साथ आजाद करके पर्णकुटी पहुचा दिया गया. जो पूना में लेडी ठाकरमी का प्रसिद्ध निवास-स्यान है।

रिहाई के वाद

ाव तया हो र ताथीजी की रिहाई के दाद भारत में ही नहीं, इंग्लैंड और अमरीया में भी यही नवाल उठाया जा रहा था। न्य्याक के ईविनित टाइम्म' ने साफ लफ्जों में मजूर किया कि नेंगर की कड़ाई के कारण अमरीबादालों की गाँगीजी की गिरफ्तारी के नयय वी अनली हालत मालूम नहीं हो नकी। रिहाई

सिर्फ 'डाक्टरी कारणी' मे हुई है, इस वहाने को किसी ने मह्न्व न दिया और एक्ट्रिक करके सभी पत्रों ने यही मन प्रकट किया कि अधिकारी अवसर मिलने ही इस कटु जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। जो भी हो, कम-से-कम सभी इस विषय में एकमत थे कि कार्य-समिति के सभी सदस्यों को नुरत रिहा किया जाय और इस तरह समझौता का एक और प्रयत्न किया जाय। जापान के विषय सर्वाणिय युद्ध चलाने के लिए सिर्फ सेना में भर्ती करना ही काफी न था। यह वात भी ध्यान देने की थी कि इस बार जापान का हमला मीमा की मुठभेड न होकर भारत का पूरा आक्रमण ही था। वे आसाम और वगाल के हिस्सो में घुन आये थे और स्थिति पहले के मुकावले में कही ज्यादा सगीन थी। प्रक्त यह था कि अव इसका मुकावला कैसे किया जाय?

गाधीजी की तदुहस्ती सुधर चली थी-या कम्-से-कम ऐसी हो गयी थी कि वह मामूली कामकाज कर सके। अब उस राजनीतिक वार्ता को फिर से चलाना जो ९ अगस्त १९४२ को एकाएक भग कर दी गयी थी, ब्रिटिश सरकार का ही काम था। सावारण तीर पर यह विञ्वास किया जाता था कि जिस तरह महात्मा गाधी ने गाधी-अरविन-वार्ता और ममझौते से पूर्व १४ फरवरी, १९३१ को लाई अरविन को पत्र लिखकर वातचीत शुरू की थी, उसी तरह इस बार भी वह वाइ-मराय को निजी तीर पर पत्र लिखकर उस जगह से वार्ती आरम्भ करेगे, जहा से वह भग हुई थी। जहा तक गाघीजी का सम्बन्ध था, उनके रुख का अदाज ९ अगस्त् १९४२ से पहले की उनकी मनोवृत्ति से लगाया जा सकता है। यदि वह और उनके सायी गिरफ्तार न कर लिये जाते तो निश्चय है कि वह वाडसराय को पत्र लिखते। परन्तु गिरफ्तार हो जाने के कारण वे ऐसा न कर सके। इस तरह् ६ मई, १९४४ को उन्होने अपने को एक ऐसी लडाई के सेनापित की स्थिति मे पाया, जो कभी गुरु ही नहीं हुई। अब रक्त और आसुओं से सने इन इक्कीस महीनो का कोई अस्तित्व ही न था और गांधीजी वाइसराय के आगे अपने विचार विना किसी वाया के जाहिर कर सकते थे। सच वात तो यह थी कि जनकी रिहाई उनकी गारीरिक अवस्था के कारण नहीं, विल्क भारत की बदली हुई परिस्थिति की वजह से हुई थी और लार्ड हैलिफक्स ने भी यही मत प्रकट किया था। हिन्दुस्तान की हाळत में जो तब्दीली आ गयी थी वह तो इतनी माफ थी कि उसे बताने के लिए लार्ड हैलिफ़ेक्स के कुछ कहने की जरूरत न थी। यह बदली हुई परिस्थिति ही तो थी, जिसमे जापानी, जिन्हे भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा ते एक सप्ताह में निकाल दिया जाना चाहिए था, नौ महीने तक वने रहे। इस वदर्ल। हुई परिस्थिति में वाइसराय से कुछ कहने का गाधीजी का अधिकार था—उनका कर्तव्य था। दूसरी तरफ उनसे मि० जिन्ना से मिलने का अनुरोध भी किया जा रहा था। इस सबव में अल्लामा मशरिकी ने जब तार-द्वारा गांधीजी से अनुरोध

अगला कदम: १९४४

किया तब गाधीजी ने कहा कि मि॰ जिन्ना के लिए मेरा पिछले वर्ष का निमत्रण कायम है और मैं उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार हू। परन्तु मैं अपने जेल जीवन तथा राजनीतिक परिस्थिति के बारे में तब तक कोई वक्तव्य न दूँगा जब तक यह विश्वास न हो जाय कि वक्तव्य में कोई काट-छाट न की जायगी। यह ठीक है कि यह प्रतिबंध गाधीजी के वक्तयों के खिलाफ न था, किन्तु उन्हें इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि सेसर के साधारण नियमों के अन्तर्गत देश से बाहर जानेवाले उनके वक्तव्यों में कोई काट-छाट न की जायगी। स्थिति यह थी कि भारत से बाहर जानेवाले सभी तारों और पत्रों के सेसर होने का नियम था ओर सरकार गाबीजी के साथ भी इस सम्बन्ध में कोई रियायत करने को तैयार न थी।

गांधीजी की रिहाई को तीन हफ्ते से अधिक समय बीत चुका था। उनके अगले कदम के बारे में इन तीन हफ्तों में तरह-तरह की अटकलबाजिया लगायी गयी। एक अनुमान यह भी था कि मई के आखिर में वह एक ऐसा वक्तव्य देगे, जिसके परिणामस्वरूप सब काग्रेसी नेता छोड़ दिये जायेगे। कुछ तो यहा तक सोचने लगे थे कि गांधीजी वम्बईवाला प्रस्ताव वापस ले लेगे। परन्तु गांधीजी चट्टान के समान अडिंग थे और १३ मई को उन्होंने डाक्टर जयकर के नाम लिखा अपना निम्न पत्र प्रकाशित कर दिया —

जुह, २० मई, १९४४

प्रिय डा० जयकर,

देश मुझसे बहुत कुछ आशा करता है। मैं नहीं जानता कि मेरी इस रिहाई के बारे में आपकी क्या राय है। सच यह है कि इससे मुझे खुशी नहीं हुई है। मैं तो इसके कारण लिजित हूँ। मुझे बीमार न पडना चाहिए था। मेरा खयाल है कि मौजूदा कमजोरी दूर होते हो सरकार मुझे फिर जेल भेज देगी। और अगर वह मुझे गिरफ्तार न करे तो मैं क्या कहें?

मैं अगस्तवाला प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता? जैसा कि आप कह चुके हैं, वह दोषहीन है। उसके समर्थन के बारे में शायद आपका मत मुझसे न मिले, लेकिन मुझे तो वह प्राणों के समान प्रिय है। मैं २९ तारीख तक चुप हूँ। इस वीच क्या मैं आपके पास प्यारेलाल को भेजूँ? यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर रहेगा, क्योंकि मैं जानता हू कि आपकी भी तन्दुहस्ती ठोक नहीं है।

आपका गुभचितक एम० के० गांधी

यह पत्र प्रकाशित होते ही जनता का ध्यान उसकी तरफ केन्द्रित हो गया, क्योंकि उसमें उन दिनों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या के विषय में मत प्रकट किया गया था। गाबीजी की रिहाई से यह आजा नहीं की गयी थी कि प्रस्ताव वापत लेकर या आत्म-समर्पण करके राजनीतिक कैदियों को छुटकारा दिलाया जागण, विलक यह सोचा गया था कि गाबीजी कोई ऐसा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, जिससे किसी पक्ष के घुटने टेके विना ही काग्रेसी नेताओं की रिहाई हो सकेगी और राजनीतिक अडगे को दूर किया जा सकेगा।

गाथीजी जब-कभी भी कैंद में छोड़े गये हैं तभी उन्होंने राजनीतिक अहों को समाप्त करने की चेष्टा की है। इसलिए जब इम बार छूटे तब उन्होंने १७ जून को लार्ड वेवल के पास पत्र लिख कर कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की इजाजत मागी और लिखा कि यदि यह न हो सके तो कोई फैमला करने से पहले आप ही मुझ से मिल ले। पत्र इम प्रकार है —

> नेचर क्योर क्लिनिक, ६, टोडीवाला रोड, पूना १७ जून, १९४४

प्रिय मित्र,

यदि यह पत्र एक ऐसे काम के सम्बन्ध में न होता, जिसमें आप व्यस्त है, तो मैं आपको पत्र लिखकर कभी कष्ट न देता।

गोिक इसकी कोई वजह नहीं हैं, फिर भी देश भर ओर गायद वाहरवाले भी सर्वसाधारण के लिए मुझसे कोई ठोस कार्य करने की उम्मीद रखते हैं। खेद हैं कि मुझे स्वास्थ्य-लाभ करने में इतना समय लग रहा है। लेकिन, विल्कुल अच्छा होने पर भी मैं काग्रेस की कार्य-समिति के विचार जाने विना क्या कर सकता था के केदी की हैसियत से मैंने उनसे मिलने की इजाजत मागी थी। अब एक आजाद व्यक्ति की हैसियत से फिर मैं उनसे मिलने की इजाजत मागता हू। यदि इस विपय में कोई फैसला करने से पहले आप मुझसे मिलना मजूर करले तो डाक्टरों के लम्बी सफर की इजाजत देने ही जहां भी आप चाहेंगे आने के लिए मैं खुशी से तैयार हो जाऊँगा।

नजरबन्दी की हालत में मेरे और आपके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे मैंने कुछ मित्रों के बीच निजी उपयोग के लिए वितरित कर दिया है। परन्तु में महसूस करता हूँ और यही इसाफ का तकाजा है कि सरकार उन पत्रों को प्रकाशित करने की इजाजत दे दे।

३० तारीख तक मेरा पता वही होगा, जैसा कि ऊपर लिखा है।

आपका शुभनिन्तक मो० क० गाधी इस पत्र का लार्ड वेवल ने २२ जून, १९४४ वाले अपने पत्र में उत्तर दिया। वाइसराय का पत्र यह है —

वाइसराय भवन, नई दिल्ली, २२ जून, १९४४

प्रिय गाधीजी,

आपका १७ जून का पत्र मिला। पिछले पत्र-व्यवहार में हम दोनों के दृष्टि-कोण में जो उग्र मतभेद प्रकट हुआ है उमें देखते हुए मैं महसूस करता हू कि अभी हमारे मिलने से कोई लाभ न होगा और उससे केवल ऐसी आशाए ही उत्पन्न होगी, जो पूरी नहीं हो सकती।

यही बात आपके द्वारा कार्यसमिति से मिलने के सम्बन्ध में कही जा सकती है। आप 'भारत छोडो' प्रस्ताव के प्रति सार्वजिनक रूप से अपनी सहमित प्रकट कर चुके है, जिसे मैं भविष्य के लिए सगत तर्क या व्यावहारिक नीति नहीं मानता।

यदि स्वास्थ्य-लाभ और सोच-विचार करने के वाद आप भारत के हित के लिए निश्चित और रचनात्मक नीति का सुझाव पेश कर सके तो मैं खुशी से उस पर विचार करूगा।

चूंकि आप मुझसे पूछे विना अपने और मेरे बीच हुए पत्र-व्यवहार को वितरित कर चुके और वह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है इसलिए मैंने आपकी नजरबदी के समय लिखे गये सभी राजनीतिक-पत्रों को प्रकाशित करने का आदेश दे दिया है।

आपका शुभचिन्तक वेवल

यदि लार्ड वेवल के पत्रो और भाषणों से उनके स्वभाव का पता लगाया जाय तो प्रकट होता है कि वह किसी निञ्चय पर तो जल्दी पहुँच जाते हैं, किन्तु आगे जाकर अपने मिस्तिष्क को प्रभावित होने से नहीं बचा सकते। १७ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय धारा सभाओं के सयुक्त अधिवेशन में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जो भी विचार प्रकट किये हैं वे मेरे पहले उठनेवाले विचार हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। गाबीजी को लिखे इस पत्र में उन्होंने शुरू में अपने और गाबीजी के बीच "उग्र मनभेद" की चर्चा की हैं और कहा है कि उसके कारण मिलने से कोई लाभ न होगा, किन्तु पत्र के अत में उन्होंने उदारतापूर्वक गाधीजी के स्वास्थ्य लाभ का जिक्र किया है और कहा है कि गाधीजों "सोच-विचार करने के बाद" किसी निश्चत और रचनात्मक नीति का सुझाव उपस्थित करें। गाधीजी को सोच-विचार करने में अविक समय नहीं लगा। उन्हें न तो कोई

गुत्थी मुलझानी थी और न राजनीति की पेचीदिगियो में ही पडना था, क्योंकि गाधीजी मत्य के जिस पथ का अनुसरण करने थे वह मीवा है और अहिंगा की रणनीति भी सरल ही है।

गाधीजी की रिहार्ड में भारत और काग्रेम के इतिहास में एक तये अध्यव का श्रीगणेश हुआ था। जनता और सरकार दोनों ही को उनमें बहुत कुछ आगाण्यी। जनता चाहती थी कि गाबीजी जादू की छड़ी घुमाकर निराशा की परिस्थित का अन्त कर उसके स्थान पर आशा और विश्वास का मचार करदे। सरकार चाहती थी कि वह व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को त्याग कर सत्य और अहिमा के अपने चिर-मिद्वातों की विल चढ़ाई और पराजित पक्ष की भाति राजनीति के अलावा अन्य राष्ट्रीय कल्याणकारी क्षेत्रों में अपना महयोग प्रदान करें। गाथीजी ने जनता से कहा कि उनके पास ऐसा कोई पारस पत्थर नहीं हैं जो जनता की शियिल मानिसक स्थिति के लोहे को मोने में बदल सके और न कोई ऐसा जीवनदायी अमृत ही है, जो उदास मन में स्फूर्ति और उत्साह का सचार कर सके। इसी तरह सरकार से भी गाथीजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। आपने अपने जीवन का आधारभ्त सिद्धात वताया—उसी जीवन का जो सत्य और अहिसा पर आधारित रहा है और जिसकी अभिव्यक्ति सत्याग्रह तथा अहिसात्मक असहयोग द्वारा हुई हैं।

गांधीजी का वक्तव्य

गायीजी की रिहाई को पाच सप्ताह है। चुके थे। समार यह जानने को उत्सुक था कि गायीजी राजनीतिक अडगे को दूर करने की क्या तरकीव निकालते ह या वह ऐसी क्या वात कहते है, जिससे सुलह की वाते गुरु होने का रास्ता साफ हो। ९ जुलाई १९४४ को यही हुआ। उन्होंने 'न्यूज क्रानिकल' के प्रतिनिधि मि० गेल्डर को एक वक्तव्य प्रकाशित होने के लिए नहीं बल्कि वाइसराय तक पहुचाने के लिए दिया। अपनी इस मुलाकात मे, तथा इसका विवरण प्रकाशित होने के सम्बन्ध में गायीजी ने जो कुछ कहा उसका सार यह है —

(१) वह काग्रेस-कार्य-सिमिति की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते।

(२) यदि वह वाडमराय से मिलेगे तो उनसे कहेगे कि इस मुलाकात का उद्देश्य मित्रराष्ट्रों के युद्ध-प्रयत्न में बाधा डालना न होकर उसमें सहायता पहुँचाना ही होगा।

(३) उनका सत्याग्रह गुरू करने का इरादा विल्कुल नहीं है। इतिहास कभी दुहराया नहीं जा सकता और वह देश को फिर १९४२ की स्थिति में नहीं रखें सकते।

(४) पिछले दो वर्ष में दुनिया आगे वढी है, इसलिए परिस्थिति की फिर से समीक्षा करनी पडेगी।

- (५) नयी परिस्थिति में गाधीजी गैर-सैनिक शासन पर पूरा नियत्रण रखनेवाली राष्ट्रीय सरकार से ही सतुष्ट हो जायँग।
- (६) यदि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई तो गाधीजी उसमें भाग लेने के लिए काग्रेस को सलाह देगे।

(७) स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद वह काग्रेस को सलाह देना बद कर देगे। गाधीजी का अगला कार्य तोड-फोड तथा गुप्त कार्रवाई की निन्दा करना था। उन्होने समाचार-पत्रो मे वक्तव्य प्रकाशित करके तोड-फोड की निन्दा की और कहा कि यह हिसा है और इसने काग्रेस के आन्दोलन को हानि पहुँचायी है। उन्होने कार्यकर्ताओं को रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करने की सलाह दी और इस सिल्सिले में १४ वातों का हवाला दिया।

इस तरह गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ब्रिटेन भारत की स्वाधीनता की घोषणा कर दे तो वह कार्य-सिमिति को बम्बईवाले प्रस्ताव के उस भाग को वापस लेने की सलाह देगे, जिसमें दडात्मक कार्रवाई का हवाला है, और साथ ही उससे युद्ध-प्रयत्नों में नैतिक तथा आर्थिक सहायता करने का भी अनुरोध करेगे। गांधी-जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह खुद युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की बाधा न डालेगे। इसके वाद उन्होंने बताया कि यदि युद्ध-क्षेत्र में २००० टन गोली-गोले भेजने और दुर्भिक्ष पीडित क्षेत्र में २००० टन भोजन भेजने का सवाल उठा तो वह इनमें में किसे तरजीह देगे और ऐसी परिस्थित उठने पर कार्य-सिमिति को क्या सलाह देगे?

महान् घटनाओं और महान् व्यक्तियों का जन्म एक साथ होता है। गांधीजी ने फरवरी-मार्च, १९४३ के अनशन के दिनों में जब साम्प्रदायिक समस्या के बारे में लीग के कुछ सुझावों पर अपनी मजूरी दी थी तब उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि इन सुझावों में से एक कुछ नयी बातों के साथ स्टुअर्ट गेल्डर की मुलाकात के साथ ही प्रकाशित होगा। गांथीजी ने कहा कि दोनों घटनाए एक साथ सिर्फ सयोगवंग हुई, और यह उन्होंने ठीक ही कहा था। परन्तु ये दोनों ही घटनाए एक साथ जिस रूप में हुई उसे ऐतिहासिक आवश्यकता कहा जा सकता है। इधर श्री राजगोपालाचारी गांथीजी की रिहाई के बाद जून, १९४४ में कुछ देरी से उनसे मिलने पहुंचे थे, उधर स्टुअर्ट गेल्डर उतने ही अप्रत्यागित रूप से जुलाई के प्रथम सप्ताह में पचगनी पहुंचे थे। फिर भी वे प्राय एक साथ ही गांधीजी के सम्पर्क में आये थे। जहा एक ने साम्प्रदायिक समस्या के निवटारे के प्रस्तावों की सूचना जनता को दी थी वहा दूसरे ने राजनीतिक गितरोध दूर करने के प्रस्तावों को अधिकारियों तक पहुंचाया था। ये दो पृथक् घटनाए जान पडती है, किन्तु वे प्रकृति के निर्जीव करिश्में के समान न होकर जीवित तथ्य के ही समान थी। वे समुद्र में जल और मछली की तरह या व्यक्ति में उसके मिस्तिष्क और प्राणों

की तरह एक साथ हुई और एक साथ ही आगे वढी। वे चाहे असम्बद्ध घटनाए ही जान पडती हो, किन्तु एक साथ घटित होने के कारण ही वे भविष्य और इतिहास का निर्माण कर सकी।

गांधी-जिन्ना-वार्ता

गांधीजी अपनी रिहार्ड के बाद जो लार्ड वेवल से मीबी बात-चीत करने लग, इसका यह मतलव न था कि वह मि० जिन्ना की उपेक्षा करके अग्रेजों से समझीता करना नाहते थे। एक मान्य सस्था को छोडकर विदेशियों के साथ मिलकर उन्नित की बात सोचना बुद्धिमत्तापूर्ण अथवा उचित कुछ भी न था। इमीलिए अपने अन्यन के समय ही आगांखा महल में गांधीजी ने आत्म-निर्णय के निद्धात के आधार पर समझीता का एक गुर निकाला था। यह योजना १ साल २ महीने तक श्री राजगोपालाचार्य की देख-रेख में अतिम रूप ग्रहण करती रही। ८ अप्रेल १९४४ को यह मि० जिन्ना के आगे उपस्थित की गयी, उन्होंने उसे स्त्रीकार नहीं किया। १७ अप्रेल को श्री राजगोपालाचार्य ने एक पत्र लिखकर श्री जिन्ना ने उस योजना पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। यह सब गांधीजी की रिहार्ड अर्थात् ६ मर्ड से पूर्व हुआ। गांधीजी की रिहार्ड के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने ३० जून को मि० जिन्ना के पास एक तार भेजा और उन्हे यह भी सूचित कर दिया कि गांधीजी योजना से पूरी तरह सहमत है।

श्री राजगोपालाचार्य ठीक वंक्त पर पचगनी पहुँचे और तार-द्वारा उन्होंने मि॰ जिन्ना से अपनी बाते जारी रखी और ऐसा करते समय गांधीजी की भी सहमति प्राप्त कर ली।

पाठकों को गायद आक्चर्य होगा कि ८ अप्रैल, १९४४ को दिल्ली में प्रस्ताव उपस्थित करने की गलती के बाद श्री राजगोपालाचार्य ने उनके सम्बन्ध में पचगनी से तार क्यों दिया? कारण स्पष्ट हैं। राजाजी ने गाधीजी से सब कुछ वताया होगा और गाधीजी ने जो कुछ हुआ उसे उसकी अवस्था तक पहुँचाने का अनुरोध राजाजी से किया होगा। तारों के आदान-प्रदान के बाद प्रस्तावों को प्रकाशित कर दिया गया। योजना इस प्रकार थी —

- (१) स्वाधीन भारत के लिए नये विधान की निम्न शर्ते पूरी होने की हालत में मुस्लिम-लीग स्वाधीनता के लिए भारत की माग का समर्थन करेगी और सकान्ति काल के लिए अस्थायी अत कालीन सरकार स्थापित करने में काग्रेस के साथ सहयोग करेगी।
- (२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व में उन मिले हुए जिलो को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें मुसलमानो का स्पष्ट बहुमत है, एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में वहां के



समाचारो तथा केन्द्रीय असेम्बली में होनेवाले सवाल-जवाबों में चिंता तथा परे-शानी की भावना फैलती जा रही थी। १९४५ के मार्च और अप्रैल तक सब नेता अपने-अपने प्रातों के जेलों में भेज दिये गये। सिर्फ श्री कृपलानी को ही अपने जन्म के प्रात को भेजा गया, जिसे वे वीस साल पहले छोड चुके थे।

इसी समय २० अप्रैल, १९४५ के लगभग कामन-सभा में भारत की वर्जा छिड़ी और श्री एमरी ने वैद्यानिक व्यवस्था भग होने के सम्यन्य में भारत-सम्बन्धी आदेगों को स्वीकृति के लिए उपस्थित किया। ऐसा करने का यह अतिम अवसर था। इन आदेगों का सम्बन्ध मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बरार और विहार से था। श्री एमरी ने कहा कि इन आदेगों का उद्देश्य प्रातों में कामन-सभा के शासन-सम्बन्धी अधिकार में एक वर्ष के लिए और वृद्धि करना है। यह व्यवस्था अस्थायी तथा अमाचारण है। यदि इनमें से किसी प्रात में राजनैतिक नेता मन्त्रि-मण्डल स्थापित करके युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करना स्वीकार कर लेगे और साथ ही उनके मित्रमंडल के पर्याप्त ममय तक स्थिर रहने और धारा-सभा का समर्थन प्राप्त कर सकने की सम्भावना दिखाई देगी तो गव-र्नरों का कर्तव्य ऐसे मन्त्रिमंडल को कायम करना होगा।

भूलाभाई-लियाकतत्र्रली-समभौता

दो दिन वाद २२ अप्रैल, १९४५ को श्री भूलाभाई देसाई ने पेशावर के मीमा-प्रातीय राजनैतिक सम्मेलन में अपनी योजना के सम्बन्य में रहस्योद्घाटन किया। अगस्त, १९४२ के वाद भारत के किसी भी प्रात में होनेवाला यह पहला राजनैतिक सम्मेलन था। सम्मेलन में उपस्थित किये गये मुख्य प्रस्ताव में काग्रेस के नेताओं की रिहाई तथा केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव पर भाषण करते हुए श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि केन्द्र में अतर्कालीन-सरकार स्थापित करने के प्रस्ताव पहले से ही ब्रिटिश-सरकार के सम्मुख उपस्थित है। उन्होंने माग उपस्थित की कि ब्रिटेन को घोषणा कर देनी चाहिए कि भार-तीय-सरकार और उसके प्रतिनिधियों का पद अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य सरकारों तथा उनके प्रतिनिधियों के समान होगा। ११ जनवरी, १९४५ को होनेवाले भूलाभाई-लियाकतअली-समझौते की शर्त अगस्त, १९४५ से पूर्व प्रकाशित नहीं हुई थी, किन्तु अप्रैल में ही उन पर प्रकाश पड चुका था। उसकी मुख्य शर्त इस प्रकार थी

(क) केन्द्रीय शासन परिपद् में काग्रेस तथा लीग के सदस्यों की सल्या वरावर रहेगी। सरकार से नामजद हुए व्यक्तियों का केन्द्रीय धारासभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। (ख) अल्पसंख्यको (विशेषकर परिगणित जातियो और सिखो) के प्रति-निधि भी रहेगे।

(ग) प्रधान सेनापति भी होगे।

"इसं प्रकार की स्थापना मौजूदा भारतीय शासन के अन्तर्गत होगी और वह वर्तमान व्यवस्था के भीतर रह कर कार्य करेगी। परन्तु यह मान लिया जायगा कि यदि मित्रमंडल अपना कोई प्रस्ताव धारासभा से पास नहीं करा पायगा तो इसके लिए वह गवर्नर-जनरल या वाइसराय के विशेषाधिकारों के प्रयोग का आश्रय न लेगा। इसके परिणामस्वरूप मित्रमंडल काफी हद तक गवर्नर-जनरल के अधिकारों से स्वतत्र हो जायगा।

"काग्रेस और लीग इस विषय में सहमत हैं कि यदि इस प्रकार की अतर्कालीन सरकार की स्थापना हुई तो उस का पहला कार्य काग्रेस कार्यसमिति के सदस्यो

की रिहाई होगा।"

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन उपायों को बर्ता जायगा उन पर भी नीचे प्रकाश डाला जाता है —

उपर्युक्त समझौते के आधार पर ऐसा कोई रास्ता निकाला जाय जिससे गवर्नर-जनरल यह प्रस्ताव या सुझाव करने के लिए तैयार हो जाय कि वह खुद काग्रेस तथा लीग के समझौते के आधार पर केन्द्र में, एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना करना चाहते हैं और जब गवर्नर-जनरल मि॰ जिन्ना और श्री देसाई को सयुक्त रूप से अथवा अलग बुलाएँ तब उपर्युक्त प्रस्ताव उनके सामने इस उद्देश्य से रख दिये जाय कि इन्हें नयी सरकार में भाग लेने के लिए तैयार किया गया है।

अगला कदम प्रान्तों में धारा ९३ का हटाया जाना और केन्द्र के ही समान

वहा मिलीजुली सरकारो की स्थापना होगा।

जबिक भारतमत्री तथा वाइसराय के प्रतिक्रियावादी रुख के बावजूद भारत में घटनाचक इस दिशा में चल रहा था तभी ७ मई को यूरोपीय युद्ध समाप्त होने का सुसम्बाद भारत में ९ मई को पहुँचा। यह समाचार पाकर सभी को प्रसन्नता हुई, किन्तु भारतीय जनता को इसके कारण कोई तसल्ली नहीं हुई। भारत के नेता जेल के सीखचों में बद थे और वह खुद गुलामी की जजीरों में जकड़ा हुआ था। इसलिए वह खुशिया कैसे मनाता!

वेवल की लद्न-यात्रा

२१ मार्च, १९४५ को लार्ड वेवल की लदन-यात्रा से पूर्व उसके सम्बन्ध में वहुत विज्ञापन किया गया और समाचार-पत्रो में उसकी बारम्बार चर्चा भी की गई। परन्तु वह एकाएक वायुयान-द्वारा रवाना हो गये। श्री एमरी ने वेवल के आगमन के सम्बन्ध में कहा कि इस अवसर से लाभ उठा कर वैधानिक स्थिति

पर विचार तो अवव्य किया जायगा, किन्तु उससे अधिक आजा न करनी चाहिए। सच तो यह था कि लार्ड वेवल को स्वय थी एमरी ने हो मलाह-मजिद के लिए आमित्रत किया था। हर तरफ से परिस्थित गम्भीर थी। ब्रिटिंग लोकमत इम बात पर जोर दे रहा था कि भारत के राजनैतिक अडगे को दूर करने में भारत और इंग्लैण्ड दोनों ही का समान रूप से लाभ है। यह घोषणा हो चुकी थी कि लक्ष में लार्ड वेवल कार्य-समिति के सदस्यों की रिट्टाई के सम्बन्ध में भारत-मंत्री थी एमरी से सलाह करेंगे और इस बातचीत में राजनीतिक परिस्थित तथा भारत की वैवानिक स्थिति पर विचार होगा। भारत में रवाना होने से पूर्व लार्ड वेवल के सामने एक रचनात्मक सुझाव भी पेग हो चुका था। यह उपर्युक्त देसाई- लियाकतअली-मुझाव था।

जव कि लार्ड वेवल अभी लदन में ही ये और उनके कार्य के सम्बन्ध में सनमनीपूर्ण तारों की झड़ी लगी हुई थी, ब्रिटिंग मित्रयों का मतभेद अपनी चरम मीमा
को पहुँच गया, जिस के परिणामस्वरूप २३ मई, १९४६ को प्रधान मन्नी चिंचल न
इस्तीफा दे दिया। मि० चिंचल १० मई, १९४० को मि० चेम्बरलेन के स्थान
पर प्रधान मन्नी बने थे। जापान के साथ होनेवाला युद्ध समाप्त होने तक नयुक्त
मित्रमंडल में रहने से मजदूर दलवाले मित्रयों के इनकार करने पर वर्तमान राजनैतिक सकट उत्पन्न हुआ था। मजदूर दल के प्रमुख नेता मि० मारीसन, मि०
वेविन और मि० डाल्टन थे। मि० विवन ने घोषणा की कि यदि अगले चुनाव
में गासनसूत्र मजदूर दल के हाथ में आया तो भारत मन्नी का कार्यालय तोड दिया
जायगा और भारत से डोमीनियन कार्यालय का सम्बन्ध रहेगा। जहा तक भारत
को स्वराज्य देने का सम्बन्ध है, मि० वेविन ने साफ कह दिया कि वह उमे कमग
ही मिलेगा।

एमरी का वक्तव्य

४ जून, १९४५ के दिन वेवल भारत वापस आये ओर दस सप्ताह की अनुपिस्थिति के वाद उन्होंने अपना कार्य-भार सभाला। इग्लैंड में वह जितने समय
रहे, वह बिल्कुल असाबारण समय था। वह उस देश के इतिहास का एक ऐसा सयय
था, जिसमें पुरानी व्यवस्था विदाई लेती है और नवीन की आशा जागृत हो
उठती है। इसी वीच श्री एमरी ने ६ जून को लदन के रोटरी क्लव में भाषण देते
हुए कहा—तीन साल से अधिक समय गुजरा कि हमने इच्छा प्रकट की थी कि
युद्ध के बाद हम भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमडल के अदर—ओर यदि वह चाहे तो
बाहर भी—पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करें, किन्तु शर्त यह है कि भारत के मुख्य
दल देश के भावी विधान के सम्बन्ध में कोई समझोता करले। अन्त में उन्होंने
यह भी कहा —

"अगर इस समस्या का कोई पूर्ण या तर्कसगत जवाब नहीं मिलता (यानी अगर सत्ता हस्तातिरत करने के लिए स्वीकृत उत्तराधिकारी नहीं मिलते) तो कोई कारण नहीं कि भारत तथा ब्रिटेन दोनों ही जिस गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं उससे बाहर निकलने का कोई-न-कोई मार्ग उन्हें प्राप्त न हो जाय। जरूरत इस बात की है कि हम फिर से कोशिश करें।"

वेवल-योजना

१४ जून, १९४५ को लार्ड वेवल ने भारत की जनता के लिए रेडियो से एक भाषण ब्राडकास्ट किया और साथ ही प्राय उसी समय भारत-मत्री श्री एमरी ने भी पार्लमेट में एक वक्तव्य दिया। इन दोनो वक्तव्यो में एक ही प्रकार के विचार तथा भाव प्रकट किये गये और एक ही योजना उपस्थित की गयी । योजना की मुख्य बात यह थी कि वाइसराय चुने हुए व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाएँ जिससें कि नई गासन-परिषद् के सदस्यों की एक सूची तैयार की जा सके। इस सूची में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित किये जाय, जो सार्वजनिक रूप से तीन वातें स्वीकार करने को तैयार हो और इन तीन बातो में सब से महत्त्वपूर्ण जापानियों के विरुद्ध युद्ध करके उन्हें हराना हो। वाइसराय ने अपने ब्राडकास्ट में कहा, "विभिन्न टल ऐसे योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करे, जो विदेश विषय को मिलाकर सभी विभागो के प्रबंध तथा उनके विषय में निञ्चय करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो।" वाइसराय ने यह भी कहा कि हिन्दुओ (अछूतो को छोडकर) और मुसलमानो की सख्या वरावर रहेगी और कार्य का सचालन तत्कालीन विधान के अनुसार होगा यानी "भारत मत्री और गवर्नर जनरल के नियत्रण मे।" उन्होने अन्त मे कहा, "मै यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव सिर्फ ब्रिटिश भारत के ही सम्बन्ध में है और इनका प्रभाव सम्राट् के प्रतिनिधि से नरेशो के सम्बन्धो पर विलकुल नहीं पडता। जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, यह स्वीकार किया जाता है कि दिमयानी वक्त मे सम्राट् के प्रति-निधि के अधिकार जारी रहेगे, फिर भी यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार को कितने ही ऐसे विषय हाथ में लेने पडेगे जिनका रियासतो से सम्बन्ध होगा, जैसे, व्यापार, उद्योग, श्रम आदि । इसके अतिरिक्त एक तरफ रियासती प्रजा तथा नरेश ओर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सरकार के सदस्यों के मध्य की दीवार हटनी चाहिए जिससे समान समस्याओं को परस्पर वाद-विवाद और सलाह-मज्ञविरे के द्वारा हल किया जा सके। यदि सम्मेलन सफल हुआ तो मुझे केन्द्रीय जासन-परिषद् स्थापित करने के विषय में सहमत होने की आजा है। ऐसी अवस्था में धारा ९३ वाले प्रातो में मन्त्रिमण्डल फिर से काम करने लगेगे। ये प्रान्तीय मित्रमडल मिलेजुले होगे। . यदि सम्मेलन दुर्भाग्यवश असफल हुआ तो विभिन्न

राजनैतिक दलो में कोई समझौता होने तक हमें वर्तमान अवस्था में र

शिमला-सम्मेलन

वेवल-गोजना के अनुसार शिमला में जून के महीने में सम्मेलन हुआ। राय ने सम्मेलन के सम्मुख पदो तथा उनमें मिलाए जाने वाले विषयों । उपस्थित की। सम्मेलन में जो वहम तथा प्रश्नोत्तर हुए, उनका यहां करना ठीक न होगा, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जव के लिए मिल-जुलकर एक सयुक्त सूची उपस्थित करना असम्भव हो । प्रत्येक दल तथा व्यक्ति से अपनी-अपनी मूची उपस्थित करने को कह फिर भी वडी विचित्र वाते हुई। २८ जून से दो बैठके हो चुकने के बाद की १४ जुलाई वाली बैठक में सफलता मिलने की आशा की जा रही यी सोच-विचार के बाद उसमें दो सूचिया उपस्थित की गई। यह बडे दु खंथी कि अवतक कोई सयुक्त सूची नही बन पाई थी। यदि ऐसा होता तो उन्नति का मार्ग खुल जाता। भाग्य में तो यही था कि मुक्क की गुला आपसी फूट के कारण हुई थी वह हमारे बीच बनी रहे। सयुक्त सूची न कर सकने का मतलब यह हुआ कि भारत के एक कोने की आवाज धंगई।

११ जुलाई को मुस्लिम लीग के नेता ने सिर्फ १५ मिनट तक वाइन् मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि वाइसराय की सूर्च गैर-लीगी नाम हैं उन्हें वे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लीग भारत है मानो की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती हैं और उन्होंने जो सूर् उसमें वे अपने दल के अतिरिक्त किसी बाहरी नाम को शामिल करने तैयार नहीं है। वाइसराय ने इससे अपना मतभेद प्रकट किया। कुछ वाद गांधीजी वाइसराय से मिले और अगले दिन काग्रेस के अध्यक्ष के लिए बुलाया गया। वाइसराय ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने मुस्लि निधियों की जो सूची वनाई हैं मि॰ जिन्ना उसमें सहमत नहीं है। इससे वाइसराय ने नेताओं को कुछ नहीं बताया। वाइसराय के कार्य की विचित्र थी। वह दलों में समझौता कराने का तो प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु उन्हों अपने हाथ में सुरक्षित रखा था और अपने इसी अधिकार के कारण वह सूची तैयार कर रहे थे। वाइसराय ने नेताओं से सूचिया तो सिर्फ इसलि थी कि उनमें से शासन-परिषद् के लिए वह नामों का चुनाव करले। परन्तु राय कोई सूची तैयार नहीं कर सके। उचित कार्य-पद्धित तो यह होती अपनी सूची काग्रेसी नेताओं को दिखाते और वे उसे स्वीकृति के लिए कार्य

के आगे उपस्थित करते। १४ जुलाई को वाइसराय ने सम्मेलन यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उन्हें अपने प्रयत्नों में असफलता मिली है और इसीलिए सम्मेलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

वेवल का भाषण

इस प्रकार १४ जून से २५ अगस्त तक का काल सुस्ती का था जो देखने मे तो थोडा जान पडता है, किन्तु भारत में वैधानिक परिवर्तन देखने को उत्सुक लोगों के लिए वह बहुत लम्बा काल था। मध्यवर्ती काल में ब्रिटिश आम चुनाव का परिणाम प्रकट हुआ और १० जुलाई, १९४५ को मजदूर-सरकार की स्थापना हुई। चुनाव में श्री एमरी हार गय और उनके स्थान पर लार्ड पैथिक लारेस भारत-मंत्री वनाये गये। इसके कुछ ही समय बाद लार्ड वेवल को इंग्लैण्ड बुलाया गया। वह लदन २५ अगस्त को पहुचे और उनकी वापसी से पहले ही भारत मे केंद्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के आम चुनावों की घोषणा की गई।

वेवल स्वय १८ सितम्बर को वापस आये। आते ही उन्होने अगले ही दिन

एक भाषण ब्राडकास्ट किया, जो सक्षेप में इस प्रकार हैं ---

"हाल ही में लदन में सम्राट् की सरकार के साथ मेरा वार्तालाप समाप्त होने पर उसने मुझे निम्न घोपणा करने का अधिकार प्रदान किया हैं:—

"जैसा कि पार्लमेट के उद्घाटन के अवसर पर सम्राट् ने अपने भाषण मे कहा था, सम्राट् की सरकार, भारतीय नेताओं के सहयोग से, भारत में शीघ्र ही पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने के लिए दृढ सकल्प है। मेरी लदन-यात्रा के अवसर पर उसने मेरे साथ उन उपायो पर सोच-विचार किया है जो इस दिशा मे किये जायगे।

"इस आशय की घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के निर्वाचन, जो अब तक युद्ध के कारण स्थगित थे, आगामी शीत ऋतु में किये जायगे। सम्राट् की सरकार को पूरी आशा है कि उसके बाद

प्रान्तो में राजनैतिक नेता मन्त्रि-पद का दायित्व ग्रहण कर लेगे।

"सम्राट् की सरकार का इरादा है कि यथाशीघ्र एक विधान-निर्मात्री-परिषद् का आयोजन किया जाय और फलत प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में उसने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं निर्वाचन समाप्त होते ही, यह जानने के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के प्रतिनिधियों से वार्तीलाप करू कि १९४२ की घोषणा में जो प्रस्ताव निहित है वे उन्हें मान्य है या किसी वैकल्पिक अथवा सशोधित योजना को वे तरजीह देते हैं। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों से भी, यह जानने के लिए वार्तालाप किया जायगा कि वे किस विधि से, विधान-निर्मात्री-परिषद् में पूरी तरह से सम्मिलित हो सकते है।

"सम्राट् की सरकार उस सन्धि के विषयो पर विचार करने जा रही है जा ब्रिटेन और भारत के मध्य आवश्यक होगी।

"इन प्रारंभिक अवस्थाओं में, भारत की गासन-व्यवस्था जारी रहनी चाहिए और तात्कालिक आर्थिक एवं समाजिक समस्याओं का निवटारा भी अवव्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को नवीन-व्यवस्था की रचना में पूरा-पूरा भाग लेना है। फलत सम्राट् की सरकार ने मुझे यह भी अधिकार दिया है कि ज्योही प्रान्तीय निर्वाचनों के परिणाम ज्ञात हो जाय में एक ऐसी जासन-परिषद् को अस्तित्व में लाने का प्रयत्न कर जिसे मुख्य-मुख्य भारतीय दलों का समर्थन प्राप्त हो।

पटली का भापण

प्रवान मत्री मि॰ क्लीमेट एटली ने १९ सितम्बर के दिन ब्राडकास्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय-विधान-परिषद् सस्था के साथ एक मि करेगी, जिसका प्रस्ताव १९४२ में की गई घोषणा में किया गया था। श्री एटली ने यह भी कहा कि इस सिंघ में ऐसी कोई वात न रखी जायगी, जो भारत के हितो के विरुद्ध होगी। आगे उन्होने कहा कि भारत के प्रति ब्रिटिश नीति की वही व्याख्या, जो १९४२ की घोषणा में निहित हैं और जिसे इस देश के सभी दलों का समर्थन प्राप्त है, अपने उद्देश्य और पूर्णता की दृष्टि से पूर्ववत् वर्तमान है। उस घोपणा में ब्रिटिंग सरकार तथा विद्यान-परिपद के मध्य एक सिध की जाने का विचार प्रकट किया गया था। सरकार तुरन्त ही सिध के मसविदे की रूपरेला तैयार कर रही है। यह कहा जा सकता है कि उस सिंध में भारत के हित के विरुद्ध कोई भी बात नहीं रखी जायगी। भारत में विधान-निर्मात्री-संस्था की स्थापना तथा उसके सचालन में जो कठिनाइया आयगी और जिन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक होगा उन्हें भारतीय मामलो की जानकारी रखनेवाला कोई आदमी नजरदाज नहीं कर सकता। इससे भी अधिक कठिनाई का सामना भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियो को करना पडेगा, जिन्हे चालीस करोड प्राणियो वाले महान भू-खड के लिए विवान तैयार करना है।

कांत्रेस कमेटी का मत

लार्ड वेवल का भाषण भारतीय लोकमत के सभी वर्गों के लिए और विशेष कर काग्रेस के लिए निराशाजनक तथा असतोषजनक सिद्ध हुआ। इसका कारण यह था कि भारत की स्वाधीनता की घोषणा नहीं की गई थी। छ महीनों के लिए न तो प्रान्तों में मित्रमंडल ही कायम होगे और न केन्द्र में शासन-परिषद् का

ही पुनस्मगठन किया जायगा। इसके अतिरिक्त गोकि यथासम्भव उत्तम निर्वाचन सूची के आधार पर चुनाव करने को कहा गया था फिर भी यह सत्य था कि देश मे इस निर्वाचक सूची के विरुद्ध गहरा असंतोष फैला हुआ था। वाइसराय का प्रस्ताव, ्जिसके उद्देश्य की व्याख्या प्रधानमत्री एटली ने की थी, वस्तुत १९४२ के किप्स प्रस्तावो को ही पुनरावृत्ति थी। परन्तु ऋिप्स-प्रस्तावो की तुलना मे नये प्रस्ताव में एक भेद भी था। जहाँ किप्स-योजना में युद्ध समाप्त होते ही प्रान्तो में मित्र-मडलो के फिर से काम जारी करने और केन्द्रीय जासन-परिपद् के पुनस्सगठन की वात थी वहा सितम्बर वाली घोपणा में न तो ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी और न प्रान्तो में मित्रमडलो की स्थापना का ही कोई समय निर्धारित किया गया था। सितम्बर वाले वक्तव्य के अनुसार जनता को १९४२ में बताई नई किप्स-योजना या घोषित नीति के अनुसार उसको किसी सगोधित रूप के मध्य चुनाव करना था। समस्या की पेचीदगियो तथा अल्पसख्यको के हितो का ध्यान रखते हुए एक नई बात यह जारी की गई कि नव-निर्वाचित धारासभाए भी मत प्रकट करे कि किप्स-योजना उन्हें स्वीकार है अथवा कोई नई योजना जारी की जाय। जहा तक विधान-परिपद् में रियासतों के प्रतिनिधित्व का सवाल था, एक बिलकुल नई बात जोडी गई थी। घोषणा में कहा गया था कि रियासतो के प्रतिनिधियो के साथ भी बातचीत करके यह जानने का प्रयत्न किया जायगा कि विधान-निर्मात्री-सस्था मे वे किस रूप मे काम करना चाहते है। यह स्पप्ट नही किया गया था कि विधान परिपद् में केवल नरेशों के प्रतिनिधि रखे जायगे अथवा रियासतो की जनता के प्रतिनिधि रखे जायगे और यदि ऐसा किया जायगा तो रियासती प्रजा के प्रतिनिधि धारासभाए चुनेगी या अखिल भारतीय देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्-द्वारा चुनाव किया जायगा।

इस घोषणा में किसी प्रान्त को पृथक् होने का अधिकार नहीं दिया गया था, किन्तु एटली के वक्तव्यों में यह विल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि किप्स-योजना को मजूर करना है तो वह पूरी की-पूरी ही मानी जानी चाहिए। सितम्बर की घोषणा के बाद जनता को यह विलकुल स्पष्ट हो गया था कि गिमला की वार्ता केवल ब्रिटेन के चुनाव के सम्बन्ध में ही थी और उस चुनाव के समाप्त होते ही उस सम्मेलन को भी समाप्त हो जाने दिया गया। इसमें भी कोई सदेह न था कि सितम्बर वाला प्रस्ताव केवल छ महीने का समय प्राप्त करने के लिए एक चाल मात्र थी, क्योंकि प्रान्तीय चुनाव मार्च १९४६ से पूर्व समाप्त न होते और इस प्रकार भारतीय समस्या का हल छ महीने के लिए और टाल देने की चेप्टा की गई। इन सब बातो पर विचार करने के वाद अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने वम्चई में इन दोनो वक्तव्यो पर विचार किया और मत प्रकट किया कि सरकार के प्रस्ताव अपर्याप्त तथा अस्पप्ट है।

भारत-मंत्री का मत

तव भारत-मत्री लार्ड पेथिक लारेस ने २३ मितम्बर के दिन उन प्रमाशे के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, "मुझे नई नीति की प्रतिक्रित से कुछ भी निराणा नहीं हुई है। यह घोषणा स्वयं भारत की राजनैतिक समस्य का हल नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए ऐसा हल नहीं किया जा सकता था। "इस घोषणा से सिर्फ बह रास्ता खुल गया है जिस पर चल कर भारतीय

"इम घोषणा से सिर्फ वह रास्ता खुल गया है जिस पर चल कर भारतीय स्वगासन की मजिल पर पहुँच सकते हैं। इस मजिल तक पहुचने से पहले उन्हें जिस भी सहायता या प्रोत्साहन की जरूरन होगी, उसे मैं उन्हें सम्राट् की सरकार

की तरफ से देने को तैयार हू।

"ब्रिटिश राष्ट्रमडल के भीतर स्वशासन का जो अधिकार मिलता है उसके अतर्गत राष्ट्रमडल के भीतर रहने या न रहने की स्वतवता पहले ही दे दी जाती है। राष्ट्रमडल के सदस्यों को जो वयन वाये रहता है वह महमित के अलाव और कोई वयन नहीं होता। यही वात भारत पर भी लागू होती हैं, किन्तु हमें आशा और विश्वास है कि जब भारतीयों को राष्ट्रमडल में रहने या न रहने की स्वतवता दे दी जायगी तब वे अपनी इच्छा से और अपने हितों का ध्यान रखते हुए राष्ट्रमडल में ही रहना चाहेगे।" अपने भाषण के प्रारम्भिक भाग में उन्होंने बताया कि "मेरा आदर्श तो यह है कि भारत और ब्रिटेन बराबरी के पद-द्वारा साझेदारी की भावना से वय जाय। अधिकाश ब्रिटिश राष्ट्र भी इसी साझेदारी के आदर्श की प्राप्ति के लिए उत्सुक है।"

चुनाव की तैयारी

लार्ड वेवल के इंग्लैंड में दूसरी बार वापस आते ही देश में आम चुनाव का शोरगुल मच गया। गोकि इंग्लैंड में लार्ड वेवल ने जो कुछ किया था उससे कमेटी खुश न थी, यह साफ था कि तत्कालीन अवस्था में चुनाव का निष्पक्षता से होना असम्भव था। कमेटी सभी अयोग्यताओं तथा प्रतिवधों से भी परिचित थी। परन्तु चुनाव में भाग लेने के विषय में उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की इच्छा को प्रकट करना और उसके लिए सत्ता प्राप्त करना था। इसलिए चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए चुनाव-उप-समिति नियुक्त की गई। समिति में ये व्यक्ति रखे गये —(१) मौ० अबुल कलाम आजाद, (२) सरदार वल्लभभाई पटेल, (३) डा० राजेन्द्र प्रसाद, (४) प० गोविंद वल्लभ पत, (५) श्री आसफ अली, (६) डा० पट्टाभि सीतारामैय्या और (७) श्री शकर राव देव।

कुछ ही समय बाद चुनाव के सम्बन्ध में केन्द्र तथा प्रान्तो से ताल्लुक रखने-

वाला एक घोषणा-पत्र निकाल दिया गया।

श्राजाद हिन्द फौज

इस समय तक आजाद हिद फौज के मुकदमो से भारत भर में बड़ी सनसनी फैल गई थी। सबसे पहले कर्नल शाह नवाज, कप्तान सहगल तथा लेपिटनेट ढिल्लन पर मामले चलाए गये। सच तो यह है कि उन्हीके कारण आजाद हिद फौज की स्थापना के इतिहास पर प्रकाश पड़ा। भारत में ऐसा गायद ही कोई व्यक्ति हो जिसका दिल फौज के रोमाचकारी अनुभवो तथा साहसिक कार्यों को जानकर हिल न उठा हो। जज-एडवोकेट की अदालत मे जिन घटनाओ का बयान किया जाता था उन्हें भारत की साक्षर जनता बडी उत्कठा से नित्य ही पढती थी और निरक्षर जनता बड़ी उत्सुकता से उसे सुनती थी। इन मुकदमो का विवरण सुनने के लिए निजी तथा मार्वेजनिक रेडियों के आस-पास भीड लगी रहती थी। इस सिलसिले में श्री भूलाभाई देसाई तथा उनके दूसरे साथियों की मेवाएँ अत्यन्त मृल्यवान सिद्ध हुई। अदालत में स्वच्छन्दतापूर्वक विचार प्रकट करने की जो मुंविधा दी गई उसके कारण पराधीन राष्ट्र के अपनी स्वाधीनता के लिए लडने के अधिकार-सम्बन्धी उदार तथा लोकतन्त्रात्मक सिद्धातो का विकास हुआ। मुकदमे रोकने और बदियो को मुक्त करने के लिए व्यापक आंदोलन हुआ। मुक-दमो की सुनवाई समाप्त होने पर तीनो अभियुक्तों को आजन्म कारावास का दंड दिया गया, किन्तु प्रवान सेनापति ने उन्हें इस दड से मुक्त कर दिया। उनके छोडे जाने पर देशभर में खुशिया मनाई गईं और देश भर में अपने दौरे के बीच "जय हिंद" कह कर उनका स्वागत किया गया।

यहां यह बता देना अप्रासिंगिक न होगा कि १९४५ के जाड़ों में आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को मुक्त कराने के आन्दोलन के सिलिसिले में देश भर में जो प्रदर्शन हुए उनके कारण कलकत्ते में गोली चली, जिसमें ४० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। इसी प्रकार बबई में भी गोली चली जिस में २३ व्यक्ति मारे गये और लगभग २०० घायल हुए। आजाद हिंद फौज के दूसरे मुकदमें में जब कप्तान रशीद को आजन्म कैंद की सजा दी गई और प्रधान सेनापित ने उसे घटा कर सात वर्ष का कठोर कारावास कर दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुए, जिनमें मुसलमानों ने भी भाग लिया। इस सिलिसिले में जो प्रदर्शन कलकत्ते में हुआ उस में ४३ व्यक्ति मारे गये और ४०० के लगभग घायल हुए। यह फरवरी १९४६ की बात है।

२३

पराधीनता के बंधन टूटे : १६४६-४७

केन्द्र में चुनाव ममाप्त हो चुंक थे, किन्तु प्रान्तों में उम्मीदवारों वा चुनाव ओर नामजदगी का कार्य जारी था और उस नार्य में नेता और अनुयायी दोनों ही व्यस्त थे। इस बीच कभी-कभी आजाद हिंद फीज के सस्दयों के मामलों की सनसनी भरी खबरे गुनायी दे जानी थी। एक समय ने ऐसा जान पड़ता था कि कर्नल बाह नवाज, कर्नल महगल और कर्नल डिल्लों की रयित राष्ट्रीय नेताओं की कीर्ति को भी डक लेगी। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे आजाद हिंद फीज काग्रेस की लोक-प्रियता छीन लेगी और विदेश में युद्ध तथा हिंसा से लंबी जानेवाली लंडाड्या अहिसात्मक लडाइयों की याद घुंबली बना देगी। परन्तु कालेपानी की सजा पाये हुए नीनों अफसरों को वाइसराय ने जो क्षमा-प्रदान किया इससे आजाद-हिंद फीज के लिए उठने वाले जोश में कमी हुई।

काग्रेम की गिवत दिन-प्रति-दिन वहने लगी। ८ जनवरी, १९४६ को श्री विलियम फिलिप्स की राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सम्मुरा उपस्थित रिपोर्ट का माराग प्रकागित हो गया। यह रिपोर्ट श्री फिलिप्स ने भारत से अमेरिका लौटने पर राष्ट्र-पति रूजवेल्ट को दी थी। इससे काग्रेम की गिवत मे और भी वृद्धि हुई। यह रिपोर्ट एक उर्दू देनिक "मिलाप" मे ८ जनवरी, १९४६ को प्रकाशित हुई थी, किंगु ८ जनवरी, १९४६ तक उस मरकारी तौर पर प्रकाशित नही किया गया था।

फिलिप्स की रिपोर्ट

"काग्रेस का उद्देश्य अपने को एक फासिस्ट सरकार के रूप में स्थापित करना न हो कर स्वाधीनता के लक्ष्य की, तथा भारतीयो-द्वारा अपना विधान आप तैयार करने के अधिकार की प्राप्ति के लिए भारत में एकता नायम करना है।" मुस्लिम लीग की माग के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया—"मुस्लिम नेता यह प्रमाणित करने में सफल नही हुए है कि काग्रेस के शासन में मुसलमानों के हितों की हानि हुई है। प्रान्तीय शासन की समीक्षा से सिर्फ यही जाहिर हुआ हे कि एक राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग कभी शासन-व्यवस्था पर नियत्रण नहीं जमा सकेगी और कितपय प्रान्तों को छोड कर घारा-सभाओं में अल्पमत में ही रहेगी। वह केन्द्रीय असेम्बली में भी अधिकाश स्थानों पर अधिकार करने में सफल नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग की शिकायत दरअसल यही है। काग्रेस ने रियासतों के सम्बन्ध में जो रूप ग्रहण किया है उसके सम्बन्ध में श्री जिन्ना तथा दूसरे मुस्लिम नेताओं की चिन्ता तथा उनकी पाकिस्तान की माग का भी इससे स्पष्टीकरण

हो जाता है।" आगे कहा गया—"मुसलमानो ने भारत को स्वराज्य देने के सम्बन्ध में जो यह आपत्ति की थी कि राजनैतिक क्षेत्र पर काग्रेस का प्रभुत्व रहेगा, वह अब नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा यह मानने के काफी कारण हैं कि अन्य राजनीतिक सगठनों में हुए परिवर्तनों का खुद मुस्लिम लीग पर असर पडेगा।"

· नवाब भूपाल की घोषणा

भारत की समस्या के सदा से दो भाग रहे है—प्रान्त और रियासत। नया वर्ष आरम्भ होते ही रियासतो की प्रजा को नवाव भोपाल की घोपणा के कारण आशा की किरण दिखायी देने लगी। नवाब साहब नरेन्द्रमडल के चासलर थे। १८ जनवरी, १९४६ को उन्होंने निम्न घोपणा की —

"नरेन्द्र-मडल ने मित्रयों की समिति से परामर्श करने के उपरान्त रियासतों में वैधानिक उन्नित के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और वह (समिति) सिफारिश करती है कि नरेन्द्र-मडल इस सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा करें और जिन रियासतों में अभी तक इम सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनमें तुरन्त उचित उपाय कियें जायें। परन्तु ठीक वैधानिक स्थिति पर इमका कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा, जिसके सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार की तरफ में घोपणा की जा चुकी है और जिसे श्री वाइमराय भी दुहरा चुके है। कहा जा चुका है कि किसी रियासत और उसकी प्रजा के लिए कैसा विधान उपयुक्त होगा—इसका निर्णय स्वय शासक के ही हाथ में रहेगा।

"अस्तु, नरेन्द्र-मडल की तरफ से उसके चासंलर को निम्न घोपणा करने का

अधिकार दिया जाता है-

"हमारा उद्देश्य ऐसे विधान का निर्माण करना है, जिसमें नरेशों की सत्ता का उपयोग नियमित वैध मार्गों से होता रहे, किन्तु इससे इन रियासतों के राजवश तथा उनकी स्वतत्रता पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। प्रत्येक रियासत में निर्वाचित बहुमतवाली लोकप्रिय संस्थाए रहे, जिस में रियासत के शासन-प्रबंध से जनता का सम्बन्ध रह सके। प्रत्येक रियासत का विस्तृत विधान तैयार करते समय उस रियासत की विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाय।"

वेवल का भाषण

केन्द्रीय-असेम्बली में वाइसराय ने २८ जनवरी, १९४६ को निम्न भाषण दिया —

"मैं कोई नई या चित्ताकर्षक राजनीतिक घोषणा करने के लिए यहा नहीं आया हूँ। मैं केवल भारत के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलने तथा उनका स्वागत करने और उनसे प्रोत्साहन की कुछ बाते कहने के लिए ही आया हूँ।

"मैं समझता हू कि सम्राट् की सरकार के मन्तव्य यथेष्ट रूप से स्पष्ट कर दिये गये है। राजनीतिक नेताओ-द्वारा सघिठत नई शासन-परिपद् स्थापित करन और शासन-विधान वनानेवाली सभा या सम्मेलन यथासम्भव शिध्न-से-शिध्र जुटाने का उसका दृढ निञ्चय हैं।

"मे यह चाहता हू कि आप इस अधिवेशन के दौरान में इस सभा की वहसों में ऐसी कोई वात न कहें, जिससे मुझे राजनीतिक आधार पर अपनी शासन-परिपद् को बनाने में कठिनाई पेश आधे अथवा मुख्य वैधानिक समस्याओं के समझौते की सम्भावना पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा देश में पहले में ही विद्यमान कट्ता और अधिक वह जाय।

"केन्द्रीय असेम्बली के चुनावों के समय काफी से अधिक वैमनस्य पैदा हो गया है और यह सम्भावना है कि प्रान्तीय चुनावों के समय भी ऐसा ही होगा। यदि इस अधिवेशन के दौरान में सभी भाषणों में सयम में काम लिया जाय तो उससे मुझे और मेरा स्थाल है कि आपके दलों के नेताओं को भी बड़ी मदद मिलेगी।

"मुझे आगा है और मैं विश्वास करता हू कि असेम्ब्रली-द्वारा विनाश-मूलक कार्यों के अन्त का समय निकट है। यदि मुख्य दलो-द्वारा समर्थन प्राप्त नई शासन-परिषद् मनोनीत करने में मैं सफल हुआ, तो अगले अधिवेशन में आप लोगों के सम्मुख अत्यधिक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य उपस्थित किया जायगा।"

सरकारी विश्वप्ति

इस बात की काफी चर्चा थी कि जुलाई,१९४५ में शिमला में जैसा लज्जाजनक नाटक हुआ था उसकी पुनरावृत्ति इस बार न हो। २९ जनवरी,१९४६ को प्रका-शित एक विज्ञित्त में उससे बचने का एक तरीका निकाला गया —

"प्रान्तो में चुनाव समाप्त हो जाने ओर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल स्थापित हो चुकने पर वाइसराय प्रान्तीय सरकारो से कार्यकारिणी परिषद् के लिए कुछ नाम मागेगे। ये नाम अधिक नही सिर्फ दो या तीन होगे।

"नाम प्राप्त हो जाने पर वाइसराय एक कामचलाऊ सरकार के सदस्यों का चुनाव कर लेगे और यदि किसी प्रान्तीय सरकार ने नाम भेजने से इन्कार कर दिया तब भी वाइसराय की योजना पर उसका कुछ प्रभाव न पडेगा।

"यदि कोई प्रान्तीय सरकार नाम भेजने से इन्कार करेगी तो वाइसराय प्रान्तीय असेम्बली के दलों के नेताओं से सम्पर्क करेगे और फिर कार्य-कारिणी परिपद में उन व्यक्तियों को रख लेगे, जिन्हें वे प्रतिनिध समझेगे।"

इस विज्ञप्ति में सदाशयता की एक झलक दिखायी देती थी। लार्ड चोर्ले से भारत के भविष्य के सम्बन्ध में कलकत्ता में प्रश्न किये जाने पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक अडगा अधिक समय तक न रहने दिया जायगा और यदि दुर्भाग्यवय भारतीयों के मतभेद मिट न सके तो ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ घोषणा करनी ही पड़ेगी। यदि किसी दल ने सम्राट्-सरकार की योजना से सहयोग करने से इन्कार कर दिया तो सरकार विरोध के बावजूद योजना को अमल में लायेगी।

मन्त्रि-मिश्रन की नियुक्ति

सन् १९४५ में इंग्लंड की मजदूर-सरकार ने भारत के लिये एक पालिया-मेण्टरी शिष्ट-मण्डल भेजने की जो एक योजना बनाई थी उससे राजनीतिक घटनाओं की प्रतीक्षा करनेवाली भारतीय जनता का घ्यान बँट गया। पहले कहा जाता था कि शिष्ट-मण्डल एम्पायर पालियामेटरी एसोसिएगन की तरफ से जायगा, किन्तु इस खबर से सभी लोगों में नाराजी फैल गई। तब पालियामेट ने यह दायित्व अपने कथो पर लिया और शिष्ट मण्डल में सभी दलों के प्रतिनिधि रखे गये। यह शिष्ट-मण्डल एक अनियमित कमीगन से अधिक और कुछ न था। १९३५ के कानून को पास हुए १९४६ में दस से भी अधिक वर्ष बीत चुके थे। इसलिये पालियामेटरी शिष्ट-मण्डल भेजकर गाही कमीगन नियुक्त करने की अप्रिय वात में बचा गया। ब्रिटिंग मरकार की यह एक चाल थी, जो चल गयी ओर छोटे-बड़े मब काग्रेसजन इस चाल में आ गये। उसमे लार्ड पैथिक लारेस, सर स्टेफर्ड किप्स तथा श्री एच० बी० अलेग्जैंडर थे।

२५ फरवरी, १९४६ को लाई पैथिक-लारेंस के सम्मान में एक भोज दिया गया, जिसमें कहा गया कि वे जैसे साथियों के साथ जा रहे हैं उससे उन्हें अपन मिजन में सफलता अवव्य ही मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, "समस्या बहुत ही पेचीदा है। हमें जिस पथ में चल कर स्वाधीन भारत के आधार के लक्ष्य तक पहुचना है वह अभी साफ नहीं है। परन्तु हमें स्वाधीन भारत का नजारा दिखायी देने लगा है और इस नजारे से उत्साहित होकर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ प्रयत्न करते हुए स्वाधीनना के मार्ग को हमें खोज निकालना है। हम भारत का सरक्षण यहें सम्मान और गौरव में उसके नेताओं को साँप सकते हैं।

मंत्रि-मिशन का श्रागमन श्रौर कार्य

लाई पैंपिक लारेम २३ मार्च १९४६ को भारत पहुंच । उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा — 'त्रिटिश नरकार तथा ब्रिटिश राष्ट्र अपने उन वायदो तथा वचनो तो पूरा करना चाहते हैं जो दिये गये हैं और हम विश्वाम दिलाने हैं नि अपनी यातचीत के बीच हम ऐसी कोई शर्त उपस्थित न करेंगे, जो भारत के स्वा-गीन अस्तित्व में मेल न पाता हो।' मर स्टैंकई क्रिप्स ने कहा लि वह हिन्दुस्तान में दिरोपी दावों का फैनला करने नहीं आये हैं, विलय भारतीयों के हाथ में मना मौपने वा उपाय गोज निरालने आये हैं।

मित्र-मिश्यन का भारत में अच्छा स्वागन हुआ। वह भारत के प्रमृत ता नीतिजों से मिला और इस देश की राजनीतिक परिस्थित से अवगत हुआ। मला काते लम्बी हुई। कार्यस की कार्यसमिति १२ अप्रेल को बुलायी गयी। सिश्मित्त ने वाइसराय को भी अपना एक सदस्य बना लिया। यह १०४२ की तुन्त में नवीनता थी, नयोंकि तब सर स्टैंकई किस ने अकेले ही जिम्मेदारी उठा की थी। मिश्रन ने वात्त्रीत चलाने के लिए कार्यस तथा लीग में अपने चार-जा प्रतिनिधि चुनने का अनुरोध विया। इन प्रतिनिधियों को मिश्रन में शिमला में मिलना था। कार्यस के प्रतिनिधियों ने निर्धारित समय स्वीकार कर लिश्म किन्तु श्री जिन्ना ने तीन दिन बाद अपना समय दिया। त्रिदल-सम्मेलन दस कि तक पहाड पर चलता रहा। फिर मिश्रन दिल्ली आ गया। निस्त्रण के सार विचार के लिए किन्त्रय प्रस्ताव उपस्थित किये गये।

यहाँ प्रस्तावों का मक्षेप दे देना अनुचित न होगा—"जिस वालिंग मताविकार पर काग्रेस जोर दे रही थी उसे सिर्फ इसीलिए रोक लिया गया कि उसे जारी करने में देरी अवश्यम्भावी है। ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए प्रान्तों की मीज्ञ निम्न धारासभाओं को चुनाव-मिनितिया मान लिया गया। परन्तु स्थानों के सन्त्रक्ष जनसङ्या ने स्थापित करके यानी १० लाख के पीछे एक प्रतिनिधि के हिमाब से कुल स्थानों की मस्या दुगनी कर दी गयी। अलामस्थकों को जो अति-रिक्त-प्रतिनिधित्व दिया गया या उनका अत कर दिया गया। मुपलमानों मिल्लों तथा अन्यों के लिए स्थान निर्धारित किये गये, किन्तु अन्तिम वर्ग में में भारतीय ईसाइयों तथा ऐंग्लो-इडियनों को छोड़ दिया गया। उमीलिए अल्पसर्यकों फिरके-वालों और अलग किये गये क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विजेप सिर्मित बनायी गयी और कहा गया कि उनके अधिकारों, का नमावेग प्रान्तों, समूहों अथवा नध के विधानों में कर लिया जायगा। इनकी पद्धित नीचे दी जाती हैं

"प्रान्त निम्त तीन ममूहो (ग्रुपो) में रखे जायँगे —'ए —मद्रास वर्म्बई, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्यप्रान्त, उडीसा, 'वी'—पजाव, मीमाप्रान्त, सिष 'मी'—गणल, आसाम। 'ए में १६७ आम और २० मुस्लिम प्रतिनिधि रहेगे। वी' में ९ आम, २२ मुस्लिम और ४ सिक्ख प्रतिनिधि रहेगे। 'मी' में ३४ आम और ३६ मुस्लिम प्रतिनिधि होगे। रियासते ९२ प्रतिनिधि भेजेगी, किन्तु चुनाव का तरीका अभी निश्चित होना वाकी है। इन कुल ३८५ प्रतिनिधियो में दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कुर्ग और ब्रिटिश विलोचिस्तान के एक-एक प्रतिनिधि को जोडना चाहिए। ये ३८९ प्रतिनिधि शोध्र ही नयी दिल्ली में एकत्र होकर अपने अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियो का चुनाव करेगे और एक सलाहकार मिनित भी नियुक्त करेगे। इसके वाद वे नवीन भारत की नीव रखने का कार्य हाथ में लेगे।

"प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए एकत्र होने के बाद प्रतिनिधि तीन भागों (सेक्यनों) में बॅट जायँगे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। वे अपने समूह के प्रान्तों के लिए विधान तैयार करेंगे। वे यह भी निश्चय करेंगे कि इन प्रान्तों के लिए समूह (ग्रूप) विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन विपयों का प्रवय सौपा जाय। इसके बाद सब सदस्य फिर एकत्र होकर भारतीय सब का विधान तैयार करेंगे। चुनाव की पद्धति आनु-पातिक प्रतिनिधित्व की रहेगी, जिसमें एकाकी हम्तातरित मत प्रणाली को आधार माना जायगा। उद्देश्य यह है कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक मतों के आधार पर नहीं बल्कि कम से कम मता के आधार पर चुने जायँ।

कांग्रेस का मत

मंत्रि-मिशन हिन्दुस्तान में करीव तीन महीने ठहरा। उसने शुरू से ही वाइसराय से मिल कर काम किया। पहले चुने हुए नेताओं से वातचीत से उसकी सरगर्मी आरम्भ हुई। पहले दो हफ्ते तक एक-एक व्यक्ति से मिलने की वही पुरानी चाल दुहराई गई। इस तरह विभिन्न दलो के नेताओ, राजनीतिजो, महात्माओ, विद्वानो, ञासन-परिपद के सदस्यो, उद्योगपतियो, व्यापारियो तथा वेगानिक कानून के अध्यापको से मुलाकाते हुई। यह गतिरोध की अवस्था थी जेसी उस समय होती है जब इजन के वॉयलर में भाप रुकी होती है या कार के सेल्फ-स्टार्टर में विस्फोट होने को होता है। साथ ही यह उन जिस्त के सचय का वक्त भी था, जो वायुयान में आपके कदम रखने और उसके आकाग में उठ जाने के दर्मियान आवय्यक होती है। इस बार मिगनस्पी वायु यान के चालक स्वय गवर्नर-जनरल थे और पहले-जैमी गलती नहीं की गयी थी। मियन का वाय्यान उठा और उचित अचाई पर पहुचकर गान से महराने लगा। मिगन के पहले दरतव्य का ही देन में अच्छा प्रभाव पड़ा। परन्तू इस ववतव्य का विश्लेषण भारत-जब पूर्वी राष्ट्र के मेघावी मस्तिष्कों ने किया तो प्रकट हुआ कि उसमे जिस व्यवस्था को उपस्थित किया गया है उसने सजीव बारीर के अग-प्रत्यन तो सभी है, किन्तु जीवन के लक्षणों का पूर्णन अभाव है। इस योजना में उस जीवनदायिनी शक्ति और लचीलेपन का अभाव था, जिससे विसी दिवान की उन्नति सम्भव होती है। वक्तव्य को देखकर पहले जो हुई और आगा की लहर दोड गयी थी उनका स्थान अय उनकी परसार-विरोधिनी बातो को देनकर उदानीनता ने छे लिया। फिर जिन वानों के सम्बन्ध से नदेह उठा उनके स्पर्प्टाकरण या प्रयन्न जन किया गया तव एवं स्वष्टीकरणों से वह उदासीनना निराशा में वदर गयी।

कारोम भारत को वंथानिक इष्टि ने स्वाधीन देखने की अधिक इच्छक नहीं भी—वह निर्फ वास्तिविक स्वाधीनता ने ही मतुष्ट हो मवनी थी। परन्तु वक्तव्य

कांग्रेस की ग्रापत्तियाँ

काग्रेस की आपत्तिया तीन थी—(१) जनाव निन्तर का चुनाव, क्योंकि मोमाप्रान्त के चुनाव में उन्हें काग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में नफरता नहीं मिली थीं और औरगजेव मित्रमंडल के एक मदस्य के रूप में उनके विरुद्ध एक अविन्वास का प्रस्ताव पेश हो चुका था, (२) अतिरम सरकार में कोई राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं रखा गया था और (३) ये परिवर्तन काग्रेस की सलाह के विना ही किये गये थे।

अस्तु, वाइसराय की सूची प्रकाशित होने पर जान पड़ा कि उसे एकाएक स्त्रीकार नहीं किया जा सकता। सरदार वलदेविमिंह के नाम के गम्द्रन्य में तिलों से सलाह लेनी वाकी थी। इसी तरह गीमाप्रान्त के नेताओं से भी परामर्थ करना था। इसके अलावा श्री हरेकृष्ण मेहताव की जगह शरत वावू का नाम रखने का सवाल था। श्री मेहताव से वाइसराय के पत्र का उत्तर देने को कहा गया कि प्रान्त के प्रधानमंत्री तथा काग्रेसजन के रूप में वह पूरी तरह कार्यसमिति के नियन्त्रण में है। सवाल था कि क्या इनमें से प्रत्येक आपित्त को इस सीमा तक बड़ाया जाय कि उससे गितरोव उत्पन्न हो जाय? क्या कोई मुनलमान ऐसा स्थान स्वीकार करेगा जो किसी काग्रेसो हिन्दू का नाम वापस ले कर बनाया गया हो? इसके अलावा, काग्रेस ने श्रीमती अमृतकीर वा जो नाम उपस्थित किया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इस में काग्रेस की मर्यादा का भी प्रश्न उठता था। काग्रेस वड़ी पेचीदी स्थिति में थी। १८ जून को अतरिम सरकार की योजना स्वीकार करने का निश्चय कर लिया गया। उस रात प्रस्ताव का मसविदा तयार कर लिया गया। अस रात प्रस्ताव का मसविदा तयार कर लिया गया। अस रात प्रस्ताव का मसविदा तयार कर लिया गया। अस रात प्रस्ताव का मसविदा तयार कर लिया गया और दूसरे दिन पड़ित जवाहरलाल नेहरू काश्मीर चले गये तथा कुछ अन्य सदस्य दिल्ली के वाहर चले गये।

इसके वाद परिस्थित एकाएक गम्भीर हो गयी। खान अब्दुल गफ्कार खाँ से परामर्श करने के वाद जनाव निरुतर-सम्बन्धी ममस्या प्रथम कोटि की नहीं समझी गई। मेहताव-सम्बन्धी मामला इस तरह हल हुआ कि शरत वाबू को नियुक्त करने की वात मान ली गई। लेकिन अगर काग्रेस राष्ट्रवादी मुसलमान को न रखने की गुस्ताखी को पी जाती तो उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रह जाता। इसी अवसर पर श्री जिन्ना ने अतिरम सरकार में राष्ट्रवादी मुसलमान को रखने के विरुद्ध चेतावनी दे कर इस प्रश्न पर और भी ध्यान आकृष्ट कर दिया और साथ ही इससे श्री इजीनियर के चुने जाने को भी महत्व प्रदान कर दिया। इन्हीं दिनों 'स्टेट्समैन' ने वाइसराय तथा श्री जिन्ना के मध्य हुए पन्न-व्यवहार का रहस्योई-घाटन किया। लोकमत का झुकाव कुछ यह हुआ कि श्री जिन्ना अपनी हठधमी- द्वारा काग्रेस से एक-के-वाद एक रियायत प्राप्त कर रहे है। तव काग्रेसी मुसलमान

के सिम्मिलित न करने और एक सरकारी अफसर का नाम मूची में सिम्मिलित करने के प्रक्रनो पर अधिक गौर किया गया और उन्होने पहले की अपेक्षा अधिक महत्व धारण कर लिया। अनुपस्थित सदस्यों को फिर बुलाया गया, क्यों कि दोनों ही वातों पर फिर से विचार करना अनिवार्य हो गया था। कार्य-सिमिति के कवो पर राष्ट्र की जिम्मेदारी थीं और वह किसी समस्या का फैसला खीं अकर या निराणा के वशीभूत हो कर कर सकती थी। सूची में निक्तर के सिम्मिलित करने, मेहताव तथा इजीनियर को विना सलाह किये रख लेने और राष्ट्रवादी मुसल-मान और एक कांग्रेसी महिला को न रखने के सम्बन्ध में गांधीजी के दृढ विचार स्पष्ट थे। कुछ सोच-विचार के बाद कार्य-सिमिति भी गांधीजी के ही मत पर आ गयी।

वाइसराय की हठधर्मी

२१ जुन को काग्रेस के अध्यक्ष ने वाइसराय से श्री जिन्ना-द्वारा उन्हें लिखे गये पत्रो और उन पत्रों के वाइसराय-द्वारा लिखे उत्तरो की प्रतिलिपि मागी। ये पत्र अतिरिम सरकार में एक काग्रेसी हिन्दू सदस्य के स्थान पर एक मुस्लिम सदस्य नामजद करने के काग्रेस के अधिकार के सम्बन्ध में थे। वाइसराय ने पत्रो की प्रतिलिपि नही दी। समाचारपत्रों में छपा था कि श्री जिन्ना ने वाइसराय से कुछ प्रश्न किये हैं। वाइसराय ने इन कथित प्रश्नो के उत्तरों के उद्धरण दिये। उनसे इस बात की पुष्टि होती थी कि वाइसराय इस समस्या के सम्बन्ध में पूर्णत श्री जिन्ना के साथ है। वाइसराय का यह रुख उनके उस दृष्टिकोण से विलकुल भिन्न था, जिस का परिचय उन्होने श्री निस्तर के अतरिम सरकार में सम्मिलत करने की समस्या को लेकर मौलाना आजाद को लिखे गये अपने पत्र में दिया था। इस पत्र में वाइसराय ने लिखा था कि जिस प्रकार लीग काग्रेस-द्वारा नामजद किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकती, उसी प्रकार काग्रेस भी लीग-हारा नामजद किसी व्यक्ति के अतरिम सरकार में सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति नहीं कर सकती। यदि १४ जून तक यह स्थिति थी तो समझ में नहीं आता कि २१ जुन या २२ जुन को वाडमराय यह कैसे कह सकते थे कि काग्रेम अतिरम सरकार के लिये किसी मुमलमान का नाम उपस्थित करने के लिये स्वतंत्र नहीं है। वाइनराय का यह कवन इमलिए और भी आपत्तिजनक था कि ऐसा वे श्री जिन्ना के आनित करने पर कह रहे थे। इसके अलावा चाइसराय ने पहले काग्रेस को यह भी आव्वासन दे दिया था कि यदि काग्रेम जाकिर हुमेन का नाम पेश करेगी तो उन पर आपत्ति न की जायगी। यह कहने के बावजूद भी बाइमराय ने अपने २२ जुन के पत्र में काग्रेस के अब्यक्ष के अन्रोब को अस्त्रीकार कर लिया।

सिर्फ यही नहीं, श्री जिन्ना के प्रश्नों में कुछ नयी वार्ते भी उठती थी। यह एक तरफ वाइसराय समान-प्रतिनिधित्व की वात में इन्कार कर रहे थे तो दूसरी तरफ श्री जिन्ना परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व काग्रेम में अलग चहते थे और अल्पस्यकों के चार प्रतिनिधियों में एक स्थान उसे भी देना चहते थे। इस तरह काग्रेस के प्रतिनिधियों की सरया निर्फ ५ कर दी गयी थी और काग्रेम को हिन्दू-सस्था घोषित कर दिया गया था। इमसे यह भी जाहिर होता था कि पिर गणित जातियों का काग्रेस या हिन्दुओं से कोई मम्बन्य नहीं रहेगा। परन्तु अतिस सरकार में अल्पस्ख्यकों के स्थाने: में से कोई स्थान रिक्त होने पर निपेवात्मक अधिकार श्री जिन्ना को साप दिया जायगा। उनके जलावा जासन-प्रवन्य के सम्बन्य में अतिस मरकार में सामूहिक बहुमत का नियम लाग होगा। इन तरह अतिस सरकार की स्थित वाइसराय की जारान-परिपद में भी बुरी हो गयी थी। सच तो यह है कि १६ मई के वक्तव्य से पूर्व जो भी बाते कही गयी थी अब उनका कुछ भी महत्व नहीं था। ऐसा जान पहता था, जैसे प्रत्येक विषय में वाइसराय श्री जिन्ना के साथ हो।

मंत्रि-मिश्रन का कार्य

समिति ने साहस करके २३ जुन को वियान-परिपद् मे जाने का फेसला कर ही लिया। फिर भी जब मिशन और वाइसराय को कागेस का निर्णय बताया गया तब प्रत्येक क्षेत्र में हर्प की लहर दीड गई। काग्रेसी हलको में सन्तोप इस वात पर था कि लीग ने 'अल्पसंख्यको' और 'समान प्रतिनिधित्व' के सवाल उठा कर काग्रेस के लिए जो बेडिया तैयार की थी उनसे वह बच गई। सरकारी अधिकारियो को यह खुशी थी कि आखिर काग्रेम को विवान-परिपद् में लाने पर उन्हें सफलता मिल ही गई। लीगी हलको की प्रसन्नता का कारण यह था कि ऐसी अन्तरिम सरकार बन रही थी, जिसमे काग्रेस नहीं होगी। परन्तु लीग की आखो पर पडा पर्दा शीध्र ही उठ गया। सरकार की तरफ से २७ जून का वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमे बातचीत स्थगित करने की घोषणा की गई थी। दूसरे लक्जो मे इसका यही अर्थ हुआ कि १६ जून का वक्तव्य रद्द किया जाता है, क्योकि काग्रेस १६ मई का वक्तव्य स्वीकार करे चुकी थी। तव श्री जिन्ना ने १६ जून के वक्तव्य की आठवी धारा पूरी करने पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि अन्तरिम सरकार में कोई अथवा दोनो दल जाने से इन्कार करेगे तब परिपद् में रिक्त स्थानो को उन दलो के प्रतिनिधियो से भर दिया जायगा, जो १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार करेगे। काग्रेस इस वक्तव्य को तो स्वीकार करती थी, किन्तु उसने अन्तरिम सरकार में जाने से इन्कार कर दिया था। मिशन ने ऐसी स्थिति का अनुमान नहीं किया था और इसीलिए उसने ब्रिटिश मन्त्रि-मडल से परामर्श किया।

तब मिशन ने २७ जून का वक्तव्य प्रकाशित किया और वह २९ जून को इग्लैंड के लिए रवाना हो गया। परन्तु जाने से पूर्व मिशन की श्री जिन्ना से बातचीत हुई। श्रो जिन्ना ने विधान-परिपद् स्थिगत करने का अनुरोध किया, क्यों कि परिषद् और अन्तरिम सरकार की योजनाएँ परस्पर सम्बद्ध थी। परन्तु मिशन ने परिपद् को स्थिगत क्रना अस्वीकार कर दिया। वाइसराय ने कहा कि वह धारा ८ के अनुसार कार्य करेगे। इससे सम्भवतः कुछ समय बीतने पर अन्तरिम सरकार स्थापित होने की पृष्ठभूमि तैयार हो जायगी।

कार्य-समिति की बैठक

अब बातचीत में व्यस्त सभी प्रतिनिधियों के अपने दलों को सूचित करने का समय आया। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की बैठक ६ और ७ जुलाई को बम्बई में हुई। उसके सामने एक पितत का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार से हुए समझौते की पुष्टि की गई। प्रस्ताव में सशोधन के लिए स्थान नहीं था, क्योंकि प्रतिनिधि समझौता कर चुके थे और काग्रेस को उस समझौते की सिर्फ पुष्टि ही करनी थी। समझौते को स्वीकार अथवा अस्वीकार ही किया जा सकता था। कमेटी ने ५१ के विरुद्ध २०५ वोटों से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी अवस्था में धारा-सभाओं ने विधान-परिषद के सदस्यों के चुनाव शुरू कर दियें और जुलाई १९४६ तक चुनाव समाप्त भी हो गये।

लीग की प्रत्यच कार्रवाई

जुलाई के अत में प्रतिक्रिया यह हुई कि लीग ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं में भाग लेने से इन्कार कर दिया। लीग ने १६ अगस्त 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' (डाइरेक्ट ऐक्शन) का दिवस घोषित किया और ऐसा जान पड़ने लगा कि सरकारी कार्रवाई भी आरम्भ हो गयी। ६ अगस्त को वाइसराय ने काग्रेस के अध्यक्ष से अतिरम सरकार के निर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया। वाइसराय ने कहा कि ऐसा निर्णय सम्राट् की सरकार की सहमित से हुआ है। कार्यसमिति की बैठक ने वर्धा में इस प्रस्ताव पर विचार किया और १२ अगस्त के सायकाल ७ वजे वाइसराय के प्रस्ताव और काग्रेस-अध्यक्ष-द्वारा उसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी गयी। इसके वाट घटना-चक्र वडी तेजी से घूमा। कार्यममिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें लीग से मधुर गव्दो में अतिरम सरकार के निर्माण में सहयोग की अपील की गयी। राष्ट्रपति ने तुरत लीग के अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा। कार्यत्तमिति के प्रस्ताव की श्री जिन्ना पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह अप्रत्याजित न थी। उसमें उन्हें नये गुम्बद में पुराना चिराग ही दिखायी दिया। वाइसराय ने इस बार श्री जिन्ना को सीधे नहीं लिखा उसका कारण

श्री जिन्ना का प्रत्यक्ष 'कार्रवार्ज' की धमकी ही थी। वगाली सरकार ने प्रत्यक्ष कार्रवाई' मनाने के लिए १६ अगस्त को सावजनिक छुट्टी कर दी। कलक्ता और सिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए। कलकत्ता की मटको पर रजत की निका वह गई। मोटे हिसाब में ७००० के लगभग व्यक्ति मारे गये और बहुनस्वर घायल हुए। कलकत्ता की तुलना में अन्य स्थानो की घटनाओं की तरफ किनी का ध्यान ही नही गया। सिलहट और डाका में भी लोग हनाहन हुए। प्रतिनेव बहुत उग्र था और मूल उपद्रव की तुलना में वह कही अधिक भयानक था। "एक के बदले तीन'' की इस मीति से नोजावाली और टिपरा में जनता उत्तेजित हो उठी। इन दोनो ही जिलो में मुसलमान बहुमस्यक और हिन्दू अल्पमस्यक है। नोआखाली में उनका अनुपात १८ लान और ४ लाख का है। पूर्वी बगाल के इत दोनो जिलो मे अपराध जिननी भयानकता ने हुए थे उमे देवते हुए हनाहतो नी संस्था अधिक न थी । नारी-निर्यातन बलपूर्वक विदाह, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों को आग लगा देने, उन पर साम्हिक हमले और प्रसिद्ध परिवारों के बन् हमलों में शिकार होने से पूर्वी वगाल में जो अविश्वाम फैल गया या वह तीन वर्ष पूर्व अकाल में हुई साम्हिय मृत्युओं से भी कही अधिक भीषण था। पूर्वी वगाल से कितने ही हिन्दू भाग कर विहार आये और वहा अत्याचारों की अनेक कहानिया फैल गर्या। इस से विहारी जनता प्रतिशोध के लिए पागल हो उठी। इस अप्रत्यागित और भीपण परिस्थिति से कार्यस तथ। प्रत्येक समझदार काग्रेसजन का अत करण चीत्कार कर उठा और जब कि गांधीजी पूर्वी वगाल की जनता में षैर्य की भावना भरने और वाहर गये लोगो को उनके घरो में फिर वापस बुलाने के लिए गये तो दूसरी तरफ शासन-परिषट् के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहर विहार की परिस्थिति का नियत्रण करने गये। किन्तु श्री जिन्ना ने कलकत्ता और पूर्वी वगाल की घटनाओं के लिए कहीं भी खद नहीं प्रकट किया। गाधीजी और उनके साथी हिन्दू जनता से अपने मुसलमान पडोसियो की रक्षा की अपील कर रहे थे, किन्तु श्री जिन्न। ने अपने मुस्लिम अनुयायियों से हिन्दुओं की रक्षा के लिए ५ दिसम्बर, १९४६ तक एक गव्द भी नहीं कहा। समझा जा सकता ह कि १६ अगस्त से ६ दिसम्बर तक का अरसा कितना अधिक होता है। यह उस समय की वात है जब श्री जिन्ना अतरिम सरकार में सहयोगपूर्वक कार्य करने और विधान-परिषद् में हिस्सा लेने की समस्या पर वातचीत करने के लिए लदन गये थे। वे वार-वार 'प्रत्यक्ष कार्रवाई' का नारा दुहरा देते थे और उसका परिणाम बुरा होता था। इसकी लहर शीघ्र उत्तर प्रदेश पहुची। गढमुक्तेश्वर मे उपद्रव हुआ, जिसकी प्रतिकिया डासना में हुई। मेरठ शहर में, जहाँ काग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था, काग्रेस के पडाल को किसी ने आग लगा दी, जिसके परिणाम-स्वरूप अधिवेशन डेलीगेटो तक सीमित कर दिया गया। मेरठ शहर में कुछ ऐसी घटनाए हुई-

जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इसकी गूँज जिलों में भी सुनायी देने लगी। दिसम्बर, १९४६ के प्रथम सप्ताह में जब वाइसराय तथा काग्रेस और लीग के प्रतिनिधि लदन में थे, अहमदाबाद में ३७ घटे का कपर्यू लगा था, बम्बई में छुरों के वारों का अत होता नहीं दिखायी देता था और ढाका में साम्प्रदायिक उपद्रवों ने पुरानी बीमारी का रूप धारण कर रखा था। इन घटनाओं के कारण आगे की प्रगति रुकने की आशका हो चली थी और इसीलिए लदन में बातचीत की जरूरत पड़ी थी। पहले तो काग्रेस ने इस बातचीत में भाग लेने से इन्कार कर दिया, किन्तु ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आश्वासन मिलने पर पड़ित जवाहरलाल अकेले ही गये और फिर ९ दिसम्बर को विधान-परिपद में सम्मिलित होने के समय तक वापस आ गये।

गांधीजी की नोत्र।खाली-यात्रा

दु ख और दर्द की घटनाओ, परिवारों के समाप्त हो जाने, स्त्रियों के जबरन भगाये और बलात्कार किये जाने के इस दु'खद काड़ के मध्य, हमें आशा की केवल एक ही किरण दिखायी देती थी। हमें बगाल की दलदल से भरी भूमि में एक व्यक्ति 'अकेला, मित्रहीन और उदास' आगे बढता हुआ दिखायी देता था, जो हजारों परिवारो-द्वारा छोड़े हुए घरों को देखता हुआ आगे बढता जाता था। इस व्यक्ति के हाथ में आशा और शान्ति की ज्योति थी। वह जनता से भय का त्याग करने और हृदय में विश्वास बनाये रखने का उपदेश करते थे। उन्होंने कहा कि अपना विश्वास या उत्साह खोने से तो अच्छा पूर्वी वगाल की दलदलों पर मर-खप जाना है। उनके हाथ में जगी हुई अहिसा की ज्योति का प्रकाश दूर-दूर तक फैल रहा था, किन्तु वह कायरता से हिसा को अच्छा मानते थ। गांधीजी पूर्वी बगाल में चट्टान की तरह अचल थे। उनके मित्र उनके उद्देश्य पर सन्देह करते थे और शत्रु उन्हें ताने देते थे, लेकिन वह हमेशा शहीद वनने के लिये तैयार होकर मनुष्यमात्र में भाई-चारे और सद्भावना का उपदेश देते थे।

श्रंतरिम सरकार की स्थापना

१७ अगस्त को पिडत जवाहरलाल वाइसराय से मिले और वापस आकर उन्होंने अपने तीनो साथियों से परामर्श किया। इस प्रकार अतिरम सरकार के सदस्यों की प्रस्तावित सूची तैयार हो गयी। अब आवश्यकता सिर्फ एन० वी० इजीनियर के स्थान पर नया नाम चुनने और लीगियों की जगह पाच राष्ट्रीय मुसलमान चुनने की थी। जब वाइसराय को यह सूची दे दी गई तब शनिवार २४ अगस्त को उन्होंने नामों की घोषणा कर दी और २ सितम्बर से नयी सरकार ने शपथ ले ली। २४ अगस्त की सायकाल के समय भाषण करते हुए वाइस-

राय ने एक बार मुस्लिम लीग को अतिरिम सरकार में सम्मिलित होने का फिर 'निमत्रण दिया।

२४ अगस्त को भाषण देने के उपरान्त वाइसराय अपनी आखों में परिस्थिति का निरीक्षण करने कलकत्ता गये। वह 'साम्राज्य के इस दूसरे नगर' में हुए अत्याचारों से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्होंने काग्रेम ने परिस्थिति पर गम्भीरतापूर्क विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने काग्रेम से अपने वर्धा के निश्चय में परिवर्तन करने का अनुरोध किया और कहा कि प्रान्तो-द्वारा समूह में सम्मिल्ति होने के सम्बन्ध में काग्रेस को मिशन की व्यास्था स्वीकार कर लेनी चाहिए कि एकवार समूह बन जाने पर कोई प्रान्त उससे नव तक पृथक् न हो सकेगा जब तक कि नये विधान के अन्तर्गत उस प्रान्त की निर्वाचित धारासभा ऐसा निञ्चय न करे। यही नहीं, बिल्क बाइसराय ने कुछ कड़ा रुख भी ग्रहण किया और कहा कि यदि ऐसी बात नहीं की जाती तो वह विधान परिपद् ही न बुलायेगे। परन्तु, बाद में बाइसराय सभल गये और २ सितम्बर को अतिरम सरकार की स्थापना हो गई।

जिस दिन अतरिम सरकार, जिसे अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कहना अधिक उचित होगा, स्थापित हुई उस दिन सभी विचार करने लगे कि भारत को स्वा-थीनता प्रदान करने को जो वचन दिया था उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई। अठारहवी जताब्दी में मेकाले ने भारत को स्वजासन मिलने के दिन को ब्रिटिंग साम्राज्य का सब से गौरवपूर्ण दिन कहा था और उसके लिए भूमि तैयार की थी। इसके उपरान्त १८८५ में देश के विभिन्न वर्गों को एक ही झड़े के नीचे लाकर स्वाधीनता का बीजारोपण श्री डल्नयू० सी० वनर्जी ने किया। १८९८ में मद्रास् में श्री आनदमोहन बोस ने 'प्रेम और सेवा' द्वारा पौधे को सीचा। १९०६ में दादाभाई नवरोजी ने कलकत्ता में उस वृक्ष को स्वराज्य का नाम दिया। १९१७ में वह वृक्ष फूला। १९२९ में उसमें पूर्ण स्वराज्य का फल लगा। इस अवसर पर -बागवा जवाहरलाल थे। ये सभी राष्ट्रीय सरकार के लक्ष्य तक पहुचने की विभिन्न अवस्थाए थी। निस्सदेह फल लग चुका था, किन्तु उसे प्राप्त करना वाकी था। स्वराज्य का फल उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले की गोद में स्वय गिर नहीं पडता, उसे पकाने के लिए चतुर मालियों की आवश्यकता होती है। स्वराज्य के फल को पकाने के लिए १४ माली अतरिम सरकार के सदस्य के रूप में नियुक्त जिये गये।

मेरठ-कांग्रेस : १८४६

इसी वीच मेरठ-काग्रेस का अधिवेशन हुआ। यद्यपि १६ जून, १९४५ को कार्य--अमिति के सदस्य अहमदनगर किले से छोड दिए गये थे तथापि मेरठ का अधिवेशन २३ नवम्बर, १९४६ को ही हो सका। इस बीच अध्यक्ष ने, अपना कार्यभार सभाल लिया और नई कार्य-सिमित की भी नियुक्ति कर दी। परन्तु केन्द्र की अन्तर्कालीन सरकार में उनके पद-ग्रहण के कारण काग्रेस के विधान के अनुसार बाकायादा नये चुनाव की आवश्यकता पड़ी और श्री जे० बी० कृपलानी नये अध्यक्ष चुन लिये गये। उन्होंने अपना भाषण हिन्दुस्तानी में दिया और विषय सिमित तथा पूर्ण अधिवेशन दोनों ही अवसरों पर काग्रेस की कार्यवाही का सचालन बड़ी योग्यता तथा सफलतापूर्वक किया। अधिवेशन के अन्त में उन्होंने अग्रेजी में जो भाषण दिया वह एक आश्चर्यजनक वक्तृता थी। उसमें जहा एक तरफ यह बताया गया था कि अहिसा को कहा तक सफलता मिली है अथवा सफलता नहीं मिली है वहां दूसरी तरफ यह कहा गया था कि लोगों से कितनी अहिसा की आशा की जाती थी। आध घटे तक जनता मत्र-मुग्य-सी उनकी गर्जना सुनती रही और उस पर इस भाषण का अभृतपूर्व प्रभाव पड़ा।

मेरठ-अधिवेशन में कोई नई या ठोस वात नहीं हुई। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने दिल्ली की सितम्बर वाली बैठक में जो-कुछ किया था उसी की पुष्टि मेरठ के अधिवेशन में हुई। उसमें अतर्कालीन सरकार में काग्रेस के पद-ग्रहण को स्वीकार किया गया। परन्तु अधिवेशन की वास्तिवक सफलता विधान-परिषद्वाला प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया कि काग्रेस 'स्वतत्र एव पूर्ण सत्ता-सम्पन्न राज्य' की समर्थक है। इससे प्रकट कर दिया गया कि भारत का भविष्य साम्राज्य के बाहर रहकर ही सुधर सकता है। अधिवेशन का सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रियासतों के सम्बन्ध में था, जिसका भाव यह था —

"काग्रेस हमेशा से हिन्दुस्तान की रियासतो के सवाल को भारतीय स्वाधीनता के सवाल का एक हिस्सा मानती आई है। स्वाधीनता प्राप्त करने का समय निकट आने की वजह से यह सवाल और भी जरूरी हो गया है और उसका हल स्वाधीनता की पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। परन्तु काग्रेस को यह देखकर खंद हुआ है कि भारत की कुछ वडी रियासते, जिन्हे शेप रियासतो के लिए उदाहरण उपस्थित करना चाहिए था, विशेप रूप से प्रतिक्रियापूर्ण तथा दमनकारी कार्यों की अपराधिनी रही है। ऐसी स्थिति मे रियासतो की स्थिति गम्भीर होने के कारण काग्रेस घोषणा करती है कि वह रियासतो में होनेवाले स्वाधीनता के सग्राम को भारत के व्यापक सवर्ष का अग मानती है। रियासतो के लोग अपने यहा नागरिक स्वतत्रता तथा उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे है उनके प्रति काग्रेस की सहानुभूति है।"

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि काँग्रेस ने रियासतो के प्रश्न को हरिपुरा के बाद पहली बार उठाया था। इस बार कांग्रेस ने नरेंगों की निरकुशता के स्थान पर राजनीतिक विभाग के पड्यत्रों पर जोर दिया था और वह जो कार्य गुप्त रूप

से कर रहा था उस पर पहली बार विचार किया था। जहा तक रचनात्मक क्षेत्र

पर कायम है।

का सम्बन्ध है, काग्रेस के सामने बड़ा कठिन तथा महान् कार्य पड़ा था। हाल में हिसा, हत्याकाड, आगजनी, नारी-निर्यातन तया वलात्कार की जो घटनाये हा थीं उनसे हुई हानि की पूर्ति काग्रेम को करनी थी। भाषणक्रतीओं ने इस विपर पर अपना मत गम्भीरतापूर्वक प्रकट किया ताकि लोगो मे जोश न फैले। इस तस प्रत्येक द्प्टिकोण से मेरठवाले अधिवेशन को निर्फ नफल ही नहीं कहा जा सकता विल्क उसे आगामी अधिवेशनों के लिए उदाहरण-स्वरूप भी कहा जा सकता है। विधान-समिति ने अखिल-भारतीय काग्रेस कमेटी के विचार के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित किये थे उनमे अधिवेशन की तडक-भडक वन्द करने तथा उनमे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्यों के ही उपस्थित होने की वात थी और इस सम्बन्ध में कुछ असन्तोप भी था। मेरठ-अधिवेदान एक प्रकार से मध्य का मार्ग था। इसमे प्रतिनिधि तो आये थे, किन्तु दर्शको को बाहर निकाल दिया गया था। पुराने विवान के अन्तर्गत मेरठ का अधिवेशन अन्तिम था। मेरठ भारत के इतिहास में एक स्मर्णीय नाम है। विद्रोह की चिनगारी पहले-पहल मेरठ में उठी थी, और मेरठ में ही भारत के 'स्वतन्त्र एव पूर्ण सत्ता-सम्पन्न प्रजातन्त्र' की घोषणा की गयी। भारतीय राज-क्रान्ति की पहली हिंसापूर्ण लडाई (१८५७) के बाद गवर्नर-जनरल वायसराय वना था, दूसरी (अहिंसापूर्ण) लडाई के बाद भारत ते वायसराय का नाम-निज्ञान मिट गया।

लीग का मत

अव हम फिर अतिरिम सरकार की ओर आते हैं। अतिरम सरकार पहले लीग के प्रतिनिधियों के विना और फिर उन्हें सिम्मिलित करके स्थापित हुई। लीग के सिम्मिलित होने के समय विश्वास किया जाता था कि वह मिशन की दीर्पन कालीन योजना से भी सहमत है ओर विधान-परिपद् में विना हिचक के सिम्मिलित हो जायगी। ऐसा अतिरम सरकार में सिम्मिलित होने की मूल शर्तों के कारण नहीं, विल्क लीग की तरफ से लाई वेवल-हारा दिये गये आश्वासन के कारण समझा जाता था। परन्तु अतिरम सरकार में सिम्मिलित होने के कुछ ही समय वाद लीग के नेता ने घोषणा की कि लीग विधान-परिपद् में सिम्मिलित नहीं होगी और वह अभी तक पाकिस्तान तथा दो विधान-परिपदों की अपनी मूल मांग

प्रतिनिधियों की लंदन-यात्रा

यही स्थिति थी कि एकाएक ब्रिटिश प्रवानमत्री ने काग्रेस तथा लीग के दो-प्रतिनिधियो तथा अतरिम सरकार के सिख-प्रतिनिधि को विधान-परिपद् के

सम्बन्ध मे वातचीत के लिए लदन वुलाया। काग्रेस की पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि इस निमत्रण को स्वीकार न किया जाय, क्योकि उसका मत था कि विधान-परिपद् का सम्बन्ध भारत के लिये विधान-निर्माण करने से है--इसलिये परिपद सम्बन्धी प्रत्येक वात का फैसला लदन मे न होकर भारत मे और भारतीयो-द्वारा होना चाहिये। इसी कारण भारत मे मित्र-मिशन भेजने के विचार का स्वागत किया गया था। काग्रेस की तरफ से कहा गया कि यदि ब्रिटिंग मत्री इस विपय पर फिर कोई बात करना चाहते है तो उन्हें भारत आ जाना चाहिए।परन्तू प्रधानमत्री श्री एटली के आवश्वासन देने पर पडित जवाहरलाल ने इस निमत्रण को स्वीकार कर लिया। २९ नवम्बर को वह लन्दन गये।पडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वलदेवसिह इंग्लैंड में थोडे ही दिनो रहे। भारत से आये मेहमानो से अलग और एक साथ मिलने के उपरान्त ब्रिटिंग प्रवानमंत्री ने सभी भारतीय मेहमानो को आमत्रित किया और उनके मध्य अपना ६ सितम्वर का प्रसिद्ध वक्तव्य पढकर मुनाया, जिसने भारतीय राजनीति मे फूट का एक वीज वो दिया। इस घोषणा के सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पहले कोई परामर्ग नहीं किया गया और काग्रेस तथा सिखो के प्रतिनिधि तुरन्त वापिस आ गये, क्योंकि ९ दिसम्बर को विधान-परिपद् का अधिवेशन आरम्भ हो रहा था।

वक्तव्य का उद्देश्य

ब्रिटिय मित्रमंडल के मतानुसार लदन में हुई वातचीत का उद्देश्य विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न दलो का सहयोग प्राप्त करना था। साथ ही यह भी माना गया था कि भारतीय प्रतिनिधि अपने साथियों ने सलाह किये विना किसी निर्णय पर नहीं पहुच सकते थे। मुख्य कठिनाई मित्र-मिश्न के १६ मई के वनतव्य पैरा १९ (५) ओर (८) के सम्बन्ध में थी। पहले पैरे का सम्बन्ध समूह बनाने ओर दूसरे का समूह से प्रान्तों के पृथक् होने से था। वक्तव्य में बताया गर्या कि समूह बनाने के लिए बहुमत के सम्बन्ध में मत्रि-मिशन का क्या मत या। इस में इस बहुमत को भाग (संद्यान) का बहुनत कहा गया। दूसरे शब्दों में दोट प्रान्तों के अलग-अलग नहीं होगे, बेल्कि ट्यवित्रयों के होगे। मंत्रि-मिशन ने लदन में प्राप्त कानूनी मलाह-द्वारा अपने मत की पुष्टि भी प्राप्त कर ली थी। फिर वनतन्य में कहा गया था कि "वनतन्य के उन अस को इसी अर्थ के साथ १६ मई की योजना का एक आवश्यव अग समजा जाना चाहिए, जिससे भारतीय राष्ट्र एक ऐसा विधान नवार कर सबे, जिसे सम्राट् की नरकार पार्छमेंट में पेटा गरन में तत्पर हो नके।" इमिएए विधान-परिषद् के नभी दलों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मनिमटल ने कागम मे मित्र-मिशन का यह मन स्वीकार तरने हा अनुरोध किया, जिनसे मुन्लिम-टीग अपने एउ पर फिर ने विचार कर सके। साथ ही मित्रमडल ने यह भी सिफारिश की कि यदि इस आधारभूत तथ्य के सम्बन्ध में सध-अदालत की निर्णय के लिए कहा जाय तो ऐसा तुरन्त होना चाहिए और निर्णय होने तक परिषद् के समुहो की बैठक स्थगित रखी जा।

कांग्रेस का मत

जिस समय लन्दन से काग्रेस तथा सिखों के प्रतिनिधि लीटे उस ममय ब्रिटिंग मन्त्रि-मण्डल का वक्तव्य प्रकाशित हो गया था। लेकिन काग्रेस को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में कुछ समय लग गया। मन्त्रिमण्डल ने काग्रेस से वक्तव्य को स्वीकार करने का अनुरोध उचित परिस्थिति में नहीं किया। यदि दो दल किसी विशेष परिस्थिति में कोई समझौता करते हें और इस समझौते का मसिवदा तैयार किया जाता है तो एक दल द्वारा उस रामझौते की गर्त में परिवर्तन करना और फिर दूसरे दल से उसे स्वीकार करने का अनुरोध करना अनुचित ही कहा जायगा। ब्रिटिश सरकार ने वक्तव्य का मनमाना अर्थ लगाया और इम अर्थ को समझौते का आवश्यक अग बना दिया और फिर काग्रेस को धमकी दी कि यदि वह इस अर्थ को स्वीकार नहीं करती तो ब्रिटिश सरकार विधान-परिषद्-द्वारा तैयार किया गया विधान पार्लमेण्ट के आगे उपस्थित ही नहीं करेगी। ब्रिटिश सरकार की यह धमकी नियम-विरुद्ध ही नहीं, विल्क नैतिक दृष्टि से विश्वासघात ही था।

इस त्रिदलीय झगडे में अन्य दो दल चाहे जो करते, लेकिन काग्रेस का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था। सवाल था कि ६ दिसम्बरवाले वक्तव्य में झगडा सब-अदालत के सुपुर्द करने का जो सुझाव किया गया था वैसा किया जाय या नहीं ? पहली इच्छा यही होती थी कि ऐसा न किया जाय। परन्तु काग्रेस कार्यसमिति ने ऐसा करने का निश्चय किया। लदन के पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में श्री जिन्ना ने मामला सब-अदालत के सुपुर्द किये जाने की अवस्था में उसका निर्णय मानने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वह इसे वक्तव्य का महत्वपूर्ण अश समझते थे। फिर भी कार्य-समिति अपने निश्चय से हटी नहीं। कहा गया कि विवान-परिषद् के अध्यक्ष इस सम्बन्य में पहले एक घोषणा करेगे, फिर परिपद् एक प्रस्ताव पास करेगी आर अत में परिषद् के अध्यक्ष सघ-अदालत के समक्ष एक अर्जी पेश करेगे।

पैथिक लारेंस का वक्तव्य

यह निश्चय ही था कि १७ दिसम्बर के दिन लाई पैथिक-लारेस ने लाई-सभा मे भाषण करते हुए निम्न शब्द कहे — "मै यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यह सवाल ऐसा नही है, जो ब्रिटिश सरकार की राय मे सघ-अदालत के समक्ष उपस्थित करने योग्य हो। ६ दिसम्बर के वक्तव्य मे यह स्पष्ट कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार जो अर्थ ठीक समझती है वह भी बता दिया गया था। सरकार का मत है कि सभी दलों को यह अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार सघ-अदालत की चर्चा सिर्फ इसीलिए करती है कि विधान-परिषद इस विपय को सघ-अदालत के सुपुर्द करना चाहती है। काग्रेस ने यही मत प्रकट किया था। ऐसा तुरत होना चाहिए। मैं यह विल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्प्राट् की सरकार १६ मई के वक्तव्य के सम्बन्ध में अपनी व्याख्या पर कायम है और सघ-अदालत से अपील करने पर भी उसका इरादा इस अर्थ से हटने का नहीं है। मुझे आशा है कि ऐसा समझौता हो जायगा, जिससे दोनो दलों की आशका मिट सके।"

कार्य-समिति का वक्तव्य

अव काग्रेस बडी दुविधा में पड गयी। विधान-परिषद् के काग्रेसी दल ने यह मामला कार्य-समिति के विचार के लिए छोड दिया और कार्य-समिति ने कई दिन और रात इस समस्या पर सोच-विचार करने में विताये। यदि ६ दिसम्बर का वक्तव्य नहीं माना जाता तो समूहों के लिए पृथक् विधान-परिपद् बन जाती और आसाम तथा सीमाप्रान्त के उस पेरिपद् में सम्मिलित होने या न होने का भी कोई प्रभाव न पडता। इस तरह लीग का मनचीता ही होता। कार्य-समिति को इन सब बातो पर विचार करना था। मेरठ में काग्रेस का अधिवेशन हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ था। इसमें कार्य-समिति तथा सम्राट् की सरकार के मध्य हुई सम्पूर्ण व्यवस्था को काग्रेस स्वीकार कर चुकी थी, किन्तु अव अनेक पेचीदिगयों से भरी नयी परिस्थिति उपस्थित थी। काग्रेंस-अधिवेशन में हुए निश्चयो पर केवल अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ही विचार कर सकती थी। अत कार्य-समिति ने यह मामला उसी के सुपुर्द कर दिया। ५ जनवरी १९४७ को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की वैठक हुई। कार्य-समिति ने २२ दिसम्बर, १९४६ को एक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमे १६ मई से अव तक की घटनाओ पर विचार करते हुए यह कहा गया कि कार्य-सिमिति को खेद है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा आचरण किया है, जो उसके अपने आश्वासनों के विरुद्ध है और जिससे भारत की बहुसस्यक जनता के मन में सदेह उत्पन्न हो गया है। इधर कुछ समय से न्निटिश सरकार तथा उनके भारत-स्थित प्रतिनिधियो का रुल ऐसा रहा है, जिसमे देश की परिस्थिति की कठिनाइया और पेचीदिगया वढ गयी है। विवान-परिपद् के सदस्यों के चुनाव के इतने समय बाद उन्होंने जो हस्तक्षेप किया है इससे भविष्य में सकट उत्पन्न हो सकता है। उसमें यह भी कहा गया कि समिति विधान-परिपद् को भारत की जनता की पूर्ण प्रतिनिधि बनाने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखेगी भीर उसे विद्यास है कि मुसलिम लीग के सदस्य उसे इस विषय में सहयोग प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने परिषद् के काग्रेसी प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण विषयो पर सोच-विचार के लिए अगली बैठक के लिए स्थगित करने की

सलाह दी है। उसका अब भी यही मत है कि भागों (मेक्सनों) में मत लिए जाने के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने जो अर्थ लगाया है वह प्रान्तीय स्वशासन के अपि कारों के विरुद्ध है—उसी प्रान्तीय स्वशासन के, जो १६ मई के वक्तव्य में प्रतािवत योजना का मूल सिद्धान्त है। समिति कोई ऐसी वात नहीं करना चाहती, जिससे विधान-परिपद् का कार्य सफलतापूर्वक चलने में वाधा पड़ने की सम्मावत हो। देश के सामने उपरिथन रामस्याओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए और होनेवाले निर्णयों के जो परिणाम हो सकते हैं उनका अनुमान करते हुए समिति जनवरी में अखिल भारतीय कार्येम कमेटी की एक बैठक दिल्ली में बुला रहीं है जिससे उचित निर्देश प्राप्त किया जा राके।

कांग्रेस-कमेटी का निर्णय

१९४७ का नया साल काग्रेस और देश के लिए महान् घटनाए लेकर शुरु हुआ। ५ जनवरी को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का अधिवेजन यह विचार करने के लिए हुआ कि ब्रिटिश मित्रमडल का ६ दिसम्बर का वक्तव्य स्वीकार किया जाय या नही । यदि वक्तव्य को अस्त्रीकार किया जाता है तो इसका मतलव यह हुआ कि काग्रेस १६ मई के वक्तव्य ने भी सम्बन्ध त्यागती है ओर इस प्रकार मुस्लिम लीग को विवान-परिपद् में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दे सकती। मुँस्लिम लीग को समूह 'वी' और 'सी' का विवान तैयार करने और उनके लिए एक केन्द्र स्थापित करने में कठिनाई होती और इसीलिए वह ब्रिटेन से नयी योजना मागती, जो ब्रिटेन उसे सहर्प दे देता। परन्तु यदि वनतव्य को स्वीकार करना था तब भी उतने ही बुरे खतरो का सामना होना था। उस हालत में श्री जिन्ना की हेकडी उठकर आसमान से छू जाती और वह कुछ और भी शर्ते मजूर करा लेते। इनमे एक गर्त समूह की सेना रखना होती और यदि कोई विदेशी सेना आक्रमण करती तो यह उसके साथ मिलकर देश की सेना को पराजित करने की चेष्टा करती। यही नही, जिन्ना साहब धारा-सभा, सेना ओर नौक्रियो में आधे स्थान अपने लिए मागते। इन सभी परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने वहुमत से कार्य-समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया और यह यही समाप्त होगया। कमेटी का प्रस्ताव इस प्रकार

ह .—
"अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पिछले नवम्बर के मेरठ-अधिवेशन से अब तक होनेवाली घटनाओ, ब्रिटिश मित्रमडल के ६ दिसम्बर के वक्तव्य और कार्य-समिति के २२ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्तव्य पर विचार करने के बाद काग्रेस को निम्न सलाह देती है —

- (१) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी कार्यसमिति के २२ दिसम्बर, १९४६ के वक्तव्य की पुष्टि करती है और उसमें प्रकट किये विचारों से सहमित प्रकट करती है।
- (२) यद्यपि काग्रेस विवादास्पद प्रश्न की व्याख्या का मामला सघ-अदालत केषपुर्द करने के पक्ष में हमेशा से रही है, तथापि ब्रिटिंग सरकार की हाल की घोझणाओं को मद्देनजर रखते हुए अब ऐसा करना बिलकुल निरुद्देश्य और अवाछनीय समझती है। यदि सम्बन्धित दल निर्णय को स्वीकार करने को तैयार हो और यह आधार मानने को तैयार हो तभी यह मामला सघ-अदालत के सुपुर्द किया जा सकता है।
- (३) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी का यह दृढ मत है कि स्वतत्र भारत के विधान का निर्माण भारतीय जनता-द्वारा और अधिक से अधिक विस्तृत मतेवय के आधार पर होना चाहिए। इस कार्य में किसी बाहरी गिक्त का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी प्रान्त-द्वारा दूसरे प्रान्त अथवा प्रान्त के भाग पर दवाव न डालना चाहिए। अखिल भारतीय काग्रेस महसूस करती है कि कुछ सूबो में जैसे आसाम, बलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, और पजाब के सिखो के मार्ग में ब्रिटिश मिशन के १६ मई, १९४६ वाले वक्तव्य से, और खासकर ६ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्तव्य से, और खासकर ६ दिसम्बर, १९४६ वाले वक्तव्य की ग्याख्या-द्वारा, किनाइया उपस्थित की गयी है। जिन लोगों के साथ यह जबर्दस्ती की जा रही है उन पर दवाव डालने में काग्रेस हिस्सा नहीं ले सकती। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसे खुद ब्रिटिश सरकार ने मजूर किया है।
- (४) अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस बात के लिए उत्सुक हैं कि विधान-परिषद् स्वाधीन भारत के लिए विधान बनाने का कार्य सभी सम्बन्धित दलों की सद्भावना से करें, जिससे व्याख्या की विभिन्नता से उठनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जासके, और परिषद् सेक्शनों में अनुसरण की जानेवाली कार्य-पद्धति के विपय में भी ब्रिटिश सरकार की व्याख्या को स्वीकार कर ले। परन्तु यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसके कारण किसी प्रान्त पर अनुचित दवाव न पडना चाहिए और साथ ही पजाब में सिखों के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए।

लीग का निर्णय

यद्यपि आगा यह की जाती थी कि मुस्लिम लीग ६ जनवरी को पास किये गये काग्रेस के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपनी वैठक कुछ पहले बुलायेगी, तो भी लीग की वैठक विधान-परिषद् होने की तारीख के ९ दिन वाद २९ जनवरी को बुलायी गयी। इससे स्पष्ट था कि लीग का इरादा विधान-परिषद् में सम्मिलित होने का नहीं था।

लीग की कार्य-समिति ने अखिल भारतीय काग्रेम कमेटी के ६ जनवरी के प्रस्ताव को वेईमानी से भरी चाल और शब्दाटम्बर बताया, जिनका उद्देश्य विदित्त सरकार, मुस्लिम लीग और लोकमत को घोषा देना था। आरोप यह था कि सिद्धातो तथा कार्य-पद्धति के विषय में जो निक्चय किये गये हैं वे १६ मई, १९४६ के वक्तव्य के क्षेत्र से परे हैं और कार्यस ने वियान-परिषद् को जैसा रूप दिया है वैस देने का मित्र-मिगन का उद्देश्य कदापि न था। लीग की कार्य-समिति ने नम्रद् की सरकार से यह घोषणा करने को कहा कि मित्र-मिगन की योजना असफल हुई है। लीग ने यह भी मन प्रकट किया कि विवान-परिषद् के लिए जो चुनाव हुए है वे अनियमित है और परिषद् में हुई कार्यवाही और निक्चय भी अनियमित ही है।

पटली का वक्तव्य

२० फरवरी १९४७ को हाउम आफ कामन्स में बोठते हुए ब्रिटिश प्रवान-मत्री श्री क्लेमेट एटली ने जो कुछ कहा वह सक्षेप में इस प्रकार हैं — "वहुत समय से ब्रिटिश सरकार की नीति रही है कि भारत में स्वायत नासन

की स्थापना कर दी जाय। इसी नीति के अनुसार भारतीयों को अधिकाविक दायित्व सीपा जाता रहा है और आज नागरिक शासन तथा सेनाओ की बागडोर वहुत हद तक भारतीय अमेनिक तथा सेनिक अफसरा के ही हाथ है। सम्राट् की सरकार की घारणा है कि यही नीति उचित है। मित्र-मिशन के उद्देश्य तया उसके कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि सम्राट् की सरकार के लिये यह खेद का विषय है कि अभी तक भारतीय दलों में मतभेद हैं जिसके कारण विघान परिषद् का कार्य सुचारु रूप से चलने में वाबाए उपस्थित हो रही है। सम्राट् की सरकार की यह इच्छा है कि मित्र-मिरान की योजना के अनुसार, भारत के विभिन्न दलो की स्वीकृति से वनाये गये विधान-द्वारा निश्चित अधिकारियों को अपना दायित्व सौंप दिया जाय। किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसे विधान तथा अधिकारियो का अस्तित्व इस समय सम्भव नहीं मालूम होता। वर्तमान अनिश्चित स्थित् विपद की आशकाओं से परे नहीं है और ऐसी स्थिति अनिश्चित समय तक रहन भी नहीं दी जा सकती। सम्राट् की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय की सूचित कर देना चाहती है कि वह जून १९४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति सौप देने के कार्य को सम्पन्न कर देगी। इसिलये यह आवश्यक है कि सव दर् आपसी मतुभेदो को भुलाकर अगले वर्ष आनेवाले भारी उत्तरदायित्व को सँभा-लने के लिये तैयार हो जायाँ।"

आगे उन्होंने कहा कि यदि निश्चित की गयी तिथि तक सब प्रकार से प्रति-निधित्वपूर्ण परिषद्-द्वारा ऐसा विधान न बनाया जा सका तो सम्राट् की सरकार को यह विचार करना पडेगा कि ब्रिटिंग भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिंग भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे ढग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, सौपा जाय। किन्तु यह निश्चित है कि ज्यो-ज्यों दायित्व सौपने का कार्य आगे वढता जायगा, भारत-सरकार के १९३५ के कानून की गर्तों को निभाना अधिकाधिक कठिन होता जायगा। निश्चित समय पर पूर्ण रूप से दायित्व सौपने का विधान लागू हो जायगा।

भारतीय रियासतो के बारे में उन्होंने कहा कि सम्राट् की सरकार अपनी सार्वभौमसत्ता (प्रभुसत्ता) के अतर्गत भारतीय रियासतो को ब्रिटिंग भारत की किसी भी सरकार के सुपुर्द नहीं करना चाहती। अतिम रूप से दायित्व सौपने से पहले सम्राट् की सार्वभौम सत्ता का अन्त कर देने की कोई इच्छा नहीं है, किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि इस अन्तर्काल में व्यक्तिगत रूप से सम्राट् हर देशी रियासत से पारस्परिक परामर्श-द्वारा अपने सम्बन्ध स्थिर कर ले।

नए वाइसराय की नियुक्ति के सवध में उन्होंने कहा कि फील्ड-मार्गल माननीय वाइकाउन्ट वेवल को १९४३ में वाइसराय नियुक्त किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि यह नियुक्ति युद्धकाल के लिये होगी। ऐसे कठिन समय में लाई वेवल ने इस उच्च पद का कार्य वडी लगन तथा निष्ठा से निभाया है। जब भारत नवीन तथा अतिम स्थिति को प्राप्त होने जा रहा है, यह सोचा गया है कि यह समय इस युद्धकाल की नियुक्ति को समाप्त करने के लिये उपयुक्त है। सम्राट्ने एडिमरल वाइकाउन्ट माउटवेटन की नियुक्ति लाई वेवल के स्थान पर प्रसन्नता-पूर्वक की है जिनको भारत की भावी समृद्धि तथा सम्पन्नता को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत-सरकार का दायित्व भारतीय हाथों में सोपने का भार दिया जायगा। यह परिवर्तन मार्च मास में सम्पन्न होगा। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि सम्राट ने प्रसन्नतापूर्वक वाइकाउन्ट वेवल को अर्ल की पदवी देना स्वीकार किया है।"

वक्तव्य की श्रालोचना

यह वक्तव्य भी सदा की तरह अस्पष्ट था। इसमें अनेक विकल्प इस तरह रखें गये थे, जिसमें जिन व्यक्तियों को सत्ता हस्तातरित की जाय वे विकल्पों के अनेक अर्थ लगा सके। काग्रेस आजा कर सकती थी कि देश की सबसे बडी राज-नीतिक सस्था के रूप में, और एक ऐसी सस्था के रूप में जिसका अल्पसंख्यक नम्दायों से (जिनमें मुसलमान भी थे) गहरा सम्बन्ध था, उसे विशेष महत्व मिलेगा। उधर लीग 'पूर्ण प्रतिनिधित्व' शब्दों के महत्व पर निर्भर थी और उसकी आणा थी कि जब नक वह विधान-परिषद् में भाग नहीं लेगी तद नक परिषद् को

संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास

"पूर्णम्प्रतिनिधित्व" नहीं कहा जा सकेगा और इस तरह लीग के दावे को पूरी तरह माना जायगा। इसके अतिरिक्त रियारातों का प्रोत्माहन यह कह कर बढ़ाया गया कि सत्ता अतिम रूप से हस्तातिरत करने तक प्रभु-शक्ति की प्रणाली का अन्त नहीं किया जायगा और दरिमयानी काल में रियामतों की धामक-शक्ति में नये सम्बन्ध कायम किये जायगे। इस प्रकार बक्तव्य के कुछ भाग अस्पष्ट थे, फिर भी काग्रेस को वह बुद्धिमत्तापूर्ण और साहिसक जान पडा। जो भी हो विधान-परिषद् को अब अधिक तेजी से काम करना था। नत्ता-हन्तातरण के लिए आवश्यक कार्रवाई तुरन्त आरम्भ हो जानी थी। उस समय यह नव बड़ा ही आकर्षक जान पडा।

भगड़े श्रीर रक्तपात

इंग्लंड के कठोर नीतिज्ञा तथा सीचे-साद हिन्दुस्तानियों की यह आशा वल-वती थी कि यह काम इतने सुचार रूप से किया जायगा कि दोनों पक्षों को नम्पूर्ण सतोप प्राप्त होगा, परन्तु यह आशा पूरी न हो सकी। भारत में खीचा-तानी क्या, आपस की मार-काट से खून की निदया वह गई और लूट तथा आग से वह तबाही हुई कि वयान नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग की तरफ से पजाब, सिंध तथा सीमाप्रात में अपना शासन जामाने की चेप्टा, खुरलम-खुला निर्लज्जता से अपनी ताकतों को सजाना, मानो युद्ध-क्षेत्र में मीजूद हो, आसाम की सरहद पर तीन ओर से आक्रमण आदि इस सस्या की नई रण-कला के प्रत्यक्ष प्रमाण ये, और इस बात के परिचायक थे कि पाकिस्तान बलपूर्वक कायम किया जायगा।

सीमाप्रान्त के दगो में जानों का भारी नुकसान, और हिन्दुओ-सिखों का वलात् मुसलमान वनाया जाना, उस समय दिखलाया गया जविक वाइसराय आने ही वाले थे। श्री मेहरचन्द खन्ना, मन्त्री इन्फार्मेशन ने पत्रकारों की कान्फरेम में वतलाया, कि दिसम्बर से अप्रैल तक, प्रात भर के दगों में ४०० हिन्दू और सिख मारे गये, १५० घायल हुए और १६०० घरों तथा ५० हिन्दू या सिख धर्मस्थानों को जलाया गया। ३०० से अधिक को जवरन मुसलमान वनाया गया और ५० को भगा ले जाया गया। उन्होंने वतलाया कि मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने विहार से लौट कर, फण्टियर के मुसलमानों को कुरान के फटे पन्ने और इन्सानी खोपडिया दिखला कर, तथा "विहार का बदला फण्टियर लेगा" और "खून का बदला खून" के नारे लगा कर मुसलमानों को भड़काया।

हिन्दुस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नई चीज नही थी। १९०६ से गुरु करके, हर वह कदम जो कि मुस्लिम अधिकारो के लिए उठाया गया, उन्हें देश से दूर ही ले गया और इससे एकता की सम्भावना नष्ट हो गई। किन्तु अन्तिम कदम, जिससे कि तख्ता पलट जाय, विचाराधीन रहा। दुख से कहना पडता है कि वल का प्रयोग किया गया। दिल्ली में बड़ी भयानक खबरे गन्त लगा रही थी और फ्रिंग्टियर तथा पजाब से छुपे-छुपे आनेवाली खबरे चौकानेवाली थी। १९४२ में, जैसे हिन्दुस्तान पर जापानी हमले का आतक छाया था, वैसे ही उत्तर से हर समयआक्रमण की आजका थी।

गांधीजी का वक्तव्य

किन्तु यह तनातनी महात्मा गाधी के उस प्रार्थना के वादवाले भापण से, जो उन्होन नये वाइसराय से मिलने के बाद ४ मई १९४७ को दिया था, कुछ हद तक कम हो गई। भगी कालोनी नई दिल्ली में प्रार्थना के बाद वोलते हुए उन्होने कहा कि वाइसराय ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वह हिन्दुस्तान में इसलिए आये हैं कि गान्तिपूर्वक सब शासन हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौप दे। गांधीजी ने यह भी कहा, कि उनकी यह दिली ख्वाहिश है, कि हिन्दुस्तान एक रहे और सब लोग चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हो, प्रेमपूर्वक मिलकर रहे। यदि, वाइसराय की कोशिशों के वावजूद, इस बीच झगडे बद न हुए तो वह फौजी ताकत का प्रयोग करने में भी नहीं चूकेगे। उनकी इच्छा है कि हिन्दुस्तानी वीती को भूल जायँ और अग्रेजों की नीयत में विश्वास रखें कि वे, यदि हो सका तो, जाने से पहले, हिन्दु-मुसलमानों में समझौता करवा देगे। ऐसी स्थिति में जवतक वाइसराय पर विश्वासघात का इलजाम साबित न हो जाय, जनता को उनकी नेकनीयती पर भरोसा करना चाहिये। यदि हिन्दू और मुसलमान लडते ही रहे तो इसका यह मतलव होगा कि वे अग्रेजों को यहाँ से नहीं भेजना चाहते। अग्रेज जून १९४८ तक जरूर चले जायँगे। वेहतर होगा, यदि परस्पर-दोषारोपण वद किया जाय।

पंजाव श्रौर बंगाल का विभाजन

पजाव और सीमाप्रात में, मार्च-अप्रैल १९४७ में हिंसा की जो आधी उठी और तीव्र हुई, उसका उद्देश्य मौजूदा मित्र-मंडलों को, वैध और कानूनी विधि के वजाय वलपूर्वक उखाड फेकना था, किन्तु मनसूवे पूरे न हुए। तिस पर भी, लूट-मार, करल और खून की वारदातों ने सारे देश को हिला दिया और अत में काग्रेस की कार्यकारिणी ने पजाव के दो प्रान्त बनाये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया तािक हिन्दू-वहुसख्यक विभाग को विरोधियों के अन्याय से मुरिक्षत बनाया जाय। ज्योही यह प्रस्ताव मार्च १९४७ के मध्य में पास हुआ, त्योही वगाल में इसकी पितिकिया प्रत्यक्ष हो गई और बगाल को बाँट देने की मांग की गई। वंगालियां ने यह अनुभव किया कि ६३० लाख की आवादी में मुसलमानों की कुल मिलाकर ७० लाख की अधिक सख्या होने से सारे प्रान्त को सदा के लिए मुम्लिम लीग के अधीन नहीं छोडा जा सकता। कुदरती तौर पर यह सवाल उठा, कि पिल्छिमी

सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास

विशिष्ठ के हिन्दू, पूरवी वगाल के हिन्दुआ की अवस्था को, जो कि अन्यविक मुस्लिम बहुमार्व के रहम पर रह जायेंगे, किम तरह ज्ञान्ति और वीरज से महन करेंगे हैं तो इसका उत्तर मिला कि पच्छिमी वगाल के मुस्लिम अत्पमस्यक जिस तरह दिन गुजारेंगे, उसी तरह पूरवी वगाल की हिन्दू अल्पमस्या रहेगी।

भारत छोड़ने की तैयारी

इन घटनाओं से फिर यह यक होने लगा कि त्रिटेन ने जो भारत छोड जाने की घोपणा की है उसमें सचाई कहां तक है। अगर वे सच्चे हैं तो फिर इम देश के टुकडे कर जाने का इरादा क्यो रयते हैं? फिर भी पिछले तीन महीनों में जो परिवर्तन हुए उनसे यही प्रतीत होना था कि अग्रेजों की यह घोपणा सच्ची और गम्भीर है। और यही तथ्य, कि हिन्दुस्तान भर के अग्रेजों की गणना की जा रही है ताकि उन्हें वापम भेजने का प्रवन्य किया जाय, जनता के मन में मदेह दूर करने को काफी था। सिविल, मेडिकल तथा पुलिस विभागों को समेट देने की योजना को, जो कि हिन्दुस्तान को ह्वाइट हाल से मालूम हुई है, यो ही नहीं उडाया जा सकता। इसे चालाकी की चाल नहीं कही जा सकती। १५० माल में, प्रथम बार हिन्दुस्तानी फौज का बनाया जाना कुछ मजाक नहीं है। रियासतों में, एजण्ट-जनरल का ओह्दा हटाये जाने के साथ-साथ पोलिटिकल डिपार्टमेट का समेटा जाना, और रेजीडेटों के अधिकारों का ह्वास इत्यादि, ऐमें लक्षण है, जिनमें अग्रेजी दुकान के उठाय जाने का निश्चय जाहिर होता है। रुपये का पिंड स्टिलिंग से बहुत पहले छुटाया जाना चाहिये था, किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिकूल होने से नहीं हो सका था। शिलिंग कमेटी तथा कोल कमेटियों ने बडी प्रवल रिपोर्ट पेश की है, जिनसे अब हिन्दुस्तान को इंग्लैंड का पुछलगा नहीं बना रहन। होगा।

कांग्रेस-समिति की बैठक

जब कि परिस्थिति ऐसी थी, तब यह घोपणा की गई कि वाइसराय ने २ मई को लार्ड इस्मे के हाथ ब्रिटिश मित्रमंडल को अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं। इस प्रकार कैबिनेट-द्वारा हिन्दुस्तान को अधिकार हस्तातरित करने का ऐलान फिर वही १६ मई को किया गया जैसा कि ठीक एक वर्ष पूर्व किया गया था। किन्तु पार्ल्यामेंट के अवकाश के कारण, यह महत्वपूर्ण काम २ जून १९४७ तक मुल्तवी किया गया।

जव निश्चित तिथि आई तब २ जून को वाइसराय ने थोडे-से नेताओं को दावत दी और ३ जून को माउण्टबेटन-योजना घोषित हुई। इसके बाद प० नेहरू, मि० जिन्ना तथा सरदार वलदेविसह के रेडियो-भाषण हए।

३ जून १९४७ के अग्रेजी सरकार के वक्तव्य पर विचार करने के लिए, विवान-परिपद्, करजन रोड नई दिल्ली में, आल इण्डिया काग्रेस कमेटी का एक विशेष अधिवेशन १४-१५ जून १९४७ को दिन के २ वजे हुआ। सभापति आचार्य कुपलानी और २१८ सदस्य उपस्थित थे।

काग्रेस कार्यकारिणी-द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्ताव का मसविदा श्री गोविदवल्लभ पत ने पेश किया और मौलाना अबुलकलाम आजाद ने उसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव के सबध में बहस समाप्त होने पर, मत लिया गया। असली प्रस्ताव २९ के विरुद्ध १५३ के बहुमत से पास हुआ। कुछ सदस्य तटस्थ रहे। प्रस्ताव यह था —

आल इडिया काग्रेस कमेटी ने, जनवरी की पिछली वैठक के बाद की घटनाओं पर पूरा-पूरा ध्यान दिया है। खासकर, ब्रिटिश सरकार के २० फरवरी तथा ३ जून १९४७ के वक्तव्यो पर गहरा विचार किया है। इस बीच, कार्यकारिणी द्वारा पास किए गए प्रस्तावो का, यह कमेटी अनुमोदन तथा समर्थन करती है।

कमेटी, ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय का स्वागत करती है कि आगामी अगस्त तक, सारे अधिकार पूर्णतया हिन्दुस्तानियों को सौप दिय जायेंगे।

ब्रिटिश कैविनट-मिशन के १६ मई १९४६ के वक्तव्य तथा बाद में ६ दिसम्बर १९४६ की उस पर की गयी व्याख्याओं को काग्रेस ने स्वीकार कर लिया है और मिशन की योजना के अनुसार विधान-परिपद कायम करके, उस पर अमल कर रही है। विधान-परिपद ६ मास से अधिक समय से अपना काम कर रही है। परिपद् ने, अपना ध्येय हिन्दुस्तान के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र राज घोषित किया है। इसके अलावा, प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिए, समान बुनियादी अधिकारों और सुअवसरों के आधार पर, आजाद हिन्दुस्तान संघ का विधान बनाने में भी विधान-परिपद् ने काफी उन्नति कर ली है।

१६ मई की योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था और विधान-सभा में शामिल होने से भी उसने इन्कार किया था। इसको दृष्टि में रखते हुए तथा काग्रेस की इस नीति के अनुसार कि, "यह किसी प्रदेश के लोगों को हिन्दुस्तानी सघ में शामिल हो जाने पर बाधित नहीं करेगी," आल इंडिया काग्रेस कमेटी ने, ३ जून की घोषणा में लिखों तजवीं को मजूर कर लिया है, जिसमें जनता का मत जानने की विधि भी लिखों है।

३ जून, १९४७ की तजवीजों के अनुसार सम्भवत हिन्दुस्तान के कुछ भाग इससे अलहदा हो जायँ। बडे खेद के साथ, मौजूदा हालात में आल इंडिया काग्रेस कमेटी इस सम्भावना को मान रही है।

गो आजादी निकट है, मगर समय भी विकट है। आजादी के दीवानो से, आज के हिन्दुरतान की परिस्थिति, सतर्क तथा सगठित रहने की माग कर रही

सक्षिप्त काग्रेस का इतिहास

हैं। आज किं सकट-समय में, जबिक देगद्रोही तथा विच्छेद करनेवाली गिक्तिया हिर्ह्युस्तान और इसकी जनता के हितों को आहत करने की चेप्टा कर रही है, किल इंडिया काग्रेस कमेटी, आम जनता और विशेषकर प्रत्येक काग्रेसी से तकाज करती हैं, कि वह अपने छोटे-मोटे झगड़े भूलकर सतर्क और सगठित हो तथा हिन्दुस्तान की आजादी को, हर उस व्यक्ति से जो इसे हानि पहुँचाना चाहता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर गुरक्षित रखने के लिए तत्पर हो जाय।

इसके वाद हिन्दुस्तानी रियासतो-विषयक प्रस्ताव जिसकी सिफारिश कार्य-कारिणी ने की थी, श्री पट्टाभि सीतारामय्या द्वारा पेश किया गया और शकरराव देव ने उसका समर्थन किया। प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पास हुआ। प्रस्ताव सक्षेप

मे इस प्रकार है

"आल इडिया काग्रेस कमेटी, विधान-परिषद् में बहुत-सी रियासतो के शामिल होने का स्वागत करती है। कमेटी आशा करती है कि शेष सभी रियासते भी, आजाद हिन्दुस्तान के विधान-निर्माण में, जिसके अनुसार रियासती इकाइया सघ में सम्मिलित होनेवाली दूसरी इकाइयो की तरह वरावर की भागीदार होगी, अपना-अपना सहयोग देंगी।

"जो वैधानिक तब्दीलिया की जा रही है उनमे रियासतो की स्थिति, कैविनट मिशन के मेमोरेडम ता० १२ मई, १९४६ के वक्तव्य में निर्धारित कर दी गयी है। ३ जून १९४७ के वक्तव्य ने इस स्थिति में कोई तब्दीली नहीं की। इन दस्तावेजों के अनुसार हिन्दुस्तानी सघ में ब्रिटिश भारत और रियासते दोनो शामिल होगी। सर्वोपिर सत्ता, अधिकार हस्तारित होने पर समाप्त हो जायगी, और यदि कोई रियासत सघ में सम्मिलित नहीं होती, तो वह किसी अन्य प्रकार के राजनीतिक नाते में बँध जायगी।

"आल इंडिया काग्रेस कमेटी, हिन्दुस्तान की किसी रियासत के स्वतत्र हो जाने का हक तस्लीम नहीं करती, जिससे कि वह शेप भारत से अलग-थलग रह सके। इसका मतलव हिन्दुस्तानी इतिहास की गित तथा आज के हिन्दुस्तानियों की वास्तविक स्थिति से इनकार करना होगा।

"आल इडिया काग्रेस कमेटी को भरोसा है कि राजा लोग, आज की स्थिति को भलीभाति समझकर, अपनी प्रजा तथा समस्त भारत के हितार्थ, अपनी प्रजा के हमराह प्रजातत्र की इकाइया बनकर हिन्दुस्तानी सघ में सम्मिलित होगे।"

कृपलानीजी का भाषण

इसके बाद काग्रेस के प्रधान ने अपना भाषण दिया। नीचे हम उनके भाषण के अन्तिम भाग का साराश देते है —

"जब मैं इस सस्था का प्रधान बना था तब गाघीजी ने अपने एक प्रार्थना-

भाषण में कहा था कि मुझे न केवल काटों का ताज सिर पर धारण करना होगा विलक काटों की सेज पर भी लेटना पड़ेगा। मैंने तव यह अनुभव नहीं किया था कि सचमुच वही होगा। १६ अक्टूबर को मेरे प्रधान चुने जाने की घोषणा हुई और १७ ता० को मुझे विमान द्वारा नोआख़ली जाना पडा। इसके बाद मुझे अरि १७ ता० को मुझ विमान द्वारा नाआखला जाना पडा। इसक वाद मुझ विहार जाना पडा और अभी-अभी पजाब भी गया था। दोनो सम्प्रदाय वाले यदबदा कर हिंसा और मारकाट कर रहे हैं और हाल की भिड़न्त में जिस प्रकार की सगदिली और जुल्म की वारदाते हुई हैं उनकी मिसाल पहले कही नहीं मिलती। मैंने एक कुआं देखा है जिसमें १०७ स्त्री-वच्चों ने अपनी आवरू वचाने के लिए छर्लाग लगाकर जान दे दी। एक दूसरी जगह, एक धर्मस्थान में पुरुषों ने ५० स्त्रियों का इसी कारण अपने हाथों वध कर डाला। मैंने एक घर में हिंदु इयों के ढेर देखे हैं, जिसमें ३०७ व्यक्तियों—अधिकाय स्त्री-वच्चों को—आकमण-कारियों ने वद कर जिन्दा जला डाला था। इन भयानक दृश्यों को देखकर उम समस्या के विषय में मेरे विचारों पर बहुत प्रभाव पडा है। कुछ सदस्यों ने हम पर सल्लाम लगाया है कि उसने भयभीत होकर ही यह निक्चय किया है। मैं इस इलजाम लगाया है कि हमने भयभीत होकर ही यह निश्चय किया है। मैं इस आरोप के तथ्य को कवूल करता हूँ, मगर उस भतलब में नहीं जिसके अधीन कि यह आरोप किया गया है। हमें जानों की क्षिति या विधवाओं के विलाप या अनायों के कल्दन या अनेक घरों के जलाये जाने का भय नहीं हैं, यिक भय उस बात का है कि यि हम इस प्रकार एक-दूसरे से बदला ऐने के लिए वार करते रहे तो अन्त में हम नर-भक्षी राक्षम या उनसे भी ज्यादा पनित हो जायँगे।

में पिछले ३० साल में गांधी जी की नगित में रहा हूँ। उनके प्रति मेरी वफा-दारी और श्रद्धा कभी डांबांडोल नहीं हुई। यह निजी नहीं वरन् राजनीतिक विकादारी है। जब-जब उनसे मेरा मतभेद भी हुआ तब नब मेरी विद्याल नर्गनित यिनयों में उनका राजनीतिक सहज-ज्ञान मुझ अधिक ठीक प्रतीन हुआ। आज भी, में नमजना हूँ कि गांधीजी अपनी श्रेण्ठनम निर्भीवना के नाथ ठीक है और मेरा मन दोषयुवन है। तो फिर में उनके साथ क्यों नहीं हूं जनका कारण यह है

संक्षिप्त काग्रेस का इतिहास

्रिड्या है। अहिसापूर्ण असहयोग की तरह, कोई निम्त्रित पथ नहीं है कि जिसपर चलकर हम अपनी मजिल पर पहुच जाय।

इसो हृदय-विदारक हालात मे, मैने हिन्दुस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया है। आप जानते होगे कि मेरा जन्मस्थान, परिवार और घर-त्रार पाकिस्तान में है। मेरे वन्यु-बाधव सभी वही रह रहे है। सन् १६०६ में जब मैने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रक्खा था तब मैंने कभी नहीं सोचों था कि मैं हिन्दुस्तान के किसी भाग-विशेष की आजादी की पातिर काम कर रहा हूँ। मैं तो समस्त भारत के लिए काम कर रहा था। इस देश का प्रत्येक नटी-नोला, कोना-कोना मेरे लिए पवित्र है और इस कृत्रिम वँटवारे के बाद भी वह मेरे लिए वैसा ही बना रहेगा। कहा जाता है कि इस फैसले से साम्प्रदायिक दगे-फिमाद वद नहीं होंगे और न हो सकेगे। हां, इस समय तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि शैतान की गुड्डी चर्छ। है। तो फिर भविष्य में ये दंगे क्योकर मँगाले जायँगे? क्या यह जहरीला चक और भी वेग पकड लेगा जैसा कि अभी-अभी बदला लेने से बटा है ? इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने मेरठ के सभापति के भाषण में दे चुका हू। मैंने तभी कहा था कि केन्द्र ढीला पड जाने से प्रान्तों में मन-मानी होने लगी है। विहार-सरकार को चाहिए था कि वगाल-सरकार को चेतावनी दे दे कि यदि वगाल के हिन्दुओ पर अत्याचार होते रहे तो विहार-सरकार अपनी नेकनीयती के वावजूद विहारी मुसलमानो की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकेगी। इसका मतलव यह होता कि मामला ऊँचे अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे पहुँच जाता जहा सुव्यवस्थित सरकार इस्-पर एक दूसरे से वात्चीत करती। तव यह मामला उत्तेजित वलवाइयो के हाया से, जिनके नजदीक नैतिकता या कानून या सयम तुच्छ होता है, निकल जाता। दगाइयो का जोश अन्या होता है। अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा भी किसी विधि से की जाती है। मुझे यकीन है कि १६ अगस्त के बाद हिन्दुस्तान की वाग-डोर जिनके हाथों में होगी वे देखेंगे कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दुओं के साथ अन्याय नहीं होता। यदि मेरे इन शब्दों का हिन्दुस्तान के पाकिस्तान विभाग पर कुछ भी असर हो सकता है तो मैं जरूर कहूँगा कि "दोनो विधान परिपदों को एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करनी चाहिये जो कि अल्पसस्यको के अधिकारो का निर्णय करे।"

हमने देशी राज्यों के सम्बन्ध में अभी-अभी प्रस्ताव पास किया है। इस सिल-सिले में में एक वात सुझाना चाहूगा। जिन रियासतों ने अभी तक अपने प्रतिनिधि विधान-परिपद् में नहीं भेजें हैं उनकी प्रजा ऐसे प्रतिनिधियों को स्वय भेज दे। जहा-जहां व्यवस्थापिका सभाओं का अस्तित्व हैं वहा-वहा वे एसेम्बलिया ब्रिटिश भारत की एसेम्बलियों की ही भाँति एकाकी हस्तातरण-मत पद्धति-द्वारा प्रति-

इस प्रकार व्यक्तियो और दगाइयो के जन-समूह और उसके बदले की आग से

इसकी रक्षा हो सकेगी।

निधियों का चुनाव करले। जहां ऐसी एसेम्बलिया नहीं है वहां प्रतिनिधियों के चुनने के लिए अन्य उपाय काम में लाए जा सकते हैं। बुनियादी अधिकारों की कमेटी में हमने सारे देश के लिये एक ही सामान्य नागरिकता मान ली है। प्रत्येक रियासत का, नागरिक हिन्दुस्तान का नागरिक है और उसे भारतीय विधान-परिषद् में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। रियासत के वाहर से आया हुआ दीवान नागरिकों का यह अधिकार सीमित नहीं कर सकता। हमें भारत का विधान बनाने में रियासती प्रजाजन के परामर्श की जरूरत है।

विधान बनाने मे रियासती प्रजाजन के परामर्श की जरूरत है।

फैसले के रूप में मैं कहँगा कि हमें उस आजादी से ही सतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये जो गीघ्र ही मिलनेवाली है। हमें उस एकता के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए जिसे हमने शीघ्र स्वतत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न में खो दिया है। यह काम केवल भारत को मुदृढ, सुखी, गणतत्रात्मक और समाजसत्तावादी राज्य वनाकर किया जा सकता है। इस प्रकार का भारत अपने विछुड़े बच्चों को फिर अपनी गोद में बिठा सकता है। इस काम में उन सभी सच्ची सेनाओं और विल्वानों की आवश्यकता होगी जिनकी हमें आजादी की लड़ाई में जरूरत थी। हमें सभी शक्ति की भूखी राजनीति का परित्याग कर देना चाहिए। हा, उस त्याग, कठिनाई और स्वेच्छापूर्ण अिकचन की गौरवपूर्ण परम्परा का परित्याग नहीं करना चाहिए जिसका निर्माण हमने जेल जाकर, लाठी-प्रहार सहकर और गोलियाँ खाकर किया है। हमें फिर अपने को उस नए कार्य में लगा देना चाहिए जो स्वतत्रता-प्राप्ति के समान ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो आजादी हासिल की है वह तबतक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत की एकता न स्थापित हो जाय। विभाजित भारत तो गुलाम बन जायगा। इसिलए हम दूसरी गुलामी से जहा तक शीघ्र हो सके दूर हो जायँ। हमें स्वभाग्य-निर्णय के जो सुअवसर प्राप्त है उन्हे अब हमारे भारत में एकता कायम करने के उत्कृष्ट ध्येय में लगा देना चाहिए। इस कार्य में ईग्वर हमारी मदद करे।"